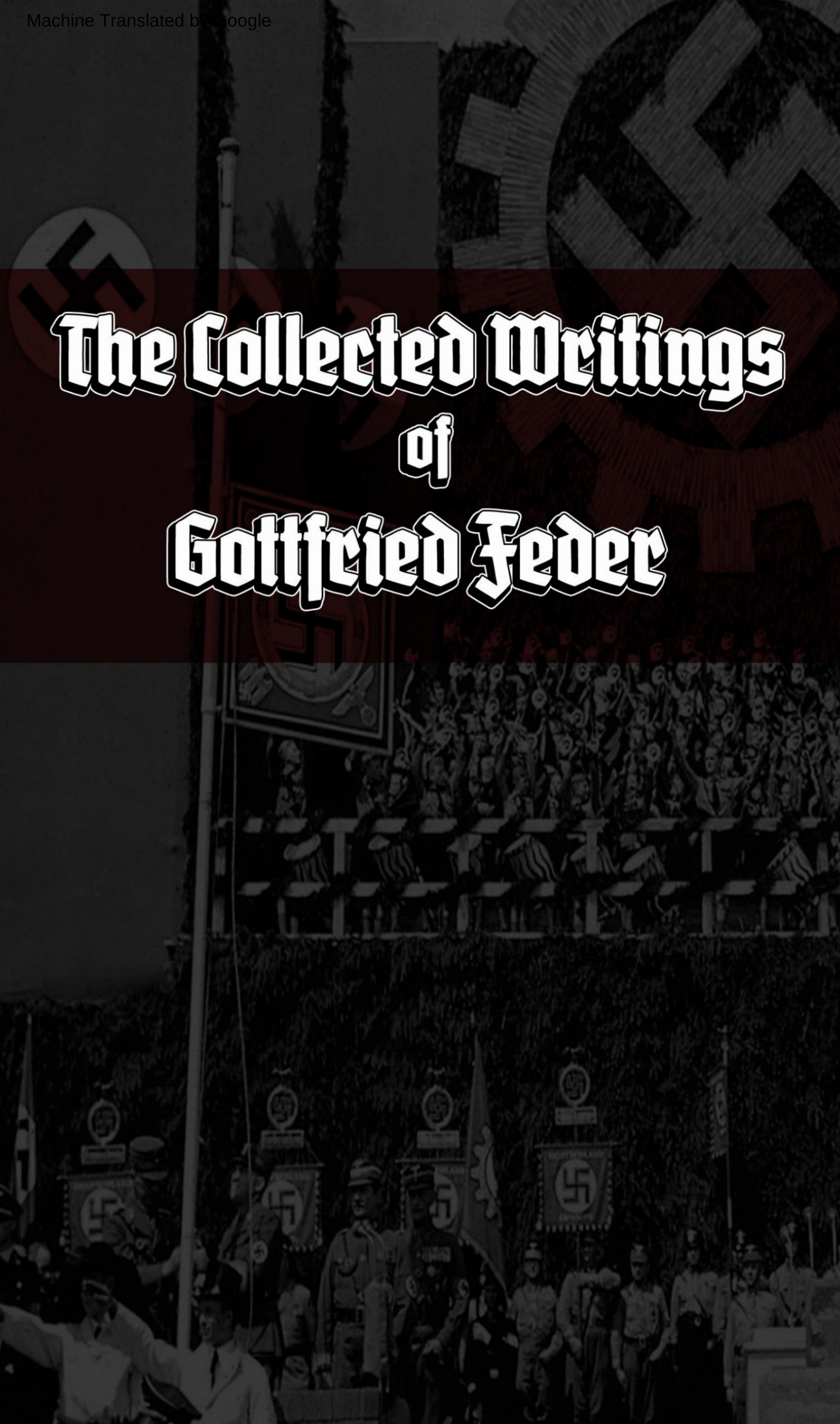


The Collected Writings of Gottfried Feder

का संग्रहित लेखन

गॉटफ्राइड फेडर

कलियुग, 130 AH में प्रकाशित

SUDETENLAND
VERLAG

विषयसूची

गॉटफ्राइड फेडर



गॉटफ्रीड फेडर, (27 जनवरी ,ᛉ1883, वुर्जबर्ग, जर्मनी — 24 सितंबर ᛦ ,
1941, मुर्नौ), एक जर्मन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो मुख्य इकोनॉमिक थ्योरिटिशियन थे।
जर्मन नेशनल सोशलिज़्म के शुरुआती दौर के बारे में।

सिविल इंजीनियर फेडर 1919 में अपनी किताब 'मैनिफेस्टो फॉर ब्रेकिंग' के लिए मशहूर हुए थे।
'द थ्रॉलडम ऑफ इंटरेस्ट', और उसी साल सितंबर में म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी की मीटिंग में उनके भाषण ने एडॉल्फ
हिटलर के लिए तुरंत प्रेरणा दी । पॉलिटिक्स में एंट्री। फेडर के सोशलिस्ट और एंटी-कैपिटलिस्ट विचार बाद में मार्च 1920 में
हिटलर के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (NSDAP) के लिए 25-पॉइंट प्रोग्राम में दिखे , साथ ही फेडर की अपनी किताब,
'जर्मन स्टेट ऑन द नेशनल सोशलिस्ट फाउंडेशन' में भी दिखे, जिसे हिटलर ने "[नेशनल सोशलिस्ट] मूवमेंट का कैटेचिज़्म" माना था।
1924 और 1936 के बीच फेडर जर्मन राइखस्टाग में बैठे और NSDAP इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन (1931), जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ़
इकोनॉमिक्स के स्टेट सेक्रेटरी (1933), और स्टेट हाउसिंग कमिश्नर (1934) के तौर पर काम किया। हालांकि, नाज़ी पॉलिसी को मौजूदा
इकोनॉमिक सिस्टम में आम तौर पर शामिल करने के साथ, पार्टी के मामलों में फेडर की भूमिका बहुत कम हो गई, और 1936 तक
वह लगभग गुमनामी में चले गए थे ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम

सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और इसकी

आम अवधारणाएँ

के उदय का ऐतिहासिक विवरण

NSDAP ने एडॉल्फ हिटलर के करियर का बायोग्राफिकल सर्वे किया

एडॉल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल, 1889 को पुराने गांव ब्रौनाऊ में हुआ था।
बवेरिया.

उनके पिता एक गरीब किसान के अनाथ बच्चे थे और उन्होंने मेहनत करके कस्टम ऑफिसर बनने का रास्ता बनाया। उनकी माँ एक जर्मन किसान परिवार से थीं। जब वे 13 साल के थे, तब उनके पिता गुज़र गए, और चार साल बाद उनकी माँ भी गुज़र गईं। एडॉल्फ हिटलर उस समय नेशनल स्कूल छोड़ने के बाद डेन्यूब पर लिंज़ के रियल स्कूल में स्कॉलर थे। उनके पिता की इच्छा थी कि वे एक ऑफिसर बनें, लेकिन उनकी अपनी इच्छा एक आर्टिस्ट बनने की थी। उनकी माँ की मौत के बाद उन्हें बिना देर किए अपना गुज़ारा खुद करना पड़ा।

17 साल की उम्र में हिटलर वियना गया, जहाँ उसका मकसद आर्किटेक्ट बनना था। उसने अपनी मेहनत से गुज़ारा किया, पहले एक बिल्डर के मज़दूर के तौर पर, मोर्टार मिलाकर, फिर एक आर्किटेक्ट के ड्राफ्ट्समैन के तौर पर। 18 साल की उम्र में ही उसे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी होने लगी थी; वह एंटी-मार्क्सिस्ट बन गया, लेकिन अब तक कोई लीडिंग रोल नहीं निभाया था। अपनी शुरुआती जवानी से ही हिटलर बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट था, और उसकी उम्मीद थी कि वह अपने काम के समय के सोशल एक्सपीरियंस को अपनी नेशनलिस्ट सोच के साथ मिला सके। कई सालों तक वह वियना में बहुत गरीबी में रहा।

1912 में वे म्यूनिख चले गए, जहाँ वे एक स्टूडेंट थे। उन्होंने कभी जवानी के मज़े नहीं देखे थे, लेकिन जिस दिन से वे जेब में 50 क्रोनन लेकर घर से निकले, मेहनत और तंगी ही उनके नसीब में थी। फरवरी 1914 में, वे ऑस्ट्रियन आर्मी में सेवा करने की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो गए। छह महीने बाद युद्ध छिड़ गया। उन्होंने तुरंत जर्मन आर्मी में सेवा के लिए अपनी मर्ज़ी से काम किया, और बवेरिया के राजा लुडविग से सीधी अपील करके, युद्ध के लिए वॉलंटियर के तौर पर बवेरियन रेजिमेंट में शामिल होने की इजाज़त ली। 10 अक्टूबर, 1914 को, नई रेजिमेंट आगे बढ़ी।

2 दिसंबर , 1914 को, 25 साल के वॉलंटियर को आयरन क्रॉस, 2nd से सम्मानित किया गया।
कक्षा।

'बायर्नवाल्ड' पर हमले और विट्सचेट के पास दूसरी लड़ाइयों में उनकी बहादुरी को देखते हुए, उन्हें डिस्पैच-कैरियर के तौर पर ड्यूटी करने का ऑर्डर दिया गया, जिसके लिए खास हिम्मत और भरोसे की ज़रूरत थी, क्योंकि अक्सर भारी गोलीबारी के बीच खुली ज़मीन से रिपोर्ट ले जानी पड़ती थी। इससे जल्द ही उनका नाम उनके साथियों के छोटे से दायरे से बाहर पूरी रेजिमेंट में मशहूर हो गया।

7 अक्टूबर 1916 को, वह एक शेल स्प्लिंटर से घायल हो गए। मार्च 1917 में, वह अपनी रेजिमेंट में वापस आ गए। उन्हें कई और सम्मान मिले, जिसमें फॉन्टेन्स के पास लड़ाई में खास बहादुरी के लिए रेजिमेंट्स-डिप्लोम और आखिर में आयरन क्रॉस, क्लास I शामिल है।

14 अक्टूबर 1918 को वे अपनी रेजिमेंट के कई साथियों के साथ मस्टर्ड गैस से बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश उस समय पहली बार कर रहे थे, और वे कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। जब वे अस्पताल में थे, तभी क्रांति शुरू हो गई।

इस पर हिटलर ने पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया। 1919 में वह 6 लोगों की एक छोटी पार्टी में शामिल हो गए और उसी पर उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई। उन्होंने नए मूवमेंट का प्रोग्राम तैयार किया और उसका कैरेक्टर और मकसद तय किए।

न्यूक्लियस: सात पुरुष

सितंबर 1919 में, एडॉल्फ हिटलर ने सात लोगों के सामने अपना पहला भाषण दिया; फिर उन्होंने 11, 25, 47; दिसंबर में 111; जनवरी 1920 में 270, और उसके तुरंत बाद 400 लोगों को संबोधित किया।

14 नवंबर , 1920 को, उन्होंने 1700 लोगों की एक बड़ी मीटिंग में भाषण दिया। अब उन्होंने नई पार्टी का प्रोपेगैंडा ऑर्गनाइज़ किया, जिसमें एक साल के काम के बाद 64 मेंबर थे। एक साल बाद — 1920 — यह पहले ही 3000 तक पहुँच चुकी थी। म्यूनिख में हिटलर की प्रोपेगैंडा एक्टिविटी ऐसी थी कि वह आखिरकार हफ़्ते में तीन बार बड़ी मीटिंग में बात कर रहा था, और सोमवार को वह ट्रेनिंग का कोर्स करता था। उसने सबसे पहले वर्साय की बेवकूफी पर हमला किया, और मार्क्सिस्ट, सेंटर पार्टी, वगैरह के इस दावे को गलत बताया कि उस ट्रीटी को पूरा करना मुमकिन है। उसने इन पार्टियों के नारे की बुराई की — "अपने हथियार डाल दो, और बाकी लोग भी हथियार डाल देंगे"। उसने यह मानकर बात की कि हमारे हथियार डालने के बाद बाकी लोग हथियार डालना जारी रखेंगे, — अगर अपने पैसे से नहीं, तो पूरी तरह से हथियार डाले हुए जर्मन देश से लिए गए लाखों डॉलर से। ट्रीटी पर साइन करने के पक्ष में SPD और सेंटर के प्रोपेगैंडा का विरोध करते हुए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि हम चाहे जिस पर भी साइन करें, रूहर पर कब्ज़ा हो जाएगा।

1921.

इस साल रोसेनहाइम और लैंडशूट में पहले लोकल ग्रुप्स की स्थापना हुई। हिटलर ने पार्टी को बचाने के लिए लोगों का पहला ग्रुप बनाया और बवेरिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। हमारे लीडर ने म्यूनिख के सर्कस में 5000 से ज़्यादा लोगों की एक मीटिंग को भी संबोधित किया।

उन्होंने अपनी मीटिंग्स में ऐलान किया कि ट्रीटी को पूरा करने से, जैसा कि SPD, सेंटर और वोक्सपार्टी ने कहा, शांति और सुकून से जर्मनी की खुशहाली बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उस बेवकूफी भरी पॉलिसी का नतीजा बड़े पैमाने पर महंगाई होना तय था, जिससे जर्मन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। हिटलर का यह कहना कि ब्लैक-रेड गवर्नमेंट स्टेट रेलवे को डी-नेशनलाइज़ करने का प्लान बना रही है, उसे 'सरासर झूठ' बताया गया। पार्टी के अंदर बगावत की कोशिश नाकाम हो गई। हिटलर ने पार्टी का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिससे उसे तानाशाही ताकतें मिलीं।

सोशल डेमोक्रेसी, जो हिटलर के नाम को नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रही थी, अब आतंकवाद के तरीकों से अपना डर दूर करने की कोशिश कर रही थी। मीटिंग्स में खूनी झड़पें होती थीं, जिसमें हमारे लीडर की हिम्मत का पलड़ा भारी रहता था। उनके दौरान एक ऐसा बॉडी-गार्ड 4 बनाया गया जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जिसे बाद में 'स्टर्माबटेइलुंग' नाम दिया गया।

1922.

जब म्यूनिख पर कब्ज़ा हो रहा था, तब यह आंदोलन बाकी बवेरिया में फैलने लगा था। हिटलर ने दूसरी पार्टियों के साथ समझौते के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने धीरे-धीरे सभी ऐसी 'नेशनलिस्ट' पार्टी बना दी और नेशनल सोशलिस्ट आंदोलन को उन पर सबसे ऊपर कर दिया।

अक्टूबर 1922 में, हिटलर 800 आदमियों के साथ कोबर्ग तक गया, और पहली बार 24 घंटे में दो बार उस शहर में रेड टेरर को पूरी तरह से कुचल दिया।

एडॉल्फ हिटलर ने तब सबके सामने ऐलान किया था कि हम महंगाई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसे उन्होंने ब्लैक-रेड कोएलिशन की पॉलिसी का नतीजा माना था।

सिस्टम के सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा नफ़रत किए जाने वाले दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। सोशल डेमोक्रेसी और सेंटर पार्टी ने बहस करके अपना बचाव करना बंद कर दिया और बदनाम करने की पॉलिसी अपना ली।

1923.

जनवरी 1923 में, पहली बड़ी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, और पार्टी के पहले बैनर लगाए गए। स्टर्माबटेइलुंग को औपचारिक रूप से शामिल किया गया।

पार्टी प्रोपेगैंडा की अच्छी तरह से स्टडी की गई और उसे बेहतर बनाया गया, और ऑर्गनाइज़ेशन के पक्के सिद्धांत तय और स्थापित किए गए। हिटलर के आस-पास बड़ी संख्या में समर्थक जमा हुए, जिनमें से ज़्यादातर आज लड़ाई में उसके पक्के साथी हैं। इस बीच, उस पर हमले और भी पक्के इरादे से किए गए; वह अपने दुश्मनों की मीटिंग में डिस्टर्ब करने के आरोप में पहली बार जेल गया; उस पर लगातार जुर्माना लगाया गया। फिर भी, उसने एक पल के लिए भी सिस्टम के खिलाफ लड़ना बंद नहीं किया।

1923 की गर्मियों में एडॉल्फ हिटलर ने बवेरिया के ज़्यादातर शहरों में रेड टेरर को खत्म करना शुरू कर दिया; रैटिसबन, हॉफ, बेयरुथ, नूर्नबर्ग, फर्थ, इंगोलस्टाट, वुर्जबर्ग, श्वेनफर्ट, — अक्सर सड़क पर लड़ाई में खून-खराबे की कीमत पर, जिसमें उन्होंने सोशल-डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट आतंकवादी गिरोहों को हराया।

राइख की नाकाबिल सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में कड़वे इल्ज़ाम भी लगे। उन्होंने रूर के मामले में सरकार के कमज़ोर विरोध की नाकामयाबी की भविष्यवाणी की, और फ्रांस के साथ समझौते और उसे पूरा करने की बेवकूफ़ी भरी पॉलिसी पर लगातार हमला किया। वह इंग्लैंड और इटली के साथ समझौते की ज़रूरत बताने में कभी नहीं चूके।

नवंबर 1923 में, एडॉल्फ हिटलर ने सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। विद्रोह नाकाम रहा, और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया।

1924.

मार्च 1921 में म्यूनिख में बड़ा ट्रायल हुआ। हालांकि तथ्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बावजूद, हमारे नेता को नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा सही ठहराया गया। हिटलर के बचाव ने कोर्ट पर इतना असर डाला, और उसकी अकेली और खास ज़िम्मेदारी लेने की बात इतनी पक्की थी कि उस पर आरोप लगाने वाले वकील की बात उसके नेक इरादों का एक शानदार सबूत बन गई। हालांकि, जज ने उसे कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की सज़ा सुनाई।

नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को अपने लीडर के जाने का दुख हुआ। उसके दुश्मनों को यकीन हो गया कि आंदोलन खत्म हो गया है, और उन्होंने हिम्मत करके बदनाम डावेस पैक्ट पर साइन किया, इस तरह जानबूझकर जर्मनी को लूटने का सिस्टम शुरू किया, जिसे यंग प्लान में आगे बढ़ाया गया। सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर के लिए क्या ही बड़ी जीत थी! जर्मनी को गुलाम बनाने का मकसद साफ तौर पर पूरा हो गया था!

हिटलर ने अपने साथियों के ज़रिए, जो आज़ाद थे, डावेस पैक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बेकार कोशिश की। बेकार में उसने उनसे सबके सामने यह ऐलान करवाया कि सेंटर पार्टी, SPD और वोक्सपार्टी का यह भरोसा कि प्लान के तहत विदेशी लोन से देश की खुशहाली बढ़ेगी, बेरोज़गारी खत्म होगी, सैलरी बढ़ेगी और टैक्स कम होंगे, खेती बचेगी, यह सब सिर्फ़ देश के साथ धोखा था। बेकार में उसने उनसे यह कहने को कहा कि डावेस पैक्ट से गरीबी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि लोन पर लगने वाला ब्याज इंडस्ट्री को कमज़ोर कर देगा, जबकि लोन खुद सिर्फ़ प्लान के तहत फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए थे; दिवालियापन और बेरोज़गारी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी।

डूब जाएगा, कीमतें और टैक्स और बढ़ जाएंगे, और किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और उन्हें अपना सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

20 दिसंबर को हिटलर ने किला छोड़ दिया।

1925.

27 फरवरी , 1925 तक , एडॉल्फ हिटलर ने पार्टी के नए जन्म की मांग की, और जेल जाने के बाद उन्होंने 4000 लोगों के सामने अपना पहला भाषण दिया।

9 नवंबर की घटनाओं के बाद नेशनल सोशलिस्ट आंदोलन टूट गया था। , और उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा ज़ब्त कर लिया गया था; इसलिए एडॉल्फ हिटलर ने अब बिना कुछ हाथ में लिए पार्टी को उसकी नींव से फिर से बनाना शुरू कर दिया। बर्लिन में वोरवर्ट्स और जर्मेनिया ने उसकी कोशिशों का मज़ाक उड़ाया और उस "मूर्ख" का मज़ाक उड़ाया जिसे जेल ने पागल बना दिया था।
फिर भी, हिटलर के नेतृत्व में पार्टी का पुनर्निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ। पुराने नेता एक बार फिर उसके आस-पास पूरी ईमानदारी से इकट्ठा हुए। हिटलर ने पार्टी प्रेस को नई गतिविधियों के लिए प्रेरित किया।

दिसंबर 1925 तक, पार्टी के 27,000 सदस्य हो गए थे।
डेमोक्रेट्स ने घबराकर फैसला किया कि नेता दो साल तक पब्लिक में नहीं बोलेंगे।

1926.

इस साल जून में हिटलर के जेल जाने के बाद पार्टी का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ।

बुर्जुआ दुनिया को अब भी यकीन था कि पूर्ति की नीति जर्मनी को बचा लेगी और डावेस पैक्ट इंडस्ट्री को फिर से ज़िंदा कर देगा। मार्क्सवादियों को यकीन था कि उनका दबदबा पक्का है।

प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग अपने सपोर्टर्स से अलग हो गए और सेंटर और SPD के साथ मार्च किया। पार्टी ने संघर्ष जारी रखा; साल के आखिर तक इसके 49,000 मेंबर हो गए।

1927.

हिटलर को पब्लिक में बोलने से रोकने वाला ऑर्डर वापस ले लिया गया, क्योंकि इसे लागू करना नामुमकिन पाया गया। उन्होंने कई बड़ी मीटिंग्स को संबोधित किया। हर महीने पार्टी और मज़बूत होती गई।

चारों ओर हो रहे घटनाक्रम से यह बात और भी ज़्यादा साबित हो गई कि हिटलर सही था।
डावेस पैक्ट का पर्दाफाश हो गया, और इसके नतीजे बहुत भयानक थे। सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर पार्टी ने झूठ और गाली-गलौज से जो बचाया जा सकता था, उसे बचाने की कोशिश की।

अगस्त में हिटलर ने नूर्नबर्ग में पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो बहुत सफल रही। साल के आखिर तक पार्टी में 72,000 सदस्य हो गए।

1928.

एडॉल्फ हिटलर ने अपनी पार्टी को मौजूदा सिस्टम पर तेज़ हमला करने के लिए लीड किया। नेशनल सोशलिज़्म अब जर्मनी के अंदर और बाहर के नुकसान पहुंचाने वालों का पक्का दुश्मन बन गया था।
हिटलर ने अपना हमला खास तौर पर किसानों और मिडिल क्लास की बेवजह बर्बादी के खिलाफ किया। उसने घरेलू बाज़ारों पर आने वाली तबाही की भविष्यवाणी की। उसने सैकड़ों मीटिंग में बार-बार कहा कि फ़ुलफ़िलमेंट की पॉलिसी पागलपन है, और यह

इसका नतीजा यह होगा कि जर्मन इंडस्ट्री की मौत और बर्बादी होगी। सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर ने अपना बदला लेने की कोशिश में उनका मज़ाक उड़ाया और उनका मज़ाक उड़ाया। उनके झूठ और गाली-गलौज हिटलर पर पर्सनली निशाना साधे गए।

साल के आखिर तक मेंबरशिप की संख्या 108,000 हो गई, और पार्टी के 12 मेंबर रैहस्टाग में बैठे।

1929.

एडॉल्फ हिटलर ने मौजूदा सिस्टम के साथ अपनी लड़ाई पूरी ताकत से जारी रखी। पार्टी का प्रेस बेहतर हुआ, स्टर्माबटेइलंग बढ़ा, संगठन मज़बूत हुए और प्रोपेगैंडा तेज़ हुआ। नेशनल सोशलिज़्म के सिद्धांत देश की सोच में गहराई तक घुसने लगे।

4 अगस्त को नूर्नबर्ग में दूसरी पार्टी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पर हुई। हिटलर ने ब्लैक-रेड सिस्टम पर लगातार बढ़ती एनर्जी के साथ हमला किया और 'डेमोक्रेसी' के सभी मतलबों के खिलाफ सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर बिना किसी मुकाबले के खड़ा हुआ। उसे पार्टी की लीडरशिप से हटाने की सभी कोशिशें नाकाम कर दी गईं।

साल के आखिर तक पार्टी के सदस्यों की संख्या 178,000 हो गई।

1930.

यंग प्लान के खिलाफ लड़ाई ज़ोरों पर थी। हिंडनबर्ग ने पूरे ज़ोर-शोर से इसका बचाव किया, यह कहते हुए कि इससे जर्मनी बच जाएगा, जर्मन इंडस्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी, बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, किसान फिर से सांस ले पाएंगे, और टैक्स कम करना मुमकिन होगा।

एडॉल्फ हिटलर ने ऐसे विचारों को झूठा और खतरनाक बताया; उसने इसके उलट भविष्यवाणी की। उसकी पार्टी ने भयंकर लड़ाई के बीच देश को जागरूक करना शुरू किया। विरोधियों ने झूठ की झड़ी लगा दी।

रीचस्टैग के चुनाव 14 सितंबर को हुए थे। , 1930. पार्टी को 6,5 वोट मिले मिलियन वोट मिले, और 107 सदस्य चुने गए। इसका अंदरूनी संगठन पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत था। बाहर से बढ़ावा दिए गए विद्रोह के कुछ छोटे-मोटे प्रयासों को हिटलर ने तुरंत कुचल दिया, और जो लोग बिना शर्त नहीं माने उन्हें निकाल दिया गया।

सेंटर पार्टी, जो अब अच्छे या बुरे के लिए SPD के हाथों में आ गई थी, ने चर्च को हिटलर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सेंटर पार्टी के बिशप और पादरियों ने नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ कट्टर हमला शुरू कर दिया, उसके मानने वालों को निकाल दिया, और उन्हें ईसाई तरीके से दफ़नाने से भी मना कर दिया। हिटलर इस बात पर अड़ा रहा कि सेंटर जर्मनी के लिए बर्बादी का कारण है और उसने पहले से भी ज़्यादा पक्के इरादे से इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उसने अपनी राय में कुछ बदलाव करवाने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मना कर दिया।

साल के आखिर तक पार्टी के सदस्यों की संख्या 389,000 हो गई।

1931.

यंग प्लान के खिलाफ लड़ाई जारी रही। हिटलर ने जो नतीजे देखे थे, वे हकीकत बन गए।

सरकार ने इंडस्ट्री को बचाने के लिए इमरजेंसी उपायों से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। इसके बाद तीखे विवाद हुए, जिसमें एडॉल्फ हिटलर ने फिर से उस पॉलिसी के खतरनाक नतीजों की ओर इशारा किया। कुछ महीनों में - कुछ हफ़्तों में भी - वह सही साबित हुआ।

इस बीच कई नेशनल सोशलिस्ट अखबार शुरू हो गए थे, और पार्टी का सेंट्रल पब्लिशिंग ऑफिस धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया था। ऑर्गनाइज़ेशन बहुत कुशल हो गया था, और स्टर्माबटेइलुंग समय के साथ डेवलपमेंट के एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था।

हमारे विरोधी झूठ में डूबे हुए थे और फ्रांस में सामान के ऑर्डर देने की अनुमति दे रहे थे।

साल 1931 के आखिर तक हिटलर पार्टी के मेंबर 806,000 हो गए, एक महीने बाद 862,000 हो गए, और फिर एक महीने बाद 920,000 हो गए। चुनाव के दिन लगभग दस लाख मेंबर थे, और पोलिंग बूथ पर अनगिनत लाखों सपोर्टर थे।

जो आदमी कभी एक गरीब मज़दूर था और बाद में मोर्चे पर एक सैनिक बन गया, उसने मुश्किल से तेरह साल में जर्मनी का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना दिया है। इस आदमी के खिलाफ़ उसके विरोधी सिर्फ़ झूठ और बदनामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह अब तक सभी झूठों के बावजूद हमेशा जीता है, और इस बार वह राइख का प्रेसिडेंट चुने जाने के करीब पहुँच गया है।

क्या जर्मनी के पूरे इतिहास में किसी ने पार्टी, हाई फाइनेंस, कैपिटल, प्रेस, पब्लिक ओपिनियन, ब्यूरोक्रेसी, झूठ, टेररिज्म और ज़ुल्म के विरोध के बावजूद, बारह साल में ऐसी कामयाबी हासिल की है?

यह कोई सुरक्षित बच्चा नहीं था; अपने शुरुआती सालों से ही वह सबसे ऊँचे दर्जे का इंसान रहा है।
शब्द का अर्थ, पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करना।

प्रस्तावना

1926 में वाइमर में पार्टी काउंसिल ने पैम्फलेट की एक सीरीज़ छापने का फैसला किया, जिसमें जर्मनी में राजनीतिक जीवन के हर पहलू पर असर डालने वाले बुनियादी सवालों को छोटे रूप में बताया गया था। हमारा इरादा था, और है, कि हम अपने सार्वजनिक जीवन के अलग-अलग कामों के प्रति नेशनल सोशलिज़्म के रवैये की एक जैसी और पूरी तस्वीर पेश करें, और यह भी कि वह अपनी गलतियों और कमियों को कैसे दूर करना चाहता है।

इसलिए हमारा काम है कि हम अच्छी तरह से देखें कि यह कैसे है, फिर साइंटिफिक तरीके से पता करें कि यह कहाँ से शुरू हुआ, और आखिर में, क्रिएटिव इंस्पिरेशन के साथ, इस अहम सवाल का जवाब दें, तो फिर क्या? इन पैम्फलेट का बड़ा मकसद स्टेट की ज़िंदगी, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए नए तरीके बताना है; इस उथल-पुथल के दौरान 'रोशेर डे ब्रॉन्ज़' को ऊँचा रखना, गहरी स्टडी करके साफ जानकारी का भंडार बनाना, ताकि इन सबसे एक एकजुट पॉलिटिकल इच्छाशक्ति निकल सके।

31 अगस्त, 1927 को बड़ी मीटिंग में , एडॉल्फ हिटलर ने ज़ोर देकर कहा: "प्रोग्राम के सवाल काउंसिल ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर असर नहीं डालते; प्रोग्राम तय है, और मैं आंदोलन के सिद्धांतों में कभी भी बदलाव नहीं होने दूंगा, जैसा कि इसके प्रोग्राम में बताया गया है।" हमारे फ्यूहरर की इस पक्की बात से मैं पूरे दिल से सहमत हूं, क्योंकि हमारे जैसे आंदोलन की जान और असरदार ताकत के लिए इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि, जैसे-जैसे समय बीतता है, इसके तय प्रोग्राम की बुरी आलोचना हो।

कोई भी आदमी जिसे लगता है कि वह यहूदी मामले में, ज़्यादा पैसे के खिलाफ हमारी लड़ाई में, डावेस पैक्ट और गरीबी हटाने वाली पॉलिसी में, या हमारे प्रोग्राम में शामिल किसी भी दूसरे मामले में हमारे साथ पूरी तरह से नहीं चल सकता, या जो लीग ऑफ़ नेशंस, लोकार्नो पैक्ट के ज़रिए जर्मन देश की आज़ादी को समझौते और कायरता से बेचने को तैयार है, उसे हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है; उसकी जगह NSDAP से बाहर है। हम उस 'बेहतर निजी जानकारी' को पूरी तरह से खारिज करते हैं जिसे वह मंच पर भाषण और पत्रकारिता में दिखाने को तैयार रहता है।

एक आदमी जो हमारे सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत है, उसे शायद कुछ छोटी-छोटी बातों पर शक हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हम सभी सवालों पर पूरी तरह सहमत होंगे, खासकर एक आक्रामक राजनीतिक आंदोलन में।

लेकिन, यह अलग बात है जब राजनीतिक दुश्मन किसी बात को गलत तरीके से पेश करके उसका मज़ाक उड़ाते हैं, जैसा कि असल में हुआ है। ऐसे मामले में ऑफिशियल कमेंट्री ज़रूरी है।

हम अपने प्रोग्राम में बदलाव करने से मना करते हैं, जैसा कि दूसरी पार्टियां तथाकथित बदली हुई स्थितियों के हिसाब से करती हैं। हम स्थितियों को अपने प्रोग्राम के हिसाब से बनाना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करके।

मुझे एडॉल्फ हिटलर ने पैम्फलेट की यह सीरीज़ जारी करने का काम दिया है, जो
पार्टी का ऑफिशियल लिटरेचर बनाने के लिए।

मैंने 6 मार्च, 1930 का पार्टी का ऑफिशियल मैनिफेस्टो शामिल किया है; साथ ही, राइशलैंडबंड के लीडिंग ऑर्गन, ड्यूश टैग्सजेइटुंग द्वारा पूछे गए दस सवालों के मेरे जवाब भी शामिल किए हैं।
उस अखबार ने मेरे जवाब स्वीकार कर लिये।

जर्मनी में ज़मीन-जायदाद के मालिकाना हक और विरासत के बारे में हमारी गलत सोच के बारे में सभी झूठ को खत्म करने का यह सबसे अच्छा और असरदार तरीका है।

1. खेती-बाड़ी करने वाली आबादी और खेती के मामले में NSDAP की स्थिति पर पार्टी का ऑफिशियल मैनिफेस्टो

म्यूनिख, 6 मार्च, 1930

1. जर्मनी के लिए किसान वर्ग और कृषि का महत्व

जर्मन देश अपने खाने का एक बड़ा हिस्सा विदेशी खाने-पीने की चीज़ों के इम्पोर्ट से कमाता है। वर्ल्ड वॉर से पहले हम इन इम्पोर्ट का खर्च अपने इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, अपने व्यापार और विदेश में जमा पैसे से उठा लेते थे। युद्ध के नतीजे ने इस संभावना को खत्म कर दिया।

आज हम अपने इम्पोर्टेड खाने के लिए ज़्यादातर विदेशी लोन की मदद से पेमेंट कर रहे हैं, जिससे जर्मन देश क्रेडिट देने वाले इंटरनेशनल फाइनेंसरों के कर्ज़ में और ज़्यादा डूबता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, तो जर्मन लोग और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे।

इस गुलामी से बचने का एकमात्र तरीका जर्मनी की अपने देश में ज़रूरी खाने की चीज़ें पैदा करने की काबिलियत है। इसलिए जर्मन खेती से ज़्यादा प्रोडक्शन जर्मन देश के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है।

इसके अलावा, देश की आबादी, जो आर्थिक रूप से मज़बूत और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, जिसे भविष्य में घरेलू बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे।

हम देश की आबादी को हेल्थ की विरासत का वाहक, देश के युवाओं का सोर्स और इसकी आर्म्ड स्ट्रेंथ की बैक-बोन भी मानते हैं।

एक कुशल खेती करने वाले वर्ग को बनाए रखना, जिसकी संख्या आम आबादी के बढ़ने के साथ बढ़ती रहे, नेशनल सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि हमारा आंदोलन आने वाली पीढ़ियों में हमारे सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचता है।

2. वर्तमान राज्य द्वारा कृषक वर्ग और कृषि की उपेक्षा

खेती का प्रोडक्शन, जिसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि किसानों पर बढ़ता कर्ज़ उन्हें खेती की ज़रूरी चीज़ें खरीदने से रोकता है, और क्योंकि खेती से फ़ायदा नहीं होता, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का लालच खत्म हो जाता है।

खेती से मेहनत का पूरा फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, इसके कारण जानने होंगे:

1. मौजूदा फ़ाइनेंशियल पॉलिसी में, जो खेती पर बेवजह बोझ डालती है। यह पार्टी की सोच की वजह से है, और क्योंकि यहूदी दुनिया का मनी मार्केट — जो असल में जर्मनी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कंट्रोल करता है — जर्मन खेती को खत्म करना चाहता है, क्योंकि इससे जर्मन देश, और खासकर मज़दूर वर्ग, उसके रहमोकरम पर आ जाएगा;

2. विदेशी किसानों के मुकाबले में, जो ज़्यादा बेहतर हालात में काम करते हैं, और जिन्हें जर्मन खेती की सुरक्षा की पॉलिसी से रोका नहीं जाता;

3. बड़े थोक बिचौलियों द्वारा किए गए फालतू मुनाफे में, जो वे खुद को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में रखते हैं।

4. किसान को बिजली और नकली खाद के लिए बहुत ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये कंपनियाँ मुख्य रूप से यहूदियों द्वारा चलाई जाती हैं।

ज़मीन पर मेहनत के कम रिटर्न से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाया जा सकता। किसान को कर्ज़ में डूबने और लोन पर ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह इस जुल्म में और डूबता जाता है, और आखिर में यहूदी साहूकार को अपना सब कुछ गँवा देता है। जर्मन किसान वर्ग को बेदखल किया जा रहा है।

3. राइख में, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, ज़मीन के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और जर्मनी के लिए एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी होगी।

जब तक जर्मन सरकार असल में इंटरनेशनल पैसे वालों के कंट्रोल में रहेगी, और उसे पार्लियामेंट्री-डेमोक्रेटिक सिस्टम से मदद मिलेगी, तब तक देश की आबादी की गरीबी की हालत में कोई बड़ा सुधार या खेती में सुधार की कोई उम्मीद नहीं हो सकती; क्योंकि ये इच्छाएँ जर्मनी की ताकत को खत्म करना चाहती हैं, जो ज़मीन पर आधारित है।

नए और बहुत अलग जर्मन राज्य में, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, किसानों और खेती को वह ध्यान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वे एक सच्चे राष्ट्रीय जर्मन राज्य का मुख्य सहारा हैं।

इससे ये ज़रूरतें सामने आती हैं:

1. जर्मनी की ज़मीन, जिसे जर्मन राष्ट्र ने हासिल किया है और जिसकी रक्षा की है, उसे जर्मन राष्ट्र की सेवा में, एक घर और रोज़ी-रोटी के साधन के तौर पर होना चाहिए। जो लोग ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, उन्हें इस तरह से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए।

2. केवल जर्मन राष्ट्र के सदस्य ही भूमि पर अधिकार रख सकते हैं।

3. उनके द्वारा कानूनी तौर पर हासिल की गई ज़मीन को विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन, प्रॉपर्टी रखने के अधिकार के साथ ही, देश के हित में इसका इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी भी जुड़ी हुई है।
   इस ज़िम्मेदारी को देखने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे; इनमें ज़मीन रखने वाले वर्ग के सभी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और राज्य का एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा।

4. जर्मन ज़मीन फ़ाइनेंशियल सट्टेबाजी का ज़रिया नहीं बन सकती, न ही इससे उसके मालिक को बिना कमाई की कमाई मिल सकती है। इसे सिर्फ़ वही खरीद सकता है जो खुद इस पर खेती करने को तैयार हो। इसलिए, सरकार को ज़मीन की हर बिक्री पर पहले से अधिकार रखने का अधिकार है।

   प्राइवेट लोन देने वालों को ज़मीन गिरवी रखना मना है। खेती के लिए ज़रूरी लोन आसान शर्तों पर किसानों को या तो राज्य से मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या खुद राज्य देगा।

5. ज़मीन के इस्तेमाल के लिए राज्य को प्रॉपर्टी की सीमा और क्वालिटी के हिसाब से बकाया दिया जाएगा। ज़मीन पर यह टैक्स ज़मीन की प्रॉपर्टी पर आगे किसी भी तरह के टैक्स से बचाएगा।

6. खेती कितनी होगी, इस बारे में कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता। हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें बड़ी संख्या में छोटे और मीडियम साइज़ के किसानों की ज़रूरत है।

खेतों में खेती करना। हालांकि, बड़े पैमाने पर खेती का बहुत ज़रूरी रोल है, और अगर इससे छोटे बिज़नेस के साथ अच्छा रिश्ता बना रहता है, तो यह सही है।

7. संपत्ति के उप-विभाजन को रोकने के लिए उत्तराधिकार का कानून आवश्यक होगा उस पर कर्ज़ का जमा होना।

8. राज्य को भूमि विनियोग करने का अधिकार होगा, जिसके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा मंज़ूर किया गया:

   क. जब राष्ट्र के किसी सदस्य के स्वामित्व में न हो;

   ख. जब - भूमि न्यायालयों के निर्णय द्वारा - यह माना जाता है कि उसका मालिक, बुरे व्यवहार से खेती, राष्ट्रीय हित में कार्य नहीं कर रहा है;

   ग. उस पर स्वतंत्र किसानों को बसाने के उद्देश्य से, जब मालिक स्वयं उस पर खेती नहीं कर रहा हो;

   d. जब देश के हित में खास सरकारी कामों के लिए इसकी ज़रूरत हो (जैसे, कम्युनिकेशन, देश की सुरक्षा)। गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई ज़मीन (जर्मन कानून के मुताबिक) बिना मुआवज़े के ज़ब्त की जा सकती है।

9. आबादी की पॉलिसी के आधार पर बनी एक स्कीम के तहत, जो ज़मीन उपलब्ध हो, उसे बसाना राज्य का काम है। ज़मीन बसने वालों को खानदानी कब्ज़े के तौर पर ऐसी शर्तों पर दी जाएगी जिनसे गुज़ारा हो सके। बसने वालों को उनकी नागरिक और प्रोफ़ेशनल काबिलियत की जांच करके चुना जाएगा। किसानों के बेटों को खास तरजीह दी जाएगी जिन्हें विरासत का अधिकार नहीं है।

पूर्वी सीमाओं पर कॉलोनाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। इस मामले में सिर्फ़ खेत बनाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इंडस्ट्री की नई ब्रांच के साथ मार्केट टाउन बनाना भी ज़रूरी होगा। छोटे खेतों को फ़ायदेमंद बनाने का यही एकमात्र तरीका है।

जर्मनी की विदेश नीति का यह कर्तव्य होगा कि वह जर्मनी की बढ़ती आबादी के पोषण और बसने के लिए बड़ी जगहें उपलब्ध कराए।

4. किसान वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाना होगा

1. ज़मीन पर रहने वाले लोगों की मौजूदा गरीबी को टैक्स में छूट और दूसरे इमरजेंसी उपायों से तुरंत दूर किया जाना चाहिए। आगे के कर्ज़ को कानून बनाकर लोन पर ब्याज दर को युद्ध से पहले के समय के बराबर कम करके और ज़बरदस्ती वसूली के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करके रोका जाना चाहिए।

2. यह राज्य की पॉलिसी होनी चाहिए कि खेती से फ़ायदा हो। जर्मन खेती को टैरिफ़, इम्पोर्ट पर राज्य के रेगुलेशन और नेशनल ट्रेनिंग की स्कीम से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

   खेती की उपज की कीमतों का तय होना बाज़ार की सट्टेबाजी से आज़ाद होना चाहिए, और बड़े बिचौलियों द्वारा खेती के हितों का शोषण बंद होना चाहिए, जिनका बिज़नेस खेती से जुड़ी एसोसिएशन को ट्रांसफर करने के लिए सरकार को बढ़ावा देना चाहिए।

   ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़ेशन का काम किसानों के रनिंग खर्च को कम करना और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। (औजार, खाद, बीज, ब्रीडिंग का इंतज़ाम)

(अच्छी स्थितियों में स्टॉक, सुधार, कीड़ों के खिलाफ लड़ाई, मुफ्त सलाह, केमिकल रिसर्च, वगैरह) राज्य संगठनों को अपना काम करने में पूरी मदद देगा। खास तौर पर राज्य को किसानों के लिए आर्टिफिशियल खाद और बिजली की लागत में काफी कमी लाने पर ज़ोर देना चाहिए।

3. ऑर्गनाइज़ेशन को खेत मज़दूरों के ग्रुप को भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए खेती करने वाली कम्युनिटी का मेंबर बनाना चाहिए जो सामाजिक नज़रिए से सही हों। इन मामलों में सुपरविज़न और आर्बिट्रेशन सरकार का काम होगा। अच्छे मज़दूरों को खेत के मालिक का दर्जा मिलना मुमकिन बनाना होगा। जैसे ही खेती के आम हालात सुधरेंगे, खेत मज़दूरों के रहने के हालात और मज़दूरी में ज़रूरी सुधार होगा। जब ये हालात बेहतर होंगे, तो ज़मीन पर बाहरी मज़दूरों को काम पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और भविष्य में इस रिवाज़ पर रोक लगा दी जाएगी।

4. किसान वर्ग के राष्ट्रीय महत्व के लिए ज़रूरी है कि राज्य खेती में टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा दे। (बच्चों के लिए स्कूल, खेती के लिए हाई स्कूल, ऐसे युवाओं के लिए बहुत अच्छी शर्तों पर जिनमें टैलेंट है लेकिन साधन नहीं हैं।)

5. प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़ेशन किसान वर्ग को ज़रूरी सारी मदद नहीं दे सकते; सिर्फ़ जर्मन आज़ादी के लिए NSDAP का पॉलिटिकल मूवमेंट ही ऐसा कर सकता है।

देश की आबादी गरीब है क्योंकि पूरा जर्मन देश गरीब है। यह सोचना गलत है कि मज़दूरों का एक अकेला वर्ग पूरे जर्मन समुदाय की किस्मत में हिस्सा लेने से बच सकता है, — और शहर के लोगों और गांव के लोगों के बीच जलन पैदा करना एक गुनाह है, जो अच्छे या बुरे के लिए एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में आर्थिक मदद से कोई पक्का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकल गुलामी ही हमारे लोगों की गरीबी की जड़ है, और सिर्फ़ पॉलिटिकल तरीके ही इसे दूर कर सकते हैं।

पुरानी राजनीतिक पार्टियां, जो देश की गुलामी के लिए ज़िम्मेदार थीं और हैं,
आज़ादी की राह पर लीडर नहीं हो सकते।

हमारे आने वाले देश में प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के सामने ज़रूरी आर्थिक काम हैं; वे अभी भी उस दिशा में बहुत तैयारी का काम कर सकते हैं; लेकिन आज़ादी की राजनीतिक लड़ाई के लिए, जो एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखेगी, वे सही नहीं हैं; क्योंकि वह लड़ाई किसी एक प्रोफेशन के नज़रिए से नहीं, बल्कि पूरे देश के नज़रिए से लड़नी होगी।

वह आंदोलन जो आज़ादी के लिए राजनीतिक संघर्ष को आखिर तक ले जाएगा
क्या NSDAP

(हस्ताक्षर) एडॉल्फ हिटलर



भूमि संपत्ति के स्वामित्व पर NSDAP की नीति

गॉटफ्रीड फेडर का जवाब

25 जनवरी, 1930 के ड्यूश टैग्सजेइटुंग (No. 47) में ब्रैंडेनबर्ग लैंडबंड के नेताओं के पूछे गए कई सवाल छापे गए थे। उनका मुख्य मकसद ज़मीन के प्राइवेट मालिकाना हक, विरासत, क्रेडिट बढ़ाने, टैरिफ, कीमत रेगुलेशन, प्रॉफिट-शेयरिंग, और आम सामाजिक-राजनीतिक और चुनाव-रणनीति से जुड़े सवालों के प्रति NSDAP के रवैये की परिभाषा जानना था।

मैं।

पार्टी प्रोग्राम के पॉइंट 17 के बाद में किसी भी तरह के मनमाने मतलब को लेकर चिंता को कम करने के लिए, पहला सवाल इन शब्दों में पूछा गया: "क्या NSDAP यह गारंटी देने के लिए तैयार है कि वह इसके खिलाफ़ नहीं जाएगी

ज़मीन का मालिकाना हक।"

उत्तर: नेशनल सोशलिज्म प्राइवेट ओनरशिप को एक प्रिंसिपल के तौर पर पहचानता है, और इसे राज्य संरक्षण में।

यह देश की आर्थिक ज़िंदगी में छोटे और बड़े सभी बिज़नेस का एक अच्छा मेल बनाए रखने की कोशिश करेगा।

पूरे प्रोग्राम की भावना साफ़ तौर पर यह साबित करती है कि नेशनल सोशलिज़्म, मार्क्सवाद का पक्का और लगातार विरोधी होने के नाते, आम कब्ज़े के उसके खतरनाक मुख्य सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करता है, और एक स्थायी खेती करने वाले वर्ग को नेशनल स्टेट के लिए सबसे अच्छी और पक्की नींव मानता है।

लेकिन बड़े कैपिटलिस्टों का पक्का विरोधी होने के नाते, जिनका मकसद खेती-बाड़ी की सारी वैल्यूज़ अपने लिए इकट्ठा करना और टैक्स और लोन पर इंटरेस्ट लगाकर किसानों को बेदखल करना है, नेशनल सोशलिज़्म बड़े बिज़नेस के हितों के हमले से किसानों की सरकारी सुरक्षा की मांग करता है।

हमें किसानों का एक मज़बूत, हेल्दी ग्रुप चाहिए, जो ब्याज की गुलामी और टैक्स की तानाशाही से आज़ाद हो।

द्वितीय.

दूसरा सवाल मुझसे पर्सनली पूछा गया था, क्योंकि मुझे हिटलर ने अपॉइंट किया था। 'प्रोग्राम से जुड़े सभी सवालों का आखिरी फैसला करने वाला'।

"संपत्ति की विरासत के प्रति राष्ट्रीय समाजवाद का रवैया क्या है, और उत्तराधिकार के कर्तव्य?"

जवाब: क्योंकि यह राष्ट्रीय विचार का मुख्य आधार है, इसलिए मालिकाना हक की निरंतरता, यानी उस ज़मीन की विरासत जिसे किसी व्यक्ति के पुरखों ने वापस लिया और खेती की, एक स्वाभाविक नतीजा है। इसलिए नेशनल सोशलिज़्म विरासत के सिद्धांत को मान्यता देता है, जैसा कि यह ज़मीन के मालिकाना हक के सिद्धांत को मानता है।

अगर प्रॉपर्टी दूर के रिश्तेदारों को जाती है तो नेशनल सोशलिस्ट स्टेट एक स्पेशल टैक्स लगाएगा, लेकिन पास के रिश्तेदारों के मामले में यह उस समय के रेट पर लगाया जाएगा।

तृतीय.

यह सवाल इस चिंता के कारण पूछा गया था - जो बिल्कुल बेबुनियाद थी - कि संभावित ज़मीन की सिक्योरिटी पर प्राइवेट कैपिटलिस्ट से लोन लेने पर रोक लगाने के नतीजे।

जवाब: एक राज्य, जो खेती की ज़मीन को कर्ज़ से आज़ाद करना चाहता है, और किसानों को प्रोफेशनल फाइनेंसरों के चंगुल से बचाना चाहता है — क्योंकि यहूदियों ने बहुत से किसानों को उनके घरों से निकाल दिया है — एक राज्य, जो कैपिटलिज़्म की पैसे की मोनोपॉली को खत्म करना चाहता है और ब्याज की गुलामी को खत्म करना चाहता है, वह ज़रूरी क्रेडिट रोकेगा नहीं और न ही बहुत ज़्यादा ब्याज लेगा; इसके उलट, नेशनल सोशलिज़्म खेती की पूरी मदद करने का इरादा रखता है।

चतुर्थ.

"ब्याज की गुलामी को खत्म करना।" बिना कमाई की कमाई को खत्म करना। "क्या है बचाई गई या विरासत में मिली पूंजी के प्रति नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का रवैया क्या है?

उत्तर: क्या आज किसी किसान को ब्याज की मांग से 'बिना कमाई' मिली है, या क्या कोई ज़मीन मालिक अपने किराए से बचाए गए पैसे पर गुज़ारा कर सकता है?

इसका मतलब है कि कुछ ज़मीन मालिकों में चिंता है जिनके पास अभी भी थोड़ी पूंजी बची है, या फिर वे नेशनल सोशलिस्ट प्रोग्राम की सबसे ज़रूरी मांग को जानबूझकर गलत समझ रहे हैं या उसे नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

ध्यान दें, हमारा मतलब सचमुच "ब्याज की गुलामी को तोड़ना" है। कोई भी सेविंग्स या मॉर्गेज या सरकारी लोन से मिलने वाले छोटे ब्याज को ब्याज की गुलामी नहीं कहेगा। हमारा मतलब है कि जब जानबूझकर महंगाई ने हमारी सारी सेविंग्स छीन ली हों, और किसान को नए मॉर्गेज और शॉर्ट-टर्म क्रेडिट पर ऐसी दरों पर ब्याज देना पड़े जो उसे बर्बाद कर दें।

जो लोग कैपिटलिज़्म के मौजूदा सिस्टम से चिपके रहने के पक्ष में हैं, वे किसानों के असली हितों के खिलाफ हैं, और बैंकों और उनके एजेंटों को खेती पर कब्ज़ा करने की इजाज़त देने के पक्ष में हैं। बाकी के लिए मैं पढ़ने वालों को अपने पैम्फलेट 'डेर स्टैट औफ नेशनलर अंड सोज़ियालर ग्रंडलेज' और 'दास प्रोग्राम डेर NSDAP' (द जर्मन स्टेट ऑन द नेशनल सोशलिस्ट फाउंडेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ़ द NSDAP) पढ़ने के लिए कहूंगा।

वी

टैक्स के बारे में हमारी पॉलिसी साफ़ और लगातार कहती है: कंज्यूमर को टैक्स से आज़ाद करना इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ से, और प्रोड्यूसर को उन टैक्स से जो उसके बिज़नेस को रोकते हैं।

"क्या पार्टी का इरादा इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का है?"

उत्तर: लैंडबंड को पता होना चाहिए कि राइखस्टाग में नेशनल सोशलिस्ट वोट पूरी तरह से खेती की उपज पर सुरक्षा ड्यूटी के पक्ष में गया था, जो उसके सिद्धांत — शहर और गांव में देश के काम की सुरक्षा — के अनुसार था।

छठी.

प्रॉफ़िट-शेयरिंग का सवाल। इस बड़े और मुश्किल विषय पर यहाँ बात करना नामुमकिन है। अपने वीकली जर्नल, डाई फ़्लैम में, मैंने कई आर्टिकल में हमारे नज़रिए के बारे में डिटेल में बताया है।

डॉयचे टैग्सजेइटुंग का आर्टिकल गुमराह करने वाला है, क्योंकि इसमें जिन वाक्यों को कोट किया गया है, उन्हें कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया गया है। मेरा पर्सनली मानना है कि कैपिटलिस्ट और मार्क्सिस्ट सोच के आम मतलब में प्रॉफिट-शेयरिंग सही सॉल्यूशन नहीं है। इस सब्जेक्ट पर हमारा प्रोग्राम फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स के बारे में है, और खेती से जुड़े पैम्फलेट में इस सवाल को क्लियर करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है।

सातवीं.

वृद्धावस्था बीमा लाभ का विस्तार।

“इस काम के लिए फंड कैसे जुटाने का प्रस्ताव है?”

जवाब: अभी ओल्ड एज इंश्योरेंस का इंतज़ाम है, लेकिन कई मामलों में यह काफ़ी नहीं है, और इसे गरीबी माना जाता है। एक बार जब टैक्स का बोझ हट जाएगा, और जो लोग अभी बेरोज़गार हैं लेकिन काम कर सकते हैं, वे आर्थिक रूप से ठीक हो जाएंगे, तो जो लोग पहले काम नहीं कर पाए हैं, उन्हें ओल्ड एज बेनिफिट देने के लिए काफ़ी तरीके होंगे।

सातवीं, नौवीं, दसवीं।

ये सवाल सिर्फ़ पार्टी की टैक्टिक्स से जुड़े हैं, किसी सिद्धांत से नहीं।

जर्मनी में दुख लाने वाले गठबंधन के खिलाफ होने के नाते, हमें स्वाभाविक रूप से कभी-कभी कम्युनिस्टों के साथ वोट करना पड़ता है (हालांकि पूरी दुनिया हमें उनसे अलग करती है), ठीक वैसे ही जैसे जर्मन नेशनल और क्रिश्चियन नेशनल फार्मर्स करते हैं। हम किसी को यह तय करने नहीं देते कि हमें अपने समर्थक कहां से मिलेंगे, बल्कि हम उन सभी की ओर देखते हैं – मज़दूरों, पूंजीपतियों और किसानों की ओर – जिनके शरीर में एक अच्छा जर्मन दिल है और जो अच्छे इरादों वाले लोग हैं, और पार्लियामेंट्री गलत सरकार और (शांति संधियों को) पूरा करने की घटिया पॉलिसी का अंत देखना चाहते हैं। हम यह नहीं मानते कि दूसरी पार्टियों के साथ 'सोशल कम्युनिकेशन' जर्मन देश को मार्क्सवाद और पार्लियामेंटेरियनिज़्म से आज़ाद करने का सही तरीका है, – क्योंकि इससे पॉलिटिकल बारगेनिंग होती है। तानाशाही कार्रवाई और ताकत का पक्का इस्तेमाल ही जर्मनी को कीचड़ से बाहर निकाल सकता है।

देश को अच्छी बातें नहीं, बल्कि ज़ोर चाहिए; मोलभाव नहीं, बल्कि हमारे गरीब, दबे-कुचले देश के लिए ठोस काम चाहिए।

ऊपर बताई गई बातों का पूरा और साफ़ ब्यौरा नेशनल सोशलिस्ट कलेक्शन — Unser tağlich Brot: Basic Questions of German Agriculture; के No. 19 में दिया गया है। यह किताब हरमन श्नाइडर, एकर्सडॉर्फ, क्रेइस नामस्लाऊ ने लिखी है। इसमें खेती के मामले में नेशनल सोशलिज़्म की पूरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इसमें जर्मनी के परेशान किसान वर्ग को फिर से बसाने के लिए सोचे-समझे प्रस्ताव शामिल हैं।

डॉ. बुचनर का लिखा लेख नंबर 16, हमारी आर्थिक नीति के अर्थ और भावना पर एक बेहतरीन निबंध है।

कर्नल हिएर्ल की किताब नंबर 12 में हमारी नेशनल डिफेंस पॉलिसी के बारे में बताया गया है।

हम कुछ सवालों पर कुछ बातों के साथ अपनी बात खत्म करेंगे, जिन्हें हमारे पॉलिटिकल दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में गलत तरीके से और गलत तरीके से पेश करते हैं।

परमानेंट ऑफिशियल क्लास के प्रति हमारा नज़रिया ज़रूर काबिले तारीफ़ है। अगर हम इस क्लास के खिलाफ़ होते तो हमें प्रशिया के महान राजा के इतने बड़े फैन नहीं होना चाहिए था। जो आर्मी विदेश में थी, वही एक पवित्र, भ्रष्टाचार-रहित ऑफिशियल क्लास देश के लिए है। हमारे अधिकारियों में सम्मान और ड्यूटी एक बार फिर ज़रूरी गुण बनने चाहिए। जो अधिकारी रेड्स और ब्लैक्स के इशारे पर चलते हैं, वे आने वाले राज्य में गायब हो जाएंगे; ऐसे पार्टी के लोगों को सम्मान और ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है।

यह कहना कि नेशनल सोशलिस्ट अधिकारियों के खिलाफ हैं और उनकी सैलरी कम करने और पेंशन खत्म करने का इरादा रखते हैं, एक पॉलिटिकल झूठ जैसा है, जिसे हमारे विरोधियों के प्रेस ने फैलाया है। इसके उलट, हम देश के उन सभी लोगों को, जिन्होंने ज़िंदगी भर ईमानदारी से जर्मनी की सेवा की है, एक सम्मान वाली पेंशन देना चाहते हैं, जिससे उन्हें बुढ़ापे में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इसी तरह से सामाजिक मदद 'गरीबी' के दाग से आज़ाद होगी।

हमें पेंशन के आइडिया को इंडिपेंडेंट ट्रेड्स और हाथ से काम करने वालों तक बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस मकसद के लिए हमें फंड कैसे जुटाना है, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम हर साल विदेश में हज़ारों मिलियन और अपने बैंकिंग हाउस को और भी ज़्यादा देना बंद कर देंगे, तो उस रकम का एक छोटा सा हिस्सा ओल्ड एज पेंशन के लिए काफी होगा।

बेरोजगारी सहायता और बीमा

यह अपने आप में राज्य का मामला नहीं है कि वह राज्य के फंड से उन लोगों की मदद करे जो काम कर सकते हैं। जो लोग गुज़ारा नहीं कर सकते, उनकी मदद के मौजूदा सिस्टम के प्रति हमारा नज़रिया कभी नहीं बदला है; हमने हमेशा पार्लियामेंट में उन लोगों के लिए बेहतर हालात की मांग की है जो काम नहीं करते।

हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि यह सही स्थिति है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि मौजूदा सरकार जैसी सरकार, जिसकी बेवकूफी भरी विदेश और घरेलू पॉलिसी ने लेबर, फ़ूड प्रोडक्शन और सभी कॉमर्स को रसातल की कगार पर पहुंचा दिया है, उसकी ड्यूटी है कि वह अपनी पॉलिसी को ऐसे ही चलने दे।

जो सरकार लाखों काम करने लायक लोगों को आर्थिक दुनिया में वापस नहीं ला सकती, उसे खत्म कर देना चाहिए; इसलिए, अगर वह बेरोज़गारी की मदद की समस्या को फाइनेंशियली पूरा करने में नाकाम रहती है, तो हम बस कंधे उचका देते हैं।

डोले सिस्टम पर अलग-अलग हमले, भले ही वे इस सोशल मदद के गलत इस्तेमाल के मामलों का ज़िक्र करते हुए सही हों, हमें उस उसूल से नहीं हटा पाते जिस पर हम यकीन करते हैं। मान लीजिए कि लगभग 3,000,000 बेरोज़गारों में 2 या 300,000 बदनाम आलसी लोग हो सकते हैं जो डोले हटा दिए जाने पर तुरंत काम पर लौट आएंगे — हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कम से कम 2.5 मिलियन अच्छे वर्कर, कर्मचारी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, फोरमैन, क्लर्क, वगैरह अभी भी काम की सख्त तलाश में हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। यह हमारी पूरी तरह से गलत सरकारी पॉलिसी की नाकामी की वजह से है कि बेरोज़गारों की इस बेचारी डोले में कोई बदलाव करना नामुमकिन है।

धर्म और पादरियों पर हमले

हम बार-बार यह नहीं कह सकते कि NSDA.P. हमला करने का सपना नहीं देख रहा है।
ईसाई धर्म और उसके योग्य सेवक।

हम सेंटर और बवेरियन पीपुल्स पार्टी की भ्रष्ट करने वाली पॉलिसी पर हमला करते हैं; ये लोग "चर्च खतरे में है" चिल्लाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, सिवाय तब जब वे नास्तिक, भगवान को न मानने वाली सोशल डेमोक्रेसी के साथ मिलकर काम कर रहे हों।

ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इंसान के अपने भगवान के प्रति रिश्ते का इतना ऊंचा और पवित्र आदर्श है कि हम धर्म को राजनीतिक लड़ाई की गंदगी से गंदा होते देखना पसंद नहीं करते।

2. 25 पॉइंट्स

नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ने 25 फरवरी, 1920 को म्यूनिख के हॉफब्रूहाउस-फेस्टसाल में एक बड़ी मीटिंग में दुनिया के सामने अपने प्रोग्राम की घोषणा की।

हमारी पार्टी के संविधान के सेक्शन 2 में इस प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता बताया गया है।

कार्यक्रम

जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रोग्राम सीमित समय के लिए है, और इसमें बताए गए मकसद पूरे होने के बाद, नेताओं का कोई इरादा नहीं है कि वे नए मकसद तय करें, सिर्फ़ बनावटी तरीके से जनता की नाराज़गी बढ़ाने के लिए, और इस तरह पार्टी का बने रहना पक्का करने के लिए।

1. हम सभी जर्मनों के मिलन की मांग करते हैं ताकि दक्षिणपंथ के आधार पर एक महान जर्मनी बनाया जा सके राष्ट्रों को मिलने वाले आत्मनिर्णय के अधिकार का।
2. हम दूसरे देशों के साथ जर्मन लोगों के व्यवहार में बराबरी के अधिकार और वर्साय और सेंट जर्मेन की शांति संधियों को खत्म करने की मांग करते हैं।
3. हम अपने लोगों के भरण-पोषण और अपनी फालतू आबादी को बसाने के लिए ज़मीन और इलाका (कॉलोनी) मांगते हैं।
4. देश के सदस्यों के अलावा कोई भी देश का नागरिक नहीं हो सकता। जर्मन खून वाले लोगों के अलावा कोई भी देश का सदस्य नहीं हो सकता, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसलिए, कोई भी यहूदी देश का सदस्य नहीं हो सकता।
5. कोई भी व्यक्ति जो राज्य का नागरिक नहीं है, जर्मनी में केवल मेहमान के रूप में रह सकता है और उसे विदेशी कानूनों के अधीन माना जाएगा।
6. राज्य की सरकार और कानून पर वोट देने का अधिकार सिर्फ़ राज्य के नागरिक को ही मिलेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी सरकारी नियुक्तियाँ, चाहे वे किसी भी तरह की हों, चाहे वे राइख में हों, देश में हों, या छोटे इलाकों में हों, सिर्फ़ राज्य के नागरिकों को ही दी जाएँ। हम संसद के इस खराब रिवाज का विरोध करते हैं जिसमें सिर्फ़ पार्टी के आधार पर और चरित्र या काबिलियत देखे बिना पद भरे जाते हैं।
7. हम मांग करते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के उद्योग और रोज़ी-रोटी को बढ़ावा देना अपना पहला कर्तव्य बनाए। अगर राज्य की पूरी आबादी का भरण-पोषण करना मुमकिन नहीं है, तो विदेशी नागरिकों (राज्य के गैर-नागरिकों) को राइख से बाहर रखा जाना चाहिए।
8. सभी गैर-जर्मन इमिग्रेशन को रोका जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि 2 अगस्त, 1914 के बाद जर्मनी में आए सभी गैर-जर्मन लोगों को तुरंत राइख से निकल जाना चाहिए।
9. राज्य के सभी नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान होंगे।
10. देश के हर नागरिक का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने मन या शरीर से काम करे। किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ पूरे समाज के हितों से टकरा नहीं सकतीं, लेकिन समुदाय के दायरे में आगे बढ़ना चाहिए और आम भलाई के लिए होना चाहिए।

इसलिए हम मांग करते हैं:

11. काम से अर्जित न होने वाली आय को समाप्त करना।

ब्याज की गुलामी का खात्मा।

12. हर युद्ध में देश से मांगी जाने वाली जान और माल की भारी कुर्बानी को देखते हुए, युद्ध की वजह से हुई निजी अमीरी को देश के खिलाफ जुर्म माना जाना चाहिए।

इसलिए हम युद्ध से मिली सभी जीत को बेरहमी से ज़ब्त करने की मांग करते हैं।

13. हम उन सभी बिज़नेस के नेशनलाइज़ेशन की मांग करते हैं जिन्हें अब तक कंपनियों (ट्रस्ट) में बदल दिया गया है।

14. हम मांग करते हैं कि होलसेल व्यापार से होने वाले मुनाफ़े को आपस में बाँटा जाए।

15. हम बुढ़ापे के लिए बड़े पैमाने पर विकास की मांग करते हैं।

16. हम एक हेल्दी मिडिल क्लास बनाने और उसे बनाए रखने, होलसेल बिज़नेस की जगहों का तुरंत कम्युनिटी में बंटवारा करने, और उन्हें छोटे व्यापारियों को सस्ते रेट पर लीज़ पर देने की मांग करते हैं, और यह भी कि राज्य, ज़िला अधिकारियों और छोटे इलाकों के सभी छोटे सप्लायरों का बहुत ध्यान रखा जाए।

17. हम अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से ज़मीन सुधार की मांग करते हैं, साथ ही, सामुदायिक कामों के लिए बिना मुआवज़े के ज़मीन ज़ब्त करने का कानून पास करने, ज़मीन के लोन पर ब्याज खत्म करने और ज़मीन पर सभी तरह की सट्टेबाजी रोकने की मांग करते हैं ।

18. हम उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं जिनकी गतिविधियां आम हितों के लिए नुकसानदायक हैं। देश के खिलाफ घिनौने अपराधियों, सूदखोरों, मुनाफाखोरों, वगैरह को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।

19. हम मांग करते हैं कि रोमन कानून, जो भौतिकवादी दुनिया की सेवा करता है, उसे पूरे जर्मनी के लिए एक कानूनी सिस्टम से बदल दिया जाए।

20. हर काबिल और मेहनती जर्मन के लिए हायर एजुकेशन का मौका खोलने और इस तरह तरक्की पाने के मकसद से, सरकार को हमारे नेशनल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से फिर से बनाने पर विचार करना चाहिए। सभी एजुकेशनल जगहों के करिकुलम को प्रैक्टिकल ज़िंदगी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए।

स्टेट के आइडिया (स्टेट सोशियोलॉजी) को समझना स्कूल का मकसद होना चाहिए, जिसकी शुरुआत स्टूडेंट में समझदारी की पहली सुबह से होनी चाहिए। हम गरीब माता-पिता के होनहार बच्चों के विकास की मांग करते हैं, चाहे उनका क्लास या काम कुछ भी हो, स्टेट के खर्च पर।

21. सरकार को देश में हेल्थ का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए माताओं और बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए, बाल मजदूरी पर रोक लगानी चाहिए, कानून में बताए गए ज़रूरी जिमनास्टिक और खेलों से शरीर की क्षमता बढ़ानी चाहिए, और युवाओं के शारीरिक विकास में लगे क्लबों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए।

22. हम पेड आर्मी को खत्म करके एक नेशनल आर्मी बनाने की मांग करते हैं।

23. हम जानबूझकर राजनीतिक झूठ और प्रेस में इसके फैलाव के खिलाफ कानूनी लड़ाई की मांग करते हैं। एक जर्मन नेशनल प्रेस बनाने में मदद के लिए हम ये मांग करते हैं:

---

[1] 13 अप्रैल , 1928 को एडॉल्फ हिटलर ने यह घोषणा की: NSDAP के प्रोग्राम के पॉइंट 17 के बारे में हमारे विरोधियों की गलत व्याख्या का जवाब देना ज़रूरी है।

क्योंकि NSDAP प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल को मानता है, इसलिए यह साफ़ है कि 'बिना मुआवज़े के ज़ब्त करना' का मतलब सिर्फ़ उन कानूनी शक्तियों से है जिनसे, अगर ज़रूरी हो, गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई ज़मीन को ज़ब्त किया जा सकता है, या जिसे देश की भलाई के हिसाब से मैनेज नहीं किया जा रहा है। यह देश की भलाई के हिसाब से है। यह सबसे पहले उन यहूदी कंपनियों के खिलाफ है जो ज़मीन में सट्टा लगाती हैं।

म्यूनिख, 13 अप्रैल, 1928। (हस्ताक्षर) एडॉल्फ हिटलर

क. सभी अखबारों के संपादक और उनके सहायक, जो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं भाषा, राष्ट्र के सदस्य होने चाहिए;

b. गैर-जर्मन अखबारों के छपने से पहले राज्य से खास इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जर्मन भाषा में छपें;

c. कि गैर-जर्मन लोगों को कानून के तहत जर्मन अखबारों में पैसे से हिस्सा लेने या उन पर असर डालने से रोका जाएगा, और कानून तोड़ने की सज़ा ऐसे किसी भी अखबार को दबाना और उसमें शामिल गैर-जर्मन को तुरंत देश निकाला देना होगा। ऐसे अखबार छापने पर रोक होनी चाहिए जो देश की भलाई के लिए काम न करें। हम कला और साहित्य में ऐसी सभी आदतों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं जो एक देश के तौर पर हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ सकती हैं, और उन संस्थाओं को दबाना जो ऊपर बताई गई ज़रूरतों के खिलाफ हैं।

24. हम राज्य में सभी धर्मों के लिए आज़ादी की मांग करते हैं, बशर्ते वे इसके लिए खतरा न हों और जर्मन जाति की नैतिक भावनाओं के खिलाफ न हों।

पार्टी, वैसे तो पॉजिटिव ईसाई धर्म के लिए खड़ी है, लेकिन पंथ के मामले में खुद को किसी खास धर्म से नहीं बांधती। यह हमारे अंदर और बाहर यहूदी-भौतिकवादी भावना का मुकाबला करती है, और यह मानती है कि हमारा देश सिर्फ़ इस सिद्धांत पर अंदर से ही परमानेंट हेल्थ पा सकता है:

खुद से पहले आम हित।

25. इन सभी बातों को पूरा करने के लिए हम राज्य की एक मज़बूत सेंट्रल पावर बनाने की मांग करते हैं। पूरे राइख और उसके संगठन पर राजनीतिक रूप से सेंट्रलाइज़्ड पार्लियामेंट का बिना सवाल वाला अधिकार; और कन्फेडरेशन के अलग-अलग राज्यों में राइख द्वारा बनाए गए आम कानूनों को लागू करने के मकसद से क्लास और कामों के लिए चैंबर बनाना।

पार्टी के नेता सीधे आगे बढ़ने की कसम खाते हैं - अगर ज़रूरी हुआ तो अपनी कुर्बानी भी देंगे जीवन - पूर्वोक्त बिंदुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में।

म्यूनिख, 24 फरवरी, 1920.

卐 卐 卐 卐 卐

22 मई, 1920 को सदस्यों की जनरल मीटिंग में पूरी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि "यह प्रोग्राम बदला नहीं जा सकता"। इसका मतलब यह नहीं है कि हर शब्द में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, न ही यह कि प्रोग्राम को और बेहतर बनाने या डेवलप करने के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, उस पर रोक होगी, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें शामिल सिद्धांतों और मुख्य विचारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

इसमें सुविधा की दृष्टि से कोई छेड़छाड़ या तोड़-मरोड़ नहीं हो सकती, कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण – और आज की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की व्यवस्था के लिए बहुत अवांछित – बिंदुओं में कोई छिपा हुआ हस्तक्षेप नहीं हो सकता, भावनाओं का कोई विचलन नहीं हो सकता।

एडॉल्फ हिटलर ने इसके दो मुख्य पॉइंट लेड वाले टाइप में छापे: खुद से पहले कॉमन इंटरेस्ट — प्रोग्राम की भावना। इंटरेस्ट की गुलामी को खत्म करना — नेशनल सोशलिज्म का मूल। एक बार ये दो पॉइंट हासिल हो जाने पर, इसका मतलब है कि 'सच्चे स्टेट' में समाज के आने वाले यूनिवर्सलिस्ट ऑर्डर की जीत, आज के समाज के इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी के भ्रष्ट करने वाले असर के तहत स्टेट, नेशन और इकोनॉमिक्स के अलग-अलग होने पर।

आज का नकली राज्य, जो मज़दूर वर्ग पर ज़ुल्म करता है और बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंज के सट्टेबाज़ों के नकली मुनाफ़े को बचाता है, बेपरवाह निजी अमीरी और सबसे कम राजनीतिक मुनाफ़ा कमाने का मैदान है; यह अपने लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, और एकता का कोई ऊँचा नैतिक बंधन नहीं देता। पैसे की ताकत, जो सभी ताकतों में सबसे बेरहम है, पूरा कंट्रोल रखती है, और राज्य, देश, समाज, नैतिकता, नाटक, साहित्य, और नैतिकता के सभी मामलों पर भ्रष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला असर डालती है, जिनका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है।

बेशक इस बड़े संघर्ष में कोई हिचकिचाहट या पीछे हटना नहीं चाहिए; या तो जीत होगी या हार।

उसी बेसिक प्रिंसिपल का थोड़ा अलग नज़रिया, जो मैंने अपनी किताब, डेर ड्यूश स्टैट औफ नेशनलर अंड सोज़ियालर ग्रंडलागे, (F. Eher Nachf.) में दिया है, कोई बदलाव नहीं है, बल्कि पॉइंट्स की एक सीरीज़ है जो ज़िंदगी के अलग-अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल पहलुओं के हिसाब से एक साथ जुड़े हुए हैं, इकट्ठा और अरेंज किए गए हैं।

अगर मेरे उन विचारों (पेज 22 देखें) को 25 पॉइंट्स से अलग या उनके खिलाफ देखा जा सकता, तो हिटलर ने अपनी छोटी सी प्रस्तावना में मेरी किताब को कभी भी "हमारे आंदोलन का धर्मसिद्धांत" नहीं कहा होता। कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी विचार चुनने के लिए आज़ाद है, लेकिन अगर वह उनकी तुलना करे तो उसे वे एक-दूसरे से अलग नहीं लगेंगे।

हमारे प्रोग्राम में बताई गई हमारी मांगों पर भविष्य में पूरी सहमति पक्की करने के लिए, और आंदोलन को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए, —
प्रोफेशनल और शौकिया क्रिटिक्स, बड़बड़ाने वालों और जानकारों के 'सुधार के सुझावों' के बाद, एडॉल्फ हिटलर ने 11 फरवरी, 1926 को बैम्बर्ग में हुई सभी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनाइज़र्स की एक कॉन्फ्रेंस में, प्रोग्राम से जुड़े सभी सवालों के लिए ऑफिशियली गॉटफ्रीड फेडर को फाइनल जज अपॉइंट किया।

3. बेसिक आइडिया

इस पैम्फलेट में हमारा मकसद राज्य की नेशनल सोशलिस्ट सोच के ज़रूरी सिद्धांतों को जितना हो सके कम समय में और आसानी से बताना है। हम बाद में उस सोच के सोशियोलॉजिकल, थ्योरेटिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे।

हम दूसरी पॉलिटिकल इच्छाओं या अलग-अलग पार्टियों और एसोसिएशन में उन्हें रिप्रेजेंट करने वालों के बारे में बताने की कोशिश नहीं करेंगे — यह अपने आप में एक काम है — लेकिन हम यहाँ सिर्फ़ अपनी मांगों के ज़रूरी पॉइंट्स बताएँगे।

दुनिया अव्यवस्था से पैदा हुई, अव्यवस्था से व्यवस्था, और बहुत ज़्यादा उलझन से संगठन।

आज दुनिया में हर तरफ अफ़रा-तफ़री फैली हुई है — कन्फ़्यूज़न, लड़ाई, नफ़रत, ज़ुल्म, लूट, बेरहमी, मतलबीपन। भाई-भाई अलग हो गए हैं। एक ही देश के लोग एक-दूसरे पर हमला करते हैं, एक आदमी को सिर्फ़ इसलिए चाकू मार देते हैं क्योंकि उसने स्वास्तिक क्रॉस पहना था। वे सब एक जैसे बोझ, एक जैसी मुश्किलों से गुज़र रहे हैं; फिर भी पिछले कुछ महीनों में किसने सुना है कि मार्क्सवादी मज़दूरों ने अपने मालिकों, या अपनी पार्टी के नेताओं, या किसी बैंकर और स्टॉक एक्सचेंज के खून चूसने वालों, या किसी थोक मुनाफ़ा कमाने वाले पर हमला किया हो या उन्हें मार डाला हो? अफ़रा-तफ़री की बलि सिर्फ़ अच्छे, सीधे-सादे मज़दूर को ही दी जाती है। मार्क्सवादी अपना दिमाग खो चुके हैं और अपनी ही क्लास के लुटेरों के साथ शामिल होने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, जबकि वे उन लोगों के ख़िलाफ़ बुरी तरह से पेश आते हैं जो उन्हें बचाने के लिए तैयार खड़े हैं।

नेशनलिस्ट और दूसरी पार्टियां सरकार में हैं या उन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने उनके नेशनल आइडियल्स को खत्म कर दिया है और इस तरह अपनी इज्ज़त और कैरेक्टर दोनों खो दिए हैं। डिफेंस एसोसिएशन 'स्टेट' में घुसने की कोशिश कर रहे हैं — स्टेट ऑफ़ सेवरिंग और ग्रेज़िंस्की, — शांतिवादियों, इंटरनेशनलिस्ट और यहूदियों में, जिनके साथ उन्हें लगता है कि वे सरकार चला सकते हैं।

वे पागल हो गए हैं! तथाकथित रेच्त्स्क्राइस यह नहीं देख पा रहे हैं कि चील और सांप, भेड़िये और मेमने, इंसान और हैजा का कीड़ा, एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। वे अव्यवस्था, राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बेकारपन को 'ऑर्डर' दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन वे नेशनल सोशलिस्टों, उन 'कट्टरपंथियों' के खिलाफ हो जाते हैं, इस पागलपन भरे डर से कि वे उन्हें उनके कुछ पुराने खास अधिकार और पद छीन सकते हैं, — यह भूल जाते हैं कि उन्होंने उन्हीं लोगों के ज़रिए सब कुछ खो दिया है जिनसे वे अब 'राजनीतिक रोटियों और मछलियों में हिस्सा' मांग रहे हैं।

इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे बड़े हों या छोटे, उनका बस एक ही मकसद होता है – प्रॉफिट –, बस एक ही चाहत – क्रेडिट –, बस एक ही विरोध – टैक्सेशन के खिलाफ; वे बस एक ही चीज़ से डरते हैं और उसकी इज्ज़त करते हैं – बैंक; वे इंटरेस्ट की गुलामी को खत्म करने की नेशनल सोशलिस्ट मांग पर कंधे उचका देते हैं।

उनकी एक ही इच्छा है 'कर्ज़ लेना'। बैंकों से बिना किसी परेशानी या मेहनत के लोन से जो बड़ी रकम मिलती है, उसे वे पूरी तरह से सही मानते हैं। उन्होंने किफ़ायती पार्टियां ढूंढीं और डावेस कानूनों के लिए वोट किया, जो भारी टैक्स का मुख्य कारण हैं।

बिज़नेस से ऑनर चला गया है, जो पूरी तरह से ताकतवर कंपनियों के हाथ में है। प्रोड्यूसर अपने सबसे बड़े दुश्मन, हाई फाइनेंस के आगे सरेंडर कर चुके हैं। फैक्ट्रियों और ऑफिस में मालिक, जो गहरे कर्ज में डूबे हैं, उन्हें बहुत कम पैसे में ही खुश रहना पड़ता है, क्योंकि मेहनत का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में इंपर्सनल मनी पावर की जेब में चला जाता है।

कंट्रोल में बैठे लोग इस अफ़रा-तफ़री को रोकने में पूरी तरह नाकाम हैं। ऊपर से टैक्स और ब्याज़ के पेमेंट से दबे हुए, नीचे से डूबे हुए लोगों की शिकायतों से परेशान।

मज़दूरों ने खुद को आँख बंद करके कैपिटलिज़्म के कंट्रोल वाले स्टेट से बांध लिया है, जबकि मौजूदा अफ़रा-तफ़री के शोषक उन्हें सिर्फ़ मेहनतकश लोगों पर गुलाम बनाने के लिए सत्ता में बने रहने दे रहे हैं। उनका गुस्सा मार्क्सवाद के पागलपन के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हुक्ड क्रॉस पहनने वालों के ख़िलाफ़ है। वे भूल जाते हैं कि हमने और सिर्फ़ हमने ही जर्मन इकॉनमी की त्रासदी को आते देखा, समझा और दिखाया कि कैसे, अगर समय रहते जर्मनी को संभाला जाए, तो वह अपनी ताकत से बैलेंस वापस ला सकता है।

हर तरह के नाम वाले एसोसिएशन, जो अपने बेसिक आइडिया में सही हैं — पब्लिक लाइफ की मौजूदा उथल-पुथल में बेकार हैं, वे ऑर्डर लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। यह सब बेकार है, क्योंकि वे एक बड़े सोशल ग्रुप के तौर पर देश के टच में नहीं हैं। सभी का मकसद सिर्फ़ अपनी जाति के लिए छोटे-मोटे फायदे छीनना है; बिना किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रिंसिपल के, वे बारी-बारी से हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होते हैं। वे मौजूदा सिस्टम के आगे झुकते हैं और तथाकथित सुप्रीम अथॉरिटी के आगे झुकते हैं।

इनसे जर्मन देश को अनगिनत ऑर्गनाइज़र, डायरेक्टर और वायर-पुलर को पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन इनमें से किसी ने भी ज़रा भी फ़ायदा नहीं किया। महंगाई — एक क्रिमिनल तरीका — ने सभी क्लास, किफ़ायती लोगों, एसोसिएशन के सदस्यों, कारीगरों से उनकी बचत छीन ली।
कोई नया टैक्स, सीधे ग्रीन टेबल से, सालों की मेहनत पर टिकी उम्मीदों को तोड़ देता है। सरकार के सामने अनगिनत मीटिंग, चर्चा, डेप्युटेशन के बाद मिला फ़ायदा, अक्सर रहने के खर्च में बढ़ोतरी, कीमतों में बढ़ोतरी या गिरावट से खत्म हो जाता है।

अफ़रा-तफ़री और पागलपन! किसान ऐसे ज़ुल्म में कैसे जी सकता है? मज़दूर कैसे खरीद सकता है जब कीमतें हर समय बढ़ रही हैं? जब गुज़ारे का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तो अफ़सरों और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का क्या फ़ायदा? वे भरोसे के साथ सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं, वही सरकार जिसने सारी गरीबी और ज़ुल्म किया है, जो 'राष्ट्रपिता' नहीं, बल्कि पैसे की तानाशाही का तानाशाह और टैक्स वसूलने वाला है।

इसलिए वे बार-बार पुरानी पार्टियों की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं कि उन्हें राजनीति की परवाह नहीं है और वे उन्हीं के हैं।
किसी भी पार्टी को नहीं, और साथ ही पार्टी के बुरे झगड़े पहले की तरह चलते रहें।

नेशनल सोशलिज़्म ने अपने सामने जो बड़ा काम रखा है, वह है पुराने ढर्रे को वापस लाना, अव्यवस्था को दूर करना, पुरानी व्यवस्था से भटक चुकी दुनिया को फिर से ठीक करना, और उस व्यवस्था की रक्षा करना - सबसे ऊँचे प्लेटोनिक अर्थ में।

यहां यह बताना ज़रूरी है कि हम 'ऑर्डर' को न तो पुलिस वाले राज्य के दिखने वाले ऑर्डर को मानते हैं, न ही रिवाज़ से पवित्र और कानून से इजाज़त पैसे की लूट को, और न ही सिंडिकेट, ट्रस्ट और देश के साथ गद्दारी के दूसरे संगठित तरीकों की साज़िशों को, चाहे वे कितने भी अच्छे से 'काम' करें। लुटेरों के एक ग्रुप में भी 'ऑर्डर' होता है, जेलों के अपने 'रेगुलेशन' होते हैं। लेकिन देश में, एक पूरे के तौर पर देखें तो, हमारी पब्लिक ज़िंदगी का हर पहलू दर्द, गुलामी, दबाव, धोखेबाज़ी दिखाता है, और सबके खिलाफ़ सबके संघर्ष की एक अस्त-व्यस्त तस्वीर पेश करता है।

सरकार जनता के विरुद्ध, पार्टी पार्टी के विरुद्ध, साथ ही सबसे अस्वाभाविक गठबंधन करते हुए, मालिक कर्मचारी के विरुद्ध, व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के विरुद्ध, जमींदार किरायेदार के विरुद्ध, मजदूर किसान के विरुद्ध, अधिकारी जनता के विरुद्ध, मजदूर जनता के विरुद्ध
'पूंजीपति', चर्च बनाम सरकार, हर कोई आँख बंद करके अपने खास दुश्मन के पीछे पड़ा रहता है और सिर्फ़ अपने मतलब, अपनी तरक्की और अपने पैसे के बारे में सोचता है। कोई यह नहीं सोचता कि दूसरे को जीने का अधिकार है, या अपने मतलब के लिए किसी और को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई अपने पड़ोसियों की भलाई, या समाज के प्रति अपने बड़े फ़र्ज़ के बारे में नहीं सोचता। अपने फ़ायदे के पीछे भागना। अपने पड़ोसी को कोहनी मारकर ऊपर चढ़ाओ, अगर तुम्हें इससे कुछ मिलना है तो उसके शरीर को रौंदो — इसकी क्या परवाह? यही तो आजकल का बिज़नेस है।

हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। हम दुनिया में एक बड़े बदलाव के बीच में हैं, और यह आम बात है कि आम लोग, बेचारे भटकते हुए लोग, इस अफ़रा-तफ़री से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखते, राहत की तलाश में रहते हैं।

आत्महत्या करो, या सोचो कि दुनिया खत्म होने वाली है और सोने के बछड़े की दौड़ में शामिल हो जाओ और बिना सोचे-समझे भंवर में कूद जाओ। "जब तक हो सके मज़े करो — हमारे बाद बाढ़ आएगी।"

किसी देश के हौसले पर इतना बड़ा झटका तभी लग सकता है और समझा जा सकता है जब समाज की पूरी बौद्धिक नींव हिल जाए या फिर झूठी हो, — और असल में हम देखते हैं कि मार्क्सवाद, कैपिटलिज़्म, और हमारी पब्लिक लाइफ़ के नेता सभी एक ही भगवान की पूजा करते हैं —

इंडिविजुअलिज़्म। पर्सनल इंटरेस्ट ही एकमात्र इंसेंटिव है, — ज़िंदगी में अपने ही छोटे वर्ग के लिए फ़ायदा पाना।

बाद में, इस सीरीज़ में एक और योगदान आएगा, जो ध्यान से समर्पित होगा।
समाज के निर्माण का सोशियोलॉजिकल अध्ययन।

यहां मैं बस थोड़ी देर में आज के स्टेट और पॉलिटिकल इकॉनमी में ऑर्गेनिक गलतियों और एक नेशनल सोशलिस्ट स्टेट के सार के बीच के अंतर की एक तुलना वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आज का सिद्धांत यह है: समाज लोगों का जोड़ है — स्टेट अपने सबसे अच्छे रूप में लोगों या एसोसिएशन का एक आसान जमावड़ा है।

हम समाज बनाने की इस थ्योरी की तुलना पत्थरों के ढेर से कर सकते हैं। इसमें असली चीज़ सिर्फ़ पत्थरों के अलग-अलग टुकड़े हैं। इसका आकार किस्मत की बात है; पत्थर ऊपर है या नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नतीजा पत्थरों के ढेर से न ज़्यादा है और न कम।

पत्थर.

इसी तरह, हमारे नेशनल सोशलिस्ट समाज के सिद्धांत और राज्य की फिलॉसफी के हिसाब से जो स्टेट है, वह घर है। मशीनी तौर पर कहें तो, घर भी कई अलग-अलग ईंटों से बना होता है — रेत, सीमेंट, जोइस्ट, खिड़कियां, दरवाजे, फर्श, वगैरह। लेकिन कोई भी देख सकता है कि एक घर, एक कमरा, एक बड़ी चीज़ है, कुछ नया और अनोखा और अपने आप में पूरा, सिर्फ़ ईंटों के एक साथ रखे जाने से कहीं ज़्यादा। कोई भी समझ सकता है कि एक घर कई अलग-अलग हिस्सों को एक साथ रखने से नहीं बनता, बल्कि इन हिस्सों को एक सोची-समझी योजना के हिसाब से जोड़ने से बनता है।

ऐसा ही एक देश के साथ होता है। जब तक अव्यवस्था को एक सोची-समझी योजना के तहत, व्यवस्थित करके आकार नहीं दिया जाता, जब तक कि हिस्सों के ढेर से एक सोची-समझी पूरी चीज़ नहीं बनाई जाती, तब तक असली राज्य सामने नहीं आ सकता। तभी हिस्से एक मकसद वाला आकार ले पाएंगे। ओथमार स्पैन, जो पहले वियना यूनिवर्सिटी के रेक्टर थे, ने अपनी किताब, डेर वाह्रे स्टैट, और अपनी किताब गेसेलशाफ्ट्सलेहरे में आज के इंडिविजुअलिस्टिक स्टेट के सोशियोलॉजिकल आधारों को बहुत अच्छे से समझाया है, जो साइंटिफिक सिद्धांतों पर बने स्टेट में यूनिवर्सल ऑर्डर के ऊंचे आदर्श के उलट है।

हम नेशनल सोशलिस्ट्स ने यह कहावत बनाई है, जिसे सभी लोग समझ सकते हैं:

व्यक्ति से पहले समुदाय।

सिर्फ़ देश के समुदाय के सदस्य के तौर पर आम लोगों के हित में काम करके ही कोई इंसान अपनी जगह पर ऊँचे जीवन के लिए जागता है। सिर्फ़ इसी तरह हर कोई असली समाजवाद, समाज की भावना, सच्चा जीवन पा सकेगा, सुरक्षा की भावना जीत सकेगा, और यह महसूस कर सकेगा कि सिर्फ़ इसी विचार के राज में ही आज के लूट के सिस्टम से एक ऑर्गेनिक, राष्ट्रीय सरकार बन सकती है, और समुदाय और समुदाय के हर सदस्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।

आज इंसान मालिकी के लिए लड़ने वाली ताकतों का बेबस शिकार है; उसके संगठन उसकी मदद करने में लाचार हैं। यह साफ़ तौर पर पता नहीं चल रहा है कि असली दुश्मन कौन है – बेकार मुनाफ़ाखोर और शोषक। कैपिटलिज़्म के ख़िलाफ़ मार्क्सवादी आवाज़, सेंटर की पवित्र घोषणाओं, बिज़नेस जगत की बोझ के बारे में शिकायतों के बावजूद।

टैक्स और ब्याज के अलावा, कोई भी दुनिया के दुश्मन, दुनिया पर हावी फाइनेंस और उसके प्रतिनिधि, यहूदी अमीर को नहीं समझता।

सभी वर्गों ने ब्याज की मार झेली है; टैक्स कलेक्टर आबादी के हर हिस्से पर भारी पड़ता है, — लेकिन बैंक और स्टॉक एक्सचेंज की ताकत का विरोध करने की हिम्मत कौन करता है? कैपिटल, दुनिया में कहीं और के सभी अनुभवों के उलट, बिना किसी मेहनत या मेहनत के, ब्याज और डिविडेंड के ज़रिए, और हर मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होते हुए, अपने चरित्र का ऐलान करता है। झूठ के शैतानी उसूल ने क्रिएटिव मेहनत की तमीज़ को हरा दिया है।

टूट जाओ, ब्याज की गुलामी हमारा नारा है।

मुझे पता है कि यह मांग, जो हर दूसरी मांग के पीछे है, इसकी पूरी अहमियत को हमारे अपने लोगों में भी ठीक से नहीं समझा जाता है। मिसाल के तौर पर, हमारे बहुत कम स्पीकर इस बेसिक सवाल पर बात करने की हिम्मत करते हैं, हालांकि उनमें से ज़्यादातर इसे कितना ज़रूरी मानते हैं; क्योंकि हमारी पार्टी का एक नारा है "कैपिटल और स्टॉक एक्सचेंज से लड़ो"। लेकिन 'ब्याज की गुलामी' असल में क्या है, इसका देश और इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, 'फाइनेंस' ने कैसे लोगों को गुलाम बना लिया है, और इसे तोड़ने के लिए कौन से सही और प्रैक्टिकल तरीके अपनाने चाहिए, और इसे तोड़ने के नतीजे पूरी आबादी के लिए क्या होंगे — यह बहुत कम लोगों को इतना साफ़ है कि वे इसे अपने शब्दों में समझा सकें।

अपनी महान रचना, माइन काम्फ (वॉल्यूम I, पेज 224—225) में एडॉल्फ हिटलर ने इस सवाल की बहुत बड़ी अहमियत को इस तरह बताया है: "जब मैंने जून 1919 में ब्याज की गुलामी को तोड़ने पर गॉटफ्रीड फेडर का पहला लेक्चर सुना, तो मुझे तुरंत पता चल गया कि यह एक थ्योरेटिकल सच था जो जर्मन देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। इंटरनेशनल कैपिटल और फाइनेंस के खिलाफ लड़ाई जर्मन देश की आज़ादी और आज़ादी की लड़ाई के प्रोग्राम का मुख्य मुद्दा बन गई है।" ...

सभी गंभीर नेशनल सोशलिस्ट इस बात को मानते हैं, क्योंकि इस सवाल का हल यहूदी सवाल का हल है, — और उससे भी कहीं ज़्यादा।

एंटी-सेमिटिज्म एक तरह से हमारे पूरे आंदोलन के पीछे की भावना की नींव है।
हर नेशनल सोशलिस्ट एंटी-सेमाइट होता है, लेकिन हर एंटी-सेमाइट का नेशनल सोशलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है।
एंटी-सेमिटिज्म नेगेटिव है; एंटी-सेमिटिज्म देश में महामारी फैलाने वाले को पहचानता है, लेकिन यह जानकारी आमतौर पर किसी एक यहूदी और बिजनेस में यहूदियों की सफलता के लिए नफरत में बदल जाती है। फिर सबसे अच्छे हालात में एंटी-सेमिटिज्म हमारे देश और आर्थिक जीवन से यहूदियों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए उठता है। एंटी-सेमिटिज्म इस बात की चिंता नहीं करता कि आगे क्या और कैसे होगा।

अगर यहूदियों को बाहर निकालने के बाद भी, आज के यहूदी दबदबे का उसूल बना रहता — आम फ़ायदे से पहले अपना फ़ायदा — और यहूदी बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम, तो भी बहुत सारे कमीने यहूदी, या मिक्स्ड रेस के 'नॉर्मल जर्मन' भी यहूदियों की जगह लेने और अपनी ही रेस के ख़िलाफ़ गुस्सा करने के लिए तैयार रहते, जैसे आज के यहूदी हैं, और शायद हमें वहाँ बहुत सारे 'एंटी-सेमाइट्स' बैठे दिखें जहाँ कभी यहूदी बैठते थे।

अब नेशनल सोशलिज्म अपनी मुख्य मांग, यानी ब्याज की गुलामी को खत्म करने के साथ, असल में कंस्ट्रक्टिव है। यह गहरी चोट करता है, और इसके नतीजे कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं।

अपने निबंध, दास हर्ज़स्टक अनसेरेस प्रोग्राम्स, (Nat.Soc. Jahrbuch, 1927) में मैंने उस अजीब जगह की ओर इशारा किया था जो मांग हमें दूसरी सभी पार्टियों और एसोसिएशन के बीच देती है। हमारी बाकी सभी मांगों में, हमें राइट और लेफ्ट पार्टियों में एक जैसी और पैरेलल उम्मीदें मिलती हैं। हमारी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी इस एक मांग का कोई मुकाबला नहीं दिखा सकती।

हम सब जानते हैं कि न तो लेफ्ट, जो "कैपिटलिज़्म मुर्दाबाद" का झूठा नारा लगाते हैं, और न ही राइट, जो फादरलैंड के बारे में अपनी बातें कहते हैं, एक नया दुनिया का दौर शुरू करने के काबिल हैं, क्योंकि न तो मार्क्सिस्ट और न ही रिएक्शनरी हमारी इकॉनमी के नेचर में कुछ भी बदल सकते हैं, बल्कि रूस में कम्युनिस्टों की तरह सिर्फ़ बर्बाद ही करेंगे। वे कंस्ट्रक्शन करने में काबिल नहीं हैं —

रूस में कम्युनिस्टों की तरह।

थ्रॉलडम ऑफ इंटरेस्ट से हमारा क्या मतलब है?

दुनिया के ज्यूरी फाइनेंस के पैसे के दबदबे में लोगों की हालत।

ज़मीन का मालिक इस गुलामी में है, जिसे अपनी खेती के कामों के लिए लोन लेना पड़ता है — इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन कि वह उसकी मेहनत की कमाई लगभग खा ही जाता है —, या जिसे लोन लेने और गिरवी रखे गए लोन को सीसे के वज़न की तरह अपने पीछे घसीटने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

ऐसा ही मज़दूर के साथ भी होता है, जो दुकानों और फ़ैक्ट्रियों में बहुत कम पैसे में काम करता है, जबकि शेयरहोल्डर को डिविडेंड और बोनस मिलते हैं, जिसके लिए उसने काम नहीं किया होता।

ऐसा ही कमाने वाले मिडिल क्लास के साथ भी है, जिनका काम लगभग पूरी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज चुकाने में चला जाता है।

ऐसे ही वे सभी हैं जिन्हें दिमागी या शारीरिक मेहनत करके अपनी रोटी कमानी पड़ती है, जबकि तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग, बिना मेहनत या परेशानी के, अपने डिविडेंड, सट्टेबाजी और बैंक शेयरों से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं। हम किफ़ायती बचत करने वालों और छोटे पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहे हैं —

हालांकि वे भी अपनी जीती हुई रकम एक झूठे सिस्टम के कर्ज़दार हैं, या थे —, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में कई बार उनके थोड़े से ब्याज की रकम उनसे टैक्स के रूप में ले ली गई, ताकि हम उनके बुढ़ापे में उनकी पूरी कमाई का कुछ हिस्सा आसानी से चुका सकें, जो उनसे छीन ली गई थी। इस बारे में मुझे बाद में और कहना होगा।

ऐसा ही इंडस्ट्रियल है, जिसने मेहनत से अपना बिज़नेस बनाया है, और समय के साथ उसे एक कंपनी में बदल दिया है। वह अब एक फ्री एजेंट नहीं है, बल्कि उसे लालची बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और अपने शेयरहोल्डर्स को भी खुश करना होगा — अगर वह बाहर नहीं निकलना चाहता।

ऐसा ही उन सभी देशों के साथ है जो लोन के ज़रिए अपने घाटे को पूरा करते हैं।

यह गुलामी किसी भी देश के लिए बर्बादी का कारण बनती है जो पैसे की ताकत, बैंकरों, अपने देश में अपने सॉवरेन अधिकार, अपने फाइनेंस, रेलवे, और टैक्स और कस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में दे देता है, जैसा कि जर्मनी ने डावेस लॉ को मानकर किया है।

क्रिएटिव काम भी उसी गुलामी में है, अगर वह सबसे पहले पैसे के बारे में सोचता है। आज
पैसा, जो 'बिज़नेस का नौकर' है, असल में मज़दूरी का मालिक, यानी क्रूर तानाशाह बन गया है।

ब्याज की गुलामी ही विरोधों की असली अभिव्यक्ति है, कैपिटल बनाम लेबर, खून बनाम पैसा, क्रिएटिव काम बनाम शोषण।

इस गुलामी को तोड़ना हमारे देश और हमारी जाति के लिए इतना ज़रूरी है कि सिर्फ़ इसी पर हमारे देश की शर्म और गुलामी से बाहर निकलने की उम्मीद टिकी है; असल में, पूरी दुनिया में खुशी, खुशहाली और सभ्यता वापस पाने की उम्मीद टिकी है।

"यह वह धुरी है जिस पर सब कुछ घूमता है; यह सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल पॉलिसी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। जबकि इसके सिद्धांत और नतीजे राजनीतिक और आर्थिक जीवन में गहरी चोट करते हैं, यह आर्थिक अध्ययन के लिए एक अहम सवाल है, और इस तरह हर एक व्यक्ति पर असर डालता है और हर एक से एक फ़ैसला मांगता है: — देश की सेवा या अनलिमिटेड प्राइवेट अमीरी। इसका मतलब है सामाजिक सवाल का हल।"

दुनिया के सभी सवालों को एक शब्द में बताया जा सकता है, जो अफ़रा-तफ़री से आग की तरह उठता है; साथ ही, अनगिनत पैगंबर और किताबें भी उस शब्द से उठने वाले सभी सवालों को खत्म नहीं कर सकतीं।

नेशनल सोशलिज़्म के इस बड़े बेसिक सिद्धांत पर हम अभी और कुछ नहीं कह सकते। मैंने अपने पैम्फलेट में इस समस्या के हर ज़रूरी पहलू पर पहले ही रोशनी डाल दी है: Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft — Munich, 1926 (अब प्रिंट से बाहर); Der Staatsbankrott, Die Rettung — Jos. C. Huber, Diessen, 1919; Der kommende Steuerstreik — Diessen, 1921; और Der Deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage — Frz. Eher Nachf., Munich, (सभी म्यूनिख में हमारी पार्टी की लाइब्रेरी, Thierschstr. 11 से मिल सकते हैं)।

इस समस्या की डिटेल्स को समझने के लिए गहरी पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 50 सालों की प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स ने कैपिटलिस्टिक आइडिया को इतने करीब से फॉलो किया है कि जो लोग इसके साथ बड़े हुए हैं, उन्हें इससे आज़ाद होने के लिए अपनी सोच में पूरी तरह बदलाव लाने की ज़रूरत है।

इस विषय पर एक पैम्फलेट जल्द ही आने वाला है, जो हमारे सदस्यों को आने वाले राष्ट्रवादी राज्य के इस बहुत ज़रूरी काम के बारे में जानकारी देगा।

हमारे प्रोग्राम के ऊपर दिए गए दो बिल्कुल नए बेसिक प्रिंसिपल्स के अलावा, हम
राज्य की सामान्य नीति के संबंध में कुछ अन्य बातों का उल्लेख करना होगा।

राज्य के बारे में हमारी नीति का मूल सिद्धांत संक्षेप में इस प्रकार है: जर्मन रीच जर्मनों का घर है।

यह हमारी पूरी विदेश नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है, और इसमें जर्मनी की राजनीतिक आज़ादी, हमारी नस्लीय नीति की सभी ज़रूरतें, और देश की सदस्यता की शर्तें शामिल हैं।

हमारा आर्थिक सिद्धांत है: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कर्तव्य ज़रूरतें पूरी करना है
जीवन का और पूंजी के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा पक्का करने का नहीं।

इकोनॉमिक पॉलिसी का यह सिद्धांत प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रति नेशनल सोशलिज़्म के बुनियादी नज़रिए को अपनाता है, और बिज़नेस के अलग-अलग रूपों के संबंध में, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक – सिंडिकेट्स, ट्रस्ट्स – और उन बड़े नैतिक सवालों के प्रति भी, जो बिज़नेस में एक ज़िंदा ताकत होने चाहिए, अगर 'नेशनल इकॉनमी' को सिर्फ़ देश का शोषण और सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए चलाया जाना नहीं है!

फाइनेंस के बारे में हमारा सिद्धांत इस प्रकार है:

फाइनेंस राज्य के फायदे के लिए होगा; बड़े-बड़े फाइनेंशियल लोग कोई संगठन नहीं बनाएंगे।
राज्य के भीतर राज्य।

इस सिद्धांत में एक बड़ा बदलाव शामिल है। यह उन प्रैक्टिकल उपायों से जुड़ा है जो ब्याज की गुलामी को तोड़ने के लिए करने होंगे, — फाइनेंस का नेशनलाइजेशन, क्रेडिट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल।

हमारे प्रोग्राम के नज़रिए से इनमें से हर काम बहुत ज़रूरी है। इनमें सभी टैक्स कानून शामिल हैं, और आखिर में — और नामुमकिन सा लगने वाला —
बिना टैक्स वाले राज्य का लक्ष्य।

सामाजिक विषयों के संबंध में हमारा सिद्धांत इस प्रकार है:

आम भलाई सबसे बड़ा कानून है।

हमारा यह सिद्धांत आज के चलन के बिल्कुल उलट है, जिसके अनुसार हर वर्ग, हर पेशा, आम हित की परवाह किए बिना सोशल पॉलिसी में अपने खास ग्रुप के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि सभी के लिए रहने की जगह और गुज़ारा हो सके, और बुज़ुर्गों की देखभाल का एक आम सिस्टम बनाया जाए।

एजुकेशनल और नैतिक तरक्की के मामले में, यह हमारा अटल उसूल है: कि उस दिशा में सारा काम सिर्फ़ जर्मन राष्ट्रीयता के नज़रिए से किया जाना चाहिए। यह ऑर्डर या ज़बरदस्ती नहीं हो सकता कि हमारे देश की नैतिक और दिमागी ताकतें एक नया रेनेसां, कला में एक नया क्लासिक दौर ला सकें। जो नुकसान हुआ है, उसे रोकना होगा।

यहूदी तानाशाही के हाथों हमारे जर्मन कलात्मक और बौद्धिक जीवन को नुकसान पहुँचाया गया, खासकर प्रेस को ज़हर देकर।

पब्लिक लाइफ के इस ज़रूरी हिस्से के अलावा, बेशक, और भी कई सुधारों पर विचार किया जाना है।

यह साफ़ है कि हमारे कानून के सिस्टम को नए इंस्टीट्यूशन की वैरायटी के हिसाब से बदलना होगा; डेमोक्रेटिक वोट से पार्लियामेंट के चुनाव का स्कैंडल खत्म करना होगा, और डिक्टेटरशिप के ट्रांज़िशनल पीरियड के बाद, हमें स्टेट के बाहरी दिखने वाले रूप और फेडरल स्टेट्स के अंदरूनी कामों पर फैसला करना होगा।

लेकिन, हम पहले से ही इस छोटी सी आउटलाइन में इन सवालों के बड़े पहलुओं को देख सकते हैं।
जब हमारे प्रोग्राम के ज़बरदस्त बुनियादी सिद्धांतों का सामना करना पड़ता है।

यह ज़रूरी नहीं है — असल में, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राजशाही होनी चाहिए या रिपब्लिक, हमारे पास 5 या 25 राज्यों का फ़ेडरेशन होना चाहिए, बस शर्त यह है कि वे सभी जर्मन राज्य हों जो एक मज़बूत सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हों, जब वे विदेशियों के आमने-सामने हों, और शर्त यह है कि घर पर सिर्फ़ जर्मन राज्य के नागरिक ही खुश और संतुष्ट रह सकें।

4. प्रोग्राम की ज़रूरतें डिटेल में

जैसा कि गॉटफ्रीड फेडर ने डेर ड्यूश स्टेट में तैयार किया है।

इससे यह साफ़ हो जाएगा कि नए सदस्यों को शामिल करते समय, प्रोग्राम का इस्तेमाल नीचे दिए गए तरीके से किया जाए। छोटे क्लॉज़ को ज़्यादा ज़रूरी हेडिंग्स के तहत रखा गया है, जो पिछले चैप्टर में बताए गए सिद्धांतों के हिसाब से हैं।

NSDAP का राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम

हमारा लक्ष्य है — जर्मन भावना में जर्मन स्वतंत्रता के लिए जर्मनी का पुनर्जन्म।

इस लक्ष्य को पाने के साधन ये हैं:

1. राजनीतिक सिद्धांत: जर्मन रीच जर्मनों का घर है।

क. विदेश नीति में:

- सभी जर्मन जातियों को शामिल करते हुए एक समान राष्ट्रीय राज्य का गठन।
- विदेशों में जर्मन हितों का ज़ोरदार प्रतिनिधित्व।

ख. नस्लीय नीति में:

- सभी जर्मन जातियों को शामिल करते हुए एक समान राष्ट्रीय राज्य का गठन।
- विदेशों में जर्मन हितों का ज़ोरदार प्रतिनिधित्व।

ग. आंतरिक नीति में:

- सिर्फ़ वही जर्मन नागरिक देश के नागरिक के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जर्मनी की भावना और नियति के साथ पूरी कम्युनिटी को मानते हैं।
- जो कोई जर्मन नहीं है वह जर्मन राज्य में केवल मेहमान के रूप में रह सकता है और विदेशी कानून के अधीन है।
- जर्मन लोगों के अधिकारों को विदेशी देशों के नागरिकों के अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

2. हमारा आर्थिक सिद्धांत: राज्य का कर्तव्य जीवन की आवश्यक चीजें प्रदान करना है कैपिटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा पक्का न करना।

a. नेशनल सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक प्रिंसिपल के तौर पर पहचानता है और उसकी रक्षा करता है कानून।

b. लेकिन, देश की भलाई के लिए यह ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसा जमा करने की एक लिमिट तय की जाए।

c. सभी जर्मन लोग आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक कम्युनिटी बनाते हैं और संस्कृति।

d. हर जर्मन की काम करने की ज़िम्मेदारी की सीमाओं के अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी की पवित्रता का सम्मान करते हुए, हर जर्मन अपनी मेहनत का फल कमाने और बेचने के लिए आज़ाद है।

ई. कृषि सहित आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में, छोटे और बड़े, सभी प्रकार के व्यवसायों के स्वस्थ संयोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सभी मौजूदा व्यवसाय जो अब तक कंपनियों के रूप में थे राष्ट्रीयकरण किया जाए।

छ. नुकसान की कीमत पर सूदखोरी, मुनाफाखोरी और व्यक्तिगत समृद्धि देश के किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाएगी।

h. (राज्य के लिए) एक साल तक काम करने की बाध्यता की शुरुआत, जो हर साल लागू होगी जर्मन.

3. हमारा फाइनेंशियल सिद्धांत: फाइनेंस राज्य के फायदे के लिए होगा; फाइनेंशियल बड़े लोग राज्य के अंदर राज्य नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारा मकसद ब्याज की गुलामी को तोड़ना है।

क. राज्य और इसलिए देश को उन बड़े फाइनेंशियल घरानों के कर्ज़ से राहत देना जो ब्याज पर उधार देते हैं।

b. राइशबैंक और जारी करने वाले घरों का नेशनलाइज़ेशन। c. सभी बड़े पब्लिक कामों (पानी, रेल, वगैरह)

के लिए पैसे का इंतज़ाम, लोन के ज़रिए नहीं, बल्कि बिना ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड देकर या बिना तैयार पैसे का इस्तेमाल किए।

घ. सुरक्षित आधार पर मुद्रा के एक निश्चित मानक की शुरूआत।

e. बिना ब्याज वाले लोन देने के लिए एक नेशनल बैंक ऑफ़ बिज़नेस डेवलपमेंट (करेंसी रिफॉर्म) बनाना।

f. सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों पर टैक्स सिस्टम की बुनियादी री-मॉडलिंग। कंज्यूमर को इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ से और प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा टैक्स से राहत (फिस्कल रिफॉर्म और टैक्स से राहत)।

4. हमारा सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांत: आम भलाई ही सबसे बड़ा नियम है।

a. एन्युइटी के सिस्टम को नेशनलाइज़ करके बड़े पैमाने पर ओल्ड एज इंश्योरेंस का विकास। जर्मन देश के हर सदस्य को एक तय उम्र होने पर, या अगर वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है, तो उस उम्र से पहले गुज़ारे के लिए काफ़ी पैसे मिलेंगे।

b. प्रोडक्टिव कामों में लगे सभी लोग अपनी काबिलियत और उम्र के हिसाब से मुनाफ़े में हिस्सा लेंगे। देश के नज़रिए से काम पूरा करने में ज़िम्मेदारी भी शेयर की जाएगी।

सी. युद्ध और क्रांति से अर्जित सभी लाभों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए जब्त करना, न कि ईमानदारी से काम करने और सूदखोरों और धन-लोलुपों के भाग्य से।

d. नंबर 20 में बताए गए तरीकों से पूरे राइख में बड़े पैमाने पर नए कंस्ट्रक्शन से घरों की कमी को दूर करना (एक नया नेशनल बैंक)।

5. हमारा कल्चरल मकसद यह है कि सभी साइंस और फाइन आर्ट्स एक पॉलिटिकली फ्री, इकोनॉमिकली हेल्दी स्टेट के बेसिस पर आगे बढ़ें। इसे पाने के तरीके ये होंगे:

क. युवाओं को शरीर से स्वस्थ और मन से मुक्त रहने के लिए प्रशिक्षण देना, महान जर्मन संस्कृति की परंपराएं।

b. पंथ और विवेक की पूरी आज़ादी।

c. ईसाई संप्रदायों के लिए विशेष सुरक्षा।

d. उन सिद्धांतों को हतोत्साहित करना, जो जर्मन नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं और जिनमें राज्य और राष्ट्र के लिए नुकसानदायक बातें हैं।

ई. प्रेस, साहित्य, मंच, कला और पिक्चर थिएटर में सभी बुरे प्रभावों को हतोत्साहित करना।

f. जर्मन सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाई की आज़ादी; एक नियम बनाना उच्च विचार वाले पुरुषों का वर्ग।

6. सैन्य मामले।

क. हर आज़ाद जर्मन को सेवा करने और सहन करने की इजाज़त देकर देश को कुशल बनाना हथियार.

ख. वेतन पाने वाली सेना को खत्म करना।

c. देश की सुरक्षा के लिए एक नेशनल आर्मी बनाना, जिसकी कमान प्रोफेशनल ऑफिसर्स की एक बहुत ट्रेंड कोर के हाथ में हो।

7. अन्य सुझाव.

a. प्रेस सुधार। देश के भले के खिलाफ जाने वाले सभी जर्नल्स को दबाना। सभी झूठी और जानबूझकर गलत जानकारी के लिए सख्त ज़िम्मेदारी।

b. वोट देने के कानूनों में बदलाव ताकि चुनाव लड़ने के हिम्मत तोड़ने वाले तरीकों को खत्म किया जा सके, और चुने गए लोगों को छूट दी जा सके।

ग. व्यापार और व्यवसायों के लिए विशेष चैंबर का गठन।

d. ज़मीन के कानूनों के बारे में न्यायिक सुधार — ज़मीन पर प्रॉपर्टी के अधिकारों को एक प्रिंसिपल के तौर पर मान्यता देना; ज़मीन की सिक्योरिटी पर प्राइवेट सोर्स से उधार लेने का कोई अधिकार नहीं; राज्य के पास प्री-एम्प्शन का अधिकार होना, खासकर विदेशियों और यहूदियों के मामले में; मालिक की तरफ से खराब मैनेजमेंट की स्थिति में राज्य को एस्टेट को मैनेज करने का अधिकार होना।

सिविल लॉ — इसमें निजी सम्मान और सेहत की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, जबकि आजकल प्रॉपर्टी के अधिकारों की एकतरफ़ा कानूनी सुरक्षा ज़्यादा है।

ई. राज्य कानून सुधार।

जर्मन कैरेक्टर के लिए सबसे सही स्टेट का तरीका है सॉवरेन कंट्रोल जो एक सेंट्रल पर्सनल पावर में जुड़ा हो। देश को बाद में तय करना होगा कि यह सेंट्रल पर्सनल पावर चुने हुए राजा के पास होगी या प्रेसिडेंट के पास।

रीच का संघीय चरित्र।

नस्ल और इतिहास से एक-दूसरे से जुड़े कई देशों से बने जर्मन राष्ट्र के संविधान के कारण यह ज़रूरी है कि हर राज्य अंदरूनी मामलों में बहुत हद तक आज़ाद हो।

विदेश में जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, और पासपोर्ट, कस्टम, और आर्मी और नेवी के लिए भी इंतज़ाम करना राइख का काम है।

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने में तीन मुख्य बाधाएँ हैं समाजवाद: मार्क्सवाद, संसदीय प्रणाली और पूंजीवादी बड़े लोग।

1. हमारा एंटी-मार्क्सिस्ट कैंपेन यहूदी, कार्ल मार्क्स के विघटनकारी सिद्धांतों के खिलाफ है — क्लास-वॉर का सिद्धांत जो देश को बांटता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने का सिद्धांत जो बिजनेस को नामुमकिन बना देता है — और इतिहास के पूरे इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिक नजरिए के खिलाफ है।

2. पार्लियामेंट के खिलाफ हमारा कैंपेन तथाकथित लोगों के नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी की कमी के खिलाफ है, जो – इम्यून होने के कारण – अपने फैसलों के नतीजों के लिए असल में कभी जवाबदेह नहीं ठहराए जा सकते; साथ ही सिस्टम से पैदा होने वाली सभी बुराइयों (नैतिक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, धोखाधड़ी) के खिलाफ भी है, जिनका नतीजा आखिरी बुराई है – एक ऐसी सरकार जो ऐसी पार्लियामेंट पर निर्भर है।

3. मैमन के खिलाफ हमारा अभियान, जो बाकी दो से ऊपर है, पैसे की दुनिया भर में फैली ताकत के खिलाफ है, यानी बड़े कर्ज देने वाले घरानों द्वारा हमारे देश का लगातार शोषण।

यह लालच और लालच की आत्मा को मारने वाली, भौतिकवादी भावना के खिलाफ़ एक ज़बरदस्त संघर्ष भी है, जो हमारे सार्वजनिक, कमर्शियल और सांस्कृतिक जीवन में मौजूद सभी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के साथ है।

मुख्य लड़ाई दो दुनिया की थ्योरी के बीच है, जिन्हें दो अलग-अलग स्ट्रक्चर दिखाते हैं — एक आत्मा जिसने बनाया है और क्रिएटिव है और दूसरी बेचैन, लालची आत्मा। क्रिएटिव आत्मा, जो गहरी जड़ें जमा चुकी है, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बाकी दुनिया से बेहतर है, उसे मुख्य रूप से आर्यन नस्ल आगे बढ़ाती है; — लालची आत्मा, जिसकी कहीं कोई जड़ नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ़ मटेरियल चीज़ें, कमर्शियल चीज़ें हैं, मुख्य रूप से यहूदियों द्वारा दिखाई जाती है।

नेशनल सोशलिज़्म, एंटी-सेमिटिज़्म की तरह, यहूदी-मैटेरियलिस्टिक भावना को बुराई की मुख्य वजह मानता है; लेकिन यह जानता है कि इतिहास का यह सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ़ सेमिटिक भावना को खत्म करने पर ही नहीं रुकना चाहिए; यही वजह है कि नेशनल सोशलिज़्म का महान प्रोग्राम, खत्म करने की एंटी-सेमिटिक इच्छा से कहीं आगे जाता है, क्योंकि यह एक पॉज़िटिव कंस्ट्रक्टिव तस्वीर पेश करता है, जो दिखाता है कि मेहनत और कामयाबी का नेशनल सोशलिस्ट स्टेट पूरा होने पर कैसा दिखना चाहिए।

एक बार यह बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी; क्योंकि तब नेशनल सोशलिज्म पूरे जर्मन देश की पूरी ज़िंदगी होगी। NSDAP आम शब्दों में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि देश का वह हिस्सा है, जिसे भविष्य पर भरोसा है, और जो जर्मनी को विदेश में शर्म और लाचारी से और देश में निराशा से बचाने के लिए मज़बूत और पक्के इरादे वाले नेताओं के साथ इकट्ठा हुआ है, और उसे विदेश में एक बार फिर मज़बूत और इज्ज़तदार, और देश में नैतिक और आर्थिक रूप से सेहतमंद बनाना है।

"जर्मन रीच जर्मन लोगों का घर है।"

आज की खराब हालत को देखते हुए, स्टेट पॉलिसी के इस सिद्धांत का हर शब्द कोड़े की मार जैसा है।

'जर्मन राइख' — आज जर्मन राइख कहाँ है? क्या जर्मनी यह दावा कर सकता है कि उसे एक आज़ाद देश कहा जाता है? नहीं! स्टेट लॉ के सबसे ज़्यादा जानकार भी जर्मनी जैसे देश को, जो अब है, अपनी सॉवरेनिटी के सभी अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने वाला देश नहीं कह सकते।

एक राज्य के पांच सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं: अपने क्षेत्र पर संप्रभुता, अपनी सेना, अपनी फाइनेंस, इसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन, और आखिर में इसका न्याय।

आपको इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी देश के अधिकारों के बारे में और ज़्यादा जानकारी दिए बिना, किसी भी आम आदमी के सामने इस तरह से बात रखनी है, और इसकी तुलना आज जर्मनी की स्थिति से करनी है, और यह साफ़ हो जाता है कि यह कहना नामुमकिन है कि अब एक आज़ाद 'जर्मन राइख' मौजूद है।

हमारे इलाके पर हमारा कंट्रोल एक मज़ाक है, क्योंकि जब भी फ्रांस चाहे, वह बिना इजाज़त मांगे और बिना विरोध झेले जर्मन ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है। चेक, पोल्स, डेन्स

बिना किसी डर के जर्मन इलाके में कोई भी घुसपैठ कर सकते हैं। 'शापित पुरानी सरकार' ने सीमा के ज़रा से भी उल्लंघन का बहुत अलग मतलब निकाला। तब जर्मन इलाके में मिलिट्री घुसपैठ का मतलब 'युद्ध की स्थिति' होता था।

अपनी ज़मीन पर किसी भी हमले को रोकने के लिए, और इसलिए अपने नागरिकों की ज़िंदगी और खुशी पर भी, एक आज़ाद देश को एक ऐसी सेना की ज़रूरत होती है जो किसी भी हमले को रोक सके। एक आज़ाद देश किसी विदेशी ताकत को अपने कामों की जांच करने, या अपनी सेना की ताकत, सामान, हथियार, सेना की टुकड़ियों को तय करने का अधिकार नहीं दे सकता; अगर ऐसा होता है, तो वह निश्चित रूप से 'सॉवरेन' नहीं है; वह अपनी ताकत के साधनों को कंट्रोल नहीं कर सकता; उसने अपनी मिलिट्री ताकतों पर कंट्रोल छोड़ दिया है। जर्मनी ने दुश्मन के डिसआर्मामेंट और कंट्रोल कमीशन के आगे झुककर ऐसा किया है।

जर्मनी पहले ही आर्मिस्टिस की शर्तों के तहत यह बेइज़्ज़ती झेल चुका था और अपने इंटरनेशनल अधिकार खो चुका था।

फिर भी, उसने अपने अंदरूनी कंट्रोल का कुछ हिस्सा बनाए रखा होगा; लेकिन जैसे ही मिलिट्री कंट्रोल खत्म हुआ, बड़े पैसे वालों ने जर्मन लेबर के बिना रोक-टोक वाले शोषण का मौका पकड़ लिया।

सबसे पहले, जर्मनी में क्रांति की गंदी बाढ़ आई; फिर सूदखोरों और मुनाफ़ाखोरों, सोशल-डेमोक्रेटिक गद्दारों, अराजकता के बेटों, भगोड़ों, जेल के कैदियों ने डेमोक्रेट्स और सेंटर के साथ सत्ता में हिस्सा लिया, और सभी फाइनेंसरों, यहूदियों के पीछे और ऊपर, अपना काम किया। जल्द ही तथाकथित नेशनल पार्टियों के फ्री मेसन, खासकर ब्रदर स्ट्रेसमैन को बुलाया गया। आखिरी झटका जल्द ही लगने वाला था। एक्सपर्ट्स ने अपने डावेस लॉ से जर्मनी से उसके फाइनेंस का कंट्रोल छीन लिया, जिसे मुट्ठी भर यहूदियों, जर्मन और विदेशी फाइनेंशियल दिग्गजों को दे दिया गया। राइखस्टैग ने रेलवे को जाने दिया, और उनके साथ कम्युनिकेशन का सारा कंट्रोल, साथ ही टैक्सेशन और कस्टम्स का एक बड़ा कंट्रोल भी, उन्हें रिपेरेशन्स कमिश्नर को सौंपकर।

न्याय पर कंट्रोल अब मुश्किल से ही रहा है। कब्ज़े वाले ज़िले विदेशी मिलिट्री कानून के तहत हैं; बाकी जर्मनी में खास नियम लागू हैं, जैसे कि रिपब्लिक की रक्षा के लिए; अधिकारों की असुरक्षा, तथाकथित Aufwertungsgesetze के ज़रिए संगठित सार्वजनिक लूट, जिससे कोर्ट को गलत को सही घोषित करने पर मजबूर होना पड़ता है।

जर्मनी अब एक आज़ाद देश नहीं रहा। वह गुलामों की कॉलोनी बन गया है। जर्मन लोगों पर ज़ुल्म किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती — सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वे अब भी 'जर्मन' हैं और अपनी गुलामी खत्म करना चाहते हैं।

हाँ, हम जर्मनी को फिर से आज़ाद देखना चाहते हैं, और यह आने वाला जर्मन राइख जर्मनों का घर होगा — सिर्फ़ व्यवस्था बनाए रखने की मशीन नहीं, सिर्फ़ एक 'स्टेट', एक 'अथॉरिटी', एक 'गवर्नमेंट', कुछ राजघरानों के लिए आराम का ज़रिया नहीं, बल्कि एक घर, वह प्यारा शब्द — घर का प्यार, प्यारा, धूप वाला, प्यारा। घर की मिट्टी की खुशबू ऊपर उठती है, घुमक्कड़ अपने पैरों के नीचे घर की मिट्टी को महसूस करके खुशी से झूम उठता है; वह खून के रिश्तों से उससे बंधा होता है।

घर जैसा एहसास सुरक्षा का एहसास है, और इसी से घर के प्यार का सुंदर फूल खिलता है। राज्य और देश का इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता।

यह एक सावधान सोशल पॉलिसी, बेरोज़गारी इंश्योरेंस, हाउसिंग स्कीम से कहीं ज़्यादा है, हालांकि असल में अपना घर होना घर के प्यार के लिए सबसे मज़बूत इंसेंटिव में से एक है।

घर किसी 'शाही राज्य' से कहीं ज़्यादा है, जिसकी सेवा कोई भी व्यक्ति उत्साह से या मजबूरी में.

यह सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा है, अपने फ़ायदों की रक्षा से ज़्यादा है, जानवरों के लिए बाड़े या इंसान और प्रॉपर्टी की सुरक्षा से ज़्यादा है। इन सभी पब्लिक चीज़ों को घर के कॉन्सेप्ट को पूरा करना चाहिए। जैसे घर के आइडिया में बच्चों का एक खास आकर्षण होता है, वैसे ही बच्चों का भी एक खास आकर्षण होता है।

संगठित परिवार, क्योंकि अपना कमरा होटल या जेल के कमरे से बहुत अलग एहसास दिलाता है; घर कुछ ऐसा है जो बहुत ही कोमल और फिर भी शक्तिशाली है, किसी मकसद के लिए एक संगठन के विचार से बेहतर है, जो सामाजिक राज्य की लिबरल - पार्लियामेंट्री - डेमोक्रेटिक सोच है।

राज्य की नीति

सिद्धांत: जर्मन राइख जर्मनों का घर होगा—यहूदियों, रूसियों (कम्युनिस्टों), सोशल डेमोक्रेट्स, जिनकी जर्मनी नाम की कोई पितृभूमि नहीं है (क्रिस्पियन), और न ही उन सभी विदेशियों का घर होगा जो जर्मन धरती पर ज़्यादा या कम समय के लिए रुकते हैं।

हम वाइमर संविधान के सख्त और बुनियादी विरोध में हैं, जो सिर्फ़ 'जर्मन नागरिकों' की बात करता है, लेकिन राष्ट्रीय, या यूँ कहें कि नस्लीय, मतलब में 'जर्मन' की सोच को नज़रअंदाज़ करता है।

(क) विदेश नीति।

1. एक मज़बूत राष्ट्रीय राज्य बनाना, जिसमें जर्मन जाति की सभी शाखाएँ शामिल हों।

सभी जर्मन खून के लोग, चाहे वे फ्रेंच, डेनिश, पोलिश, चेक या इटैलियन राज के तहत रहते हों, एक जर्मन राइख में एक होंगे। हम अपने दुश्मनों के लिए जो मांगा था, उससे न तो कम मांगते हैं और न ही ज़्यादा — जर्मनों का अपनी मातृभूमि, जर्मन राज्य से जुड़ने का फैसला करने का अधिकार।

हम सुडेटन जर्मनी, अलसैस-लोरेन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया की लीग कॉलोनी और पुराने ऑस्ट्रिया के बाद बने राज्यों में सभी जर्मनों पर अपना दावा करते हैं। हालांकि, यह मांग साफ़ तौर पर साम्राज्यवाद की तरफ़ किसी भी झुकाव को बाहर करती है; यह एक सीधी और स्वाभाविक मांग है, जिसे कोई भी मज़बूत राष्ट्रीयता अपनी स्वाभाविक ज़रूरत के तौर पर सामने रखती है।

2. विदेशों में जर्मन हितों का मज़बूत प्रतिनिधित्व एक और ज़रूरी नतीजा है बिन्दु a का.

आमतौर पर सबसे अच्छे, सबसे मेहनती और हिम्मत वाले लोग – इंजीनियर, खोजकर्ता, प्रोफेसर, व्यापारी, डॉक्टर – ही विदेशी देशों में जाते हैं, और अपने साथ जर्मन कल्चर ले जाते हैं। वे महान जर्मन राष्ट्रीय परिवार के सदस्य हैं, जिससे उन्हें कभी दूर नहीं होना चाहिए। जब वे विदेश में हों तो उन्हें घर से सुरक्षा की उम्मीद करने का अधिकार है। उन्हें सिर्फ़ कल्चर फैलाने वाले नहीं, बल्कि दुनिया में जर्मनिक विचार के जागरूक अगुआ होने चाहिए; 'इंसानियत के दूत' नहीं, बल्कि नॉर्डिक विचार के वाहक होने चाहिए।

जो लोग विदेश में जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें विदेशी सोच नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि अपने बेहतर जर्मन कैरेक्टर पर टिके रहना चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस को लोहे के हथौड़े से साफ करना होगा। हमें एर्ज़बर्गर और स्ट्रेसमैन की तरह विदेशियों के प्रति चापलूसी खत्म करनी होगी, और यह देखा जाएगा कि जर्मन हितों के मज़बूत रिप्रेजेंटेशन का काफी सम्मान किया जाएगा, और नतीजा यह होगा कि जर्मन इच्छाओं पर ध्यान दिया जाएगा, नफ़रत नहीं।

(बी) नस्लीय नीति।

3. यहूदियों और सभी गैर-जर्मनों को पब्लिक लाइफ में सभी ज़िम्मेदार पदों से बाहर रखा जाए।

यह मांग हम नेशनल सोशलिस्ट लोगों के लिए इतनी स्वाभाविक है कि इसके लिए और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है; लेकिन जो लोग हमारे नस्लीय सिद्धांत के सिद्धांतों को समझने में नाकाम रहते हैं, उन्हें शॉर्ट में ठोस तर्क देना मुमकिन नहीं है।

जो कोई भी यहूदी को 'यहूदी धर्म के राज्य का नागरिक' मानता है — न कि एक अलग-थलग, अलग-थलग लोगों के तौर पर, जो स्वभाव से परजीवी हैं, वह इस मांग की ज़रूरत को समझने में नाकाम रहेगा। अगर कोई आदमी यह कहे या सोचे कि स्ट्रॉबेरी के पौधे के बीच में अचानक उगी पत्तागोभी स्ट्रॉबेरी का पौधा है, और उससे अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल सकती हैं, तो वह उतना ही गलत होगा जितना यह सोचना कि भेड़ों के झुंड में घुसने वाला शेर का बच्चा भेड़ बन गया। एक जर्मन चीन या भारत में सरकारी अधिकारी के तौर पर अच्छा नहीं होगा, और हम किसी चीनी या हॉटेंटॉट को ट्रेजरी अधिकारी या जर्मन शहर का मेयर नहीं बनाना चाहेंगे।

और फिर भी, जर्मनी में एनवर पाशा या चांग काई चेक का कंट्रोल होना बेहतर होगा, बजाय इसके कि एक यहूदी को उसकी बिखरती नस्लीय खासियतों के लिए खुली छूट दी जाए।
यह तो पक्का है कि क्रांति ने राज्य में व्यवस्था की डोर ढीली कर दी, और पुराने यहूदी बैंकरों, साथ ही पूरब से हाल ही में जर्मनी में आकर बसे यहूदियों ने जर्मनी को गरीब बनाकर खुद को अमीर बनाया है। हम सबने यह देखा है और इसका अनुभव भी किया है; नॉर्डिक संस्थाओं का यह टूटना हमेशा से होता आ रहा है। "इन चालाक लोगों के लिए बस एक ही रास्ता खुला है, — जब तक व्यवस्था बनी रहती है, तब तक इनके पास उम्मीद करने के लिए कुछ नहीं है।" (प्लंडर्सवीलेन के मेले में गोएथे)

इसलिए, हम मांग करते हैं:

4. पूर्वी यहूदियों और दूसरे परजीवी एलियंस का इमिग्रेशन रोका जाएगा, और
कि अनचाहे विदेशियों और यहूदियों को देश निकाला दिया जाएगा।

जब बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो गैलिशिया और पोलैंड से यहूदी कीड़े-मकौड़ों की तरह जर्मनी के शहरों में आ गए। हालाँकि वहाँ घरों की बहुत कमी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें बहुत अच्छे घर मिल गए, जबकि जर्मनों को छिपकर रहना पड़ा। उन्होंने अपना गंदा धंधा शुरू कर दिया, सब कुछ खरीद लिया — मोती, फ़ारसी कालीन, हीरे, सोना, चाँदी, प्लैटिनम, वॉर लोन, हज़ार मार्क के नोट, तांबा, सीसा, साहित्य, थिएटर, अनाज (इवैपोरेटर कंपनी)। वे जल्द ही अमीर हो गए, — और 'आम जर्मनों' की नज़र में जर्मनों जैसा दर्जा पा लिया।

इस मामले में समझौता बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। हमारे पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए जिनकी नस्लीय सोच साफ़ और पक्की हो। एंटी-सेमिटिक ट्रीटमेंट को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करके नस्ल की सेहत को ठीक किया जाना चाहिए, और हमारे देश को नॉर्डिक आइडिया के हिसाब से उत्तर की ओर मोड़ना चाहिए।

यह सवाल शायद NSDAP के 'प्रोविजनल प्रोग्राम' से ठीक से जुड़ा नहीं है; लेकिन हम सभी को यह साफ तौर पर समझना चाहिए कि जर्मन देश के साथ तब तक कुछ खास नहीं किया जा सकता जब तक उसे 'डीबैस्टर्डाइज़' नहीं कर दिया जाता।

लेकिन हम अभी और यहीं कह सकते हैं कि भयानक नस्लीय गिरावट सिर्फ़ — कम से कम थ्योरी में — इसलिए रुकी है, क्योंकि आम तौर पर नस्ल के सवालों में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है और इस विषय पर कई किताबें हैं; लेकिन सिर्फ़ ठोस और लगातार काम ही हमें असली तरक्की करने में मदद कर सकता है।

(ग) राज्य की नागरिकता के संबंध में हम मांग करते हैं:

5. कि जर्मन संस्कृति और साझा नियति में विश्वास करने वाले जर्मनों के अलावा कोई नहीं
सभी जर्मनों को राज्य के नागरिक के अधिकार मिलेंगे।

यहां भी सीमाएं तय करनी होंगी। जो लोग, भले ही जर्मनी में पैदा हुए हों, लेकिन जानबूझकर देश और राज्य के लिए नुकसानदायक काम करते हैं, और बाहर से आदेश लेते हैं और उनका पालन करते हैं — यानी आम किस्मत में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जा सकते; ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें इन अधिकारों का आनंद लेने के बड़े सम्मान से वंचित करना होगा।

6. गैर-जर्मन लोग जर्मन राज्य में केवल मेहमान के रूप में रह सकते हैं और उन्हें विदेशी कानून के अधीन होने के कारण।

यह एक ज़रूरी नियम है, जिसका मकसद विदेशियों के प्रति हमेशा की चापलूसी को हमेशा के लिए खत्म करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत न करें और उनके साथ मेहमानों जैसा अच्छा बर्ताव न करें, जब तक वे ठीक से पेश आते हैं; लेकिन

7. जर्मन लोगों के अधिकारों और हितों को किसी विदेशी देश के नागरिकों के अधिकारों और हितों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

हमारी आगे की ज़रूरतों को हमारे प्रोग्राम में डिटेल में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, विदेशियों पर असर डालने वाले कानूनों का रूप बाद में तय किया जाएगा, साथ ही यहूदियों को बाहर रखने के तरीके भी। सिद्धांतों के प्रोग्राम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह एक्शन का प्रोग्राम हो, जिसमें यह बताया गया हो कि वर्चस्व कैसे हासिल किया जाए, वगैरह। मैं अपने प्रोग्राम को बहुत सख्ती से तय करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इस बड़ी लड़ाई में हमें पहले उन सिद्धांतों को तय करना होगा जिनसे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, और बुर्जुआ और सोशलिस्ट पार्टियों के वोट पाने के तरीकों की नकल नहीं करनी चाहिए।

आर्थिक नीति

राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य जीवन की आवश्यक चीजें उपलब्ध कराना है, न कि कैपिटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा पक्का करना।

सीधे-सादे, सीधी-सादी सोच वाले लोगों को लग सकता है कि इस साफ़ बात को एक सिद्धांत के तौर पर बताना बेकार है। प्रोड्यूसर, किसान, कारीगर, मैन्युफैक्चरर के लिए यह आम बात है कि वह जो बनाता है, उसका इस्तेमाल या इस्तेमाल होता है — खुद उसके द्वारा या, व्यापार की चीज़ के तौर पर, दूसरे लोग।

उनकी नज़र में वह बिज़नेस जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन से जुड़ा नहीं है, वह है बेतुका, नामुमकिन, कॉमन सेंस के खिलाफ।

यह हमें हमारे भर्ती के काम में सबसे बड़ी दिमागी मुश्किलों में से एक पर लाता है। हमारे देश के लोग यह कहने के लिए मजबूर हैं: — बेशक, लेबर और इकोनॉमिक्स के मतलब और मकसद के बारे में सोचने में आपकी नैचुरल भावना बिल्कुल सही है, लेकिन बदकिस्मती से आज की हमारी सो-कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इस नैचुरल दावे का जवाब नहीं देती है। अगर आप करीब से देखेंगे, तो आपको वे भयानक बातें पता चलेंगी जो सभी नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के साफ कर्तव्य के बिल्कुल खिलाफ हैं।

लेकिन साहूकारों और मुनाफ़ाखोरों का क्या? क्या ये दुनिया भर के लुटेरे ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के बारे में सोचते हैं? नहीं! क्या वे वैल्यू बनाने में लगे हैं, क्या वे कुछ बनाते हैं? नहीं! वे आर्थिक तौर पर लुटेरे और देशद्रोही हैं, और सिर्फ़ अपने लिए दौलत जमा करते हैं।

बैंकों का क्या? वे पैसे सर्कुलेट करते हैं और 'क्रेडिट' देते हैं। हाँ; लेकिन पोस्ट ऑफिस यह काम करता है, और सस्ता, जल्दी और बेहतर तरीके से; और बैंक किसे क्रेडिट देते हैं? —

ज़रूरतमंद, मेहनतकश लोग, जिनके पास अपना घर नहीं है, या घर बनाने के लिए, रहने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए? नहीं! या किसानों को, या उन लोगों को जो बिज़नेस चलाते हैं और जो ज़रूरी आर्थिक चीज़ें बनाते और बांटते हैं? मुफ़्त में नहीं, और सिर्फ़ तभी जब सिक्योरिटी दी जाए, चुकाने के नैचुरल काम के अलावा; और तो और, वे ब्याज भी लेते हैं। क्या बैंकों को इस बात की परवाह है कि प्रोड्यूसर के कस्टमर को अच्छी, सस्ती और तुरंत सर्विस मिल रही है, या ज़रूरी आर्थिक चीज़ें जल्दी, सस्ती और ध्यान से मिल रही हैं? नहीं! उनका एक ही ख्याल है ब्याज, कमीशन, या पैसे की सप्लाई का इस्तेमाल करने के बैंकिंग प्रोसेस को जो भी कहते हैं, उससे अपना मुनाफ़ा कमाना। बैंक क्या बनाते हैं? कुछ नहीं! वे क्या कमाते हैं? बहुत ज़्यादा रकम।

इस तरह साहूकार, मुनाफ़ाखोर, बैंक, फाइनेंसर, कोई ज़रूरत पूरी नहीं करते, बल्कि वे मौजूदा कैपिटलिस्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं, — असल में वे आज के समाज-विरोधी आर्थिक सिस्टम पर ज़ुल्म करते हैं और उसका शोषण करते हैं। इकोनॉमिक्स का मुख्य काम यह देखना है कि लोन पर ब्याज सुरक्षित रहे, यानी मज़दूरों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा 'शहर' को देने के लिए मजबूर किया जाए। फैक्ट्री मालिक, या जैसा कि मज़दूर उसे कहते हैं, 'शोषक' और 'खून चूसने वाला' क्या करता है? सबसे कम मज़दूरी देकर, घटिया सामान इस्तेमाल करके, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके, एवरेजिंग करके, और ऊँची रिटेल कीमतों से, वह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करता है।

वह अपने कर्मचारियों की गरीबी के बारे में नहीं सोचता; उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसका सामान जल्दी से कचरे की तरह फेंक दिया जाए, — यह और भी अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है उसके लिए ज़्यादा काम और ज़्यादा मुनाफ़ा। बेवकूफ़ लोग सस्ते कचरे के पीछे बार-बार भागते हैं, अगर उसे अच्छे से दिखाया जाए।

उसके लिए उसकी पूंजी पर रिटर्न सबसे पहले आता है, और जीवन की ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करना उसके बाद आता है।

लेकिन वह कुछ तो करता है। वह काम देता है।

असली फैक्ट्री-मालिक कुछ अलग होता है, वह जो एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पर अपने बड़े काम के प्रति जागरूक होता है। उसमें नैतिक मूल्य होना चाहिए - कम से कम इकोनॉमिक अर्थ में।

उसका काम लोगों की असली आर्थिक ज़रूरतों का पता लगाना है — अगर वह एक इन्वेंटर भी है तो वह यह पायनियर काम खुद करता है। उसे अपनी लागत जितनी हो सके कम रखनी चाहिए और उन्हें सबसे अच्छे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने सामान को बाज़ार में लाने के लिए कीमतें जितनी हो सके कम रखनी चाहिए; प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बनाए रखनी चाहिए, अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ताकि वे आसानी से सामान खरीद सकें, हमेशा प्लांट और ट्रेडिंग के तरीकों में सुधार और रिन्यूअल के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह अपने बिज़नेस में इन सब चीज़ों को सबसे पहले रखता है, तो वह सबसे अच्छे और सबसे ऊँचे मतलब में 'ज़िंदगी की ज़रूरतों की सप्लाई' कर रहा है, और मुनाफ़ा अपने आप आएगा, बिना उन्हें अपना पहला मकसद बनाए। 'इस तरह के मैन्युफैक्चरर का सबसे अच्छा और सबसे जाना-माना उदाहरण हेनरी फोर्ड है। हमारी अपनी भारी इंडस्ट्रीज़ में और भी नाम हैं जो उतने ही ऊँचे हैं, —

क्रुप, किर्डोर्फ, एबे, मैनेसमैन, सीमेंस, और कई अन्य।

ऐसे बिज़नेस का कैरेक्टर तब बिल्कुल अलग होता है जब उन्हें पर्सनली अच्छे नैतिक गुणों वाले लोग कंट्रोल नहीं करते जो अपने वर्कर्स के हितों का ध्यान रखते हों, बल्कि उन्हें इंपर्सनल लिमिटेड कंपनियों को सौंप दिया जाता है।

जब तक किसी बिज़नेस का फाउंडर ही उसका चीफ शेयरहोल्डर भी होता है और अपने प्रोडक्ट्स का बेहतरीन स्टैंडर्ड बनाए रख सकता है, तब तक सब ठीक रहता है; लेकिन जैसे ही बदलाव होता है, कैपिटलिस्ट शेयरहोल्डर्स के फायदे उस पर हावी हो जाते हैं। पहले के मालिक, मैनेजर, अब बिज़नेस के तरीकों और काम करने के हालात में सुधार के लिए शेयरहोल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाले बोर्ड पर निर्भर रहते हैं, — और शेयरहोल्डर्स को वर्कर्स की भलाई और काम के बेहतरीन होने में (गुलाम-चालक के अलावा) कोई दिलचस्पी नहीं होती, जब तक

इससे मिलने वाला डिविडेंड अच्छा और बड़ा होता है। प्रोप्राइटरी शेयर्स के आने का बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि कोई भी सट्टेबाज शेयर्स पर कब्ज़ा कर सकता है और असल में बड़े इंडस्ट्रियल कामों का मालिक बन सकता है, बिना उनके बारे में कुछ जाने। स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टॉक्स और शेयर्स उनके खेलने के लिए बस एक कागज़ हैं। उन्हें प्रोडक्शन और लेबर के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनमें से ज़्यादातर यह नहीं बता सकते कि जिस बिज़नेस के वे कानूनन मालिक हैं, उसमें प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग, लेबर, सैलरी और मेंटेनेंस के हालात क्या हैं। (!) और वे असल में मालिक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मार्केट में इस या उस फैक्ट्री के शेयर्स पर कब्ज़ा कर लिया है।

आइए अब हम पॉलिटिकल इकॉनमी पर इसके असर की रोशनी में इस हालात की जांच करें, ताकि कैपिटलिस्ट सिस्टम के करप्ट कैरेक्टर को समझा जा सके।

आज बिज़नेस सिर्फ़ कैपिटल पर रिटर्न चाहता है।

बड़े रिटेल स्टोर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। वे 'अट्रैक्शन', 'ब्लफ़', 'अट्रैक्शन ...
'एवरेजिंग', 'लग्ज़री आइटम', और गैर-ज़रूरी चीज़ों की इच्छा जगाना, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया।

बड़े-बड़े महल, जो पूरी शान से बनाए गए हैं, सस्ते दिखने वाले, लेकिन ज़्यादातर बेकार सामान खरीदने के लिए बुलाते हैं, और पेमेंट की आसान शर्तें देकर वे अपने कस्टमर्स को सिर्फ़ लग्ज़री पर हर तरह के पैसे खर्च करने के लिए लुभाते हैं। रेस्ट-रूम इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग दुकानों में ज़्यादा समय बिता सकें, जो इस तरह सिर्फ़ फ़िज़ूलखर्ची का अड्डा बन जाते हैं, क्योंकि कोई यह न सोचे कि उसे तोहफ़े में कुछ मिला है। सच में अमीर लोग बड़ी दुकानों से कुछ नहीं खरीदते; वे जानते हैं जो गरीब नहीं जानता — जो सस्ता खरीदता है वह महंगा खरीदता है। क्या उन महलों में खरीदने वाली भीड़ यह सोचती है कि वे उनके बचाए हुए पैसों से नहीं बने थे? क्या उन्हें लगता है कि वे एस्केलेटर, लिफ़्ट, रेस्ट-रूम, परियों जैसी रोशनी के लिए पैसे देकर बच जाते हैं?

यह भी समझें कि बड़े स्टोर छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर देते हैं, वे घर पर काम करने वाले लोगों और अपने कर्मचारियों का बहुत बेरहमी से शोषण करते हैं, और जो कुछ भी बनता है वह ज़्यादातर कचरा होता है। अच्छी चीज़ें आमतौर पर अच्छी खास दुकानों से ज़्यादा महंगी होती हैं, यही बात बड़े स्टोर के खिलाफ हमारी लड़ाई को सही ठहराती है। हम उन्हें असल में कैपिटलिस्टिक सोच का एक खास रूप मानते हैं, जो ज़िंदगी की ज़रूरतें नहीं देता, बल्कि सिर्फ़ शेयरहोल्डर्स के लिए भारी मुनाफ़ा कमाने के मकसद से होता है।

ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों के इंतज़ाम की इस मुख्य सोच को देखते हुए (जिसका, हमें ध्यान देना चाहिए, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स स्कीम से कोई लेना-देना नहीं है), यह सवाल प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रति हमारे नज़रिए में सबसे ज़रूरी है।

8. नेशनल सोशलिज़्म प्रॉपर्टी के प्राइवेट मालिकाना हक को एक प्रिंसिपल मानता है और कानून से उसकी रक्षा करता है, — बशर्ते कि इसे इज्ज़त से हासिल किया जाए और इस्तेमाल किया जाए। हम यहाँ इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कोई भी 'काम' शब्द को ठीक से समझता है, वह जल्दी ही देख लेगा कि 'काम' का प्रोडक्ट उसी की प्रॉपर्टी होना चाहिए जो काम करता है। एक प्रोड्यूसर यह समझने में नाकाम रहेगा कि उसका काम, या उसकी कीमत, एक धुंधली 'कम्युनिटी' की प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, और न ही वह आसानी से यह मानेगा कि उसकी मेहनत का फल एक व्यक्ति, यानी कैपिटलिस्ट को मिलना चाहिए। इसलिए 'काम' के मतलब की सही समझ से नैचुरली प्राइवेट मालिकाना हक को पहचान मिलती है।

आखिर में एक और टॉपिक है — घर का कॉन्सेप्ट। घर तब तक असलियत नहीं है जब तक वह सच में किसी आदमी की अपनी प्रॉपर्टी न हो, और उसका अपना घर उसके अपने परिवार को पनाह देता हो। किसी आदमी के अपने बगीचे से उगाए गए फल और सब्ज़ियाँ, भीड़ भरे रेस्टोरेंट में खाए गए खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। जो कोई भी चीज़ों की चाहत या उनके होने की खुशी नहीं जानता, वह प्राइवेट ओनरशिप को पहचानने की अहमियत को नहीं समझ पाएगा। ऐसे आदमी की कहीं कोई जड़ नहीं होती, यह अजीब बात है कि

शिकार करने वाला आदमी हमेशा जलता रहता है, हमेशा कुछ नया पाने की कोशिश करता है, जबकि नॉर्डिक आदमी, ज़मीन का पक्का आदमी, अपने विचारों में बिल्कुल सीधा-सादा होता है। उसे अपने काम से जितना मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक मज़दूर ऐसा बढ़िया विला नहीं चाहता जिसे वह कभी कमा न सके; उसे अपना एक अच्छा सा छोटा घर चाहिए, किराए का नहीं जिसे बनाने में उसे अपनी ज़िंदगी में घर की कीमत से तीन या चार गुना ज़्यादा देना पड़े। लेकिन यहूदी, कैपिटलिस्ट, — वह किसी ज़मीन के टुकड़े से बंधा नहीं रहना चाहता; उसका आदर्श एक बड़ी तिजोरी है जिसमें स्क्रिप, मॉर्गेज डीड और प्रॉमिसरी नोट्स भरे हों। उसका मकसद दौलत है, प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि दूसरों की मॉर्गेज प्रॉपर्टी में। वह काम नहीं करता, लेकिन जब तक उसके पास बॉन्ड के बंडल जमा नहीं हो जाते, जो उसे उन सभी पर कंट्रोल करने में मदद करें जिन्हें उसने पैसे उधार दिए हैं, तब तक वह चैन से नहीं बैठता। हमारे प्रोग्राम की अगली मांग इसे रोकने के लिए बनाई गई है।

9. देश की भलाई के लिए यह ज़रूरी है कि धन इकट्ठा करने की एक सीमा तय की जाए।
व्यक्तियों के हाथों में।

दौलत अपने आप में नुकसानदायक नहीं है; इसके उलट, अगर चीज़ों का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो उन सभी का भला होता है जो उनसे जुड़े होते हैं। लेकिन फिर, यह लोन का कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसने दौलत को वरदान से श्राप में बदल दिया है; यह लूट है। बिना दौलत वाले मज़दूरों का बड़ा ग्रुप 40 और कर्ज़ में डूबा मिडिल क्लास अमीरों से और दूर होता जा रहा है; अनगिनत छोटे मालिकों पर कर्ज़ का बोझ डाला जा रहा है, और फाइनेंसरों की ताकत, जिन्हें न तो अपनी जन्मभूमि पता है, न ही अपना घर, और भी खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि वे अपने आज के लुटेरे-बैरन महलों, यानी बैंकों में बैठे हैं। इससे निपटने के लिए, नेशनल स्टेट को यह देखना होगा कि:

10. सभी जर्मनों को एक काम करने वाले समुदाय में शामिल किया जाएगा ताकि
आम कल्याण और संस्कृति।

काम की कम्युनिटी का यह आइडिया समाज की यूनिवर्सल सोच को आर्थिक रूप से खत्म करने जैसा है। सभी काम और प्रोडक्शन को कम्युनिटी की सेवा के ऊंचे आइडिया में शामिल किया जाना चाहिए। यह किसी भी तरह से पर्सनल कोशिश और मेहनत के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि पर्सनल तरक्की अपने साथी इंसानों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। नीचे दिया गया पॉइंट इस मांग को दिखाता है।

11. हर जर्मन से जुड़े काम के आम कर्तव्य के दायरे में, और प्राइवेट मालिकी को एक सिद्धांत के तौर पर मान्यता देते हुए, हर जर्मन अपनी मर्ज़ी से कमाने और अपनी मेहनत के नतीजों को इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद होगा।

ऊपर बताई गई बातें मार्क्सवाद की सोशलाइज़िंग स्कीम और हाई फाइनेंस को साफ़ तौर पर खारिज करती हैं। राज्य में सर्विस के सोशल आइडिया से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी शामिल होगी। — बेशक, छोटे पैमाने पर खदानें, ब्लास्ट-फर्नेस, रोलिंग मिल, शिप-यार्ड चलाना तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एक लाख आज़ाद और इंडिपेंडेंट मास्टर-शूमेकर पाँच बड़ी जूता फैक्ट्रियों से बेहतर हैं।

जर्मनी के नॉर्थ और ईस्ट में बड़ी ज़मीनें छोटे फ्रीहोल्ड किसानों के मैनेज करने के बजाय बड़े लेवल पर चलाने पर ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। छोटे फ्रीहोल्ड तब सबसे अच्छे होते हैं जब वे कस्बों और गांवों के पास हों। हमारा अगला पॉइंट यह है कि:

12. खेती-बाड़ी समेत सभी तरह के बड़े और छोटे बिज़नेस का एक अच्छा मेल,
बनाए रखा जाएगा।

13. बड़े बिज़नेस (सिंडिकेट, ट्रस्ट) नेशनलाइज़ किए जाते हैं। यह मांग कैपिटलिस्टिक सोच के खिलाफ़ हमारे आम संघर्ष से मेल खाती है। — प्रोडक्शन की किसी भी खास ब्रांच में सिंडिकेट और ट्रस्ट का पहला मकसद दूसरे मिलते-जुलते बिज़नेस के साथ एक होना होता है।

कीमतें तय करने के मकसद से। वे सस्ते दाम पर अच्छा सामान बांटने की किसी इच्छा से नहीं चलते। ऐसे 'रिंग्स' खास तौर पर नए बिज़नेस की तरफ खिंचते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह के बिज़नेस में नई फर्मों को खरीद लिया जाता है और रास्ते से हटा दिया जाता है, अक्सर मुआवज़े के तौर पर बहुत बड़ी कीमत पर। सप्लाई को पूलिंग से रेगुलेट किया जाता है, जिसका मतलब है कि वे असली 'सप्लाई और डिमांड' के हिसाब से कीमतें रेगुलेट कर पाते हैं। यही बात शेयरहोल्डर्स को परेशान करती है, जो कॉम्पिटिशन से कीमतें कम नहीं देखना चाहते। नए आइडिया और इन्वेंशन को बुरी नज़र से देखा जाता है, और बेहतर होगा कि उन्हें दबा दिया जाए अगर उन्हें अपनाने से पुराने प्लांट की पेमेंट कैपेसिटी को खतरा हो। ऐसे बिज़नेस, जो एक बड़े सेंट्रल ऑफिस से बड़े ट्रस्ट के तौर पर चलते हैं, साफ तौर पर 'सोशलाइज़ेशन के लिए तैयार' हैं, यानी उन्होंने कम्युनिटी को वे सभी सर्विस देना बंद कर दिया है जो अलग-अलग कॉम्पिटिशन करते हैं। वे शुरू से ही पैरालाइज्ड हैं और सिर्फ कैपिटलिज़्म के लालच को पूरा करते हैं।

14. सूदखोरों और मुनाफाखोरों, और देश की कीमत पर बेरहमी से खुद को अमीर बनाने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी।

कानून, जैसा कि अभी है, लोगों की प्रॉपर्टी को खास सुरक्षा देता है। छोटी चोरियों के लिए इंसानियत के खिलाफ सज़ा दी जाती है, जबकि कानून बड़े पैमाने पर ठगी करने वालों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं बताता, जो 'कैपिटलिस्टिक तरीकों' से पूरे देश को लूटते हैं। हम खासकर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने महंगाई को बढ़ावा दिया और उससे फायदा उठाया। इतिहास में यह पहली बार था कि जर्मनी में हुए बड़े पैमाने पर महंगाई के जुर्म में एक पूरे मेहनती देश की सारी बचत लूट ली गई।

स्टेबिलाइज़ेशन के बाद बैंकों का लालच हाईवे पर होने वाली डकैती से भी बुरा था। किसी ऑर्गनाइज़्ड लुटेरे गिरोह के मुकाबले ज़्यादा जर्मन 'वॉर कंपनियों' के तरीकों का शिकार हुए।

जब समय आएगा तो हम इन चीज़ों पर और डिटेल में बात करेंगे और इनके लिए कोई लीगल फ़ॉर्मूला ढूंढेंगे। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत होगा कि 'देश के ख़िलाफ़ ऑर्गनाइज़्ड फ्रॉड' को पैसे की छोटी-मोटी चोरी या फ्रॉड से भी ज़्यादा सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए।

15. हर जर्मन के लिए एक साल की मेहनत या सेवा की शुरुआत।

काम करके सेवा करने की ज़िम्मेदारी, सेवा के फ़र्ज़ को जनता के सामने साफ़ तौर पर दिखाएगी। इसका मकसद सिखाना है, और हर जर्मन के सामने पूरे समुदाय के एक साथ मिलकर काम करने का एक उदाहरण रखना है। यह हर जर्मन को देश की सेवा के लिए काम करने में फ़र्ज़ को पूरी तरह से निभाने का आशीर्वाद दिखाएगा।

वित्तीय नीति

ब्याज की जकड़न को तोड़ना।

इस विषय पर हमारे सिद्धांत दूसरे चैप्टर में इतने अच्छे से बताए गए हैं कि हम हम यहां सिर्फ़ उन उपायों के बारे में बताएंगे जो असल में हमारे मकसद को पाने के लिए सही हैं।

16. राज्य और इस तरह देश को उसके कर्ज़ और बड़े फाइनेंशियल घरानों को ब्याज देने की ज़िम्मेदारी से आज़ादी।

राज्य कोई कर्ज़ नहीं ले सकता — क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य और उस आम आदमी के बीच कोई तुलना नहीं है जिसे कभी-कभी कर्ज़ की ज़रूरत होती है और वह कर्ज़ लेने के लिए मजबूर होता है। राज्य मिंट को कंट्रोल करता है; इस तरह वह पैसा बना सकता है, जो आम आदमी नहीं कर सकता! उसने यह पागलपन भरे तरीके से किया:

महंगाई के दौरान। इसने रेंटेनमार्क के साथ भी ऐसा ही किया, और तथाकथित राइशबैंक को अपना कंट्रोल सौंपने के बाद, तथाकथित राइशमार्क के साथ भी ऐसा ही किया।

सरकार पैसे कमाने के इस अधिकार का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकती है, बिना महंगाई के खतरे के। — लेकिन सिर्फ़ तभी जब पहले:

17. राइशबैंक और सभी जारी करने वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और

18. अगर सभी बड़े पब्लिक कामों (पानी-बिजली, रेलरोड, वगैरह) के लिए पैसे का इंतज़ाम लोन से नहीं, बल्कि बिना ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड देकर, या बिना तैयार पैसे के किया जाए।

दूसरे शब्दों में: — बिना नई वैल्यू बनाए, बैंक नोटों की बेतहाशा छपाई का मतलब है महंगाई। हम सबने इसे देखा है। लेकिन सही नतीजा यह है कि अगर सरकार बिना ब्याज वाले बॉन्ड जारी करती है, तो महंगाई नहीं हो सकती, अगर उसी समय नई वैल्यू भी बनाई जा रही हों।

यह बात कि आज बड़े आर्थिक काम बिना लोन लिए शुरू नहीं किए जा सकते, सरासर पागलपन है। यहीं पर राज्य के पैसे बनाने के अधिकार का सही इस्तेमाल होता है जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नतीजे मिल सकते हैं।

यह बात किसी को भी साफ़ पता होनी चाहिए कि, उदाहरण के लिए, पानी से चलने वाली बिजली का इस्तेमाल करने वाला एक बड़ा बिजली प्लांट इस आसान तरीके से बनाया जा सकता है:

सरकार सभी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके बवेरिया, सैक्सनी वगैरह की पानी की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पेश करती है। लोकल डाइट या कोई दूसरी बॉडी, कंस्ट्रक्शन का फैसला करती है, फाइनेंस मिनिस्टर या स्टेट बैंक को बैंक नोटों की एक सीरीज़ जारी करने का अधिकार देती है, जिन पर खास तौर पर यह दिखाने के लिए निशान होता है कि वे सोचे जा रहे नए कामों से पूरी तरह कवर हैं। इन नोटों को स्टेट या राइख के मिले-जुले क्रेडिट से सपोर्ट मिलता है। महंगाई के मामले में कोई भी कोई एतराज़ नहीं दिखा सकता। कंस्ट्रक्शन देश को रिप्रेजेंट करने वाली काउंसिल द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा क्रेडिट पर होता है, और नोट बाकी नोटों की तरह लीगल टेंडर बन जाते हैं।

जब काम पूरा हो जाता है, तो इस पैसे से कस्टमर्स को नाइट्रेट या बिजली दी जाती है, और कुछ सालों में इस इश्यू को वापस मंगाकर खत्म किया जा सकता है। नतीजा: राज्य, देश ने एक नया काम शुरू किया है, जिससे उन्हें रेवेन्यू का एक बड़ा नया सोर्स मिला है, और देश इससे और अमीर हुआ है।

मौजूदा सिस्टम की बेवकूफी को साबित करने के लिए, आइए हम ऊपर बताई गई बातों की तुलना मौजूदा सिस्टम से करें।
अब चालू।

लोन लिया जाता है। कुछ कैपिटलिस्ट वो करते हैं जो पूरा देश, भले ही पार्लियामेंट उसके पक्ष में वोट करे, नहीं कर सकता; वे स्टेट को उनसे पैसे उधार लेने देते हैं। देश के फायदे के लिए अपनी सीधी अथॉरिटी का इस्तेमाल करने के बजाय, स्टेट कुछ काम पूरा करने के लिए ज़रूरी रकम पर परमानेंट इंटरेस्ट देने का वादा करता है, जिससे उसके गले में चक्की का पत्थर लटक जाता है। और, जो सबसे महंगा है, वह बॉन्ड जारी करता है जिससे 'नई खरीदने की कैपेसिटी' बनती है। बैलेंस शीट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया काम नए पेपर मनी से दिखाया गया है या नए बॉन्ड से।

लेकिन कम्युनिटी को नुकसान होता है क्योंकि बॉन्ड का मतलब है कि नया काम कैपिटल के पास गिरवी रखा गया है, जो नैचुरली खुद को काफी सिक्योर बनाता है, कीमतें तय करता है, और प्रॉफिट लेता है। इस तरह, असल में फाइनेंसर ही देश की वॉटर-पावर के डेवलपमेंट से अमीर होते हैं; उन्हें रीपेमेंट की कोई परवाह नहीं होती; उन्हें परमानेंट दूध देने वाली गायों जैसी मोनोपॉली पसंद है। आबादी मजबूर है।

बिजली के करंट या नाइट्रेट के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और एक बार फिर देश की संपत्ति का एक हिस्सा फाइनेंसरों के फायदे के लिए बदल दिया जाता है।

मुझे पढ़ने वालों को अपनी पिछली किताबें, खासकर डेर ड्यूश स्टैट, दिखानी चाहिए, जिसमें इन सवालों पर इस पैम्फलेट में जितना हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में बात की गई है। इसके अलावा, इस सीरीज़ के कई नंबर आने वाले सरकार के पैसे बनाने के नए तरीकों के अलग-अलग खास पहलुओं से जुड़े हैं।

19. हम सिक्कों के एक तय स्टैंडर्ड की मांग करते हैं। माना कि अब हमारे पास वह है, लेकिन लूट पहले जैसी ही है। हम नेशनल सोशलिस्ट्स के पास, एक बार जब हम सत्ता में आए, तो महंगाई की धोखाधड़ी को तुरंत खत्म करने और सिक्कों के एक नए गारंटीड स्टैंडर्ड को लाने के लिए सब कुछ तैयार था।

20. विकास और अर्थव्यवस्था के लिए एक नए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना।

इस मांग को नेशनल सोशलिस्ट लाइब्रेरी के पैम्फलेट 8 में विस्तार से समझाया गया है: Die Wohnungsnot und die Sociale Bau - und Wirtschaftsbank als Retterin aus Wohnungselend, Wirtschaftskrise und Erwerbs1osene1end. यह ध्यान देने वाली बात है कि फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए हमारी यह मांग हमारे अपने हलकों के अलावा दूसरे राजनीतिक हलकों में भी गहराई तक पहुंच गई है।

1921 में मैंने यह मांग बवेरियन सरकार के सामने एक पूरी तरह से तैयार बिल के रूप में रखी। शुरू में इस विचार से बहुत सहानुभूति थी: लेकिन एक बार जब 'एक्सपर्ट्स' – बैंकिंग बिरादरी – से सलाह ली गई, तो सरकार ने 'फेडर के यूटोपिया' को अस्वीकार कर दिया।

फरवरी 1921 में थुरिंगिया में सफल चुनाव के बाद, वहां के लैंडटैग में हमारी पार्टी ने ऐसा बैंक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और पाया कि फाइनेंस मिनिस्टर वॉन क्लुच्ट्ज़नर सहयोग करने के लिए तैयार थे; पूंजीपति वर्ग भी इससे सहमत था। लैंडटैग में बहुमत से सरकार को विकास और अर्थव्यवस्था के लिए एक सोशल बैंक बनाने का अधिकार मिला। इसके बाद, राइख्सबैंक के दबाव में राइख की सरकार ने लोगों की इच्छा पूरी करने पर रोक लगा दी।

इस बीच, मैं राइखस्टाग में एक बिल पेश करवाने में कामयाब रहा, जिसमें अलग-अलग राज्यों में ऐसे ही बैंकों का इंतज़ाम था; लेकिन, डावेस साल (1924) के छोटे सेशन में, सरकारी पार्टियों ने इसे सावधानी से उस साल के पतझड़ में भंग होने तक टाल दिया।

बैंक के लिए एक बिल मेक्लेनबर्ग के लैंडटैग के सामने था। जर्मन राष्ट्रवादी फाइनेंस मिनिस्टर के ढुलमुल रवैये की वजह से यह प्रस्ताव बेअसर हो गया, साथ ही राइक्सबैंक से रास्ते में आने वाली रुकावटों की वजह से भी।

डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाने का आइडिया, बड़े पब्लिक कामों के लिए पैसा बनाने के ऊपर बताए गए प्लान से कम आसान नहीं है।

एक कंबाइंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जैसे कि बैंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट के लिए पैसे जारी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए (बॉमार्क-शेनन), जो नए बने घरों की कीमत से कवर होगा। फिर इन्हें ब्याज के भारी बोझ से मुक्त होकर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से आज काफी मात्रा में घर बनाना नामुमकिन है।

हर जर्मन का अपना घर है। बिना किसी बंधन वाली ज़मीन पर आज़ाद लोग।

21. सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर टैक्सेशन सिस्टम की पूरी री-मॉडलिंग। कंज्यूमर को इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बोझ से और प्रोड्यूसर को उन टैक्स से मुक्ति दिलाना जो उसके कामों में रुकावट डालते हैं।

सामाजिक नीति

सोशल पॉलिसी हमारी आजकल की पॉलिटिकल क्योर-ऑल का पसंदीदा मोटो है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पॉपुलर बनाता है, और उस पार्टी के लिए वोट खींचता है जो सब कुछ ठीक करने का वादा करती है।

जब हर पार्टी किसी अधिकारी से, उदाहरण के लिए, सैलरी बढ़ाने का वादा करती है, तो वे उसे सोशल पॉलिसी कहते हैं।

ऐसा ही तब भी होता है जब वे क्लर्कों और मज़दूरों की इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं; या जब वे कम इनकम वाले लोगों, या युद्ध से जूझ रहे लोगों, या युवा टीचरों, या विदेश में रहने वाले जर्मन लोगों की मदद के लिए थोड़ा-बहुत करते हैं।

और जब ये पॉलिटिकल चूहे पकड़ने वाले अपनी 'सोशल' बांसुरी बजाते हैं, तो सारे लोग उनके पीछे भागते हैं ।

सबसे पहले यह साफ़ कर देना चाहिए कि सोशल पॉलिसी का मतलब है, लोगों की भलाई सबसे बड़ा कानून, और जैसा कि अब समझा जा रहा है, सोशल पॉलिसी असल में अपने फ़ायदे के लिए है, जिसमें आम भलाई का कोई ध्यान नहीं है। हर तरह के लापरवाही भरे वादे किए जाते हैं, और जो लोग उन्हें करते हैं, उन्हें शुरू से ही पता होना चाहिए कि उन्हें पूरा करना नामुमकिन है।

अब जब जर्मनी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो गया है — जिसका असर पहले डावेस लॉज़ और अब यंग लॉ में दिखता है, और तथाकथित फुलफिलमेंट पॉलिसी में भी, जिसने हमारे देश पर बोझ डाल दिया है, जिससे ज़िंदगी लगभग नामुमकिन हो गई है — तो 'सोशल पॉलिसी' के बारे में बात करना झूठ और मज़ाकिया दोनों है। अब जब जर्मनी की ज़िंदगी इतनी तंग हो गई है, जब हर आदमी अपने पड़ोसी पर हावी हो रहा है और उससे आगे निकलने और उसे किनारे करने की कोशिश कर रहा है, जब आबादी के अलग-अलग क्लास में मतभेद हैं, तो एक ग्रुप को दूसरे की कीमत पर फ़ायदा पहुँचाने के वादे 'आम भलाई के लिए सोशल पॉलिसी' नहीं हैं, बल्कि एक क्लास को दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने वाले हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ समय के लिए हुआ 'सुधार' ज़्यादा महंगाई और ज़्यादा टैक्स से खत्म हो जाता है।

सामाजिक नीति का अर्थ कुछ बहुत अलग है - सामाजिक समस्या को हल करने का दृढ़ संकल्प।

बदकिस्मत, शोषित मज़दूर वर्ग का मानना है कि उनका सही वेतन, उनका उचित
सामाजिक व्यवस्था में उनसे उनका स्थान छीना जा रहा है - इसलिए कै1स युद्ध।

यह सभी को साफ़ है कि हमारी आर्थिक ज़िंदगी गहरी चोटों से जूझ रही है; कड़वे अन्याय से।
और फिर भी मार्क्सवाद अपने 'क्लास वॉर' और अपनी 'सोशल और इकोनॉमिक मांगों' जैसे 'एक्सप्रोप्रिएटर को एक्सप्रोप्रिएट करना' और 'सोशलाइज़ेशन' के ज़रिए जो नतीजे निकालता है, वे पूरी तरह से झूठे हैं, क्योंकि यह एक असली सोशल पॉलिसी की सभी असली ज़रूरतों पर चोट करता है, जिसका सबसे बड़ा नियम आम भलाई है।

क्लास वॉर का मुख्य सिद्धांत — पॉलिसी के सिद्धांत के तौर पर — नफ़रत है। 'एक्सप्रोप्रिएटर का एक्सप्रोप्रिएटेशन' जलन को इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बनाता है, और 'सोशलाइज़ेशन' का मतलब है लीडरशिप में पर्सनैलिटी को खत्म करना, और समझदारी और एफिशिएंसी की जगह मैटेरियलिज़्म, यानी मास को स्थापित करना।

---

2 हैमेलन के पाइड पाइपर का एक संकेत।

मार्क्सवादी सिद्धांतों के पूरी तरह से टूटने को साबित करने के लिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से दिवालिया हो गया है और 1918 की जर्मन क्रांति बुरी तरह फेल हो गई है।

मैं अपने पढ़ने वालों का खास ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि मार्क्सवाद से पैदा हुआ यह नकली समाजवाद, न तो कॉमन सेंस पर आधारित है और न ही किसी 'सोशल' आइडिया पर, यह कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल सोच की सबसे निचली गहराइयों में डूबा हुआ है, कि यह उसी आम उसूल पर टिका है जो बेकार और अस्त-व्यस्त व्यक्तिवाद का है, जैसा कि हम हमेशा से जानते आए हैं। यह सिर्फ कुछ लोगों का मानना है, जो देश के दूसरे आधे हिस्से के खिलाफ नफरत और जलन की भावनाओं से एकजुट हैं — किसी कंस्ट्रक्टिव मकसद से नहीं। क्या हमें हैरानी हो सकती है कि सामाजिक सवाल इस तरीके से हल नहीं हो सकता, और न ही हो सकता है, और उनका एकमात्र हल नफरत और लूट की इच्छा है; कि मार्क्सवादी स्टॉक एक्सचेंज विद्रोह से एक जीता-जागता देश नहीं बन सकता, बल्कि सिर्फ खंडहरों का ढेर बन सकता है।

एक बार फिर नेशनल सोशलिज़्म को सही शब्द मिला: स्टॉक एक्सचेंज विद्रोह। मार्क्सवाद कैपिटलिस्ट देशद्रोह का एक रूप है। कैपिटलिस्ट, क्योंकि जब इंडिविजुअलिज़्म पर बना समाज अराजकता में गिर जाता है, तो वह ज़रूरी तौर पर बड़े फाइनेंशियल टाइकून के असर में आ जाता है।

सोशल-पॉलिटिकल थ्योरी, जो 'एंटी-कैपिटलिस्टिक' (मार्क्सवाद, क्लास के बीच युद्ध) होने का दिखावा करती हैं — आज की सोशल पॉलिसी — ज़रूरी तौर पर कैपिटलिस्टिक हैं, क्योंकि वे एक ही इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल शेयर करती हैं। उनकी इच्छा यह नहीं है कि वे एक-एक सदस्य को ऑर्गेनिकली बनाएं, नेशनल यूनिटी के ऊंचे कॉन्सेप्ट के तहत काम करने वाले अलग-अलग क्लास को बहुत ध्यान से जोड़ें, बल्कि उनकी ख्वाहिशें पूरी तरह से मतलबी हैं, उनकी इच्छा दूसरों की परवाह किए बिना अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की है।

कैपिटलिज़्म और मार्क्सिज़्म एक ही हैं! वे एक ही इंटेलेक्चुअल स्टेम पर उगते हैं।
उनमें और हममें, जो उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। समाज बनाने का हमारा पूरा आइडिया उनसे बहुत अलग है। यह न तो क्लास-स्ट्रगल है और न ही क्लास-सेल्फ़िशनेस, बल्कि — हमारा मुख्य नियम आम भलाई है।

22. लाइफ-एन्युइटी को नेशनलाइज़ करके ओल्ड एज इंश्योरेंस में बड़ा डेवलपमेंट। जर्मन देश के हर सदस्य को एक तय उम्र होने पर, और उस उम्र से पहले अगर वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है, तो उसे गुज़ारे के लिए काफ़ी पैसे मिलेंगे।

यही सामाजिक समस्या का समाधान है।

मज़दूरी, सैलरी और इनकम से सीधे तौर पर नाराज़गी उतनी सोशल टेंशन की वजह नहीं है, जितनी अनिश्चितता, एक आदमी की अपने बाद के सालों को लेकर चिंता, कि कहीं वह सड़कों पर न आ जाए। यही वह बेचैनी है जो अलग-अलग कामों को मार्क्सवादी और कैपिटलिस्ट टाइप के दिखावटी सोशल ऑर्गनाइज़ेशन में एक साथ आने के लिए मजबूर करती है और मालिक और कर्मचारी के बीच दुश्मनी को और बढ़ाती है। यह दोनों तरफ की सबसे बुरी सोच को बाहर निकालती है, और नतीजा आपसी दुश्मनी होता है। मज़दूर की ज़िंदगी का सही मकसद मज़दूरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की लड़ाई में खत्म हो जाता है, और उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि सोशल पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद बुज़ुर्गों के लिए सही इंतज़ाम होना चाहिए।

आयु।

हम एक बार फिर देखते हैं कि कैसे राज्य ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए इंतज़ाम करके उनके लिए एक अच्छा और तारीफ़ के काबिल हल निकाला। यह इनकम के कैपिटलिस्ट आइडियल का सही और अच्छा हल है, यानी इसे पर्सनल मेहनत और एफिशिएंसी पर आधारित, इंतज़ाम के असली राज्य के आइडियल में बदलना।

आम भलाई के इस स्टैंडर्ड को हासिल करना नेशनल सोशलिज़्म का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मकसद होगा।

23. सभी के लिए प्रॉफ़िट शेयरिंग।

NSDAP खुद को इस मांग से जोड़ता है। असल में यह शब्द के सही मतलब में पूरी तरह से सोशलिस्ट मांग है; फिर भी, यह हमारे पास कैपिटलिज़्म की तरफ से एक आकर्षक लेकिन भ्रष्ट करने वाला तोहफ़ा बनकर आता है।

दूसरों के काम से होने वाले मुनाफ़े को बाँटना, बिना कमाई की इनकम के कैटेगरी में आता है, जिस पर नेशनल सोशलिज़्म सबसे ज़्यादा हमला करता है। किसी आदमी के अपने काम से होने वाले मुनाफ़े को बाँटना एक ऐसी मांग है जो इतनी नैचुरल और सामाजिक रूप से इतनी सही है कि इसके खिलाफ़ कोई भी बात एक सिद्धांत के तौर पर नहीं कही जा सकती।

इसे करने में ही मुश्किल आती है, यानी वर्कर के प्रोडक्शन, स्किल और मेहनत की वजह से हिस्से की रकम को लिमिट करना, और इन्वेंटर, अकाउंटेंट, व्यापारी, मैनेजमेंट और बिज़नेस से जुड़े दूसरे हालात की वजह से हिस्से की रकम को लिमिट करना।

यह ज़रूर बहुत ज़रूरी है कि जो लोग किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज़ न किया जाए। मौजूदा सिस्टम में भी, कैपिटल को बिज़नेस से जो लूट मिलने की उम्मीद होती है, उसका कुछ हिस्सा वर्कर को वापस मिल सकता है।

हम यहां इस सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे कि बाद में नेशनल सोशलिस्ट स्टेट इस समस्या का समाधान कैसे करेगा।

मैंने खुद सोचा कि कीमतों में आम कमी करना, और साथ ही मज़दूरी को मौजूदा लेवल पर बनाए रखना, हमारे पूरे नेशनल प्रोडक्शन के मुनाफ़े को बांटने की मांग को पूरा करने का बेहतर और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका होगा।

लेकिन, यह हो सकता है कि नेशनल सोशलिस्ट स्टेट इस समस्या को मार्क्सवादी और कैपिटलिस्टिक सोच वाले लोगों की आज की सोच से कहीं ज़्यादा बड़े तरीके से हल करेगा। प्रॉफ़िट-शेयरिंग की मौजूदा मांग या तो प्रॉफ़िट की चाहत (असल में कैपिटलिस्टिक) से, या जलन (असल में मार्क्सवादी) से पैदा होती है।

सिर्फ़ आइडियल स्टेट में, जैसा हम सोचते हैं, यह सही है, क्योंकि जब हम इसे हल करने की बात करते हैं, तो हमें बिज़नेस में छोटा हिस्सा देने के कैपिटलिस्टिक तरीके से बचना चाहिए, जिसका एकमात्र मकसद बड़े शेयरहोल्डर्स के लिए उनके डिविडेंड पर उनका अधिकार पक्का करना है, और जलन के मार्क्सवादी विचार से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह पर्सनल फैक्टर को कमज़ोर करता है और आम जनता को नुकसान पहुँचाता है।

साफ़-साफ़ समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

जूते की फैक्ट्री में 'प्रॉफिट-शेयरिंग' करने वाले मज़दूरों को बिज़नेस में कुछ शेयर या छोटा सा बोनस या कॉस्ट प्राइस पर एक जोड़ी जूते मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर उन्हें अपनी शर्ट, सूट, मोज़े, खाने-पीने की चीज़ों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि दर्जी, बेकर और शराब बनाने वाले अपने 'प्रॉफिट-शेयरिंग' से कपड़ा बेचने वालों, बेकरी और शराब बनाने वालों का लालच पूरा करते हैं।

कीमतें कम करना ही वह आकर्षण है जिससे देश के हर सदस्य को राष्ट्रीय उत्पादन के मुनाफ़े में हिस्सा मिलना चाहिए।

अगर सड़क पर झाड़ू लगाने वाले, दिहाड़ी मज़दूर, रेलवे वाले, पोस्टमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हॉस्पिटल वर्कर – ये तो बस कुछ नाम हैं – खेतिहर मज़दूर, माइनर, बिल्डर, मज़दूर, को प्रॉफ़िट शेयरिंग से बाहर रखा जाए, तो यह एक असली नेशनल सोशलिस्ट की सोशल जस्टिस की भावना को पूरा नहीं करेगा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये क्लास वैल्यू बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देते। साथ ही, खेती के बारे में (जिसमें सिर्फ़ खेती की डिटेल्स पर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े दूसरे बिज़नेस में लगे लाखों लोगों पर भी विचार करना होगा) यह कहना होगा कि यह उन सालों में 'पेस' करती है जब फ़सल अच्छी होती है; भारी इंडस्ट्रीज़ में भी, दुनिया भर में कॉम्पिटिशन के दबाव के कारण खदानों से सिर्फ़ मामूली प्रॉफ़िट मिलता है।

क्या हम यह कह सकते हैं कि ये लाखों वर्कर और कर्मचारी, जो अक्सर इंडस्ट्री की सबसे ज़रूरी ब्रांच में लगे होते हैं, लेकिन हालात की वजह से, प्रॉफिट में सीधे हिस्से की उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें उस बड़े क्लास से कम तवज्जो मिलनी चाहिए, जो शायद नाइट क्लब या टर्किश बाथ में कपड़े धोने या कुली का काम करते हैं, या किसी ऑप्टिकल या केमिकल फैक्ट्री में मोनोपॉली का मज़ा लेते हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं? क्या बाद वाले लग्ज़री प्रोडक्शन पर प्रॉफिट और डिविडेंड में हिस्सा लेंगे, तो क्या वे देश के ज़्यादातर लोगों के लिए इन फायदों को पाना और भी नामुमकिन बना देंगे?

हम उन मज़दूरों और अफ़सरों पर बरस रहे डिविडेंड, बोनस, क्रिसमस गिफ़्ट और पैसों की बारिश के बारे में सोचना पसंद करते हैं, जिन्होंने सालों तक किसी बिज़नेस के लिए शानदार काम किया है। इस आम सिद्धांतों पर लिखी किताब में सामाजिक-राजनीतिक तरह की ऐसी उम्मीदों पर चर्चा और बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी अभी चीज़ें हैं, यह एक ज़रूरी मांग है, और इसे मानने वालों को आकर्षित करना चाहिए। 'मुनाफ़ा' मुख्य रूप से बिज़नेस की आम स्थिति और मैनेजमेंट की टेक्निकल स्किल और सेल्समैनशिप पर निर्भर करता है; नाकामी खराब कंस्ट्रक्शन या कैलकुलेशन में गलती से हो सकती है। मज़दूर कितने भी काबिल हों, कितने भी मेहनती हों, साल भर के काम के नतीजों पर, या फ़ायदे या नुकसान पर उनका बहुत कम या कोई असर नहीं हो सकता।

उनकी काबिलियत उन्हें सही और काफ़ी सैलरी मांगने के लिए सही ठहराती है, लेकिन प्रॉफ़िट में हिस्सा मांगने का कोई नैतिक या आर्थिक आधार नहीं है। वे इस सुझाव का बिल्कुल विरोध करेंगे कि उन्हें बिज़नेस साल के किसी भी नुकसान को अपनी सेविंग्स से पूरा करना चाहिए; वे डायरेक्टर्स के खराब मैनेजमेंट या फ़िज़ूलखर्ची वाली ज़िंदगी की भरपाई सैलरी कम करके करने की उम्मीद किए जाने का भी सही विरोध करेंगे। लेकिन 'प्रॉफ़िट-शेयरिंग' तभी सही है जब रिस्क और नुकसान को शेयर करने की काबिलियत और तैयारी हो, या अगर खास काबिलियत इसके लायक हो।

यहाँ सामान्य प्रॉफ़िट-शेयरिंग का एक पहलू है।

उदाहरण के लिए, जर्मनी के बड़े रंग कारखाने, जिनकी मोनोपॉली ज़्यादातर है, वे IG Farbenindustrie के शेयरहोल्डर्स के लिए सिर्फ़ एक कैपिटलिस्टिक दूध देने वाली गाय क्यों बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा, कीमतें बढ़ाकर, अपने मज़दूरों और अधिकारियों को मुनाफ़े में हिस्सा क्यों दें?

नेशनल सोशलिस्ट स्टेट का यह काम होगा कि वह यह देखे कि कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी करके मोनोपॉलिस्ट का बड़ा मुनाफ़ा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

यह साफ़ है कि समस्या सोशल पॉलिसी का सवाल नहीं है, बल्कि आज के कैपिटलिस्टिक सोशल सिस्टम (शेयरहोल्डर्स के दावे) से गहराई से जुड़ी हुई है।

हम इन बताए गए सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं; और इनसे गाइड होकर उन सभी बिज़नेस में प्रॉफ़िट-शेयरिंग को जितना हो सके बड़े पैमाने पर करने का अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, जिनमें प्रॉफ़िट सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल फ़ाइनेंसर की जेब में जाता है।

24. ईमानदारी से काम करके नहीं, बल्कि युद्ध, क्रांति से कमाए गए सभी मुनाफ़े को ज़ब्त करना — और इसके अलावा — मार्क का स्थिरीकरण और पुनर्मूल्यांकन; साथ ही, साहूकारों और हड़पने वालों की संपत्ति।

यह सज़ा और न्याय का एक तरीका है, जिसके लिए किसी भी सिद्धांत के तहत किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है।

25. नंबर 20 (डेवलपमेंट के लिए बैंक) के तहत दिए गए तरीकों से पूरे राइख में बड़े पैमाने पर बिल्डिंग बनाकर घरों की कमी को दूर करना। इससे सामाजिक-राजनीतिक मांगों की लिस्ट खत्म होती है। टेक्निकल फाइनेंशियल सवाल पर नहीं, इस पैम्फलेट में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा खास विषय है, और ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ फाइनेंशियल दिमाग वाले लोग ही समझते हैं, और जिसे असल में उन्हें ही करना होगा। NS लाइब्रेरी का पैम्फलेट 8 इस विषय पर पूरी तरह से बात करता है।

धर्म और कला

इस विषय पर एक प्रोग्राम के तौर पर कुछ खास सिद्धांतों से ज़्यादा कुछ कहना मुमकिन नहीं है। वह तो पहले ही किया जा चुका है। बाकी के लिए यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि धर्म के सवालों को आम राजनीति पर बयानों में न घसीटा जाए; हालांकि हम यहूदी धर्म के गुप्त सिद्धांतों के भ्रष्ट करने वाले असर को पब्लिक बयानों और हमलों का एक मुद्दा मान सकते हैं।

यही बात ईसाई धर्म पर होने वाले सभी बेवकूफी भरे हमलों पर भी लागू होती है। "ईसाई धर्म ने सिर्फ़ नुकसान ही किया है" जैसी बातें सिर्फ़ यह दिखाती हैं कि ऐसा कहने वाले आदमी में न तो इंसानी समझ है और न ही पॉलिटिकल समझ।

कोई भी पॉलिटिक्स में दखल देने के लिए चर्च को दोषी ठहरा सकता है, और सभी अच्छे ईसाई इनक्विजिशन द्वारा क्रॉस के नाम पर की गई क्रूरता और जादू-टोने के मुकदमों को गलत ठहराएंगे, लेकिन इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी घटना को आम तौर पर लोगों की गलतियों और बुराइयों के लिए बुरा-भला कहना गलत है। ईसाई धर्म ने लाखों-करोड़ों लोगों को बड़ा किया है और दुख के रास्ते से उन्हें भगवान के पास लाया है।

मिडिल एज का कल्चर क्रॉस के निशान पर खड़ा था; कामयाबी, त्याग, हिम्मत वाले विश्वासों की जड़ें ईसाई धर्म में हैं। इसलिए, हमें ईसाई धर्म के अंदरूनी आध्यात्मिक पहलू को इतिहास में इसके अलग-अलग रूपों में दिखने वाले उभार से अलग करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

हमारी पार्टी पॉजिटिव ईसाई धर्म के आधार पर खड़ी है।

यह उन सभी समस्याओं, उम्मीदों और इच्छाओं पर चर्चा करने की जगह नहीं है कि क्या जर्मन राष्ट्र कभी अपने धार्मिक विश्वासों और अनुभवों के लिए कोई नया रूप खोज पाएगा; ये मामले नेशनल सोशलिज़्म जैसे प्रोग्राम की सीमाओं से बिल्कुल बाहर हैं।

यह बहुत ज़रूरी है कि हम उन सभी रुकावट डालने वाले असर का सामना करें जो कला, साहित्य, विज्ञान, स्टेज, चलती-फिरती फ़िल्मों और सबसे बढ़कर पूरे प्रेस के क्षेत्र में हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारे सिद्धांतों का प्रोग्राम — 25 पॉइंट्स —

इसमें इतनी डिटेल में बात की गई है कि इस विषय पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।

सैन्य और अन्य सुधार

नेशनल आर्मी, ट्रेड्स और प्रोफेशन के चैंबर, फ्रैंचाइज़ और कानून में सुधार, ये ऐसे बड़े सवाल हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं, और इन्हें कुछ वाक्यों में खारिज नहीं किया जा सकता। मुख्य आइडिया प्रोग्राम में ही दिए गए हैं, लेकिन उन पर सोचना और उन पर काम करना, और सबसे बढ़कर, उन्हें इतिहास के अतीत से जोड़ना, आने वाले सालों की सबसे बड़ी समस्या होगी, जब हम उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकल पावर हमारी होगी, और जब हम राज्य का काम संभालने के लिए ज़रूरी ताकत और जानकारी से लैस होंगे।

यहां हमारे पास नेशनल सोशलिज्म के तहत रिसर्च के लिए एक बड़ा फील्ड है।

नेशनल सोशलिज़्म का महत्व इस बात से पता चलता है कि यह नेशनल लाइफ़ के किसी भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ता; क्योंकि यह एक बिल्कुल नई नींव देता है जिस पर हमें उस ज़िंदगी को बनाना होगा।

5. हम क्या नहीं चाहते

हमारे प्रोग्राम के पॉज़िटिव पहलू को मज़बूत करने के लिए, जल्दी ही यह बताना अच्छा रहेगा जो हम नहीं चाहते।

हम नहीं चाहते कि इतिहास का पहिया पीछे की ओर घूमे और न ही उन राजवंशों को फिर से ज़िंदा किया जाए जो अपनी ही गलती से खत्म हो गए, और अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। न ही हम उन वर्गों को फिर से उनके पहले के खास पदों पर बिठाना चाहते हैं जिन्हें गद्दी से हटा दिया गया है।

ऑफिसर क्लास और अधिकारी असल में किसी भी दूसरे प्रोफेशनल क्लास से ऊंचे या बेहतर नहीं हैं, जब तक कि वे सच में सबसे पहले देश की सेवा करने के हमारे विचार के साथ काम करते हैं।

यूनिफॉर्म या गोल्ड लेस नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस ही किसी इंसान को बनाती है।

हम मज़दूर वर्ग के लिए एकतरफ़ा तरजीह या बनावटी तरक्की नहीं चाहते, न ही किसी तरह की मज़दूर तानाशाही। कोई भी आदमी खुद को यह यकीन नहीं दिला सकता कि कोई भी वर्ग, सिर्फ़ पहले दबे होने की वजह से, सत्ता पाने का दावा कर सकता है। ऐसी ख्वाहिशें, जब असलियत में बदल जाती हैं, तो ज़रूर भयानक नतीजे लाती हैं, जैसे नवंबर 1918 के स्टॉक एक्सचेंज विद्रोह के साथ हुए थे। अभी तक आबादी का 'दबा हुआ' हिस्सा ऊपर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल ठगों, लालची एडवेंचर करने वालों, मुनाफ़ाखोरों, बकवास करने वालों और मूर्खों की भीड़ है, जिन्होंने पॉलिटिकल मशीन और एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्ज़ा कर लिया है। मज़दूर वर्ग की वादा की गई तानाशाही बदल गई है।

'प्रॉफिटेरियट' की तानाशाही।

नेशनल सोशलिज़्म के तहत राज्य की नई व्यवस्था के भी सफल होने की कोई उम्मीद नहीं थी, जब तक कि उसके पास पक्के इरादे वाले लोगों का एक बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड स्टाफ न हो, जो हमारे प्रोग्राम के सिद्धांतों से पूरी तरह से जुड़े हों, एनर्जी और अनुभव वाले गंभीर लोग हों। हमारे साथ भी, बहुत से पक्के तानाशाह नई व्यवस्था में अपनी जगह बना लेंगे और फायदा उठाएंगे।

टूटती हुई सामाजिक व्यवस्था की कमियों की आलोचना करना, उस पर अच्छा काम करने से कहीं ज़्यादा आसान है।

हमें सिर्फ़ एक नई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, जो धीरे-धीरे पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जगह बना ले, और फिर शायद किसी कोएलिशन मिनिस्ट्री में एक-दो पोस्ट ले ले, सिर्फ़ आखिर में उसकी कमर टूट जाए — क्योंकि तब इतिहास में हमारा रोल खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज जर्मनी में सोशल डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल ताकत के तौर पर खत्म हो गई है। यही बात जर्मन नेशनलिस्ट्स पर भी लागू होती है, जो सरकार में सीटें पाने के लिए पहले ही अपने मुख्य सिद्धांतों से पीछे हट चुके हैं।

हम ऐसे मंत्री नहीं चाहते जो सिर्फ़ पद या पावर के लिए पद संभालें, लेकिन हम ऐसे किसी भी पद को अपने बड़े मकसद की तरफ़ एक पड़ाव मानेंगे। हमारे और बाकियों के बीच हमेशा हमारी दुनिया की थ्योरी की जलती हुई तलवार रहती है।

एक तरफ स्टेट; या यूँ कहें कि लिबरल-डेमोक्रेटिक-पार्लियामेंट्री छाप वाला नकली स्टेट, जिसे फाइनेंसरों के ज़ुल्म को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसके पीछे यहूदी कैंप-फॉलोअर्स और जगह ढूंढने वालों की एक उग्र भीड़ थी, जो इस सिस्टम से अपना गुज़ारा करने के लिए लड़ रही थी।

हमारी तरफ से, हमारे लोगों की आज़ादी और शुद्धिकरण के लिए लड़ाई जारी रहेगी, जब तक कि हम सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आज़ादी की सच्ची स्थिति हासिल नहीं कर लेते।

6. निष्कर्ष

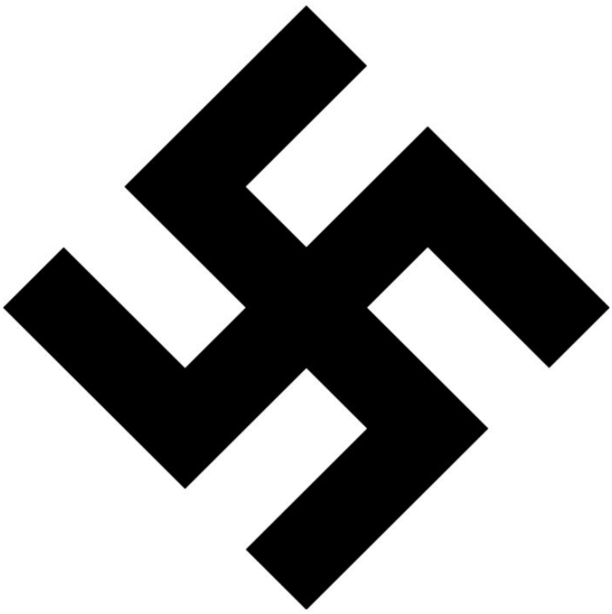
NS लाइब्रेरी के इस पहले पैम्फलेट का काम नेशनल सोशलिस्ट को यह सिखाना है कि उसे पार्टी प्रोग्राम के बारे में क्या पता होना चाहिए। हमने बार-बार एक ही मुख्य सिद्धांत देखा है जो हमारे सभी तर्कों में एक लाल धागे की तरह खींचा गया है: नेशनल सोशलिज्म दुनिया की एक थ्योरी है, जो आज की कैपिटलिज्म की दुनिया और उसके मार्क्सवादी और बुर्जुआ साथियों के बिल्कुल उलट है।

हमारा जीवन इस महान विचार की सेवा में एक संघर्ष है, एक नए जर्मनी के लिए संघर्ष है।

हम नेशनल सोशलिस्ट दुनिया के सामने अपना तूफानी झंडा लहराते हैं। हमेशा जवान, चमकते हुए। और धूप में चमकता हुआ, हुक्ड क्रॉस उगता है, जो जीवन को फिर से जगाने का प्रतीक है।

के उन्मूलन के लिए घोषणापत्र

रुचि का बंधन



मैमोनिज़्म एक बहुत बड़ी, सबको घेरने वाली और बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है जिससे हमारा आज का कल्चरल एरिया, और असल में पूरी इंसानियत, परेशान है। यह एक खतरनाक बीमारी की तरह है, एक ऐसे ज़हर की तरह है जिसने दुनिया के लोगों को जकड़ लिया है।

मैमोनिज़्म से यह समझा जाता है:

एक ओर, जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय धन-शक्तियाँ, लोगों के आत्मनिर्णय के किसी भी अधिकार से ऊपर विराजमान सुपरगवर्नमेंटल वित्तीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी पूंजी, विशुद्ध रूप से गोल्ड इंटरनेशनल;

दूसरी तरफ, एक ऐसी सोच जिसने लोगों के बड़े ग्रुप पर कब्ज़ा कर लिया है; कभी न खत्म होने वाली फ़ायदे की चाहत, ज़िंदगी की पूरी तरह से दुनियावी सोच जिसने पहले ही सभी नैतिक सोच में डरावनी गिरावट ला दी है और आगे भी ला सकती है।

यह सोच इंटरनेशनल अमीरों के राज में दिखाई देती है और अपने चरम पर पहुँचती है।

मैमोनिज़्म के लिए ताकत का मुख्य सोर्स ब्याज से होने वाली बिना मेहनत की और कभी न खत्म होने वाली कमाई है।

लोन पर ब्याज के पूरी तरह से गलत विचार से गोल्ड इंटरनेशनल का जन्म हुआ।
हर तरह के ब्याज और मुनाफ़े की चाहत से बनी मानसिक और नैतिक बनावट ने पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से में भयानक भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

लोन पर ब्याज का आइडिया बड़ी लोन-कैपिटल की शैतानी खोज है; सिर्फ़ इसी से कुछ अमीर लोगों की आलसी ज़िंदगी मुमकिन होती है, जो प्रोडक्टिव लोगों और उनके काम करने की क्षमता की कीमत पर जीते हैं; इससे गहरे, कभी न सुलझने वाले मतभेद, क्लास-नफ़रत पैदा हुई है, जिससे नागरिकों और भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हुई।

पीड़ित मानवता को ठीक करने का एकमात्र इलाज, क्रांतिकारी तरीका है

ब्याज की गुलामी का खात्मा।

पैसे पर ब्याज की गुलामी को खत्म करना ही एकमात्र संभव और
छिपी हुई ज़बरदस्ती वाली पैसे की ताकत से प्रोडक्टिव लेबर की पक्की आज़ादी।

ब्याज की गुलामी खत्म होने का मतलब है आज़ाद 7 पर्सनैलिटी की वापसी, इंसान का गुलामी से छुटकारा, उस श्राप से छुटकारा जिससे मैमोनिज़्म ने उसकी आत्मा को बांध रखा था।
जो कोई भी कैपिटलिज़्म से लड़ना चाहता है, उसे ब्याज की गुलामी खत्म करनी होगी।

ब्याज की गुलामी को खत्म करने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? लोन-कैपिटल से!

क्यों?

क्योंकि लोन-कैपिटल, सभी इंडस्ट्रियल बड़ी कैपिटल की तुलना में, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि बड़ी मनी-पावर से असरदार तरीके से सिर्फ़ इंटरेस्ट-स्लेवरी को खत्म करके ही लड़ा जा सकता है। लोन-कैपिटल का इंडस्ट्रियल बड़ी कैपिटल से अनुपात 20:1 है। जर्मन लोगों को लोन कैपिटल के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, किराए और बढ़ती महंगाई के रूप में हर साल 12 बिलियन से ज़्यादा इंटरेस्ट इकट्ठा करना पड़ता है, जबकि युद्ध के तेज़ी वाले सालों में भी जर्मन जॉइंट-स्टॉक कंपनियों द्वारा बांटे गए सभी डिविडेंड का कुल जोड़ सिर्फ़ 1 बिलियन था।

लोन-कैपिटल की तेज़ी से बढ़ोतरी, इंसानी हिसाब-किताब की सारी काबिलियत से कहीं ज़्यादा है,
ब्याज से तथा ब्याज पर ब्याज से अनन्त, अंतहीन तथा सहज आय के माध्यम से।

ब्याज की गुलामी खत्म होने से मेहनतकश लोगों को क्या फायदा होगा?
जर्मनी के, पृथ्वी के सभी देशों के मज़दूरों के लिए?

ब्याज की गुलामी खत्म होने से हमें सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करने की गुंजाइश मिलती है । सभी देशों, सभी राज्यों और महाद्वीपों के वैल्यू बनाने वाले लोगों, यह सुनो: डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स से आने वाला सारा सरकारी रेवेन्यू लगातार बड़े लोन-कैपिटल की जेबों में जाता है।

सरकारी बिज़नेस, जैसे पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेलरोड, माइंस, जंगल वगैरह का प्रॉफिट, स्कूलों, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों और सोशल वेलफेयर के लिए सरकार के सभी ज़रूरी कामों की फंडिंग के लिए पूरी तरह से काफी है।

इस प्रकार, कोई भी सच्चा समाजवाद मानवता के लिए कोई आशीर्वाद नहीं लाएगा जब तक कि इससे होने वाले लाभ
पब्लिक एंटरप्राइज़ बड़े लोन-कैपिटल के अधीन बने हुए हैं।

इसलिए, हम राज्य के एक बुनियादी कानून के तौर पर, पहले जर्मन लोगों के लिए, फिर उन सभी मिलते-जुलते लोगों के लिए एक बुनियादी कानून के तौर पर, जो हमारे साथ लीग ऑफ़ नेशंस के कल्चरल कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, ये मांग करते हैं:

1. जर्मन राइख के सभी दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वॉर-बॉन्ड्स, जर्मन फेडरल राज्यों के सभी दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर रेलरोड-बॉन्ड्स, और सभी लोकल सरकारों के डिबेंचर-बॉन्ड्स, ब्याज की ज़िम्मेदारी खत्म होने के बाद, फेस-वैल्यू के लिए लीगल टेंडर घोषित किए जाते हैं [या यूं कहें कि बैंक-क्रेडिट में बदल दिए जाते हैं]।

2. दूसरे सभी फिक्स्ड-इंटरेस्ट पेपर्स, कवर्ड बॉन्ड्स, इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स, मॉर्गेज वगैरह के साथ, ब्याज की ज़िम्मेदारी की जगह प्रिंसिपल चुकाने की ज़िम्मेदारी आ जाती है; इस तरह 20 या 25 साल बाद, ब्याज दर के आधार पर, उधार दिया गया कैपिटल चुका दिया जाता है, और कर्ज़ चुका दिया जाता है।

3. सभी रियल-एस्टेट के कर्ज़, मॉर्टगेज वगैरह, लैंड-रजिस्टर में दर्ज चार्ज के हिसाब से, अब तक चुकाए गए पेमेंट के बराबर किश्तों में चुकाए जाने हैं। इस तरह कर्ज़ से आज़ाद हुए घरों और ज़मीन की प्रॉपर्टी कुछ हद तक राज्य या लोकल सरकार की प्रॉपर्टी बन जाती है। [इस तरह राज्य किराए को कंट्रोल करने और कम करने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाता है।]

4. पूरा मॉनेटरी सिस्टम राज्य के सेंट्रल बैंक के अंडर होना चाहिए। इसी तरह सभी प्राइवेट बैंक; पोस्टल-चेक बैंक, सेविंग्स बैंक और क्रेडिट यूनियन, सभी ब्रांच-ऑपरेशन के तौर पर जुड़े हुए हैं।

5. रियल एस्टेट के लिए सारा क्रेडिट सिर्फ़ सरकारी बैंक से ही दिया जाता है। पर्सनल क्रेडिट और कमर्शियल क्रेडिट सरकारी छूट के तहत प्राइवेट बैंकरों को देना ज़रूरी है।
यह छूट ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है, और कुछ ज़िलों में ब्रांच खोलने पर रोक है। चार्ज का लेवल राज्य तय करता है।

6. इक्विटी-सिक्योरिटीज़ का पेमेंट फिक्स्ड-इंटरेस्ट पेपर्स की तरह ही 5% की सालाना दर पर किया जाता है। ज़्यादा मुनाफ़े का कुछ हिस्सा स्टॉकहोल्डर्स को "रिस्क्ड" कैपिटल के मुआवज़े के तौर पर दिया जाता है (फिक्स्ड इंटरेस्ट और कॉइन-बैक्ड पेपर्स के उलट), जबकि बचा हुआ सरप्लस, लेबर के सॉवरेन अधिकार से, या तो सोशली बांटा जाता है या प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

7. उन सभी लोगों के लिए जो शारीरिक कारणों (बढ़ती उम्र, बीमारी, शारीरिक या मानसिक काम करने में अक्षमता, बहुत कम उम्र) से अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की स्थिति में नहीं हैं, मौजूदा कैपिटल एसेट्स से मिलने वाली ब्याज-आय को सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी के बदले में पेंशन के रूप में उसी स्तर पर और अंततः बढ़े हुए स्तर पर भी दिया जाता रहेगा।

8. कागज़ के पैसे की मौजूदा महंगाई को कम करने के लिए, राइख और राज्यों के वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट और दूसरे कर्ज़ के साधनों पर एक यूनिवर्सल, मज़बूती से तय टैक्स लगाया जाता है। इन कागज़ों को पल्प किया जाएगा।

9. लोगों को अच्छी तरह जागरूक करके, उन्हें यह साफ़ करना होगा कि पैसा, पूरे किए गए काम के लिए एक वाउचर के अलावा और कुछ नहीं है और होना भी चाहिए; जबकि हर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकॉनमी को पैसे की ज़रूरत होती है।

एक्सचेंज के साथ ही पैसे का काम भी खत्म हो जाता है, और किसी भी हालत में पैसे को प्रोडक्टिव लेबर की कीमत पर, ब्याज के ज़रिए खुद को बढ़ाने की कोई सुपरमॉडर्न पावर नहीं दी जानी चाहिए।

हमने यह सब पहले से क्यों नहीं किया, जो इतना साफ़ है, जिस पर ध्यान देना चाहिए सामाजिक सवाल के लिए कोलंबस के अंडे के रूप में?

क्योंकि अपने अमीरों के अंधेपन में हमने यह साफ-साफ देखना भूल गए हैं कि ब्याज की पवित्रता का सिद्धांत एक बहुत बड़ा खुद को धोखा देना है, कि लोन-ब्याज का सिद्धांत, जो अकेले इंसान को खुशनसीब बनाता है, ने हमारी पूरी सोच को इंटरनेशनल अमीरों के सुनहरे जाल में उलझा दिया है। क्योंकि हम भूल गए हैं और सबसे ताकतवर पैसे वालों ने जानबूझकर हमें इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रखा है कि — कुछ अमीर लोगों के मामले को छोड़कर —

जो ब्याज इतना प्यारा लगता है, और जो बिना सोचे-समझे लोगों को इतना पसंद आता है, वह टैक्स से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब तक हमें ब्याज की गुलामी से आज़ादी नहीं मिल जाती, हमारे सभी टैक्स-कानून सिर्फ़ बड़ी पूंजी के लिए एक श्रद्धांजलि-दायित्व हैं, और जैसा हम सोचते हैं, समाज के लिए मेहनत करने के लिए अपनी मर्ज़ी से किया गया त्याग नहीं हैं।

इसलिए, पैसे पर ब्याज की गुलामी से आज़ादी ही ग्लोबल क्रांति का साफ़ मकसद है, और प्रोडक्टिव लेबर को सुपरगवर्नमेंटल मनी-पावर की जंजीरों से आज़ादी दिलाना है।

कार्यान्वयन और तर्क

हम अपने गरीब लोगों के दर्दनाक इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक के बीच खड़े हैं। हमारे लोग बहुत बीमार हैं; पूरी दुनिया बहुत बीमार है।
देश बेबस होकर हकला रहे हैं; एक गहरी चाहत, मुक्ति की पुकार उदास लोगों में से गुज़र रही है। हंसी और नाच के साथ, सिनेमा और दिखावे के साथ, लोग अपनी दुखद किस्मत को भूलना चाहते हैं — अपनी निराश उम्मीदों को, गहरे अंदरूनी दर्द को भूलना चाहते हैं,

उस भयंकर निराशा के बारे में जिसे कोई खुशी-खुशी "क्रांति के लाभ" कहेगा।
लेकिन हमने यह सब अलग तरह से कैसे सोचा? सारे अच्छे वादे अलग तरह से कैसे हुए? रात के अंधेरे में, हमारी मिलिट्री के खत्म होने के अंधेरे में हम जो कुछ भी पाने की उम्मीद कर रहे थे, वह सब चमकता हुआ सोना लग रहा था, लेकिन अब, जब धुंधलका दिन इस खोज को रोशन कर रहा है, तो यह सब सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े हैं।
अब हम यहाँ उलझन में हैं। रात में इतनी अच्छी तरह चमकने वाली इन सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़ों के लिए, हमने वह सब कुछ फेंक दिया है जो अब तक हमें प्यारा और कीमती लगा था और अपनी सारी जेबें इस बेकार खजाने से भर ली हैं। कोई हैरानी नहीं कि निराशा का गुस्सा ठीक सबसे गरीब लोगों को जकड़ लेता है, और वे अपने ही भाइयों पर बेवजह गुस्से में भड़क उठते हैं, और मुक्ति की अपनी गहरी चाहत में रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खत्म करना चाहते हैं।

अगर विवेकहीनता और मूर्खता लोगों को और उकसाती है, तो यह स्थिति पूरी तरह से पागलपन की ओर ले जाएगी।

और यह पागलपन कहाँ ले जाता है, यह हम बोल्शेविक रूस में देखते हैं। नेशनलाइज़ेशन, जिसे रूस में सोशलाइज़ेशन कहा जाता है, फेल साबित हुआ है, लेनिन ने बिना किसी परेशानी के कहा। इकॉनमी खत्म हो गई है, पैसे की खरीदने की ताकत खत्म हो गई है, इंटेलेक्चुअल लोग मारे जा रहे हैं, मज़दूर बिना रोटी के है। पूरे लोगों में निराशा है; सिर्फ़ चीनी और लातवियाई किराए के सैनिकों पर आधारित खूनी आतंक ही रेड डिक्टेटर को धोखा खाए लोगों के बदले से बचा सकता है। हमारे बीच भी डेवलपमेंट इसी रास्ते पर चलेगा, अगर इंटरनेशनल सट्टेबाजों, जुनूनी पार्टी के दीवानों, सबसे ज़्यादा बोझ तले दबे अमीरों के नुमाइंदों, और जर्मन लोगों से बिल्कुल अलग तरह की नस्ल के लोगों को सरकार में जगह मिलती रही।

असल में वो प्यारे-प्यारे शब्द क्या थे जो किसी ने हमारे कान में फुसफुसाए थे? नेगोशिएटेड शांति, लीग ऑफ़ नेशंस, पार्लियामेंटेरियनिज़्म, लोगों की सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप, सोशलिज़्म, कैपिटलिज़्म का विनाश, मिलिट्रीवाद से आज़ादी, और ऐसे ही दूसरे सुंदर नारे। एक नए आज़ाद लोग पैदा होने वाले थे, जो अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। इनमें से कुछ भी सच नहीं हुआ है, सच हो पाया है, या कभी सच हो सकता है, अगर हम पूरी नैतिक गंभीरता के साथ इन सभी प्रेतों, इन सभी नारों की जांच नहीं करते हैं — अगर हम एक समझदार, चिंतित डॉक्टर की तरह ईमानदारी से बीमारी के लक्षणों की जांच नहीं करते हैं, और बीमार व्यक्ति की मौजूदा हालत का ध्यान से पता नहीं लगाते हैं, यह पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि यह गंभीर बीमारी कहां से आई है।

卐卐卐卐卐

हमारे ज़माने की बीमारी को मैमोनिज़्म कहा जाता है।

मैमोनिज्म क्या है?

मैमोनिज़्म बड़ी इंटरनेशनल मनी-पॉवर का खतरनाक, दिखाई न देने वाला, रहस्यमयी राज है। मैमोनिज़्म हालांकि एक सोच भी है; यह उन सभी लोगों की तरफ से इन मनी-पॉवर की पूजा है जो मैमोनिस्टिक ज़हर से इन्फेक्टेड हैं। मैमोनिज़्म इंसान की – जो अपने आप में हेल्दी है – चीज़ें पाने की चाहत का अनलिमिटेड हाइपरट्रॉफी है। मैमोनिज़्म पैसे की वह हवस है जो पागलपन में बदल गई है, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं है, सिवाय पैसे के ऊपर पैसा जमा करने के, जो बेमिसाल बेरहमी से दुनिया की सभी ताकतों को अपनी सेवा में मजबूर करने की कोशिश करता है, और दुनिया के सभी लोगों की काम करने की क्षमता के शोषण के लिए, आर्थिक गुलामी की ओर ले जाता है। मैमोनिज़्म वह सोच है जिसने सभी नैतिक विचारों को खत्म कर दिया है। मैमोनिज़्म को एक दुनिया भर की घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसकी तुलना इंसान में क्रूर, बेरहम अहंकार से की जानी चाहिए। मैमोनिज़्म लालच की भावना है, राज करने की बेहिसाब इच्छा है, ऐसी सोच है जो पूरी तरह से दुनिया के सामान और खज़ानों पर कब्ज़ा करने पर फोकस करती है; यह मूल रूप से पूरी तरह से दुनियादारी पर ध्यान देने वाले इंसान का धर्म है।

मैमोनिज़्म, सोशलिज़्म का ठीक उल्टा है। सोशलिज़्म, सबसे ऊंचे नैतिक विचार के तौर पर देखा जाता है, यह विचार कि इंसान दुनिया में सिर्फ़ अपने लिए नहीं है, कि हर इंसान की समाज के प्रति, पूरी इंसानियत के प्रति ज़िम्मेदारी है, और वह सिर्फ़ अपने परिवार, अपने कबीले के लोगों, अपने लोगों की कुछ समय की भलाई के लिए ही ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि अपने बच्चों और अपने लोगों के भविष्य के प्रति भी उसकी पक्की नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं।

और साफ़ तौर पर, हमें मैमोनिज़्म को सभी लोगों के सत्ता के भूखे बड़े पूंजीपतियों की सोची-समझी मिलीभगत के तौर पर देखना चाहिए। इसमें मैमोनिज़्म का छिपा हुआ आना हमेशा से ध्यान देने लायक रहा है।

बड़े टाइकून असल में दुनिया भर में फैले एंग्लो-अमेरिकन साम्राज्यवाद के पीछे असली ताकत के तौर पर छिपे हुए हैं; और कुछ नहीं। बड़े पैसे वालों ने असल में वर्ल्ड वॉर में हुए भयानक सामूहिक हत्याकांडों को फाइनेंस किया था। बड़े पैसे वालों ने असल में, सभी बड़े अखबारों के मालिकों के तौर पर, दुनिया को झूठ के जाल में बुना है। उन्होंने खुशी-खुशी सभी छोटी-मोटी भावनाओं को भड़काया है, आज के ट्रेंड्स को बढ़ाने में मेहनत की है, और चालाक प्रेस-प्रोपेगैंडा के ज़रिए फ्रेंच बदला लेने की सोच को उबाल दिया है। उन्होंने पैन-स्लाविक आइडिया, सर्बिया के बड़ी ताकत होने के घमंड, और इन देशों की पैसे की ज़रूरत को इतनी सावधानी से बढ़ावा दिया कि दुनिया में आग लगनी ही चाहिए।

जर्मनी में हमारे बीच भी मैमोनिज़्म की भावना थी जो सिर्फ़ एक्सपोर्ट के आंकड़े, देश की दौलत, विस्तार, बड़े बैंक प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल फाइनेंस डील के बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी।

इससे पब्लिक मोरैलिटी खत्म हो गई, हमारा रूलिंग सर्कल मैटेरियलिज़्म और हेदोनिज़्म में गिर गया, हमारी नेशनल लाइफ में ऊपरीपन आ गया, ये सभी फैक्टर्स इस भयानक गिरावट के लिए ज़िम्मेदार हैं।

हैरानी के साथ हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैमोनिज़्म कहाँ से आता है, जहाँ से इंटरनेशनल बड़ी कैपिटल को अपनी ज़बरदस्त ताकत मिलती है।

इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि बड़ी मनी पावर्स का इंटरनेशनल सहयोग एक बिल्कुल नई चीज़ है। इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। पैसे से जुड़ी इंटरनेशनल ज़िम्मेदारियाँ असल में अनजान थीं। सिर्फ़ बढ़ती ग्लोबल इकॉनमी, आम ग्लोबल कॉमर्स के साथ ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट-इकॉनमी का आइडिया बना, और यहाँ हमने सबसे गहरी जड़ को छुआ है, यहाँ हमने ताकत के उस अंदरूनी सोर्स को छुआ है जहाँ से गोल्डन इंटरनेशनल को अपनी ज़बरदस्त ताकत मिलती है।

ब्याज, यानी बिना किसी मेहनत के सिर्फ़ पैसे के मालिकाना हक के आधार पर चीज़ों का बिना किसी मेहनत के और कभी न खत्म होने वाला आना, बड़ी मनी-पावर को बढ़ाने का कारण बना है। लोन-ब्याज वह शैतानी सिद्धांत है जिससे गोल्ड इंटरनेशनल का जन्म हुआ। लोन-कैपिटल ने हर जगह अपनी खून की नली मज़बूती से लगा ली है। एक रत्नजड़ित पौधे की तरह बड़ी लोन कैपिटल ने दुनिया के सभी देशों, सभी लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है।

सरकारी लोन, सरकारी बॉन्ड, रेलरोड बॉन्ड, वॉर बॉन्ड, मॉर्गेज, कवर्ड-बॉन्ड ऑब्लिगेशन — शॉर्ट में कहें तो हर तरह के लोन-इंस्ट्रूमेंट ने एक तरह से हमारी पूरी इकोनॉमिक लाइफ को फंसा लिया है, ताकि अब से दुनिया के सभी लोग बेबस होकर इन सुनहरे जालों में फँसें। इंटरेस्ट प्रिंसिपल के लिए, इस पूरी तरह से पागल पॉलिटिकल गलतफहमी के हिसाब से कि हर तरह की चीज़ से कमाई का हक मिलता है, हमने पैसे पर इंटरेस्ट की गुलामी कर ली है। एक भी असली, सही नैतिक कारण नहीं दिया जा सकता कि सिर्फ पैसे रखने से हमें हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट का हक क्यों मिलना चाहिए।

ब्याज और बिना किसी मेहनत के हर तरह की इनकम का यह अंदरूनी विरोध सभी लोगों और समय की आत्मा में फैला हुआ है। लेकिन पैसे की ताकत का यह गहरा अंदरूनी विरोध देशों के लिए हमारे समय जितना जागरूक कभी नहीं हुआ।

मैमोनिज़्म को दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए इतने बड़े तरीके से कभी तैयार नहीं किया गया। इसने अपनी सेवा में इतनी चालाकी से छिपाकर और फिर भी बेरहमी से दबाव डालने वाले तरीके से सारी नीचता, ताकत की चाहत, बदला लेने की चाहत, लालच, जलन और झूठ को कभी इस्तेमाल नहीं किया, जितना अब किया है। वर्ल्ड वॉर अपने दिल के अंदर इंसानियत के विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़े फैसलों में से एक है, यह तय करने की कोशिश में कि भविष्य में मैमोनिस्टिक-मटेरियलिस्टिक दुनिया की सोच या सोशलिस्टिक-अरिस्टोक्रेटिक दुनिया की सोच किसकी किस्मत तय करेगी।

दुनिया.

ऊपर से देखने पर, मैमोनिस्टिक एंग्लो-अमेरिकन गठबंधन बेशक शुरू में जीत गया था। इसके रिएक्शन में, पूरब में बोल्शेविज़्म पैदा हुआ, और अगर कोई बोल्शेविज़्म में कोई बड़ा आइडिया देखना चाहता है, तो वह बिना किसी शक के मैमोनिस्टिक नज़रिए के बिल्कुल उलट है। लेकिन, इसके लिए बोल्शेविज़्म जो तरीके इस्तेमाल करना चाहता है, वे डॉ. आइज़नबर्थ के खराब इलाज जैसे हैं। वे अंदरूनी ज़हर से बीमार किसी व्यक्ति का सिर, हाथ और पैर काटकर उसकी मदद करने की कोशिश हैं।

बोल्शेविज़्म के इस कहर के खिलाफ़, इस बेमतलब की उथल-पुथल के खिलाफ़, हमें एक काम करने वाला नया आइडिया पेश करना होगा जो सभी मेहनतकश लोगों को एक साथ लाए, ताकि उस ज़हर को बाहर निकाला जा सके जिसने दुनिया को बीमार कर दिया है।

मैं इसका मतलब पैसे पर ब्याज की गुलामी को खत्म करने में देखता हूं।

तीन वजहें हैं जो लोन-कैपिटल पर ब्याज को हमारी फाइनेंशियल परेशानी की असली और सच्ची वजह बनाती हैं।

पहला, फिक्स्ड-इंटरेस्ट लोन-कैपिटल का बहुत ज़्यादा अनुपात, यानी वह कैपिटल जो बिना किसी क्रिएटिव मेहनत के अपने आप बढ़ती है, और असल में हमेशा बढ़ती रहती है।
जर्मनी में हमारे बीच यह लोन-कैपिटल पहले ही 250 बिलियन के लेवल पर पहुँच चुका है जिसे हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते। इस बड़ी रकम के मुकाबले, हमारी पूरी जर्मन इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल वर्किंग कैपिटल सिर्फ़ 11.8 बिलियन है। इसके अलावा, 16,000 इंडस्ट्रियल लिमिटेड-लायबिलिटी कंपनियों [GmbH] का 3.5 बिलियन कैपिटल है, तो कुल मिलाकर हमारे पास टेबल में लगाने के लिए सिर्फ़ लगभग 15 बिलियन इंडस्ट्रियल कैपिटल है। 20:1 पहली बुनियादी बात है[3] ।

इस आकलन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ाइनेंशियल समस्याओं में, लोन-कैपिटल से जुड़े सभी उपाय, इंडस्ट्रियल बड़ी कैपिटल के लिए किए गए उपायों से 20 गुना ज़्यादा असरदार साबित होने चाहिए।

दूसरा: ऊपर दिए गए लोन-कैपिटल पर इंटरेस्ट-पेमेंट, जिसका अंदाज़ा 250 बिलियन है, हर समय के लिए कुल मिलाकर, सालाना लगभग 12½ बिलियन होता है। इसके उलट, साल 1916 में बांटे गए सभी इंडस्ट्रियल डिविडेंड का टोटल साल 1915 में लगभग एक बिलियन मार्क्स था। पिछले दशकों में यह संख्या, एवरेज, लगभग 600 मिलियन थी। युद्ध के आखिरी दो सालों [1914-1918] में यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन इस साल [1919] में यह और भी ज़्यादा क्रैश रिकॉर्ड करेगा।

सभी जर्मन स्टॉक-कॉर्पोरेशन [AG] का औसत प्रॉफिट 8.21% था; इस तरह, यह फिक्स्ड-इंटरेस्ट लोन-वैल्यू पर औसत रिटर्न से सिर्फ़ लगभग 3½% ज़्यादा था।

इस तरह, मैं दोहराता हूँ, भविष्य में जर्मन लोगों को बड़े लोन-कैपिटल के अलग-अलग हमेशा लगने वाले ब्याज-चार्ज के लिए [सालाना] लगभग 12.5 बिलियन देने होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा तेज़ी वाले साल में इंडस्ट्रियल कैपिटल से यील्ड 1 बिलियन थी, और बिना किसी रुकावट के खुशहाली के समय में सिर्फ़ 0.6 बिलियन थी। इस तरह, हम यहाँ फिर से 20:1 से 12:1 के अनुपात को देखते हैं।

तीसरा और सबसे खतरनाक फैक्टर है ब्याज और ब्याज पर ब्याज के ज़रिए बड़े लोन-कैपिटल की समझ से परे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी। मुझे यहाँ थोड़ा और अलग होना होगा और उम्मीद है कि हायर मैथमेटिक्स में थोड़ी सी जानकारी के ज़रिए मैं इस समस्या को समझा पाऊँगा। पहले कुछ उदाहरण।

शतरंज के खेल के आविष्कार की दिलचस्प कहानी सब जानते हैं। अमीर भारतीय राजा शिहराम ने शाही खेल के आविष्कार के लिए धन्यवाद के तौर पर आविष्कारक को एक इच्छा पूरी करने का तोहफ़ा दिया। समझदार आदमी की इच्छा थी कि राजा उसे शतरंज के खेल के पहले खाने में गेहूं का एक दाना दें, दूसरे पर दो, तीसरे पर चार, और इस तरह हर खाने में हमेशा पहले वाले से दोगुना गेहूं दें। राजा समझदार आदमी की मामूली सी इच्छा पर मुस्कुराए और आदेश दिया कि गेहूं की एक बोरी लाई जाए ताकि हर खाने में गेहूं के दाने बांटे जा सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह इच्छा पूरी करना दुनिया के सबसे अमीर राजकुमार के लिए भी नामुमकिन था। हज़ार साल में दुनिया की सारी फसल भी शतरंज की बिसात के 64 खाने भरने के लिए काफी नहीं होगी।

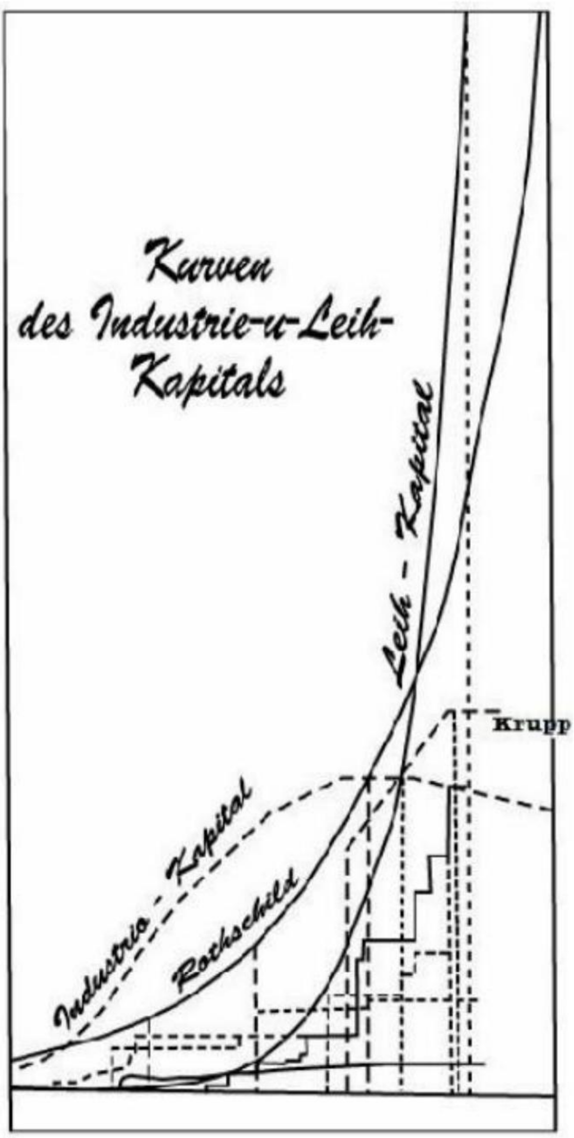
[3] ज़ाहिर है 17:1 ज़्यादा सही है, लेकिन शायद फेडर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यह अनुपात बढ़ेगा।

एक और उदाहरण: बहुत से लोगों को अपने स्कूल के दिनों से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की परेशानी याद होगी; कैसे ईसा मसीह के जन्म के समय इन्वेस्ट किया गया पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना बढ़ जाता है कि हर 15 साल में दोगुना हो जाता है। ईसा मसीह के जन्म के 15 साल बाद वह पैसा 2 पैसे का हो गया, 30AD में 4 पैसे का, 45AD में 8 पैसे का और इसी तरह। बहुत कम लोगों को याद होगा कि आज उस पैसे की क्या वैल्यू होगी: पृथ्वी, सूरज और सभी ग्रहों के कुल वॉल्यूम के बराबर सोने का वॉल्यूम भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किए गए इस पैसे की वैल्यू बताने के लिए काफी नहीं होगा।

तीसरा उदाहरण: सबसे पुराने इंटरनेशनल अमीर घराने, रोथ्सचाइल्ड की दौलत आज लगभग 40 बिलियन डॉलर है। यह सब जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट में लगभग 1800 में, बूढ़े मेयर एमशेल रोथ्सचाइल्ड ने, जिनके पास खुद की कोई खास दौलत नहीं थी, हेस्से के काउंट विल्हेम I ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो लाखों डॉलर दिए थे, उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके उधार देकर अपने घर की बहुत बड़ी दौलत की नींव रखी।

अगर रोथ्सचाइल्ड के साथ ब्याज और ब्याज पर ब्याज से पैसा जमा करना सिर्फ़ एक पैसे की मामूली दर पर ही सफल होता, तो यह कर्व इतना तेज़ी से नहीं चढ़ता। लेकिन यह मानते हुए कि रोथ्सचाइल्ड्स की कुल दौलत सिर्फ़ एक पैसे की दर से बढ़ी, तो साल 1935 में रोथ्सचाइल्ड्स की दौलत 80 बिलियन, 1950 में 160 बिलियन, 1965 में 320 बिलियन होती, और इसके साथ ही यह पहले ही कुल जर्मन राष्ट्रीय दौलत से कहीं ज़्यादा हो जाती।

इन तीन उदाहरणों से एक मैथमेटिकल नियम निकाला जा सकता है। वह कर्व जो रोथ्सचाइल्ड की किस्मत के बढ़ने को दिखाता है, वह कर्व जो शतरंज की बिसात के लिए गेहूं के दानों की संख्या से निकाला जा सकता है, और वह संख्या जो पेनी के गुणा से निकलती है।



चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाले, सरल गणितीय वक्र हैं। इन सभी वक्रों में

वही कैरेक्टर। शुरू में मामूली और धीरे-धीरे बढ़ोतरी के बाद कर्व और भी ज़्यादा तीखा हो जाता है और जल्द ही प्रैक्टिकली इनफिनिटी के लगभग टैंजेंशियल जैसा हो जाता है।

हालाँकि, इंडस्ट्रियल कैपिटल का ग्रोथ-कर्व पूरी तरह से अलग तरीके से आगे बढ़ता है।
इसी तरह, ज़्यादातर छोटी शुरुआत से शुरू होने पर, जल्द ही कर्व्स में तेज़ बढ़ोतरी दिखाई देती है, जब तक कि कैपिटल का एक खास सैचुरेशन नहीं हो जाता।

फिर कर्व फ्लैट हो जाते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में शायद थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, अगर नए इन्वेंशन की वजह से मौजूदा फैक्ट्रियों, मशीनों वगैरह की वैल्यू कम हो गई हो। मैं यहाँ सिर्फ़ एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्रुप वर्क्स का डेवलपमेंट। 1826 में बूढ़े क्रुप की मौत लगभग बिना किसी प्रॉपर्टी के हो गई। 1855 में अल्फ्रेड क्रुप को मिस्र सरकार की तरफ़ से 36 तोपों का पहला ऑर्डर मिला।

1873 में क्रुप में पहले से ही 12,000 वर्कर काम करते थे। 1903 में फ्राउ बर्टा क्रुप ने पूरा काम और प्रॉपर्टी अल्फ्रेड क्रुप को बेच दी।

160 मिलियन की जॉइंट-स्टॉक कंपनी। आज स्टॉक-कैपिटल की कुल वैल्यू 250 मिलियन है। हम जर्मन लोगों के लिए क्रुप नाम का क्या मतलब है? हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पराकाष्ठा। दुनिया का पहला [स्टील] तोप बनाने वाला। सबसे मज़बूत, मकसद वाली, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की एक बड़ी रकम। हमारे लाखों साथियों के लिए क्रुप की कोशिश का मतलब रोटी और काम रहा है। हमारे देश के लिए, हथियार और डिफेंस – और फिर भी यह रोथ्सचाइल्ड के अरबों के सामने बहुत छोटा है। एक सदी में क्रुप की दौलत में बढ़ोतरी, ब्याज और ब्याज पर ब्याज से बिना मेहनत और कभी न खत्म होने वाली बढ़ोतरी से रोथ्सचाइल्ड की दौलत में बढ़ोतरी की तुलना में क्या अहमियत रखती है?

मोटी लाइनों में बने दो कर्व लोन-इंटरेस्ट को दिखाते हैं और असल में ऊपर वाला कर्व रॉथ्सचाइल्ड की दौलत के डेवलपमेंट को दिखाता है और नीचे वाला कर्व, जो पहले फ्लैट होता है और फिर तेज़ी से बढ़ता है, बहुत आम तौर पर ऐसे सभी कर्व्स के खास डेवलपमेंट को दिखाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थोड़ी सी बढ़त वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यू को दोगुना कर सकती है। हैच की हुई लाइन पिछले 40-50 सालों में हमारी कुल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट-कर्व को दिखाती है। अलग-अलग हैच की हुई बारीक लाइनें कई रैंडमली चुने गए बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट को दिखाती हैं, जिनसे इंडस्ट्रियल कैपिटल के हैच किए हुए कर्व का आम कैरेक्टर मिलता है।

यह साफ़ तौर पर बताना ज़रूरी है कि लोन-कैपिटल के कर्व बहुत ज़्यादा दबे हुए दिखाए गए हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, रॉथ्सचाइल्ड की दौलत का कर्व क्रुप कर्व से 80 गुना ज़्यादा होना चाहिए। कर्व दिखाने का मकसद बेशक सिर्फ़ दो तरह के कैपिटल के असल में अलग-अलग कैरेक्टर को दिखाना है। लोन-कैपिटल के कर्व पहले तो काफ़ी धीरे-धीरे बढ़ते हुए डेवलपमेंट को दिखाते हैं; फिर डेवलपमेंट तेज़ी से होता जाता है, जब तक कि यह और भी ज़्यादा बेकाबू होकर और सब कुछ अपने साथ घसीटते हुए, इंसानी सोच से कहीं आगे नहीं निकल जाता और हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ जाता।

इसके उलट, इंडस्ट्रियल कैपिटल का कर्व सीमित रहता है! एक ट्रेस डिटेल में कितने भी बड़े अंतर क्यों न दिखाए जाएं, कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मूल चरित्र हमेशा ऐसा होगा कि मज़बूत शुरुआती डेवलपमेंट के बाद मैच्योरिटी, सैचुरेशन का एक निश्चित समय आता है, जिसके बाद देर-सवेर गिरावट आ जाती है।

卐卐卐卐卐

लोन-कैपिटल और इंडस्ट्रियल कैपिटल के बीच का गहरा ज़रूरी अंतर हमें इससे ज़्यादा साफ़ तौर पर कोई और चीज़ नहीं दिखाती। लोन-कैपिटल के खतरनाक असर और बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज़ में लगाए गए और जोखिम में डाले गए बिज़नेस कैपिटल के बिज़नेस-प्रॉफिट (डिविडेंड) के बीच का अंतर इस तुलना से ज़्यादा साफ़ कोई और चीज़ नहीं बता सकती।

इस बात पर जितना ज़ोर दिया जाए कम है कि लोन-कैपिटल और इंडस्ट्रियल कैपिटल जिन मैथमेटिकल नियमों को फॉलो करते हैं, उन्हें पहचानना ही हमें वह साफ़ रास्ता दिखाता है जहाँ हमारी बर्बाद फाइनेंस-इकॉनमी को ठीक करने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाना है। हम साफ़ तौर पर मानते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, और न ही कैपिटल अपने आप में और इस तरह से, इंसानियत के लिए मुसीबत है। बड़े लोन-कैपिटल की कभी न खत्म होने वाली ब्याज-ज़रूरत पूरी मेहनत करने वाली इंसानियत के लिए श्राप है!

कैपिटल होना चाहिए! लेबर होना चाहिए! लेबर अकेले कुछ नहीं कर सकता। कैपिटल अकेले कुछ नहीं कर सकता!

बिना मेहनत के कैपिटल सिर्फ़ बेकार हो सकता है! इसलिए, सबसे ज़रूरी मांग, क्रांति का सबसे बड़ा काम, दुनिया भर में क्रांति का सबसे समझदारी भरा मतलब, पैसे पर ब्याज की गुलामी को खत्म करना है।

आज रोथ्सचाइल्ड हाउस की कीमत 40 बिलियन डॉलर है। अमेरिकन हाई फाइनेंस के अरबपति, मिस्टर कान, लोएब, शिफ, स्पेयर, मॉर्गन, वेंडरबिल्ट और एस्टोर की कुल कीमत 40 बिलियन डॉलर है।

कम से कम 60-70 बिलियन। सिर्फ़ 5% के इंटरेस्ट-रेट पर इसका मतलब है कि इन आठ परिवारों की इनकम 5-6 बिलियन है, जो कार्ल हेल्फ़रिच की रिसर्च के अनुसार, साल 1912 में प्रशिया के सभी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम का लगभग 75% है। (उस समय लगभग 21,000,000 टैक्सपेयर्स थे, जिनमें से 75% लगभग 15,000,000 होंगे। हर टैक्सपेयर्स के औसतन 1.56 रिश्तेदार हैं; इसलिए 23 मिलियन रिश्तेदार।)

इस तरह करीब 38,000,000 जर्मन लोगों को ऊपर बताए गए अरबपतियों की सालाना इनकम पर गुज़ारा करना पड़ा है। ज़रूर, अमेरिकी अरबपति उसी तरह प्योर लोन-कैपिटलिस्ट नहीं हैं जैसे रॉथ्सचाइल्ड हाउस वगैरह। मुझे इस बात पर बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अमेरिकी अरबपति असल में "100- मिलियन-डॉलर मिलियनेयर" हैं या "1000-

मिलियन-मार्क बिलियनेयर"; पहले वाले मामले में तो बस एक या दो दर्जन और क्रोइसस का हिसाब लगाना होगा। या फिर हम राथेनौ के "300" को मान लें; तब हमारी इन्वेंटरी ज़रूर ठीक हो जाएगी। यहाँ सही नंबर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 300 से 38,000,000 का माना हुआ रेश्यो इंटरनेशनल लोन-कैपिटल के क्रूर राज के बारे में हमारी आँखें खोलता है।

इसलिए, आइए हम इन भयानक ज़ंजीरों को तोड़ दें जो सिर्फ़ सारी मेहनत वाली मेहनत का गला घोंट सकती हैं; आइए हम पैसे से ब्याज देने की ताकत छीन लें, और तब तक ब्याज देते रहें जब तक कि पूरी इंसानियत इंटरनेशनल लोन-कैपिटल के ब्याज के लिए पूरी तरह से मजबूर न हो जाए।

इस प्रकार, ये तीन बिंदु हैं जो हमें पहली बार स्पष्ट करते हैं कि अकेले लीवर कहाँ है
हमारे अंदरूनी फाइनेंशियल संकट को कम करने के लिए इसे असरदार तरीके से लागू किया जा सकता है।

दूसरी बात, हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल के खिलाफ़ सोशलिस्ट विचारों की पूरी दुनिया का हमला पूरी तरह से गलत रहा है, क्योंकि अगर इकॉनमी कमज़ोर न हो तो भी सभी एंटरप्रेन्योरियल प्रॉफ़िट का पूरा रेगुलेशन या सोशलाइज़ेशन –

हमारे राइख और हमारे राज्य के बजट के भारी फाइनेंशियल बोझ की तुलना में, यह रकम बहुत ही कम होगी।

पैसे पर ब्याज की गुलामी खत्म करके पूरी फाइनेंशियल परेशानी एक ही झटके में खत्म की जा सकती है। तुरंत हमें अपने पैरों के नीचे फिर से मज़बूत ज़मीन महसूस होगी; तुरंत हमें यह साफ़ हो जाना चाहिए और हो जाएगा कि हमने इस बुरी बॉन्ड-इकॉनमी से सिर्फ़ खुद को सबसे अजीब तरीके से धोखा दिया है।

लोन-कैपिटल और क्या है, कर्ज़ के अलावा? लोन-कैपिटल तो कर्ज़ है! यह बात बार-बार नहीं दोहराई जा सकती। यह कैसा पागलपन है जब जर्मनी के लोगों ने अपनी पूरी लड़ाई के लिए 150 बिलियन का कर्ज़ लिया है? जब उसने इसके लिए खुद से 7½ बिलियन ब्याज के तौर पर देने का वादा भी किया है और अब वह खुद को एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जो शुरू से ही ज़रूरी थी, कि वह खुद से यह 7½ बिलियन पूरी तरह से मनगढ़ंत टैक्स के रूप में वसूलने की कोशिश करे?

卐卐卐卐卐

इस खुद को धोखा देने की दुखद बात इस पूरी वॉर-बॉन्ड इकॉनमी की बेवकूफी से ज़्यादा है, जिसका हमने हमेशा बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है, बल्कि यह है कि इससे बहुत कम बड़े कैपिटलिस्ट ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जबकि मीडियम और छोटे कैपिटलिस्ट के साथ-साथ बिज़नेस, ट्रेड और इंडस्ट्री समेत सभी मेहनतकश लोगों को ब्याज देना पड़ता है। और यहीं इस पूरे आइडिया का पॉलिटिकल पहलू सामने आता है। यहां वे यह पहचान सकते हैं कि असल में बड़ा लोन-कैपिटल और सिर्फ़ यही [यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल नहीं] पूरी मेहनतकश इंसानियत का श्राप है। कोई भी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से घुमा-फिरा सकता है, लेकिन आखिर में मेहनतकश लोगों को ही लोन-कैपिटल पर ब्याज चुकाने का खर्च उठाना पड़ता है। मीडियम और छोटे कैपिटलिस्ट के पास अपने प्यारे ब्याज चुकाने के लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं होता; उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि

ब्याज पर पूरी तरह से टैक्स लगना चाहिए। चाहे डायरेक्ट टैक्स के रूप में हो या इनडायरेक्ट टैक्स, स्टैम्प, टैरिफ या कॉमर्स पर दूसरे बोझ के रूप में, मेहनती लोग हमेशा बेवकूफ बनते हैं और बड़ी पूंजी को फायदा होता है। अब यह देखना काफी हैरान करने वाला है कि मार्क्स और एंगेल की सोशलिस्ट सोच की दुनिया कैसे बदल गई है।

अब यह देखना काफी हैरानी की बात है कि मार्क्स और एंगेल्स की सोशलिस्ट सोच की दुनिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेकर एरफर्ट प्रोग्राम (खासकर काउत्स्की) तक, और यहाँ तक कि आज के सोशलिस्ट नेता भी, लोन-कैपिटल के इंटरेस्ट को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे उन्हें कोई हुक्म हो। इंटरेस्ट की पवित्रता पर कोई रोक नहीं है; इंटरेस्ट सबसे पवित्र चीज़ है; अभी तक किसी ने इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की है। जबकि प्रॉपर्टी, अमीरी, इंसान और सामान की सिक्योरिटी, क्राउन के कानून, खास अधिकार और धार्मिक विश्वास, अफसरों का सम्मान, जन्मभूमि और आज़ादी कमोबेश गैर-कानूनी हैं, इंटरेस्ट पवित्र और अजेय है। दौलत को ज़ब्त करना और सोशलाइज़ेशन, इस तरह कानून का सीधा उल्लंघन जो बस थोड़ा मीठा होता है, जब तक कि वे दिखावे के लिए सभी लोगों के नाम पर किए जाते हैं, आजकल आम बात है: यह सब अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नोली मी टैंगेरे है, “मुझे मत छुओ।”

राइख के कर्ज़ पर ब्याज देना ही राज्य के बजट का अल्फा और ओमेगा है। इसका बहुत बड़ा वज़न राज्य के जहाज़ को रसातल में खींच ले जाता है और फिर भी... यह सब एक बड़ा धोखा है... बहुत बड़ा खुद को धोखा देना, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े पैसे वालों के फ़ायदे ए के लिए बनाया गया है।

यहां मैं छोटे पेंशनर्स से जुड़ी आपत्तियों पर थोड़ी बात करना चाहूंगा, जिन पर बाद में बात होगी, ताकि कोई उनके बारे में सोचते हुए उलझ न जाए। बहुत बड़े सवालों पर विचार करते समय इन पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुआवज़े सोशल-वेलफेयर सर्विसेज़ को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर दिए जाएंगे।

मैंने कहा , ठगी ! ब्याज-धोखाधड़ी! एक कड़ा शब्द। लेकिन अगर इस शब्द का कोई औचित्य है, जो युद्ध के दौरान शायद मैदान में और घर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द था, तो ब्याज-धोखाधड़ी के मामले में इसका सबसे ज़्यादा औचित्य है।

लेकिन वॉर-बॉन्ड का क्या? पहले 5 बिलियन के साथ, राइख ने लोगों की जेब से असल में मौजूद बचत निकाल ली। पैसा फिर से वापस बहने लगा। फिर पैसा चूसने के लिए नया लोन आया, और उसके साथ बची हुई बचत भी। और फिर, पंप आया और अरबों को चूस लिया, और फिर वे वापस नीचे आ गए, जब तक कि खुशी-खुशी, इस प्यारे खेल के नौ बार दोहराए जाने के बाद, राइख पर 100 बिलियन का कर्ज़ नहीं हो गया।

बदले में लोगों के हाथों में 100 बिलियन बारीक छपे हुए कागज़ थे - पहले तो हमने सोचा कि हम बहुत अमीर हो गए हैं - लेकिन फिर सरकार आती है और कहती है, "मैं दिवालिया होने का सामना कर रहा हूँ।"

हाँ, लेकिन क्यों? – मैं खुद तो पक्का दिवालिया नहीं हो सकता, भले ही मैं कभी-कभी अपनी दाहिनी ऊपरी जेब से सौ मार्क का नोट निकालकर बाईं जेब में डाल लूँ। पक्का, यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर हम दिवालिया घोषित करके अपनी वॉर-बॉन्ड इकॉनमी की बेवकूफी जारी रखें[4] ।

आइए, पैसे पर ब्याज की गुलामी को तोड़ें! आइए, वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट को लीगल टेंडर घोषित करें और ब्याज खत्म कर दें, और सरकारी बैंकरप्सी का बुरा सपना हमसे ऐसे पिघल जाएगा जैसे मार्च में सूरज के नीचे बर्फ पिघल जाती है।

4 फेडर यहां जर्मन देश को सिर्फ़ लोगों के ग्रुप के बजाय एक साथ देख रहे हैं: कुछ जर्मन लोगों से दूसरे जर्मन लोगों को ट्रांसफर किया गया पैसा जर्मन देश के अंदर ही रहता है, जिसका मतलब है कि जर्मन सरकार के पास डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करने का अधिकार है, शायद कुछ लोगों के लिए तुरंत नुकसानदायक हो लेकिन पूरे देश के लिए अच्छा हो।

लोग मुझसे कहते हैं; इंटरेस्ट पेमेंट कैंसल करना एक तरह से छिपा हुआ सरकारी बैंकरप्सी है।
नहीं, यह सच नहीं है! – सरकारी बैंकरप्सी का डर असल में सिर्फ़ एक परीकथा और एक डरावना सपना है जिसे मैमोनिस्ट ताकतों ने बनाया है।

फ्रांज रोहर की किताब, 'वाज़ जेडर वोम स्टैट्सबैंकरॉट विसेन मुस' [स्टेट बैंकरप्सी के बारे में हर किसी को क्या जानना चाहिए], पूरी तरह से मैमोनिस्टिक सोच पर टिकी हुई है।
हालांकि लेखक आम तौर पर उन आर्थिक समस्याओं को साफ़ तौर पर पहचानता है जो सोशलाइज़ेशन के ज़रिए हमारे लिए खतरा हैं, और हालांकि वह ज़ोर देकर और सही सलाह देता है कि आखिर में सिर्फ़ हमारी इकॉनमी को फिर से बनाना ही हमें बचा सकता है – वह खुद को ब्याज की पवित्रता में अंधविश्वास से आज़ाद नहीं कर पाता है, और इसलिए वह सरकारी दिवालियापन को पूरी तरह से मैमोनिज़्म के हित के हिसाब से, एक बहुत ही डरावनी तबाही के तौर पर दिखाता है।

यह देखना दिलचस्प है कि रोहर, बेहतर ऐतिहासिक जानकारी के बावजूद, खुद को मैमोनिस्टिक नज़रिए से आज़ाद नहीं कर पाए, और अपने आखिरी शब्दों में लिखते हैं: “अगर यह भयानक आर्थिक तबाही टाली नहीं गई, तो इससे कोई नहीं बचेगा,” जबकि पेज 81 पर वह मानते हैं कि पब्लिक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के नतीजे कुछ हद तक बहुत जल्दी उलट गए हैं, और पेज 68 पर वह कहते हैं कि किसी भी हाल में इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रूस (पिछली सदी में) इन करेंसी-क्राइसिस से बिना किसी लंबे समय तक चलने वाली दिक्कतों के उबर गया। पेज 76 पर वह कहते हैं, सरकारी बैंकरप्सी के असर की जांच करते हुए, कि हालांकि बेशक गहरी आर्थिक दिक्कतें वगैरह हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर न तो सरकारी तबाही हुई और न ही उसकी आर्थिक ताकत। इसके उलट, नेशनल इकोनॉमी में तेज़ी से सुधार और पब्लिक फाइनेंस में रिकवरी अक्सर देखी गई है। जब लेखक फिर तीन और लाइनें आगे कहते हैं कि सरकारी बैंकरप्सी का मतलब पक्का आर्थिक तबाही है और इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है; तो मुझे इस लॉजिक को न समझ पाने का अफसोस है।

लेकिन वापस हमारे खास मामले पर आते हैं! कौन सा ज़्यादा ईमानदार होगा? लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ डालकर उन पर ज़ुल्म करते हुए, वॉर-बॉन्ड की अजेयता के बारे में फरीसी की तरह बात करना?
या, अगर किसी फाइनेंस-मिनिस्टर में इतनी हिम्मत होती कि वह लोगों के सामने खुलकर कहता, “मैं वॉर-बॉन्ड पर इंटरेस्ट-पेमेंट नहीं कर सकता, या मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं आपसे ठीक उतना ही टैक्स जमा करूँ। “...लेकिन उस समय युद्ध के दौरान मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी; मुझे इससे ज़्यादा स्मार्ट (इंग्लैंड देखें) कुछ नहीं सूझा, और इसलिए मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट वाले वॉर बॉन्ड के साथ धोखाधड़ी की। आप मुझे माफ़ करें, प्यारे लोगों; यह सब आखिरकार आपके लिए ही था, लेकिन अगर हम अब और लुका-छिपी नहीं खेलना चाहते... तो मैं, राज्य, अब और इंटरेस्ट नहीं दूँगा, और आपको, टैक्सपेयर को, इन इंटरेस्ट पेमेंट को कवर करने के लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है... इससे हमारे लेन-देन पूरी तरह से आसान हो जाते हैं; हम बहुत बड़ी टैक्स-ब्यूरोक्रेसी और इसी तरह बहुत बड़ी इंटरेस्ट-पेइंग ब्यूरोक्रेसी से बचते हैं, इस तरह बहुत सारा पैसा और काम करने की क्षमता बचती है।”

मैंने इस धोखाधड़ी को उजागर करने में बहुत समय लगाया है, लेकिन मैं इसे बहुत ज़रूरी मानता हूँ
यहां किसी भी समय बड़ी तस्वीर से नज़र नहीं हटानी चाहिए।

卐卐卐卐卐

बवेरियन टैक्स-रिटर्न के अनुसार, जिन लोगों को नुकसान होगा — मान लीजिए, ठीक वही लोग जिन्हें उनके टैक्स-रिटर्न के अनुसार 30,000 मार्क्स से ज़्यादा ब्याज मिला — वे 822 लोग हैं, जो पूरे जर्मनी में टैक्स देने वालों (Bayr. St-Z. 1913) का सिर्फ़ 0.4% है, इसलिए, लगभग 10,000। (ऊपर के 10,000!)

आइए, अब हम इस क्रांतिकारी मांग की सबसे ज़रूरी बातों को जितना हो सके संक्षेप में अपने लिए साफ़ कर लें, और असल में, सबसे पहले इन सवालों पर अपने देश के नज़रिए से विचार करें।

इसके लिए सबसे पहले हमारी मौजूदा स्थिति को साफ़ तौर पर देखने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट यूजेन शिफ़र ने बर्लिन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स में अपने बड़े भाषण में कहा है कि इसे "नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है।" यह बात सिर्फ़ थोड़ी ही सही है। नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, हमारी नेशनल इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, और हमारी करेंसी का पहले कभी न हुआ डीवैल्यूएशन है —

संक्षेप में, सच तो यह है कि हम रातों-रात गरीब लोग बन गए हैं।

लेकिन, शांति-संधि के ज़रिए हम पर जो बोझ डाला जा रहा है, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा है, अभी कर्ज़ के जो सर्टिफिकेट मौजूद हैं, उनकी रकम लगभग 250 बिलियन है। चलिए पहले मान लेते हैं कि एंटेंटे हम पर किसी न किसी रूप में युद्ध-मुआवज़े के तौर पर और 50 बिलियन लगाता है: इससे कुल कर्ज़ लगभग 300 बिलियन हो जाता है।

भले ही यह इस किताब के छोटे दायरे पर कितना भी भारी पड़े, फिर भी जर्मन नेशनल वेल्थ के बारे में कुछ बातें ज़रूर कही जानी चाहिए। हेल्फ़ेरिच और स्टीनमैन-बुचर की जांच के मुताबिक जर्मन नेशनल वेल्थ लगभग 350 बिलियन है। ऐसे नतीजों को बहुत कम वैल्यू दी जा सकती है, चाहे वे कितनी भी सावधानी से निकाले गए हों। वे सिर्फ़ तब के लिए सही हैं जब कोई आर्थिक गतिविधि न हो। लेकिन वे काफी गुमराह करने वाले भी हैं क्योंकि इसमें राज्य और नगर निगम की प्रॉपर्टी भी शामिल हैं, जैसे सड़क की मरम्मत, पानी के रास्ते में बदलाव, वगैरह। यह साफ़ है कि भले ही ऐसे कामों को बनाने में बहुत पैसा लगा हो, फिर भी सच कहें तो उनकी कोई अंदरूनी वैल्यू नहीं है। नेशनल वेल्थ का एक बेहतर पैमाना तथाकथित टैक्सेबल वेल्थ है जो डिफेंस-कंट्रीब्यूशन या युद्ध के समय वेल्थ-टैक्स के लिए टैक्स-रिटर्न से निकलती है। इसके लिए कुल 192 बिलियन मिलते हैं, जो हेल्फ़ेरिच के आंकड़े से बहुत कम है। फिर भी, अनुभव के अनुसार, इस रकम में कानूनी तौर पर टैक्स-फ्री छोटी दौलत के लिए लगभग 10% और "साइलेंट रिज़र्व " के लिए लगभग इतनी ही रकम जोड़ी जा सकती है।

वैसे भी, मुझे 250 बिलियन से ज़्यादा की नेशनल वेल्थ की बात करना ज़्यादा उम्मीद भरा लगता है। लेकिन इस नंबर की भी बहुत कम अहमियत है। सबसे सही बात यह होगी कि हम इस सोच से पूरी तरह अलग हो जाएं कि नेशनल वेल्थ को नंबरों के हिसाब से समझा जा सकता है, और इस बात को समझें कि नेशनल वेल्थ सिर्फ़ पूरे देश की मेंटल और फिजिकल काम करने की क्षमता में दिखती है, और इस तरह यह उस लेवल की है जिसका कैपिटल के छोटे कॉन्सेप्ट से कोई लेना-देना नहीं है। सच तो यह है कि हमें मिनरल रिसोर्स, जंगल की दौलत और उपजाऊ मिट्टी में नेशनल वेल्थ का एक और सोर्स देखना होगा, लेकिन इन चीज़ों को भी नंबरों के हिसाब से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़ीरो और इनफिनिटी के बीच ऊपर-नीचे होती रहती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिनरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या, जियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर, उन्हें अरबों टन कोयला माना जा सकता है और

जल्द ही।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी सच में एक गरीब देश है। उसके पास मोनोपॉली लगभग नहीं है। मिनरल रिसोर्स की दौलत में, यह अपने ज़्यादातर पड़ोसियों से बहुत पीछे है, चीनी, भारतीय और अमेरिकी साम्राज्यों के बेमिसाल मिनरल रिसोर्स की तो बात ही छोड़िए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के मामले में यह रूस की काली मिट्टी के उपजाऊ खेतों और ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल ज़मीन के आसानी से उपजाऊ हिस्सों के मुकाबले बहुत पीछे है। इसलिए, आखिर में हमारे पास हमेशा सिर्फ़ हमारे लोगों की काम करने की क्षमता और इच्छाशक्ति होती है, साथ ही काफ़ी काम की मौजूदगी भी होती है, और हमें यह साफ़ तौर पर समझना चाहिए कि इस हालत में सिक्योर्ड कर्ज़, हमारे कर्ज़ के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोलैटरल की कोई बात नहीं हो सकती...

---

5 "साइलेंट रिज़र्व" अकाउंटिंग में पॉज़िटिव वैल्यू को कम आंकने और नेगेटिव वैल्यू को ज़्यादा आंकने का नतीजा हैं, इसलिए ताकि सबसे कम नेट-वर्थ का दिखावा किया जा सके।

चाहे ब्याज वाले वॉर-बॉन्ड हों या बिना ब्याज वाले राइख बैंकनोट, उनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी जनता की टैक्स-पोटेंशियल होती है – और टैक्स-पोटेंशियल पूरी वर्किंग पॉपुलेशन की वर्क-पावर के फ़ंक्शन के अलावा और क्या है?

卐卐卐卐卐

अब हमें अपने लिए एक और ज़रूरी सवालों के कॉम्प्लेक्स को साफ़ करना होगा, और बेशक हमारे राज्य के रेवेन्यू-सोर्स और खर्चों की मुख्य एंट्रीज़ को भी। हमारी निजी ज़िंदगी में पैसा कमाने की चिंता और हमारे राज्य के फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के बड़े सवालों पर हम जो ध्यान देते हैं, उनके बीच एक बड़ा फ़र्क है, और फिर भी इंडिविजुअल इकॉनमी और नेशनल इकॉनमी के बीच कोई ज़रूरी फ़र्क नहीं है।

राज्य के रेवेन्यू के लिए मुख्य एंट्री हैं: पहला, पोस्ट-ऑफिस और रेलवे का नेट प्रॉफ़िट; दूसरा, माइंस, फॉरेस्ट्री-एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे सरकारी एंटरप्राइज़ का; तीसरा, टोल और इनडायरेक्ट टैक्स; चौथा, डायरेक्ट टैक्स।

ऐसे बहुत प्रैक्टिकल सवालों पर सिर्फ़ थ्योरी वाली चर्चा को बढ़ावा न देने के लिए, मैं साल 1911 के बवेरियन स्टेट बजट की अलग-अलग एंट्रीज़ को उनके हिसाब से समझाना चाहता हूँ। पोस्ट, टेलीग्राफ़ और रेलरोड से 120 मिलियन आए; जंगल, खदानें वगैरह से लगभग 40 मिलियन; इनडायरेक्ट टैक्स से 53 मिलियन; डायरेक्ट टैक्स से 60 मिलियन। इसके अलावा 67 मिलियन स्टाम्प-ड्यूटी, फीस, विरासत-टैक्स, ज़मीन-टैक्स, राइख से रेवेन्यू-ट्रांसफर वगैरह से आए।

खर्चों का क्या? सबसे पहले, हम यहाँ 85 मिलियन के साथ रेलवे के कर्ज़ सहित सरकारी कर्ज़ पर ब्याज के पेमेंट को देखते हैं। शाही घराने के लिए, 5 मिलियन; न्याय प्रशासन के लिए, 27 मिलियन; अंदरूनी प्रशासन के लिए, 40 मिलियन; चर्च और स्कूल के लिए, 51 मिलियन; फाइनेंशियल प्रशासन के लिए, 13 मिलियन; राइख से जुड़े कामों के लिए खर्च, 50 मिलियन; पेंशन के लिए, 36 मिलियन। अलग-अलग खर्च 5 मिलियन। उस समय, बवेरियन फाइनेंस के इस अच्छे साल में, सालाना बजट में 27 मिलियन का रेवेन्यू-सरप्लस बचा था।

लेकिन हमारी सोच के दायरे में सिर्फ़ वही खर्चे आते हैं जिन्हें ब्याज़-गुलामी खत्म करके छोड़ा जा सकता है। यहाँ सरकारी कर्ज़ पर ब्याज़-पेमेंट सबसे पहले आता है, जो 85 मिलियन मार्क्स है; इसमें फ़ाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पेमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा, जो लगभग 10 मिलियन है, जोड़ दें; इसके अलावा, राइख से जुड़े कामों के लिए पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें से आधा, 25 मिलियन, और आखिर में शाही घराने के लिए पेमेंट के 5 मिलियन अब खत्म हो गए हैं: कुल 125 मिलियन।

इन एंट्री के गायब होने का मतलब है कि सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने की संभावना है , जिससे, जैसा कि हमने देखा, 53 मिलियन और 60 मिलियन मार्क्स आए, यानी कुल 113 मिलियन मार्क्स!

अब हम इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पूरी तरह खत्म कर देने चाहिए; बेशक, सही लिमिट के अंदर वे एक तरफ एजुकेट करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ रेगुलेट करने का। यह निश्चित रूप से सही और फेयर है कि फ्री और क्लियर प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट पर एक मॉडरेट, ग्रेजुएटेड टैक्स लगे, क्योंकि राज्य को अपनी पुलिसिंग एजेंसियों के साथ सिक्योर ओनरशिप भी बनाए रखनी चाहिए। यह भी उतना ही सही लगता है कि ट्रेड और इंडस्ट्री को अपने वर्किंग प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स-कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि राज्य को उनके लिए कॉमर्स के पब्लिक रास्तों के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होता है। वोट देने के हकदार हर नागरिक के लिए एक मिनिमम पोल-टैक्स भी इसी तरह एक

निष्पक्षता की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति और उसकी संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखना भी राज्य से अपेक्षित है।

इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में, सभी प्योर लग्ज़री-टैक्स को मज़बूती से बढ़ाने से सबसे अच्छे तरीके से रेगुलेटरी असर होता है, जबकि लोगों के सभी आम खाने-पीने की चीज़ों और ज़रूरतों को टैक्स से मुक्त रखा जाना चाहिए!

ऐसी टैक्स-पॉलिसी का नतीजा ज़्यादा रेवेन्यू में कम मिलेगा – जिसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर आबादी के लिए टैक्स असली बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ एक याद दिलाने वाला होना चाहिए कि इंसान सिर्फ़ एक इंसान ही नहीं है, बल्कि देश का नागरिक भी है, और नागरिक अधिकारों के अलावा उसके नागरिक कर्तव्य भी हैं।

सरकारी बिज़नेस के कर्ज़ चुकाने के लिए टैक्स से होने वाली कमाई कम ज़रूरी होनी चाहिए, जिनका नेट-प्रॉफिट, जैसा कि हमने देखा है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, न्याय प्रशासन, अंदरूनी प्रशासन वगैरह के लिए राज्य के आम खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। टैक्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राज्य के खास सांस्कृतिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए आम राज्य बजट के दायरे में कभी भी ज़रूरी रिसोर्स मौजूद नहीं थे। यहाँ मैं मुख्य रूप से अनाथालयों, अंधों और अपाहिजों के लिए इंस्टिट्यूट, डे-केयर सेंटर, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीबी, शराब और यौन रोगों के खिलाफ लड़ाई, और गार्डन-सिटी और बस्तियों के निर्माण के बारे में सोच रहा हूँ, खासकर हमारे युद्ध में विकलांग हुए लोगों के रहने और उनकी मानवीय देखभाल के लिए।

हमारी सोच बड़ी होती है। हम वर्जिन लैंड देखते हैं। क्या ब्याज-गुलामी खत्म होने का मतलब सभी टैक्स खत्म करना हो सकता है? इसका मतलब यह होगा, अगर हम इस बड़े संघर्ष से जीतने वाले लोगों के तौर पर निकले होते। जैसे हालात हैं, हमें बहुत जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए; हमारे दुश्मनों ने हम पर जो बोझ डाला है, वह यह पक्का करेगा कि हम ऐसा न करें। लेकिन किसी भी हाल में, हम वर्जिन लैंड को अपने बवेरियन स्टेट बजट के बहुत ही आसान उदाहरण के आधार पर देखते हैं, जिसका हमने अभी इस्तेमाल किया है...

आम तौर पर हम दूसरे जर्मन फ़ेडरल राज्यों में भी काफ़ी मिलते-जुलते रिश्ते देखते हैं, और यह कहना ज़्यादा नहीं होगा कि सरकारी बिज़नेस, रेलवे, पोस्ट-ऑफ़िस, टेलीग्राफ़, जंगल, खदानें वगैरह के सरप्लस से, पूरे न्याय प्रशासन के लिए, सभी अंदरूनी प्रशासन के लिए, जिसमें सरकारी कंस्ट्रक्शन-प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के लिए सभी खर्च, और सांस्कृतिक कामों के लिए, सभी खर्च बिना किसी मुश्किल के पूरे किए जा सकते हैं। इस तरह, यह एक बिल्कुल सही हालत है।

ऐसा क्यों नहीं है? ब्याज तो आ गया है। ब्याज देने की वजह से लोगों का खाना महंगा हो जाता है; ब्याज की वजह से चीनी और नमक, बीयर और वाइन, माचिस और तंबाकू और रोज़मर्रा की ज़रूरत की अनगिनत दूसरी चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है।

ब्याज की वजह से, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिन्हें ज़मीन पर लगने वाले टैक्स में बांटा जाता है, जो अनाज की ज़्यादा कीमतों के रूप में आगे बढ़ते हैं, घर पर लगने वाले टैक्स जो किराया बढ़ाते हैं, और बिज़नेस पर लगने वाले टैक्स जो
प्रोडक्टिव लेबर पर बोझ, इनकम-टैक्स जो सिविल सर्वेंट्स और फिक्स्ड सैलरी पाने वाले लोगों के रहन-सहन के स्टैंडर्ड को ज़रूर कम कर देते हैं, और आखिर में, देने में कम लेकिन लेने में कभी न थकने वाली, लोन-कैपिटल कैपिटल डिविडेंड पर टैक्स देती है। साल 1911 के टैक्स-रिटर्न के मुताबिक, बवेरिया में मिले 253 मिलियन कैपिटल डिविडेंड में से, पूरा 8.1 मिलियन स्टेट टैक्स के तौर पर दिया गया था।

हमने देखा है कि सभी कैपिटल डिविडेंड, कैपिटल पर सारा ब्याज, आखिरकार सभी लोगों की मेहनत से जुटाया जाना चाहिए। हमने देखा है कि पब्लिक कर्ज़ पर ब्याज का पेमेंट

यह हमारे राज्य के बजट में सबसे बड़ी एंट्री है, और हमने देखा है कि जिन लोगों को ब्याज पर टैक्स देना होता है, वे राज्य के रेवेन्यू में बहुत कम योगदान देते हैं।

रिलेटिव मैग्नीट्यूड के हिसाब से, कैपिटलिस्ट ने कुल 60 मिलियन में से 8 मिलियन डायरेक्ट टैक्स के तौर पर दिए, जो 1911 में बवेरिया में दिए गए डायरेक्ट स्टेट टैक्स का सिर्फ़ आठवां से छठा हिस्सा है। लेकिन, डायरेक्ट टैक्स कुल स्टेट रेवेन्यू का सिर्फ़ पाँचवां हिस्सा है। इसलिए लोन-कैपिटल राज्य की कुल ज़रूरतों में सिर्फ़ तीसवां से अड़तालीसवां हिस्सा ही देता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध के दौरान, खासकर पिछले सालों में, टैक्स-कानूनों में कैपिटल डिविडेंड पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, लेकिन ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन ने भी कमोबेश इसके साथ तालमेल बनाए रखा है, इसलिए रिलेटिव साइज़ में शायद ही कोई बदलाव आया हो।

जब हम राइख के बजट पर विचार करते हैं तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। यहां अनुपात अपने आप में पहले से ही बहुत कम अनुकूल हैं। राइख के पास अलग-अलग फेडरल राज्यों की तरह टैक्स के सोर्स नहीं हैं। डायरेक्ट टैक्स फेडरल राज्यों के लिए रिज़र्व हैं; राइख के काम राइख के पोस्ट-ऑफिस और रेलरोड तक सीमित हैं (ध्यान दें कि इसमें प्रशिया के राज्य रेलरोड शामिल नहीं हैं), और इसलिए केवल टोल और इनडायरेक्ट टैक्स ही बचे हैं।

रीच के रेवेन्यू-सोर्स (साल 1917 और 1918 के लिए स्टेटिस्टिशेस जहरबुख फर दास ड्यूश रीच देखें) का बड़ा ऑर्डर , साल 1915 में, इनडायरेक्ट टैक्स में 1 बिलियन, स्पेशल रेवेन्यू (युद्ध-योगदान, मैट्रिकुलर फीस) में 0.8 बिलियन, वगैरह थे। यहां भी वही तस्वीर है। एक तिहाई से ज़्यादा, खास तौर पर 1.3 बिलियन, साल 1915 में ही रीच के कर्ज पर ब्याज के पेमेंट में खत्म हो गया था। यहां भी लोन-कैपिटल ने फिर से अपनी जगह बनाई। यहां भी इसे पूरा करने के लिए सभी डायरेक्ट टैक्स की ज़रूरत है। चीनी पर 163 मिलियन, नमक पर 61 मिलियन, बीयर पर 128 मिलियन, तंबाकू, श्नैप्स, स्पार्कलिंग वाइन, लैंप-फ्यूल, माचिस, ताश, और अनगिनत दूसरी चीज़ों पर टैक्स लगाना पड़ा ताकि एक बिलियन मार्क जमा हो सकें जो फिर पूरी तरह से कैपिटलिस्ट की जेब में चला जाता है।

आज, राइख के कर्ज़ पर ब्याज कैसे चुकाया जाए, यह एक पहेली है। सिर्फ़ ब्याज देने में ही [सालाना] 8 बिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं, जो 100 बिलियन वॉर-बॉन्ड और दूसरे वॉर क्रेडिट पर आधारित है। पोस्ट-ऑफिस और रेलरोड से होने वाली कमाई को शायद ही और बढ़ाया जा सकता है। टोल में और बढ़ोतरी शायद ही बर्दाश्त की जाएगी; इसलिए, शायद इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ़ पाँच या दस गुना बढ़ोतरी ही बची है — जो नामुमकिन है! — या यह साफ़ समझ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे पर ब्याज की गुलामी खत्म करने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। पूरी वॉर बॉन्ड इकॉनमी एक बहुत बड़ा खुद को धोखा देने वाली थी। जर्मन देश ने अपनी लड़ाई के लिए खुद से सौ बिलियन डॉलर उधार लिए। इसके लिए उसने खुद को 5 बिलियन डॉलर ब्याज में देने का वादा किया; इसलिए उसे 5 बिलियन डॉलर टैक्स देना होगा। सारा फ़ायदा बड़े कैपिटलिस्ट को जाता है, जो कैपिटल डिविडेंड में इतना ज़्यादा पैसा खींचता है कि वह उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, और फिर भी कैपिटल डिविडेंड पर टैक्स के ज़रिए उसका बहुत कम हिस्सा ही लिया जाता है, जैसा कि हमने देखा है।

卐卐卐卐卐

मुझे उम्मीद है कि अब मेरे प्रेजेंटेशन के मुख्य पॉइंट्स से कई रीडर्स के मन में यह डर दूर हो गया होगा कि आखिरकार उन्हें अपने सुंदर सर्टिफिकेट्स से मिलने वाली इंटरेस्ट-इनकम खोनी पड़ेगी। बस एक उदाहरण से यह दिखाना है कि पूरी इंटरेस्ट-इकॉनमी एक बड़ा खुद को धोखा है, और इसके साथ ही मैं एक ऊपरी लेवल की सॉलिड मिडिल-क्लास इनकम को देखना चाहता हूं।

मान लीजिए कि एक घर के मुखिया की मेहनत से 10,000 मार्क की इनकम है, और उसके ऊपर कैपिटल डिविडेंड से 5000 मार्क और हैं। सबसे पहले, इसमें से लगभग 1500 मार्क डायरेक्ट टैक्स में दिए जाएंगे; फिर कम से कम 1000-1200 मार्क ज़्यादा किराए के रूप में मिलेंगे।

हमेशा के लिए ब्याज के लिए छीन लिया गया। पांच या छह लोगों के परिवार के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में और 1000 मार्क निकलने की संभावना है, और अब यह एहसास हो रहा है कि छोटे और मध्यम आकार के पूंजीपतियों को पहले के सालों के अच्छे टैक्स रेट के तहत जो शानदार कैपिटल डिविडेंड मिलते थे, उनमें से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। असल में, आज "सरप्लस" की कोई बात नहीं हो सकती; इसके उलट, अगर कोई आज खुद मौजूदा शानदार टैक्स-प्रपोज़ल की जांच करे, तो शायद मेहनत से होने वाली काफी ज़्यादा इनकम पर टैक्स लगेगा।

ज़ाहिर है, बड़े कैपिटलिस्ट के लिए हालात काफ़ी अलग लगते हैं, जो, मान लीजिए, कैपिटल डिविडेंड में सिर्फ़ 1 मिलियन जमा करते हैं। (आज जर्मनी में ऐसे लोग काफ़ी हैं।) कैपिटल डिविडेंड पर टैक्स में से यह खुशकिस्मत आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार मार्क देता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी वह पिछले उदाहरण के परिवार के पिता से ज़्यादा नहीं देता। आख़िरकार, अपने बजट के हिसाब से वह आज के महंगे ज़माने में भी 40-50 हज़ार मार्क में काफ़ी आराम से रह सकता है। अगर उसके पास लगभग 900,000 मार्क कैश बचता है, तो लोन पर 5% ब्याज के साथ उसे अगले साल और 45,000 मार्क मिलेंगे और वह भी, कानून के हिसाब से, काम करने वाले लोगों की कीमत पर।

जो छोटा पेंशनर सिर्फ़ अपने ब्याज पर गुज़ारा करता है, उसे ज़रूर नुकसान होगा। अगर वह काम कर सकता है, तो उसे ज़रूर मेहनत से कमाई करने का फ़ैसला करना चाहिए। इससे वह अपने उन लाखों साथियों से कहीं बेहतर हालत में होगा जिनके पास सिर्फ़ अपनी शारीरिक या मानसिक काम करने की क्षमता है। अगर वह ऐसा नहीं चाहता, तो उसे अपनी दौलत खानी होगी। आख़िरकार, उसके पास इसे बार-बार खाने के लिए 20 साल हैं, अगर वह 5% ब्याज पर मिलने वाली सालाना रकम खर्च करता रहता है। जो लोग काम करने की हालत में नहीं हैं, या बीमारी या उम्र की वजह से कमज़ोर हैं, उनके लिए ज़ाहिर है कि आबादी के सभी हिस्सों के लिए सोशल वेलफ़ेयर के विकास के ज़रिए सही रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए।

मैं सामाजिक कल्याण को इस तरह देखता हूँ:

मान लीजिए कि एक बूढ़ी औरत, एक विधवा, जिसे अब तक 60,000 मार्क के कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले ब्याज पर गुज़ारा करना पड़ता था, कानूनी तौर पर घोषित ब्याज-गुलामी खत्म होने की वजह से, उसकी इनकम का सोर्स छीन लिया गया है। यहां, पेंशन-सिस्टम को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर, ऊपर बताए गए व्यक्ति को अपनी कैपिटल के हिसाब से पेंशन लेने का मौका दिया जाएगा, जिससे सालाना पेंशन को पिछले ब्याज-यील्ड के मुकाबले बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि इस ग्रुप के लोगों को भी पैसे की कम हुई वैल्यू के लिए कुछ मुआवजा मिल सके। इस तरह, उदाहरण के लिए, राइख, राज्यों के डेट-इंस्ट्रूमेंट्स या कवर्ड बॉन्ड में सरेंडर किए गए 60,000 मार्क के बदले, 4000 मार्क की सालाना लाइफलॉन्ग पेंशन दी जा सकती है। अगर विधवा के बच्चे हैं और वह अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उन्हें देना चाहती है, तो उसे सिर्फ़ 40,000 मार्क्स पेंशन में बदलने की इजाज़त दी जा सकती है, जबकि बाकी 20,000 बच्चों के लिए रखे जाएँगे। 40,000 मार्क्स में से, पेंशन-एप्लीकेंट की उम्र के हिसाब से, मिली हुई पूंजी का 1/12 हिस्सा सालाना दिया जा सकता है। इसके अलावा, यहाँ यह भी ध्यान दें कि ब्याज-गुलामी खत्म होने की वजह से ज़्यादा टैक्स बंद होने से विधवा के गुज़ारे का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा।

आबादी के हर तबके के निजी हितों की विस्तार से जांच करना इस लेख के दायरे से बाहर होगा। ऐसी क्रांतिकारी मांग निजी हितों के बारे में नहीं हो सकती; फिर भी, जैसे-जैसे यह विचार असर करेगा, कोई पाएगा कि इसके अच्छे नतीजे आखिर में हर व्यक्ति को निजी तौर पर फ़ायदा पहुंचाएंगे।

ठीक ऊपर बताई गई समस्या, कि वॉर-बॉन्ड पर ब्याज से कैसे छुटकारा पाया जाए, के ज़रिए मैंने यह साफ़ करने की कोशिश की है कि छोटे कैपिटलिस्ट – मेरा मतलब है वे लाखों लोग जिन्हें हाइपर-अमेरिकन एडवरटाइजिंग के ज़रिए लुभाया गया है –

युद्ध-बांड के लिए अपनी बचत को समर्पित करने का अभियान - न केवल ब्याज से कोई लाभ प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि निश्चित रूप से उन्हें करों के साथ इसके लिए स्वयं भुगतान करना होगा, बल्कि, बड़ी पूंजी की सुरक्षा के लिए तैयार कर-कानून के साथ, मिलियन-मार्क सदस्यता के लिए ब्याज-भुगतान का समर्थन करना चाहिए।

मुझे लगता है कि इन तुरंत की बातों के अलावा, अपने बच्चों की भलाई के लिए सभी से की गई अपील, परेशान बॉन्डहोल्डर को यह मानने के लिए राज़ी कर लेगी कि वे राइख के कर्ज़ों से हमेशा के लिए ब्याज देना छोड़ दें। ऐसे में, जिस देशभक्त ने अपनी मातृभूमि को सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय 10,000 मार्क दिए हैं, उसे असल में क्या नुकसान होगा, सिवाय इसके कि वह सौ साल के अंदर 50,000 मार्क ब्याज लेने का लालची दावा करेगा, और वह भी बिना मूलधन कम किए? उसके बच्चों और नाती-पोतों को हमेशा काम करना होगा, ताकि सारा ब्याज चुकाया जा सके।

卐卐卐卐卐

उधार दी गई रकम चुकाने का सवाल कई तरीकों से हल किया जा सकता है। इस समस्या के बारे में मेरे मुख्य विचार, जो मैंने पिछले साल 20 नवंबर [1918] को बवेरिया के पीपुल्स स्टेट [कर्ट आइज़नर के तहत] की सरकार को दिए थे, में मैंने बस यह प्रस्ताव रखा था कि 20 साल तक हर साल 5% की दर से ब्याज देने की जगह चुकाने का प्रस्ताव रखा जाए। मेरा मानना है कि आगे मैं एक और भी बेहतर सुझाव दे सकता हूँ, जो अपनी सादगी के कारण निश्चित रूप से पसंद किया जाना चाहिए: "ब्याज रद्द होने पर वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट को करेंसी घोषित कर दिया जाएगा।" यह कोलंबस का अंडा है। इस उपाय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी को भी इससे कुछ खास महसूस नहीं होता। वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट डिपो में पड़े रहते हैं; लेकिन किसी भी युवा को वे नहीं मिलते, ठीक वैसे ही जैसे कोई किताब, या कैबिनेट, या कोई और काम की चीज़ जो कोई अपने दोस्त को उधार दे।

अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वह बस एक वॉर-बॉन्ड नोट निकालता है और उससे पेमेंट कर देता है।
आखिरकार, वॉर-बॉन्ड नोटों में भी उतनी ही खूबसूरती और पेपर-वैल्यू होती है जितनी हमारे दूसरे 10, 20, 100, और 1000-मार्क नोटों में होती है। इंटरेस्ट-इकॉनमी से इंटरेस्ट-फ्री नेशनल इकोनॉमी में ऐसे बिना किसी रुकावट के बदलाव में मार्केट के करेंसी से भर जाने की कोई बात नहीं हो सकती।
इकॉनमी। सभी वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट असल में पहले से ही अच्छी तरह से सुरक्षित हैं और बैंक वॉल्ट में, या लोगों द्वारा सुरक्षित मानी जाने वाली दूसरी छिपने की जगहों, जैसे ऊनी मोज़े या खाद के ढेर में रखे हुए हैं। असल में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी जारी की गई पेपर करेंसी, लगभग 40 बिलियन, भी सर्कुलेशन में नहीं है, बल्कि ज़्यादातर ऊपर बताए गए तरीके से जमा की गई है। युद्ध से पहले इकॉनमिक बूम के समय में भी हमें करेंसी की ज़रूरत सिर्फ़ लगभग 4-6 बिलियन थी, और यह सोचा भी नहीं जा सकता कि आज की ज़्यादा आम कैशलेस इकॉनमी में हमें इससे दोगुने से ज़्यादा की ज़रूरत होगी6 ।

卐卐卐卐卐

सभी फिक्स्ड-इंटरेस्ट एसेट्स के लिए इंटरेस्ट कैंसलेशन ठीक उसी तरह किया जाना है। इन एसेट्स के लिए, डिविडेंड देने वाले एसेट्स की तरह ही, 20 या 25 साल की सालाना पेंशन में शुरू में सुझाए गए "रीपेमेंट" की सलाह दी जाती है, खासकर मॉर्गेज के लिए।

मॉर्टगेज के लिए ब्याज-गुलामी खत्म होने का मतलब बिना किसी शक के हाउसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा किराए से आज़ादी। यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि होल्डर क्यों

6 बाद के एक सेक्शन में फेडर कहते हैं कि उन्होंने तय किया है कि सिर्फ़ वॉर-बॉन्ड सर्टिफ़िकेट को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने देना सही नहीं है।
सबसे अच्छा आइडिया है। उनका सुझाव है कि इसके बजाय उन्हें बैंक-क्रेडिट में बदल दिया जाना चाहिए।

एक मॉर्गेज को एक बार उधार दी गई रकम पर हमेशा ब्याज का फायदा क्यों मिलना चाहिए, उसे बिना किसी मेहनत के और कभी न खत्म होने वाला सामान क्यों मिलना चाहिए, क्यों लोगों का एक बड़ा हिस्सा, सिर्फ इस खराब ब्याज के नियम के लिए, साल-दर-साल ऊंचा किराया देता रहे। यह बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि किराया पूरी तरह खत्म करने की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि घरों के मैनेजमेंट और रखरखाव में लगातार मेहनत और पैसा लगता है। इस तरह किराए में कमी तभी हो सकती है जब यह मॉर्गेज के पूरे पेमेंट के ज़रिए अपने आप हो।

सिर्फ़ एक बात पर ज़ोर देना चाहिए, कि ब्याज़ की गुलामी खत्म होने का हमारे कुल वैल्यू बनाने वाले काम से ज़रा भी लेना-देना नहीं है, जब तक कि काम करने की भावना, प्रोडक्टिव काम, सामान बनाने, दौलत कमाने में किसी भी तरह की रुकावट न आए। इसके उलट, जैसा कि हमने देखा है, पूरी मेहनत करने वाली आबादी एक दम घोंटने वाले, बेमतलब, भारी बोझ से आज़ाद हो जाती है; हमारी रूह की ज़िंदगी एक नशीले ज़हर से साफ़ हो जाती है।

卐卐卐卐卐

हम यह बता सकते हैं कि इतिहास में ब्याज की समस्या कितनी फायदेमंद रही है, क्योंकि हर उम्र और हर व्यक्ति का दिमाग इसी में लगा रहा है...

ओल्ड टेस्टामेंट के अलग-अलग हिस्सों में, जैसे कि लेविटिकस 25 और ड्यूटेरोनॉमी 15 में, हमें ब्याज बंद करने के बारे में नियम मिलते हैं, जैसे कि सातवां साल हमेशा एक एक्सेप्टिलेशन या जुबली होना चाहिए, जिसमें लोक-साथियों के सभी कर्ज़ माफ कर दिए जाने चाहिए।

साल 594B.C. में सोलन ने कानून बनाकर पर्सनल कर्ज़-गुलामी को खत्म कर दिया। इस कानून को ग्रेट सेसाचथिया (बोझ उतारना) कहा जाता था।

प्राचीन रोम में 332 BC के लेक्स जेमिसिया ने रोमन नागरिकों को कोई भी ब्याज लेने से अचानक पूरी तरह मना कर दिया था।

जस्टिनियन के राज में कंपाउंड इंटरेस्ट पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें यह नियम था कि जब बकाया इंटरेस्ट, शुरू में दी गई रकम के बराबर जमा हो जाए, तो उससे और इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा।

पोप लियो I (महान) ने साल 443 में ब्याज लेने पर आम रोक लगा दी थी; तब तक सिर्फ़ पादरियों को ही लोन पर ब्याज मांगने से मना किया गया था। ब्याज पर रोक अब कैनन लॉ का हिस्सा थी और आम लोगों के लिए भी एक ज़रूरी नियम थी। सेक्युलर कानून भी धीरे-धीरे कैनन के विचारों के हिसाब से ढल गए, और ब्याज लेने पर सज़ा देने की धमकी भी दी गई। यह हमें पवित्र रोमन साम्राज्य के साल 1500, 1530, और 1577 के पुलिस कानूनों में मिलता है।

बेशक, ऐसे कानूनों का अब बहुत विरोध किया जाता था और अक्सर उन्हें टाला जाता था, और इस छोटी सी ऐतिहासिक घटना में इसे एक हैरान करने वाली ऐतिहासिक बात के तौर पर ही बताया जा सकता है कि हालांकि 11वीं से 17वीं सदी के कैनन कानून के तहत ईसाइयों के लिए ब्याज लेना मना था, लेकिन यहूदियों के लिए इसकी इजाज़त थी।

हर मामले में यह देखना बहुत अच्छा होगा कि किन आर्थिक दिक्कतों की वजह से इतने बड़े पैमाने पर बोझ कम हुए। यह देखना खास तौर पर फायदेमंद होगा कि किन ताकतों और ताकतों ने ब्याज पर लगी रोक को बार-बार तोड़ा है।

मध्य युग में ज़रूर सूदखोरों से अक्सर छोटे काम करवाए जाते थे; किसान या नागरिक जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते थे, वे एक साथ मिलकर मुनाफाखोरों को पीट-पीटकर मार डालते थे। आज हमारे पास

ब्याज की समस्या के एक बिल्कुल अलग दौर में प्रवेश कर गया है। ऐसे नरसंहारों को बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है।

साथ ही, अब यह बीमारी के किसी एक खास लोकल लक्षण का मामला नहीं है, जिसे मवाद निकालकर ठीक किया जा सकता है; जो हो रहा है, वह पूरी इंसानियत के लिए एक गंभीर बीमारी है।

इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि हमारी आज की संस्कृति, और आर्थिक संबंधों की इंटरनेशनलिटी ही इंटरेस्ट-प्रिंसिपल को इतना जानलेवा बनाती है।

ऊपर बताई गई ऐतिहासिक घटनाओं को आज के हालात का उदाहरण नहीं मानना चाहिए। जब बेबीलोन के लोगों ने असीरियन को हराया, रोमनों ने कार्थागिनियों को, और जर्मनों ने रोमनों को, तब ब्याज की गुलामी जारी नहीं थी; कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड-पावर नहीं थीं। लड़ाइयों को भी उधार लेकर नहीं, बल्कि शांति के दौरान जमा किए गए खज़ानों से फाइनेंस किया जाता था। डेविड ह्यूम ने अपनी किताब 'एस्से ऑन पब्लिक क्रेडिट' में इसका बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया है। सिर्फ़ मॉडर्न ज़माना ही, अपनी ओनरशिप की कंटिन्यूटी और अपने इंटरनेशनल लॉ के साथ, लोन-कैपिटल को इनफिनिटी तक बढ़ने देता है। ईसा मसीह के जन्म के समय जो पैसा ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया था, वह अब नहीं रहा, क्योंकि तब से ओनरशिप के सभी अधिकार कई बार हिंसा के आगे झुक गए हैं; इसके उलट, जो पैसा पुराने रोथ्सचाइल्ड ने ब्याज पर इन्वेस्ट किया था, वह आज भी मौजूद है, और अगर इंटरनेशनल लॉ है, तो हमेशा रहेगा।

इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धरती के बड़े हिस्से आज के ज़माने में ही नेचुरल इकॉनमी से मनी-इकॉनमी में बदले हैं। इस बारे में यह बात खास तौर पर ज़रूरी है कि 19वीं सदी के बीच में ही ब्याज लेने पर लगी सभी रोक, और इसी तरह ब्याज पर लगी सभी रोक खत्म कर दी गईं: जैसे, इंग्लैंड ने साल 1854 में, डेनमार्क ने 1856 में, बेल्जियम ने 1865 में, ऑस्ट्रिया ने 1868 में।

इस तरह, आज ब्याज को पैसे के होने से अलग न करने का कॉन्सेप्ट आधी सदी से ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन ठीक इसी ब्याज-कॉन्सेप्ट ने पहली बार पैसे को ऐसी यूनिवर्सल ज़बरदस्ती की शैतानी ताकत में बदल दिया है जिसके बारे में हम जानते हैं।

इसी तरह, देशों पर कैपिटलिस्ट का कर्ज़ शुरू हुआ और फिर लगातार बढ़ता गया। सिर्फ़ उसी समय से हम देखते हैं कि देश आम लोगों के ट्रस्टी से गिरकर कैपिटलिस्ट हितों का ट्रस्टी बन गया है। यह डेवलपमेंट वॉर-बॉन्ड के रूप में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, जो हमें सभी देशों में देखने को मिलता है, जो खास तौर पर, जैसा कि हमने पहचाना है, सिर्फ़ अमीरों के हितों की सेवा करते हैं, जिन्हें दुनिया भर के लोन की बड़ी क्रेडिट-इमारत से सजाया जाना चाहिए।

इन संक्षिप्त पूर्वावलोकनों से हमारे लिए अंततः इस धारणा को तोड़ना आसान हो जाना चाहिए कि उधार पूंजी को अलौकिक शक्ति उधार दी जानी चाहिए ताकि वह स्वयं से अनंत और अंतहीन रूप से बढ़ सके। सूख जाने की भयानक क्षमता से संपन्न। हमें इस धारणा को तोड़ना होगा कि उधार पूंजी, सांसारिक कर्मों और कुकर्मों से अप्रभावित, बादलों के ऊपर सिंहासनारूढ़ बैठने में सक्षम होनी चाहिए, क्षणभंगुरता से अप्रभावित, विनाश की शक्तियों से अप्रभावित, हमारी विशाल तोपों के गोलों से अप्रभावित। क्योंकि, अगर घर और झोपड़ियाँ, रेलमार्ग और पुल गोले से चकनाचूर होकर धूल और राख में डूब जाएं, तो भी बंधक मौजूद रहेंगे;

रेलरोड बॉन्ड और कर्ज़ के पब्लिक सर्टिफिकेट इससे मिटते नहीं हैं। अगर गाँव और शहर, पूरे प्रांत युद्ध की भयानक तबाही का शिकार हो जाएँ, तो नतीजा क्या होगा? कर्ज़ के नए सर्टिफिकेट ही इसका मतलब हैं। लालच भरी आँखों से बादलों के ऊपर बैठा गोल्ड इंटरनेशनल इंसानों की पागलों जैसी दौड़ को देख रहा है। और वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब सारी इंसानियत आखिरकार सिर्फ़ मैमोनिज़्म की गुलाम बनकर रह जाएगी।

यह विचार अंतरराष्ट्रीय है; इसे पूरी दुनिया को आज़ाद करना चाहिए। उस देश की जय हो जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाने वाला कदम उठाओ। जल्द ही दूसरे भी ऐसा करेंगे।

मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता था कि क्या यह आइडिया देश भर में सच हो सकता है? हाँ में जवाब दें। हम अंदर से आपके आभारी हैं।

विदेशी ब्याज के दावों के खिलाफ हम अभी स्वाभाविक रूप से बेबस हैं; इन्हें बस चुकाना होगा। ज़्यादा कैपिटल-आउटफ्लो को जितना हो सके रोकना होगा, लेकिन, जैसे कानून बनाने वाला मर्डर, गैर-इरादतन हत्या, धोखाधड़ी वगैरह के खिलाफ कानून बनाने से बचता है, क्योंकि बदमाश तो हमेशा रहेंगे ही, वैसे ही लोगों को अपने पब्लिक फाइनेंस को ठीक करने के लिए ज़रूरी माने जाने वाले कदम उठाने से खुद को रोकना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों के सबसे अच्छे लोग अपनी लूट को देश के बाहर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम मान लें कि वॉर बॉन्ड सर्टिफिकेट में करोड़ों, यहाँ तक कि अरबों डॉलर विदेश में खर्च किए जाएँगे; तब भी यह ब्याज-गुलामी को खत्म करने में नाकाम रहने के लिए कोई खास वजह नहीं हो सकती; क्योंकि इसी अनुपात में, फिक्स्ड-इंटरेस्ट वाले घरेलू इन्वेस्टमेंट-एसेट्स में 250 बिलियन मार्क्स से ज़्यादा का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी देश में ही होगा।

आइए, हम फिर से संक्षेप में बताते हैं। – ब्याज की गुलामी को खत्म करना हमारे पब्लिक फाइनेंस को आखिरी और हमेशा के लिए ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका है। – ब्याज-कम्युनिटी को खत्म करने का मतलब है, दबाने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़ने की संभावना, क्योंकि सरकारी बिज़नेस, खासकर आगे के सही सेक्टर (इनलैंड नेविगेशन, बिजली, एयर-ट्रैफिक, वगैरह) के सोशलाइज़ेशन के बाद, सरकारी खजाने में इतना सरप्लस देंगे कि राज्य के सभी सोशल और कल्चरल कामों को सपोर्ट किया जा सके।

इस फाइनेंशियल बात के अलावा, इंटरेस्ट-कम्युनिटी को खत्म करने से काम के सभी फील्ड में प्रोडक्टिव लेबर को वह प्रायोरिटी मिलेगी जिसका वह हकदार है। पैसा एक बार फिर अपनी सही भूमिका में लौट आएगा, हमारी नेशनल इकॉनमी को चलाने में एक सेवक की तरह। यह फिर से वही बन जाएगा जो यह है, पूरे किए गए काम का वाउचर, और इसके साथ ही एक बड़े लक्ष्य के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, हमारे ज़माने की पैसे की लालच से दूर रहने के लिए।

यह आइडिया पूरी मेहनतकश आबादी का एक साथ आना चाहता है: बिना प्रॉपर्टी वाले मज़दूर से, जिस पर, जैसा कि हमने देखा है, लोन-कैपिटल की संतुष्टि के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ है, सिविल सर्वेंट और कर्मचारियों के पूरे बुर्जुआ वर्ग से, खेती और छोटे-मोटे काम करने वाले मिडिल क्लास से, जो खराब घरों, खेती की ज़मीन के किराए, बैंक-ब्याज, वगैरह के रूप में पैसे की बेरहम तानाशाही महसूस करते हैं, हमारी बड़ी इंडस्ट्री के बड़े हेड, इन्वेंटर और डायरेक्टर तक, जो कमोबेश बड़ी लोन-कैपिटल के पंजों में एक साथ फंसे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी का पहला काम हमेशा पर्दे के पीछे खेलने वाले पैसे वालों के लिए पेंशन, डिविडेंड और ब्याज के लिए काम करना होता है। इसी ग्रुप में इंटेलेक्चुअल लोगों के सभी ग्रुप – कलाकार, लेखक, एक्टर, स्कॉलर, साथ ही दूसरे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल भी शामिल हैं।

हालांकि बड़ी लोन-कैपिटल, आम लोगों के एक ग्रुप के तौर पर या इंटरेस्ट-प्रिंसिपल के रूप में, जान-बूझकर या अपने आप कंट्रोल की अपनी बहुत ज़्यादा चाहत को छिपाने की कोशिश करती है, और हालांकि हमारी पूरी कानूनी परंपरा रोमन कानून पर आधारित है, यानी अमीरों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले कानून पर, इसने हमेशा प्रॉपर्टी की सुरक्षा पर बहुत ज़ोर दिया है और इसके साथ ही हमारे लोगों की इंसाफ की भावना में भी जगह बनाई है, इंटरेस्ट की गुलामी को खत्म करना।

पैसा आना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड इंटरनेशनल द्वारा पूरी दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाने के खतरे से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है, और यह हमारे समय की मानसिकता को भ्रष्ट करने वाले मैमोनिज़्म के ज़हर को बाहर निकालने के तरीकों में से एक है।

युद्ध-बांड का बैंक-ऋण में रूपांतरण

धारा 1 में वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट वगैरह को लीगल टेंडर में बदलने की मांग पर कई बार यह एतराज़ जताया गया है कि इसका मतलब होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी आ जाएगी। यह एतराज़ अपने आप में काफी गलत है। सिर्फ़ वॉर-बॉन्ड होने से ही महंगाई होती है।

लेकिन यह सच है कि, अपनी गलत सोच के बावजूद, करेंसी घोषित किए गए इन कागज़ों की फिजिकल मौजूदगी को लेकर चिंता खत्म नहीं हो रही है, और इसलिए, अवास्तविक होने के बावजूद, यह चिंता बुरे साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है, जैसे कि असल में कोई नई महंगाई हो गई हो। इसलिए, धारा 1 में बदलाव करते हुए, हम मांग करते हैं कि ब्याज देने की ज़िम्मेदारी को कानूनी तौर पर रद्द करने के बाद, वॉर-बॉन्ड सर्टिफिकेट्स को, दूसरे पब्लिक डिबेंचर-बॉन्ड्स के साथ, [करेंसी में नहीं बल्कि] बैंक-क्रेडिट में बदला जाए।

इस फॉर्मूलेशन का बड़ा फ़ायदा यह है कि कागज़ के तौर पर वॉर-बॉन्ड का असल वजूद खत्म हो जाएगा; वॉर-बॉन्ड सर्टिफ़िकेट बैंक, बैंकर, थ्रिफ़्ट-इंस्टीट्यूशन वगैरह राइशबैंक को दे देंगे, और फ़ेस-वैल्यू का क्रेडिट-नोट जारी होने के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इससे जर्मनी में लगभग हर व्यक्ति को एक बैंक-क्रेडिट, एक खुला बैंक-अकाउंट मिलेगा जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है।

इस तरह के प्रोसेस का यह भी बड़ा फ़ायदा होगा कि बड़े इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट कब्ज़े में रखना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक तय डेडलाइन खत्म होने के बाद, डिलीवर न किए गए सर्टिफ़िकेट को रद्द घोषित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, कम से कम यह कंट्रोल करना मुमकिन होगा कि देश के बाहर कितना वॉर-बॉन्ड खर्च किया जाता है [इससे जर्मनी के ट्रेड-बैलेंस पर असर पड़ेगा]। लेकिन, आखिरी बात किसी भी तरह से ब्याज की गुलामी को खत्म करने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि हम सच में विदेशी देशों के मुकाबले बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, इसलिए हमें (सिर्फ़) उन ब्याज-मांगों को पूरा करना चाहिए जिनका सामना विदेश से हमें करना पड़ता है। पर्सनली, मेरी पूरी राय है कि हमें विदेशी बॉन्डहोल्डर्स के लिए भी ब्याज रद्द करने का समर्थन करना चाहिए। हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि विदेशी ब्याज-दावों को हथियारों के ज़ोर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि [युद्ध-पागलपन से] खुद को जानने जैसी किसी चीज़ पर लौटने में बहुत तरक्की हुई है, और इतिहास में कभी भी किसी बड़े देश के खिलाफ़ निजी लोगों को प्रभावित करने वाले फाइनेंशियल उपायों की वजह से युद्ध जैसी कार्रवाई नहीं की गई है।

यह भी नहीं सोचना चाहिए कि फ्रांस के लोग भी जर्मनी को अल्टीमेटम देंगे क्योंकि जर्मनी के मेयर, शुल्ज़े और कोहन ने बॉर्डर पार किए गए अपने जर्मन वॉर-बॉन्ड के आधार पर अपने हितों के दावे किए हैं।

इसके अलावा, यह भी मुमकिन होगा कि बाकी दुनिया को देश के दिवालिया होने का एहसास भी न हो, इसके लिए वॉर बॉन्ड की लॉटरी निकाली जाए, जिसे फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरी डिलीवरी से मिले आंकड़ों के आधार पर आसानी से बदला जा सके, ताकि पहले सिर्फ़ विदेश में रहने वाले लोगों के नंबर निकाले जाएं और उन्हें रीच बैंकनोट में चुकाया जाए।

फिर भी एक तीसरी बात यह होगी कि वॉर बॉन्ड के डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा, और साथ ही वेल्थ-टैक्स के बहुत आसान कलेक्शन का मौका भी मिलेगा, जबकि बर्सरी को बेशक सिर्फ़ राइक्सबैंक ऑफिस को मिस्टर NN के अकाउंट से इतने मार्क्स टैक्स चार्ज करने का निर्देश देना होगा। इस तरह टैक्स-

भुगतान अब तक अधिक दर्द रहित होगा - हालांकि करदाताओं का अपील का अधिकार निश्चित रूप से पूरी तरह मौजूद रहेगा।

वॉर-बॉन्ड को बैंक-क्रेडिट में बदलने से एक तरह का सोशल लेवलिंग भी हो सकता है, जहाँ तक वॉर बॉन्ड में छोटे इन्वेस्टमेंट की बात है, इस तरह उन सभी लोगों के सभी छोटे सब्सक्रिप्शन, जिनके लिए वॉर-बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन सच में देशभक्ति का काम माना जाता है; मान लीजिए 5 या 10 हज़ार मार्क तक, बराबर रेट पर वापस किए जाएँगे, जबकि सभी बड़े सब्सक्रिप्शन को तय रेट पर क्रेडिट किया जा सकता है। बाकी सभी सरकारी कागज़ों के क्रेडिट को भी ठीक वैसे ही हैंडल किया जाएगा।

कानून की मांग पर विशेष टिप्पणियाँ
घोषणापत्र

§ 1 पर

यह पूरी तरह से ज़रूरी है कि सभी राज्य और नगर निगम के कर्ज़-सब्सक्रिप्शन के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, क्योंकि हमारे पूरे मॉनेटरी सिस्टम का सिर्फ़ इतना एक बड़े पैमाने पर रेगुलेशन, ब्याज-गुलामी को खत्म करने के साथ ही लागू किया जा सकता है।

धारा 2 पर

यह पहले से ही साफ़ है कि ब्याज़-गुलामी को खत्म करने का काम बाकी सभी फिक्स्ड-इंटरेस्ट पेपर्स पर एक साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि इन पेपर्स में कोई अजीब तेज़ी न आए, जो ज़ाहिर है तब होगी जब सिर्फ़ पब्लिक पेपर्स को ही ब्याज़-मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। कर्ज़ में कमी सालाना रीपेमेंट से होगी, जिससे सभी कर्ज़-लदे ऑब्जेक्ट्स को लगातार और एक जैसा अनडेटिंग किया जा सकेगा।

धारा 3 पर

यह पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से बहुत करीब से जुड़ा है, साथ ही § 5 में मॉर्गेज-लेंडिंग के नेशनलाइजेशन की मांग से भी। मॉर्गेज के बोझ तले दबा किसान या घर का मालिक, पहले की तरह, अपने क्रेडिटर्स को उतनी ही रकम चुकाता रहता है, जितनी उसे चुकानी थी, लेकिन अब हमेशा के लिए ब्याज के तौर पर नहीं, बल्कि रीपेमेंट के तौर पर। इस तरह 20, 25, या 30 साल बाद, पहले से मौजूद ब्याज दर के आधार पर, ज़मीन और घर का मालिकाना हक कर्ज़ से आज़ाद हो जाएगा। (मॉर्गेज-बैंक भी अपनी तरफ से स्वाभाविक रूप से इसी दौरान कवर्ड बॉन्ड-होल्डर्स को कवर्ड बॉन्ड पर ब्याज देना जारी रख सकता है।) कर्ज़ से इस आज़ादी के साथ-साथ मॉर्गेज से आज़ाद रियल-एस्टेट में कम्युनिटी का मालिकाना हक भी पैदा होता है।

घरों की एक यूनिवर्सल रजिस्ट्री, या यूँ कहें कि एक रियल-एस्टेट कैडेस्टर, पहले आना होगा; क्योंकि कर्ज़-मुक्त रियल-एस्टेट ओनरशिप में स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टेड कैपिटल के रीपेमेंट का अधिकार भी होता है, और किराए के एक हिस्से पर एक परमानेंट क्लेम भी होता है, रियल-एस्टेट ओनरशिप के साथ आने वाले सभी चार्ज, खर्च वगैरह का पेमेंट करने का अधिकार होता है, साथ ही मालिक द्वारा खुद किए गए काम के लिए सही कम्पेनसेशन भी मिलता है ।

आइए, एक शहरी अपार्टमेंट हाउस के उदाहरण से इस पर मोटे तौर पर विचार करें।
घर की कीमत 100,000 मार्क्स है। इसके मुकाबले, पोजीशन 1 में 4% पर मॉर्गेज-बैंक का 50,000 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट, पोजीशन 1 में 5% पर 20,000 मार्क्स का नॉन-कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया है।

---

7 घरों की रजिस्ट्री और कर्ज़-मुक्त मालिकों के अधिकारों के बीच का कनेक्शन उलझन भरा है, जब तक कि इसका मकसद किराए की प्रॉपर्टी की ग्रोथ को इस तरह मैनेज करना न हो कि वह ठीक-ठाक फ़ायदेमंद बनी रहे।

स्थिति 2, और 30,000 मार्क्स वह रकम है जो घर के मालिक ने खुद लगाई है। किराए से होने वाली कमाई 7000 मार्क्स है। इसमें से पहले मॉर्गेज के लिए 2000 मार्क्स, दूसरे मॉर्गेज के लिए 1000 मार्क्स, और खर्चों, खर्चों वगैरह के लिए 1000 मार्क्स देने होंगे: कुल मिलाकर 4000 मार्क्स। इस तरह घर के मालिक के पास अपनी 30,000 मार्क्स की इन्वेस्ट की गई पूंजी के लिए ब्याज के तौर पर 3000 मार्क्स बचते हैं।

पैसे पर ब्याज को कानूनी तौर पर खत्म करने के बाद, दस साल बाद स्थिति यह है: पहला मॉर्गेज 30,000 मार्क्स, दूसरा मॉर्गेज 10,000 मार्क्स। घर के मालिक ने अपना कैपिटल-इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वापस पा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ 50,000 मार्क्स की रकम में मालिकाना हक का एक नया, पब्लिक अधिकार है। इसके साथ ही किराए से होने वाली आगे की इनकम के बारे में अपनी बात रखने और किराए की रकम तय करने का राज्य का अधिकार शुरू होता है8 ।

अब, रीपेमेंट के मामले में, घर के मालिक को मॉर्गेज के बराबर रखना गलत होगा। क्योंकि उसकी कैपिटल उस छोटे मतलब में प्योर लोन-कैपिटल नहीं है जिस पर ब्याज-गुलामी खत्म होने का असर पड़ना चाहिए; यहाँ हम "रिस्क" कैपिटल की बात कर रहे हैं, खास तौर पर उस पैसे के बारे में जिसे किसी कीमती चीज़, खासकर घर में बदला गया हो। इसलिए यह घर के मालिक पर है कि वह पेमेंट के लिए ज़्यादा समय दे, या घर के ऑपरेटिंग खर्चों में एक बराबर परसेंटेज हमेशा के लिए शामिल करे।

यहां कोई ज़रूरी प्रपोज़ल देना मकसद नहीं हो सकता; यहां सिर्फ़ सुझाव दिए जा रहे हैं कि रियल एस्टेट के एरिया में भी इंटरेस्ट इकॉनमी का इंटरेस्ट-फ्री इकॉनमी में बिना किसी रुकावट के बदलाव कैसे हो सकता है।

तो उदाहरण को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि 25 साल बाद की स्थिति ऐसी होगी: उस समय तक सभी मॉर्गेज चुका दिए जाते हैं; सिर्फ़ परमानेंट खर्चे वही रहते हैं या, घर की ज़्यादा उम्र की वजह से, 1000 मार्क्स से बढ़कर शायद 1500 मार्क्स हो जाते हैं। मान लीजिए कि इस रकम से घर के मालिक को मिलने वाला रिटर्न भी लगभग 1000 से 1500 मार्क्स होता है; इस हिसाब से ऐसा लगता है कि किराए से होने वाली कमाई के लगभग 3000 मार्क्स नॉन-नेगोशिएबल चार्ज को कवर करने में चले जाते हैं, जबकि किराए से होने वाली कमाई के ओरिजिनल 7000 में से बाकी 4000 मार्क्स आसानी से खर्च हो जाएँगे। इस तरह राज्य के पास किराए को आधे से ज़्यादा कम करने का मौका है; वह ऐसा मज़दूरों के घरों में करेगा, या राज्य किराए में सिर्फ़ 20, 30, या 40% की कटौती कर सकता है, और इस तरह इस अंतर से दूसरी पब्लिक ज़रूरतों के लिए, खासकर ज़ाहिर है पब्लिक में होने वाले घर बनाने के लिए, रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हासिल कर सकता है। हवेलियों का किराया कम नहीं किया जाता, या बहुत कम नहीं किया जाता, जिससे घरों को बेहतर बनाने या खास सामाजिक कामों के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा साधन भी मिल जाते हैं। लेकिन, भविष्य की यह स्थिति दिखाती है – और मैं इसे एक बहुत अच्छी उम्मीद मानता हूँ – कि कम्युनिटी (राज्य) के लिए अभी भी किराए की रकम तय करने में हिस्सा लेने का अंदरूनी कारण है, जैसा मैंने ऊपर बताया है, जिसमें मज़दूरों के घरों का किराया कम करना शामिल है।

रियल-एस्टेट-ओनरशिप में भाग लेने के राज्य के बढ़ते अधिकार में यह भी शामिल है
यह एक मज़बूत बैंक ऑफ़ इश्यू और मॉर्गेज क्रेडिटर्स को क्रेडिट जारी करने की नींव रखता है।

धारा 4 और 5 पर

ये पैराग्राफ पूरे मॉनेटरी सिस्टम के सोशलाइज़ेशन की मांग करते हैं। पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा वाउचर है जो पूरे किए गए काम के लिए होता है, जिसे एक कम्युनिटी जारी करती है, जिसका अपना होता है।

8 फेडर यह नहीं बताते कि उन्होंने 50,000 मार्क्स का आंकड़ा कैसे निकाला: यह अपार्टमेंट-घर की आधी कीमत है, लेकिन कॉर्पोरेट मॉर्गेज की रकम के बराबर भी है। शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मॉर्गेज में बकाया रकम से ज़्यादा नहीं है, और इसलिए घर के मालिक को कोई परेशानी नहीं होती। शायद, फेडर बिना किसी परेशानी के बदलाव पर जो ज़ोर देते हैं, उसे देखते हुए, अगर घर पर बकाया रकम कीमत के आधे से भी कम होती, तो भी फेडर के प्लान के हिसाब से राज्य मॉर्गेज पर बकाया रकम से ज़्यादा मालिकाना हक का दावा नहीं करेगा।

राज्य। मनी-टोकन जारी करना राज्य के सॉवरेन फंडामेंटल राइट्स में से एक है। राज्य के मनी-टोकन की नकली बनाने पर सबसे कड़ी सज़ा दी जाती है; इसलिए, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक मांग है कि मॉनेटरी सिस्टम को कलेक्टिविटी के कंट्रोल में रखा जाए। कलेक्टिविटी की वर्क-पावर ही मनी-टोकन का एकमात्र सबस्ट्रेट है, और सिर्फ़ इस बुनियादी बात को न समझने की वजह से ही आम तौर पर हमारे पब्लिक फाइनेंस में गिरावट आई है और मॉनेटरी सिस्टम में पूरी तरह से अराजकता फैल गई है।

प्राइवेट बैंकरों द्वारा पर्सनल और कमर्शियल क्रेडिट के सरेंडर के साथ, जैसा कि § 5 में प्रस्तावित है, टोटल क्रेडिट-सिस्टम में एक गहरी कटौती की गई है। स्टेट क्रेडिट-सिस्टम के साथ-साथ म्युनिसिपल और यहां तक कि रियल-एस्टेट क्रेडिट के लिए भी, ब्याज-गुलामी को पूरी सख्ती और ऊर्जा के साथ खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह आम तौर पर सोशल स्टेट के लिए ज़रूरी शर्त है।

पर्सनल क्रेडिट के मामले में स्थिति अलग है। हम पर्सनल क्रेडिट पर ब्याज न देने की भी मांग करते हैं; फिर भी इस मांग का उतना बड़ा और मुख्य महत्व नहीं है। हमें फिक्स्ड-इंटरेस्ट लोन-कैपिटल में 250 बिलियन की तुलना याद है।

डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में सिर्फ़ 12 बिलियन।

ऐसे सभी क्रेडिट, स्टॉक, पार्टिसिपेशन-सर्टिफिकेट, माइनिंग शेयर, इक्विटी-होल्डिंग, वगैरह, रिस्क कैपिटल हैं। इस कैपिटल का यील्ड उन लोगों की मेहनत और कुशलता पर निर्भर करता है जिन्हें पैसा सौंपा गया था। यहाँ रिस्क और नुकसान का खतरा, साथ ही पर्सनल भरोसे का सवाल भी आता है। उसके लिए, एक खास तरह का मुआवज़ा अभी भी ज़रूरी लगता है। स्टॉक वगैरह के मालिक को किसी भी तरह से मुआवज़ा या फ़ायदा नहीं मिलता अगर जिस कंपनी को उसने अपना पैसा सौंपा है, वह कुछ नहीं कमाती। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो वह अपना पूरा पैसा खो देता है।

उदाहरण के लिए, रीचेसेनबाहन के डिबेंचर-बॉन्ड के मालिक के साथ ऐसा नहीं है।
एल्सा-लोथ्रिंगन के नुकसान के साथ ही रीच के रेलरोड [एल्सास-लोथ्रिंगन में] पूरी तरह से खत्म हो गए। फिर भी, रेलरोड-बॉन्ड के होल्डर को इंटरेस्ट-पेमेंट मिलते रहते हैं। किससे? कलेक्टिविटी के टैक्स से। रेलरोड किसी भी बड़े डेफिसिट बैलेंस के साथ काम कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल प्रशिया और बवेरिया में हुआ था; फिर भी बॉन्डहोल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट वैसे ही मिलता है। किससे? वर्किंग पॉपुलेशन की वर्क-पोटेंशियल और कंजम्प्शन से दिए गए ट्रिब्यूट से।

हम बस यह बुनियादी अंतर पूरी तरह से साफ़ कर देना चाहेंगे, ताकि आखिर में
यह पहचानना कि वैम्पायर लोगों की काम करने की क्षमता को कहाँ से चूसता है।

इस तरह, पर्सनल क्रेडिट प्राइवेट बैंक के ज़रिए पर्सनल डीलिंग के लिए बना रहना चाहिए, या यूँ कहें कि फिर से दिया जाना चाहिए। क्रेडिट लेने वाले की पर्सनल एफिशिएंसी, जिससे बैंकर पर्सनली परिचित है, पर्सनल क्रेडिट के लिए फिर से तय करने वाला फैक्टर बन जाना चाहिए। राज्य द्वारा तय की गई फीस खुद ही रेगुलेट हो जाएगी, पैसे की लिक्विडिटी के हिसाब से जो किसी भी हालत में ब्याज-गुलामी के खत्म होने के साथ शुरू होगी।

धारा 6 पर

धारा 5 का मुख्य पॉइंट खास तौर पर डिविडेंड-एसेट्स के लिए भी सही है। सामाजिक राज्य-समुदाय के हित में यह मांग की जानी चाहिए कि एक बार उधार दी गई पूंजी को बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के लिए भी चुकाने की कोशिश की जाए – ताकि यहां अलग-अलग इंडस्ट्रियल कामों का उन लोगों के प्रति कर्ज़ कम हो सके जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं।

असल में, हम लोन-कैपिटल के सभी लोगों के साथ रिश्ते में जो देख पाए, वही यहाँ भी छोटे पैमाने पर दोहराया गया है। यहाँ भी कैपिटलिस्ट मज़दूर का शोषण करता है,

फोरमैन, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, सभी को बराबर फ़ायदा होता है, क्योंकि डिविडेंड कमाने की मजबूरी को पहले रखा जाता है ।

लेकिन, अगर हम इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस को हमेशा ब्याज़ चूसने वालों से आज़ादी दिला देते हैं, तो प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करने और सरप्लस वैल्यू को कुछ हद तक कम्युनिटी को, कुछ हद तक मज़दूरों, मिडिल मैनेजमेंट और खास कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को देने और बांटने का रास्ता साफ़ हो जाएगा, और इस तरह उन लोगों को भी जो असल में अकेले ही मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यूज़ बनाते हैं।

धारा 7 पर

इस पैराग्राफ में ज़ाहिर है, इंश्योरेंस का पूरा फील्ड भी शामिल है, जिसे एक जैसे इंटरेस्ट-फ्री बेसिस पर बनाया जा सकता है। पेमेंट किए गए प्रीमियम इंटरेस्ट जोड़कर नहीं बढ़ सकते; बल्कि इंश्योरेंस-कंपनियां थ्रिफ्ट-इंस्टीट्यूशन बन जाएंगी; दूसरे शब्दों में, इंश्योरेंस का रिस्क और फायदा बना रहेगा। इसके लिए पॉलिटिकल कम्युनिटी को ज़िम्मेदार होना होगा।

धारा 8 पर

हमारे पैसे के डीवैल्यूएशन के बारे में, जो हमारे अनगिनत कर्ज़ के सर्टिफिकेट के भारी ढेर की वजह से हुआ है, हम एक मज़बूती से ग्रेजुएटेड वेल्थ-टैक्स की मांग करते हैं। हम इसमें “मज़बूती से ग्रेजुएटेड” पर ज़ोर देते हैं।

नोटों की संख्या कम करने वगैरह के लिए एक [फ्लैट] वेल्थ-टैक्स लगाना खुद को धोखा देने जैसा होगा, जिससे लोगों की आँखों में धूल झोंकी जा सके। क्योंकि अगर मैं हर जगह की आधी दौलत भी ज़ब्त कर लूँ और बॉन्ड और पल्प के रूप में पेमेंट लूँ, तो इससे असल में सिर्फ़ कागज़ की मात्रा कम होगी, जबकि बदले में एक कन्वर्ज़न-फ़ैक्टर सर्कुलेटिंग कागज़ की कुल मनगढ़ंत कीमत को पहले के बराबर बढ़ा देगा। असली कीमत हमेशा सिर्फ़ इस्तेमाल और इस्तेमाल के सामान की होती है, कभी भी पूरी मेहनत के कागज़ के वाउचर की नहीं।

एक और सवाल यह है कि क्या हमारी मार्क-करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज-रेट में सुधार किया जा सकता है। लेकिन एक्सचेंज-रेट में यह सुधार भी फाइनल एनालिसिस में सिर्फ वर्क-पोटेंशियल और प्रोडक्शन पर निर्भर करता है, दूसरे शब्दों में हमारी पूरी नेशनल इकॉनमी के प्रोडक्शन की संभावना पर।

आपत्तियाँ और उनका खंडन

आज तक कोई भी आइडिया बिना विरोध के अपनी जगह नहीं बना पाया है, खासकर ऐसा आइडिया जो इंटरेस्ट की पवित्रता और उसे बनाए रखने के बारे में लंबे समय से बनी सोच से इतना बड़ा बदलाव करता हो। पहले से उठाए गए ऑब्जेक्शन और जिनकी उम्मीद थी, उनके साथ हमेशा दो बातें ध्यान देने वाली होती हैं: यह पूछा जाना चाहिए, पहला, ऑब्जेक्शन का कौन सा हिस्सा इंटरेस्ट-स्लेवरी को खत्म करने के आइडिया को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश करने पर आधारित है, और दूसरा, सभी सच्ची और सच पर आधारित शंकाओं के जवाब में क्या कहा जाना चाहिए?

सबसे ज़्यादा आपत्ति यह है कि: बिना ब्याज लिए कोई भी पैसा उधार नहीं देगा।

---

9 यह जॉइंट-स्टॉक कंपनियों की समस्या है। जर्मनी में आम तौर पर, परिवारों के पास स्वतंत्र और स्पष्ट स्वामित्व वाली कंपनियाँ होती हैं, यह विशेषता नहीं है।

असल में हम नहीं चाहते कि कोई भी अब उसे पैसे उधार दे। क्रेडिट ही ट्रिक थी, जाल, जिसमें हमारी इकॉनमी फंस गई, और जिसमें अब वह बेबस होकर फंस गई है।

अगर लोगों को सच में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो उन्हें सेंट्रल स्टेट ट्रेजरी से बिना ब्याज के ज़रूरी पैसा मिल जाएगा, बस उसे चुकाना होगा। आखिर में यह नए बैंक नोट जारी करेगा। इसे ब्याज वाले सर्टिफिकेट क्यों जारी करने चाहिए?! कागज़ पर ब्याज हो या न हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता! इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ सहारा लोगों की काम करने की क्षमता और टैक्स देने की क्षमता है। हर सरकारी खर्च पर शुरू से ही हमेशा ब्याज का बोझ क्यों डाला जाए?

हाँ, लेकिन राज्य को समुदाय के लिए अपने सांस्कृतिक काम कैसे पूरे करने चाहिए? उसे अभी भी ज़रूरत है पैसा और इस काम में सही तभी हो सकता है जब ब्याज वाले लोन हों।

यह दावा पूरी तरह से मैमोनिस्टिक सोच पर आधारित है। इस मैनिफेस्टो को अच्छी तरह पढ़ने के बाद इसे जानबूझकर गलत दिशा में ले जाने के लिए बनाया गया लगता है; क्योंकि सबसे पहले तो हमने यह साबित कर दिया है कि ब्याज-गुलामी खत्म होने के बाद राज्य के सभी कल्चरल और सोशल काम राज्य के बिजनेस, पोस्टल सर्विस, रेलरोड, खदानों, जंगलों वगैरह से होने वाली कमाई से बिना किसी और चीज़ के पूरे किए जा सकते हैं। दूसरी बात, सॉवरेन लोगों के राज्य [वोल्क्सस्टेट] के पास यह पावर है कि वह किसी भी समय, मैमोनिस्टिक राज्य में नियम माने जाने वाले ब्याज वाले सर्टिफिकेट के बदले ब्याज-मुक्त वैल्यू-टोकन जारी करके खास कल्चरल कामों को पूरा कर सकता है। यह समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि राज्य को खास कल्चरल काम, जैसे रेलरोड, नहर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन, को अपने लिए महंगा क्यों बनाना चाहिए, जबकि ब्याज का वादा हमेशा के लिए किया जाता है, जो पूरी तरह से गैर-ज़रूरी है। अगर वह अपने मौजूदा राज्य के बिजनेस से होने वाली कमाई से कंस्ट्रक्शन का खर्च नहीं उठा सकता, तो यह देखने का कोई कारण नहीं है कि राज्य को पैसा क्यों नहीं बनाना चाहिए; आज़ाद लोगों को ज़रूर इसके लिए पैसे देने होंगे, जबकि वे ठीक इसी पैसे को पेमेंट का ज़रिया मानते हैं। लेकिन लोग, अपने पूरे काम और टैक्स की क्षमता के साथ, एक और कागज़ (ब्याज वाला लोन) के पीछे क्यों खड़े हों, जो पूरी तरह से लोगों पर सिर्फ़ कैपिटलिस्ट के फ़ायदे के लिए हमेशा ब्याज की ज़िम्मेदारी डालता है!? इसलिए, अमीरों वाले राज की इस सनक से दूर रहो!

फिर पूंजीपति जारी किए गए कागजी नोट ले लेंगे और कागजी नोट जमा कर लेंगे धन।

इसे दो तरह से गलत साबित किया जा सकता है। पहला, यह मांग कि सिर्फ़ पैसे रखना फ़ायदेमंद नहीं होना चाहिए, तब तो पहले ही पूरी हो चुकी होगी, और ब्याज़-गुलामी को खत्म करने का काम कैपिटलिस्ट खुद अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट अगर घर पर अपने कागज़ के नोट जमा कर लेता है तो वह अपनी मर्ज़ी से ब्याज़ छोड़ देता है। दूसरा, कैपिटलिस्ट को अपने पैसे का डर इसे मुमकिन नहीं बनाता; बस उस करेंसी जमा करने वाले की रातों की नींद हराम करने वाली कल्पना कीजिए जो घर पर बहुत सारा पैसा जमा करके रखता है और उसे लगातार चोरों, लुटेरों, चोरों, घर की तलाशी, आग और बाढ़ से अपने पास मौजूद चीज़ों पर खतरा मंडराता रहता है। मुझे यकीन है कि एक नेक नागरिक जल्द ही इन चिंताओं से थक जाएगा और जल्द ही स्टेट बैंक का रास्ता ढूंढ लेगा। स्टेट बैंक एक रसीद देता है और अब कानूनी तौर पर अकाउंट के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन किसी भी ब्याज़ पेमेंट के लिए नहीं। नहीं तो, बेशक एक तीसरी संभावना अभी भी हर किसी के लिए खुली है, खासकर अपने पैसे से काम करने के लिए, वैल्यू बनाने और सामान बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कामों में हिस्सा लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और बेहतर बनाने के लिए, कला और स्कॉलरशिप को सपोर्ट करने के लिए, संक्षेप में, मैमन के पंथ को नकारते हुए अपने पैसे का फायदेमंद इस्तेमाल करने के लिए।

फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लक्ष्यों के लिए प्राइवेट कैपिटल की तुरंत ज़रूरत पड़े, जैसे कि इन्वेंशन की टेस्टिंग, युवा, काबिल कारीगरों या बिज़नेसमैन द्वारा बिज़नेस शुरू करना, वगैरह।

सबसे पहले तो, इसका ब्याज गुलामी खत्म करने से कोई लेना-देना नहीं है!
क्योंकि, सबसे पहले, यह मानना होगा कि कैपिटलिस्ट, जिसके पास ब्याज-गुलामी खत्म होने के बाद, अपने पैसे को बम-प्रूफ़ तरीके से इन्वेस्ट करने और ब्याज के बेकार खर्च की उम्मीद करने का कोई मौका नहीं है, बल्कि, पहले की तरह, ऐसे मकसदों के लिए अपने पैसे को रिस्क में डालने के लिए तैयार होगा, ताकि इस दिशा में कमी या ज़रूरत अब तक की तुलना में बहुत कम हो। या क्या हमने इसके उलट बार-बार कुशल बिज़नेसमैन, सबसे चालाक इन्वेंटर से यह शिकायत नहीं सुनी है कि अमीरों के राज में ऐसे मकसदों के लिए पैसा मिलना कितना मुश्किल है, जब तक कि "डिविडेंड" की गारंटी न हो? दूसरी बात, आने वाले राज का काम हर काबिल ताकत को दिल खोलकर सपोर्ट देकर बढ़ावा देना होना चाहिए। पुराने ब्यूरोक्रेटिक राज में असल में अब से पहले भी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इतनी छोटी दिल वाली कि स्टिमुलस के बजाय, पब्लिक सपोर्ट देने के साथ आने वाले परेशान करने वाले नियमों की वजह से रुकावट और हिचकिचाहट हुई। तीसरी बात, यह ध्यान दें कि कई मिलियन मार्क्स के बंटवारे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जर्मन इन्वेंटर, इंजीनियर, कारीगर, वगैरह की मेहनत, लगन और लगन इतनी ज़्यादा है कि, अच्छे इन्वेंशन के नतीजों में राज्य के हिस्से के अधिकार से, खर्च का ज़्यादातर अच्छा इनाम मिलेगा (इंग्लैंड इसका एक उदाहरण है)।

ब्याज-गुलामी खत्म होने से ज़रूरी है कि धन खत्म हो जाए।

ओहो! ऐसा कौन दावा करता है? लेकिन हाँ! जिसने भी अपनी ज़िंदगी को कैपिटल पर ब्याज़ के पेमेंट के हिसाब से ढाल लिया है और काम करने का तय नहीं कर सकता, उसके लिए यह बात बिल्कुल सच है: हर साल 5% खर्च करके वह 20 साल में अपनी दौलत पूरी तरह खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन यह सच में पूरी तरह से सही है! हम जो चाहते हैं, वह असल में ब्याज़ की गुलामी को खत्म करना है; हम चाहते हैं कि पेंशन पर जीना नागरिक का सबसे बड़ा आदर्श न रहे। हम इस अमीरों वाली गिरावट को खत्म करना चाहते हैं; असल में, हम अब यह बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि कोई, कि कई लोग, सिर्फ़ लोन पर ब्याज़ के पेमेंट से हमेशा आराम से रह सकते हैं — दूसरे शब्दों में दूसरों की कीमत पर!

मैं दोहराता हूँ: यह भी बिल्कुल सच नहीं है कि ब्याज की प्रभुता खत्म होने से दौलत खत्म हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। इसके उलट, ब्याज-गुलामी खत्म होने से ऐसी मेहनत पर आधारित दौलत बनेगी जो सामान बनाती है और कीमत पैदा करती है, और हमेशा के ब्याज-खर्च से मुक्त और आज़ाद होगी। जैसा कि हमने देखा है, ब्याज-गुलामी खत्म होने से ज़िंदगी के सभी खर्चों में पूरी तरह से कमी आती है; यह हमें टैक्स के बहुत ज़्यादा बोझ से मुक्त करता है ताकि हर काम करने वाले आदमी के लिए भविष्य में बचत जमा करने की संभावना पहले से ज़्यादा हो। एक और बात! इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड की सामान और कीमत बनाने वाली नेशनल-इकोनॉमिक मेहनत में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती, बल्कि ब्याज-गुलामी खत्म होने से इसे पूरी तरह बढ़ावा मिलता है।

अगर कैपिटलिस्ट को अब कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगा तो मज़दूर को क्या मिलेगा?

यह सवाल अब और नहीं उठना चाहिए! पहली बात तो यह है कि मज़दूरों का हमेशा यही नारा रहा है कि पूंजीपति मज़दूरों का शोषण करेंगे; दूसरी बात यह है कि हमने साफ़-साफ़ देखा है कि लोन पर ब्याज देने के लिए मज़दूरों को ही सबसे ज़्यादा मजबूर किया जाता है। [दूसरे शब्दों में, मज़दूर को कम टैक्स और रहने का कम खर्च मिलता है।]

अगर कोई अपने पीछे कोई दौलत नहीं छोड़ पाता है, तो परिवार के रिश्ते कमज़ोर और खराब हो जाते हैं।
बच्चों.

हाँ, यहाँ असलियत क्या है? आम तौर पर मुझे लगता है कि पैसे का परिवार की भावना से बहुत कम या कोई लेना-देना नहीं है। या फिर क्या आपने सुना है कि अमीर माता-पिता के बच्चे परिवार से चिपके रहते हैं?

क्या अमीर माता-पिता अपने बच्चों को गरीब माता-पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं? या क्या अमीर माता-पिता अपने बच्चों को कम पैसे वाले बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चों के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होगा, कि उनके माता-पिता उनकी सबसे अच्छी परवरिश करें और उन्हें कुछ डिसिप्लिन सिखाएं, उन्हें मेहनती, हेल्दी और हिम्मत वाला इंसान बनाएं, या कि वे उनके लिए सबसे बड़ा मनीबैग छोड़ जाएं?

खास मामलों में, बच्चों के फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने की सही कोशिश को ज़रूर मानना होगा। यह कोशिश, और इस तरह माता-पिता की अपने बच्चों के लिए बचत करने की आदत, ब्याज की गुलामी खत्म होने से किसी भी तरह से बुरी तरह प्रभावित नहीं होगी; बल्कि इसके उलट। जब हमारी नेशनल इकॉनमी ब्याज की गुलामी के हर तरह के दबाव से आज़ाद हो जाएगी, तो बचत की संभावना और बढ़ जाएगी।

हमने 10,000 मार्क कमाने वाले और 5000 मार्क पेंशन-इनकम वाले आदमी के उदाहरण से देखा है कि सभी मीडियम और छोटी दौलत असल में घर के किराए वगैरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के घुमावदार रास्ते से किसी भी फायदेमंद असर से वंचित रह जाती हैं। मैं बार-बार दोहरा नहीं सकता: कम और मीडियम रकम वाले लोगों के लिए बॉन्ड पर ब्याज एक धोखा है, खुद को धोखा देना है, गोल-गोल घूमना है, लेकिन बड़ी पूंजी ने अपने समर्पित प्रेस के ज़रिए पूरी दुनिया में ब्याज की पवित्रता और उसे न मानने के विश्वास को बहुत शैतानी तरीके से फैलाया और ऐलान किया है। यह हर किसी को ब्याज के प्यारे, बेहोश करने वाले इस्तेमाल में हिस्सा लेने देता है, ताकि उस बुरी अंतरात्मा को सुला दिया जा सके जो हमेशा ब्याज के बेकार, बिना मेहनत वाले इस्तेमाल के साथ होती है – और इस सबसे बड़े फायदे की रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए साथियों को भर्ती करने के लिए।

सिविल सर्वेंट, स्टेट्समैन, कहेगा: राज्य अपने क्रेडिटर्स के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर नहीं सकता।

"ऑब्लिगेशन" का क्या मतलब है? क्या ऐसी ऑब्लिगेशन लेना किसी भी तरह से नैतिक है जिसके बारे में राज्य को शुरू से पता होना चाहिए कि वह इन ऑब्लिगेशन को तभी पूरा कर सकता है जब वह क्रेडिटर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए ठीक उतनी ही रकम में ब्याज ले? इसमें नैतिकता कहाँ है? या शायद यह मानना ज़्यादा ईमानदारी की बात नहीं है: "मैं ब्याज तभी दे सकता हूँ जब मैं उतना ही टैक्स जमा करूँ – लेकिन युद्ध के दौरान मेरे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए मैंने वॉर-बॉन्ड के साथ धोखाधड़ी की; आप मुझे माफ़ करें, प्यारे लोगों; यह आखिरकार आपके लिए था, और अब हम और लुका-छिपी नहीं खेलना चाहते; मैं राज्य कोई ब्याज नहीं दे रहा हूँ और आप, टैक्सपेयर, को ब्याज के लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है; इससे हमारे लेन-देन काफ़ी आसान हो जाएँगे। इस तरह, हम बहुत बड़ी टैक्स-ब्यूरोक्रेसी और इसी तरह बहुत ज़्यादा ब्याज कमाने वाली ब्यूरोक्रेसी के बिना काम चला लेंगे। सही? क्या हमारी डील हो गई?" और आप, हेर शीडेमैन, वॉर-बॉन्ड की सुरक्षा और उसे बनाए रखने से जुड़ी बेवकूफी भरी घोषणाओं के बीच, पुरानी समझौतावादी सरकार के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट के तौर पर हर एडवरटाइजिंग पिलर पर अपना नाम दोबारा पोस्ट न करें। आप सिर्फ़ खुद को शर्मिंदा करेंगे: इस पूरे घोटाले का फ़ायदा असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े लोन-कैपिटल को ही मिला है।

फाइनेंशियल अधिकारी और बैंकिंग प्रोफेशनल कह रहे हैं कि वॉर-बॉन्ड और पब्लिक कर्ज़ पर ब्याज की गुलामी खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि यह पब्लिक बैंकरप्सी जैसा है।

आप मुझे माफ़ करेंगे: आपके भाषणों के अनुसार हम वैसे भी पब्लिकली बैंकरप्ट हैं या हमें ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन, पब्लिक बैंकरप्ट होने की खुली घोषणा हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी: मौजूदा पावर-होल्डर्स की असली नाकाबिलियत के साथ-साथ यह इस नाकाबिलियत की हिस्टॉरिकल कन्फर्मेशन को समय से पहले ही जोड़ देगा।

दिवालिया क्यों घोषित करें? अगर मैंने पैंट की दाहिनी जेब से 3 निशान बाईं जेब में डाल दिए हैं,
मुझे अभी भी इस वजह से दाहिनी पैंट की जेब का दिवालियापन घोषित नहीं करना चाहिए!

वॉर-लोन के साथ भी ऐसा ही था! राइख ने लोगों की जेब से पहले असल में मौजूद अरबों डॉलर निकाल लिए, फिर पैसा वापस आने लगा; फिर नया लोन आया और पैसा फिर से वापस आने लगा; एक बार फिर पंप आया और अरबों डॉलर खींच लिए और फिर से कम होने लगे, जब तक कि यह खेल नौ बार दोहराया नहीं गया, तब तक सरकार ने खुशी-खुशी 100 अरब का कर्ज़ बना लिया। इसके लिए लोगों के हाथों में बारीक छपे कागज़ में 100 अरब थे। पहले तो लोगों ने सोचा कि वे बहुत अमीर हो गए हैं; फिर सरकार आई और बोली: "यह बहुत बुरा है; मुझ पर 100 अरब का कर्ज़ है और मैं दिवालिया होने वाला हूँ।" – हाँ, लेकिन क्यों? यह तो वैसे भी खुद को धोखा देना है! मैं खुद कभी दिवालिया नहीं हो सकता अगर मैं कभी-कभी अपने पैसे एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालूँ। इसलिए, हम अपने अंदरूनी वॉर-बॉन्ड कर्ज़ों के मामले में सरकार के दिवालिया होने के बारे में बेफिक्र रह सकते हैं। इसलिए, हमें सच में पब्लिक बैंकरप्सी घोषित करने की ज़रूरत नहीं है और हम सच में बेवकूफी भरे इंटरेस्ट-पेमेंट और बड़े, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेवकूफी भरे टैक्स की बड़ी मेहनत से खुद को बचा सकते हैं।

चलो, आखिरकार हम खुद को बड़े लोन-कैपिटल के कहने पर चलने से आज़ाद कर लें! इस लोन-इंटरेस्ट टैक्स-धोखाधड़ी से सिर्फ़ बड़े लोन-कैपिटल को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके लिए सोने का एक अच्छा टुकड़ा बच जाता है और मेहनतकश लोग इस सरप्लस को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चुकाते हैं; इस बीच, छोटे और मध्यम आकार के कैपिटलिस्ट बस अपनी ही पूंछ के पीछे भागते रहते हैं।

ग्लोबल इकोनॉमिक अधिकारी कहते हैं: हमारे लिए सिर्फ़ जर्मनी में इंटरेस्ट-स्लेवरी को खत्म करना मुमकिन नहीं है; इसे इंटरनेशनल लेवल पर करना होगा; नहीं तो हम सारा क्रेडिट खो देंगे, कैपिटल बह जाएगा, और हमें बाकी दुनिया के प्रति अपनी इंटरेस्ट-ऑब्लिगेशन्स को पूरा करना होगा।

मैं मानता हूँ कि मैं खुद भी इस सवाल को लेकर बहुत लंबे समय तक उलझन में था। यह सबसे मुश्किल सवाल है क्योंकि इसमें बाकी दुनिया के साथ हमारा रिश्ता शामिल है; इस बीच इस मामले के दो पहलू हैं। एक तरफ, ब्याज-गुलामी को खत्म करने का विचार सभी प्रोडक्टिव लोगों का नारा है, जो पैसे पर ब्याज की इंटरनेशनल गुलामी के खिलाफ है; दूसरी तरफ, यह हमारी अंदरूनी फाइनेंशियल परेशानी का पक्का इलाज है। लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि हम किसी इलाज का इस्तेमाल करने से बचें, सिर्फ इसलिए कि उतना ही बीमार पड़ोसी उसी समय उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन यह और भी बेवकूफी होगी अगर हम जर्मनी में एक पागलपन भरे चक्कर में घूमते रहें और टैक्स और ब्याज देते रहें, जबकि हमने साफ तौर पर यह पहचान लिया है कि इस बेकार काम से सिर्फ बड़े कैपिटलिस्ट को फायदा होता है और किसी और को नहीं। इसलिए, आइए हम अपने आज़ादी देने वाले उदाहरण से रास्ता दिखाएं; आइए हम खुद को पैसे पर ब्याज की गुलामी से आज़ाद करें, और हम जल्द ही देखेंगे कि इस जीतने वाले आज़ादी देने वाले विचार की ताकत दुनिया के लोगों को हमारा पीछा करने के लिए उकसाएगी।

मुझे सच में यकीन है कि हमारी पहल – अगर इस पहल को दबाया नहीं गया
जर्मन मैमोनिस्ट – ज़बरदस्त ज़रूरत के साथ दूसरे लोगों को भी अपने साथ ले जाएंगे।

स्पार्टासिस्ट कहते हैं: पूरा आइडिया सिर्फ़ कैपिटल की सुरक्षा के लिए है; यह अभी भी
तब भी स्थिति वैसी ही बनी रहती है: गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता और अमीर बना रहता है।

हाँ, मेरे दोस्त; आम तौर पर आपसे बात करना बहुत मुश्किल है — अगर आप सच में दिल से कम्युनिस्ट हैं, और इसलिए असल में यह मानते हैं कि "सब कुछ सभी लोगों का है"10

, और अगर इसके साथ ही आप वाकई रूस के महान बोल्शेविक नेताओं, खासकर लेनिन के असली विचारों से वाकिफ हैं, और उन्हें सही मानते हैं, और उसी हिसाब से लेनिन द्वारा बताए गए सोवियत रिपब्लिक के अगले कामों, "सारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब-किताब और कंट्रोल," को इंसानी तौर पर मुमकिन मानते हैं।

10पीटर क्रोपोटकिन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ़ ब्रेड

लेकिन अगर आप इस बात को लेकर पूरी तरह से साफ़ हैं कि यह काम असल में सिर्फ़ एक भयानक तानाशाही के तहत ही मुमकिन है, और आप अभी भी अपने दिल की गहराइयों में एक पक्के कम्युनिस्ट या स्पार्टासिस्ट वगैरह बने हुए हैं, तो हमें एक-दूसरे से और बहस नहीं करनी चाहिए; हम बस एक-दूसरे को समझते नहीं हैं और अलग-अलग भाषाएँ बोल रहे हैं, और भविष्य तय करेगा, या तो बोल्शेविज़्म की अव्यवस्था से बनने वाले स्ट्रेट-जैकेट स्टेट के लिए, या उस नए स्टेट के लिए जिसके लिए मुझे उम्मीद है, जिसमें ब्याज-गुलामी से आज़ाद नेशनल इकॉनमी होगी।

लेकिन अगर, आपके कम्युनिस्ट दिल की गहराई में - अगर आप ईमानदार हैं - आप पाते हैं कि आप अभी भी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचते हैं, तरसते हैं, एक ऐसे मानव आत्मा के लिए जो एस्किमो या ज़ुलु काफ़िर से भी ज़्यादा आपके करीब हो, अगर सोवियत-निदेशक के नेतृत्व में कारखाने में काम करते समय आपको लगता है कि अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा बगीचा होना अभी भी अच्छा होगा, अगर वास्तव में आपकी आत्मा की गहराई में यह वास्तव में कोई सच्चा संतोष नहीं देता कि आपको सड़क पर एक कुत्ते की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर कुतिया का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए, अगर आप किसी को अपनी पत्नी कहना चाहते हैं, अगर आप केवल अपने वेतन से कुछ बचाने के बारे में सोचते हैं, जो तब केवल आपका होना चाहिए, तो आप पहले से ही कम्युनिस्ट नहीं रहे; तब आप अपने दिल में पहले ही अपने इतने ज़ोर से घोषित नारे, "सभी चीजें सभी मनुष्यों की हैं" से टूट चुके हैं; तब ठीक जो आप नहीं चाहते वो ये है आप वही चाहते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं – पत्नी, बच्चा, घर, खेत, बचत – चाहे ये सब आपके पास पहले से हो या आप सिर्फ इसे पाने की आशा रखते हों, तब भी ये सिर्फ आपके लिए होना चाहिए।

और देखो, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें बस अपने दिल में शक है कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ सकता है, अगर कोई अनजान आदमी आकर बस “सबके” नाम पर तुम्हारी सेविंग्स ले ले, और अगर वह तुम्हारे लिए दूसरा बच्चा ले आए और तुम्हारा बच्चा भी अपने साथ ले जाए क्योंकि सभी बच्चे “सबके” हैं, तो मेरे दोस्त, हमें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग बात नहीं करनी चाहिए।

शायद मैं आपसे यह सोचने के लिए कह सकता हूँ कि क्या सच में कम्युनिस्ट मैसेज कि सभी चीज़ें सभी इंसानों की होनी चाहिए, का मतलब हर कल्चर का अंत नहीं होगा, क्योंकि ओनरशिप के किसी भी कॉन्सेप्ट की कमी, मज़बूत लॉजिक के साथ इंसान को जानवर के लेवल तक ले जाती है।

अगर सभी चीज़ें सभी इंसानों की हैं, अगर लेनिन के हिसाब से ज़मीन के ऊपर होने वाले सभी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब-किताब और कंट्रोल ज़बरदस्ती किया जा सकता है, तो सबसे अच्छे हालात में चींटियों की कॉलोनी बन जाएगी। लेकिन उस हालत में, हम भाषा, आत्मा और सोच के बिना भी काम चला सकते हैं; चुपचाप और अपने आप हम अपना ज़बरदस्ती का काम कर सकते हैं। इंसान का अंत वहीं है।11

लेकिन अब बहुत हो गया, दोस्त स्पार्टाकस। इस ज़रूरी बात को अपने दिमाग और दिल में गहराई से बिठा लो। तुम्हारे सवाल का ज़्यादा सही जवाब तब दूसरी पार्टियों से बातचीत के दौरान मिलेगा।

और अब, आप दो सोशलिस्ट सोच वाले साथियों, मॉडरेट और इंडिपेंडेंट!12

मैं सोच भी नहीं सकता कि ब्याज-गुलामी को खत्म करने के खिलाफ कोई गंभीर विरोध या आपत्ति आपकी तरफ से आएगी, और फिर भी मुझे मार्क्स से लेकर आज के नेताओं एबर्ट, शीडेमैन, कौत्स्की वगैरह तक, विचारों की पूरी सोशलिस्ट दुनिया के साथ, आपके साथ साफ-साफ बात करनी होगी।

1. सोशलिस्ट इच्छा: मज़दूर वर्ग का उत्थान एक ऐसा विचार है जो बिना किसी शर्त के प्रबल होगा; अब तक, हम इस पर सहमत हैं।

---

11 “इंसान का अंत” यहेजकेल से है। वहाँ इसका मतलब इंसान का मकसद है लेकिन यहाँ इसका दोहरा मतलब हो सकता है। कम्युनिज्म के तहत इंसान का मकसद बिना सोचे-समझे गुलामी बन जाता है, जो इंसान का विनाश है।

12 फेडर यहां सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी शांतिवादी शाखा, इंडिपेंडेंट सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी का ज़िक्र कर रहे हैं।

2. इस महान लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए रास्ते लगभग पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि वे

3. गलत अंदाज़ों पर आधारित हैं।

4. राज्य का [मार्क्सवादी] समाजवादी विचार अनिवार्य रूप से साम्यवाद की ओर ले जाता है, इस प्रकार गिरावट।

5. हालाँकि सोशल-डेमोक्रेसी का लक्ष्य अलग है, मज़दूर वर्ग का, आम तौर पर सभी काम करने वाले लोगों का उत्थान, लेकिन इसे एक भयानक अंदरूनी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्क्सवाद के लॉजिकल नतीजे मज़दूर आंदोलन के प्रैक्टिकल लक्ष्य के ठीक उलटे होते हैं।

6. इस अंदरूनी बँटवारे से दिशा में साफ़ अनिश्चितता पैदा होती है सरकार।

7. बड़े प्रैक्टिकल लक्ष्य (मज़दूर वर्ग की तरक्की) के लिए स्पार्टाकस और बोल्शेविक कम्युनिज़्म के खिलाफ़ एक और कड़ी लाइन खींचनी होगी, और उनके तरीकों का पूरी ताकत से मुकाबला करना होगा। लेकिन लेबर-यूनियन के ज़रिए बनी सोशल डेमोक्रेसी आज इन रेडिकल ग्रुप्स के सामने कमज़ोर महसूस करती है, क्योंकि इसने मार्क्सवादी सोच को शिक्षा का अपना बुनियादी सिद्धांत बना लिया है, और क्योंकि मार्क्सवादी सोच के सभी तरीके लॉजिकली कम्युनिज़्म की ओर ले जाते हैं।

अब सबूत: पॉइंट 2 कहता है कि सोशल-डेमोक्रेसी के रास्ते लगभग पूरी तरह से गलत हैं।

पूरे देश में हुए इस पूरे आंदोलन की वजह से हमारे देश की आबादी में गहरा बँटवारा हो गया है। हर तरह के मालिकों, बल्कि हर बड़े मालिक के खिलाफ़ लगातार की जाने वाली बदनामी, जो बिना किसी मदद के काम करने वाले मेहनती मज़दूरों का शोषण करने वाले और खून चूसने वाले हैं, ने बेवजह की कड़वाहट और मज़दूरों के घमंड को जन्म दिया है, जो आज ज़रूरी तौर पर "सर्वहारा वर्ग की तानाशाही" (कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो) की माँग में दिखता है। एरफ़र्ट प्रोग्राम की ज़रूरी माँग – प्रोडक्शन के साधनों को प्राइवेट मालिकी से कम्युनिटी की मालिकी और कामकाज में ट्रांसफर करना – आज "सोशलाइज़ेशन" की पुकार में दब गई है।

हर सीरियस पॉलिटिशियन को यह बात पूरी तरह साफ़ है कि हमारी इकॉनमिक बर्बादी का पूरा सोशलाइज़ेशन का मतलब होगा पूरी तरह से स्टेट बैंकरप्सी। लेकिन कोई भी इसे लोगों के सामने खुलकर और बिना किसी रोक-टोक के मानने की हिम्मत नहीं करता।

अब सोशलाइज़ेशन नहीं बल्कि डीसोशलाइज़ेशन ही मोटो होना चाहिए। इस तरह, हर सोशलाइज़ेशन की साफ़ नाकामी की भरपाई गुमराह करने वाले टैक्स-प्रोजेक्ट्स के ज़रिए करने की कोशिश की जाती है और इस रास्ते से दूसरी बार "एक्सप्रोप्रिएटर्स को एक्सप्रोप्रिएट" किया जाता है। इन सबका मतलब पूरी नेशनल इकॉनमी को पूरी तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ देने के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रोथ के बजाय (प्रोडक्शन का दोगुना होना, जैसा कि क्रांति के बाद के समय के पूरे सोशलिस्ट लिटरेचर में वादा किया गया था, सवाल ही नहीं उठता) ठीक इसका उल्टा हुआ है।

लेकिन सबसे बुरी बात यह होगी कि अगर मौजूदा सोशलिस्ट सरकार बड़े विदेशी लोन लेने के बारे में सोचे। इससे न सिर्फ़ हमारी आर्थिक गिरावट रुक जाएगी, बल्कि हम पूरी तरह से एंटेंटे की ब्याज़ की गुलामी में पड़ जाएँगे, जिससे कोई वापसी नहीं होगी।

बुनियादी नाकामी, बुनियादी गलती, जिस पर लोगों से किए गए समझौतों, मांगों और वादों की यह पूरी गलत चेन बनी है, वह है इंडस्ट्रियल कैपिटल और लोन-कैपिटल के प्रति पूरी तरह से गलत रवैया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एरफर्ट प्रोग्राम, मार्क्स,

एंगेल्स, लासेल, कौत्स्की ने इंडस्ट्रियल कैपिटल और लोन-कैपिटल के बीच बड़े अंतर को नहीं पहचाना है।

इस बात पर पूरी सोशल-डेमोक्रेसी को फिर से सीखना होगा; इस बुनियादी गलती को साफ तौर पर पहचानना होगा और बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर मानना होगा। फिर, फिर भी, किसी को लगातार एकमात्र मुमकिन नतीजे भी निकालने होंगे। हालांकि, ये इंडस्ट्री के खिलाफ, मालिक के खिलाफ बेकार के गुस्से को पूरी तरह से छोड़ने का इशारा करते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। मज़दूर और काम देने वाला एक साथ हैं; उनका एक ही मकसद है -- काम, प्रोडक्शन; क्योंकि बिना प्रोडक्शन के, बिना काम के, कोई ज़िंदगी नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई आगे नहीं, और कोई ऊपर नहीं। इंसानों के बीच जो खुद-ब-खुद और जिन्हें टाला नहीं जा सकता, विरोध मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि वे इंसान हैं, वे मालिक और कर्मचारी के बड़े साझा फायदे से बहुत कम ज़रूरी हैं। ये विरोध दोनों तरफ के आपसी सैटिस्फैक्शन के लिए सैलरी-कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड-ऑर्गनाइजेशन के ज़रिए हल किए जा सकते हैं और किए गए हैं।

लेकिन आइए हम इन सवालों पर आगे न बढ़ें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत पर हमारी किताब के दायरे में मामूली हैं, और हम सिर्फ़ इस बात पर ज़ोर दें कि मज़दूरों का हित मिलकर हमारे नेशनल इंडस्ट्री, हमारे लोगों की नेशनल इकॉनमी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।

जो कोई भी इसके उलट सिखाता है और मालिक और कर्मचारियों के बीच के विरोध को ज़्यादा ज़रूरी बताता है, वह ठीक मज़दूरों के मामले में खुद को गैर-ज़िम्मेदार दिखाता है; क्योंकि ऐसा करके वह उस पेड़ की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारता है जो मज़दूर को पालता और सहारा देता है।

लेकिन सोशल-डेमोक्रेसी ने ऐसा किया है, और इसके साथ ही उसने जर्मन मज़दूरों के सामने हमेशा के लिए गुनाह मोल ले लिया है; इसके साथ ही इसने हमारे लोगों पर बहुत ज़्यादा दुख ला दिया है, क्योंकि यह अपने सभी वादे पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमें आपसी समझ की शांति नहीं दे सकता, क्योंकि यह हमारे लिए काम नहीं बना सकता, क्योंकि इसे हमारे खिलाफ़ एक हथियारबंद सेना भी बनानी होगी, क्योंकि यह सिविल सर्विस के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे काम करने की ज़िम्मेदारी मांगनी होगी, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए यूनिवर्सल बराबर और सीधा वोट देने का अधिकार किसी को भी गुज़ारा करने में मदद नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा की राज्य की गारंटी के बिना अराजक हालात पैदा होंगे, क्योंकि व्यक्ति के समाज में जुड़ने और उसके अधीन होने के बिना राज्य की कोई भी जान मुमकिन नहीं है।

इस तरह, निराशा की एक गहरी, निराशा भरी लहर पूरे लोगों में फैल जाती है। अगर लोग अब भी इसे नहीं समझते हैं, तो मंत्री, संसद के सदस्य और लोगों के प्रतिनिधि खुशी-खुशी एक-दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं कि “क्रांति के फ़ायदों” को “रिएक्शन” से बचाना होगा: इन दो शब्दों का क्या मतलब है, अगर कुछ है भी, तो कोई भी ईमानदार नेता लोगों को साफ़-साफ़ नहीं बता पाएगा।

क्रांति के बुरे काम, पुराने राजवंशों को हटाना, अधिकारियों को हटाना, अमीरों का खात्मा, सेना को खत्म करना, संक्षेप में, “बड़ी तोड़फोड़,” असल में कोई “फायदा” नहीं है।

और रिएक्शन?! ईश्वरीय अधिकार के घिसे-पिटे, सड़े-गले सिद्धांत को पूरी जनता में कहीं भी इतना नैतिक सपोर्ट नहीं है कि कोई ज़बरदस्त कार्रवाई हो सके; असली बुर्जुआ के मामले में, बुर्जुआ वर्ग बहुत ज़्यादा डरपोक है, नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, कि वह वर्ग-चेतन मज़दूरों के खिलाफ़ रैली करे: इसलिए मज़दूरों के शासक वर्ग को वंशवादी या बुर्जुआ रिएक्शन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

लेकिन क्रांति के तथाकथित फ़ायदों को लेकर लोगों की गहरी निराशा, दूसरे शब्दों में लोगों की हालत में कोई असली सुधार न होने को लेकर, यही सबसे बड़ा खतरा है। इस निराशा की वजह से बड़ी संख्या में लोग लेफ़्ट की तरफ़ और दूर चले जाते हैं, जहाँ पहले से किए गए वादे कहीं ज़्यादा पूरे हो जाते हैं।

आखिरकार, कोई भी "सब लोगों को सब कुछ" जैसे वादे नहीं कर सकता। यह तो पूरी तरह पागलपन है, लेकिन हर विचार, हर बात, हर काम जिसे बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाए, आखिर में पागलपन बन जाता है, और फिर उसका उल्टा हो जाता है। तो, कम्युनिस्ट विचार भी यही कहता है कि सब कुछ सबका होना चाहिए, क्योंकि यह आखिर में खत्म हो जाता है और सबके पास... कुछ भी नहीं रह जाता। रूस में भूख, निराशा, दुख, बीमारी और ज़रूरत आ गई है; लोगों ने जीने की हिम्मत और खुशी का आखिरी बचा हुआ हिस्सा भी खो दिया है।

मैं दोहराता हूँ: सोशलिस्ट सोच की दुनिया में सबसे बड़ी बुनियादी गलती आखिरकार इंडस्ट्रियल कैपिटल और लोन-कैपिटल के बीच गहरे ज़रूरी अंतर को न पहचानने में नाकामी से जुड़ी है। ब्याज खाने वाली लोन-कैपिटल इंसानियत के लिए मुसीबत है। यह बड़ी लोन कैपिटल की लगातार, बिना मेहनत के और कभी न खत्म होने वाली बढ़ोतरी है, न कि प्रोडक्टिव, सामान बनाने वाली, इंडस्ट्रियल वर्किंग-कैपिटल, जो लोगों के शोषण की ओर ले जाती है।

मैं यहां इस सवाल की जांच करने से नहीं बच सकता कि इस ज़रूरी अंतर को क्यों नहीं पहचाना गया; क्या इसे सच में नहीं पहचाना गया, या शायद इसे बड़े लोन-कैपिटल के फ़ायदे के लिए छिपा दिया गया; क्या कैपिटलिज़्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में लीडर और चीफ़, क्या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एरफ़र्ट प्रोग्राम के लेखक, और मौजूदा लीडर हमेशा ज़रूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े हैं।

यह सबसे गंभीर और भयानक बात है जब कोई दूसरे की पूरी ईमानदारी और पक्के यकीन पर शक करता है; यह बात और भी गंभीर लगती है, जब कोई ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं से जुड़े कारणों और रिश्तों को ज़्यादा ध्यान से खोजता है। इसलिए मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि सिर्फ़ डिज़रायली, जो सबसे महान इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड बीकन्सफ़ील्ड थे, की एक बात का ज़िक्र करके बड़े, अस्पष्ट कनेक्शन की ओर इशारा करना चाहता हूँ। यह उन्होंने अपने नॉवेल एंडिमियन में लिखा है:

"कोई भी इंसान नस्ल के उसूल को नज़रअंदाज़ नहीं करेगा। यह इतिहास की चाबी है, और इतिहास अक्सर इसलिए इतना कन्फ्यूज्ड होता है क्योंकि इसे ऐसे लोगों ने लिखा है जो इस उसूल और इससे जुड़े सभी ज्ञान से अनजान थे।" [बैरन सर्जियस से एंडिमियन]

बुर्जुआ.

बुर्जुआ, जिसके लिए आराम करना उसका बुर्जुआ फ़र्ज़ लगता है, हर नई क्रांतिकारी मांग से ज़रूर परेशान होता है, जैसा कि हमेशा हर नए विचार से होता है। इसका मतलब उसके लिए बेचैनी है; क्योंकि शायद उसे इसके बारे में कुछ सोचना भी पड़े। हर बदलाव उसे बुरा लगता है; वह आराम करना चाहता है, और धिक्कार है उस पर जो अपने पैसों का लालच करता है। अब सच में कोई उससे उसका ब्याज़-पेमेंट, घरों के किराए से होने वाली उसकी इनकम, उसके कवर्ड बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज़-पेमेंट, मॉर्गेज पर मिलने वाला ब्याज़ चाहता है; संक्षेप में, जो उसके आराम, उसकी संतुष्टि और उसकी अच्छी किस्मत का हिस्सा है।

फिर भी, हमें यह पूछना होगा कि लोन-कैपिटल वाले क्लास के लोगों का क्या कहना होगा। वे, सच्चे बुर्जुआ के अलावा... बुर्जुआ एक इंसानी टाइप है, जिसके साथ आगे कुछ भी शुरू नहीं किया जा सकता; बुर्जुआ इंसानियत के पेड़ की एक डाली है जिसे जितनी जल्दी काट देना चाहिए, उतना अच्छा है। ये घमंडी, खुद से खुश रहने वाले बैबिट्स हैं जिनका नज़रिया बहुत छोटा है, जिनमें कोई जोश नहीं है। वे कॉफी, सुबह का अखबार, सुबह का ड्रिंक, दोपहर का पेपर, लंच, दोपहर की झपकी, कूपन-क्लिपिंग, दोपहर का ड्रिंक, पब में दोस्तों के साथ और कभी-कभी मूवी हाउस में हमेशा की बोरियत में अपने दिन बिताते हैं। दुनिया को चलाने वाली हर चीज़, जिसके लिए युवा तरसते हैं, जो लोगों, राज्य और समाज को परेशान करती है, उसकी समझ की कमी के कारण, युद्ध और जीत से बेफिक्र, वे जड़ हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, साथ ही घमंडी और चापलूस भी – लेकिन बुर्जुआ इतना बड़ा क्लास है कि उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इस तरह, ब्याज-गुलामी खत्म होने से बचत खत्म हो जाती है; लोग गरीब हो जाते हैं।

इस बात से पूरी तरह इनकार किया जाना चाहिए कि ब्याज-गुलामी के खत्म होने का आम तौर पर बचत पर असर पड़ सकता है। बचत का मौजूदा आर्थिक विचारों से उतना ही लेना-देना है, जितना कि फिजूलखर्ची से। बचत और फिजूलखर्ची इंसानी गुण हैं जो या तो होते हैं या नहीं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ज़माना ब्याज के विचार को मंज़ूरी देता है या नापसंद करता है।

बदलाव के समय में शायद बचत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन, इस मामले में, मेरा मानना है कि एक समझदार, पैसे बचाने वाला इंसान खुद से यह कहेगा: "मैं अब भविष्य में सिर्फ़ अपने ब्याज पर नहीं जी सकता। लेकिन मैं बाद के सालों में जीना चाहता हूँ और अपने बच्चों के लिए भी कुछ पीछे छोड़ना चाहता हूँ; इसलिए, मुझे अब ज़्यादा बचत करनी होगी।" मेरी राय में, ब्याज-गुलामी खत्म होने का ज़्यादातर लोगों पर यही असर होना चाहिए। जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, तो बेशक उन्हें पब्लिक सपोर्ट के लिए भेजा जाएगा।

यहां भी मुझे एक बार फिर ज़ोर देकर कहना होगा कि प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट टैक्स के मौजूदा बोझ और हर लाइफस्टाइल पर इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ को देखते हुए, अच्छे इंटरेस्ट-पेमेंट में से कुछ भी नहीं बचता, सिवाय उस व्यक्ति के मामले में जिसके लिए – और यह वाकई गलत है और जिसका सामना करना होगा – सारी इनकम सिर्फ़ हमेशा इंटरेस्ट-पेमेंट से आती है। इसलिए, बचत में कमी से शायद डरने की ज़रूरत नहीं है।

क्या (घिनौना) बड़ा कैपिटल सच में इतना बेकार है? क्या इसने बड़े पैमाने पर तरक्की के ऐसे तरीके भी नहीं बनाए हैं जो इंसानियत के लिए उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे देते हैं जो लोन-कैपिटल पर ब्याज से बर्बाद होते हैं?

नहीं! यह सवाल पूछने से यही साबित होता है कि मैमोनिस्टिक कहावतों ने हमारी साफ़ सोच को धुंधला कर दिया है।

बड़ी कैपिटल ने बड़े पैमाने पर तरक्की के तरीके नहीं बनाए हैं; बल्कि बड़ी कैपिटल मेहनत से बढ़ी है! सारी कैपिटल जमा की गई मेहनत है। बड़ी कैपिटल अपने आप में बेकार है, क्योंकि सादा पैसा अपने आप में पूरी तरह से बेकार चीज़ है। दिमाग, मेहनत, और मौजूद या पहले से बने कच्चे माल या मिनरल रिसोर्स से, वैल्यू बनती हैं, और सामान बनता है – मेहनत से और सिर्फ़ मेहनत से।

क्योंकि अगर कोई सबसे उपजाऊ खेत में, सबसे अमीर कोयले की खदान में इतना पैसा डालता है, तो उस वजह से खेत में अनाज नहीं उगता, और न ही कोयले की खदान खुद कोयला उगलती है! आइए हम इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं।

अगर लोगों ने पैसे का आविष्कार किया है, तो यह काफी उपयोगी और उचित है; क्योंकि हर
कॉम्प्लेक्स इकॉनमी के लिए इस (सबको पता) "पूरे काम का वाउचर" चाहिए। लेकिन इन "पैसे के साम्राज्यों" में यह पोटेंशियल होना चाहिए कि वे हमेशा खुद से बढ़कर बहुत बड़े हो जाएं – और पैसा ऐसा करता है, अगर वह ब्याज दे सके – यही वह चीज़ है जिसके खिलाफ हमारा मूल अस्तित्व बगावत करता है; यही वह चीज़ है जो पैसे को दुनिया की बाकी सभी चीज़ों से बहुत ऊपर उठाती है; यही वह चीज़ है जो पैसे को एक आइडल बना देती है। और यह सब सच में इंसानियत का सबसे बड़ा खुद को धोखा देना है!

सिर्फ़ पैसे से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल सकता। टेबल, अलमारी, कपड़े, घर, औज़ार, शॉर्ट में कहें तो हमारे आस-पास की हर चीज़ की कुछ न कुछ कीमत होती है; आखिर में कोई भी टूटे हुए फ़र्नीचर को जलावन की तरह इस्तेमाल करके खुद को गर्म कर सकता है, लेकिन बीस मार्क के नोट से कोई कुछ नहीं कर सकता;
मैं इसमें पनीर का एक टुकड़ा भी नहीं लपेट सकता। जब लोग समझदारी से इस्तेमाल के लिए सामान के लेन-देन की सुविधा पर सहमत हो जाते हैं, पूरी की गई मेहनत के लिए वाउचर लिखते हैं, तभी कागज़ की पर्ची को मतलब और मकसद मिलता है, और यह बहुत सही है कि किसान अपने अनाज के बदले कोयला खदान कंपनी से कोयला नहीं बल्कि पैसा ले; इस तरह

दूसरे पूरे किए गए काम के लिए वाउचर, जैसे पिचफोर्क, क्रॉकरी, हल और दरांती। लेकिन इसके साथ ही पैसे की ताकत खत्म हो जानी चाहिए।

इस तरह, इंसानियत की बड़े पैमाने पर तरक्की पैसे से नहीं, बल्कि खुद इंसानों से हुई है, उनकी हिम्मत, उनकी गर्व भरी हिम्मत, उनका चालाक दिमाग, उनके हाथों की ताकत, उनकी मिली-जुली, इसलिए सामाजिक, मेहनती मेहनत से। हमें इतने गर्व से और इतने साफ तौर पर देखना चाहिए। इंसान ही असली चीज़ थे, पक्का वो बेचारे कागज़ के टुकड़े नहीं जिन्हें इंसानों ने कॉमर्स को आसान बनाने के लिए बनाया था।

आगे का कार्यक्रम

हालांकि ब्याज-गुलामी को खत्म करना नई सरकार का आखिरी मकसद नहीं है; यह सच में सबसे असरदार काम है, अकेला ऐसा काम है जो सभी लोगों को एक सच्चे लीग ऑफ़ नेशंस में एकजुट कर सकता है, उस मैमोनिज़्म के ज़ुल्म के खिलाफ़ जो सभी लोगों को घेरता है। लेकिन यह अंत नहीं है।

इसके उलट, ब्याज-गुलामी को खत्म करने के लिए और कदम उठाने होंगे, क्योंकि, जैसा कि हमने देखा है, यह दुनिया भर की बुराई को जड़ से, और असल में मुख्य जड़ से पकड़ लेती है।

जब ब्याज-गुलामी को खत्म करने की बुनियादी मांग पूरी हो जाती है, तभी पहली बार सोशल स्टेट के लिए रास्ता साफ होता है। इसे साफ तौर पर पहचानना होगा, और इसे सभी मैमोनिस्टिक ताकतों के बावजूद पूरा किया जाना चाहिए। सोशलाइजेशन की मांग [जब तक ब्याज-गुलामी बनी रहती है] सभी इंडस्ट्रीज़ का एक ट्रस्ट बनाने और हर जगह बड़े ग्रुप बनाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर बड़ी लोन-कैपिटल, सभी वेल्थ टैक्स के बावजूद, स्वाभाविक रूप से भविष्य में फिर से निर्णायक असर डालेगी। मैमोनिस्टिक नींव पर एक सोशलिस्टिक स्टेट एक बेतुकी बात है और यह स्वभाव से सोशल-डेमोक्रेसी, जो पहले से ही मैमोनिज्म से बुरी तरह दूषित है, और बड़ी कैपिटल के बीच समझौते की ओर ले जाती है।

इसके उलट, हम अमीरों वाले राज्य को पूरी तरह से खारिज करने और समाजवाद की सच्ची भावना के हिसाब से राज्य को फिर से बनाने की मांग करते हैं, जिसमें मुख्य बुनियादी विचार पोषण करने की ज़िम्मेदारी है -- जिसमें कम्युनिज़्म की एक पुरानी बुनियादी मांग को उसकी सही और काम की संतुष्टि मिल सकती है -- इस रूप में कि लोगों के हर सदस्य को राज्य द्वारा सबसे ज़रूरी खाने की चीज़ों के बंटवारे के ज़रिए देश की मिट्टी पर उसका तय हक मिलेगा।

हम आगे मांग करते हैं कि नए राज्य के ढांचे के तौर पर, चैंबर ऑफ़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिसे सबसे बड़े आधार पर चुना जाएगा, और उसके बाद एक परमानेंट चैंबर ऑफ़ लेबर, सेंट्रल काउंसिल हो जिसमें देश के मज़दूरों को उनके पेशे और आर्थिक वर्ग के हिसाब से उनके बंटवारे के हिसाब से आवाज़ मिले।

आखिर में, हम राज्य के डायरेक्टरों के लिए सबसे ज़्यादा जवाबदेही की मांग करते हैं। सोशलिस्ट-एरिस्टोक्रेटिक आधार पर राज्य के इस नए कंस्ट्रक्शन को एक एक्स्ट्रा काम माना जाएगा।

जो जल्द ही उसी पब्लिशर से आएगा। लेकिन, इस सारे कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़रूरी बात ब्याज-गुलामी को खत्म करना है।

मेरा पक्का यकीन, बल्कि मेरा ज्ञान मुझे यह साफ तौर पर बताता है कि ब्याज-गुलामी को खत्म करना न सिर्फ लागू करने लायक है, बल्कि इसे हर जगह बहुत खुशी के साथ उठाया जाएगा और उठाया जाना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखें: बाकी सभी विचारों, आंदोलनों और कोशिशों के उलट, चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा क्यों न हो, जिनका मकसद इंसानियत को बेहतर बनाना है, मेरा प्रस्ताव इंसानी फितरत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता; बल्कि यह खुद को एक ज़हरीली चीज़ के खिलाफ, एक ऐसी चीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करता है जिसे चालाकी से – नहीं, शैतानी तरीके से – बनाया गया था, जो इंसान की सबसे गहरी भावना के बिल्कुल उलट थी, ताकि इंसानियत बीमार हो जाए, इंसानियत को मैटेरियलिज़्म में फंसाया जा सके, ताकि उससे उसकी सबसे अच्छी चीज़, आत्मा, छीन ली जाए। उसके साथ हाथ में हाथ डाले।

पैसे वालों का डरावना, बेरहम ज़ुल्म जारी है, जिसके लिए लोग सिर्फ़ ब्याज़ के गुलाम हैं, सिर्फ़ डिविडेंड और ब्याज़ के लिए काम करने के लिए मौजूद हैं।

बहुत परेशान होकर हम पुरानी बाइबिल की कहावतों की डरावनी साफ़ और सच्चाई को पहचानते हैं, जिसके अनुसार यहूदियों के भगवान यहोवा अपने चुने हुए लोगों से वादा करते हैं: "मैं तुम्हें दुनिया के सारे खज़ाने देना चाहता हूँ; तुम्हारे पैरों के नीचे धरती के सभी लोग होंगे और तुम उन पर राज करोगे।"

यह ग्लोबल सवाल अब आप सबके सामने है। ग्लोबल सवाल हाथ हिलाने से हल नहीं होते, लेकिन यह बात साफ़ है। और इस काम को लगन से फैलाना होगा; हमें साफ़ तौर पर समझना होगा कि हमारा सामना सबसे बड़े दुश्मन से है, दुनिया भर में फैली पैसे की ताकत से। सारी ताकत दूसरी तरफ, हमारी तरफ सिर्फ़ न्याय, मेहनत का हमेशा रहने वाला न्याय।

सभी देशों के मेहनतकश लोगों, एक हो जाओ, मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ!

राष्ट्रीय स्तर पर जर्मन राज्य

समाजवादी फाउंडेशन

प्रस्तावना

द्वारा

एडॉल्फ हिटलर

हर महान विचार के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकत की इच्छा और साफ़ लक्ष्य। ताकत की इच्छा, आज़ादी की इच्छा, हमारे दिलों में चमकती और मज़बूत होती है, गॉटफ्रीड फेडर ने अपनी किताब, द जर्मन स्टेट ऑन ए नेशनल एंड सोशलिस्ट फाउंडेशन में, हमारे लक्ष्यों को साफ़ और आसान तरीके से और हर किसी को समझने लायक तरीके से बताया है। इसमें लाखों लोगों की उम्मीद और चाहत को एक रूप और मज़बूत अभिव्यक्ति मिली है। हमारे आंदोलन के साहित्य को इसमें अपना धर्मसिद्धांत मिला है।

म्यूनिख, 8 नवंबर, 1923

एडॉल्फ हिटलर

प्रस्तावना

पांचवें संस्करण के लिए

यहाँ मेरा काम, द जर्मन स्टेट ऑन ए नेशनल एंड सोशलिस्ट फाउंडेशन, "नेशनल सोशलिस्ट लाइब्रेरी" की सीरीज़ में है। टेक्स्ट असल में और बेसिकली बदला नहीं गया है, लेकिन वे हिस्से जो उस समय के हालात का ज़िक्र करते हैं जब यह काम आया था (1923) और वहाँ से उदाहरण लिए गए थे, उन्हें हटा दिया गया है और यहूदी सवाल के एक्सप्लेनेशन को छोटा कर दिया गया है क्योंकि बाद वाले सवाल पर एक खास काम किया जाएगा।

नए एडिशन में खास तौर पर इस बात का सबूत होना चाहिए कि बेसिक प्रोग्राम में ज़रा भी बदलाव नहीं किया गया।

मुर्नौ, अक्टूबर 1931

गॉटफ्राइड फेडर

'धन्य हैं वे लोग जिनके लिए यह बहुत ज़रूरी है
एक ऊंचा राजनीतिक विचार थोपता है,
महान और सरल होने के नाते,
युग के हर दूसरे विचार को अपनी सेवा में लगा देता है।

हेनरिक वॉन ट्रेइट्स्के

परिचय

पहले संस्करण के लिए

हम भविष्य को मज़बूत उम्मीद और चाहत से देखते हैं। जर्मनी ज़िंदा रहेगा, जर्मनी नीचे नहीं गिर सकता। जर्मनी ऐसे हिल रहा है जैसे नए ज़माने की तेज़ प्रसव पीड़ा से। खुद को दोषी मानने की भयानक बेड़ियाँ, साथ ही विदेशी परेशान करने वाले, टूट जाएँगे और ज़ोर से कंधे उचकाकर दूर हो जाएँगे, और जर्मनी देशों में सबसे आगे चलेगा।

अगर इतनी तकलीफ़ और परेशानी, बर्बादी और पतन से जुड़ी न होती, तो हम एक नए ज़माने की शुरुआत के दिनों में एक खास खुशी के एहसास के साथ हिस्सा ले पाते। अगर हम आज की गिरावट, आज की उलझन पर नज़र डालें, तो हमें हर जगह एक मज़बूत इच्छाशक्ति, गंभीर काम, प्रेरित इंट्यूशन दिखता है। जर्मन आत्मा एक नई ऊंची उड़ान के लिए अपने पंख फैलाती है।

आज के काम जर्मनों के इतने दर्दनाक इतिहास में पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर, बड़े और मुश्किल हैं।

इसलिए, दोहरे काम को हल करना ज़रूरी है - सिर्फ़ राज्य और अर्थव्यवस्था को "फिर से बनाना" नहीं -
बल्कि उन्हें एक नया रूप देना है। और इससे हमारे लोगों के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन को भी एक नया रूप मिलेगा।

एक जर्मनी की पुरानी जर्मन चाहत आखिरकार सच होनी चाहिए, एक नया इकोनॉमिक कानून आएगा और इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स के बुरे सपने जैसे रूप को खत्म कर देगा।

हमारे लिए जो काम बहुत बड़े और मुश्किल हैं, वे बहुत बड़े हैं। हमारे पीछे अतीत की भावना गंभीर और डराने वाली है; जो इतिहास में हुआ है, उससे हम बहुत हैरान हैं, सबसे अच्छी जर्मन परंपरा की मज़बूत ज़मीन पर, जो सबसे पुरानी आर्यन समझ पर आधारित है, लोगों और राज्य, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नए सिरे से बनाना होगा।

यहां मज़दूरों को अपनी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, असल में उन पर पूरे देश की उम्मीद टिकी है - आज़ादी की ओर!

लेकिन नेशनल सोशलिस्ट आइडिया सिर्फ़ पुराने पुरखों के रीति-रिवाजों में वापसी या भटकाव से कहीं ज़्यादा है, यह मार्क्सवादी राज्य और आर्थिक रूप की ज़ंजीरों को तोड़ता है, यह, पहले और सबसे पक्के आइडिया के तौर पर, जान-बूझकर मैमोनिस्टिक ताकतों के खिलाफ़, पूरी दुनिया को घेरने वाली यहूदी साम्राज्यवाद की ताकत के खिलाफ़, लालच, स्वार्थ और बेपरवाही की भावना के खिलाफ़ सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ता है।

इस यूनिवर्सल और महान जर्मन आज़ादी के आंदोलन को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में अपना सबसे ताकतवर, मज़बूत इरादों वाला और लक्ष्य के प्रति जागरूक कैंपेनर मिला है। पार्टी ने अपने लक्ष्यों को एक छोटे प्रोग्राम में बताया है जो 25 क्लॉज़ में आंदोलन की बुनियादी मांगों को आसान तरीके से बताता है। नेशनलिस्ट ऑब्ज़र्वर13 के चीफ एडिटर अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, जो ग्रेटर जर्मनी के नेशनल सोशलिस्ट आंदोलन का विवादित ऑर्गन है, ने, शुक्रिया के लायक तरीके से, एक छोटे काम14 में प्रोग्राम के पॉइंट्स को अलग-अलग समझाया है ।

13वोल्किशर बेओबैक्टर को 1920 में NSDAP ने पार्टी के ऑर्गन के तौर पर खरीदा था और इसे डिट्रिच एकर्ट ने एडिट किया था। 1923 में उनकी मृत्यु तक, जब इसे अल्फ्रेड रोसेनबर्ग ने लीड किया।

14रोसेनबर्ग ने सबसे पहले अपनी किताब Wesen, Grundsdtze und Ziele der Nationatsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei पब्लिश की। Programm der Bewegung 1923 में।

इस काम के आधार पर कम से कम दोस्तों और दुश्मनों को यह बताना तो मुमकिन है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी क्या चाहती है। दूसरी ओर, नेशनल सोशलिज़्म के लिटरेचर में ऐसा कोई पूरा काम नहीं है जो उन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडिया का ब्यौरा दे जिनसे नेशनल सोशलिज़्म आगे बढ़ता है, नेशनल पॉलिटिक्स के मामले में यह कौन से रास्ते बनाना चाहता है ताकि अपने आखिरी लक्ष्य, यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन स्टेट, काम और परफॉर्मेंस की स्थिति तक पहुँच सके। यह काम इस काम को पूरा करना चाहता है।

इसलिए हमें नेशनल सोशलिज़्म के शुरुआती पॉइंट, रास्ते और लक्ष्य पर रोशनी डालनी होगी, हम दिखाएंगे कि जर्मन नेशनल सोशलिस्ट राज्य मौजूदा राज्य से असल में कैसे अलग होगा, कौन से फ़ील्ड असल में वैसे ही रहेंगे, किन फ़ील्ड में बड़े सुधार होंगे, और कहाँ असल में नए रास्ते अपनाने होंगे।

हमें पब्लिक लाइफ़, खासकर नेशनल फ़ाइनेंशियल पॉलिसी, नस्लीय सवाल और उससे जुड़े सवालों के लिए नए तरीके खोजने और बताने होंगे। हमें उन दुश्मनी भरे विरोधों, तोड़-मरोड़कर पेश की गई बातों और झूठों से भी असल में निपटना होगा जो पहले ही ज़ोर पकड़ चुके हैं।

हमने जो काम खुद के लिए तय किया है, वह बहुत बड़ा है और फिर भी जर्मनी के रिन्यूअल के पूरे स्कोप का एक छोटा सा हिस्सा है।

अगर मौत तक का पक्का इरादा और बिना रोक-टोक की इच्छा हो, तो सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी।
लीडर ने आइडिया के असर के लिए काम नहीं किया।

सबसे मज़बूत इच्छाशक्ति भी बेकार हो जाएगी अगर हम अपने दिल में पक्के तौर पर यह साफ़ तस्वीर न रखें कि यह जर्मन देश - जर्मनी, हमारे पिताओं और बच्चों की ज़मीन - हमारी जीत के बाद हमारी इच्छा के अनुसार कैसा दिखेगा!

1. नींव

नैतिक आधार

नेशनल सोशलिस्ट राज की नींव लोगों और खुद के प्रति पूरी ज़िम्मेदारी है।

"स्व-हित से पहले जनहित" नेशनल सोशलिज्म का पहला नियम है।

यह अजीब लग सकता है कि किसी राज्य के लिए आम तौर पर ऐसा सिद्धांत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम इतिहास के उन दौरों से जानते हैं जब शासकों के मन में राज्य के नेतृत्व की नींव के तौर पर सबकी भलाई होती थी। अगर आज इस सिद्धांत को बाकी सभी बातों से पहले रखना ज़रूरी है, तो यह सिर्फ़ इस बात का सबूत है कि आज के सार्वजनिक हालात इस अकेली सही राजनीतिक भावना का सबूत नहीं हैं। हम इस पहले सिद्धांत में भी बराबर देखते हैं कि नैतिकता और अर्थशास्त्र एक-दूसरे से कितने करीब से जुड़े हुए हैं।

अपने फ़ायदे से पहले पब्लिक का फ़ायदा एक नैतिक मांग है। लेकिन साथ ही यह बहुत अच्छी भाषाई साफ़गोई के साथ पूरे समाज की भलाई और किसी व्यक्ति की निजी चीज़ें खरीदने और प्रॉपर्टी पाने की सही कोशिश के बीच के क्रम को भी दिखाता है। इसलिए यह नेशनल सोशलिस्ट सिद्धांत किसी भी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाहर नहीं करता है। इसके उलट: नेशनल सोशलिज़्म प्रॉपर्टी की अहमियत को पूरी तरह से मानता है। यह जानता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और खरीदी गई चीज़ों को आज़ादी से बेचने का अधिकार हर इकॉनमी और उससे भी आगे, हर ऊँची संस्कृति की बुनियाद है; लेकिन नेशनल सोशलिज़्म ने यह भी माना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानने के लिए कुछ तय सीमाएँ तय करना ज़रूरी है, यानी, जहाँ प्रॉपर्टी सिर्फ़ ताकत का ज़रिया बन जाए और पूरे समाज की भलाई के ख़िलाफ़ शोषण करने वाले तरीके से इस्तेमाल की जाए।

शायद ही कोई गंभीरता से सोचने वाला इंसान होगा जो इस पहले सिद्धांत को इस आम रूप में गलत साबित करना चाहेगा। मुश्किल यह होगी कि आम लोगों के हितों का सही अंदाज़ा किसी एक व्यक्ति के हितों से लगाया जाए। बेशक, इसके बावजूद कि

इस बात पर सहमति कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट से पहले ध्यान में रखना चाहिए, हैरानी की बात है कि हमारे बीच जो कानूनी विचार हैं, उनके हिसाब से, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के तरीके के बारे में, क्रिमिनल से ज़्यादा कोई नैतिक लिमिट तय नहीं की गई है। पक्का, अपने साथी इंसान के खिलाफ हिंसा करना मना है (एक्सटॉर्शन - मर्डर -

हत्या - धोखा और नाजायज़ फायदा, वगैरह), लेकिन कभी भी और कहीं भी बहुत ज़्यादा दौलत जमा करना और उसमें अक्सर काफी शक वाले बैंकिंग और स्टॉक-एक्सचेंज टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करना मना नहीं किया गया है। इसके अलावा, कानून हर क्रेडिटर को यह अधिकार देता है कि वह खराब हालात में किसी बकायादार को बेरहमी से उसके घर और सामान से वंचित कर दे -

बीमारी, मौत, शारीरिक कमी, खराब फसल और अकाल - इन वजहों से किए गए कर्ज़ों को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। हर अनुभवी जज ऐसे अनगिनत मामले बता सकता है जिनमें हमारे सख़्त कानून ने आर्थिक ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, ऐसे मामलों में जहाँ न्याय की हर अच्छी भावना ने एक मेहनती, मेहनती आदमी को, जो कुछ समय के लिए बुरी किस्मत से परेशान रहा है, कर्ज देने वाले के क्रूर दबाव और पकड़ में आने से रोक दिया है।

कुल मिलाकर, सही और कानूनी दावों के लिए पर्सनल अधिकार की बिना किसी रोक-टोक के मान्यता, लॉजिकली, हमारे राज्य के सिद्धांत "खुद के हित से पहले पब्लिक हित" के खिलाफ, इस असल में उल्टे एंटी-सोशल कानूनी विचार के स्वार्थी इस्तेमाल के ज़रिए पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहिए।

हमारे बीच जो गलत बुनियादी सोच है, यानी कैपिटलिस्टिक, उसके उलट, दूसरा एक्सट्रीम है, राज्य और इकॉनमी का मार्क्सवादी विचार। इस इकॉनमिक रूप का बुनियादी विचार प्राइवेट प्रॉपर्टी को नकारना है। मार्क्सवादी सिद्धांत तो प्रॉपर्टी को सीधे "चोरी" (प्रूधों)15 के तौर पर समझाता है। यह विदेशी भाषा में, जो खासकर जर्मन प्रोलेटारियंस के लिए साफ़ नहीं है, "एक्सप्रोप्रिएटर्स का एक्सप्रोप्रिएशन"16 की मांग करता है - दूसरे शब्दों में, प्रॉपर्टी से बेदखली! राज्य, लोगों, संस्कृति और इकॉनमी को खत्म करने वाले इस सिद्धांत को रूसी बोल्शेविज़्म में अपना एक्सट्रीम लेकिन लॉजिकल रूप मिला है। इसके इकॉनमिक पहलू में इस एक्सट्रीम को इस वाक्य में बताया जा सकता है:

"सब कुछ सबका है"।

यहां हमारा काम प्रॉपर्टी के डीपर्सनलाइज़ेशन से है, जिसमें सारी प्रॉपर्टी को पूरी प्रॉपर्टी की एनॉनिमस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना है।

दूसरी तरफ, हमारे बीच अभी भी प्रॉपर्टी पर अनलिमिटेड अधिकार का जो बहुत ज़्यादा चलन है, उसने हमें पहले ही मैमन देवता के मंदिर के सामने आखिरी कदम पर पहुंचा दिया है, जिसके दरवाज़े पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है: "सब कुछ एक का है"। यह डरावना आर्थिक रूप भी प्रॉपर्टी के पर्सनलाइज़ेशन को उतना ही कम करेगा - बस एक अलग तरीके से - जिसमें, आखिरकार, पूरी मेहनत करने वाली इंसानियत को एक अनजान फाइनेंशियल ताकत की डरावनी कर्ज़ की गुलामी में धकेल दिया जाता है।

मार्क्सवादी समाजवाद और पश्चिमी डेमोक्रेट्स के हाई कैपिटलिस्ट मैमनिज़्म के अभी बताए गए आर्थिक चरम सीमाओं के बिल्कुल उलट, नेशनल सोशलिज़्म का आर्थिक आदर्श इस सिद्धांत को लागू करने की मांग करता है, "हर किसी का अपना"।

ठीक इसी सिद्धांत में नैतिकता और अर्थशास्त्र एक बार फिर सबसे गहराई से जुड़े हुए हैं। कमर्शियल ज़िंदगी से नैतिक सिद्धांतों को हटाना आज की अर्थव्यवस्था की खासियत है, जिसमें ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा चालाकी, सबसे खतरनाक सौदों में भी सरकारी अथॉरिटी से बचने की कला ही संतुलन बिगाड़ देती है। बड़े शहरों में अपनी शरारतें करने वाले हज़ारों ज़्यादातर बुरे लोगों पर एक नज़र, जो बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, उन कई मुकदमों पर एक नज़र जो हिस्सा लेने वालों के विरोध के बावजूद ट्रायल तक पहुँचते हैं, हमें दिखाता है कि आज की कमर्शियल नैतिकता कितनी भयानक रूप से खराब हो चुकी है। आइए, इसके उलट, मिडिल-क्लास और शादीशुदा कामकाजी लोगों के बीच की भयानक तकलीफ़ पर विचार करें, जो अब अपने बच्चों के लिए दूध और ब्रेड का खर्च नहीं उठा सकते, यह साफ़ हो जाए कि आम तौर पर कई, कई मामलों में सम्मानजनक काम से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें भी मुश्किल से ही मिल पाती हैं, खासकर

जब बच्चों की देखभाल और परवरिश करनी होती है। इंटेलेक्चुअल और फ्री प्रोफेशन की परेशानी हद से ज़्यादा होती है; सबसे अच्छे दर्जे के आर्टिस्ट, खासकर जब उनका रुझान आज के यहूदी पसंद के रुझान से मेल नहीं खाता, तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है; असली जर्मन कविताएँ पब्लिक में परफ़ॉर्म नहीं कर पातीं। लेकिन उन लोगों की परेशानी तो बयान नहीं की जा सकती, जिनकी फाइनेंशियल पॉलिसी के मामले में सरकार की गलत मैनेजमेंट की वजह से बचत ठगी गई है, छोटे कैपिटल वाले पेंशनर और रिटायर्ड लोग, युद्ध में विकलांग हुए लोग, जिन्हें चैरिटी की मदद लेनी पड़ी, साथ ही वे सभी लोग जिन्होंने पब्लिक बॉन्ड की निश्चितता के साथ-साथ हमारी नेशनल करेंसी की स्थिरता और मार्क के गोल्ड कवरेज पर भरोसा किया है। ऐसी हालत इकॉनमी का टूटना है - अराजकता। मेहनत का बदला कम मेहनताना मिलता है, आलस को इनाम मिलता है, इज्ज़तदार व्यापार मुश्किल में पड़ता है, अनहेल्दी व्यापार, बिचौलिया व्यापार, मुनाफ़ाखोरी सबसे ज़्यादा फलती-फूलती है। कोई प्रोडक्शन कल्चरल तौर पर जितना बेहतर होगा, उतना ही बुरा मेहनताना मिल सकता है। विश्वास का बदला चुकाया जाता है

---

15 पियरे जोसेफ प्राउडन (1809-1865) ने अपनी 1840 की रचना Qu 'est-ce que la proriete? में कहा कि "la propriete c'est le वॉल.

16 यह वाक्यांश, फ्रेंच 'टेक्सप्रोप्रिएशन डेस एक्सप्रोप्रिएट्स' से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल मार्क्स ने दास कैपिटल, I, Ch.24 में किया है: "प्राइवेट प्रॉपर्टी के आखिरी घंटे में ज़ब्त करने वालों को ज़ब्त कर लिया जाता है।"

विश्वासघात, और असल में राज्य द्वारा, जिसे कानून और न्याय का रक्षक, सार्वजनिक नैतिकता का वकील होना चाहिए।

हमें अब पब्लिक लाइफ में करप्शन, प्रेस के यहूदीकरण और गरीबी और हमारी फॉरेन पॉलिसी की बुरी तरह से कमज़ोर और बेकार लीडरशिप की ओर इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी पब्लिक लाइफ और हमारी इकोनॉमिक नैतिकता की बहुत ज़्यादा गिरावट का पता चल सके।

इस भौतिकवादी गरीबी और सार्वजनिक जीवन की गंदगी के खिलाफ, राज्य का नेशनल सोशलिस्ट विचार राज्य और अर्थव्यवस्था का लंबे समय से आजमाया हुआ सिद्धांत तय करता है: "हर किसी का अपना ", लेकिन सबसे ऊपर "अपने हित से पहले जनता का हित"। इस सिद्धांत को नेशनल सोशलिस्ट राज्य का गाइडिंग सिद्धांत बनाने के साथ, नेशनल सोशलिज्म खुद को जर्मन इतिहास के सबसे अच्छे और सबसे शानदार समय से जोड़ता है।

"सुम क्यूइक"17 पहले से ही हेल्दी जर्मन शुरुआती मिडिल एज का इकोनॉमिक प्रिंसिपल था, लेकिन खासकर लंबे समय तक गिल्ड के ऑर्डर से यह पक्का किया गया कि हर किसी को उसका अपना काम दिया जाए। आधे या एक तिहाई पैसे के लिए मास्टर और अप्रेंटिस के बीच काम का कॉमन होना कम से कम वर्कर को उसकी इनकम, बेहतर काम और परफॉर्मेंस को उनकी पहचान और इनाम मिलना पक्का करता था और, शानदार परफॉर्मेंस के मामलों में, नाम और अच्छी कमाई होती थी।

"सुम क्यूइक" प्रशिया के सबसे ऊंचे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ़ द ब्लैक ईगल को भी सुशोभित करता है, हालांकि यहां इस खास मतलब में कि खास काबिलियत को ही इसका ताज मिला है। ठीक यही मतलब नेशनल सोशलिज़्म से काफी मिलता-जुलता है - इसलिए नहीं कि यहां दरबारी सजावट के सामान या मिलिट्री सर्विस के एकतरफ़ा सम्मान की बात है, बल्कि इसलिए कि राज्य और लोगों के प्रति ड्यूटी को इनाम के तौर पर पूरा करने का नैतिक पहलू इसमें दिखता है, ड्यूटी का ऐसा काम जो बिना किसी इरादे के और पहले से कम तनख्वाह की परवाह किए बिना, निजी हितों को पीछे छोड़कर, राज्य और लोगों के प्रति ज़िम्मेदारी की अंदरूनी मज़बूत भावना से पैदा होता है।

हम नेशनल सोशलिस्ट इस सिद्धांत को दूसरी तरफ भी बढ़ाते हैं, हम जर्मन मध्य युग के "हर किसी का अपना" और फ्रेडरिक के राज्य के "अपने ताज के लायक बनने" के विचार में सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हुए यह जोड़ते हैं: "अपराधी को उसकी सज़ा!"। हर किसी का अपना, अपने ताज के लायक बनने के लिए, हर सही और सम्मानजनक काम के लिए उसका सही पेमेंट, हर खास काम के लिए उसका ज़्यादा मेहनताना, हर गरीब इंसान और हर वो इंसान जो बेगुनाह मुसीबत में पड़ गया है, उसे सरकारी पैसे से पूरी मदद, लेकिन उन सभी को भी जो पब्लिक मोरैलिटी और आर्थिक इज़्ज़त के खिलाफ काम करते हैं - उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।

लेकिन, हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह किसी भी तरह से नेशनल सोशलिस्ट राज्य की ड्यूटी के दायरे में नहीं आता कि वह आर्थिक मामलों में राज्य के नागरिकों की अलग-अलग निगरानी करे, ताकि इकॉनमी ब्यूरोक्रेटिक देखरेख से जितना हो सके, आज़ादी से सबसे अच्छी तरह आगे बढ़े। हम यह भी जानते हैं कि राज्य के ज़रिए हर राज्य के नागरिक के मामले में रिस्क में कमी - बल्कि नौमान के "रिस्क-फ्री आदमी" के मतलब में, यानी, एक ऐसे आदमी के लिए जिसके बुनियादी अस्तित्व का इंतज़ाम राज्य को करना चाहिए - ठीक उसके उलटा होगा जिसकी नौमान ने उससे उम्मीद की थी।18 राज्य की ड्यूटी सिर्फ़ एक ऐसी इकॉनमी के लिए ज़रूरी शर्तें बनाने तक ही सीमित होनी चाहिए जो खुद को संभाले।

---

[17] हर किसी का अपना

18 फ्रेडरिक नौमान (1860-1919) एक प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्री और लिबरल नेता थे, जिन्होंने 1896 में इसकी स्थापना की और अपनी पत्रिका डाई हिल्फ़ के ज़रिए एक तरह के सामाजिक उदारवाद का प्रचार किया। पहले विश्व युद्ध के बाद, नौमान ड्यूश डेमोक्रेटिक पार्टी (DDP) के पहले चेयरमैन बने।

आज के ब्याज वाले पूंजीवादी राज्य में हम जिस भयानक सूदखोरी की घटना को जानते हैं, उससे जितना हो सके उतना मुक्त होना चाहिए।

इसलिए राज्य की भलाई एक बार फिर सबसे बड़ा कानून बन जाना चाहिए, राज्य की कुशलता को बाकी सभी बातों से पहले "खुद के हित से पहले जनता का हित" के सिद्धांत को अपनाना चाहिए।

लेकिन अब यह सिद्धांत नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक लाइफ में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच एक ऐसी खासियत को ज़रूरी बना देता है, जो आज सरकार और पब्लिक लाइफ से लगभग पूरी तरह गायब हो गई है - ज़िम्मेदारी।

आज हमारी पूरी पब्लिक लाइफ सीधे तौर पर गैर-ज़िम्मेदारी की निशानी बन गई है। डेलीगेट्स पार्लियामेंट में जो करते हैं और बोलते हैं, उसके लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं - एक कहते हैं "इम्यून टू" -।
यह एक निराशाजनक शब्द है, जब कोई याद करता है कि यह कहावत मेडिसिन से ली गई है जिसमें कहा जाता है कि शरीर पहले से ही ज़हर से इतना भर चुका होता है कि नए डाले गए ज़हर शरीर को बहुत कम या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते, जबकि एक स्वस्थ शरीर उनसे मर जाएगा। बहुमत के फ़ैसलों के लिए गुट ज़िम्मेदार नहीं होते, मंत्री अपने पद के निर्वहन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते क्योंकि वे सिर्फ़ उन पार्टियों के पदाधिकारी होते हैं जो ठीक सरकार बनाने में हिस्सा लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है, तो लोगों को सच में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन तथाकथित ज़िम्मेदार मंत्री की जगह सिर्फ़ कोई दूसरा उतना ही गैर-ज़िम्मेदार पार्टी पदाधिकारी ले लेता है। असली ज़िम्मेदारी का कोई ज़िक्र नहीं है।

राजाओं के दैवीय अधिकार के ज़माने में, भगवान से अपील करना, बदकिस्मती से, अक्सर शासकों की गैर-ज़िम्मेदारी का एक बहुत ही खास रूप था - (कुछ ऐसे अपवाद भी थे जिनके लिए अपने भगवान के प्रति ज़िम्मेदारी, अपने लोगों के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना का पर्याय थी, यह साफ़ तौर पर माना जाता है)। हालांकि, आम तौर पर, यह प्यारा भगवान हमेशा, आखिर में, सिर्फ़ एक आरामदायक सुरक्षा कवच ही था, जिसके पीछे, सिर्फ़ अपने सीनियर के प्रति ज़िम्मेदार अधिकारी, सिर्फ़ अपने राजा के प्रति ज़िम्मेदार मंत्री और सिर्फ़ अपने भगवान के प्रति ज़िम्मेदार शासक की सीढ़ी पर, लोगों की असल ज़िंदगी की ज़रूरतों के मामले में शासक वर्ग और उसके प्रतिनिधियों की सबसे अविश्वसनीय गैर-ज़िम्मेदारी छिपी रह सकती थी।

नेशनल सोशलिज़्म को इस सरकारी गैर-ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से खत्म करना होगा।

नेशनल सोशलिस्ट स्टेट के एंट्रेंस गेट पर लोहे के अक्षरों में 'सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी' लिखी होगी। जिसे महान लोगों के हितों के लिए एक लीडिंग पोजीशन में खड़े होने का सम्मान मिला है, उसे उसकी ज़िम्मेदारी की जितनी ज़ोर से याद दिलाई जाए कम है। असल में, सिर्फ़ वही लीडर हो सकता है जिसके सीने में ज़िम्मेदारी की यह गहरी भावना हो। सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक लाइफ़ में खड़े लोगों के लिए यह ज़िम्मेदारी खास तौर पर तय की जानी चाहिए और इसे पूरी सख्ती से निभाया जाना चाहिए। सिर्फ़ इसी तरह से, कह सकते हैं, असल में रिकवरी को मजबूर किया जा सकता है।

सिर्फ़ इसी तरह सबसे कीमती चीज़ फिर से ज़िंदा हो सकती है और बढ़ सकती है, जिससे लीडर और लोग एक बार फिर एक असली नेशनल और ऐतिहासिक कम्युनिटी बन सकें - भरोसा। और भरोसे से ही फिर से विश्वास बढ़ सकता है, जो लीडर की ज़िम्मेदारी के साथ, जर्मनी की रिकवरी और रिन्यूअल लाएगा, जर्मन आत्मा को फिर से जगाएगा, काम और परफॉर्मेंस की एक नेशनलिस्ट हालत में जिसमें हर कोई अपना रास्ता ढूंढेगा।

आर्थिक नींव

एक हेल्दी इकॉनमिक बॉडी में मोरैलिटी और नेशनल इकॉनमी को अलग नहीं किया जा सकता। नहीं तो इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खासकर हर इकॉनमी के सबसे इज्ज़तदार काम – डिमांड को पूरा करने के मामले में। कॉमर्स में भरोसे के बिना, मेहनत के बिना, अधिकारियों और मज़दूरों की वफ़ादारी के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता।

एफिशिएंसी, न्याय, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, एनर्जी, किसी इकोनॉमिक काम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के बीच आपसी भरोसा, ये हर इकॉनमी की तरक्की के लिए ज़रूरी शर्तें हैं। इन सभी बातों को सिर्फ़ कहने की ज़रूरत है ताकि उनकी खास अहमियत को माना जा सके।

आज और हाल के दिनों में जो भी आर्थिक रूप से एक्टिव रहा है, वह जानता है कि आज इन अच्छी चीज़ों की कितनी कमी है। और मार्क्सवाद के मुक्ति के सिद्धांतों और उसके काम करने के तरीकों, हड़तालों, तोड़-फोड़ और लापरवाही और लापरवाही भरे कामों का नुकसान आखिर किसे होता है? – लेकिन आखिर में सिर्फ़ आबादी को ही नुकसान होता है, जिसने ऐसे राज्य और लोगों को तोड़ने वाले सिद्धांतों के ज़रिए, समुदाय की सारी भावना खो दी है और क्लास-स्ट्रगल में अपना सबसे ज़रूरी काम देखती है। इसलिए, इस तरफ़ उन शिकायतों को भी भेजा जाना चाहिए जो खासकर राष्ट्रवादी कैंपों से आती हैं कि हम अब लोग नहीं रहे, कि अगर हम अपनी खोई हुई ताकत और इंटरनेशनल स्टैंडिंग वापस पाना चाहते हैं तो हमें पहले फिर से लोग बनना होगा।

ये शिकायतें सही हैं, लेकिन शिकायतों से कोई आगे नहीं बढ़ता। मार्क्सवाद ने अपने आर्थिक और राजनीतिक आदर्श को तब पूरा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जब उसके पास ऐसा करने की ताकत थी, वह विरोधियों को बेरहमी से दबाने से भी नहीं कतराया: रूस में उसने हमारे बीच के पूरे बुर्जुआ बुद्धिजीवियों का कत्लेआम करके अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए चुप करा दिया, गणतंत्र की सुरक्षा के लिए कानूनों के ज़रिए।[19] राजनीतिक सत्ता हासिल करना ज़ाहिर तौर पर हर आर्थिक या राष्ट्रीय राजनीतिक सुधार की पहली शर्त है। यह हम कम्युनिस्टों और सोशल डेमोक्रेट्स की तरह जानते हैं, लेकिन हम राजनीतिक सत्ता सिर्फ़ अपने लिए नहीं चाहते, किसी खास वर्ग के ख़िलाफ़ हासिल की गई सत्ता का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि एक मज़दूर समुदाय में बंधे राष्ट्रीय साथियों के बीच आर्थिक शांति के लिए पहली शर्तें बनाना चाहते हैं। मांग को पूरा करना[20] राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का काम है – मुनाफ़ा नहीं, जो आज सामान के उत्पादन में लगभग पूरी तरह से तय करने वाला है। राष्ट्रीय समाजवाद के इस बुनियादी नज़रिए के साथ, हम पूंजीवादी राज्य के बुनियादी आर्थिक विचारों के पक्के विरोध में उतरते हैं। सबसे पहले वह नहीं बनाया गया जो ज़रूरी था, बल्कि वह बनाया गया जो मुनाफ़े वाला था। जिस भी चीज़ से काफ़ी इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलने का वादा नहीं किया जाता था, उसे शुरू से ही नहीं लिया जाता था। मौजूदा इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के प्रॉफिटेबिलिटी के पागलपन का एक खास उदाहरण यह हो सकता है कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत के बावजूद – यानी सबसे ज़रूरी ज़रूरत के बावजूद – बस इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह प्रॉफिटेबल नहीं है! यह कि नेशनल पॉलिटिकल नज़रिए से हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को ऊँचे अर्थों में देखा जाए तो यह वाकई प्रॉफिटेबल होगा, इसके लिए यहाँ और किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह बात साफ़ है कि खासकर राज्य के सोशल कामों के बारे में जो कहा गया है, उससे यह साफ़ है। इसके अलावा, अगर लोग भूखे मरते हैं और ठंड से ठिठुरते हैं, तो प्रॉफिट कमाने वाली कैपिटलिस्ट इकॉनमी किसी भी तरह से सस्ते और अच्छे जूते, कपड़े और अंडरवियर वगैरह बनाकर इस ज़रूरत को पूरा करने में अपनी ड्यूटी नहीं देखती, क्योंकि आबादी की खरीदने की क्षमता कम होने के कारण यह "प्रॉफिटेबल" नहीं है। दूसरी ओर, सभी फील्ड में लग्ज़री इंडस्ट्री पूरी तरह से बिज़ी है, क्योंकि पहले कभी इतनी आसानी से दौलत नहीं कमाई गई थी।

---

[19] युद्ध के बाद जर्मनी में भी ऐसा ही एक कानून है, संविधान की सुरक्षा के लिए फेडरल लॉ। (बुंडेस्वेरफसंग्सचुट्ज़गेसेट्ज़), जो 1950 में पास हुआ था।

[20] मांग पूरी होने का मतलब है, किफ़ायती दामों पर ज़िंदगी की ज़रूरतों की पूर्ति। उन सभी का पूरा समूह जो एक राष्ट्रीय समुदाय में एक साथ बंधे हैं।

आज की तरह, वे खुद को सिर्फ़ लग्ज़री से घेरने के लिए बेताब हैं। लेकिन मुनाफ़े का कैपिटलिस्ट विचार असल में हमारी इकॉनमी की उन ब्रांच में एक इकॉनमिक बकवास बन जाता है जो आज हर चीज़ पर राज करती हैं, बैंकिंग और स्टॉक-एक्सचेंज सिस्टम में। बैंकों की रूलिंग पोजीशन का सच कैपिटलिस्ट विचार की इकॉनमिक बेवकूफ़ी को सबसे साफ़ तौर पर साबित करता है। बैंकों और स्टॉक-एक्सचेंज के "प्रोडक्शन" से अभी तक किसी बच्चे को खाना नहीं मिला है, अभी तक किसी ठंड से ठिठुरते इंसान को कपड़े नहीं मिले हैं, आम तौर पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी छोटी से छोटी ज़रूरत भी कभी पूरी नहीं हुई है। यह बात बिल्कुल भी कोई भड़काऊ नारा नहीं है, इसमें पैसे के लेन-देन के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी शामिल नहीं है, यह सिर्फ़ साफ़ तौर पर दिखाता है कि नेशनल सोशलिस्ट इच्छाओं जैसी डिमांड की असल में नेशनल इकॉनमिक पूर्ति और पूरी तरह से प्राइवेट-कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेड मुनाफ़े पर आधारित इकॉनमी के बीच कितना बड़ा फ़र्क है।

नेशनल सोशलिस्ट देश के भी अपने बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, लेकिन वे अब नेशनल इकॉनमी के रूलर नहीं होंगे, बल्कि उनके नौकर होंगे, पैसा अब देश और लोगों का मालिक नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ सामान के लेन-देन के लिए ज़रूरी मदद होगा।

हम ठीक-ठीक जानते हैं कि बैंक और स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल के खिलाफ यह लड़ाई नेशनल सोशलिस्ट आंदोलन के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई होगी, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी ताकत है, वह बैंक और स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल में ही जमा है।

यहाँ सत्ता के लिए ज़िंदगी और मौत की लड़ाई का सवाल है, यह बात विरोधी हमारे ज़्यादातर दोस्तों और फॉलोअर्स से बेहतर जानते हैं। यह लड़ाई इसलिए और भी मुश्किल होगी क्योंकि आबादी का पूरा हिस्सा अभी भी प्रॉफिट कमाने के पागलपन में फंसा हुआ है।

एक बुनियादी सवाल जिसका जवाब इस जगह पर एक बार फिर पूरी साफ़-साफ़ दिया जाना चाहिए, वह यह है कि प्रॉपर्टी के मामले में नेशनल सोशलिज़्म असल में कैसा है। पहले चैप्टर की बुनियादी बातों और खासकर मार्क्सिस्ट सोशलिज़्म के बताए गए बुनियादी विरोध से, नेशनल सोशलिज़्म के लिए प्रॉपर्टी की बुनियादी पहचान का नतीजा निकलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की यह पहचान आर्यन ज़िंदगी में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। क्रिएटिव दिमाग जो माहौल को पहचानता है, जो माहौल पर सोचता है ताकि उससे अपनी दुनिया बना सके, क्रिएटिव इंसान जो कड़ी मेहनत से धरती से उसके फल उगाता है, जो बस जाता है, अपने लिए घर और शहर बनाता है, जो अपने रिश्तेदारों, अपने नस्लीय साथियों के बीच बस जाता है और अपनी जड़ें जमा लेता है, वह इंसान जो फिर मिट्टी में बसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे बढ़कर ऊँचे कल्चर की ओर बढ़ता है और अपने लिए ऊँचे इंटेलेक्चुअल मतलब में, फिलॉसफी, पोएट्री, म्यूज़िक, आर्ट और स्कल्पचर के फील्ड में अपनी – अपनी – दुनिया बनाता है – यह इंसान निश्चित रूप से इसे इससे अलग तरीके से नहीं सोच सकता कि उसके हाथ के काम, जो उसके अपने हाथों से पैदा हुए हैं, वे भी उसकी प्रॉपर्टी हैं। क्रिएटिव इंसान के इस ज्ञान से सीधे तौर पर दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए सम्मान पैदा होता है, और कानून बनता है।

क्रिएटिव दिमाग के बिल्कुल उलट, दूसरे लोगों का लालची, चोर दिमाग होता है, जो अलग तरह से सोचते हैं, जिन्होंने कभी क्रिएशन की सांस नहीं ली, जो बेचैनी से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो कभी कहीं जड़ें नहीं जमा पाए, जो बड़े पैमाने पर नहीं उठे, और मिट्टी से, लंबे समय तक लगातार ऊंचे कल्चर की ओर नहीं बढ़े, बल्कि अपने बेचैन दिमाग और अपने पैसे से, एक देश से दूसरे देश घूमते रहे, जब उन्होंने अलग-अलग शहरों या ज़मीन के हिस्सों को "चारा" लिया था। क्रिएटिव देशों के खेतों में भी यहूदी असल में होने वाले प्रोडक्शन से काफी दूर थे, हम यहूदी को किसान के तौर पर नहीं जानते, न ट्रेडमैन के तौर पर, न इंजीनियर या मास्टर-बिल्डर के तौर पर, न फैक्ट्री और मज़दूर के तौर पर, और असली क्रिएटिव जीनियस उसके लिए फाइन आर्ट्स और साइंस में भी अजनबी है। चलता-फिरता दिमाग अपनी खास एक्टिविटी तभी शुरू करता है जब किसी क्रिएटिव हाथ से कोई काम बनाया गया हो, कोई चीज़ बनाई गई हो, वहीं लालची दिमाग इन चीज़ों को खरीदना जानता है।

खुद को और उन्हें अपने पैसे के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। देश की आर्थिक मांग को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्शन से कंजम्प्शन तक के इस ट्रैफिक से अपने लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसने खुद को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच खड़ा किया – ट्रेडर का जन्म हुआ। आज ट्रेडर और मनी-चेंजर, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और बैंकिंग लॉर्ड बन गए हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी को बहुत ही बेवकूफी भरे तरीके से उलट-पुलट कर दिया गया है। चालाक, इन्वेंटिव, डेयरिंग, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव दिमाग अब राज नहीं करता; टेढ़ा दिमाग, जो खुद कुछ भी नहीं बना सकता, शोषण करने वाला और लालची, राज करता है। पैसा काम और खून पर राज करता है।

यहूदी का चलता-फिरता दिमाग हर चीज़ को मोबाइल बना पाया है, यहाँ तक कि मॉर्टगेज के ज़रिए ज़मीन को भी, एनोनिमाइज़ेशन और स्टॉक कंपनी के ज़रिए सबसे बड़ी पुरानी इंडस्ट्रीज़ को भी, और, स्टेट बॉन्ड इकॉनमी के ज़रिए, इंटरनेशनल कैपिटल ने सरकारों को उनके लोगों से भी अलग कर दिया है। आज सभी सरकारें बड़े लोन कैपिटल पर निर्भर हैं और अपने लोगों के मामले में वे वॉल स्ट्रीट, सिटी ऑफ़ लंदन और पेरिस में अपने गुमनाम लॉर्ड्स के लिए सिर्फ़ ब्याज वसूलने वाली हैं।

इन छोटी बातों ने हमें क्रिएटिव लोगों और लालची यहूदी के बीच कभी न सुलझने वाले विरोध का सबसे गहरा राज़ दिखाया है। "आर्यन बनाता है, यहूदी दुनिया को अपने लिए हड़प लेता है।"

यहां यह भी संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी और कब्ज़े में बहुत बारीक अंतर होता है। कब्ज़ा ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी ही हो, कब्ज़ा खुद से नहीं बनाया जा सकता। कब्ज़े के मामले में कब्ज़े की शुरुआत पर सवाल नहीं उठाया जाता। यहूदी ने आर्य लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया है और अब अपनी फाइनेंशियल पावर से बनाने वालों पर राज करता है। कानूनी दावों, बॉन्ड, मॉर्गेज वगैरह के रूप में प्रॉपर्टी के इस अलग रूप ने आज पूरी दुनिया को ब्याज के ज़रिए कैपिटल के अधीन कर दिया है। ब्याज वाला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक रूप आम तौर पर कब्ज़े की कोई सीमा नहीं जानता, यह पूरे देशों को उनके सारे काम के साथ कुछ बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के बड़े लोगों के ब्याज के अधीन होने देता है।

इस डरावनी ब्याज-कैपिटलिस्टिक लुटेरी इकॉनमी के खिलाफ, नेशनल सोशलिज्म प्रॉपर्टी के अधिकार की लिमिट तय करता है। इस लिमिट का सिद्धांत इस वाक्य में है: "खुद के हित से पहले पब्लिक का हित"। इसके अलावा, प्रॉपर्टी की यह लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, यह इस बात से पता चलता है कि नेशनल सोशलिज्म किसी भी तरह से सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कामों को भी मना नहीं करेगा, जब तक वे बनाने वालों (हम क्रुप, मैनेसमैन, थिसेन, वगैरह के बारे में सोचते हैं) के प्राइवेट कब्ज़े में रहें, क्योंकि वे पूरे के हितों के खिलाफ हैं, खासकर तब जब इन बड़े कामों के मालिकों को सामाजिक सवालों की समझ हो और वे प्रोडक्शन से सही खुद के फायदे, बिक्री के लिए सही कीमत और नेशनल इकॉनमी की मांग को पूरा करने, और कामों से होने वाली कमाई में वर्कफोर्स की सही और सही हिस्सेदारी के बीच सही लिमिट ढूंढ सकें।

यहां हम प्रोडक्शन के बाहरी रूपों पर कुछ बुनियादी बातें बताने आए हैं।
युद्ध से पहले, तेज़ी से बढ़ती जर्मन इकॉनमी की पहचान बड़े, मीडियम और छोटे बिज़नेस के बहुत अच्छे मिक्सचर से थी। अब, आम तौर पर, बड़े बिज़नेस की तरफ झुकाव में नेशनल इकॉनमी के लिए एक खतरा है, क्योंकि बड़े बिज़नेस के ऊपर अगला कदम अब डिमांड पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट पर कब्ज़ा करने और कीमतों की तानाशाही के बड़े कैपिटलिस्ट हितों के लिए है। फिर भी, यह साफ़ तौर पर माना जाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ सिर्फ़ बड़े बिज़नेस के तौर पर ही काम कर सकती हैं। यह उन इंडस्ट्रियल ब्रांच पर लागू होता है जिन्हें हम आम तौर पर भारी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इस पॉइंट पर डिटेल में जाए बिना, यह कहा जा सकता है कि नेशनल सोशलिस्ट स्टेट के पास इकॉनमी के इन बाहरी रूपों में बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश करने का कोई कारण नहीं है। नेशनल सोशलिज़्म मार्क्सवादी मतलब में हर तरह के "सोशलाइज़ेशन या नेशनलाइज़ेशन" को मना करता है। हमारा इकॉनमिक आइडियल बड़े पैमाने पर मांग करता है।

मीडियम और छोटे बिज़नेस में आर्थिक रूप से आज़ाद लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि सिर्फ़ आज़ाद और स्वतंत्र लोग ही अपने काम और अपनी कमाई को आज़ादी से चला सकते हैं, उनमें अपने काम को लेकर ज़िम्मेदारी की गहरी भावना होती है, कि सिर्फ़ इसी ज़मीन पर ताकतवर लोग पैदा होते हैं और सिर्फ़ आज़ादी और ज़िम्मेदारी की ज़मीन पर ही समुदाय की भावना फलती-फूलती है जो आम काम से जुड़े लोगों को ज़िंदगी और किस्मत के समुदाय से जोड़ती है और इससे वे एक आज़ाद, जागरूक देश बनते हैं।

केवल ऐसी ज़मीन पर ही व्यक्ति की भलाई को पूरे कल्याण के साथ जोड़ा जा सकता है।

राज्य और अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर

जब इकॉनमी में दखल देते समय सरकार को किन सीमाओं का पालन करना चाहिए, यह तय करने की बात आती है, तो मैनचेस्टरिज़्म21 और स्टेट सोशलिज़्म एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। पहला सिद्धांत हर सरकारी रखवाली से जितनी हो सके उतनी आज़ादी की मांग करता है, यह तो राज्य को रात के पहरेदार की भूमिका में देखना पसंद करेगा। स्टेट सोशलिज़्म का मानना है कि ज़्यादातर बिज़नेस सबसे अच्छे तरीके से राज्य ही चलाता और मैनेज करता है। सोशलाइज़ेशन या नेशनलाइज़ेशन के सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम रूप, जो सभी के द्वारा बिज़नेस चलाने के लिए रूसी शब्द है, ने उन सभी को दिखाया है जिन्होंने सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट को बिना किसी भेदभाव के, पक्की सफाई के साथ देखा है, कि प्रोडक्शन के ऐसे कम्युनिस्ट तरीके लंबे समय में मुमकिन नहीं हैं।

जिसने भी इकॉनमी की बुनियाद के बारे में हमारी बातें समझी हैं, वह इस बात के अंदरूनी कारणों को आसानी से पहचान पाएगा। एक तरफ, बिज़नेस की पहल को दबाना, मुनाफ़े का मकसद न होना, कॉम्पिटिशन का खत्म होना, दूसरी तरफ काम करने की मजबूरी, जिसे सोवियत ने बेरहमी से लागू किया, उससे प्रोडक्शन का फ़ायदा कम से कम हो गया।

बिज़नेस पर "स्टेट-कंट्रोल" का धीरे-धीरे और हल्का तरीका, जैसा कि हम अपनी जर्मन इकॉनमिक ज़िंदगी से जानते हैं, उसे सिर्फ़ पब्लिक इकॉनमी के अलग-अलग फील्ड में ही फ़ायदे के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जिन फील्ड में फ्री इकॉनमी के साथ मुकाबला होता है, खासकर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (कोयला) के फील्ड में, फ्री इकॉनमी की तुलना में कमर्शियल सफलता बहुत कम होती है, जो सरकारी कंपनियों के मुकाबले सभी ज़रूरी फ़ैसले ज़्यादा तेज़ी से और आज़ादी से ले सकती है। यह सही अंदाज़ा लगाने के लिए कि आम तौर पर कौन से बिज़नेस स्टेट कंट्रोल के लिए सही हैं, हमें यह साफ़ होना चाहिए कि नेशनल इकॉनमी के पूरे ऑपरेशन में स्टेट की क्या भूमिका है।

हमने बताया है कि नेशनल सोशलिज़्म इकोनॉमिक्स का काम डिमांड को पूरा करने में देखता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर और यूज़र, हर इकोनॉमी में दो मुख्य हिस्सा लेने वाले होते हैं। अब हम जानते हैं कि इस्तेमाल, आखिर में, हमेशा और हर जगह पूरी तरह से पर्सनल होता है, या बहुत साफ तौर पर बताया जाता है: रोटी का हर टुकड़ा असल में सिर्फ एक ही इंसान खा सकता है, कपड़े भी सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए होते हैं, एक फिएट किसी भी समय सिर्फ एक छोटे, जुड़े हुए सर्कल को छत देता है, काम की जगह किसी भी समय सिर्फ शायद ज़्यादा लेकिन फिर भी लिमिटेड संख्या में काम करने वाले साथियों को ही जगह देती है, इसलिए हम प्रोडक्ट्स के कॉमन कंजम्प्शन या इस्तेमाल की बात बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए अगर कंजम्प्शन, आखिर में, पर्सनल है, तो यही बात प्रोडक्शन, सामान के प्रोडक्शन के बारे में भी सच है। प्रोडक्टिव काम का प्रोडक्ट जितना कीमती होता है, यह उतना ही साफ होता है कि यह सिर्फ एक बहुत ही पर्सनल क्रिएटिव ताकत से पैदा होता है।

साइंस और फाइन आर्ट्स के फील्ड में दिमाग के कामों के लिए, टेक्निकल इन्वेंशन और खोजों के फील्ड में यह बात तुरंत साफ हो जाती है, लेकिन यहां तक कि असेम्बल किए गए काम के मामले में भी।

21 मैनचेस्टरिज़्म आर्थिक सोच का एक स्कूल है जो 19वीं सदी में मैनचेस्टर में 1815 और 1846 के प्रोटेक्शनिस्ट कोरा कानूनों के खिलाफ़ एक रिएक्शन के तौर पर शुरू हुआ था। इसने फ्री ट्रेड की वकालत की और ज़मीनदार अमीर लोगों के खेती के हितों के खिलाफ़ उद्योगपतियों का साथ दिया। इस आंदोलन के मुख्य समर्थक रिचर्ड कोबडेन (1804-1865) और जॉन ब्राइट (1811-1889) थे।

फैक्ट्री जैसे काम, जिनमें मशीनों के ज़रिए मशीनीकरण लगभग पूरी तरह से इंसान के अकेले काम को दबा देता है, वहाँ यह बात आखिर में भी सही है कि जो जूते ठीक यही मज़दूर बनाता है, उन्हें सिर्फ़ यही मज़दूर बना सकता है, कोई और नहीं। लेकिन, बढ़ते मशीनीकरण के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरती जाती है। खेती के बिज़नेस में भी पुराना नियम लागू है: "भगवान की नज़र ही जानवरों को मोटा करती है", यानी, सिर्फ़ ब्रीडर की पर्सनल देखभाल से ही सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं।

कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था की सभी कोशिशें हर बार पूरी तरह से फेल हो गईं।
इसलिए हमें असल में यह कहना होगा कि कंजम्प्शन और प्रोडक्शन दोनों ही सोशलाइज़ेशन के खिलाफ़ हैं। अब, जैसे ही इंसान ने परिवार में अलग-अलग इकॉनमी के असली इकॉनमिक तरीकों को छोड़ दिया और लेबर के बँटवारे के ज़रिए ज़्यादा मुश्किल इकॉनमिक तरीकों की ओर बढ़ गया और बड़े स्टेट कम्युनिटी बना लिए, प्रोडक्शन और कंजम्प्शन के बीच कुछ नया दखल देने लगा — ट्रेड और कॉमर्स और फाइनेंशियल सिस्टम।

यह बहुत ही सीधी-सादी इकोनॉमिक फिलॉसफी हमें उन फील्ड्स का सबसे साफ सबूत देती है जिनमें सरकार को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिमिट करना होता है। यह सच में तुरंत साफ हो जाता है कि यह उन मामलों का सवाल है जिनमें हर इंसान की बराबर दिलचस्पी है। और यह लॉजिकल है कि यहां सरकार को अपने कामों का दायरा आम हितों के रूप में मिलेगा।

अगर हमारी इकॉनमिक सोच सही है, तो अगर सरकार ने पहले भी इनमें से किसी एक फील्ड में हाथ आज़माया है, तो उसने ज़रूर कुछ बहुत अच्छा किया होगा। ट्रांसपोर्ट के फील्ड में भी उसने ऐसा ही किया है। युद्ध से पहले जर्मन रेलवे अधिकारियों का काम बहुत अच्छा था, और आज भी वैसा ही है, क्योंकि पुरानी ड्यूटी और ईमानदारी अभी भी कायम है। अमेरिका में नॉन-स्टेट रेलवे सिस्टम को भी अक्सर खास परफेक्शन का क्रेडिट दिया जाता है; यह एक खास मामले में सही भी है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आसानी से होता है, और कई छोटी-मोटी मुश्किलें जो हमारे यहां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ी हैं, उनसे शायद ही बचा जा सकता था। अमेरिका में बड़े साइज़ के लोकोमोटिव बनाने पर भी पहले हम हैरान थे, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि अमेरिकी रेलवे नेटवर्क के बड़े गेज ने इसे टेक्निकली ज़्यादा आसानी से मुमकिन बना दिया था। लेकिन यह ट्रांसपोर्ट का पहलू नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल बात है जो हमारे ऑब्ज़र्वेशन के दायरे में नहीं आती। दूसरी ओर, हमारे सवाल के लिए इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है - रेलवे में ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी। इस फील्ड में जर्मन रेलवे को सरकारी ट्रांसपोर्ट के इस सबसे बड़े काम के बारे में हमेशा पता था और वह टेक्निकली और ऑर्गनाइज़ेशनली वह सब कुछ करने का नाम भी ले सकता है जो मुमकिन था। इस फील्ड में, ठीक अमेरिकन और फ्रेंच रेलवे में, यात्रियों की जान को किस गैर-ज़िम्मेदाराना लापरवाही से खतरे में डाला गया, यह नेशनलाइज़ेशन से पहले अमेरिकन रेलवे और फ्रेंच रेलवे पर हुए रेल हादसों के इतिहास से पता चलता है, जब तक कि ये पेरिस रोथ्सचाइल्ड्स के बेपरवाह मुनाफ़े के पीछे भागने का काम करते थे। – इसलिए यहाँ भी हम एक बार फिर मुनाफ़े के कैपिटलिस्टिक विचार और डिमांड पूरी करने वाली इकॉनमी के ड्यूटी के विचार के बीच बुनियादी विरोध देखते हैं।

कॉमर्स का काम, सबसे पहले, सामान और लोगों को इस्तेमाल या काम की जगहों पर सुरक्षित, तेज़ और सस्ते ट्रांसफर के ज़रिए नेशनल इकॉनमी की सेवा करना है। किसी सरकारी कंपनी में मुनाफ़े का सवाल दूसरे नंबर पर आता है, या यह सिर्फ़ टैरिफ़ पॉलिसी का सवाल है। पोस्ट और टेलीग्राफ़ सिस्टम भी स्वाभाविक रूप से कॉमर्स से जुड़ा है। यहाँ भी, यह दिखाने के लिए कि सरकार ने यह ज़रूरी नेशनल इकॉनमिक काम कितनी सुरक्षित, तेज़ी और भरोसे के साथ पूरा किया, सिर्फ़ जर्मन पोस्ट और टेलीग्राफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कामों की सम्मानजनक याद की ज़रूरत है।

दूसरी तरफ, ट्रेड को हमेशा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरियल पहल का खास काम माना जाता रहा है। अब, ट्रेड के बारे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना साफ-साफ नहीं कहा जा सकता। स्टेट रेगुलेशन के लिए शुरू से ही सिर्फ एक खास तरह के सामान, असल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सामान पर ही ध्यान दिया जाता है। युद्ध से पहले सबसे ज़रूरी खाने की चीज़ों के ट्रेड पर स्टेट रेगुलेशन की जितनी कम समझ की उम्मीद की जा सकती थी – क्योंकि फ्री ट्रेड डॉक्ट्रिन हमारे देश की आर्थिक सोच पर राज करता था – उतनी ही कम उम्मीद आज भी की जा सकती है, युद्ध के बाद के उस समय में सबसे ज़रूरी खाने की चीज़ों में बेशर्म सूदखोरी को देखते हुए, जिसे भुलाया नहीं गया है, कि यह विचार कि सबसे ज़रूरी खाने की चीज़ों को तैयार करने, ट्रांसफर करने और बांटने का इंतज़ाम करना स्टेट का काम है, सही साबित होगा। खास तौर पर हम देखते हैं, यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे विरोधी बोल्शेविस्टों में भी, इस समस्या को हल करने की कोशिशें, यानी प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टेट कंट्रोल के ज़रिए। जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, इसमें जो गलत है, वह है प्रोडक्शन को हमेशा स्टेट-कंट्रोल्ड तरीके से करना या समझना। दूसरी तरफ, प्रोडक्शन का सही डिस्ट्रीब्यूशन बेशक एक बहुत ज़रूरी सरकारी काम है। यह बात ध्यान देने वाली है कि रूस में सिर्फ़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और कंज्यूमर कोऑपरेटिव ही बचे रह गए, यानी, दूसरे शब्दों में, वे ऐसे संगठन थे जिन्होंने आम हित में सबसे ज़रूरी खाने के प्रोडक्ट्स को स्टोर करने और इकट्ठा करने का काम तय किया था और दूसरी तरफ, आम हित में कंज्यूमर को सप्लाई करने का काम किया था।

आर्थिक ज़िंदगी अब हमें दिखाती है कि हमारे बीच भी यह आइडिया पूरी तरह से नया नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव आइडिया हर जगह तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है और इसके साथ ही वे पहले से बनी शर्तें बना रहा है जो नेशनल सोशलिज़्म के मन में इस बहुत ज़रूरी सवाल को रेगुलेट करने के लिए हैं। खेती के प्रोडक्ट्स का कोऑपरेटिव इस्तेमाल, एक तरफ तो किसान को उसके प्रोडक्ट्स सही दामों पर मिलना पक्का करता है, यह फर्टिलाइज़र, खेती के औज़ार वगैरह की कोऑपरेटिव खरीद पक्का करता है, और यह खास तौर पर खेती के गोदाम बनाकर डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ, कंज्यूमर यूनियनों ने अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स को जितना हो सके सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं और सबसे बढ़कर बिचौलिए के व्यापार को दबाया है। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव का सरकारी निगरानी में मिलना इस सवाल को हल करने के लिए तय है।

यहां भी सवाल का सार एक बार फिर यही है: प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि डिमांड को पूरा करना इकॉनमी का पहला काम है।

ट्रेड के लिए, खासकर उन सभी फील्ड्स में जहाँ रिस्क का पर्सनल फैक्टर सवाल में आता है, उसमें काफी कुछ बचा रहता है। एक फूड प्रोडक्ट के लिए जो हमेशा सिक्योर रहता है, और सेल्स के सभी हालात में, बिजनेसमैन की पहचान बताने वाले फैक्टर्स शुरू से ही खत्म हो जाते हैं।

फाइनेंशियल सिस्टम तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे स्टेट रेगुलेशन के तहत लाया जाना है। कई फाइनेंशियल थ्योरिस्ट पैसे को प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज के तरीके के तौर पर समझाते हैं; यह एक्सप्लेनेशन सच में गलत नहीं है, लेकिन पूरी और साफ़ भी नहीं है। फिर भी, यह डेफिनिशन सही एहसास दिखाती है कि पैसा सामान के ट्रैफिक में मदद करता है। यह बात कि स्टेट खुद के लिए सिक्के बनाने का खास अधिकार मांगता है, यह पहले ही साबित कर देता है कि स्टेट पैसे को पब्लिक लाइफ का एक खास ज़रूरी हिस्सा मानता है। यह बात कि स्टेट ने पीनल कोड में नकली नोटों से निपटने वाले सेक्शन की एक पूरी सीरीज़ बनाई है, इसी तरह यह भी साबित करता है कि यह सबसे ज़रूरी पब्लिक मामला है। असल में, स्टेट ने लंबे समय से अपनी अथॉरिटी से यह भी तय किया है कि पब्लिक में पैसे के तौर पर क्या वैलिड होगा।

कॉमर्स। फाइनेंशियल थ्योरिटिशियन – चार्टलिस्ट22 – का एक खास झुकाव पैसे की स्टेट थ्योरी को दिखाता है, जो सीधे तौर पर कहता है: "पैसा वह है जिसे स्टेट पैसा घोषित करता है"। इसके साथ ही पैसा, पैसे के असल रूप से पूरी तरह अलग हो जाता है, और स्टेट सॉवरेनिटी की मुहर लोहे, एल्युमिनियम, पोर्सिलेन और सबसे बढ़कर, कागज़ से "पैसा" बनाने के लिए काफी है। आज हमें सिखाता है कि यह थ्योरी असल में हकीकत बन गई है। इन फाइनेंशियल थ्योरिटिशियन के विरोधी – मेटलिस्ट23 – इस पुराने विचार से चिपके रहते हैं कि पैसे की एक अंदरूनी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए यह कीमती मेटल (सोना और चांदी) से बना होना चाहिए। आज के रिश्ते इस झुकाव को सही नहीं ठहराते, क्योंकि असल में, स्टेट कागज़ से भी पैसा बनाता है, और असल में ऐसा पैसा जिससे कोई सच में कुछ खरीद सकता है, तब भी जब बैंक नोट बिल्कुल बेकार कागज़ से बने हों। लेकिन इस पैसे की परचेज़िंग पावर का सवाल एक अलग कहानी है। यहाँ पैसे की घटती परचेज़िंग पावर, जो बढ़ते हुए पेपर मनी के उलटे अनुपात में है, मेटलिस्ट्स को सही साबित करती है, क्योंकि असल में सोने और चाँदी के सिक्कों ने पेपर मनी की परचेज़िंग पावर को कम नहीं किया है। लेकिन यह एक और वजह से है, यानी गोल्ड मनी के कमोडिटी कैरेक्टर के कारण। गोल्ड मनी असली सोना होने की वजह से अपनी परचेज़िंग पावर नहीं बनाए रखता, बल्कि इसलिए क्योंकि गोल्ड मनी भी एक कमोडिटी है। आज बीस मार्क का सिक्का अपनी परचेज़िंग पावर स्टेट करेंसी के स्टैम्प्ड साइन '20 मार्क्स' से बिल्कुल नहीं, बल्कि रिफाइंड गोल्ड की कमोडिटी के कंटेंट से लेता है। लेकिन हम यहाँ इन फाइनेंशियल थ्योरेटिकल विवादित सवालों पर ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, हमें नेशनल सोशलिस्ट रिफॉर्म के तर्क के अनुसार स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन में इन सवालों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करनी होगी। यहां यह मानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सिस्टम, इस समय राज्य और अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बारे में हमारे सामने जो सवाल है, उसमें किसी भी हाल में उन क्षेत्रों से जुड़ा है जो पूरी आर्थिक ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी मामला है, ठीक वैसे ही जैसे सबसे ज़रूरी खाने की चीज़ों में कॉमर्स और व्यापार, निश्चित रूप से राज्य की तरफ से सबसे ज़्यादा सावधानी से भरोसेमंद रेगुलेशन के अधीन होना चाहिए।

आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम की अहमियत को किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं है।
बड़ी फाइनेंशियल ताकतों की ताकत हर चीज़ पर राज करती है, यह हर उस इंसान के सामने साफ़ दिखता है जो इसे देखना चाहता है। समझदार इंसान ने बहुत पहले ही यह पहचान लिया है कि फाइनेंशियल सिस्टम के मामले में सरकार ने जिस नाकाबिल और झूठे तरीके से खुद को दिखाया है, वही आज सरकारी फाइनेंस की खराब हालत की असली वजह है। यह बात कि ज़्यादातर तथाकथित सरकारी सेंट्रल बैंक पूरी तरह से सरकारी संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि स्टॉक कंपनियाँ हैं जिनमें सरकारों ने अपने लिए सिर्फ़ कुछ सुपरवाइज़री अधिकार रखे हैं, इससे पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम के उलझे हुए हालात का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है।

राष्ट्रीय राजनीतिक नींव

बिना पावर के कोई राज्य नहीं और बिना अधिकार के कोई सरकार नहीं। इससे ज़्यादा साफ़ और कॉमन सेंस के लिए तुरंत साफ़ कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी हलकों में हममें से कोई आज भी यह मानता है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर की पूरी कमी के बावजूद कोई राज कर सकता है, तो इसे हमारी पब्लिक सोच की पूरी तरह से अनदेखी मानना होगा।

बिना पावर के साधन के पावर के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता; पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर के साधन एक-दूसरे को वैसे ही जोड़ते हैं जैसे इकॉनमी और नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता। खोई हुई पावर वापस पाने के लिए, मिलिट्री पावर का साधन बनाना ही एकमात्र तरीका है।

22 चार्टलिस्ट नेशनल करेंसी के तौर पर फिएट मनी या सरकार द्वारा जारी टोकन (लैटिन: चार्टा) के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं।
23 मेटलिस्ट मानते हैं कि पैसे की वैल्यू कीमती मेटल से आती है और वे फिएट मनी का विरोध करते हैं क्योंकि उसकी कोई अंदरूनी वैल्यू नहीं होती।

हमारी बेचारी मातृभूमि को कितनी भयानक सज़ा मिली है क्योंकि उसने पावर का विचार छोड़ दिया है और खुद को उस शांतिवादी दिखावे के हवाले कर दिया है जिसे हम अब हर दिन और हर घंटे महसूस करते हैं। "और भी बुरी हालत को रोकने के लिए" हमने खुद सरेंडर कर दिया है और अपने हथियार नष्ट कर दिए हैं, "और भी बुरी हालत को रोकने के लिए" हमने वर्साय के हुक्म पर साइन किए हैं, "और भी बुरी हालत को रोकने के लिए" बर्लिन सरकार ने हमसे जो भी मांगा गया था, उसके लिए हाँ और आमीन कहा है, "और भी बुरी हालत को रोकने के लिए" हमने अपने खिलाफ हर बुराई, हर बेइज्जती, हर शोषण को होने दिया है। कायरता और नीचता के इस बेशर्म नारे से जर्मन लोगों को और भी गहरी मुसीबत में धकेल दिया गया है। हमसे जो मांगा गया था, हमने उसे पूरा किया, और

एक जर्मन मंत्री, डॉ. राथेनौ24, ने सबके सामने यह कहने की हिम्मत की: कोई भी काम पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाबी नहीं है, बस बात यह है कि लोगों को कितनी गहरी मुश्किल में पड़ने दिया जा सकता है! इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है - हालांकि राथेनौ के शब्द पहले से ही काफी साफ हैं: जर्मन देश पूरी तरह से बेबस है, यह राजनीतिक रूप से पूरी तरह से बेबस है, दिमागी तौर पर यह लगभग बेबस हो गया है, यह बस काम करता रह सकता है। इसने खुद पर इतने बड़े गुनाह के बोझ को लाद लिया है कि चुने हुए लोगों के सदस्य, इन हर्जानों पर, जर्मन काम की कीमत पर दुनिया के सभी देशों में हमेशा के लिए बिना काम के एक शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अब यह खतरा है कि जर्मनों की बहुत बड़ी वर्कफोर्स भी इस बहुत बड़े बोझ के नीचे टूट सकती है। इसलिए जर्मनों को लगातार स्टिमुलेंट्स के ज़रिए ज़िंदा रखना होगा और ठीक इसी तरह उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस कैपेसिटी की लिमिट पर बनाए रखना होगा ताकि वे हमेशा इस धोखे वाली उम्मीद में पूरी ताकत लगाकर काम कर सकें कि वे एक दिन अपने बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। "यह सिर्फ़ इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को कितनी गहरी परेशानी में पड़ने दिया जा सकता है!" यह मंत्री राथेनौ की राजनीतिक भावना थी, जिसे सभी रिपब्लिकन बहुत पसंद करते थे।

अगर हमने आज के जर्मन राज के इस तरीके को याद किया है, तो यह सिर्फ़ इस डरावने उदाहरण को पक्का करने के लिए था जो हमारे इतने करीब है कि एक बिना हथियार वाला देश, जिसे बस सब कुछ, यहाँ तक कि हर मज़ाक भी सहना पड़ता है। इसके खिलाफ़, हमारे लिए एक बाहरी ताकतवर देश में विश्वास सही है, जो अकेले शांति और आज़ादी की गारंटी दे सकता है। हम ऐतिहासिक कारणों को नज़रअंदाज़ करते हैं, यह किसी मैनिफेस्टो का काम नहीं है, बल्कि इतिहासकार का मामला है।

बाहर से चलने वाली पावर पॉलिटिक्स के आइडिया का दूसरा रूप अंदर से चलने वाला सख्त संवैधानिक राज्य है। हम बिस्मार्क के पावर स्टेट में इस आइडियल हालत के काफी करीब आ गए थे, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम और प्राइवेट प्रॉपर्टी की अनलिमिटेड पहचान और उससे मिलने वाली मांगों से जुड़े फील्ड में हमारे कानूनी आइडिया पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक आइडिया के नीचे थे।

इस बात पर खास ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अंदरूनी राजनीति के मामले में नेशनल सोशलिज़्म बिना किसी शर्त के कानून के नज़रिए पर खड़ा है, जहाँ तक कानून के सामने हर कोई बराबर होना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी बदलाव ज़रूर होना चाहिए।

कानून के मूल विचार के संबंध में महसूस किया जा सकता है जो जर्मनों के लिए एक आंतरिक आवश्यकता, समग्र के उच्च हितों के लिए एक स्वैच्छिक अधीनता को दर्शाता है, जबकि आज हमारे बीच मान्य कानून के नुस्खे केवल शक्ति के आदेश के रूप में दिखाई देते हैं और वास्तव में एक ऐसी शक्ति के आदेश के रूप में दिखाई देते हैं जो समग्र की सेवा में नहीं है, बल्कि संपत्ति के प्रश्नों के संबंध में, सुरक्षा से पहले संपत्ति की सुरक्षा को रखा है।

---

24 वाल्थर राथेनौ (1867-1922) एक यहूदी उद्योगपति और राजनेता थे, जिन्होंने 1922 में पुनर्निर्माण मंत्री और 1922 में विदेश मंत्री के तौर पर काम किया। उनके इस आग्रह ने कि जर्मनी को वर्साय की संधि के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, जर्मन राष्ट्रवादियों की दुश्मनी को भड़का दिया और जून 1922 में उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या पर वाइमर सरकार की प्रतिक्रिया जुलाई 1922 में रिपब्लिकशूट्ज़गेसेट्ज़ (गणतंत्र की सुरक्षा के लिए कानून) को लागू करना था, जिसका ज़िक्र फेडर अक्सर करते हैं।

व्यक्ति का। पब्लिक लॉ के नए ऑर्डर के सवाल पर दूसरे सेक्शन में और ज़्यादा डिटेल में बात करनी होगी।

अब हम थोड़े समय के लिए बाहरी राज्य के रूप के सवालों पर आते हैं। इस सवाल पर आखिरी फैसला किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं है। इसे आम तौर पर हमारे अंदरूनी राजनीतिक हालात की एक बेसिक सफाई के बाद ही हल किया जा सकता है। हमें लगता है कि इस अंदरूनी राजनीतिक सफाई का एकमात्र मुमकिन तरीका सिर्फ़ एक तानाशाही है जो पूरे पक्के इरादे से हमारे देश में सड़न और बीमारी के सोर्स को काटकर जला दे।

ऐसे लीडर से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं; अपने लोगों के लिए गहरा प्यार, पक्की इच्छाशक्ति, अपने सभी फैसलों में लगभग सोते-जागते पक्का यकीन ही उसे अलग पहचान दिलाएगा। यह तो साफ़ है कि उसकी दिमागी काबिलियत औसत से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग फील्ड में ज्ञान और काबिलियत ही सब कुछ तय नहीं करती। ज्ञान और सीख दूसरों को भी मिल सकती है - कितने ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, सोच साफ़ है, ज़बरदस्त समझ है, बेहतरीन कला का टैलेंट है - लेकिन अगर उनमें आखिरी चीज़ की कमी है, वह है गहरा इरादा, पक्का इरादा, जो गहरी नैतिक गंभीरता पर आधारित हो, तो वे कभी भी देशों के लीडर के तौर पर, आगे बढ़कर नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्राइस्ट और लूथर, सवोनारोला25 और मोहम्मद जैसे धार्मिक जीनियस, बिस्मार्क और क्रॉमवेल जैसे नेताओं, फ्रेडरिक द ग्रेट और योर्क26 जैसे जनरलों वगैरह के बारे में सोचते हैं । तानाशाह को सभी फालतू पाबंदियों और हिचकिचाहटों से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास वही बनाता है और जब उसका समय आता है तो वह हिम्मत और पक्के इरादे से उसे पकड़ लेता है, वह देश की चाहत का प्रतीक होता है, और इसलिए वह कभी गलती नहीं करता और उन लोगों के कट्टर प्यार से जीता है जिन्हें उसका काम आज़ादी दिलाता है। उसे अपने लोगों और अपने पवित्र काम से उतनी ही मज़बूती और बेरहमी से नफ़रत करने में काबिल होना चाहिए, जितनी वह अपने लोगों से और अपने पवित्र काम से प्यार करता है। अपने असिस्टेंट और साथियों के मामले में वह आज़ाद और बराबर लोगों में सबसे पहले आता है।

यह पुराना जर्मन विचार लीडर और लीडर के बीच इस मज़बूत रिश्ते की नींव रखता है।
और अपने दोस्तों के साथ इस मकसद के लिए।

वह लीडर हैं क्योंकि उन्होंने खुद को साबित किया है, और जब तक वह खुद को साबित करते रहेंगे।

ऐसा लगता है कि उसकी मौजूदगी से हर शक्ति दोगुनी हो जाती है
वह हर छिपी हुई ऊर्जा को बाहर निकालता है,
हर एक को अपना अनोखा टैलेंट दिखाते हुए,
फिर भी सबको वैसा ही छोड़ दिया जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है,
और बस यही देखते रहते हैं कि वे और कुछ न हों
सही जगह और समय पर।

(शिलर, वॉलेनस्टीन)27

वह खुद को लेकर सख्त और कठोर है, वह अपने ही नियमों के हिसाब से खुद को चलाता है। उसके पास सबके लिए समय है और वह सबकी सुनता है, लेकिन वह ज़रूरी और गैर-ज़रूरी चीज़ों में फर्क करने में भी माहिर है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह डरता नहीं है।

---

25 गिरोलामो सवोनारोला (1452-1498) एक डोमिनिकन फ्रायर थे जिन्होंने सरकार और पादरी वर्ग के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार किया और भविष्यवाणी की कि अगर फ्लोरेंस अपनी नैतिक बुराइयों को सुधार ले तो वह एक शक्तिशाली न्यू जेरूसलम बन जाएगा।
फ्रांस के खिलाफ पोप अलेक्जेंडर VI के पवित्र लीग का समर्थन करने के कारण 1497 में उन्हें समाज से निकाल दिया गया और उसके बाद फांसी दे दी गई।
वर्ष।

[26] लुडविग ग्राफ योर्क वॉन वार्टनबर्ग (1759-1830) एक प्रशियाई फील्ड मार्शल थे, जिन्होंने 1812 में रूस पर नेपोलियन के हमले के दौरान प्रशियाई जनरल जूलियस वॉन ग्रेवर्ट के फ्रांसीसियों के साथ सहयोग का विरोध किया था और इस तरह नेपोलियन के खिलाफ छठे गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसका अंत 1814 में नेपोलियन के एल्बा देश निकाला के साथ हुआ।

27 फ्रेडरिक शिलर, डाई पिकोलोमिनी, उनकी वॉलेनस्टीन ट्रिलॉजी (1799) का पहला नाटक। इसका अनुवाद सैमुअल टेलर कोलरिज ने किया है।

खून और युद्ध के बाद, वह तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक उसका लक्ष्य पूरा न हो जाए, फिर वह अपनी रचना को जितना हो सके उतना सुरक्षित करता है, लेकिन वह खुद पीछे हट सकता है, जैसा कि तानाशाह सुल्ला ने किया था, और इस तरह अपने काम को दो तरह से सुरक्षित करता है, जिसमें वह दूर से काम करता है लेकिन फिर भी अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से हर चीज़ को असाधारण स्टैंडर्ड से मापने के लिए मजबूर नहीं करता; दूसरी ओर, अगर टाइटन लगातार राजनीतिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तय नहीं करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से लीडर बना रहता है, तो एक ज़्यादा आज़ाद और स्वतंत्र फ़ॉलोइंग डेवलप हो पाएगी। ऐसे काम की चमक उस तानाशाह को अलग पहचान देगी जो जर्मनी को फिर से ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर तब एक असाधारण लीडर की कामयाबी से कीचड़ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जीवन के लिए अंदरूनी और बाहरी शर्तें फिर से मिल जाएंगी, तो देश एक बार फिर राज्य के बाहरी रूप के बारे में फैसला कर सकता है।

भविष्य के राज्य के रूप के बारे में हमारा नज़रिया मुख्य रूप से इस बात से प्रभावित होगा कि सार्वजनिक जीवन के कुछ रूप, खासकर मताधिकार और उससे मिलने वाला लोकप्रिय प्रतिनिधित्व, कैसे बनाए जाएंगे। हम निश्चित रूप से एक स्वस्थ रिपब्लिकन राज्य के रूप की संभावना के बारे में सोच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन रोम में था। असल में, जर्मनी की लगभग सभी ऐतिहासिक यादें राजशाही राज्य के रूप की ओर इशारा करती हैं। अब, राजशाही राज्य के रूप के साथ वंशवाद का विचार किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा लगता है कि अक्सर वंशवाद के हित देशों के नुकसान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। एक और बात हमें राजशाही राज्य के रूप के संभावित दोबारा आने के सवाल में बहुत सावधान रहने की सलाह देती है - वंशों के बीच विरासत का नतीजा। जर्मन लोगों के दर्दनाक इतिहास में बार-बार यह देखा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण शासक के बाद तीसरी पीढ़ी ने अपने पुरखों की विरासत को बर्बाद कर दिया है, देश के सम्मान और योग्यता को नुकसान पहुंचाया है, साम्राज्य की ताकत की स्थिति खो दी है, और नागरिकों की शांति और भलाई को नष्ट कर दिया है। जब कोई जर्मन राजा के फ़ायदों की बात करता है, खासकर खानदानी राजघराने के तहत, तो वह हमेशा उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें इतिहास ने "महान" का नाम दिया है। हम चार्ल्स द ग्रेट, ओटो द ग्रेट28, फ्रेडरिक द ग्रेट29 और उन कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें इन असली शासकों के बराबर माना जाता है; लेकिन यह नाकाबिलियत, आलस, मतलबीपन, फ़िज़ूलखर्ची, कल्पना, लोगों से दूरी, और दूसरी खतरनाक आदतों की बस एक पल की याद है जो लुई द पियस30, ओटो III31, वेंसस्लॉस32, चार्ल्स VI33 के नामों से जुड़ी हैं।

,

[28] शारलेमेन (लगभग 742-814) 768 में फ़्रैंक्स के राजा बने और उन्होंने अपना शासन फ्रांसिया से आगे कैरोलिंगियन साम्राज्य तक बढ़ाया।
एक ऐसा साम्राज्य जिसमें पश्चिमी यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा शामिल था।

29 ओटो द ग्रेट (912-973) सैक्सनी के ड्यूक थे जो 936 में जर्मनों के राजा बने, 955 में मैग्यार को हराया और 961 में इटली के राज्य पर जीत हासिल की। 962 में उन्हें पोप जॉन XII ने सम्राट का ताज पहनाया और उन्होंने रोम से पवित्र रोमन सम्राट के रूप में राज किया।

30 लुई ले पियू (778-840) शारलेमेन के बेटे थे, जिनके साथ उन्होंने 813 से को-एम्परर के तौर पर राज किया। 817 में उन्होंने अपना एम्पायर अपने तीन बेटों और अपने भतीजे बर्नार्ड के बीच बाँट दिया, जो इटली के राजा के तौर पर राज करता था। हालाँकि, बर्नार्ड ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत की और उसे अंधा करने की सज़ा दी गई, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। लुई ने अपनी क्रूरता के लिए सबके सामने प्रायश्चित किया और इस तरह एक शासक के तौर पर अपनी बहुत सारी इज़्ज़त खो दी। उनके बाकी राज के दौरान फ्रैंकिश एम्पायर में सिविल वॉर हुए।

[31] ओटो III (980-1002) 996 से पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक थे और अपने राज में उन्हें स्लाविक लोगों से बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें एल्बे के पूरब में शाही इलाकों को छोड़ना पड़ा, हालांकि फिर भी वह पोलैंड और हंगरी में ईसाई धर्म का असर मज़बूत करने में कामयाब रहे।

[32] प्रीमिस्लिड राजवंश के वाक्लाव I (लगभग 907-935) 921 से बोहेमिया के ड्यूक थे। 929 में, बोहेमिया पर पूर्वी फ्रैंकिश राजा, हेनरी द फाउलर ने हमला किया और उन्हें फाउलर को फिर से कर देना पड़ा। वाक्लाव की हत्या उनके भाई बोल्स्लाव के साथ मिलकर अमीरों के एक ग्रुप ने कर दी, जो बोहेमिया के अगले ड्यूक बने।

33 चार्ल्स VI (1368-1422) को 'ले बिएन-एमे' (प्यारा) और 'ले फ़ू' (पागल) दोनों कहा जाता था। उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और उनके राज में तथाकथित सौ साल के युद्ध के लगातार झगड़े होते रहे। बरगंडी के साथ चार्ल्स के चल रहे झगड़े का फायदा इंग्लैंड के हेनरी V ने उठाया, जिन्होंने 1415 में एगिनकोर्ट की लड़ाई में फ़्रांसीसियों को हराया।

1420 में साइन की गई ट्रॉयेस की संधि के तहत, हेनरी को चार्ल्स VI की बेटी कैथरीन से शादी करने के साथ-साथ फ्रांस की गद्दी का उत्तराधिकार भी दिया गया।

फ्रेडरिक विल्हेम III34, विल्हेम II35 यह साफ तौर पर पहचानने के लिए काफी हैं कि वंशवादी राज्य किसी भी तरह से देश की भलाई की गारंटी नहीं देता है।

जर्मन लोगों का राजशाही की तरफ झुकाव दिखाने वाली बात यह है कि उन्हें एक लीडर की ज़रूरत होती है, और वे खुद को एक लीडर के अधीन करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक यही आखिरी खासियत शायद जर्मन लोगों की एक खास खासियत है, हम जर्मन कैरेक्टर की इस खासियत को उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं में अच्छी तरह जानते हैं। मरते दम तक वफ़ादारी ने उन्हें सबसे बड़ी जीतों के लिए लड़ने और जीतने दिया, इसने उन्हें विदेशी झंडों का भी पालन करने दिया; लेकिन इसमें कमज़ोर लोगों में आज़ादी की बहुत कमी भी शामिल है, यहाँ तक कि वे बेकार और गुलामी की हद तक पहुँच जाते हैं, विदेशी चीज़ों से प्यार करते हैं और समझदारी की कमी होती है।

इसलिए, उत्तराधिकार से जुड़ा सवाल जर्मनी में ही हल करना मुश्किल नहीं है।
इससे भी ज़्यादा मुश्किल सवाल लीडर की समस्या में है।

अब तक लीडर का चुनाव लगभग हमेशा किस्मत पर छोड़ दिया गया है।
शाही शादी असल में किसी भी तरह से दिमागी ताकत और उन ज़रूरी खासियतों की गारंटी नहीं है जो एक राजा से हर हाल में मांगी जाती हैं। और अगर हम आज की जर्मन इकॉनमी को याद करें, जहाँ सिर्फ़ पार्टी की मेंबरशिप ही सबसे ऊँचे सरकारी पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन तय करती है, तो हमें इस सवाल पर खास ध्यान देना चाहिए।

वैसे भी, मुश्किल उस इंसान के नैतिक और चारित्रिक गुणों को बचाने में है जिसके हाथों में लोगों की किस्मत होनी चाहिए। हालांकि एक तानाशाह देश की चाहत को आगे बढ़ाने वाले के तौर पर खुद से लीडरशिप अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन भविष्य का लीडर असल में देश की सोची-समझी इच्छा से सबसे अच्छा और सबसे सही बनकर उभरना चाहिए।

इस तरह यह पूरी तरह से खुला रह सकता है कि सबसे बड़ी कीमत एक ही व्यक्ति में होनी चाहिए या राज्य का नेतृत्व दो या उससे ज़्यादा लोगों का होना चाहिए। किसी भी मामले में, हमारे लिए एक बात पक्की है, कि जिसे राज्य के सबसे बड़े मामलों का नेतृत्व सौंपा गया है, चाहे वह ताज पहनाया गया प्रमुख हो या कॉन्सुलर ड्यूमर या तिकड़ी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, सबसे अच्छे मामले में, संविधान में होगी। इसलिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय राजनीतिक बुनियाद होगी जो नेशनल सोशलिस्ट राज्य को पिछले शासन के तरीकों से अलग करेगी।

नेशनल सोशलिस्ट राज्य की नेशनल पॉलिटिकल बुनियाद का एक खास पहलू एक ऐसे नेशनलिस्ट राज्य की मांग है जिसमें दूसरे देशों और जातियों के लोगों को राज्य के मामलों की लीडरशिप और सरकारी पद संभालने से बाहर रखा जाता है।

पूरे जर्मन इतिहास का सबसे बड़ा सबक इस बात में बताया जा सकता है कि जर्मनी हमेशा गरीब, कमज़ोर और दुखी रहा जब उसके शासकों ने विदेशी हितों का पीछा किया और जब अलग-अलग प्रांतों और शहरों की छोटी-छोटी चिंताओं को राइख के आम मामलों से ऊपर रखा गया; और इसी तरह जर्मनी हमेशा मज़बूत और ताकतवर रहा जब वह एकजुट था और उसके शासक जर्मन तरीके से सोचते और महसूस करते थे और प्रांतों और शहरों को महान आम पितृभूमि का सदस्य महसूस होता था। देश को बाहर से बंद करना और अंदर से सारी आज़ादी और विविधता। यह जर्मन राज्य का सही विचार है। बिस्मार्क राइख पहले से ही

34 फ्रेडरिक विल्हेम III (1770-1840) 1797 से प्रशिया के राजा थे। हालांकि उन्होंने नेपोलियन युद्धों में न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी अपनाने की कोशिश की और थर्ड कोएलिशन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी रानी लुईस की सपोर्ट वाली युद्ध-समर्थक पार्टी ने उन्हें 1806 के फोर्थ कोएलिशन में शामिल होने के लिए मजबूर किया, जिससे जेना की लड़ाई हुई जिसमें प्रशिया नेपोलियन से हार गया।

35 विल्हेम II (1859-1941) आखिरी जर्मन सम्राट थे और उन्होंने 1888 से नवंबर 1918 तक राज किया। विल्हेम ने बिस्मार्क के सख्त एंटी-सोशलिस्ट कानूनों का समर्थन नहीं किया और 1890 में चांसलर को हटा दिया। जब साराजेवो में आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया-हंगरी का समर्थन करने का फैसला किया, भले ही उन्हें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड को शामिल करने वाले युद्ध के खतरों के बारे में पता था।

जर्मन राज्य के विचार के इस आदर्श के बहुत करीब आ गए, बस फर्क इतना था कि जर्मन ऑस्ट्रिया36 में हमारे नस्लीय भाई अभी भी राइख के बाहर रह गए थे।

इसलिए, सभी जर्मन कबीलों को एक बंद नेशनल स्टेट में एक करना हमारा सबसे खास नेशनल पॉलिटिकल लक्ष्य है। अंदरूनी पॉलिटिकल तौर पर, बड़े प्रांतों का फेडरल और फ़ेडरल कैरेक्टर, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से बना था, उसे बनाए रखना या फिर से बनाना है। इस मामले में नेशनल पॉलिटिकल बेस लाइन ये हैं: राइख के सभी काम जिनमें पावर का सवाल है, विदेशी देशों के मामले में जर्मन राइख की पॉलिटिकल पोजीशन राइख के मामले हैं। ये हैं फॉरेन ऑफिस, एम्बेसी और कॉन्सुलेट, पासपोर्ट सिस्टम, विदेशी व्यापार का कंट्रोल, कस्टम सिस्टम और सबसे बढ़कर, आर्मी और नेवी।

दूसरी तरफ, अंदरूनी राजनीतिक तौर पर, अलग-अलग प्रांतों या फेडरल राज्यों की सबसे बड़ी आज़ादी के विचार को बढ़ावा देना है। देश के आज़ाद होने के लिए फाइनेंशियल आज़ादी ज़रूरी है, इसलिए टैक्स कानून ज़्यादातर प्रांतों को सौंपने होंगे।

सिविल, ट्रेड और पीनल लॉ के कानून को कानून से रेगुलेट किया जाएगा।
रीच लेकिन असल में प्रांतीय न्याय और पुलिस अधिकारियों के अधीन था।

इसी तरह ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन भी निश्चित रूप से रीच के कानून के निर्देशों के अनुसार रेगुलेट किए जाएंगे, लेकिन फिर भी वे अपने फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रूप से, प्रोविंशियल सॉवरेनिटी के तहत ही रहेंगे।

संविधान में धर्म की आज़ादी को पूरी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए, इसके लिए किसी खास बात की ज़रूरत नहीं है; दूसरी ओर, जिन धर्मों की लिखावट पूरी तरह से जर्मन भाषा में नहीं लिखी गई है और सभी के लिए आसानी से समझ में नहीं आती है और जिनके कंटेंट में राज्य के लिए खतरनाक सिद्धांत शामिल हैं, उन्हें यह सुरक्षा नहीं मिलेगी।

राइख के बेसिक सोशलिस्ट कैरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल रूप पर खास तौर पर लेबर लॉ के साथ-साथ बीमारी, एक्सीडेंट, बुढ़ापे और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के क्षेत्र में ज़ोर दिया गया है और इसे आज की तुलना में बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा।

अंतर्दृष्टि और लक्ष्य-निर्धारण

यदि समय से संबंधित मामलों के हर गहन उपचार में तीन सवालों का जवाब चाहिए होता है: अब क्या है? यह कैसे हुआ? और अब क्या? – क्योंकि इस बुनियादी जांच के बिना एक पूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ कार्य की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती – यह एक उच्च अर्थ में मान्य है जब यह एक नए राज्य के निर्माण की बात हो। इस कार्य के दायरे में वर्तमान स्थिति का विवरण स्वाभाविक रूप से तभी स्थान रखता है जब यह राज्य और अर्थव्यवस्था की वर्तमान महत्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यक विशेषताओं को निकालने का सवाल हो। ऐसे कार्य में किसी भी लक्षण को कारण के रूप में लेने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यह वास्तव में हर निदान की कला है जो बाहरी कारकों या वृद्धि से धोखा नहीं खाता बल्कि चीजों के कारण को गहराई से देखता है। यह चिकित्सा उदाहरण या जीवित मनुष्य के मामले में सबसे स्पष्ट हो जाता है। यदि शरीर में कहीं सूजन दिखाई देती है तो लेकिन इस जानकारी को भी आखिरी वजह नहीं मानना चाहिए, बल्कि खून की खराब हालत बदले में खराब या कम पोषण का नतीजा होगी। अब, अगर डॉक्टर लड़ाई करे तो इलाज कामयाब नहीं हो पाएगा।

36 जर्मन ऑस्ट्रिया गणराज्य, 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के जर्मन बोलने वाले इलाकों से बने राज्य का नाम था। इसमें अभी के ऑस्ट्रियाई इलाकों के अलावा, साउथ टायरॉल और टार्विसियो (अब इटली में), दक्षिणी कैरिंथिया और दक्षिणी स्टायरिया (अब स्लोवेनिया में) और सुडेटेनलैंड और जर्मन बोहेमिया (अब चेक रिपब्लिक में) शामिल थे।

सिर्फ़ बाहरी चीज़ें; इससे सबसे अच्छे हालात में कुछ समय के लिए आराम तो मिल जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, लेकिन बीमारी बनी रहेगी। खून साफ़ करने वाले इलाज से इलाज की कोशिश भी पक्का इलाज नहीं ला पाएगी, अगर असली वजह, यानी कमी या खराब खाना या दूसरी नुकसानदायक बातें, दूर न की जाएं। सिर्फ़ अंदर से बाहर की तरफ़ ऐसा इलाज ही असली इलाज ला सकता है। यह बात सबको साफ़ है। अगर हमें किसी बीमार देश के मामले में काम करना है, तो ठीक इसी तरह जांच करनी चाहिए। यहां भी अगर बीमारी के बाहरी लक्षणों से निपटा जाए तो यह बहुत कम काम आता है। यह मशहूर कहावत एक दुखद सच्चाई के तौर पर बहुत अच्छी तरह महसूस होती है: "छोटे बदमाशों को फांसी दी जाती है; बड़े बदमाशों को छोड़ दिया जाता है"। आम हितों के खिलाफ़ उल्लंघन की बार-बार होने वाली घटनाएं सिर्फ़ इस बात का बाहरी संकेत हैं कि पर्दे के पीछे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आम भलाई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि, सिर्फ़ तभी जब देश में कुछ गड़बड़ हो, इतने बड़े नुकसान बने रह सकते हैं और देश के वजूद के लिए हमेशा के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर इस तरह राज्य खुद बीमार है, तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि इसका कारण लोगों की चिंताओं और राज्य के असल कामों और अधिकार के बारे में गलत सोच है। इसलिए, आखिर में, राज्य के एक नए हेल्दी आइडिया से, एक हेल्दी, ताकतवर राज्य लीडरशिप बनाकर, जो पूरी तरह से आज़ाद हो और जिस पर अतीत के पापों का बोझ न हो, इलाज की उम्मीद की जा सकती है। हर वह हल जो मौजूदा ताकतों के साथ समझौते से हटकर होता है या जो खुद को पहले के राज्य के खत्म हो चुके रूपों से फिर से बांधना चाहता है, वह खुद ही अपनी बर्बादी का बीज बोता है। इस सिलसिले में, किसी को भी उन पुराने राज्य रूपों से खुद को बांधने से सावधान रहना चाहिए जो असल में अपने आप में बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी खत्म हो गए।

आज के संकट की सबसे खास बातें क्या हैं?

बाहर से और ऊपर से – जैसे बुखार के मामले में – तेज़ बुखार या, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों में कहें तो: बेचैनी, हर मौके पर तनाव, बेचैनी और अव्यवस्था। यह बहुत ज़रूरी है कि हर घुटन महसूस करने वाला और आलसी इंसान, बल्कि असली कर्ज़दारों की पूरी फौज ने हमेशा सबसे ऊँची आवाज़ में "आराम और व्यवस्था" को हर बीमारी का इलाज बताया है। आराम और व्यवस्था आम तौर पर कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक शर्त है जो दिखाती है कि देश के अंदर सेहतमंद हालात हैं। लेकिन अगर कोई देश बीमार है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक और साफ़ है कि यह बेचैनी और अव्यवस्था में दिखता है। इसलिए, एक राजनीतिक नज़रिया जो सिर्फ़ "आराम और व्यवस्था" का उपदेश देता है और उसे स्थापित करना चाहता है, वह पूरी तरह से गलत है; दूसरी ओर, यह बीमारी को और भी गहरा करने में मदद करता है, जब तक कि मौत सबसे डरावनी ऐंठन के साथ न आ जाए।

अल्सर और मवाद भी, जिन्हें इंसानी रूप माना जाता है, वे भी स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति शांत रहे क्योंकि बैक्टीरिया तब बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं और पूरे शरीर में फैल सकते हैं और उसे अंदर से भी पूरी तरह से सड़ा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल उल्टा: मवाद को दूर भगाओ! इन्हें निकालना होगा, ऑपरेशन के दर्द को इसका उल्टा कारण नहीं बताया जा सकता; मरीज़ को उसके बुरे माहौल से बाहर निकालना होगा, और सबसे बढ़कर उसे हेल्दी और मज़बूत खाना मिलना चाहिए।

इसके और लक्षण हैं सरकारी पदों को गलत लोगों से भरना, सरकारी मामलों को बहुमत के फैसलों से निपटाना, संसद में ऐसे बहुमत के फैसले होना जिनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, ऐसी संसदों का चुनाव ऐसे वोट के अधिकार के हिसाब से होना जो बाहर से तो सबसे आज़ाद और सबके लिए होता है, लेकिन अंदर से अटकलें लगाता है।

जनता की समझ की कमी और बेहतर समझ और ज़िम्मेदारी की ज़्यादा भावना को दबा देती है। एक सरकार जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी पर निर्भर है – जो पूरी तरह से इत्तेफ़ाक से आती है और जिसके लिए सिर्फ़ पार्टी-पॉलिटिकल बातें ही तय होती हैं – वह स्वाभाविक रूप से आम भलाई की ऑब्जेक्टिव गार्डियन नहीं रह सकती, बल्कि यह

महत्वाकांक्षी पार्टी नेताओं और जिद्दी सिद्धांतवादियों के लिए ज़मीन तैयार करना। इन सभी लक्षणों को "संसदवाद" शब्द में बताया जा सकता है।

यह पार्लियामेंटेरियनिज़्म लोगों की सेल्फ-गवर्नमेंट की क्षमता का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक झूठ है। बेशक, हम सोच सकते हैं कि ज़िम्मेदारी के प्रति जागरूक राज्य के नागरिक पब्लिक मामलों पर अधिकार के साथ फैसला करने और अपने समुदाय या देश की किस्मत तय करने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन यूनिवर्सल वोटिंग जैसा अधिकार, जो 21 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सीधा और सीक्रेट हो, अपने आप में ज़रूरी तौर पर घटिया और बेईमान लोगों के बुरे राज का बीज बोता है।

पार्लियामेंट और उन पर निर्भर सरकारों के घटिया राज के साथ-साथ, मार्क्सवादियों के सभी एंटी-कैपिटलिस्टिक नारों के बावजूद, आज असल में बड़ी लोन कैपिटल का राज है। हाई फाइनेंस ही राज्य और इकॉनमी का बिना रोक-टोक वाला रूलर है। कोई भी सरकार बैंकिंग और स्टॉक-एक्सचेंज की दुनिया के प्रॉफिट के हितों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने की हिम्मत नहीं करती। सभी देश बहुत बड़े नेशनल कर्ज़ों के ज़रिए इस सुपर-नेशनल वर्ल्ड पावर के इंटरेस्ट और टोल से बंधे हुए हैं। इस इंटरेस्ट की गुलामी के नतीजे बहुत बड़े हैं, वे पूरी दुनिया को इकोनॉमिक और नेशनल पॉलिटिकल रिश्तों में उसकी नींव तक हिला देते हैं। इंटरेस्ट कलेक्शन वाकई सरकारों का मुख्य काम बन गया है। इसका मतलब है देशों के लिए एक भयानक टैक्स एक्सप्लॉइटेशन और डायरेक्ट और खासकर, इनडायरेक्ट टैक्स के अलग-अलग तरीकों से, एक बिना रुके बढ़ती महंगाई के ज़रिए, जो अपने पीक पर पूरे मिडिल-क्लास की सेविंग्स को लूटने तक ले गई है। इंटरेस्ट के कानूनी दावे के मुखौटे के पीछे, मनी-बैग एक्सरसाइज का यह बिना रोक-टोक वाला राज, दुनिया पर अब तक का सबसे क्रूर राज है। इससे आम लोग और खासकर वे लोग गरीब और कंगाल हो जाते हैं जिनके लिए पैसा कमाना अपने आप में कोई मकसद नहीं होता और इसलिए यह उनकी पूरी सोच का सेंटर भी नहीं होता। बस इसी से इस पक्के फाइनेंशियल नियम का सबसे डरावना नतीजा निकलता है, यानी इस नियम के तहत आने वाले लोगों का नैतिक पतन। सारी सोच पाने और कब्ज़ा करने की तरफ हो जाती है, वफादारी और विश्वास के सारे कॉन्सेप्ट फायदे की बेरहमी से कोशिश में डूब जाते हैं, इज्ज़तदार आदमी को यह महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अपनी इज्ज़त के इनाम के तौर पर, उसे और नीचे गिरना होगा, जबकि बेईमानी सभी मुमकिन और नामुमकिन बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाती है। बहुत बड़े ग्रुप अपनी रोजी-रोटी के लिए जूझ रहे हैं, सिर्फ काम से ठीक-ठाक इनकम मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है।

बंद फ्रंटलाइन में मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरी वसूलने की कोशिश करते हैं, हड़तालें काम की जगहों को हिला देती हैं, उनके प्रोडक्शन को कमज़ोर कर देती हैं और इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा उन लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं जो देश की इकॉनमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान के प्रोडक्शन पर निर्भर हैं, खासकर खुद मज़दूरों को।

एक पूरी घटना के तौर पर हम इन हालात को "मैमोनिज़्म" के कॉन्सेप्ट के तहत शॉर्ट में बता सकते हैं ।

इस मैमोनिज़्म का दूसरा पहलू मार्क्सवादी नज़रिया है जो मैमोनिस्टिक उल्लंघन के शिकार लोगों के दिमागी मूड से पैदा हुआ है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मार्क्सवादियों के मास्टरमाइंड बड़ी चालाकी से इस दिमागी मूड का इस्तेमाल इंटरनेशनल कैपिटल के लिए खुद के लिए करने में कामयाब रहे हैं और साथ ही, शोषितों की नफ़रत को खुद से दूर करने में भी कामयाब रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ एक ऐसे दिमागी मूड से निपटना है जो न केवल रुकावट डालता है बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से बनाने के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा दुश्मनी भरा तरीका अपनाता है।

राज्य।

मार्क्सवाद का सार हमें इस बात में देखना चाहिए कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी को नकारता है और इस तरह हर इकॉनमी और उससे भी आगे, हर हायर कल्चर से ज़मीन काट देता है; इसके अलावा, इस बात में कि इसने क्लास-स्ट्रगल के विचार को बढ़ावा दिया है और इस तरह लोगों को दो हिस्सों में बाँट दिया है।

अलग-अलग वर्ग आपस में लड़ रहे थे। रूसी लोगों की गुमनाम तकलीफ़ की ओर इशारा करना ही काफ़ी है, जहाँ सोवियत सरकार में, देश और अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाली इस गलत सोच को सबसे ज़्यादा हद तक सच में बदला गया।

और अगर अब हम बीमारी के असली पैथोजन्स को देखें, तो अजीब बात है कि हर जगह हमें लीडर और मुख्य बेनिफिशियरी के तौर पर यहूदी ही मिलते हैं।

यहूदी प्रश्न एक विश्व-प्रश्न बनता जा रहा है जिसके समाधान पर कल्याण और राष्ट्रों का दुःख निर्भर करेगा।

इस सवाल पर इस लाइब्रेरी सीरीज़37 में एक खास काम किया जाएगा ।

इतिहास देखने पर पता चलता है कि हताश देशों ने बार-बार यहूदियों को खूनी दमन और खत्म करके इस बुराई से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की है – लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद यहूदी ऐसे नरसंहारों के बाद फिर से ज़्यादा मज़बूत और आर्थिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होकर लौटे हैं।

इसलिए हमें यहूदी सवाल का हल इस पुराने तरीके से ढूंढने से बचना चाहिए - असल में कोई अकेले प्लेग के बैक्टीरिया को नहीं मार सकता, उसे सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें उससे काटकर ही खत्म किया जा सकता है।

पूरी दुनिया में जो एंटी-सेमिटिज्म भड़क रहा है, वह इस बात का संकेत है कि देशों ने अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन को पहचान लिया है, लेकिन अब यह हमारा काम है कि हम इस सही इमोशनल जानकारी को सही और सही तरीके से आगे बढ़ाएं।

मार्क्सवाद और उसके साथ यहूदियों के खिलाफ लड़ाई, ज़हरीले लोगों को लगातार शिक्षा देने से ही सफल होती है। यह हमारी लड़ाई का पहला स्टेज है।

ब्याज की गुलामी को तोड़ना, लोगों और राज्य को सुपर-नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के सुनहरे जाल से आज़ाद कराने के लिए आर्थिक क्षेत्र में आखिरी और सबसे मुश्किल लड़ाई है।
शक्ति।

इन स्टेज से लड़ने के बाद, और जब जीत पूरी तरह से मिल जाए और पक्की हो जाए, तभी आगे के सभी सुधार करने का समय होगा जो कमज़ोर और बीमार देश को जीने की नई इच्छा और नई ताकत देंगे, जो सबसे पहले यह समझेगी कि हम सबके मन में क्या है, जिस पर हम सब पूरे दिल से विश्वास करते हैं और जिसके लिए हम पक्की इच्छा शक्ति से कोशिश करते हैं:

जर्मनी का पुनर्जन्म।

एक नया, आज़ाद, एकजुट ग्रेटर जर्मनी, जो काम और परफॉर्मेंस की एक हेल्दी, मज़बूत और पावरफुल स्थिति में हो।

37 यहूदियों पर फेडर का काम, डाई जुडेन, 1933 में नेशनलसोज़ियालिस्टिशे बिब्लियोथेक के वॉल्यूम 45 के रूप में प्रकाशित हुआ था

2. कार्यक्रम

कार्यक्रम की उत्पत्ति

हर काम के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है, हर काम को पूरा करने से पहले दिमागी तौर पर कुछ बनाना ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन प्लान जितने साफ़ और बेहतर तरीके से बनाए जाएंगे, बिल्डिंग उतनी ही खूबसूरती से और जल्दी बनेगी। नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए भी एक साफ़ कंस्ट्रक्शन प्लान की ज़रूरत होती है, इसे यहां पॉलिटिकल प्रोग्राम कहा जाता है।

एक पॉलिटिकल प्रोग्राम पर जो मांगें रखी जानी चाहिए, वे बहुत ज़्यादा और बहुत अलग-अलग तरह की होती हैं। यह सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वाले काम का सवाल है, क्योंकि अपने लोगों की भलाई और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि प्लान अच्छा था या नहीं। एक प्रोग्राम को पब्लिक लाइफ के सभी ज़रूरी क्षेत्रों को बहुत कम शब्दों में और संक्षेप में देखना चाहिए, हर आलोचना का सामना करना चाहिए, डिटेल में खोना नहीं चाहिए, विरोधियों को कोई फालतू कमज़ोर पॉइंट नहीं देना चाहिए, कोई ऐसी यूटोपियन उम्मीदें नहीं जगानी चाहिए जिन्हें बाद में पूरा न किया जा सके। प्रोग्राम को आने वाले राज्य और नई इकॉनमी की एक सच्ची तस्वीर होना चाहिए। इसमें सभी को उस राज्य और इकॉनमिक ऑर्डर का खाका दिखाना चाहिए जो चाहा गया है, लेकिन यह अपनी डिटेल्स में उसे पूरा करने में रुकावट या उम्मीद भी नहीं डाल सकता।

हर प्रोग्राम का एक इतिहास और एक डेवलपमेंट होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी आंदोलन के बुनियादी तौर पर सही होने की कसौटी है, अगर इतने सालों के बाद भी, उसके बेसिक फीचर्स में कुछ भी ज़रूरी बदलाव न किया जाए और सिर्फ़ कुछ अस्पष्टताएँ दूर की जाएँ। 24 फरवरी 1923 के पुराने प्रोग्राम, नंबर 11 का सबसे ज़रूरी और खास प्रोग्राम पॉइंट, "बिना काम और मेहनत के इनकम खत्म करना, ब्याज की गुलामी को तोड़ना" को नेशनल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल टर्म्स में पूरी तरह से प्रोग्रामेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उस समय इस पॉइंट पर डिटेल में ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय, इससे जुड़े ज़्यादा डिटेल्ड लेख, ब्याज की गुलामी को तोड़ने और स्टेट बैंकरप्सी, इसके सॉल्यूशन के लिए मैनिफेस्टो, लगभग अकेले मौजूद लेख थे और आंदोलन के फाउंडर्स और पहले फॉलोअर्स को पूरी तरह से पता थे। एक तरह से यह इन लेखों का इंटेलेक्चुअल कंटेंट था जिसने एक्टिविटी के सोशलिस्ट स्कोप को जोड़ा -

उन योजनाओं के साथ जो उस समय पहले से ही अपनी बुनियादी विशेषताओं में तय हो चुकी थीं - नवीनीकरण की इच्छा तक जिसने एंटोन ड्रेक्सलर38 और एडॉल्फ हिटलर के आसपास एक छोटे से समूह को, राष्ट्रवादी और लोकप्रिय विचारों के समूह तक एक साथ ला दिया था।

ठीक यही प्रोग्राम पॉइंट्स और मांगें हैं जिनके ज़रिए नेशनल सोशलिज़्म का जर्मन फ्रीडम मूवमेंट असल में और बुनियादी तौर पर खुद को दूसरे सभी पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मूवमेंट्स और पार्टियों से अलग करता है, और जिनके ज़रिए यह खुद को खासकर उन सभी सो-कॉल्ड पार्लियामेंट्री पार्टियों से अलग करता है, जो अपनी तरफ से, सिर्फ़ मैमोनिस्टिक-प्लूटोक्रेटिक राज का एक रूप हैं।

प्रोग्राम को नए तरीके से बनाने में एक और ज़रूरत यह थी कि एक साफ़ जानकारी मिले।
सार्वजनिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में एक रूप और एक स्पष्ट संरचना। ऐसा हुआ है।

यहां मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं एक और ज़बरदस्त काम के बारे में सोचूं, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया और बोहेमिया में नेशनल सोशलिज़्म के पैरेलल रूप से हुई है, मेरा मतलब है किताब

---

38 एंटोन ड्रेक्सलर (1884-1942), डिट्रिच एकार्ट और फेडर के साथ, म्यूनिख में मूल रूप से ऑस्ट्रियाई ड्यूश आर्बिटर पार्टी के जर्मन समकक्ष के संस्थापकों में से एक थे। ड्रेक्सलर ने पार्टी के मानद अध्यक्ष के रूप में काम किया, जिसके हिटलर 1921 में ही स्पष्ट नेता बन चुके थे। ड्रेक्सलर ने 1923 में पार्टी छोड़ दी और 1933 में हिटलर के सत्ता में आने पर फिर से शामिल हो गए।

इंजीनियर जंग39, प्राग पार्लियामेंट में चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन जर्मनों के प्रतिनिधि।

ऑस्ट्रियाई नेशनल सोशलिज़्म की शुरुआत युद्ध से बहुत पहले के समय से हुई। इसके विचारों का दायरा सोशलिस्ट विचारों की दुनिया को नेशनलिस्ट विचार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश पर ज़्यादा टिका था, जबकि राइख का जर्मन नेशनल सोशलिज़्म, जो ऑस्ट्रियाई नेशनल सोशलिज़्म के पतन के बाद ही पैदा हुआ – असल में इस ऑस्ट्रियाई नेशनल सोशलिज़्म के होने की जानकारी के बिना – उसने शुरू से ही मार्क्सवाद के खिलाफ़ एक बुनियादी लड़ाई का रुख अपनाया।

आज दोनों आंदोलन अपने कॉमन लक्ष्यों के लिए एक साथ आ गए हैं।

[39] इंजीनियर रुडोल्फ जंग, ट्रॉपाऊ से एक प्रतिनिधि

NSDAP का राष्ट्रीय और आर्थिक कार्यक्रम

हमारा लक्ष्य है – जर्मन भावना से जर्मनी का पुनर्जन्म, जर्मन आज़ादी के लिए।[40]

इस मुख्य लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता यह है:

I. राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत: जर्मन रीच जर्मनों का घर है।

1. विदेश नीति में:

1. एक बंद राष्ट्रीय राज्य की स्थापना जिसमें सभी जर्मन शामिल हों।

2. विदेश में जर्मन हितों का शक्तिशाली प्रतिनिधित्व।

2. नस्लीय नीति में:

3. यहूदियों और सभी गैर-जर्मनों को सभी ज़िम्मेदार पदों से हटाना सार्वजनिक जीवन।

4. पूर्वी यहूदियों और दूसरे परजीवी विदेशियों के इमिग्रेशन पर रोक। परेशान करने वाले विदेशियों और यहूदियों को देश निकाला दिया जा सकता है।

3. नागरिक नीति में:

5. सिर्फ़ वही जर्मन जो खुद को जर्मन संस्कृति और समुदाय के लिए समर्पित कर दे, वह जर्मन हो सकता है राज्य के नागरिकता अधिकारों का इस्तेमाल करें।

6. जो जर्मन नहीं है, वह जर्मन राज्य में केवल मेहमान के रूप में रह सकता है और विदेशी कानून के तहत आता है।

7. जर्मनों के अधिकार और हित विदेशी सदस्यों से पहले आते हैं राष्ट्रों.

II. आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का काम मांग को पूरा करना है, न कि लोन कैपिटल के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना।

8. नेशनल सोशलिज्म मूल रूप से प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता देता है और इसे राज्य संरक्षण।

9. लेकिन लोगों की भलाई के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है।

10. सभी जर्मन लोग आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक वर्क कम्युनिटी बनाते हैं और संस्कृति।

11. हर जर्मन की इस आम काम की ज़िम्मेदारी के दायरे में और प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुनियादी मान्यता के साथ, हर जर्मन को अपने काम से होने वाली इनकम को पाने और उसे मुफ़्त में बेचने की आज़ादी है।

12. आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, और इस प्रकार कृषि में भी, छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों का स्वस्थ मेल बना हुआ है।

13. बड़े एंटरप्राइज़ (कॉर्पोरेशन, सिंडिकेट और ट्रस्ट) का मुकाबला किया जाएगा।

14. सूदखोरी और रैकेट चलाने, साथ ही लोगों की कीमत पर और उन्हें नुकसान पहुंचाकर बेरहमी से अमीर बनाने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी। 15. हर जर्मन के लिए एक साल का ज़रूरी काम शुरू किया जाएगा।

---

[40] इन बातों पर डिटेल में बात करने के लिए फेडर की किताब 'दास प्रोग्राम डेर NSDAP अंड सीन वेल्टनशॉलिचेन ग्रंडलागेन', म्यूनिख, 1927; अनुवाद: ईटीएस डगडेल, द प्रोग्राम ऑफ़ द NSDAP एंड इट्स जनरल कॉन्सेप्शन्स, म्यूनिख, 1932 देखें।

III. फाइनेंशियल पॉलिटिकल प्रिंसिपल: फाइनेंशियल सिस्टम राज्य की सेवा में है, फाइनेंशियल पावर राज्य के अंदर राज्य नहीं बना सकतीं; इसलिए हमारा लक्ष्य: ब्याज की गुलामी को तोड़ना:

16. राज्य तथा उसके साथ-साथ लोगों को बड़े ब्याज-आधारित ऋण से मुक्ति लोन कैपिटल।

17. रीच्सबैंक GmbH. और सेंट्रल बैंकों का नेशनलाइज़ेशन।

18. सभी बड़े पब्लिक कामों (हाइड्रो-एनर्जी, रोडवेज़, वगैरह का डेवलपमेंट) की फाइनेंसिंग, बिना इंटरेस्ट वाले स्टेट ट्रेजरी वाउचर जारी करके या कैश-फ्री तरीके से लोन से बचकर।

19. कवर्ड बेसिस पर स्टेबल करेंसी की शुरुआत।

20. बिना ब्याज के क्रेडिट देने के लिए एक नॉन-प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक (करेंसी रिफॉर्म) बनाना।

21. सोशलिस्ट, नेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना। इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ से कंजम्प्शन को और मुश्किल टैक्स (टैक्स रिफॉर्म और टैक्स छूट) से प्रोडक्शन को आज़ाद करना।

IV. सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत: आम कल्याण सर्वोच्च कानून है।

22. लाइफ-एन्युइटी सिस्टम के नेशनलाइज़ेशन के ज़रिए बुढ़ापे के इंश्योरेंस का बड़े पैमाने पर विकास। हर ज़रूरतमंद जर्मन नेशनल कॉमरेड को एक तय उम्र से या समय से पहले हमेशा के लिए गुज़ारा न कर पाने की हालत में काफ़ी पेंशन की गारंटी दी जाएगी।

23. प्रोडक्टिव कामों में लगे सभी लोगों का परफॉर्मेंस और उम्र के हिसाब से काम से होने वाली कमाई में हिस्सा, साथ ही काम के नेशनल इकोनॉमिक कामों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी में भी हिस्सा।

24. ईमानदारी से काम न करने वाले सभी युद्ध और क्रांति के मुनाफ़े को ज़ब्त करना, साथ ही जमाखोरी और सूदखोरी से कमाई गई संपत्ति को ज़ब्त करना और उनका इस्तेमाल सोशल इंश्योरेंस के विकास के लिए करना।

25. आर्टिकल 21 के अनुसार बनाए जाने वाले नए नॉन-प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक बैंक के ज़रिए पूरे रीच में बड़े पैमाने पर नई हाउसिंग बिल्डिंग बनाकर घरों की कमी को दूर करना।

V. कल्चरल-पॉलिसी में: एक पॉलिटिकली फ्री, इकोनॉमिकली हेल्दी देश की नींव पर सभी साइंस और फाइन आर्ट्स का फलना-फूलना हमारा मुख्य कल्चरल लक्ष्य है।

इस तक इस तरह पहुंचा जा सकता है:

26. युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र पुरुषों के रूप में शिक्षित करना जर्मन बौद्धिक जीवन की महान परंपराओं के अनुसार।

27. धर्म और अंतःकरण की पूर्ण स्वतंत्रता।

28. ईसाई धर्म का विशेष संरक्षण।

29. उन धार्मिक सिद्धांतों को दबाना और बाहर करना जो जर्मन नैतिक भावना के खिलाफ हैं और जिनका कंटेंट राज्य और राष्ट्र को नष्ट करने वाला है।

30. साहित्य और प्रेस, मंच, कला और में सभी हानिकारक प्रभावों का दमन सिनेमा.

31. जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की आज़ादी, अच्छे चरित्र वाले लोगों का एक रूलिंग क्लास बनाना।

VI. सैन्य दृष्टि से:

32. हर आज़ाद के लिए मिलिट्री कानून लाकर देश को सुरक्षित बनाना
जर्मन.

33. भाड़े के सैनिकों का उन्मूलन।

34. देश की रक्षा के लिए एक प्रोफेशनल ऑफिसर कोर के तहत एक मिलिशिया सेना बनाना, जिसे सख्त हायरार्किकल डिसिप्लिन के ज़रिए बनाया जाएगा।

VII. अन्य सुधार:

35. प्रेस सिस्टम में सुधार। जर्मन लोगों की चिंताओं के खिलाफ़ सभी प्रेस टूल को दबाना। सभी खबरों के लिए सबसे सख्त ज़िम्मेदारी।

झूठा या जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

36. चुनाव प्रचार के मौजूदा भ्रष्ट तरीकों और चुने हुए लोगों की ज़िम्मेदारी की कमी (इम्युनिटी) को खत्म करके वोट देने के अधिकार में सुधार।

37. व्यावसायिक चैम्बरों का विकास।

38. न्यायपालिका में सुधार

लैंड लॉ – (ज़मीन पर प्रॉपर्टी के अधिकार की बुनियादी पहचान, प्राइवेट कैपिटल की तरफ से ज़मीन को लीज़ पर न देना, राज्य का प्रीएम्प्शन अधिकार, और लापरवाह मैनेजमेंट के मामले में ज़मीन का राज्य को वापस करना)।

सिविल कानून - (आज के प्रॉपर्टी के एकतरफ़ा कानूनी सुरक्षा के मुकाबले, निजी सम्मान और सेहत की कहीं ज़्यादा सख़्त सुरक्षा)।

39. संवैधानिक सुधार:

संविधान: जर्मन कैरेक्टर के हिसाब से संविधान एक सॉवरेन स्टेट लीडरशिप है जो सबसे ऊंचे पद पर फोकस करता है। - इस सबसे ऊंचे पद पर लोगों द्वारा चुने गए राजा का कब्ज़ा होगा या दो या तीन ज़िम्मेदार राइख के सबसे ऊंचे अधिकारियों का, यह लोगों को बाद में तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए।

राइख का फेडरल चरित्र: अलग-अलग प्रांतों के जर्मन लोगों की बनावट, जो कबीलों और इतिहास के ज़रिए अंदरूनी तौर पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग-अलग फेडरल राज्यों को उनके अंदरूनी मामलों में पूरी आज़ादी देती है।

राइख की चिंता जर्मन लोगों का बाहरी तौर पर प्रतिनिधित्व, पासपोर्ट और टोल, और इसके अलावा, सेना और नौसेना है।

नेशनल सोशलिज़्म के इस नेशनल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को पूरा करने के रास्ते में तीन मुख्य विरोधी हैं। मार्क्सवाद, पार्लियामेंटेरियनिज़्म और, इन दोनों से ऊपर, बड़ी लोन कैपिटल।

हमारी मार्क्सवाद-विरोधी लड़ाई 1 यहूदी कार्ल मार्क्स के राज्य-विघटनकारी सिद्धांत के खिलाफ, वर्ग-संघर्ष के लोगों को विघटित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ, निजी संपत्ति के इनकार के अर्थव्यवस्था-विघटनकारी सिद्धांत के खिलाफ और इतिहास की पूरी तरह से आर्थिक भौतिकवादी अवधारणा के खिलाफ है।

2. हमारी संसद-विरोधी लड़ाई तथाकथित लोकप्रिय प्रतिनिधियों की गैर-ज़िम्मेदारी के खिलाफ़ है, जिन्हें - इससे बचाकर - असल में अपने फ़ैसलों के नतीजों की ज़िम्मेदारी कभी नहीं लेनी पड़ती, साथ ही इससे होने वाले सभी नुकसानों (भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी) और, सबसे बुरे नतीजे के तौर पर - ऐसी संसद पर निर्भर सरकार के खिलाफ़ भी है।

3. हमारी एंटी-मैमोनिस्टिक लड़ाई, जो बाकी दो लड़ाई के मोर्चों से ऊपर है, दुनिया भर में फैली फाइनेंशियल ताकत के खिलाफ है, यानी बड़े लोन कैपिटल के ज़रिए हमारे लोगों का लगातार फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नुकसान और शोषण।

लेकिन, दूसरी तरफ, यह लड़ाई हमारी पब्लिक, इकोनॉमिक और कल्चरल ज़िंदगी के सभी फील्ड्स में मौजूद, आत्मा को खत्म करने वाली, घमंड और लालच की मैटेरियलिस्टिक भावना के खिलाफ एक ताकतवर दिमागी लड़ाई भी है।

आखिरी और सबसे गहरे एनालिसिस में, यह दो दुनिया को देखने के नज़रिए की लड़ाई का मामला है, जो दो बिल्कुल अलग इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं – प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्पिरिट और मोबाइल लालची स्पिरिट। मिट्टी में बसी क्रिएटिव स्पिरिट और फिर से मेटाफिजिकल अनुभव में दुनिया पर जीत हासिल करने वाली स्पिरिट, आर्यन इंसान में अपने मुख्य रिप्रेजेंटेटिव पाती है – लालची, बिना जड़ वाली कमर्शियल और मैटेरियलिस्टिक स्पिरिट जो पूरी तरह से इस दुनिया की तरफ़ है, यहूदी में अपना मुख्य रिप्रेजेंटेटिव पाती है।

एंटी-सेमिटिज्म की तरह नेशनल सोशलिज्म भी यहूदी मटेरियलिस्टिक सोच में बुराई की असली जड़ को देखता है, लेकिन यह भी जानता है कि दुनिया के इतिहास की यह सबसे ताकतवर लड़ाई सिर्फ नेगेटिव एंटी-सेमिटिक मांगों पर टिकी नहीं रह सकती, इसलिए नेशनल सोशलिज्म का पूरा नेशनल और इकोनॉमिक प्रोग्राम निश्चित रूप से ज़मीनी लेकिन नेगेटिव एंटी-सेमिटिक लड़ाई से बहुत ऊपर उठता है, यह पॉजिटिव तरीके से एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इमेज देता है कि नेशनल सोशलिस्ट के काम और परफॉर्मेंस की हालत कैसी दिखनी चाहिए।

अगर यह मुख्य लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो जाएगी। तब नेशनल सोशलिज्म पूरे जर्मन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी असल में आम तौर पर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, बल्कि आबादी का सिर्फ़ पक्के इरादे वाला, आगे की सोचने वाला और भविष्य को देखने वाला हिस्सा है जो एक मज़बूत इच्छाशक्ति और दिमाग वाले नेता के आस-पास इकट्ठा हुआ है, ताकि जर्मनी को बाहर से शर्म और बेबसी से, अंदर से तबाही और भ्रष्टाचार से, बाहर से एक ताकतवर और प्रभावशाली स्थिति में ले जा सके, और अंदर से, एक आर्थिक रूप से मज़बूत, सांस्कृतिक रूप से फलता-फूलता, दिमागी और नैतिक रूप से ऊँचा नेशनल समुदाय बना सके।

हम जर्मन इच्छा का रीच बनाना चाहते हैं जैसा कि गेइबेल41 गाते हैं:

एक बाहरी रूप से, एक शक्तिशाली तलवार के साथ,
एक ऊंचे बैनर के चारों ओर रैली करते हुए,
आंतरिक रूप से समृद्ध और बहुआयामी,
हर जनजाति अपने तरीके से!

41 इमानुएल गेइबेल (1815-1884) एक जर्मन कवि और नाटककार थे, जिन्होंने कई देशभक्ति वाली कविताएँ लिखीं। यहूदी लेखकों, हेनरिक हेन और लुडविग बोर्न के आस-पास के उस समय के लिबरल 'यंग जर्मन' साहित्यिक ग्रुप ने उन पर हमला किया, लेकिन बाद में नेशनल सोशलिस्टों ने उनका साथ दिया।

3. राष्ट्रीय राज्य संरचना

समाजवादी राज्य

जर्मन राज्य का राष्ट्रीय समाजवादी विचार

पावर पॉलिटिकल फाउंडेशन वाले चैप्टर में हम पहले ही इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि जर्मन शासकों का अपने पूरी तरह से जर्मन कामों से हर भटकाव जर्मन लोगों के लिए सबसे बुरे नतीजों के साथ हुआ। अगर कोई जर्मन इतिहास को देखे तो हमेशा पाता है कि एक बंद नेशनल स्टेट की जर्मन चाहत सिर्फ़ छोटे ऐतिहासिक समय में ही पूरी हुई, बार-बार यह जर्मन सपना धुंधला गया, और बार-बार जर्मनी बेबसी और टूटने में डूब गया। इस तरह पूरे जर्मन इतिहास से एक सबक साफ है कि सिर्फ़ एक ताकतवर लीडरशिप वाले स्टेट के अंदर देश का बंद होना ही जर्मनी को उन बड़े खतरों का सामना करने में काबिल बनाता है जो सिर्फ़ उसकी खराब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से पैदा होते हैं। जर्मनी की लगभग कहीं भी नेचुरल बाउंड्री नहीं है, लगभग हर जगह यह दुश्मन के हमलों से आज़ाद और बिना सुरक्षा के है। न तो इंग्लैंड को घेरने वाला समुद्र और न ही स्पेन और इटली को उसके पड़ोसियों से अलग करने वाले ऊंचे पहाड़ जर्मनी को नेचुरल डिफेंस देते हैं। फ्रांस के पास हमारे खिलाफ़ सिर्फ़ एक खुली साइड है, रूस भी वही है। सिर्फ़ जर्मनी ही दूसरे देशों के बीच में है - दिल की तरह - और यूरोप के युद्ध के मैदान की तरह। जर्मन ज़मीन पर स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, स्वीडिश, रशियन और मंगोल सेनाओं ने लड़ाई लड़ी, जर्मन ज़मीन पर तीस साल के युद्ध के भयानक धार्मिक युद्ध लड़े गए, और इसके उलट, जर्मनों ने सभी देशों में विदेशी हितों के लिए विदेशी सेवा में खून बहाया। मदर जर्मेनिया हज़ारों ज़ख्मों से खून बहा जो उसकी विदेशी सेनाओं ने दिए थे और - जो उसके अपने बेटों की लड़ाई से उसे लगे थे। जर्मन इतिहास बहुत दुखद है, इतना दुखद कि एक एकजुट, बंद जर्मन राइख की जर्मन चाहत को परियों की कहानियों में, किफ़हाउसर42 में बूढ़े बारबारोसा की कहानियों में शामिल किया गया था। सदियों तक जर्मन राज्य का विचार साकार होता रहा – देश के सबसे अच्छे लोगों की चाहत और उम्मीद, जब तक कि 1871 में, एक ताकतवर लोहार ने जर्मनी की एकता नहीं बना दी। महान जर्मन राज्य को साकार करने में अभी भी बहुत कुछ बाकी था, जिसमें वे सभी जर्मन शामिल थे जो मातृभूमि के साथ क्षेत्रीय संबंध में रहते थे। लेकिन जर्मन चाहत के इस थोड़े-बहुत एहसास ने ही हमें जर्मन इतिहास को पहले से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया।

लेकिन हमें 'अगर' और 'लेकिन' की बात नहीं करनी है, बल्कि हमें इतिहास से सीखना है। पॉलिटिक्स इतिहास बन रहा है, और अगर "इतिहास बनाने" से हमारे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए, तो हमारी सरकार, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स को, इतिहास में जो हुआ है, उसका सम्मान करते हुए, पहले की गलतियों से बचना चाहिए और खुद को सबसे अच्छी परंपरा से जोड़ना चाहिए। वह आदमी, जिसका कोई इतिहास नहीं है और जो अपनी कुर्सी से हठधर्मिता से इतिहास बनाता है, वह लोगों पर सिर्फ़ मुसीबत ही ला पाएगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में नई जर्मन मार्क्सवादी सरकार-दिखावटी लोगों से देखा है। पुराने सामाजिक ढांचे का पूरी तरह से टूटना जितना खतरनाक और नुकसानदायक है, खासकर जब यह तबाही मार्क्सवादी आंदोलन की ताकत जैसी ही हो, उतना ही पुराना सिर्फ़ इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि वह पुराना है।

इसमें एक बार फिर रूढ़िवादी भावना की त्रासदी छिपी है, जो रचनात्मक रूप से निष्फल और

42 थुरिंगिया और सैक्सोनी-एनहाल्ट राज्यों के बीच की पहाड़ियों की किफहाउसर रेंज को पवित्र रोमन सम्राट, फ्रेडरिक बारबारोसा (1122-1190) की आराम करने की जगह माना जाता है, जो तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान तुर्की में सालेफ नदी में डूब गए थे।

बिना कल्पना के, यह हर नई चीज़ को सिर्फ़ इसलिए मना कर देता है क्योंकि वह नई है, और क्योंकि यह पुराने तरीकों से मज़बूती से जुड़ा रहता है जो बहुत पहले ही अपना असर खो चुके हैं। लोग और देश ममी और बनावट नहीं हैं, बल्कि ज़िंदा चीज़ें हैं; एक बार काटे गए कपड़े हमेशा अच्छे नहीं लगते।

देशों की किस्मत से सिर्फ़ कुछ बहुत बड़ी बुनियादी बातें ही तय होती हैं, और ऐसी बुनियादी जानकारी को नज़रअंदाज़ करने का हमेशा देशों पर बुरा असर पड़ा है। हम जर्मन लोगों के लिए बुनियादी ऐतिहासिक राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत है: "एक हो जाओ!"

लेकिन "यूनाइटेड"43 शब्द का मतलब "यूनिटी"44 नहीं बल्कि "एग्रीमेंट में होना"45 है। सिर्फ़ बाहरी और अंदरूनी पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स पर जर्मन ट्राइब्स की सहमति से ही एक अंदरूनी तौर पर आज़ाद देश अपने सबसे अच्छे फूल के तौर पर उग सकता है जो बाहर से ताकतवर हो और जिसका इंटरनेशनल लेवल पर वज़न हो।

इसलिए, जर्मन सरकार के लिए कोई यूरोपियन या इंटरनेशनल आर्थिक, चर्च या इंसानी मकसद नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ़ पूरे जर्मन देश की भलाई हो सकती है। मेरा मतलब है पॉलिटिकल एक्शन के लिए "मकसद"। इसके साथ ही, चर्च, आर्थिक और आम तौर पर इंसानी किरदार का असर भी स्वाभाविक रूप से होता है, जिसे ठीक से महत्व दिया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन यह उसूल होना चाहिए और बना रहना चाहिए कि जर्मन नेशनल स्टेट को सिर्फ़ जर्मनों को रिप्रेजेंट करना है और यह अंदरूनी पॉलिटिक्स के साथ-साथ बाहरी पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए।

इसलिए हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य है:

1. एक बंद राष्ट्रीय राज्य की स्थापना जिसमें सभी जर्मन शामिल हों।

2. विदेश में सभी जर्मन हितों का शक्तिशाली प्रतिनिधित्व।

राष्ट्रवादी विचार

एक मज़बूत राष्ट्रीय चेतना की जागृति या बेहतर कहें तो फिर से जागृति के लिए पहली शर्त है

सभी यहूदियों और गैर-जर्मनों को पब्लिक लाइफ में सभी ज़िम्मेदार पदों से हटाना।

हमारी पब्लिक लाइफ के लगभग सभी फील्ड में यहूदियों के हमले के खिलाफ पक्की डिफेंसिव लड़ाई पूरी एनर्जी के साथ सिर्फ नेशनल सोशलिज्म ही करता है। यहूदियों के खिलाफ लड़ाई जर्मन स्पिरिट और जर्मन आज़ादी के लिए एक सचेत संघर्ष है।

यहूदियों का अपने होस्ट लोगों पर जो असर होता है, उसकी तुलना दूसरे लोगों के पावर रिलेशन और लड़ाइयों से बिल्कुल नहीं की जा सकती, बल्कि सिर्फ़ एक हेल्दी शरीर और उस पर हमला करने वाले जानलेवा ज़हरीले जर्म्स के बीच ज़िंदगी और मौत की लड़ाई से की जा सकती है। जब किसी ज़िंदा जीव पर ज़हरीले बैक्टीरिया हमला करते हैं, तो सवाल सिर्फ़ यह होता है: या तो शरीर की हेल्दी ताकत बाहरी घुसपैठियों पर काबू पा लेगी – फिर वह उन्हें काट देगी – या वह उन पर काबू नहीं रख पाएगी, फिर उनकी वजह से मर जाएगी। इसी तरह, दुनिया भर में यहूदियों के होस्ट लोगों के लिए भी बस यही है: या तो यहूदियों को देश से निकाल दो – या यहूदियों की वजह से मर जाओ।

इंसानी शरीर और जर्म्स की तुलना से हमें साफ़ पता चलता है कि यह पसंदीदा गुमराह करने वाली राय कितनी एकतरफ़ा है, कि यहूदियों ने सिर्फ़ अपनी ज़्यादा काबिलियत की वजह से हर जगह काम किया और इसी वजह से उन पर हमला करना और उन्हें परेशान करना बहुत गलत और नाइंसाफ़ी है। कोई यह नहीं कह सकता कि हैजा का बैसिलस भी इंसान से ज़्यादा मज़बूत और काबिल है और इसीलिए उसने सेहतमंद इंसान को हरा दिया है – नहीं,

---

[43] 'ईनिग'

[44] 'Einheit'

[45] 'Einigkeit'

यह आदमी के लिए ज़हर है। और, ठीक वैसे ही जैसे ज़हरों के खिलाफ़ ज़िंदा जीव की इस लड़ाई में, ज़हर के खास लक्षण बुखार, ऐंठन, लकवा के लक्षण वगैरह के साथ दिखते हैं, वैसे ही यहूदी जिन देशों पर हमला करते हैं, उनकी लड़ाई बीमारी के बिल्कुल वैसे ही लक्षणों में दिखती है – नागरिक और राजनीतिक जीवन में अशांति और हलचल, देश में ज़ोरदार उथल-पुथल, उथल-पुथल, डर, सिविल वॉर, जो देशों के दिमागी हिस्सों में – खासकर सरकारों में – लकवा के आम लक्षणों के साथ बारी-बारी से आते हैं। फिर बस एक ही सवाल है, कि क्या दुश्मन को पहचानने वाले देश के जागरूक लोग सरकारों को चेतावनी देने और उन्हें समझाने में कामयाब होते हैं या सरकार बनाने और खुद यहूदियों को बेअसर करने में – तब इलाज पक्का हो जाता है; अगर वे ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो देश की मौत भी उतनी ही पक्की है। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। एक टेम्परेरी अकेलापन – मेडिकल इमेजरी के साथ रहने के लिए – सिर्फ़ ऊपरी तौर पर दिखने वाले इलाज लाता है: देर-सवेर बैक्टीरिया शरीर की खून की नसों में फिर से फैल जाते हैं, इस दूसरी लड़ाई का अंत मरीज़ के लिए जानलेवा होता है।

आखिरी कामयाबी के लिए – जैसा कि आम ज़िंदगी में होता है – ताकत की इच्छाशक्ति ज़रूरी है। इस ताकत की इच्छाशक्ति के बिना – देश को बनाए रखने की इस इच्छाशक्ति के बिना देश बेबस होकर नीचे गिर जाता है। जो सच में नीचे नहीं जाता, वह पूरी तरह से यहूदी दुनिया की ताकत का गुलाम, गुलाम, गुलाम और नौकर बन जाता है।

यह ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है। कई काबिल सैनिक निकल पड़े हैं – लेकिन हमारे ज़्यादातर नेशनल साथी अभी भी सो रहे हैं। बार-बार, बिना थके, शिक्षा ही इसका हल है। जो बात इस शिक्षा को इतना मुश्किल बनाती है, वह है आर्यों की इन ज़रूरी नस्लीय सवालों में सीधी-सादी और नरमी।

हमारे जर्मन लोगों के अंदर ही मज़बूत नस्लीय मेलजोल ने बेशक बहुत से लोगों में साफ़ और ऊँची नस्लीय समझ को लगभग पूरी तरह से दबा दिया है, जिससे नस्लीय कानूनों की सही जानकारी के बजाय सिर्फ़ नस्लीय रूप से विदेशी यहूदियों के लिए हमेशा नफ़रत की भावना रह गई है। यहूदी अपनी तरफ़ से दो हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से अपने नस्लीय कानूनों का बहुत सख्ती से पालन करते आए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की साफ़ जानकारी है कि चरित्र और देश के लिए खून की शुद्धता बनाए रखना कितना ज़रूरी है46 ।

दूसरी तरफ, वह नस्लीय आंदोलन को पुरानी बकवास बता पाए हैं, जो जर्मनी में नस्लीय मिक्सचर के मामले में, बदकिस्मती से उनके लिए कुछ हद तक सही लगने के साथ मुमकिन था। जर्मनों की तरफ से नस्लीय साइंस के लिए यहूदियों की नफ़रत का पूरी मज़बूती से विरोध करने के बजाय, यह मांग करके: "जर्मन, अपना खून साफ़ रखो!", जर्मन इस मामले में भी यहूदियों की साइकोगॉजिक आर्ट्स47 से कमतर थे। एनलाइटनमेंट की सदी ने अपने इंसानी आदर्शों के साथ यहूदियों को उन ज़ंजीरों से आज़ादी दिलाई जो हमारे पुरखों ने अपनी ऊँची समझ से लूट और सूदखोरी की यहूदी भावना के फैलने के खिलाफ़ बनाई थीं, लेकिन हमें इस बुनियादी सवाल पर सिर्फ़ कन्फ्यूजन और अनिश्चितता ही मिली। इस वाक्य के साथ: "यहूदी भी इंसान हैं" – एक ऐसा वाक्य जिस पर कभी किसी ने विवाद नहीं किया था और है – यहूदियों को नागरिक समान अधिकार दिए गए। इससे पूरी तरह से अलग सोच वाले यहूदी विदेशी लोगों के खिलाफ़ देश-नस्लीय विरोध कम हो गया और नागरिक आज़ादी के खिलाफ़ लड़ाई शुरू से ही कमज़ोर हो गई।

इस मंच से अब हमारी पूरी आर्थिक और,
हाल ही में, यहूदियों के बिना रोक-टोक वाले शासन की मौजूदा स्थिति तक पब्लिक लाइफ।

46 Cf. नेशनल सोशलिस्ट लाइब्रेरी के नस्ल और यहूदियों पर लिखे गए वॉल्यूम!
47 मनाने की कलाएँ।

यहूदियों के खुद के बयानों की पूरी सीरीज़ से पता चलता है कि वे खुद को एक देश के अंदर एक देश जैसा महसूस करते हैं, कि वे अपने होस्ट लोगों के मुकाबले दूसरे देशों में अपने नस्लीय साथियों से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।

लोगों के बीच एक-दूसरे से करीब होने की इस यहूदी भावना से, युद्ध और शांति के समय देशों के विदेशी राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में मूल निवासियों के लिए सीधे खतरे पैदा होते हैं।

लेकिन, शुरू में यहूदियों का ध्यान आर्थिक फ़ायदों की मांग पर था। यहाँ एक बार फिर, बिना रोक-टोक के मुनाफ़े की उनकी चाहत, जिसमें उनके मेज़बान लोगों के लिए कोई सामाजिक भावना नहीं थी, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई।

मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम के इन्वेंटर और चलाने वाले होने के नाते, उनके लिए जल्द ही राज्यों की पूरी फाइनेंशियल इकॉनमी और बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज के ज़रिए, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को भी अपने असर में लाना आसान हो गया।

यहाँ से, इस तरह अपनी फाइनेंशियल स्थिति बनने के बाद, यहूदियों ने देश के इंटेलेक्चुअल-कल्चरल प्रोडक्ट्स की तरफ भी हाथ बढ़ाया; यहाँ उनकी जोशीली भावना, उनकी तेज़ बुद्धि, उनकी क्रिटिकल समझ – ऐसी खासियतें जो अक्सर गंभीर, भारी, ज़मीन से जुड़ी आर्यन भावना के लिए पक्के फायदे के तौर पर दिख सकती हैं – उनकी मदद के लिए आईं।

लेकिन असल में, यह सिर्फ़ चोरी करने की आदत, उनके ज़मीर की कमी और बेईमानी थी – जो उनके धार्मिक सिद्धांतों में पहले से ही बताया गया है। यहूदी के लिए, शुलचन अरुच48 के सिद्धांतों के अनुसार, गैर-यहूदी की प्रॉपर्टी बिना मालिक की प्रॉपर्टी की तरह है – ताकि यहूदी उसे हड़प सके! यहूदी ने बैंकिंग और स्टॉक-एक्सचेंज तकनीक के सभी तरीके अपनी सेवा में लगा दिए। एनोनिमाइज़ेशन – पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्टॉक-मार्केटेबल रूप के ज़रिए हमारी इकॉनमी का डीपर्सनलाइज़ेशन – ने कुछ हद तक कैपिटल को काम से अलग कर दिया है, शेयर-होल्डर को बहुत कम मामलों में अपनी फैक्ट्री के बारे में कुछ पता होता है, उसे अपने पैसे के प्रॉफिट में सिर्फ़ एकतरफ़ा दिलचस्पी होती है।

जब उसने इसे शेयर के रूप में इन्वेस्ट किया हो। इस बात का ज़िक्र यहाँ इसलिए करना होगा क्योंकि हमारी इकॉनमी के इस डीपर्सनलाइज़ेशन के साथ-साथ इसकी गिरावट भी होती है। वह एंटरप्रेन्योर और मैन्युफैक्चरर जिसने अपना एंटरप्राइज शुरू से बनाया है, जो अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को जानता है, जिसमें अभी भी पुराना बिज़नेस ऑनरेबल है और जो इकॉनमी की असल ज़रूरतों के हिसाब से एक ठोस, अच्छा, टिकाऊ प्रोडक्ट बनाना अपना फ़र्ज़ समझता है, यह असल में ठोस एंटरप्रेन्योर आज के बड़े शेयर-होल्डर से बिल्कुल अलग है, जो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक होने के नाते एक बड़े शेयर पैकेज पर कब्ज़ा करके सिर्फ़ एक ही फ़ायदा जानता है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने का लक्ष्य रखना। चाहे एंटरप्राइज में अच्छी और सस्ती चीज़ें बनाई जाती हों, चाहे आम तौर पर एक स्टॉक कंपनी द्वारा प्रोडक्टिव वैल्यू बनाई जाती हों या, जैसा कि क्रेडिट कंपनियों (बैंकों) के मामले में होता है, आम तौर पर कोई वैल्यू नहीं बनाई जाती, यह कैपिटलिस्ट - शेयर-होल्डर के लिए बिल्कुल बेपरवाह बात है। इसका एक और नतीजा यह होता है कि प्रोडक्शन ज़रूरतों पर कम ध्यान देता है, बल्कि, सिर्फ़ एक साफ़ ज़रूरत को ही बड़े एडवरटाइज़िंग के ज़रिए जगाने की ज़रूरत होती है। पहले बिज़नेसमैन के कोड ऑफ़ ऑनर में अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करना पूरी तरह मना था; ऐसा करने वाला मार्केट-क्राइयर होता था, और इस तरह मार्केट-क्राइयर जैसे अपने सामान की तारीफ़ करना एक अच्छा बिज़नेसमैन बेईमानी वाला कॉम्पिटिशन मानता था। लेकिन यहूदी व्यापारी ठीक इसी तरह का मार्केट-क्राइइंग वाला बिज़नेस पूरी ज़िद के साथ करते थे, जिसमें उनकी मनाने की कला काम आती थी। आज ज़िद करने वाले यहूदी क्राइयर की जगह यहूदी एडवरटाइज़िंग आ गई है।

48 शुलचन अरुच यहूदी कानून का सबसे आधिकारिक कोड है और इसे 1563 में उत्तरी फ़िलिस्तीन में योसेफ़ कारो ने बनाया था।

साइंस के फील्ड में भी ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ, खासकर इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में – जिसे नेशनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। धीरे-धीरे नेशनल इकोनॉमिक्स का काम नेशनल इकोनॉमिक लेजिटिमेसी और ज़रूरतों की जांच करने और जांच के नतीजों से इकोनॉमिक लीडरशिप के लिए गाइडलाइन निकालने में नहीं रहा, बल्कि यह देखा गया कि सिर्फ़ हालात का ब्यौरा दिया जाता था, बिना यह जांचे कि सामने आई इकोनॉमिक घटनाएं और रूप नेशनल इकोनॉमी की असल ज़रूरतों के लिए भी अच्छे, सही और लागू होते हैं या नहीं। इस तरह लोग कामयाब हुए, और आज पहले से कहीं ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, इकोनॉमी को और इसके साथ ही, नेशनल कम्युनिटी को – साइंटिफिक तरीके से देखा जाए – और इसी वजह से, एक ऐसे तरीके से जिसे बदला नहीं जा सकता। इस फील्ड में खास तौर पर स्टेट और प्राइवेट क्रेडिट सर्विसेज़ इंडस्ट्री का सिद्धांत, और खास तौर पर इंटरेस्ट का सिद्धांत आता है। हमने इस सवाल पर दूसरी जगह डिटेल में बात की है, यहाँ यह बताना काफी होगा कि असल में जिसे हम आज नेशनल इकॉनमी कहते हैं, वह असल में सिर्फ़ पर्सनल अमीरी के लिए एक प्राइवेट कैपिटलिस्टिक इंस्ट्रक्शन है और प्रोडक्टिव देशों की वर्कफ़ोर्स की सूदखोर कैपिटलिस्टिक लूट को सही ठहराने की एक सोची-समझी कोशिश है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल इकोनॉमिक्स के लेक्चरर में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं।
यहूदियों का प्रतिशत।

आम आदमी के लिए ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहूदियों ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी दखल दिया।
मैदान।

जो कोई भी आज के थिएटर के बारे में सोचता है, वह वहां फैली हुई नीचता और बुराई देखकर हैरान रह जाएगा। यह बात आज के सिनेमा के मामले में खास तौर पर सही है। हमारे स्टेज पर बदतमीज़ों और घटिया लोगों का ड्रामा राज करता है; तोड़-फोड़ वाली और चालाकी भरी बातों से, अच्छे जर्मन लोगों को यह लेक्चर दिया जाता है कि नैतिकता, आचार-विचार, सम्मान और ईमानदारी असल में बेवकूफी हैं, जिनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जनता पर इन हमलों के साथ यहूदी थिएटर-एजेंसी की परेशानी भी होती है, जिसमें कला में दिलचस्पी रखने वालों का ज्ञान, पद चाहने वालों के थिएटर- और कॉन्सर्ट-एजेंटों के प्रति आभार से ज़्यादा मायने रखता है।

लेकिन फिर बड़े पैमाने पर डेली प्रेस के ज़रिए पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाने लगा। लगभग सभी बड़े अखबार धीरे-धीरे यहूदियों के मालिकाना हक में चले गए।
इसके साथ ही जर्मन लोगों के चारों ओर का घेरा बंद हो गया। आर्थिक नियम के साथ-साथ दिमागी नियम भी जुड़ गया। यहूदियों के हितों के लिए जो कुछ भी नुकसानदायक था, उसे जितना हो सके जनता से छिपाया गया और चुप कराया गया; अगर फिर भी कोई विचार या प्रदर्शन सामने आता, तो असली विच-हंट शुरू होता, पहले तो ऐसी कोशिशों को मज़ाकिया बनाने की कोशिश की जाती, और अगर इससे भी मदद नहीं मिलती, तो झूठ और गलत बयानी के साथ-साथ निजी बदनामी भी की जाती थी। रिश्वत, धमकियाँ देने की कोशिश की जाती थीं और आखिर में कोई भी मुश्किल में डालने वाले विरोधी या डाँटने वाले को आर्थिक रूप से लूटने, या उसे जान से मारने से भी नहीं हिचकिचाता था।

यह आखिरी सबसे डरावना हथियार आम तौर पर आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, या बहुत कम किया जाता था, क्योंकि शायद ही कभी लोगों के किसी सच्चे दोस्त का रिएक्शन, जिसके पास कोई पॉलिटिकल या सरकारी पद न हो, तब तक असरदार होता था, जब तक कि वह यहूदियों के पब्लिक ऑर्गन्स में झूठ और बदनामी की बौछार से टूट न जाए।

पार्टियों में, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर लोगों की नाराज़गी को भड़काया गया, और अमीर लोगों और उनके तथाकथित रक्षकों, सरकारी अधिकारियों और सेना के खिलाफ़ क्लास की नफ़रत को भड़काया गया। यहाँ भी – जैसा कि देश पर इन हमलों के मामले में हर जगह होता है – यहूदियों ने ही ज़्यादातर आंदोलन किया और भड़काया। बस यह याद रखना ज़रूरी है कि क्लास-स्ट्रगल के मार्क्सवादी सिद्धांत के फाउंडर कार्ल मार्क्स असल में एक यहूदी थे (मर्दोचाई)

जर्मनी में उनके हेराल्ड, फर्डिनेंड लैसल49, जो मूल रूप से फीस्ट लैसल थे, भी एक यहूदी थे।

युद्ध और क्रांति में जर्मन सरकार के खिलाफ यहूदियों का तबाही का काम पूरा हो गया था। राजकुमारों को भगा दिया गया, अफसरों के कंधे की पट्टियाँ फाड़ दी गईं, अफसरों को भूखा रखकर आज्ञाकारी बना दिया गया ताकि वे अपनी मैनपावर - जो आज के जर्मनी के सोशलिस्ट-हाई-कैपिटलिस्ट राज्य के लिए भी ज़रूरी थी - उपलब्ध करा सकें। इस तरह जर्मन देश को हथियारहीन कर दिया गया, उसे कमज़ोर कर दिया गया, उसके नेताओं को लूट लिया गया, बेदखल कर दिया गया और उसका उल्लंघन किया गया, उसका हौसला तोड़ दिया गया और उसे कमज़ोर कर दिया गया, जबकि हर जगह पब्लिक लाइफ़ में, इकॉनमी और पॉलिटिक्स में, आर्ट और थिएटर में, यहूदियों ने खुद पर बिना किसी शक के दबदबा बना लिया।

उनके शासन का आधार उनकी अपार संपत्ति है।

अपने मेज़बान लोगों के मुकाबले उनकी संख्या कम होने के बावजूद, वे पब्लिक लाइफ़ के सभी ज़रूरी पोस्ट अपने यहूदी नस्लीय साथियों या यहूदियों से करीबी रिश्ते रखने वाले जर्मन लोगों के हाथों में लाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन फिर भी, जर्मन नेशनल बॉडी से यहूदियों को हटाना पूरी तरह से मुमकिन है – और भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री और खेती, प्रोफ़ेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में असली ज़रूरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी लगभग पूरी तरह से यहूदियों से आज़ाद है।

हमारे देश से यहूदियों को हटाने से न तो खेती-बाड़ी में रुकावट आएगी – मैंने अभी तक किसी यहूदी को हल के पीछे हल चलाते नहीं देखा है – और न ही मज़दूरों की कमी से फैक्ट्रियों को रुकना पड़ेगा – मज़दूरों को सच में पता चल जाएगा कि कोई यहूदी मेहनत से कोयला नहीं उठाता या भट्टी पर खड़ा नहीं होता – लोहार और मेटलवर्कर, बढ़ई और मोची के हमारे काम की जगहें अनाथ नहीं होंगी – यहूदियों को निकालने के बाद घरों को किसी भी तरह से खंडहर नहीं बनना पड़ेगा, आंकड़ों में यहूदी राजमिस्त्री और बढ़ई, छत बनाने वालों या शीशे लगाने वालों का कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन अगर यहूदी नहीं रहे तो व्यापार और कॉमर्स में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मामले में, सरकार ने अब तक पर्सनल और माल ढुलाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है और, वैसे भी, यहूदियों को रेलवे कंडक्टर या लोकोमोटिव ड्राइवर के तौर पर किसने देखा है –

या ट्राम कंडक्टर के तौर पर, या गाड़ी चलाने वाले या ट्रांसपोर्ट वर्कर के तौर पर?

लेकिन यहूदियों के ट्रेड और फाइनेंस के प्रति आम झुकाव के मामले में भी, युद्ध से पहले मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ने दिखाया है कि वे ध्यान से स्टोरेज और प्रोविजन सर्विस दे सकते थे, खुद ट्रेड में लाखों कमर्शियल क्लर्क और जर्मन बिजनेसमैन एक्टिव हैं जो ट्रेड के असली पहलुओं और ज़रूरतों को समझते हैं, और स्टेट बैंक और पोस्टल बैंक में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो यहूदी लुटेरी इकॉनमी से आज़ाद एक हेल्दी नेशनल इकॉनमी का आधार बन सकते हैं।

अगर हमने इस छोटे से सर्वे में देखा है कि यहूदी किसी भी तरह से हमारे देश और देश की ज़िंदगी में कोई ऐसी अहम भूमिका नहीं निभाते जिसे बदला न जा सके, बल्कि वे, दूसरी तरफ, अपने देश के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने दबदबे का सबसे बेरहमी से गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक साफ़ और लॉजिकल नतीजा यह होता है कि यहूदियों को हमारे देश से निकालने की मांग उठती है।

सिर्फ़ वही व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है जो खुद को जर्मन राष्ट्रीय समुदाय के प्रति समर्पित कर दे ।

---

49 फर्डिनेंड लैसल (1825-1864) एक जर्मन-यहूदी सोशलिस्ट थे जो मार्क्स को जानते थे, हालांकि मार्क्स उन्हें कंजर्वेटिव बिस्मार्क के साथ समझौता करने की उनकी इच्छा के कारण एक मौकापरस्त मानते थे। इसलिए जब लैसल ने ऑलगेमाइनर ड्यूशर आर्बेइटरवेरिन (जनरल जर्मन वर्कर्स) की स्थापना की, तो मार्क्स ने उनका समर्थन नहीं किया।

एसोसिएशन) का 1863 में बनाया गया यह संगठन मुख्य रूप से सबको सीधे वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया था।

50 यह शर्त 15 सितंबर, 1935 के नूर्नबर्ग कानूनों के दूसरे हिस्से , 'द राइख सिटिज़नशिप लॉ', आर्टिकल 2 में पहले से ही शामिल थी: "रईख का नागरिक सिर्फ़ वही नागरिक है जो जर्मन या उसके जैसे खून का हो और जो अपने व्यवहार से यह दिखाए कि वह जर्मन लोगों और राइख की ईमानदारी से सेवा करने के लिए इच्छुक और काबिल है।" इन कानूनों के पहले हिस्से, 'जर्मन खून और जर्मन सम्मान की सुरक्षा के लिए कानून' में यहूदियों को जर्मन समाज से पूरी तरह अलग करने का आदेश दिया गया था।

नस्ल के सवाल की इस समीक्षा से स्वाभाविक रूप से और ज़रूरी तौर पर पूर्वी यहूदियों के इमिग्रेशन पर रोक के दूसरे नतीजे भी सामने आते हैं। अगर कोई यह मानता है कि इमिग्रेशन पर रोक लगाकर पूर्वी यहूदियों को दूर भगाना काफी है, तो यह यहूदी सवाल की पूरी समझ की कमी है। हमारे बीच बसे हमारे लोगों के दुश्मन यहूदियों को एक एलियन के काम के तहत रखना भी बहुत ज़रूरी है। पूर्वी यहूदी बेशक वह बड़ा ज़रिया हैं जिससे यहूदी लगातार खुद को भरते रहते हैं। इस इमिग्रेशन में जो बड़ा खतरा है, वह पिछले कुछ सालों के अनुभवों से पूरी तरह सामने आ गया है। कुछ ही सालों में ये पूर्वी यहूदी हर मुमकिन बिज़नेस चालों और तरकीबों से बहुत सारा पैसा बनाने में कामयाब हो गए हैं। हमारे कोर्टरूम ऐसे विदेशी लोगों की धोखाधड़ी से भरे पड़े हैं। सरकार को ऐसे लोगों के इमिग्रेशन में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है जो किसी भी तरह से खुद को प्रोडक्टिव तरीके से काम का नहीं बनाते।

पूर्वी यहूदियों के प्रति नेशनल सोशलिस्ट राज्य की यह स्थिति इस बात को बाहर नहीं करती कि यहां तक कि दूसरे देशों के सदस्य जो देश पर पैरासाइट हैं, उन्हें भी निकाला जा सकता है।

इन सवालों पर चर्चा अब हमें राज्य की नीति के तीसरे भाग पर ले जाती है। नेशनल सोशलिज्म: नागरिकता के अधिकार के लिए।

नागरिकता का अधिकार

नागरिकता का अधिकार हासिल करना होगा। इस सिद्धांत में नेशनल सोशलिज़्म अभी के मान्य अधिकार से काफ़ी अलग है, जिसके अनुसार 20 साल से ज़्यादा उम्र का हर वयस्क जर्मन, चाहे वह पुरुष हो या महिला, राज्य की नागरिकता के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह, आज, वाइमर संविधान के अनुसार, यह संभावना यहूदी जाति के सदस्यों के लिए खुली है। इसी तरह, यह राज्य की सदस्यता कोई भी विदेशी कुछ ऊपरी औपचारिकताओं को पूरा करके हासिल कर सकता है।

वाइमर संविधान आम तौर पर राज्य के नागरिक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, लेकिन आर्टिकल 110 में राज्य की मेंबरशिप और आर्टिकल 109 में राज्य के सभी सदस्यों, चाहे वे पुरुष हों या महिला, के लिए कानून के सामने बराबर अधिकारों की बात करता है। इस कॉन्सेप्ट का साफ़ न होना, ज़ाहिर है, नागरिकता के अधिकार को पाने के लिए नैतिक और नस्लीय शर्तों की मांग को बाहर कर देता है। इसके उलट, राइख संविधान का आर्टिकल 113 विदेशी बोलने वाले "देश के हिस्सों" (!) को अपनी खास सुरक्षा में लेता है; उन्हें "अपने आज़ाद पारंपरिक विकास में, खासकर शिक्षा में अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल में, साथ ही अंदरूनी प्रशासन और न्याय के प्रशासन में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता"।

अगर कोई विदेशी नागरिकों के इस सबसे बड़े विचार की तुलना अपने ही देश के साथियों के खिलाफ हमारे रिपब्लिक की सुरक्षा के लिए कानून के तरीके से करे, तो तथाकथित युद्ध-अपराधियों को दुश्मन के हवाले करने की ज़िम्मेदारी, आर्टिकल 1 12 में दी गई इस पक्की गारंटी के साथ कि "किसी विदेशी सरकार के किसी भी जर्मन को जुल्म या सज़ा नहीं दी जा सकती", और, अगर एक बार ठीक इसी आखिरी बताए गए आर्टिकल की तुलना फ्रांस के क्रुप51 और उसके डायरेक्टरों के खिलाफ बदनाम फैसलों से करे, तो शायद इस बात का ज़िक्र कि इस संविधान का लेखक यहूदी प्रूस52 था, इन सभी घटनाओं पर पक्की रोशनी डालने के लिए काफी है।

---

51 गुस्ताव क्रुप वॉन बोहलेन अंड हालबाख (1870-1950) ने 1909 से 1941 तक फ्रेडरिक क्रुप AG को चलाया। हंस वॉन सीकट (1866-1936) के तहत राइशवेहर के साथ मिलकर, क्रुप ने वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी को गुप्त रूप से फिर से हथियारबंद किया। 1923 में, जब फ्रांसीसी और बेल्जियम ने रुहर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने क्रुप पर जुर्माना भी लगाया।

एसेन में क्रुप फैक्टर के तेरह मज़दूरों के लिए एक बड़ा सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें कब्ज़े के दौरान फ्रांसीसी लोगों ने गोली मारकर मार डाला था।

52 ह्यूगो प्रूस (1860-1925) वाइमर रिपब्लिक के जर्मन-यहूदी आंतरिक मंत्री थे और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1919 के वाइमर संविधान के निर्माण में।

"पोल्स का ज़्यादा अच्छा भविष्य" नहीं, जैसा कि बेथमैन-हॉलवेग53 ने अपने एक खराब पार्लियामेंट्री भाषण में कहा था, और न ही रोमानिया में यहूदियों की बेहतरी (कुलमैन के अनुसार)54 जर्मन देश का मुख्य विचार हो सकता है, बल्कि सिर्फ़ जर्मन लोगों की भलाई ही हो सकती है। यह मुख्य बात NSDAP के नेशनल और इकोनॉमिक प्रोग्राम (द प्रोग्राम, पेज 35) में नंबर 7 के तहत बताई गई है: "जर्मन लोगों के अधिकार और हित दूसरे देशों के सदस्यों से पहले हैं" और नंबर 6 के तहत: "जो जर्मन नहीं है वह जर्मनी में सिर्फ़ मेहमान बनकर रह सकता है और एलियंस एक्ट के तहत आता है"।

इसके अनुसार, राज्य की नागरिकता का अधिकार हासिल किया जाना चाहिए। यह अयोग्यता के कारण भी खोया जा सकता है। यह एक ऐसा अधिकार है जिससे यहूदियों को मूल रूप से बाहर रखा गया है, जिससे दूसरे देशों के सदस्यों को भी बाहर रखा जा सकता है।

जर्मन स्टेट की नागरिकता के लिए एप्लीकेंट के लिए अंदरूनी शर्त जर्मन कल्चर और कम्युनिटी के प्रति कमिटमेंट है। जो इस तरह से जर्मन देश के प्रति कमिटमेंट नहीं करता, जो खुद को जर्मन स्टेट का दुश्मन बताता है, जो अपने लोगों से ज़्यादा दूसरे देशों के लोगों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसे जर्मन स्टेट की नागरिकता का कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि वह असल में जर्मन कम्युनिटी से कोई लेना-देना नहीं रखना चाहता।

यह सच में पागलपन लगता है जब जो लोग खुलेआम कहते हैं कि वे जर्मनी नाम की कोई मातृभूमि नहीं जानते, जैसा कि क्रिस्पियन55 और दूसरों ने किया, फिर भी इस देश के भविष्य पर सलाह देना चाहते हैं, जब वे लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर, डेलीगेट के तौर पर अभी भी खास सुविधाओं का आनंद लेने का दावा करते हैं और जब उन्हें अभी भी खास तौर पर सख्त कानूनों (रिपब्लिक की सुरक्षा) का संरक्षण प्राप्त है, अगर उन्हें इस पार्लियामेंट से सरकारी पदों पर प्रमोट किया जाता है।

नेशनल सोशलिस्ट जर्मन सरकार ऐसे लोगों से सबसे कड़ी सज़ा की मांग करेगी और क्रांतिकारी सरकारों और संसदों के सदस्यों को अपने कामों या गलतियों की ज़िम्मेदारी बाद में लेनी होगी। इसलिए, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले सभी लोगों की ज़िम्मेदारी पर जो कानून बनाए जाने हैं, उन्हें पिछली शक्तियों से लैस करना होगा।

यहाँ बात, जर्मन क्रांति की गलती की तरह, भूखे "मज़दूरों" की मज़दूरी के लिए तृप्त और कभी न तृप्त होने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ़ लड़ाई की नहीं है, यानी क्लास-स्ट्रगल के विचार से मेहनतकश लोगों की सही और अच्छी भावनाओं को गुमराह करने की नहीं है, बल्कि यहाँ बात इस नैतिक मांग की है कि मौजूदा पार्लियामेंट्री और सरकारी सिस्टम के मौजूदा फ़ायदों की गैर-ज़िम्मेदारी खत्म होनी चाहिए, और जिन्होंने लोगों की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं या जिन्होंने दूसरे ग्रुप की साज़िशों में मदद की है, उन्हें सही सज़ा दी जानी चाहिए।

यह नारा: "छोटे बदमाशों को फांसी दी जाए; बड़े लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाए" सही साबित नहीं होना चाहिए। इसके उलट, नेशनल सोशलिस्ट सरकार सज़ा तय करते समय, छोटे बदमाशों के बहकावे में आने को बहुत कम करने वाली बात मानेगी और दूसरी तरफ, जर्मन लोगों के खिलाफ़ बड़े अपराधियों को कानून की पूरी सख्ती से सज़ा दिलाएगी।

---

53 थियोडोर वॉन बेथमैन-हॉलवेग (1856-1921) ने 1909 से 1917 तक जर्मन चांसलर के रूप में काम किया। युद्ध के दौरान, ऐसा लग रहा था कि बेथमैन-हॉलवेग मिलिट्री लीडर्स की बताई गई पॉलिसी के मुकाबले ज़्यादा मॉडरेट पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे।

54 रिचर्ड वॉन कुलमन (1873-1948) ने अगस्त 1917 से जर्मनी के विदेश मामलों के सचिव के रूप में कार्य किया जुलाई 1918. मई 1918 में उन्होंने रोमानिया के साथ बुखारेस्ट की शांति के लिए बातचीत की।

55 आर्थर क्रिस्पियन (1875-1946) 1920 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए और 1922 में सोज़ियालडेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के को-चेयरमैन बने।

इस स्टेट कोर्ट का शुद्धिकरण का काम अब किसी भी तरह से उन लोगों तक सीमित नहीं रह सकता जो क्रांति के साथ सबसे पहले सत्ता में आए थे। इसे इंपीरियल सरकार के उन लोगों को भी टारगेट करना होगा जिन्होंने अपनी लापरवाही से जर्मनी की इस गिरावट को मुमकिन बनाया। मुख्य ज़िम्मेदार – बेथमैन-हॉलवेग – को असल में उसके दुनियावी जजों से हटा दिया गया है, यही बात अगले सबसे दोषी – एर्ज़बर्गर56 के बारे में भी सच है, जिसने जुलाई 1917 की बुरी पार्लियामेंट्री क्रांति के जनक के तौर पर, दुश्मनों की जीतने की डूबती हुई इच्छा को एक बार फिर जगाया। यहाँ तक कि आइज़नर57 ने भी।

और राथेनौ को उनके देश तोड़ने वाले काम की जगह से हटा दिया गया है, पक्का गैर-कानूनी तरीके से लेकिन इतिहास के पक्के नियमों के हिसाब से। लेकिन उनमें से कई लोग अभी भी ज़िंदा हैं जिन्होंने जनवरी 1918 में हथियारों की हड़ताल के ऑर्गनाइज़ेशन के ज़रिए, लड़ने वाली सेना की पीठ में खंजर घोंप दिया था, और वे लोग अभी भी ज़िंदा हैं जिन्होंने बोलकर और लिखकर जीतने की इच्छा को तोड़ा, वे लोग अभी भी ज़िंदा हैं जिन्होंने 'जीतने वालों और हारने वालों के बिना शांति' का उपदेश दिया, वे लोग अभी भी ज़िंदा हैं और इसे सही मानते हैं जिन्होंने युद्ध और क्रांति में लोगों की परेशानी का गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया।

ज़रूर, ऐसी नेशनल पॉलिटिकल मांग से डर और दहशत फैलेगी, और हज़ारों लोग अपनी जान के लिए डरेंगे क्योंकि उनका दिल साफ़ नहीं है। लेकिन नेशनल सोशलिज़्म के लिए सोशल जस्टिस की इस मांग के साथ जर्मन लोगों की किस्मत का सवाल खड़ा होता है और गिरता है, कि क्या जर्मन लोग एक नेक देश बन पाएंगे, या क्या वे एक फ़ेलाहीन देश के तौर पर बदहाली और करप्शन में एक दुखी ज़िंदगी जीएंगे। नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए इसका मकसद भी इसी सवाल से तय होता है।

इसलिए, राज्य की नागरिकता का अधिकार ऐसी चीज़ नहीं है जो जर्मनी में पैदा हुए हर किसी के जन्म में आ जाएगी; बल्कि, इस राज्य की नागरिकता के अधिकार में राज्य और देश के प्रति सबसे बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। हालाँकि, राज्य और देश के प्रति इस ज़िम्मेदारी को इस संभावना से भी बचाना होगा कि अयोग्य होने पर यह अधिकार फिर से खो सकता है।

दूसरी ओर, राज्य की नागरिकता का अधिकार मिलना कोई दया का काम नहीं होगा, बल्कि यह एक दावा होगा जिसे हर मेहनती जर्मन उठा सकता है जो खुद को जर्मन समुदाय के लायक साबित करता है और जो खुद को जर्मन नस्लीय और ऐतिहासिक समुदाय के लिए समर्पित करता है।

जिसने अपनी सेना और काम की ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है, जो अपने पेशे में एक इज्ज़तदार कर्मचारी के तौर पर एक्टिव है, उसे राज्य की नागरिकता पाने का अधिकार है।

लेकिन इस राज्य नागरिकता के अधिकार के साथ यह ज़िम्मेदारी भी जुड़ी है कि अपने सभी कामों में बड़े नज़रिए को न भूलें और अपनी आर्थिक गतिविधियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने काम को समग्रता में फिट करना है, यानी, खास क्षेत्रों में पूरी आज़ादी के साथ भी, जर्मन राज्य नागरिक की गतिविधि समग्रता की भलाई के खिलाफ़ नहीं होनी चाहिए।

---

56 मैथियास एर्ज़बर्गर (1875-1921) ड्यूश ज़ेंट्रम्सपार्टी (कैथोलिक सेंटर पार्टी) के सदस्य थे, जिन्हें बेथमैन-हॉलवेग का दाहिना हाथ माना जाता था। युद्ध के दौरान, 1917 के बीच में, उन्होंने बातचीत से युद्ध खत्म करने की अपील की और जर्मन सेना में भरोसा कम किया। एर्ज़बर्गर ने पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाले युद्धविराम पर साइन किए और वाइमर रिपब्लिक में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, उन्होंने वर्साय की संधि का समर्थन किया। 1921 में फ्रीकॉर्प्स कमांडर, हरमन एहरहार्ट (1881-1971) द्वारा बनाए गए 'ऑर्गनाइज़ेशन कॉन्सल' के कट्टर सदस्यों ने उनकी हत्या कर दी।

57 कर्ट आइज़नर (1867-1919) एक जर्मन यहूदी समाजवादी थे जिन्होंने विटल्सबाख को उखाड़ फेंकने वाली क्रांति का आयोजन किया था। नवंबर 1918 में बवेरिया के राजवंश के नेता बने। वे बवेरिया के रिपब्लिकन प्रधानमंत्री बने और बर्न कॉन्फ्रेंस ऑफ़ सोशलिस्ट्स में उन्होंने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की गलती न मानने के लिए नरमपंथी समाजवादियों पर हमला किया। फरवरी 1919 में राष्ट्रवादी काउंट आर्को वॉन वैली ने उनकी हत्या कर दी।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

नेशनल इकॉनमी का काम डिमांड को पूरा करना है, न कि लोन कैपिटल पर जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्ट-यील्ड पाना।

कोई सोचेगा कि यह सिद्धांत हर इकॉनमी के लिए मान लिया जाता है, और फिर भी नेशनल सोशलिस्ट इकॉनमी मौजूदा इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकॉनमी से ठीक इसी गाइडिंग सिद्धांत में अलग है। प्रोडक्टिव आदमी की सीधी-सादी समझ के लिए ऐसी नेशनल इकॉनमी की कल्पना करना इतना आसान नहीं है जो डिमांड को पूरा करने में मदद न करे; और फिर भी अब यह साफ़ हो जाना चाहिए कि इकॉनमी के मौजूदा मालिकों - बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज कैपिटल - के लिए डिमांड को पूरा करना असल में बहुत कम ज़रूरी है। इंटरनेशनल कैपिटल का इंटरेस्ट है।

इसमें सिर्फ़ इस हद तक कि मांग की इस पूर्ति का फ़ायदा सूदखोरी वाले कैपिटलिस्टिक तरीके से उठाया जा सके।

असल में, हमें यहां इकॉनमी के बारे में दो बिल्कुल अलग नज़रिए देखने को मिल रहे हैं।
पूरी आबादी की तरफ से पूरी इकॉनमी पर एकमात्र ज़रूरी मांग, ज़ाहिर है, खाने की ज़रूरत को पूरा करना है, फिर घर और कपड़ों की मांग को पूरा करना है, और उसके बाद ही रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरतें, जैसे कि ऊँची कलाएँ और सांस्कृतिक खुशियाँ, सब एक साथ आती हैं। इनके बीच सपोर्ट सर्विस, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उससे जुड़ी हर चीज़, व्यापार और फाइनेंशियल सिस्टम आते हैं। एक हेल्दी इकॉनमी में सामान के प्रोडक्शन का सबसे अच्छा मकसद होता है कि ज़रूरत को सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया जाए, एक ऐसे पेमेंट के ज़रिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करे और जिसमें एंटरप्रेन्योर के लिए काम से होने वाली इनकम और एक सही प्रॉफिट-शेयर शामिल हो, जिससे ज़रूरी नुकसान और एंटरप्राइज में सुधार और रेनोवेशन दोनों को पूरा किया जा सके।

एक सही एंटरप्रेन्योर का ध्यान अलग-अलग मामलों में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने पर नहीं होता, भले ही किस्मत से ऐसा हो जाए। एक सही एंटरप्रेन्योर अपने देश के आर्थिक कामों के बारे में पूरी तरह से जानता है, ताकि प्रोडक्शन इस तरह से शुरू किया जा सके कि यूज़र की ज़रूरत कम से कम लागत में पूरी हो सके, साथ ही कंपनी बढ़े और फले-फूले, और मज़दूरी कम हुए बिना प्रोडक्शन की लागत और भी कम हो जाए।

शायद एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसी सच्ची सोच का सबसे अच्छा उदाहरण अर्न्स्ट एबे58 हैं, जो जेना में ज़ीस वर्क्स के को-फ़ाउंडर और डायरेक्टर हैं। इस आदमी ने एंटरप्रेन्योर के इस नेशनल इकोनॉमिक काम को बहुत अच्छे से समझा है और अपनी पूरी काबिलियत से इसे पूरा करने की कोशिश की है।

लेकिन इस मामले में, आम तौर पर हमारे पास युद्ध से पहले के अपने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कोई खास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है। अल्फ्रेड क्रुप59, मैनेसमैन60, वर्नर सीमेंस61 जैसे लोग ,
थिसेन62, बोरसिग63, क्रॉस, माफ़ेई64, वगैरह ने जर्मन इंडस्ट्री के इतिहास में सामाजिक तौर पर भी अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई है। वे सभी एकतरफ़ा मुनाफ़े की चाहत से नहीं चलते थे,

---

[58] अर्न्स्ट एबे (1840-1905) एक फिजिसिस्ट और एंटरप्रेन्योर थे, जिन्हें जेना के फाउंडर कार्ल ज़ीस ने हायर किया था।
कंपनी, कार्ल ज़ीस AG जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम बनाती थी। एबे फर्म के को-ओनर बन गए।

59 अल्फ्रेड क्रुप (1812-1887) फ्रेडरिक क्रुप (1787-1826) के बेटे थे, जिन्होंने 1811 में क्रुप कास्ट स्टील कंपनी की स्थापना की थी। अल्फ्रेड क्रुप के डायरेक्टरशिप के दौरान, कंपनी उस समय की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी बन गई।

[60] मैनेसमैन की स्थापना 1890 में हुई थी और यह शुरू में सीमलेस स्टील ट्यूब बनाती थी।

[61] वर्नर सीमेंस (1816-1892) एक आविष्कारक थे और 1847 में टेलीग्राफेन-बाऊनस्टाल्ट कंपनी के संस्थापक थे। आज
सीमेंस AG दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजिकल कंपनियों में से एक है।

[62] ऑगस्ट थिसेन (1842-1926) ने 1867 में थिसेन-फौसोल आयरन वर्क्स की स्थापना की और दूसरी भारी इंडस्ट्रियल कंपनियों को खरीदा, जिन्हें 1926 में वेरीनिग्टे स्टाहलवर्के में मिला दिया गया, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग और स्टील कार्टेल था।

[63] बोरसिग एक लोकोमोटिव कंपनी थी जिसकी स्थापना अगस्त बोरसिग (1804-1854) ने 1837 में की थी।

64 क्रॉस-मैफेई एक मशीन बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी।

वे सभी अपने लिए सीधे-सादे और विनम्र बने रहे, केवल उनके कामों की समृद्धि ही उनका मार्गदर्शक थी।

असल में, जर्मन इंडस्ट्री की बिना थके प्रोडक्टिव और इन्वेंटिव पावर का नतीजा यह हुआ है कि न सिर्फ़ आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी से लोगों को काम और रोटी मिली, बल्कि बढ़ती सैलरी के बावजूद, आबादी के सभी हिस्सों के रहन-सहन के स्टैंडर्ड में बड़े पैमाने पर सुधार के बावजूद, सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट्स को लगातार नए सुधारों और इन्वेंशन की वजह से सस्ता बनाया जा सका। जर्मन हाथ से काम करने वाले मज़दूर को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सब दिमाग से काम करने वालों का उसका एहसान है।

और एक और बात पर यहाँ फिर से ज़ोर देना ज़रूरी है: कि जर्मन इकॉनमी के इस तरक्की की नींव और शर्त थी बिस्मार्क राइख का मज़बूत लीडरशिप। इन दो वजहों, जर्मन राइख की एकजुट और इसलिए मज़बूत पॉलिटिकल सिचुएशन और जर्मन एंटरप्रेन्योर्स और वर्कर्स की ज़बरदस्त मेहनत ने यह मुमकिन बनाया कि पूरी आबादी के रहन-सहन के स्टैंडर्ड में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ, जर्मनी की आबादी में हुई ज़बरदस्त बढ़ोतरी को खाना, कपड़े और घर मिल सका और जर्मनी से बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई।

1870 के बाद के दशकों में जर्मन माइग्रेशन की संख्या में सिर्फ़ जर्मन एंटरप्रेन्योर और व्यापारी भावना का अच्छा-खासा सरप्लस शामिल था, जो जर्मन मेहनत और जर्मन परफॉर्मेंस के पायनियर के तौर पर दुनिया में फैला।

ज़्यादातर जर्मन राइख की पूरी नेशनल इकॉनमी ने उन बुनियादी मांगों के साथ न्याय किया जो हम भी एक हेल्दी नेशनल इकॉनमी पर रखते हैं।

मांग पूरी तरह से पूरी हो गई थी। फिर भी, उस समय भी गहरी
हमारी इकॉनमी को हुए नुकसान को अलग-अलग तरीकों से दिखाया गया।

1. हमारे देश का फाइनेंस उसी समय और ज़्यादा कर्ज़ में डूब गया जब जर्मन लोग और ज़्यादा अमीर और ताकतवर होते गए, जब जर्मन इंडस्ट्रियल और ट्रेड की कुशलता के प्रोडक्ट्स ने दुनिया के सेल्स मार्केट पर कब्ज़ा कर लिया, उस समय हमारी अंदरूनी इकॉनमी एक के बाद एक सफलता की ओर बढ़ रही थी और मेडिकल और रहने की हालत साल दर साल बेहतर होती जा रही थी।

अब, ज़ाहिर है कि अगर कर्ज़ और बढ़ता जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी बात हमेशा इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि यह सच में पूरी तरह से बेतुका और बकवास माना जाना चाहिए अगर एक ऐसा देश जिसके नागरिक बढ़ती दौलत का मज़ा ले रहे हैं, उसी समय खुद को सेहतमंद और खुशहाल सरकारी फाइनेंस की हालत में न पाए। यह तब और भी हैरानी की बात होगी जब जर्मन राइख और फेडरल राज्यों को उनके रेलवे, पोस्ट और माइनिंग के कामों के साथ-साथ सरकारी जंगलों वगैरह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, इस बात से बिल्कुल अलग कि राइख और फेडरल राज्य अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के दम पर अपने नागरिकों की काफी टैक्स कैपेसिटी का दावा कर सकते थे।

2. एक और गहरा आर्थिक नुकसान हमारी खेती और शहरी रियल एस्टेट पर बढ़ता कर्ज़ था। इसके खिलाफ़ जो ज़मीन सुधार का आंदोलन चलाया गया, उसने पूरी समस्या के एक बहुत ज़रूरी हिस्से को सही ढंग से पहचाना, लेकिन बदकिस्मती से वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया।

3. हर तरह के क्रेडिट से हमारी इंडस्ट्री में महंगाई बढ़ने की बात ने भी तेज़ नज़र वाले लोगों को चिंता में डाल दिया होगा। ज़रूर, बढ़ती खुशहाली के समय में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंपनियाँ विदेशी पैसे लेने और उससे जुड़ी ब्याज की ज़िम्मेदारी को हल्के में लेती हैं, क्योंकि सच में काम और इनकम की बहुत ज़्यादा संभावना इन बोझों को उठाने की इजाज़त देती है।

लेकिन अगर आर्थिक संकट आ जाए तो बुरा होगा! तब ब्याज वाले क्रेडिट का इस्तेमाल अपने पूरे आर्थिक नुकसान के साथ सामने आता है।

इन सालों में स्टॉक कंपनी का जो रूप सामने आया, जिसमें कैपिटल को उससे जुड़े काम से असल में अलग कर दिया गया, यानी, पैसे के मुनाफ़े में शुद्ध कैपिटलिस्टिक हितों को क्रेडिटर्स की तरफ़ से, व्यक्तिगत एंटरप्रेन्योर के अच्छे सहयोग से और उसके अस्तित्व की उसके एंटरप्राइज़ के साथ पूरी पहचान से अलग कर दिया गया, उसने भी इसी तरह गहरे आर्थिक नुकसान के बीज बोए।

4. पैसे की दलाली करने वाली संस्थाओं, यानी बैंकों की बढ़ती ताकत से देश के सम्मानित दोस्त को चिंता होनी चाहिए थी। इकॉनमी के नौकरों से बैंक पूरी देश की इकॉनमी के बिना रोक-टोक वाले मालिक बन गए। एक खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंकों की बढ़ती ताकत के साथ हमारी देश की इकॉनमी में कोई तरक्की नहीं हुई, बल्कि इसके उलट, हमारी इकॉनमी जितनी खराब होती गई, बैंकों ने उतना ही खुद को बड़ा किया।

हम यहां इस डेवलपमेंट में और आगे नहीं जाना चाहते, पूरी तरह से फाइनेंशियल और मॉनेटरी इकोनॉमी की चर्चा में इस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम के ज़रिए बड़े नेशनल इकोनॉमिक नुकसान की चार वजहों का ज़िक्र बहुत ज़रूरी था क्योंकि पूरी इकोनॉमी का यही पहलू एक असली नेशनल इकोनॉमी के बिल्कुल उलट हो गया है, यानी फाइनेंशियल ताकतों की एकतरफ़ा लुटेरी इकोनॉमी।

जिस पर पैरासाइट से परेशान शरीर की इमेज अपने आप नहीं बनती, उसे मौजूदा हालात को बनाए रखने में बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए या इस शोषण करने वाली इकॉनमी के फ़ायदों पर निर्भर होना चाहिए। बदकिस्मती से, बहुत सारे आदमियों के साथ आखिरी बात होती है। इसीलिए इस मॉडर्न इकॉनमिक लुटेरे सिस्टम के खिलाफ़ अंदरूनी विरोध उस तरह से सामने नहीं आता।

यह बहुत बुरा है कि साइंस भी, और सच में वह साइंस भी, जिसे इन चीज़ों से पूरी ज़िम्मेदारी से निपटना है, कुछ अपवादों (ओथमार स्पैन65) को छोड़कर, अभी भी मौजूदा ब्याज वाली कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के जाल में फंसा हुआ है और खुद को उस पर निर्भर पाता है। आज की नेशनल इकॉनमी सच्चाई और सही ज्ञान की तरफ़ लीडर नहीं है, बल्कि नेशनल इकॉनमिक क्राइम की स्पोक्सपर्सन बन गई है।

सभी महान सत्य और ज्ञान को हर आम आदमी उनके ज़रूरी पहलुओं में समझ और सोच सकता है। इससे कन्फ्यूज़ न हों, यह बात भी सच है कि ऐसे बुनियादी ज्ञान तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। सच तो यह है कि ज्ञान खुद, यानी इंट्यूशन, एक तेज़ रोशनी की तरह है जो ज्ञान की हमेशा प्यासी आत्मा में चमकती है। हालाँकि, बाद में समझ का काम मुश्किल होता है, जिसमें बहुत मेहनत से ईंट पर ईंट जोड़कर, बहुत ध्यान से चीज़ों को चुनकर, पूरी सोच का ढांचा बनाना होता है ताकि पूरा काम सबको साफ़ दिखे।

ऐसे मामलों में इससे बड़ी तारीफ़ और क्या हो सकती है कि कभी-कभी कोई खुद ही ऐसे विचार सोचने लगे। इस तरह, जब मैं इस काम पर काम कर रहा था (गर्मियों में 1923), तो मुझे एक

---

65 ओथमार स्पैन (1878-1950) एक ऑस्ट्रियाई एंटी-सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे, जो एडम मुलर (1779-1829) की इकोनॉमिक थ्योरीज़ से प्रभावित थे – जिन्होंने एडम स्मिथ की मटेरियलिस्टिक लिबरल इकोनॉमिक्स का विरोध किया था। वह 1919 से 1938 तक वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जब नेशनल सोशलिस्ट्स ने उन्हें प्रोफेसर बनने से रोक दिया था।
ऑस्ट्रिया का एन्स्क्लस (एनेक्सेशन)। हालांकि स्पैन को NSDAP के राष्ट्रवादी नज़रिए से हमदर्दी थी, लेकिन कॉर्पोरेटिस्ट राज्य के बारे में उनके विचारों को नेशनल सोशलिस्टों का पूरा समर्थन नहीं मिला।

अब बूढ़े हो चुके ऑस्ट्रियन इंजीनियर डब्ल्यू. शोबर66 का बहुत बढ़िया काम, जिसमें ऑस्ट्रियन फाइनेंशियल और क्रेडिट की हालत के पूरे खराब डेवलपमेंट का अंदाज़ा 30 साल पहले ही बहुत साफ़-साफ़ लगा दिया गया था।

शोबर ने इस बात की ओर इशारा किया कि सिर्फ़ बुनियादी रूप से झूठे राष्ट्रीय आर्थिक सिद्धांतों से पूरी तरह हटकर ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के खतरनाक विकास को रोका जा सकता है –
दुर्भाग्य से इसमें ज़रा भी सफलता नहीं मिली।

उस समय इसका मुख्य कारण यह था कि शोबर के क्रिश्चियन-सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों ने, शुरू में तो बहुत जोश में सहमति जताने के बाद, आलसी बहाने बनाकर उससे मुंह मोड़ लिया: "अभी सही समय नहीं आया है", लेकिन असल में, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह क्रिश्चियन हाई फाइनेंस को सूट नहीं करता था।

बैंक ने बहुत पहले ही सेविंग्स कैपिटल और इकॉनमी के दावों और वर्किंग कैपिटल के बीच भरोसेमंद बिचौलिया बनना बंद कर दिया था। आज, बड़े बैंकों के डायरेक्टर और डेलीगेट सभी स्टॉक कंपनियों में बैठे हैं। बैंक की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और अब बैंक का इकॉनमी में क्या इंटरेस्ट है? उसका सिर्फ़ इतना इंटरेस्ट है कि कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट दे; और वह इससे बिल्कुल बेपरवाह है। वह इकॉनमी को सबसे सस्ती दरों पर पैसे के लोन के ज़रिए मज़बूत करने में अपना काम नहीं देखता, ठीक उस समय जब देश की इकॉनमी सबसे बुरे संकटों से खतरे में हो – हालाँकि यह उसका सबसे बड़ा काम होगा –; बड़े बैंक ठीक उसी समय क्रेडिट पैकेज और क्रेडिट नोटिस के साथ सामने आते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने काम के लिए पहले से क्रेडिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।

कोई आगे इस बात पर भी सोच सकता है: बैंक कौन सी ज़रूरत पूरी करते हैं? – कोई कहेगा: पैसे की ज़रूरत। बिल्कुल। लेकिन कैसे और किन हालात में? बेकर, मोची, फैक्ट्री मालिक, बिज़नेसमैन, सच में खाना, कपड़ा वगैरह की असली ज़रूरत पूरी करते हैं, और उन्हें उसके बदले में पैसे या पैसे ट्रांसफर के ज़रिए बराबर कीमत मिलती है।

इससे ज़रूरत पूरी हो जाती है, और फ़ैक्टरी मालिक वगैरह के पास खरीदारी, मज़दूरी देने और आगे बनाने के लिए फिर से वर्किंग कैपिटल हो जाता है। यहाँ हम एक इकोनॉमिक सर्कल पूरा होते देखते हैं। प्रोड्यूसर यूज़र की ज़रूरत पूरी करता है, पैसा एक्सचेंज बिज़नेस के बिचौलिए के तौर पर अपना सही काम पूरा करता है और प्रोड्यूसर के हाथों में इकॉनमी को फिर से मज़बूत करता है।

पैसे उधार देने के बिज़नेस के मामले में यह बिल्कुल अलग है। पहली बात, किसी भी बैंक पर अपना सामान – पैसा – देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, जैसे हर व्यापारी पर होती है। इसलिए यह पक्का कर सकता है कि वह सिर्फ़ उन्हीं को पैसा दे जो उसके लिए सही हों। इसके अलावा, ज़्यादातर मामलों में, बैंक ऐसी सिक्योरिटीज़ की मांग करता है जो लोन की वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती हैं, वह आगे एक डेट सर्टिफ़िकेट की मांग करता है जिसके अनुसार कर्ज़दार को अपनी सारी दौलत और कमाई के साथ कर्ज़ चुकाने का वादा करना होगा। दूसरे शब्दों में, पैसे देने के बदले बैंक अपने पावर-डोमेन एसेट्स में ऐसे पैसे जमा करता है जो लोन की रकम से कहीं ज़्यादा होते हैं; वह एक डेट सर्टिफ़िकेट भी देता है जिससे कर्ज़दार की काम से होने वाली इनकम उसके हाथ लग जाती है। लेकिन यह काफ़ी नहीं है: इस दोगुने, और कई गुना ज़्यादा सुरक्षित पैसे के लोन के लिए, बैंक खुद को ब्याज के रूप में और भी ज़्यादा पैसे लेने देता है जो समय के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह हमें यहाँ एक ऐसे तरीके से काम करना पड़ता है, जिसे आर्थिक रूप से देखें तो यह बिल्कुल भी फायदेमंद काम नहीं है, वापसी का पेमेंट – गिरवी रखना, कर्ज़ का सर्टिफ़िकेट – तुरंत दिया जाता है, और इसके अलावा, कर्ज़दार को एक और लगातार पेमेंट के लिए सहमत होना पड़ता है जो कुछ सालों में मिले हुए पैसे की कीमत से ज़्यादा हो जाता है, गिरवी रखने वाले के बिना।

66 वेन्ज़ेल शोबर (1846-1928) एक ऑस्ट्रियाई रेलवे इंजीनियर थे, जिन्होंने – वियना के प्रोफेसर जोसेफ़ श्लेसिंगर (1830-1901) की तरह – अपने आर्थिक लेखों में ऑस्ट्रिया की आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण यहूदी इंटरनेशनल फाइनेंस पर निर्भरता को बताया। उनके मुख्य कामों में डाई नोथ अंड इहरे उर्साचेन, 3 वॉल्यूम, वियना, 1880-82, और डाई वैलुटा-रेगलियरंग इन ओस्टररिच, 1892 शामिल हैं।

आज़ाद होना या कर्ज़ चुकाना। ऐसा फ़ाइनेंशियल बिज़नेस नैचुरली नेशनल इकॉनमिकली एक बेवकूफ़ी है, यह पूरी तरह से सूदखोरी है।

क्रेडिट का असली मतलब, यानी दूसरे के ज़्यादा इकोनॉमिक असर पर यकीन, असल में यह है कि बचाए हुए पैसे का मालिक यह नहीं देखता कि वह अपने पैसे को खुद फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करने की हालत में है, इसलिए वह किसी ऐसे इंसान के पास जाता है जिस पर वह भरोसा कर सके कि वह यह पैसा उसे सौंप सकता है और जो उसे गारंटी देता है कि वह मांगने पर उसकी सेविंग्स उसे पूरी और बिना कम किए वापस कर देगा। अगर लोन कर्जदार की इकोनॉमिक काम करने की क्षमता को इतना मज़बूत करता है कि वह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकता है, तो इसे सही या शुक्रगुज़ारी का काम माना जा सकता है अगर कर्जदार, पैसे वापस करने के अलावा, क्रेडिटर को अपने प्रॉफ़िट का एक निश्चित हिस्सा भी देता है। प्राइवेट मॉनेटरी और क्रेडिट इकॉनमी का यह कॉन्सेप्ट पूरे मिडिल एज पर राज करता है, यह चर्च के इंटरेस्ट के सिद्धांत का मुख्य हिस्सा था। इंटरेस्ट की मांग को सूदखोरी माना जाता था। आज, जिस इंटरेस्ट को चर्च सूदखोरी मानता था, वह असल में हमारी पूरी इकॉनमी का एक हिस्सा बन गया है – क्रेडिट का नेशनल इकॉनमिक मतलब एक नेशनल इकॉनमिक बकवास बन गया है। यकीनन, पैसे वाले आदमी के लिए ऐसी शिक्षा हमेशा के लिए बिना मेहनत के अमीर बनने का ज़रिया है। असल में इसलिए नहीं कि सोना – जैसा कि वह दिखना चाहता है – असल में एक ऐसी ताकत है जो खुद से पैसा बनाती है, एक सुपरह्यूमन चीज़ जो, दुनिया के खत्म होने के नियमों से आज़ाद होकर, हर चीज़ को हमेशा के लिए अपने काबू में कर लेती है, बल्कि इसलिए कि मॉडर्न फाइनेंशियल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इसे बस एक नियम के तौर पर महसूस किया जाता है कि हर तरह की फाइनेंशियल चीज़ में अपने आप में एक तरह का इंटरेस्ट होता है, जो कुछ हद तक पैसे में पैदा होता है, काम और पैसे के बीच के रिश्ते का यह सबसे भयानक उलटफेर है, जिसे एक नियम के तौर पर माना जाता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसके लिए इससे जुड़ी साइंस को बहुत सारे सही कारण बताने पड़ते हैं।

सिर्फ़ इसी तरह से पूरी नेशनल इकॉनमी को ज़रूरत पूरी करने और उसके साथ सबके लिए काम और खाना बनाने के उसके अकेले और नैचुरल काम से भटकाना और इसका गलत इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज कैपिटल के मालिकों की पर्सनल अमीरी के लिए एक ज़रिया के तौर पर करना मुमकिन था।

हमारे आंदोलन के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई की अब यह एक पसंदीदा चाल बन गई है कि हमारी नेशनल इकॉनमी के बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक शोषण के खिलाफ हमारे इस विरोध और सोशल जस्टिस की मांगों को पूरा करने वाली नेशनल इकॉनमी के लिए हमारी लड़ाई को प्रॉपर्टी और दूसरे तरह के कब्ज़े के बीच विरोध के तौर पर दिखाया जाता है, कि हमारी मांग "खुद के हित से पहले पब्लिक इंटरेस्ट" को कम्युनिस्ट बताकर बुरा-भला कहा जाता है। इसके खिलाफ, हमें लगातार नेशनल और इकोनॉमिक प्रोग्राम (द प्रोग्राम, पेज 35) के आर्टिकल 8 की ओर इशारा करना चाहिए:

"नेशनल सोशलिज़्म असल में प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता देता है और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर रखता है। सरकारी सुरक्षा"।

हालांकि, कानून का काम इसके संबंध में सीमाएं तय करना होगा। पूरे समाज की कीमत पर कुछ लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा जमा करना।

पॉज़िटिव तौर पर और खुद इकॉनमी के लिए, नेशनल सोशलिज़्म की भावना से पूरी इकॉनमी और उसके कामों के लिए एक मांग उठती है, "नेशनल और इकॉनमिक प्रोग्राम" की मांग नंबर 10: सभी जर्मन लोग जर्मन लोगों की आम भलाई और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक वर्क कम्युनिटी बनाते हैं।

यहीं से यह नैतिक मांग निकलती है कि हर जर्मन को अपनी ताकत के हिसाब से दिमागी और शारीरिक रूप से काम करना चाहिए, लेकिन उसका यह काम पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।

मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि यह एक नैतिक मांग है। इसलिए यह किसी संगठन की स्थापना का मामला नहीं है। सोवियत रूस में काम करने की मजबूरी शुरू की गई थी। कुछ अलग बात है

हमने मांग की थी कि हर जर्मन को पूरे देश की नागरिकता का अधिकार मिलने से पहले एक साल तक काम करना ज़रूरी होगा।

यह बात फिर से काफी अलग है कि हमारा मुख्य लक्ष्य उन सभी राष्ट्रीय साथियों के लिए चिंता-मुक्त बुढ़ापा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापे में मेहनत की है।
ठीक उसी तरह, अगर कोई नेशनल इकॉनमी लगातार लोन कैपिटल के ब्याज और टोल की ज़िम्मेदारी के बोझ तले दबी नहीं रहती, तो यह आसानी से हो सकता है, और होना भी चाहिए, कि वह इस तरह से बड़ा सरप्लस दे दे कि सभी नेशनल साथियों को एक सही और ज़रूरी बुढ़ापे की पेंशन – जो अधिकारियों की रिटायरमेंट सैलरी जैसी होती है – एक तय उम्र तक पहुँचने पर या समय से पहले काम से जुड़ी विकलांगता की हालत में मिल जाए।

मैं यह सोशल पॉलिटिकल मांग यहां इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस काम को पूरा करना पूरी नेशनल इकॉनमी के काम से जुड़ा है, क्योंकि यह वह बात है जो न सिर्फ वर्कर से शब्द के बड़े मतलब में लगातार कह सकती है: तुम्हें काम करना ही होगा!, बल्कि इसलिए भी क्योंकि, काम की मजबूरी के पीछे, यह कुछ सुकून देने वाली और मेलजोल वाली बात तय करती है - हर उस इंसान के लिए एक सुरक्षित बुढ़ापे की उम्मीद जिसने ज़िंदगी भर अपना काम किया है।

प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमारी इकॉनमी की नींव मानने के दायरे में यह बात भी आती है कि हर जर्मन को गुज़ारा करने और अपने काम से होने वाली इनकम और अपनी कमाई हुई दौलत को आज़ादी से इस्तेमाल करने की आज़ादी है ("नेशनल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम" का नंबर 11)। इस बुनियादी अधिकार को सीमित करने की इजाज़त सिर्फ़ कानून से ही दी जा सकती है, जिसके तहत इस गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए कि सिर्फ़ ऐसे काम को ही काम माना जाए जो कम्युनिटी के हितों के खिलाफ़ न हो। चेन-ट्रेड और मुनाफ़ाखोरी भी बेशक बहुत काम करवाते हैं; इसी तरह, एक चोर अक्सर अपने "काम" में घर बनाने वाले मिस्त्री से ज़्यादा पसीना बहाता है, लेकिन ऐसा "काम" असल में सिर्फ़ दूसरों की कीमत पर और उन्हें नुकसान पहुँचाकर एकतरफ़ा निजी फ़ायदा कमाने के लिए होता है। इसलिए ऐसा "काम" आम तौर पर नुकसानदायक होता है और इसलिए इसकी सज़ा बहुत सख़्ती से दी जानी चाहिए।

ऐसा साफ़ फ़ैसला किसी भी तरह से फालतू नहीं है, क्योंकि कानून की प्रैक्टिस से अक्सर और बहुत ज़्यादा साफ़ पता चलता है कि कितनी चीज़ों को वहाँ ईमानदार काम माना जाता है। ऐसी कई एक्टिविटीज़ भी हैं जो बॉर्डर-लाइन के बहुत करीब हैं, जहाँ यह कहना मुश्किल है कि यह काम अभी भी "पूरे काम" से मेल खाता है।

किसी भी हाल में, कानूनी तरीके बनाने होंगे ताकि ऐसी सभी एक्टिविटी या काम जो देश की सेहत के खिलाफ़ हैं, उन्हें दबाया जा सके। यही बात मुनाफ़ाखोरी और सूदखोरी के ज़रिए लोगों की परेशानी का फ़ायदा उठाने के बारे में भी सच है।

ऐसे कीड़े-मकौड़ों के लिए जो देश के दुश्मन हैं, हम मौत की सज़ा की मांग करते हैं। फाइनेंशियल
ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ सज़ा या जेल भी बेअसर है।

इसलिए, संक्षेप में, नेशनल सोशलिज़्म की इकोनॉमिक पॉलिसी, मुनाफ़े पर इकोनॉमिक्स के असल में झूठे फोकस को हटाने की दिशा में काम करेगी और इसी वजह से नेशनल इकोनॉमिक्स के एकमात्र सही और सही काम: डिमांड को पूरा करने को फिर से सम्मान देगी।

इससे व्यापारी, फैक्ट्री मालिक और ईमानदार बिजनेसमैन की इनकम और प्रॉफिट किसी भी तरह से खत्म नहीं होता; बल्कि, कमाई के लिए सही कोशिश करने में किसी भी तरह से मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, जब तक कि यह कोशिश पब्लिक के हितों के दायरे में हो।

इसलिए यह एक रेचक कार्रवाई का मामला है, और फिर जर्मन अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का मामला है, जो अपने रूप और प्रदर्शन, दोनों के मामले में बिना किसी आपत्ति के हो। इससे यह समझा जा सकता है कि "नेशनल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम" का नंबर 12 क्या मांग करता है: आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, और इस तरह खेती में भी, बड़े, मध्यम और छोटे व्यवसायों का स्वस्थ मेल बना रहे।

इसके साथ ही अलग-अलग सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए नेशनल सोशलिज़्म की बुनियादी स्थिति भी दी गई है।

नेशनल सोशलिज़्म एक ताकतवर देश की नींव और लोगों के पोषण के लिए किसानों को हर तरह से सपोर्ट और बढ़ावा देगा।

अगर प्रोग्राम के पॉइंट 17 में ऐसा क्लॉज़ है जो खास हालात में बिना किसी रोक-टोक के ज़मीन पर कब्ज़ा करने की बात करता है, तो इसका मतलब सिर्फ़ वही था, जैसा एडॉल्फ हिटलर ने 13 अप्रैल, 1928 को कहा था, "ज़रूरत पड़ने पर गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई या लोगों की भलाई के नज़रिए से मैनेज न की गई ज़मीन को ज़ब्त करने की कानूनी गुंजाइश बनाना। यह मुख्य रूप से यहूदी ज़मीन की सट्टेबाजी करने वाली कंपनियों के खिलाफ़ है"। इसलिए यह क्लॉज़ सिर्फ़ वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था।

नेशनल सोशलिज़्म को खास तौर पर एक हेल्दी कमर्शियल और मर्केंटाइल मिडिल क्लास की खुशहाली और आज़ादी भी बहुत पसंद है।

और तथाकथित भारी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के तरीकों में भी, नेशनल सोशलिज़्म के नज़रिए से, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है जिस पर एतराज़ किया जा सके। ठीक इसी बड़ी इंडस्ट्री ने हर चीज़ को एक मिसाल के तौर पर सही बनाया है, यानी, इसने बेहतर और आसान प्रोडक्शन के तरीके लाने के लिए कोई खर्च नहीं बचाया है। कंपनियों पर मौजूदा ज़्यादा बोझ –

साम्यीकरण का लक्ष्य रखना – जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हों जो सच में बेकार हों (हम यहां मुख्य रूप से अपने टैक्स और बीमा अधिकारियों को बनाए रखने की ज़रूरत के बारे में सोच रहे हैं, वगैरह) स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की कोशिशों के सीधे खिलाफ काम करता है।

नेशनल सोशलिज़्म के इन आर्थिक राजनीतिक कामों के आखिर में एक और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशनल काम है: "हर जर्मन के लिए एक साल की वर्क-सर्विस की शुरुआत"।

यहां भी यह एक गहरा नैतिक सिद्धांत है जो इस मांग को मजबूर करता है – कर्तव्य।

जो कोई भी राज्य की नागरिकता के अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे राज्य की सेवा भी करनी होगी, उसे अपने काम से और असल में बिना किसी मेहनताने के, यानी अमीर बनने की संभावना के, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और राज्य के प्रति वफादार साबित होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक अपने देश की सेवा करता है।

हम कम्पलसरी वर्क सर्विस के आइडिया में यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विस के आइडिया का एक पूरी तरह से सप्लीमेंट्री आइडिया देखते हैं।

जितना हम यह मानना चाहेंगे कि पहले के दो और तीन साल के सर्विस पीरियड के मुकाबले कुशल सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग को काफी कम किया जा सकता है, उतना ही हम यह भी ज़रूरी और सही मानते हैं कि हर युवा जर्मन को एक या ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिनसे वह देश की सेवा कर सके।

मशीन के राज और एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ़ मज़दूरों की क्लास दुश्मनी के और भी ज़्यादा खतरनाक सिद्धांत के तहत काम की क्वालिटी को लेकर ड्यूटी-कॉन्शसनेस को इतना नुकसान हुआ है कि इस फील्ड में एक जैसे सिद्धांतों के हिसाब से सख्त सरकारी डायरेक्शन में ट्यूशन पूरी तरह से ज़रूरी लगता है। ठीक इसी तरह, एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे सेंस में, ऐसे इंस्टीट्यूशन का स्वागत करेंगे और इसे किसी भी तरह से कॉम्पिटिशन नहीं मानेंगे। ऐसी वर्क आर्मी पहले से ही कॉम्पिटिशन नहीं हो सकती क्योंकि, अनुभव के अनुसार, राज्य की हर प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी पर उसके ऑफिशियल सिस्टम का बहुत ज़्यादा बोझ होना चाहिए, क्योंकि एक युवा, कम अनुभवी वर्कफोर्स को काम पर रखने और ट्रेनिंग देने में उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी खर्च हो जाती है।

दूसरी तरफ, इस साल के काम-सर्विस का काम मॉडल सरकारी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को टेक्नोलॉजी की सभी तरक्की से बेहतर तरीके से परिचित कराना होगा। अगर वे चाहें तो

जितना हो सके, वर्कफोर्स और मिलिट्री में काम कर रहे नेशनल साथियों की असली ज़रूरतों को पूरा करना।

इस तरह, बाकी नेशनल इकॉनमी के साथ सरकारी कॉम्पिटिशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, यह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फील्ड में प्राइस रेगुलेटर के तौर पर काम कर सकता है, जिसमें मार्केट प्राइस ऐसे हों जो आज़ाद ट्रेडर्स और आज़ाद एंटरप्रेन्योर्स के लिए ठीक-ठाक प्रॉफिट कमाने का बड़ा मौका छोड़ दें।

इस मैनिफेस्टो का काम और ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। फिर भी, उन्हें संक्षेप में बताना और समझाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सवाल का सही हल हमारे आर्थिक मनोबल को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसके अलावा पूरी इकॉनमी को इस बात से भी फ़ायदा होगा कि काम के प्रति फ़र्ज़ का विचार देश के प्रति एक नैतिक फ़र्ज़ के तौर पर जागेगा।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में राज्य-नागरिक की स्थिति के संबंध में
बिस्मार्क ने एक बार घोषणा की थी:

"हम खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने के लिए जीते हैं।"

यह नैतिक सिद्धांत राज्य और उसके संबंध में हमारी स्थिति के आधार पर भी है।
अर्थव्यवस्था।

राष्ट्रीय वित्तीय सुधार - धन और ऋण

राष्ट्रीय समाजवादी राज्य

'ब्याज का नियम।'

ब्याज-गुलामी को खत्म करने की मांग एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में बहुत नई बात है। सिर्फ़ यही बात नेशनल सोशलिज़्म का सबसे कड़ा विरोध करने के लिए बड़े ग्रुप्स के लिए काफ़ी होगी।

विरोधियों में सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जिन्होंने सच में मौजूदा इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की वजह से सब कुछ खो दिया है और जो इन विचारों में पले-बढ़े हैं, उन्हें अब भी पहले से खोए हुए खास अधिकारों के खोने का डर है। इस विरोध में सच में कोई जोश नहीं है, क्योंकि किसी भी अंदरूनी जोश की कमी कैपिटल पेंशन आइडियल में फंसे लोगों की खासियत है।

एक और ग्रुप उन लोगों का है जो लोन पर निर्भर हैं या कम से कम ऐसा मानते हैं।
ज़ाहिर है, इस ग्रुप को इंटरेस्ट देने की ज़िम्मेदारी खत्म होने का डर नहीं है, बल्कि उन्हें डर है कि जब तक सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता, उन्हें और वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा।

एक और ग्रुप शानदार नेशनल इकोनॉमिस्ट का है जो इस प्रॉब्लम का विरोध करते हैं।
ब्याज से मुक्ति उनकी राष्ट्रीय आर्थिक समझ का अल्फा और ओमेगा है।

एक और ग्रुप बुरे लोगों का है, जो असल में बेहतर सोच नहीं रखते, लेकिन जो पर्सनल या पार्टी के टैक्टिकल कारणों से, नेशनल सोशलिज़्म की इस बेसिक मांग का झूठे दावों और गलत बयानों से मुकाबला करते हैं।

कि इंटरनेशनल फाइनेंस के सर्कल, ब्याज के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक उसी पर
इस मांग को ध्यान में रखते हुए, हमारे सबसे कट्टर और कट्टर दुश्मन खुद ही साफ़ हैं।

बुरे इरादे वाले और प्रोफेशनल तौर पर दिलचस्पी रखने वाले विपक्ष को छोड़कर, दुश्मनी और भरोसे न करने वाले रवैये के मुख्य कारण हैं - अज्ञानता और दिमागी आलस, बेवकूफी।

यहां हमारा काम काफी ताकतवर विरोधियों से है, ऐसे विरोधियों से जिनके बीच कोई भी सिस्टम लागू करने की कोशिश करे, फेल हो जाता है, जो समझाने वाले एक्सप्लेनेशन के प्रेशर से जेली-फिश की तरह पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रेशर कम होते ही फिर से पुरानी सोच में लौट आते हैं।

तो, "ब्याज गुलामी" का क्या मतलब है? ब्याज गुलामी का मतलब है देश और लोगों का सुपरनेशनल फाइनेंशियल ताकतों पर ब्याज से जुड़ा कर्ज़। इसलिए यहाँ गुलामी के एक नए रूप की बात है, फाइनेंस के शासन की गुलामी की। यह गुलामी किसी भी तरह के शासन से ज़्यादा डरावनी और क्रूर है जो कभी भी निरंकुश राजाओं के शासन में था, क्योंकि यह बिना किसी इंसानी भावना के, बिना किसी तृप्ति के, सिर्फ़ फैलने और बड़ा होने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा से, और बेमिसाल ताकत के लालच से किया जाता है।

इस नियम के होने के लिए आम कहावत है: "पैसा दुनिया को चलाता है"।
लेकिन यहाँ पैसे का इस्तेमाल सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल पावर के लिए मास्टरी के सिंबल के तौर पर किया जाता है। पैसा खुद, मेटल और पेपर करेंसी, अपने आप में नैचुरली न तो अच्छा है और न ही बुरा, और किसी तरह का रूल नहीं करता। करेंसी के तौर पर पैसा, चीज़ों और सर्विसेज़ के लेन-देन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए फ़ाइनेंशियल पावर्स के रूल से सिर्फ़ पैसे के नज़रिए से निपटने की सभी कोशिशें शुरू से ही गलत हैं और बेअसर होने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस रूल के मामले में हम असल में छोटे मॉनेटरी सिस्टम के सवाल से नहीं बल्कि पावर के सवालों से निपट रहे हैं।

जैसा कि बताया गया है, पैसा ताकत का एक ज़रिया है, जो अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, यह सिर्फ़ इसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। यह बात कि इसका जानलेवा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी गलत इस्तेमाल, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

किसी भी तरह से इसके अनगिनत अलग-अलग और ज़रूरी काम के इस्तेमाल की संभावनाओं को बेअसर नहीं किया जा सकता। पैसे का भी, अगर इस्तेमाल काम के तरीके से किया जाए, तो देश की इकॉनमी पर फ़ायदेमंद असर पड़ता है। पैसे को देश की इकॉनमी का खून कहना गलत नहीं है। जब तक पैसा लेन-देन के तरीके के तौर पर अपने काम पर टिका रहता है, जब तक मिला या कमाया गया पैसा फिर से इकॉनमी में लगाया जाता है, तब तक यह देश की इकॉनमी पर कोई नुकसानदायक असर नहीं डाल सकता।

अब एक बात सामने आती है: वह है पैसे को सेविंग के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने की इच्छा। यह इच्छा अपने आप में पूरी तरह से सही है, इसके उलट, यह पूरी तरह से दुआ की जानी चाहिए कि सेविंग की भावना को फिर से सम्मान मिले अगर – हाँ, अगर – आज के हालात में सेविंग सच में मुमकिन हो। एक गैर-ज़िम्मेदार सरकारी फाइनेंशियल पॉलिसी के ज़रिए हमारे जर्मन पैसे का लंबे समय तक, खतरनाक डीवैल्यूएशन सच में सेविंग को बेवकूफी बना देता है, क्योंकि कुछ हफ़्तों या दिनों के बाद, पैसे की वैल्यू उसकी पहले की वैल्यू के एक हिस्से तक गिर सकती है। इसलिए, अगर पैसे को सेविंग मनी के तौर पर अपना काम पूरा करना है, तो उसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए।

क्योंकि जर्मन पैसा, कुछ वजहों से जिनकी हमें अभी जांच करनी होगी, अभी स्टेबल वैल्यू का नहीं है और स्टेबल वैल्यू का हो भी नहीं सकता, इसलिए जर्मन सेवर हर अस्थिर समय में स्टेबल वैल्यू वाले ऐसे पैसे की तलाश करता है। स्टेबल वैल्यू वाला ऐसा पैसा तथाकथित नोबल करेंसी, डॉलर, स्विस फ्रैंक और डच गुल्डेन, स्कैंडिनेवियाई लोगों का पैसा, वगैरह है, साथ ही कीमती धातुओं से बना मेटैलिक पैसा भी है।

लेकिन अब इकॉनमी की वर्किंग कैपिटल के तौर पर पैसे का नेशनल इकॉनमिक काम, स्टेबल पैसे जमा करने की इस इच्छा के उलट है। इस सवाल को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि पैसा अपने असल में "किए गए काम की निशानी" के अलावा कुछ नहीं है और होना भी चाहिए। आम तौर पर कहा जाता है कि 'पैसा लेन-देन का एक ज़रिया है' यह किसी भी तरह से गलत नहीं है, लेकिन यह सवाल को खत्म नहीं करता। पैसे का एक काम है, और सच में इसका सबसे ज़रूरी काम है, सामान के लेन-देन में बीच-बचाव करना। लेकिन यह काम दूसरी चीज़ों से भी पूरा होता है, जैसे चीनियों के चाय के पैकेट, नीग्रो लोगों के कौड़ी के गोले, वगैरह। आज सरकार जो पैसा देती है, और पैसे के बदले पैसे भी, उसका सबसे अंदरूनी मतलब यह है कि वे दूसरे लोगों के किए गए किसी काम की निशानी हैं – कोई इसे वाउचर भी कह सकता है। "किए गए काम" से हमें हर इकॉनमिक प्रोडक्ट, यानी कच्चे माल को भी पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि इनकी भी कमर्शियल या सेल्स वैल्यू तभी होती है जब उन्हें निकाला जाता है और बाज़ार में लाया जाता है। आपस में सामान के इस लेन-देन को आसान बनाने के लिए, असल में एक मुश्किल इकॉनमी में इसे मुमकिन बनाने के लिए, लेन-देन का एक ऐसा तरीका बनाना पड़ा जिससे सीधे तौर पर यह मुमकिन हो सके कि सिर्फ़ एक सामान बनाने वाला अपनी कई ज़रूरतों को इस लेन-देन के तरीके से पूरा कर सके, जिसकी आम तौर पर वैलिडिटी थी। एक मोची साल भर जूते और बूट बनाता है - लेकिन उसे अपनी रोज़ की रोटी, मीट, दूध, अंडे, कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं। बेकर, जिससे मोची अपनी रोटी खरीदता है, उसे साल में एक या दो जोड़ी बूट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसे पूरे साल की पेमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि हर कोई सिर्फ़ बूट से रोटी खाता है, उसे अपने मिलर और लकड़ी के सप्लायर को भी आटे और फ्यूल के लिए पेमेंट करना होगा, लेकिन वे भी और बूट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वे खुद पहले से ही दूसरे मोची से बूट और जूते लेते हैं।

लेकिन बेकर अपने आटे से मिलर को उसके आटे का पेमेंट नहीं कर सकता, बेकर को कम्युनिटी के लिए रोटी बनानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में: एक डेवलप्ड नेशनल इकॉनमी में, जिसमें लेबर का बहुत ज़्यादा बँटवारा हो, प्योर एक्सचेंज इकॉनमी बिल्कुल नामुमकिन है। एक एक्सचेंज बिचौलिया

इसलिए यह ज़रूरी है। सबसे आम तौर पर, यह एक्सचेंज बिचौलिया नेशनल इकॉनमी के प्रोडक्शन का एक आम तौर पर माना हुआ रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसे राज्य सुरक्षित रखे; इन रिकॉर्ड से कोई कुछ खरीद भी सके और हर किसी को इस एक्सचेंज मनी के बदले अपने कमर्शियल प्रोडक्ट देने के लिए मजबूर होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यह कहना भी गलत है कि पैसा किए गए काम का रिकॉर्ड है। ज़रूर, कोई इस पैसे को एक किए गए काम के तौर पर मान सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसके साथ एक इकोनॉमिक साइकिल पहले ही पूरा हो चुका है, बल्कि इसलिए कि यह पैसा असल में किए गए कई कामों का एक रिकॉर्ड है – ऐसे रिकॉर्ड जिनसे हर कोई अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों और दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जब यह ज़रूरत पूरी हो जाती है, और पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाता है, तभी पैसे का बेसिक साइकिल पूरा होता है। लेकिन अगर पैसा एक हाथ में जमा या बचा हुआ पैसा पड़ा रहता है, तो सिर्फ़ आधा एक्सचेंज, सिर्फ़ आधा साइकिल ही पूरा होता है। पैसे ने अभी तक अपना मकसद पूरा नहीं किया है, बल्कि, यह उस मकसद से हट गया है जिसके लिए इसे बनाया गया था और जिसके लिए यह मौजूद है। हमें असल में यह ऐलान करना होगा कि पैसे के नेशनल इकोनॉमिक काम में यह रुकावट, नेशनल इकोनॉमिक और नेशनल पॉलिटिकल वजहों से, नामंज़ूर है। साफ़ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मिली हर फ़ाइनेंशियल रकम तुरंत दे दी जाए, फ़ाइनेंशियल मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा दिया जाए कि हर आम आदमी अपने आर्थिक इंतज़ाम इस तरह कर सके कि वह अपनी महीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या साल में एक बार होने वाली बड़ी सेवाओं के लिए पैसे बचा सके, लेकिन इसे देश के हिसाब से पूरी तरह से नामंज़ूर घोषित कर दिया जाना चाहिए कि सरकार जो करेंसी समाज की भलाई के लिए देती है, उसे जमा किए गए पैसे के तौर पर पब्लिक सर्कुलेशन से हटा लिया जाए।

इसलिए वित्तीय प्रणाली के साथ खर्च करने का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, यानी, हासिल किए गए पैसे को वापस सर्कुलेशन में लाना।

यहां यह भी साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि इससे बचत करना किसी भी तरह से नामुमकिन नहीं हो जाता। बचत, सही समझा जाए तो, किसी भी तरह से लालची और कंजूस तरीके से पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि – अगर कोई बचत के आइडिया और बच्चों की देखभाल के पसंदीदा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहे –

, यह सामान बनाना और खरीदना, एक छोटा घर खरीदना या बनाना, कीमती चीज़ें खरीदना, कलेक्शन, किताबें, तस्वीरें, घरेलू सामान खरीदना, बिज़नेस को बढ़ाना और बेहतर बनाना, स्टॉक बढ़ाना वगैरह है, और यह सोना जमा करने से कहीं बेहतर "बचत" है।

ठीक इसी तरह हम जर्मन लोगों को इस सवाल पर दुनिया को देखने के नज़रिए की सबसे बड़ी शिक्षा लेनी पड़ी है। अभी बताई गई सही "बचत" ने खुद को सबसे अच्छा इनाम दिया है, पैसे पर ध्यान देने वाली झूठी बचत का कड़ा बदला लिया गया है।

इन मामलों में भी लोगों की यह बिल्कुल सही भावना कहानियों और परियों की कहानियों में बिल्कुल सही दिखाई देती है। जमा किया हुआ पैसा बेकार हो जाता है या गायब हो जाता है, या यह हमेशा आने वाली मुसीबतें लाता है। दूसरी ओर, हमेशा और हर जगह, जिसने अपनी मेहनत से "कुछ हासिल किया है" – और उस अच्छी सोच से हमेशा एक फलती-फूलती प्राइवेट इकॉनमी को समझता है, चाहे वह मर्केंटाइल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल –

इज्जत और सम्मान मिला है। दौलत का ऐसा विकास बिना किसी आपत्ति के होता है, यह पैसे की भावना के खिलाफ नहीं है, यह पूरी इकॉनमी के एक बढ़ते हुए सदस्य के तौर पर, सबसे अच्छे अर्थों में सामाजिक है।

फाइनेंशियल सिस्टम पर इन छोटी लेकिन ज़रूरी, क्योंकि ज़रूरी, बातों के बाद, आइए हम अपने सवाल के शुरुआती पॉइंट पर वापस आते हैं: "ब्याज-गुलामी से हमारा क्या मतलब है?"

अगर, उन लोगों के हाथों में पैसा रोककर रखा जाए जो पैसे के नेशनल इकोनॉमिक काम के बारे में नहीं जानते, या उन लोगों के हाथों में जो जमा किए गए पैसे को पावर के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोई रुकावट पैदा होती है, जो पैसा सर्कुलेशन में रहता है वह कम हो जाता है, पैसे की कमी होने लगती है। लेकिन जिनके पास पैसा है, वे अभी भी, नेशनल इकोनॉमिकली हेल्दी तरीके से, अपने पैसे को वापस सर्कुलेशन में नहीं लाते क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से लगातार ज़रूरतें पूरी कीं और घर बनवाए या दूसरी चीज़ें खरीदीं।

कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसलिए वे बिज़नेसमैन या फैक्ट्री मालिक से, जिन्हें अपनी कंपनी के मेंटेनेंस के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, उनके प्रोडक्ट नहीं छीनते, बल्कि वे उन्हें वह पैसा देते हैं जो उन्होंने गलत तरीके से रोक रखा है, नेशनल इकोनॉमिक नज़रिए से, एक खास टोल के बदले – इंटरेस्ट के बदले। नेशनल इकोनॉमिक दबाव

शुरू होता है.

नेशनल इकोनॉमिक वर्कर का सामान बनाने वाले – यानी बनाने वाले – और पैसे का रिश्ता एक झटके में उलट जाता है। पैसा, जो अपने असली रूप और अपनी खोज के हिसाब से, इकॉनमी की सेवा के लिए था, अचानक आज़ाद हो गया है और सामान के प्रोडक्शन पर दबाव डाल रहा है। फाइनेंशियल राज शुरू होता है। ज़रूर, प्राइवेट इकॉनमी खुश है कि वह कम से कम इस तरह से अपने काम चला सकती है, क्योंकि वह खुद को नेशनल इकॉनमिक रूप से प्रोडक्शन की सेवा करने के लिए मजबूर महसूस करती है। पैसा जमा करने वाले को नेशनल इकोनॉमिक वर्कर की नेशनल इकॉनमिक ड्यूटी की इस भावना से दोहरा फ़ायदा होता है: पहला, उसके पास एक कर्ज़ का सर्टिफ़िकेट बन जाता है – इस तरह एक कानूनी टाइटल – जिसके अनुसार कर्ज़दार अपनी पूरी दौलत के साथ उधार ली गई रकम को बिना कम किए चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होता है, ज़्यादातर मामलों में दौलत की दूसरी पक्की चीज़ें भी खास तौर पर गिरवी रखी जाती हैं, और दूसरा, कर्ज़दार को खुद को एक लगातार एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए गिरवी रखना पड़ता है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं।

इसलिए, गारंटी वाला क्रेडिट उन वजहों से नहीं दिया जाता जो क्रेडिट शब्द के असली मतलब से मेल खाते हों, यानी ज़्यादा इकोनॉमिक असर और परफॉर्मेंस कैपेसिटी पर भरोसा, बल्कि सिर्फ़ इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत का फ़ायदा उठाने के इरादे से दिया जाता है ताकि वह बिना किसी मेहनत के अपने काम से होने वाली इनकम का एक हिस्सा अपने लिए हासिल कर सके। क्रेडिट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ़ पैसे को "मुनाफ़े वाला" बनाने के लिए दिया जाता है। क्रेडिट का इस्तेमाल किन बिज़नेस के लिए किया जाता है, इससे क्रेडिटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता; अगर उसे इसमें दिलचस्पी है, तो ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि वह खुद को यकीन दिला सके कि उसका पैसा सुरक्षित है और सबसे बढ़कर, उस पर असरदार तरीके से ब्याज भी मिल रहा है।

आम तौर पर देखा जाए तो, बैंकों के ज़रिए चलने वाला क्रेडिट सिस्टम आज इस तरह से बना है कि आम तौर पर कैपिटलिस्ट, जिसके पास पैसा और क्रेडिट होता है, काम से पूरी तरह अलग रहता है। प्रोडक्शन की अलग-अलग ब्रांच से उसका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होता, जिसमें वह "अपने पैसे को काम करने देता है", जैसा कि पसंदीदा गुमराह करने वाली कहावत है। शेयर-होल्डर को "गिर्मेस", "पोगे", "वेसर", "रीबेक मोंटान", "ओटावी", "सालिट्रेरा", "स्टीउआ रोमाना"67 के बारे में क्या पता, उसे क्या पता कि इन कामों में क्या बनता है? उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस एकतरफ़ा इंटरेस्ट है कि शेयर बढ़ते हैं या गिरते हैं, और उसकी कैपिटल से कितना ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक कंपनियाँ या कैपिटलिस्टिक एक्टिविटी के दूसरे रूप (जॉइंट-स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी, यूनियन, वगैरह) आम तौर पर प्रोडक्शन के काम आते हैं या नहीं। मुख्य बात, एकमात्र तय करने वाली बात है – "प्रॉफिटेबिलिटी"। इस बात का एक सबूत बैंक के शेयरों की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। बड़े बैंक, और हर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, आम तौर पर सामान बनाने के मतलब में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं। यहाँ, बड़े बैंक सिस्टम में, इंटरेस्ट का आइडिया – यानी, प्रोडक्टिव काम से होने वाली इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ पैसे वाले के कब्ज़े में ट्रांसफर करने की संभावना, और सच में, पैसे वाले के लिए, पूरी तरह से बिना किसी मेहनत के – असली मज़ाक उड़ाता है। आज लगभग कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं बचा है जो किसी न किसी रूप में बैंक पर निर्भर न हो, जो पूरी तरह से इंटरेस्ट-कैपिटलिस्टिक तरीके से न चलाया जाता हो। पूरा नेशनल इकोनॉमिक काम बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज कैपिटल पर निर्भर है और उससे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है।

---

67 गिरमेस एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसे जोहान्स गिरमेस (1854-1912) ने शुरू किया था; वेसर एक शिप-बिल्डिंग कंपनी थी, रीबेक-मोंटान एक माइनिंग कंपनी थी, ओटावी एक माइनिंग और रेलवे कंपनी थी, सालिटेरा एक चिली की साल्टपीटर कंपनी थी, स्टीउआ रोमाना एक रोमानियाई तेल-रिफाइनिंग कंपनी थी।

बैंकों के मालिक – हाई फाइनेंस – प्रोडक्शन के भी मालिक हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि काम रुकता है या मार्केट में बहुत सारा कचरा भर जाता है। ऑर्गनाइज़्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए, डिमांड पूरी करना पूरी तरह से एक इत्तेफ़ाक की बात है।

मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम के इस इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक रूप के मामले में, हमें सबसे पूरी तरह से नेशनल इकोनॉमिक अनैतिकता से निपटना होगा, जिसमें फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम के मतलब को पूरी तरह से बिगाड़कर, इकोनॉमी के सेवक के तौर पर इकोनॉमी के पूरे मालिक की स्थिति में पहुंचा दिया गया है।

क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम गुलाम बन गए हैं और चालाकी से लालची, हमेशा चलने वाली यहूदी सूदखोरी की भावना दुनिया पर राज करती है। ज़बरदस्ती वसूली का एक ऐसा तरीका जो सिर्फ़ देश में पैसे रोककर, आर्थिक रूप से नाजायज़ तरीके से इमरजेंसी की बनावटी हालत बनाकर ही मुमकिन है। और आज इसे सही माना जाता है, एक ऐसा अधिकार जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इससे उसका दुनिया पर राज करने वाली बड़ी लोन कैपिटल से टकराव होता है।

ब्याज की गुलामी पूरी हो गई है!

यह इस बात से और बेहतर हुआ कि चलती-फिरती आत्मा की लुभावनी कलाओं ने फाइनेंशियल सिस्टम के रक्षक, राज्य को भी ब्याज की गुलामी में बांध दिया, ताकि वह भी, बंधे हुए हाथों से, इंटरनेशनल कैपिटल को अपना मालिक मान ले और खुद को नेशनल इकॉनमी के रक्षक के अपने असली काम से हटाकर, बड़े लोन कैपिटल के लिए ब्याज वसूलने वाले, बेलिफ की जगह पर जाने दे।

राष्ट्रीय वित्तीय अर्थव्यवस्था

अब हमारा खास काम है कि हम नेशनल फाइनेंशियल इकॉनमी के इस डेवलपमेंट का पता लगाएं।

यहां भी आज के तथ्यों के निर्धारण से शुरू करना सही तरीका होगा।

पश्चिमी कल्चरल सर्कल के देशों की नेशनल लाइफ़ में सबसे खास बात यह है कि सभी देशों पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। चाहे जीतने वाले हों या हारने वाले, सभी की नेशनल इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ का बोझ है, जो युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है।

ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़रूरी स्टैटिस्टिकल काम द स्टेट्समैन ईयरबुक है; यह ऑफिशियल नेशनल ईयरबुक अलग-अलग राज्यों को उनके पब्लिक कर्ज़ वगैरह की हालत का सही ओवरव्यू देती है।

इसके अनुसार, 31 मार्च, 1930 को इंग्लैंड का – यानी इंग्लिश वर्किंग क्लास का – इंटरनेशनल कैपिटल पर कर्ज़ 7,596,000,000 पाउंड स्टर्लिंग था, जिस पर सालाना ब्याज लगभग 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग था। इस रकम को जर्मन मार्क में बदलना काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस तरह से सबसे अच्छा पता चलता है कि ब्याज के इस सवाल में यह सबसे बड़े दायरे का एक इंटरनेशनल सवाल है।

फ्रांस पर अपने अंदरूनी और विदेशी इंटरेस्ट क्रेडिटर्स का लगभग 279 बिलियन गोल्ड फ्रैंक बकाया है।

डॉलर की पवित्र भूमि, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका, सार्वजनिक ऋण वहन करता है लगभग 16 बिलियन डॉलर का बोझ।

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हर जगह हमें देशों और लोगों के इंटरनेशनल कैपिटल के कर्ज़ की एक ही बुरी तस्वीर देखने को मिलती है। हर जगह देश की ज़िंदगी एक ही सवाल के आस-पास घूमती है: हम अपने लोन का ब्याज कैसे चुकाएं, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस, बड़े लोन कैपिटल के कर्ज़ का?

सभी राज्यों में फाइनेंस मिनिस्ट्री नए टैक्स सोर्स का इस्तेमाल करने में लगातार लगी हुई हैं, पार्लियामेंट नए टैक्स बिल पर महीनों तक सलाह देती हैं, लेकिन सारा विरोध बेकार है। इंटरनेशनल सूदखोर कैपिटल की शान और इंटरेस्ट पेमेंट पर उसके बनाए "कानूनी" दावों के आगे पार्लियामेंट और सरकारें बार-बार गिर जाती हैं और अपने लोगों पर पहले कभी नहीं हुए टैक्स के बोझ से ज़ुल्म करती हैं, बजाय इसके कि वे इस बड़े इंटरनेशनल फ्रॉड को साफ 'नहीं' कहकर खत्म करने की हिम्मत करें।

अन्याय कानून बन गया, स्वामी गुलाम बन गया।

हमारे गरीब देश में हालात कैसे हैं, यह हम हर दिन और हर घंटे महसूस करते हैं।

खून और लोहे से देश में एकता बनाने के बाद, जर्मनी का यह युवा काम का बड़ा आदमी ज़ोरदार और ताकतवर तरीके से उभरा। उसकी बिना थके मेहनत, उसकी क्रिएटिव सोच ने हमेशा नए आविष्कार किए। जर्मन एंटरप्रेन्योर की सोच और हिम्मत ने दुनिया के बाज़ारों पर कब्ज़ा कर लिया। हैरान करने वाली चिंता के साथ, रॉथ्सचाइल्ड्स और दूसरे बैंक के बड़े लोगों की फ्रेंच और इंग्लिश लोन कैपिटल, साथ ही अमेरिकी फाइनेंशियल लोगों, कान्स, लोएब्स, स्पेयर्स, वगैरह की ट्रस्ट कैपिटल को अपने मुनाफ़े में सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। जर्मन मार्क की वैल्यू, यानी जर्मन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सस्तापन, लगातार बढ़ रहा था, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि मार्क कब डॉलर की वैल्यू तक पहुँचेगा, जब तक कि इंग्लिश वर्ल्ड ट्रेड जर्मनी से आगे नहीं निकल जाता, हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया में जर्मन ट्रांसपोर्ट इंस्टॉलेशन, जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जर्मन सैनिटेशन ऑर्गनाइज़ेशन, जर्मन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जर्मन मिलिट्री तरीकों को एक मॉडल के तौर पर लिया गया, हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में जर्मन इंजीनियरों ने जर्मन काम करने की क्षमता के पायनियर के तौर पर रेलवे, पुल और सड़कें बनाईं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि लोन पर दी गई कैपिटल का प्रॉफिट

पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फाइनेंस से खतरा था। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस ने इंटरनेशनल फ्रीमेसनरी की मदद से जर्मनी को घेरने और झूठ और बदनामी के सभी तरीकों का इस्तेमाल करके जर्मनी को दुनिया का दुश्मन दिखाने का फैसला किया। – एडवर्ड VII इस शतरंज के खेल में बस एक मोहरा था। जर्मनी के खिलाफ, इंग्लैंड के साथ-साथ फ्रांस में भी राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठीं। विश्व युद्ध के राजनीतिक इतिहास की ओर इशारा करना यहां नहीं है, लेकिन यह किसी भी मामले में पक्का है कि जर्मनी का पक्ष, अपनी सैन्य ताकत के बावजूद, हार गया था, क्योंकि आम तौर पर एंटेंटे शक्तियों के साज़िश के खेल के खिलाफ राजनीतिक जवाबी खेल की कोई बात नहीं हो सकती (cf. रोसेनबर्ग, इंटरनेशनल फ्रीमेसनरी68)।

जर्मनी में जिस अकेले ग्रुप में अब भी विदेशी पॉलिटिकल सोच थी, यानी ऑल जर्मन69, उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हथियारबंद देशों के बीच यह ज़बरदस्त लड़ाई पॉलिटिकल कामयाबी के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद जर्मन मज़दूरों को इंटरनेशनल कैपिटल की ब्याज की गुलामी में फाइनेंशियल तौर पर डुबोना था। जर्मनी पर मिलिट्री तरीके से कब्ज़ा करना ज़ाहिर तौर पर फ्रांस का खास मकसद था, जर्मन नेवी को खत्म करना इंग्लैंड का खास मकसद था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के इन दोनों इंपीरियलिस्टिक मकसदों से ऊपर हमेशा इंटरनेशनल कैपिटल के दुनिया पर राज की कोशिश रही।

जब इस तरह देश एक-दूसरे को जंगली लड़ाई में चीर रहे थे और सबसे अच्छे लोगों का खून लड़ाई के मैदानों में बह रहा था, तब पूरी दुनिया के यहूदी लोग हरकत में थे। पूरे यहूदा के लिए कटाई का समय आ गया था।

हाई फाइनेंस ने वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस किया; दुनिया के सभी देशों में यहूदी लेखक इंटरनेशनल प्रेस के एडिटोरियल ऑफिस में बैठे और झूठ बोला और देशों को एक-दूसरे के खिलाफ नई कोशिशों के लिए उकसाया। इस तरह 26 देश सेंट्रल पावर्स के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए। पूरब से पूर्वी यहूदियों की एक धारा जर्मन ज़मीन पर बह रही थी; ये आगे बढ़े, मोलभाव किया, लूटा और अमीर बने, शहरों के फ्लैटों पर कब्ज़ा किया और जो कुछ भी मिल सका, उसे हासिल कर लिया। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनियों में जर्मन वर्कफोर्स की लूट और कुशासन का यह काम यहूदी जाति के लोगों ने संभाला, और यहूदियों ने खुद को आगे बढ़ाया और राज्य और अर्थव्यवस्था के सभी पदों पर पहुँच गए। इसी तरह, अंदरूनी निराशा को जानबूझकर यहूदियों, हासेस, डिटमैन्स, कोन्स, लक्जमबर्ग्स, बार्थ्स, फिर परवस-हेल्पहैंड्स, आइज़नर्स, लेविएन्स, ग्रैडनॉयर्स70 ने बढ़ावा दिया और उकसाया, जिसे महत्वाकांक्षी लोगों, मूर्खों और सत्ता के भूखे अपराधियों ने जर्मन लोगों के खिलाफ सपोर्ट किया।

---

68 अल्फ्रेड रोसेनबर्ग ने दास वर्ब्रेचन डेर फ्रीमानरेरी (1921) नामक कार्य प्रकाशित किया, साथ ही फ्रीमाउरेरिशे नेशनसोज़ियालिस्टिस्चे बिब्लियोथेक श्रृंखला में वेल्टपोलिटिक इम लिचटे डेर क्रिटिसचेन फ़ोर्सचुंग (1929), खंड 9.

69 ऑलड्यूशर वर्बैंड 1891 में बना एक जर्मन राष्ट्रवादी संगठन था। पहले विश्व युद्ध के दौरान, इस संगठन ने जर्मन विस्तारवादी लक्ष्यों को बढ़ावा दिया, और युद्ध के बाद, इसने जनरल एरिक लुडेनडॉर्फ (1865-1937) के इस दावे का समर्थन किया कि युद्ध में सोशलिस्ट और डेमोक्रेट ने जर्मनी को धोखा दिया था ("पीठ में छुरा घोंपा था")।

[70] ह्यूगो हासे (1863-1919) एक यहूदी सोशलिस्ट थे, जो 1911 में जर्मन ऑगस्ट बेबेल के साथ सोशलडेमोक्रेटिक पार्टी ड्यूशलैंड्स (SPD) के चेयरमैन बने। उन्होंने खुद को शांतिवादी बताया और जुलाई 1914 में एक बड़ी युद्ध-विरोधी रैली की। विल्हेम डिटमैन (1874-1954) SPD के एक जाने-माने सदस्य थे, जिन्हें फरवरी 1918 में बर्लिन आर्मामेंट वर्कर्स की हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद नवंबर क्रांति के दौरान और उसके बाद, डिटमैन ने जर्मनी की इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (USPD) के सदस्य के तौर पर एक एक्टिव पार्लियामेंट्री भूमिका निभाई। 1933 में, हिटलर के सत्ता में आने के बाद, डिटमैन स्विट्जरलैंड भाग गए। ऑस्कर कोहन (1869-1934) एक यहूदी पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने स्पार्टासिस्ट लीग के फाउंडर कार्ल लिबनेच्ट के साथ काम किया था, और वे एक पक्के ज़ायोनिस्ट थे। वह भाग गया

1933 में पेरिस। रोज़ा लक्ज़मबर्ग (1871-1919) एक यहूदी मार्क्सवादी थीं, जिन्होंने लिबक्नेच्ट के साथ मिलकर स्पार्टासिस्ट लीग की स्थापना की, जो बाद में जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी (KPD) बन गई। 1919 में फ्रीकॉर्प्स ने लक्ज़मबर्ग और लिबक्नेच्ट दोनों की हत्या कर दी थी। एमिल बार्थ (1879-1941) 1917 में USPD में शामिल हुए और जर्मन राजशाही के पतन के बाद नवंबर 1918 में बनी काउंसिल ऑफ़ डेप्युटीज़ ऑफ़ द पीपल (रैट डेर वोक्सब्यूफ़्रैगटेन) के छह सदस्यों में से एक थे (दूसरे सदस्य SPD के फ्रेडरिक एबर्ट, फिलिप शेइडेमैन और ओटो लैंड्सबर्ग और USPD के हासे और डिटमैन थे)।

अलेक्जेंडर परवस (पूर्व में इज़राइल हेलफैंड) (1867-1924) बेलारूस के एक यहूदी थे, जिन्होंने रोज़ा लक्ज़मबर्ग, लेनिन, ट्रॉट्स्की और के साथ अपने अलग-अलग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए "परमानेंट रेवोल्यूशन" की मार्क्सिस्ट स्ट्रेटेजी को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी।
यंग टर्क्स। मैक्स लेवियन (1885-1937) एक रूसी यहूदी बोल्शेविक थे जो 1913 में जर्मन नागरिक बन गए और सदस्य बन गए।

इस तरह जर्मन देश आखिरकार अंदर से टूट गया। जूडा का सितारा खून जैसा लाल हो गया। आखिरी देश जिसने इंटरनेशनल फाइनेंस और उसके जादू-टोने का डटकर विरोध किया था, वह टूट गया, उसने हथियार डाल दिए और वर्साय हुक्म के डरावने जुए के आगे झुक गया। हज़ारों ज़ख्मों से खून बह रहा था, लीडरविहीन था, असल में राजकुमारों को निकालने की वजह से नहीं, क्योंकि असल में ये ही असली लीडर के तौर पर पूरी तरह फेल हो गए थे, जर्मन देश को उसकी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री सरकारों ने उस खतरनाक वाक्य के साथ लीड किया जो ऐसे समय में हमेशा लागू हो सकता है, इस कहावत के साथ, "बुरे से बचने के लिए", लोन कैपिटल की ब्याज-गुलामी में।

अप्रैल 1919 में, लेवियन ने KPD के एक और रूसी यहूदी सदस्य, यूजेन लेवाइन (1883-1919) के साथ मिलकर बवेरियन सोवियत रिपब्लिक की स्थापना की। लेकिन इस 'सोवियत' एक्सपेरिमेंट को प्रेसिडेंट फ्रेडरिक एबर्ट ने रोक दिया, जिन्होंने म्यूनिख में व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्रीकॉर्प्स को काम पर रखा। मई 1919 में फ्रीकॉर्प्स ने लेवाइन को गिरफ्तार कर लिया और मार डाला, लेकिन लेवियन ऑस्ट्रिया और सोवियत यूनियन भाग गया, जहाँ 1937 में स्टालिन के ग्रेट पर्ज के दौरान उसे भी मार डाला गया।

जॉर्ज ग्रैडनॉयर (1866-1946) SPD के एक यहूदी सदस्य थे, जिन्होंने सैक्सोनी किंगडम के खत्म होने के बाद सैक्सोनी के पहले मिनिस्टर-प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। एक नरमपंथी सोशलिस्ट, उन्होंने म्यूनिख में एबर्ट की तरह, फ्रीकॉर्प्स की मदद से लाइपज़िग में कट्टरपंथियों को दबाने की कोशिश की। इसकी वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 1920 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

वर्साय हुक्म,
डावेस पैक्ट और यंग प्लान

वर्ल्ड वॉर का मकसद पूरा हो गया था: जर्मनी, दुनिया का सबसे मेहनती और काबिल देश, वर्ल्ड मार्केट में एक कॉम्पिटिटर के तौर पर हटा दिया गया, मिलिट्री तौर पर उसे हरा दिया गया, लीडरलेस बना दिया गया और झूठे मार्क्सिस्ट सिद्धांतों से बहकाया और ज़हर दिया गया, नैतिक रूप से खत्म कर दिया गया और कर्ज़ के पहाड़ के नीचे दबा दिया गया जिसे वह फिर कभी खुद से नहीं हटा सकता, बल्कि उसे हमेशा इंटरनेशनल कैपिटल के इंटरेस्ट का गुलाम बनकर काम करना पड़ा।

लंदन पेमेंट प्लान के अनुसार, जर्मनी को इसमें दिलचस्पी दिखानी पड़ी है-
इस पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का कर्ज़ था, और इस कर्ज़ में ब्याज भी जोड़ा गया था।

यह मज़ाकिया होता अगर यह इतना डरावना सीरियस न होता और अगर दुश्मन इसे इतनी बेरहमी से न लेते, ठीक शांतिवादियों की सभी आम बातों के उलट, "लेकिन यह इतना बुरा नहीं होगा", और "समझदारी की जीत होगी"। नहीं! यह जीत नहीं होगी! और इंटरनेशनल फाइनेंस जर्मनी को लगातार इस स्वार्थ की गुलामी में रखने के लिए सब कुछ करेगा। सिर्फ़ हम ही खुद को आज़ाद कर सकते हैं।

जर्मन देश की यह गहरी ट्रेजेडी है कि वह आम तौर पर अपने छोटे काम के दायरे में जितना भी कुशल हो, जब वह रोज़ाना के काम की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया की बड़ी घटनाओं के सामने खड़ा होता है, तो वह तुरंत अनिश्चित हो जाता है। यहाँ ईमानदार और सटीक जर्मन सारी हदें खो देता है, वह एक दूरदर्शी और उत्साही बन जाता है। "जर्मन प्रोफेसर", जो अपनी स्पेशलाइज़ेशन में शानदार काम करता है, दुनिया की चीज़ों का सामना करने पर, मज़ाकिया अखबारों का विषय बन जाता है, अपनी छतरी भूलने से लेकर विचारकों की लंबी-चौड़ी बातों तक; जर्मन ऑफिसर, अपने सैनिकों की बेहतरीन कुशलता पर भरोसा करते हुए, राजनीतिक प्रकृति की आध्यात्मिक मुश्किलों और विचारों की ताकत को कम आंकने लगता है, और इस तरह आखिरी सफलता को शक में डाल देता है; जर्मन ऑफिसर खुद को पूरी आबादी का नौकर समझने के बजाय लोगों का बॉस समझने लगता है।

तो, हम जर्मन लोगों के कैरेक्टर में यह खतरनाक बात हर जगह देखते हैं: जर्मन लोग स्पेशलिस्ट और सपने देखने वाले होते हैं। वे अकेले सभी खास फील्ड में किसी भी दूसरे देश के लोगों से ज़्यादा काबिल और मेहनती होते हैं, यहाँ तक कि किसी भी बड़े आइडिया के लिए जोश में आने और किसी आइडिया के लिए अपनी जान देने में भी पूरी तरह काबिल होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मामलों के बीच के दायरे में सही सॉल्यूशन देखने और उस पर पहुँचने में कम काबिल होते हैं।

पॉलिटिकल फील्ड में जर्मन लोगों में इस तरह की एक बुनियादी खासियत की झलक, उनमें देश के लिए भावना की कमी और उनकी पॉलिटिकल नाकाबिलियत है। एक आम जर्मन में कुछ हद तक बड़े ऑर्डर की समझ की कमी होती है; इसलिए, वह ज़्यादातर यह भी नहीं समझता कि ये कर्ज़ के आंकड़े ही असल में उसकी किस्मत हैं, कि ये आंकड़े, कि इस कर्ज़ को मानना और पैसे और चीज़ों से इस कर्ज़ को चुकाने की इच्छा और कोशिश ही जर्मन देश की पूरी बुरी हालत की असली वजह है।

लेकिन, वह यह कम ही देखते हैं कि इस जर्मन पेमेंट की ज़िम्मेदारी से फ़ायदा पाने वाले असल में दूसरे देश नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ इंटरनेशनल फ़ाइनेंस है।

लेकिन, इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए लोन का रीपेमेंट किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ इंटरेस्ट के लिए लंबे समय तक चलने वाली ज़िम्मेदारी ज़रूरी है। सिर्फ़ इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसने अपने फाइनेंशियल हिस्सों में वर्साय का हुक्म बनाया था, ने शुरू से ही बेसिक रकम इतनी ज़्यादा तय की कि रीपेमेंट के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन, बेसिक रकम में आख़िरकार कमी होने पर भी (किसी भी हालत में सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट में एक साथ बढ़ोतरी के साथ), जर्मनी हमेशा के लिए इंटरेस्ट की गुलामी में रहेगा।

हमारे गरीब मेहनती लोगों पर इस ब्याज का राज थोपना ही आखिरी मकसद था। विश्व युद्ध का लक्ष्य ज़्यादा फाइनेंस था और यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो गया है।

वर्साय हुक्म के ज़रूरी क्लॉज़ इतने डरावने हैं, वे इस इंटरेस्ट रूल की पूरी गंभीरता और नुकसान पहुंचाने वाली सख्ती को इतने साफ़ तौर पर दिखाते हैं, जो हमारे पास जो कुछ भी है और जिसके लिए हम काम करते हैं, उसे इंटरनेशनल फाइनेंस की पकड़ में लाता है कि मैं उन्हें नीचे कुछ हिस्सों में बता रहा हूँ:

आर्टिकल 231. मित्र देशों और उनसे जुड़ी सरकारें यह ऐलान करती हैं, और जर्मनी यह मानता है (!), कि जर्मनी और उसके सहयोगी देश, शुरू करने वाले (!) के तौर पर, उन सभी नुकसानों और क्षतियों के लिए ज़िम्मेदार हैं जो मित्र देशों और उनसे जुड़ी सरकारों और उनके सदस्यों को जर्मनी और उसके सहयोगियों के हमले की वजह से हुए युद्ध की वजह से हुए हैं।

हालांकि आर्टिकल 232 में यह बात बहुत ही निंदनीय तरीके से मानी गई है कि "जर्मनी के पास इन सभी नुकसानों की पूरी भरपाई करने के लिए काफी नहीं हैं", फिर भी यह मांग की गई है कि "इन सभी नुकसानों की भरपाई की जाए।"

आर्टिकल 233 कहता है: "नुकसान की सीमा का निर्धारण क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा किया जाएगा।

आर्टिकल 234 कहता है: "मुआवज़ा कमीशन समय-समय पर जर्मनी की पेमेंट कैपेसिटी को टेस्ट करेगा... लेकिन वह कमीशन में शामिल अलग-अलग सरकारों की मंज़ूरी के बिना कोई भी रकम माफ़ नहीं कर सकता"।

आर्टिकल 234 तय करता है: "जर्मनी मुआवज़े के दावे की आखिरी रकम तय होने से पहले ... 20 बिलियन मार्क सोने में (सोने, सामान, जहाज़ों, सिक्योरिटीज़ या दूसरे तरीकों से) देगा"

इसके अलावा जर्मनी एनेक्स II के आर्टिकल 12c में बताए गए बॉन्ड भी जारी करेगा।

और अब आता है, इस Annex II Art. 12c में सेक्शन VIII में, जिसे वर्साय शांति संधि कहा जाता है, जर्मनी का फाइनेंशियल पॉलिटिकल गला घोंटने के बारे में, जिसे आखिर में रखा गया है। यह Art. 12 अपनी सबसे ज़रूरी बातें इस तरह कहता है:

कमीशन के पास सभी अधिकार हैं और वह उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल करता है जिनकी गारंटी इस ट्रीटी में दी गई है।

आम तौर पर, कमीशन के पास हर्जाने के मामलों में सुपरविज़न और लागू करने की सबसे बड़ी पावर होती है। उसे नीचे दी गई शर्तों और तय नियमों का पालन करना होता है:

a) तय की गई मांगों की पूरी रकम का हर हिस्सा, जिसका पेमेंट सोने, जहाज़ों, सिक्योरिटीज़ या सामान या किसी और तरीके से नहीं किया गया है, उसे जर्मनी को कमीशन द्वारा तय शर्तों के तहत, बकाया रकम की मंज़ूरी के लिए बॉन्ड या किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन में उसी रकम को ट्रांसफर करके सुरक्षित करना होगा।

b) कमीशन समय-समय पर जर्मनी की पेमेंट कैपेसिटी को इवैल्यूएट करेगा और जर्मन टैक्स सिस्टम (!) की जांच करेगा, ताकि, सबसे पहले, जर्मनी के सभी रेवेन्यू, जिसमें उसके घरेलू लोन के इंटरेस्ट और डेब्ट सर्विसिंग के लिए तय रेवेन्यू भी शामिल है, का इस्तेमाल बेहतर होगा (!) उन रकमों के पेमेंट के लिए किया जाए जो उस पर टाइटल या

> मुआवज़ा, और दूसरा, यह पक्का करने के लिए कि जर्मन टैक्स सिस्टम ठीक (!) उतना ही दबाने वाला है जितना कमीशन में मौजूद किसी भी दूसरी ताकत का सिस्टम।

यह पैराग्राफ़ जर्मनी को हमेशा दबाए रखने पर शैतानी तरीके से फ़ोकस किया गया है, इसमें असल में यह संभावना है, किसी छोटे लुटेरे देश के ज़िक्र के साथ जिसमें बिना रोक-टोक वाले टैक्स लगाने का आदेश है, कि जर्मनी में भी वही टैक्स लगाए जाएं। लेकिन साथ ही यह बेरहमी से यह भी मानता है कि दूसरे देशों को भी उसी तरह कर्ज़ की गुलामी में रखा जाना चाहिए। और अब आता है बदनाम पैराग्राफ़ c.

> c) मित्र देशों और उससे जुड़े देशों में आर्थिक जीवन को फिर से शुरू करने और उसे आसान बनाने के लिए, कमीशन, जैसा कि आर्टिकल 232 में तय है, जर्मनी से अपनी गलती की गारंटी और मंज़ूरी के तौर पर पहला पेमेंट लेगा। इसमें होल्डर्स को बॉन्ड दिए जाएँगे, जो सोने में देने होंगे, और जो किसी भी तरह के टैक्स या चार्ज (!) से मुक्त होंगे, जो राइख या जर्मन राज्यों की सरकारों द्वारा लाए गए हैं या लाए जा सकते हैं। ये बॉन्ड किश्तों (!) में दिए जाएँगे और वह भी तीन किश्तों में, जैसा कि नीचे तय किया गया है: 1. 20 बिलियन गोल्ड मार्क्स तुरंत देने होंगे। 2. 40 बिलियन गोल्ड मार्क्स बॉन्ड में दिए जाएँगे, जिन पर 1926 से अमॉर्टाइज़ेशन के लिए 5% + 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 3. 5% ब्याज कवरेज के साथ, बॉन्ड में 40 बिलियन गोल्ड मार्क्स और देने की एक लिखित ज़िम्मेदारी तुरंत दी जाएगी।

यह क्लॉज़ पूरे वर्साय हुक्म का मूल है। हम जानते हैं कि लंदन अल्टीमेटम[71] ने न सिर्फ़ कम पेमेंट तय किए, बल्कि इसके उलट, पूरी रकम 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स तय की। आर्टिकल 16 में फिर साफ़ तौर पर कहा गया है: "1 मई 1921 से जर्मन सरकार को अपने कर्ज़ पर ब्याज देना होगा"। ब्याज दर 5 परसेंट तय की गई है।

इसके बाद आर्टिकल 17 आता है जो हर उल्लंघन का हल बताता है:

> आर्टिकल 17. अगर जर्मनी ट्रीटी के पिछले सेक्शन के तहत किसी कर्ज़ को चुकाने में देर करता है, तो कमीशन तुरंत हर पार्टिसिपेंट पावर को इस डिफ़ॉल्ट के बारे में बताएगा और साथ ही उसके खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देगा।

और अब पूरी ट्रीटी का सबसे अजीब क्लॉज़ आता है:

> आर्टिकल 18. जर्मनी वादा करता है कि वह उन उपायों का मतलब नहीं निकालेगा जिन्हें एलाइड और उससे जुड़ी ताकतें जर्मनी के जानबूझकर (!) न मानने पर अपनाना सही मानती हैं (और दुश्मनों की नज़र में क्या सही नहीं होगा?)। इन उपायों में इम्पोर्ट पर रोक और आर्थिक और फाइनेंशियल पाबंदियां शामिल हो सकती हैं और आम तौर पर (!) वे सभी उपाय (!) जो संबंधित सरकारों को हालात की मांग लग सकते हैं।

इस क्लॉज़ के साथ, ज़ाहिर है, हर तरह के, यहाँ तक कि सबसे क्रूर आतंक के लिए भी दरवाज़ा और गेट खुल गए हैं, और जर्मन सरकार ने आगे साफ़ तौर पर साइन किया है कि वह इस पर भी विचार नहीं कर सकती है।

---

71 जनवरी 1921 में इंटर-एलाइड रिपेरेशन्स कमीशन ने जर्मनी को हर्जाने के तौर पर 269 बिलियन गोल्ड मार्क्स देने का अमाउंट तय किया, जिसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड-जॉर्ज ने 5 मई 1921 को लंदन में जर्मन एम्बेसडर को छह दिन का अल्टीमेटम दिया। इसके मुताबिक, अगर जर्मनी 132 बिलियन मार्क्स (जनवरी के 269 बिलियन से कुछ अलग कैलकुलेशन) और वर्साय ट्रीटी के दूसरे नियमों को नहीं मानता, तो एलाइड देश रुहर इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे।

सबसे ज़्यादा ज़ुल्म, जर्मनों की हत्या, सबसे बेरहमी से निकालना, लूटपाट, तबाही, वगैरह "दुश्मनी वाले बर्ताव" के तौर पर!

एक क्रूर, बदला लेने वाले, और सख्त दुश्मन को जर्मन लोगों की यह लिखी हुई बात,

इसके अलावा, हमेशा के लिए परिकल्पित, क्योंकि अनुच्छेद 23 कहता है:

> कमीशन तब खत्म हो जाएगा जब जर्मनी और उसके साथी देश मौजूदा ट्रीटी को लागू करने के लिए या कमीशन के फैसलों के हिसाब से बकाया सारी रकम चुका देंगे और जब ये सारी रकम या उनके बराबर रकम हिस्सा लेने वाली ताकतों में बांट दी जाएगी।

यह जर्मनी की हमेशा की गुलामी है।

शायद हमारे पॉलिटिकल दोस्त और दुश्मन अब समझ जाएंगे कि इंटरेस्ट स्लेवरी का क्या मतलब है, शायद कोई यह समझ जाएगा कि इस डरावनी इंटरेस्ट स्लेवरी को तोड़ना हमारी मांगों के सेंटर में क्यों है। शायद कोई यह भी समझ जाएगा कि इस मांग के मामले में यह एक इंटरनेशनल सवाल क्यों है जो सबसे पहले आता है। यह जर्मनी के लिए बस किस्मत का सवाल है और दूसरे देशों के लिए भी यह रिकवरी के लिए सबसे अहम सवाल है।

इस इंटरनेशनल सवाल की तुलना में, बाकी सभी सवाल बेकार हैं, क्योंकि इंटरेस्ट स्लेवरी को तोड़े बिना प्रोडक्टिव देशों का बनना आम तौर पर मुमकिन नहीं है। अगर अभी शुरू हुई इंटरेस्ट स्लेवरी बनी रहती, तो भगवान मैमन गद्दी पर बैठ जाते। भगवान मर चुके हैं, देशों की आत्माएं मर चुकी हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस के इंटरेस्ट स्लेव के तौर पर दुनिया में इंसानी गंदगी फैली हुई है। पैसा दुनिया पर राज करता है।

वर्साय हुक्म के नियम ज़रूरी बातें थीं, जिन्हें 1924 में डावेस पैक्ट ने बदल दिया। अब महंगाई के डर के बाद जर्मनी की और लूट "ज़्यादा मज़बूत नींव पर" जारी रहनी थी। अच्छे फाइनेंस की वजह से हर तरह के भरोसे दिए जा सके, जिनमें सबसे ज़रूरी और दूरगामी हैं राइशबैंक और राइश रेलवे का डीनेशनलाइज़ेशन। सभी "सिल्वर क्लाउड" भविष्यवाणियों के बावजूद, जर्मन इकॉनमी गिरती रही, डावेस पैक्ट के हिसाब से पेमेंट करना नामुमकिन था, यह बात आखिरकार इसे लागू करने के कट्टर समर्थकों को भी समझ आ गई। डावेस पैक्ट की जगह यंग प्लान आया। माना जा रहा था कि इससे "राहत" मिलेगी। अब इसका अंत हो गया है।

आना।

नेशनल सोशलिस्ट लाइब्रेरी (कीमत 1.80 मार्क्स) की किताब 'ऑन द हॉरर्स ऑफ़ द डावेस पैक्ट' Vol.7 सबसे सटीक जानकारी देती है, जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट का रीप्रिंट और एक पूरी क्रिटिकल कमेंट्री शामिल है। इस सीरीज़ का Vol.13 यंग प्लान के मुख्य पॉइंट्स से जुड़ा है।

ऋण अर्थव्यवस्था

"अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो उसे यह पैसा अपने उन नागरिकों से उधार लेना होगा जिनके पास इतना पैसा है कि वे खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है, उसे इस पैसे को वापस करने के लिए ब्याज देना होगा, वरना उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे अपने लोन चुकाने में पहले ही काफ़ी मुश्किल हो रही है।"

यह बात पहले के सोशलिस्ट मिनिस्टर डॉ. डेविड72 ने बर्लिन में मेरे साथ एक बातचीत में कही थी। मैंने यह बात यहाँ जान-बूझकर रखी है क्योंकि यह हमारे ज़माने की सोच के कैपिटलिस्टिक तरीके को बहुत अच्छे से दिखाती है; कि वह सबसे बढ़कर एक मार्क्सवादी थे, यह बात पूरी दुनिया को एक खास अट्रैक्शन देती है।

अब मैं सैकड़ों चर्चाओं और लेक्चर से जानता हूँ कि ऊपर कही गई बात पूरी तरह से आज के इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक विचारों की दुनिया से ली गई है, इसलिए शायद ही कोई राज्य की इंटरेस्ट और कर्ज़ वाली इकॉनमी के इस एक्सप्लेनेशन के झूठ को महसूस करेगा, इसका सही जवाब ढूंढना तो दूर की बात है।

इसका एक बहुत ही आसान सा साइकोलॉजिकल कारण है, यानी ऊपर दिया गया एक्सप्लेनेशन, इकॉनमी के इंटरेस्ट-कैपिटलिस्टिक रूप के दायरे में एक आम आदमी की पैसे की ज़रूरत को कवर करने पर लागू होता है।

आम तौर पर प्राइवेट इकॉनमी की तरह, एक आम आदमी के लिए भी यह बात सही है: "अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो उसे यह पैसा उन लोगों से ब्याज पर उधार लेना चाहिए जिनके पास इतना पैसा है कि वे खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते"।

लेकिन हमें नेशनल फाइनेंशियल इकॉनमी के सवालों का जवाब प्राइवेट कैपिटलिस्टिक नज़रिए से देने से बचना चाहिए, बल्कि एक राजनेता की तरह जवाब देना चाहिए। मेरा मतलब है कि यह सच में एक बड़ी बदकिस्मती होगी अगर कोई इस प्राइवेट इकॉनमिक सोच को बिना सवाल किए नेशनल इकॉनमी में ट्रांसफर कर दे।

अपनी ताकत के साधनों, अपनी सॉवरेन पावर के साथ राज्य की तुलना किसी भी आम आदमी से नहीं की जा सकती। राज्य के पास तीन ताकतवर मौके होते हैं, जिनके ज़रिए वह अपनी सॉवरेनिटी के दम पर अपने कामों को पूरा करने की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये हैं उसकी सर्विस सॉवरेनिटी, उसकी कॉइनेज सॉवरेनिटी और उसकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी।

सर्विस सॉवरेनिटी का मतलब है राज्य का अपने नागरिकों को मुफ़्त सर्विस के लिए बुलाने का सॉवरेन अधिकार। व्यक्ति पर राज्य की यह सॉवरेनिटी अपने सबसे मज़बूत दायरे में ज़रूरी मिलिट्री सर्विस और उससे भी ज़्यादा युद्ध सर्विस में दिखती है। युद्ध के समय राज्य अपने नागरिकों से जो माँग कर सकता है, उसे देखते हुए सभी निजी बातों को पीछे हट जाना चाहिए। परिवार, पेशा, बिज़नेस और कमाई, जब राज्य अपने बेटों को झंडे के पास बुलाता है तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। लेकिन राज्य अपने नागरिकों को न सिर्फ़ युद्ध सर्विस के लिए बुला सकता है, बल्कि राज्य उन्हें बड़े आर्थिक कामों के लिए भी बुला सकता है, हमें सहायक सर्विस कानून याद है, जो दुर्भाग्य से, मिलिट्री सर्विस के बिल्कुल उलट, की गई सर्विस के लिए ज़्यादा और लगातार बढ़ती हुई पेमेंट देता था, जिससे जल्द ही मोर्चे पर तैनात सैनिकों, जिन्हें रोज़ाना अपनी मातृभूमि के लिए – बिना पेमेंट के – अपनी जान देनी पड़ती थी – और उन लोगों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई, जो मोर्चे के पीछे, अपनी मातृभूमि में, ज़्यादा सैलरी पर सुरक्षित, काम पर रखे गए थे। बस चलते-चलते, दूसरे देशों के मज़बूत प्रदर्शन जो सर्विस की ज़िम्मेदारियों पर आधारित थे, उन्हें भी याद किया जा सकता है: हमें चीनी दीवार का बनना, हमारे पुराने ज़माने के शहरों की घेराबंदी याद है।

इसलिए, असल में यह पूरी तरह से राज्य की संप्रभुता के अंदर होगा।

---

72 एडुआर्ड डेविड (1863-1930) ने जून से अक्टूबर 1919 तक वाइमर रिपब्लिक में आंतरिक मंत्री के रूप में काम किया।

पुराने हाथ और टीम सर्विस73 को फिर से शुरू करना और बढ़ाना और इस तरह मौजूदा ताकतों के इस्तेमाल के लिए उनके साथ बड़े आर्थिक कामों को हल करना।

राज्य की सिक्कों की आज़ादी ताकत का दूसरा सोर्स है जिससे राज्य सीधे अपनी पैसे की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। कोई भी राज्य के सिक्के ढालने या ट्रेजरी नोट जारी करने के अधिकार को नहीं मानता, असल में इसके अलावा, राज्य ने अपनी आज़ादी के दम पर हर मुमकिन सोर्स से पैसा बनाया है। कॉपर, निकल, आयरन, पोर्सिलेन, एल्युमिनियम और सबसे बढ़कर, कागज़ से। मुझे बस वह समय याद करना है जब हमारी राइख सरकार रोज़ाना 100,000,000,000,000 मार्क और उससे भी ज़्यादा नए कागज़ के पैसे जारी करना सही समझती थी। हम यहाँ इस सवाल पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे कि क्या यह सही और मंज़ूर था, हमें यहाँ सिर्फ़ यह कहना है कि राज्य असल में अपनी सिक्कों की आज़ादी के दम पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, और उसे "अपने उन नागरिकों से ब्याज पर पैसा उधार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनके पास अपने इस्तेमाल से ज़्यादा पैसा है"।

इसी तरह, राज्य की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी या टैक्स सॉवरेनिटी पर भी कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, और जो कोई भी इसे चुनौती देगा और एक व्यक्ति के तौर पर इसे प्रैक्टिकली चलाने की कोशिश करेगा, वह बेलीफ के रूप में राज्य के अधिकार को महसूस कर पाएगा। राज्य की फाइनेंशियल या टैक्स सॉवरेनिटी, यानी राज्य का अपने नागरिकों को फाइनेंशियल सर्विस के लिए बुलाने का अधिकार, उतना ही साफ़ और पुराना है जितना कि राज्य के स्ट्रक्चर। यह रूप सबसे नेचुरल और हेल्दी भी है, भले ही इस फील्ड में टैक्सेशन के सही मतलब को पूरी तरह बकवास में बदलना और टैक्स सिस्टम को सुपरनेशनल फाइनेंशियल पावर्स के पक्ष में लोगों को पूरी तरह लूटने का ज़रिया बनाना हमारे समय के लिए रिज़र्व रहा है। यहां भी टैक्स की परमिशन का सवाल हमें और परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य टैक्स के ज़रिए अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है, इस तरह, फिर से, एक ऐसे तरीके से जो प्राइवेट इकॉनमी के लिए खुला नहीं है, लेकिन जो कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन अपनाकर राज्य से अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरत को पूरी तरह से खत्म कर देता है।

ज़रूर, हर आम आदमी की तरह, सरकार के पास भी कर्ज़ लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने का एक और मौका होता है। लेकिन आम आदमी के लिए यह पहले से ही दोधारी तलवार है; लेकिन सरकार के लिए, अगर आसान और अच्छी जर्मन भाषा में कहें तो, यह सबसे बेवकूफी भरा काम है जो वह आम तौर पर कर सकती है। लेकिन यह न सिर्फ़ सबसे बेवकूफी भरा काम है, बल्कि आम हितों की रक्षा करने वाले सरकार के मिशन के लिए यह पूरी तरह से गुनाह है।

राज्यों की लोन इकॉनमी ने राज्यों को लगभग बर्बाद कर दिया है और उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंस के हाथों में सौंप दिया है, इसने देशों की दौलत को फाइनेंशियल ताकतों के हाथों में सौंप दिया है, और आज सरकारी लोन वह डरावनी जोंक हैं जिनसे देश खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं और अगर हमने ब्याज की गुलामी को तोड़कर इस डर को खत्म करने का पक्का इरादा नहीं किया तो वे बेबस होकर गिर जाएंगे।

इसके साथ हम नेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी के फील्ड के बीच में हैं, यानी एक ऐसे फील्ड में जिसमें आम जर्मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इतने सारे और बड़े नंबरों के साथ क्या करना चाहिए? आम नागरिक आम तौर पर बजट की बहस नहीं पढ़ता है, और फाइनेंशियल आर्ट के सीक्रेट रास्तों और गुमराह करने वाले तरीकों के लिए उसका इतना धार्मिक सम्मान है कि वह इन चीज़ों से पूरी तरह दूर रहना चाहेगा। अनजाने में, यह निश्चित रूप से इस बात से भी जुड़ा है कि हर व्यक्ति के अंदर राज्य की टैक्स सॉवरेनिटी के लिए थोड़ी सी भावना होती है और कोई भी नंबरों की याद नहीं दिलाना चाहता। जब टैक्स पेपर उसके घर आते हैं, तभी आज का आदमी यह कहता है कि ये चीज़ें असल में उसे बहुत परेशान करती हैं और वह हमेशा हर तरह की झूठी नेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी का शिकार होता है।

---

73 मध्य युग में किसानों से उनके मालिकों द्वारा मांगी जाने वाली खेती की सेवाएँ, चाहे हाथ से या जानवरों से

अब यह बहुत खास बात है कि असल में नेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी के मामले उतने साफ़ और रहस्यमयी नहीं हैं, जितने पहली नज़र में लगते हैं, बल्कि असल में वे इतने साफ़ और आसान हैं कि हर आम आदमी उन्हें कम से कम मोटे तौर पर समझ सकता है।

इसलिए, यह किसी बड़े संवैधानिक स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है कि राज्य के पास अपनी पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बताई गई संभावनाएँ बहुत अच्छी तरह से मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई जानता है और उसने अपने जीवन में अनुभव किया है कि राज्य की सेवा संप्रभुता का नेचर क्या है, और हर किसी को रोज़ाना राज्य द्वारा जारी किए गए कागज़ के नोट मिलते हैं, और कोई भी टैक्स से नहीं बचता है। इसलिए यह दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात होगी अगर राज्य अपनी पैसे की ज़रूरत को सिर्फ़ इन तीन तरीकों से पूरा करे।

लेकिन आम आदमी के लिए ये तीनों रास्ते खुले नहीं हैं, क्योंकि न तो वह अपने पड़ोसी को काम करने या टैक्स सर्विस के लिए बुला सकता है और न ही अगर वह खुद पैसे छापकर उन्हें सर्कुलेशन में लाने की कोशिश करे तो वह सुरक्षित रहेगा। उसके लिए असल में ब्याज पर कर्ज़ लेने का ही रास्ता है, अगर वह पहले से ही यह पक्का सोचता है कि वह दूसरों के पैसे से ही खुश रह सकता है और कर्ज़ लेने से बच नहीं सकता।

लेकिन यह कि सरकार आम तौर पर ब्याज वाले लोन लेने को ही सही मानती है – यानी कर्ज़, जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है और वह आज अपने दूसरे सॉवरेन अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ़ लोगों से लिए गए कर्ज़ वसूलने के लिए गलत तरीके से करती है, ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिनके लिए कोई सही वजह ढूँढ़ने की कोशिश बेकार में ही की जाती है। असल में इसकी कोई सही वजह नहीं है, बस यही बात है कि देश के फाइनेंशियल पॉलिटिकल मामलों में भी हमारी पूरी सोच एक प्राइवेट कैपिटलिस्टिक तरीके से चलती या बिगड़ती है। पब्लिक ओपिनियन के इतने आम पॉल्यूशन के साथ, सरकार की लोन पॉलिसी के लिए ऐसी लॉजिकल वजहें, जैसा कि मैंने बताया है, एक बहुत बड़ी, बल्कि बहुत ज़रूरी भूमिका निभाती हैं।

यहूदी ने इन मामलों में भी खुद को साइकोगॉजी का मास्टर साबित किया है। ऐसे मामलों में, ज़िम्मेदार नेताओं के सीधे करप्शन के बारे में तुरंत बात न करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, यह अंदाज़ा तो साफ़ है, और फिर भी ज़्यादातर मामलों में कोई करप्शन नहीं हुआ है, बल्कि फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम के मामलों में सिर्फ़ अनिश्चितता रही है, दूर की न सोचना और लापरवाही, जिसकी वजह से सरकारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन धीरे-धीरे लेकिन पक्का लोन के चक्कर में फँस गए हैं, जिससे उन्हें अब तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।

हालात के इस बदलाव में इस बात का बहुत ज़रूरी योगदान रहा है कि पहले तो रेलवे बिल्डिंग वगैरह जैसे बड़े पब्लिक कामों की फाइनेंसिंग को, जिनसे रेवेन्यू मिलने का वादा था, लोन के ज़रिए नुकसान न पहुंचाने वाला माना गया। फिर इस तरह तय किया गया: रेलवे या वॉटरवेज़ के रेवेन्यू से ब्याज तुरंत कवर किया जा सकता है, फिर हम सच में प्राइसिंग कंट्रोल में कर सकते हैं। अपने रिसोर्स से राज्य इतने बड़े काम एक बार में अपने खजाने से नहीं कर सकता, इसलिए वह शुक्र है कि बैंकों की दी गई क्रेडिट मदद मान लेता है। इससे सरकार को राज्य की पार्लियामेंट में नए टैक्स मंज़ूर करने की परेशानी नहीं होती, राज्य के लिक्विड रिसोर्स पर दावा नहीं किया जाता, और रेलवे आसानी से सरप्लस से ब्याज चुका सकता है। लोन कैपिटल की लुभावनी कला, जो खुद पैसे से कुछ नहीं कर सकती अगर उसे कोई ऐसा न मिले जो उससे पैसे छीन ले और उसे ब्याज भी दे, काले को सफेद करने में कामयाब रही और राज्य को खुद प्राइवेट कैपिटल के लिए ब्याज वसूलने वाला बना दिया।

लेकिन, अपनी ज़िम्मेदारी समझने वाली सरकार या पार्लियामेंट की तरफ़ से सबसे आसान आर्थिक सोच से भी ये बातें सामने आनी चाहिए थीं: अगर कोई विदेशी पैसे से रेलवे बनाता है और उसे हर साल सिर्फ़ 5% ब्याज देना पड़ता है, उससे जुड़ी हर चीज़ के साथ, तो वह 20 साल में पूरी रकम चुका देता है, जो पहले ही 40 साल में चुका दी जाती है।

पहले ही दो साल हो चुके हैं और फिर भी वही कर्ज़ बाकी है। ये बहुत ज़्यादा रकम, जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा है, असल में एक बार फिर इनडायरेक्टली लोगों से, पूरी आबादी से ही जुटाई जानी चाहिए, जिन्हें इन इंटरेस्ट अमाउंट के हिसाब से ही बढ़ाए गए रेलवे ट्रांसपोर्ट टैरिफ़ का पेमेंट करना होगा। लोगों के लिए एक बार बड़ी रेलवे लेवी का अनाउंसमेंट करना बेहतर होता, या होता। तब ये लेवी, बेशक, कुछ सालों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होतीं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और रेलवे बहुत जल्द सरकार की सच में कर्ज़-फ़्री एसेट बन जातीं, जिससे बाद में उसे बड़ी सालाना कमाई का भरोसा मिलता। लेकिन यह पुरानी कहानी है कि कोई कुत्ते की पूंछ को थोड़ा-थोड़ा करके काटना पसंद करेगा क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे बहुत कम दर्द होगा। ज़ाहिर है, इसका उल्टा सच है। ऐसे नेशनल काम की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट असल में आबादी को ही चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर उन्हें लोन पर डेवलप किया जाता है, तो इसके साथ ही इंटरेस्ट भी ज़रूर जुड़ जाता है, जो सालों में कर्ज़ से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए, ऐसे पब्लिक कामों को लोन से फाइनेंस करना पूरी तरह से फाइनेंशियल बेवकूफी है। हम पहले ही बता सकते हैं कि सरकार को लोन के पागलपन से कैसे बचाया जा सकता है: कोई भी सरकार को, उदाहरण के लिए, ऐसे प्रोडक्टिव कामों के लिए, क्रेडिट नोट, स्टेट ट्रेजरी क्रेडिट नोट जारी करने और उससे कामों का पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में, जहाँ महंगाई का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नए टोकन की भी नई वैल्यू होती है, सरकार का ऐसा पैसा बनाना एक ही झटके में सारी मुश्किलें हल कर देगा और सरकार और लोगों को प्राइवेट कैपिटल के ब्याज वाले कर्ज़ से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा।

हमें इस प्रॉब्लम पर कहीं और डिटेल में बात करनी होगी। एक कुशल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चीज़ों को इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि इतने बड़े काम स्पेशल टैक्स के साथ-साथ राज्य के दूसरे रेवेन्यू सोर्स के इस्तेमाल से और सिर्फ़ कुछ नए नोट जारी करके किए जाएं। यह पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक तभी होगी जब राज्य के बाकी सभी खर्चे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन वगैरह के लिए तथाकथित अनप्रोडक्टिव खर्चे, राज्य के कमर्शियल एंटरप्राइज के सरप्लस से पूरे किए जा सकें।

रेलवे, पोस्ट, वगैरह की मौजूदा घाटे वाली इकॉनमी को देखते हुए, यह एक अजीब बात लग सकती है, लेकिन हम ऐसी संभावनाओं से बहुत दूर नहीं थे, जैसा कि मैंने 1919 में सुडड्यूश मोनात्शेफ़्टे (फ़रवरी) में अपने पहले पब्लिकेशन, "अब क्या?" में "रेडिकल तरीके" हेडिंग के तहत दिखाया था। सिर्फ़ प्राइवेट कैपिटल के लिए राज्य की ब्याज की ज़िम्मेदारी ही हमें नेशनल फ़ाइनेंशियल इकॉनमी की इस आदर्श स्थिति से अलग करती थी। उस समय पहले से ही यह भ्रम था कि जब राज्य को पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसे बस ब्याज पर खुद में पैसा डालना चाहिए, इसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया।

यह साफ़ है, और हर कोई मेरी बात समझ सकता था, कि जब सरकार कुछ करना चाहती है, तो वह किसी भी तरह से विदेशी पैसे, यानी कर्ज़ लेने के लिए तैयार नहीं होती है, कि वह, उदाहरण के लिए, काम और टीम-सर्विस की मांग कर सकती है और आखिर में ऐसे लक्ष्यों के लिए सरकारी खजाने से क्रेडिट नोट जारी करना बिना किसी शक के सही होगा, ताकि लोगों पर बोझ डाले बिना इन कामों को शुरू किया जा सके। इस तरह के तरीके का यह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि ऐसे कामों को शुरू से ही हर ब्याज और टोल-देन से आज़ाद कर दिया जाएगा; काम तुरंत मुफ़्त और कर्ज़-मुक्त सरकारी संपत्ति बन जाएंगे। कामों से होने वाली कमाई से जारी सरकारी खजाने के वाउचर को वाकई थोड़े समय में भुनाया और खत्म किया जा सकता है; ऐसे कामों से होने वाले प्रोडक्ट, या माल और यात्री ट्रांसपोर्ट की कीमतें, काफ़ी कम हो सकती हैं। इस तरह, आम तौर पर पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी सर्विस दी जा सकती थी, सरकार को काफ़ी बड़े रेवेन्यू सोर्स मिल सकते थे जो पूरे राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा काम के होते और सरकार खुद को ज़्यादा फाइनेंस से भी काफ़ी आज़ाद बना देती। लेकिन यह भी होना चाहिए था

हाँ। क्योंकि राज्य फाइनेंशियल सिस्टम का मालिक है, हाई फाइनेंस का नहीं, यानी भविष्य के नेशनल सोशलिस्ट राज्य में ऐसा ही होगा।

यह असल में एक साइकोगॉजिक फ्रॉड वाली चाल है कि बैंक ऐसे साफ़ और खुद-ब-खुद साफ़ सोच को आने नहीं दे पाए हैं, जिन्हें – एक बार कह देने के बाद – अब गलत साबित नहीं किया जा सकता, और ऊपर बताए गए वाक्य से राज्य और अर्थव्यवस्था को कन्फ्यूज़ कर दिया है और उन्हें कैपिटल की ब्याज गुलामी में फंसा दिया है।

मुझे पता है कि, भले ही ये बातें अब दिन की रोशनी की तरह साफ़ हैं, फिर भी मेरे कई रीडर्स अपनी अच्छी इंसानी समझ पर भरोसा नहीं करते और बस यह मानना नहीं चाहते कि ऐसी बेवकूफी कैसे हो सकती है और इसके बजाय मान लेते हैं: "यह सही नहीं हो सकता, हमारे नेता इतने बेवकूफ नहीं हो सकते – लेकिन मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता"। फाइनेंशियल पॉलिटिकल मामलों में सरकार की इतनी साफ़ नाकाबिलियत के बारे में फैसला न कर पाने की यह बात, सरकार के कदमों पर पहले से मौजूद गलती ढूंढने और बकवास करने के उलट है, और इस बात के भी कि यह उन मामलों का सवाल है जो हर किसी की जेब पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं।

इन लोगों के लिए मैं एक और नज़रिया रखना चाहूँगा जो है
प्रांतीय या रीच संसद के ज़रिए क्रेडिट मंज़ूरी के तरीके से जुड़ा हुआ।

ऐसे बड़े सरकारी कामों पर पार्लियामेंट में अच्छी तरह से बातचीत होती है। लंबी बहस के बाद आखिरकार क्रेडिट को "मंज़ूरी" मिलती है। आम सरकारी नागरिक अब मानता है कि अब सब कुछ ठीक है और सरकार, जो वाकई इतनी अमीर और ताकतवर है, उसके पास पहले से ही मंज़ूर किए गए लाखों डॉलर हैं। बहुत चालाक लोग शायद अब भी अपने कान पीछे खुजलाएंगे और खुद से कहेंगे, 'इसका मतलब है फिर से नए टैक्स'। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हिम्मत से यह कह सकता हूं कि, शुरू किए गए लोगों को छोड़कर - जिनके न तो नुमाइंदों और न ही मंत्रियों को शामिल होने की ज़रूरत है, बल्कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ एक को यह बात साफ़ हो जाती है कि प्रांतीय या रीच पार्लियामेंट में इस बड़े क्रेडिट की मंज़ूरी का मतलब सिर्फ़ इस "क्रेडिट" को किसी और तरीके से ब्याज पर खुद को उधार देने की इजाज़त देना है। इस तरह यह "संसद के ज़रिए क्रेडिट की मंज़ूरी" सिर्फ़ संबंधित मंत्री को बड़े बैंकों से ब्याज पर यह क्रेडिट लेने का अधिकार देती है। – , इस तरह "संसद के ज़रिए क्रेडिट की मंज़ूरी" स्वाभाविक रूप से एक मज़ाक, एक कॉमेडी बन जाती है, क्योंकि पूरी आबादी - जिसे आखिर में कैपिटल और ब्याज का भुगतान करना ही होगा - असल में "क्रेडिट" देने की स्थिति में भी नहीं थी, नहीं, इसे पहले बड़े लोन कैपिटल से बनाया जाना चाहिए।

असल में, सबसे लॉजिकल और नेचुरल बात यह होगी कि, पार्लियामेंट से क्रेडिट अप्रूवल के मामले में, साथ ही और ऑटोमैटिकली यह भी अप्रूवल होगा कि अब स्टेट बैंक भी लागू करने वाली अथॉरिटीज़ से पेमेंट ऑर्डर के आधार पर संबंधित एंटरप्रेन्योर्स को अप्रूव्ड रकम का पेमेंट करेगा या ऑथराइज़ करेगा।

क्रेडिट मंज़ूर हैं, ज़रूरी करेंसी के लिए कुछ तो करना ही होगा; इसलिए यह बेवकूफी है अगर – जैसा कि आजकल आम बात है – पहले लोन माफ़ कर दिया जाए और फिर सही "मंज़ूर" क्रेडिट को कैपिटलिस्ट एक तरह से दूसरी बार दे दें।

अब कोई यह कह सकता है कि सरकार से सरप्लस पैसा इसी तरह निकाला जाता है और इसका देश की आम फाइनेंशियल हालत पर अच्छा असर पड़ता होगा, कि इस तरह का क्रेडिट मैनेजमेंट महंगाई कम करने वाले तरीके से काम करेगा। लेकिन यह बात सच नहीं है और असल में ऐसे कारणों से है जिनका कोई भी बैंकिंग एक्सपर्ट विरोध नहीं कर सकता। यह माना जा सकता है कि ऐसे ड्राफ्ट और ऐसे लोन के पेमेंट का एक बहुत छोटा हिस्सा कैश में दिया जाता है, यहाँ सवाल उन छोटे बचत करने वालों के ग्रुप का है जो ऐसे ड्राफ्ट लेकर बैंक जाते हैं, जिन्होंने सौ या हज़ार मार्क बचाए हैं जिन्हें वे अब एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक ऐसे जादुई कागज़ में जिससे हर साल सिर्फ़ एक टुकड़ा काटना होता है ताकि एक तय रकम मिल सके और सर्टिफिकेट की कीमत कम न हो। लेकिन इस तरह से बैंक में आने वाला पैसा काफी

बहुत कम। इसके अलावा, जिन बैंकों में ऐसे पैसे जमा किए जाते हैं, वे अपनी तरफ से इन कैश अमाउंट को सरकारी खजाने में बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ऐसे ड्राफ्ट अमाउंट का ट्रांसफर सिर्फ ट्रांसफर या क्लियरेंस के ज़रिए किया जाता है।

लेकिन ऐसे लोन पर सभी बड़े ड्राफ्ट कैपिटलिस्ट शुरू से ही अपने बैंकों में, बिना कैश के ट्रांसफर के ज़रिए या बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के प्रोसेस से करते हैं।

वगैरह।

इसलिए असल में, सरकार के हाथ में कोई कैश नहीं आता है और अगर उसे मिलता भी है, तो उसे अपने कामों को पूरा करने के लिए तुरंत दे देना चाहिए। इसलिए यह माना हुआ फ़ायदा मौजूद नहीं है। इसके उलट, यह होता है: जैसा कि हम जानते हैं, सरकार उधार दी गई रकम के लिए तथाकथित सिक्योरिटी सर्टिफ़िकेट या बॉन्ड जारी करती है। सरकार के ये बॉन्ड बारीक, या इतने बारीक नहीं, छपे हुए कागज़ होते हैं जिनमें मिली रकम पर सभी सरकारी सुरक्षा उपायों वाला एक कर्ज़ का दस्तावेज़ होता है, और इसके अलावा ब्याज़ चुकाने की तारीखों का ज़रूरी फ़ैसला होता है और, अपनी कूपन-शीट पर, वे कूपन होते हैं जिनके आधार पर सरकार कूपन-शीट में लिखी रकम पर तिमाही, छमाही या सालाना ब्याज़ देने का वादा करती है।

इसके अलावा, इस कूपन-शीट में एक और तथाकथित रिन्यूअल सर्टिफिकेट (टैलोन) जोड़ा जाता है जो मालिक को एक नई कूपन-शीट पाने का अधिकार देता है, अगर पहली कूपन-शीट कुछ सालों के बाद एक्सपायर हो गई है।

अब ऐसा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो राज्य जारी करता है, जिसके लिए राज्य अपनी पूरी दौलत कैपिटल और इंटरेस्ट के साथ ज़िम्मेदार होता है, इसका मतलब है कि मालिक के हाथ में खरीदने की क्षमता ज़रूर होती है। ऐसे राज्य सर्टिफिकेट का मालिक इन सर्टिफिकेट से कभी भी अपने लिए कुछ खरीद सकता है, चाहे वह इन सर्टिफिकेट को सीधे पेमेंट के तौर पर दे या पहले इन सर्टिफिकेट को स्टॉक-एक्सचेंज या अपने बैंकर को बेचकर उससे मिले पैसे से कैश पेमेंट करे।

अब इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार द्वारा नए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब है ज़्यादा खरीदने की क्षमता बनाना – यह सही है या सही, इस बारे में अभी हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है – ठीक ऐसा ही तब होगा, उदाहरण के लिए, अगर सरकार नए कागज़ के पैसे छापे। फ़र्क यह होगा कि एक मामले में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं जो कर्ज़ के अलावा, सरकार पर लंबे समय तक ब्याज की ज़िम्मेदारी का बोझ डालते हैं, जबकि कागज़ के पैसे के नए जारी होने के मामले में ब्याज की ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आती। इसलिए हम अब देख रहे हैं कि किसी भी मामले में आखिरी तरीका सरकार और लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।

लेकिन अब, अगर हम इस तरह की फाइनेंसिंग के तरीके को और आगे देखें, तो यह पता चलता है कि लोन के रास्ते से बचते हुए बड़े सरकारी कामों की सीधी फाइनेंसिंग से और भी बड़े फायदे मिलते हैं।

हमने देखा है कि सरकारी कामों की फाइनेंसिंग का जो तरीका अभी अपनाया गया है, उससे एक्स्ट्रा खरीदने की क्षमता बनती है, जिसे नए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी करके दिखाया जाता है। इस मामले में, ज़ाहिर है कि पूरी नई लोन की रकम एक ही बार में दी जाएगी और दी जानी चाहिए, भले ही नए बनने वाले रेलवे, वॉटरवे वगैरह अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में हों और अभी भी बताने लायक कोई असली वैल्यू न दिखाते हों।

अगर कोई मेरे बताए तरीके से इतने बड़े सरकारी कामों की फाइनेंसिंग करता है, तो लोन के लिए एडवरटाइजिंग का बहुत ज़्यादा खर्च सबसे पहले खत्म हो जाता है। आपको याद होगा कि अकेले अखबारों में टेंडर देने में कितनी बड़ी रकम खर्च होती है। इसके अलावा, बैंकों और दूसरे क्रेडिट संस्थानों को शुरू से जो परसेंटेज दिए जाते हैं, वे भी खत्म हो जाते हैं। ये भी, फिर से, लाखों में होते हैं। इसके अलावा, लोन पार वैल्यू पर जारी करने की आदत होती है, दूसरे शब्दों में, 1000 मार्क के बॉन्ड के लिए इन सर्टिफिकेट को खरीदने वाले को लगभग सिर्फ़ 970 मार्क देने होते हैं, और फिर भी उसे ब्याज के साथ पूरी रकम मिलती है। ये भी ऐसे नुकसान हैं जो शुरू से ही होते हैं।

सरकार या कंपनी के लिए बोझ बन जाते हैं और कैपिटलिस्ट के पक्ष में होते हैं। असल में, स्टॉक-एक्सचेंज की कहावत के मुताबिक, ऐसे लोन को दूसरे आकर्षणों से "सजाने" की कोशिश की जाती है, जिसमें उम्मीद के मुताबिक खास एक्स्ट्रा फायदे दिए जाते हैं, जिसमें टैक्स में छूट भी शामिल हो सकती है। मुझे यहां माइनिंग प्रीमियम लोन याद है जिसने ऐसे सबसे शानदार आकर्षण दिखाए जो किसी सरकार ने कभी नहीं दिखाए। लोन के विज्ञापन में लॉटरी और जुए के शैतान को लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे 1000 मार्क बॉन्ड पर लाखों की जीती हुई रकम देने का वादा किया गया था; इसके अलावा, तथाकथित बोनस पेमेंट दिए गए थे, और आगे, 5% का घोषित इंटरेस्ट-रेट था जिसे हालांकि क्लॉज के साथ हेज किया गया था, और, इसके अलावा, कई टैक्स के मामले में सेविंग्स प्रीमियम लोन हर टैक्स से मुक्त था! इन प्रीमियम और फायदों, इन शानदार लॉटरी जीती हुई रकमों को देने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से मिलेगी, इस पर किसी ने विचार नहीं किया – भले ही यह हर गंभीर और समझदार आदमी को साफ होना चाहिए था कि ये सारी रकम एक बार फिर लोगों की जेब से निकालनी होगी। क्योंकि, तब मिले पैसे तुरंत सबसे ज़रूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल किए गए। ये सभी लोगों के खिलाफ फाइनेंशियल पॉलिटिकल क्राइम हैं, जिन्हें कितनी बेशर्मी से किया गया है, इस पर हैरानी होती है।

इसलिए अगर कोई लोन का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाता, बल्कि सीधे पैसे बनाने का रास्ता अपनाता है, तो राज्य के बजट के ये सारे मुश्किल और गलत बोझ हट जाएँगे – किसी को ज़रूरी रकम एक साथ नए पेपर मनी में जमा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी , लेकिन यह काफी धीरे-धीरे हो सकता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि नया काम कैसे आगे बढ़ता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह होगा कि बिना पैसे के पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि नया पैसा तभी दिया जाएगा जब काम का एक और बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा। हमें यहाँ ऐसे पैसे से काम चलाना होगा जो पूरी तरह से असली कीमतों से कवर हो, यानी ऐसे पैसे से जो स्थिर हो, ऐसे पैसे से जो इतने घंटों के काम के बराबर हो।

लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए नए पैसे को लगातार जारी करने का यह तरीका, जो पहले से ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है, किसी भी तरह से आख़िरी कदम नहीं है। क्योंकि नए बनाए गए कामों के बराबर पैसे को सर्कुलेशन में लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि नए जारी किए गए नोट असल में सरकारी खजाने में वापस आ जाते हैं; इस तरह उन्हें नई सीरीज़ को सर्कुलेशन में लाए बिना फिर से जारी किया जा सकता है। और अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, यानी, ऐसे खास राज्य के लिए अपने नए पैसे जारी करने का ऐलान करते हैं।

काम अपने आप में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं, भले ही हम कंस्ट्रक्शन के लिए अपना पैसा जारी करने में फाइनेंसिंग प्रोसेस की इजाज़त, और खासकर क्लैरिटी को अच्छी तरह समझा सकें और कुछ खास मकसदों के लिए इसका पालन करना चाहें।

यह आखिरी स्टेप ऐसे सरकारी कामों की पूरी तरह से कैशलेस फाइनेंसिंग है । जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, यह मानना गलत है कि लोन के ज़रिए सरकार के पास कैश आ जाएगा जिससे वह रेलवे या बिजली प्लांट बनाने वाले एंटरप्रेन्योर और वर्कर्स को पेमेंट कर सके।

फिर भी, एंटरप्रेन्योर्स को अपने काम के पेमेंट के लिए हर हफ़्ते अपने बैंकों से कैश में ज़रूरी रकम निकालनी होगी। बैंकों को अपनी तरफ़ से सेंट्रल बैंकों या राइशबैंक वगैरह से अपने ट्रेजरी स्टॉक पर इन बहुत ज़्यादा मांगों को एक बार फिर पूरा करना होगा। अब, नॉर्मल टाइम में, पूरी मौजूदा लिक्विडिटी पहले से ही पूरे वर्कफ़ोर्स के हर हफ़्ते के वेतन पेमेंट के लिए काफ़ी है, और यह असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ समय के लिए, जैसे, बवेरियन वाल्चेन्सी पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा वर्कफ़ोर्स एक ही जगह पर जमा हो जाएं, क्योंकि, अगर वे वहां काम नहीं करते, तो उन्हें दूसरी कंपनियों में बांटने पर भी अपने हर हफ़्ते के वेतन पेमेंट की उम्मीद करनी पड़ती और उन्हें मिलता, या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के ज़रिए पैसे मिलते। इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए पेमेंट के तरीकों की पूरी ज़रूरत का ध्यान रखना एक आम सरकारी काम है।

अर्थव्यवस्था, चाहे बड़े सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा वर्कफ़ोर्स को एक ही जगह पर कुछ समय के लिए रखा गया हो या नहीं।

सैलरी पेमेंट के लिए पेमेंट का तरीका देना और एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे कैशलेस ट्रांसफर देना, पेमेंट ट्रांज़ैक्शन के काम हैं और इनका क्रेडिट की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है।

इसलिए यह सबसे साफ़ और नेचुरल बात होगी अगर पूरी आबादी के कानूनी रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए किसी बड़े सरकारी काम के लिए क्रेडिट अप्रूवल के साथ, उसी समय यह ऑथराइज़ेशन भी जुड़ा हो कि स्टेट बैंक इन अप्रूव्ड क्रेडिट के आधार पर ज़रूरी पेमेंट कर सकता है। ज़ाहिर है, नॉर्मल तरीके से - कि ये पेमेंट तभी किए जाते हैं जब अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टेड सरकारी अथॉरिटी (एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्ट्रीट और रिवर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रेलवे कंस्ट्रक्शन सेक्शन, स्पेशल मकसद के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट, वगैरह) एंटरप्रेन्योर्स द्वारा मांगी गई पेमेंट अमाउंट को देख लेते हैं और, रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, पेमेंट को ऑथराइज़ कर देते हैं।

पूरा लोन घोटाला जो इसमें डाला गया है - क्योंकि यह एक देश को धोखा देने का मॉडर्न तरीका है - पूरी तरह से बेकार है और सिर्फ नुकसानदायक है।

रीच्सबैंक निगम

जैसा कि हर भोले-भाले सरकारी नागरिक को लगता है, राइशबैंक असल में कोई सरकारी बैंक नहीं है, बल्कि एक स्टॉक कंपनी है। इसलिए राइशबैंक किसी भी तरह से सरकारी संस्था नहीं है, भले ही जून 1922 तक, जब एंटेंटे की मांगों पर इसे पूरी तरह से "ऑटोनॉमाइज़्ड" कर दिया गया था, सरकार के पास कुछ रेगुलेटरी अधिकार थे। बैंक के अधिकारियों का नाम और पेमेंट भी राइश ही करता था, लेकिन एडवाइज़री काउंसिल में सिर्फ़ बड़े बैंकों और इंटरनेशनल ज्यूरी के प्रतिनिधि ही थे – ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं।

1873 में अपनी शुरुआत में ही पहली सलाहकार काउंसिल में लगभग 15 सदस्यों के नाम दर्ज थे: बैरन रोथ्सचाइल्ड, प्रिवी काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स ब्लेइक्रोडर, प्रिवी काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स मेंडेलसोहन, थियोडोर प्लॉट, प्रिवी काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स ओपेनहाइमर, प्रिवी काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स वार्सचौअर और प्रिवी काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स ज़्विकर, काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स स्टर्न, काउंसलर ऑफ़ कॉमर्स गेल्पके; यानी ग्यारह शुद्ध नस्ल के बड़े यहूदी और, सजावट के तौर पर, जर्मन नाम वाले चार और सज्जन।

यह फिर से एक चालाक शतरंज की चाल थी जिसमें बिस्मार्क को सलाह देने वाले बैंकर, ब्लेइक्रोडर ने पुराने राइख्सचांसलर को सलाह दी कि राइख्सबैंक को पूरी तरह से सरकारी संस्था के तौर पर न बनाया जाए, क्योंकि इससे युद्ध की स्थिति में दुश्मन इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त सुरक्षा के आधार पर अपने कब्ज़े में नहीं ले पाएगा, जबकि पूरी तरह से सरकारी बैंक के तौर पर यह दुश्मन के हमले के लिए तुरंत खुला रहेगा।

असल में, चालाक यहूदी, दूसरे बड़े फाइनेंसरों के साथ, ज़ाहिर है, सिर्फ़ राइख के मुख्य फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट को अपने अधिकार में लेना चाहता था। वे लोग इसमें भी कामयाब हो गए और राइख ने इसके साथ ही अपने सिक्के बनाने के अधिकार के सबसे ज़रूरी क्षेत्रों में से एक – बैंक नोट जारी करने के अपने अधिकार को पूरी तरह से छोड़ दिया।

राइक्सबैंक आज जर्मन राइख के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत खास जगह रखता है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में आज भी कम अहमियत रखने वाले लोग साफ़ तौर पर जानते हैं कि राज्य और लोगों के लिए इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं।

यह एक अलग जांच का काम होना चाहिए कि बड़े बैंकों ने राइशबैंक की शुरुआत से लेकर अब तक अपने मतलब के लिए उस पर अपने असर का गलत इस्तेमाल कैसे किया है।

जब तक बिस्मार्क ऑफिस में थे, उनके स्टेट्समैन वाले नज़रिए और उनके लिए इज्ज़त ने स्टॉक-एक्सचेंज हाइना को कंट्रोल में रखा; राइक्सबैंक के पूरे इतिहास में सिर्फ़ एक बार बिस्मार्क ने राइक्सबैंक कानून में दिए गए चांसलर के वीटो का इस्तेमाल किया, यानी जब उन्होंने रूसी स्टॉक लेने पर रोक लगाई। आज राइक्सबैंक, जैसा कि शुरू में बताया गया है, इंटरनेशनल बैंकरों के दोस्ताना दबाव में पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। इस तरह राइक्सगवर्नमेंट के पास अब बिज़नेस के कामकाज पर कोई बड़ा फ़ैसला लेने का कोई चांस नहीं है।

देशों की ब्याज की गुलामी का मतलब है बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज का राज। ब्याज की गुलामी को तोड़ना नेशनल सोशलिज़्म का अब तक का सबसे बड़ा काम है।

आज देश और इकॉनमी में जो कुछ भी होता है – वह सब प्रोडक्टिव काम के बदले बड़ी कैपिटल के इंटरेस्ट की मांग बन जाता है। अगर रेलवे बनता है, तो उससे लोन मिलता है, अगर युद्ध होता है, तो उससे वॉर लोन मिलता है, अगर नेचुरल रिसोर्स या हाइड्रोएनर्जी डेवलप होती है, तो उससे हाइड्रो-एनर्जी लोन मिलता है, अगर कोई फैक्ट्री बढ़ाई जाती है, नए शेयर जारी किए जाते हैं, अगर कोई नई कंपनी शुरू होती है, तो कोई इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक कंपनी का रूप चुना जाता है जिससे काम और रिस्क एंटरप्रेन्योर्स को और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा फाइनेंसर्स को मिलता है। अगर यह लोन के ज़रिए आगे नहीं बढ़ता है, तो यह कहीं ज़्यादा आसान और ज़्यादा है।

पैसे छापने का बड़ा तरीका चुना गया, जैसा कि 1923 की महंगाई के समय में हुआ था, जिससे बड़ी पूंजी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसा कि कहानी में राजा मिडास के मामले में हुआ, जिनके लिए वह जो कुछ भी छूते थे वह सोना बन जाता था, वैसे ही आज जो कुछ भी होता है वह ब्याज़ वाली सिक्योरिटीज़ में बदल जाता है।

बदकिस्मती से, वर्ल्ड-बैंकर्स की भूख बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटीज़ सच में उनका पसंदीदा खाना है, जो ज़ाहिर है उन्हें बहुत सूट करता है। हम उनके भूखे रहने पर भरोसा नहीं कर सकते, जैसे राजा मिडास, जिनके लिए, जैसा कि सब जानते हैं, उनके मुंह का खाना भी सोना बन जाता था। इसके उलट, ब्याज़ के मालिक पहले भूखे मरेंगे, उससे पहले मज़दूर भूखे मरेंगे।

वे अपने नियम को छोड़ने या नरम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, इसलिए इस ब्याज नियम को तोड़ना होगा।

अब हमें तीसरे पहलू पर भी रोशनी डालनी होगी जो आम आदमी के लिए भी ब्याज पर कैपिटलिस्टिक शोषण की तस्वीर को पूरा और पूरा कर देगा, वह है महंगाई।

मुद्रा स्फ़ीति

महंगाई हमारी फाइनेंशियल पॉलिटिकल बदहाली का साफ-साफ दिखना है। महंगाई हर किसी को प्रभावित करता है - हर उस व्यक्ति को जो अपनी आजीविका अर्जित करता है - भयावह गंभीरता के साथ।

लेकिन महंगाई कहाँ से आती है? इस सवाल पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलते हैं जो कुछ हद तक जवाब देने वाले के छोटे नज़रिए से लिए गए हैं, कुछ हद तक डेमोगॉजिक नारों की डिक्शनरी से, और कुछ हद तक असली वजहों को बताते हैं, लेकिन असली वजह पर सही से बात नहीं करते। जब कोई अलग-अलग पार्टियों द्वारा महंगाई के इन कारणों को पहचानते हुए सुनता है, तो जल्द ही कोई भी सोशल सिस्टम और कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं रह जाता जिसे कोई न कोई पक्ष महंगाई का कारण न बताए।

जिन लोगों ने इंटरेस्ट स्लेवरी पर किताब में दिए गए एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, उनके लिए जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। महंगाई की असली गलती काम से कैपिटल पर इंटरेस्ट की ज़िम्मेदारी है।

ब्याज – टैक्स – महंगाई, इस तरह एक लॉजिकल चेन चलती है, जो शुरू होती है राज्य की तरफ से ब्याज का खतरनाक और बेतुका वादा, इस नतीजे पर मजबूर करता है कि राज्य को लोगों से टैक्स के ज़रिए ब्याज की अपनी ज़िम्मेदारी वसूलनी पड़ती है; टैक्स, और असल में सभी तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ड्यूटी, साथ ही सबसे गलत इनडायरेक्ट टैक्स, जो बिना नोट जारी करने पर मिलते हैं, फिर उनके साथ महंगाई भी आ जाती है। इस तरह यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर चलता रहता है, क्योंकि महंगाई राज्य के खर्चों को और बढ़ाती है, जिसे वह, कर्ज के पागलपन में फंसा हुआ, हमेशा सोचता है कि वह सिर्फ़ नए कर्ज लेकर ही पूरा कर सकता है, ये नए कर्ज अपने आप में नए ब्याज लाते हैं, नए ब्याज नए टैक्स को ज़रूरी बनाते हैं, टैक्स कानून धीरे-धीरे पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि ऐसी करेंसी के गिरने की स्थिति में, सारा टैक्स रेवेन्यू करेंसी के डीवैल्यूएशन से बहुत पीछे रह जाता है और अब राज्य बिना किसी विरोध के मनी प्रिंटिंग प्रेस के फाइनेंशियल बोल्शेविज़्म के आगे सरेंडर कर देता है, जैसा कि हमने 1923 की महंगाई में बहुत बुरा अनुभव किया है।

मेरे पहले पोलिमिकल काम मुख्य रूप से इन कनेक्शन को उजागर करने के लिए थे। 'ब्याज की गुलामी को तोड़ने के लिए मैनिफेस्टो'74 में मैंने आम तौर पर ब्याज की समस्या के सभी बड़े महत्व को बड़े पैमाने पर बताया, 'राज्य की बैंकरप्सी' में: समाधान में मैंने खास तौर पर राज्य के लोन सिस्टम की बेवकूफी को उजागर किया और उन अनगिनत टैक्स कानूनों की ओर इशारा किया जिनसे आम जनता की रोजी-रोटी और महंगी हो गई, जिनका उत्पादन पूरी तरह से ब्याज सेवा के लिए इस्तेमाल होना था। 'आने वाली टैक्स हड़ताल' में, 1920 और 1921 के टैक्स कानूनों की नई बाढ़ के साथ-साथ 1918 के राइशबजट में, यह पक्का सबूत दिया गया कि राइश और राज्यों का पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बड़े लोन कैपिटल के लिए ब्याज सेवा से जुड़ा हुआ है। हालांकि, पिछली किताब में, इन पूरी तरह से खराब हालात को बदलने का रास्ता पहले ही एक साफ उदाहरण के साथ बताया गया है।

यह बिल्कुल साफ़ है कि, देश की इकॉनमी में कागज़ी पैसे की बाढ़ आने से, इस पेपर मनी की परचेज़िंग पावर लगातार कम होती जाएगी।

क्योंकि पैसा अपने अंदरूनी रूप में, जैसा कि हमने पहचाना है, किए गए काम का एक निशान है, इसलिए पैसे की तथाकथित क्वांटिटी थ्योरी, कम से कम अपनी ज़रूरी बातों में, होनी चाहिए।

---

74 पोटेंशियल परचेज़िंग पावर वह बचाई हुई परचेज़िंग पावर है जिसका अभी मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें जमा किया हुआ कैश और पक्की इन्वेस्ट की गई सेविंग्स कैपिटल दोनों शामिल हैं।

इफेक्टिव परचेज़िंग पावर नेशनल इकॉनमी पर सभी डिमांड क्लेम की कुल रकम है जो कैश के रूप में होती है। या सिक्योरिटीज़ के रूप में गुड्स मार्केट में लगाए जाते हैं और खुद को मटीरियल गुड्स में बदलने की कोशिश करते हैं।

पोटेंशियल परचेज़िंग पावर को कभी भी असरदार में बदला जा सकता है, इस मामले में इसे "फ्लाइट फ्रॉम द मार्क" कहा जाता है।

हमने माना है। यह थ्योरी सिखाती है कि अगर परचेज़िंग पावर में बदलाव नहीं होना है, तो किसी नेशनल इकॉनमी में सर्कुलेशन में मौजूद पैसे का अमाउंट एक खास स्टेबल रिश्ते में रहना चाहिए। पैसा कुछ हद तक सामान के स्टॉक के मुकाबले खड़ा होता है और - सामान की मात्रा से कैलकुलेट किया जाता है – आम करेंसी की वैल्यू की कुछ यूनिट बनती हैं, यानी सामान की एवरेज कीमत। यहाँ मैं 'एवरेज' एडजेक्टिव पर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। असल में, हमें और आगे जाकर कहना होगा: एवरेज प्राइस लेवल – इस तरह किसी भी तरह से अलग-अलग कीमतों का अमाउंट – देश में कुल मिलाकर मौजूद परचेज़िंग पावर के अमाउंट पर एक खास डिपेंडेंस में होता है। लेकिन परचेज़िंग पावर पहले से ही सिर्फ कैश एसेट्स के अमाउंट से कहीं ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम यहाँ इकोनॉमिक डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं खोना चाहते, नहीं तो कीमतों पर इसके असर में इफेक्टिव और पोटेंशियल परचेज़िंग पावर का सवाल यहाँ उठाना होगा। वैसे भी, यह पक्का है कि, उदाहरण के लिए, सर्कुलेटिंग करेंसी का हज़ार गुना मल्टिप्लिकेशन नैचुरली कीमतों का लगभग हज़ार गुना मल्टिप्लिकेशन लाएगा। असल में कीमतें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि करेंसी की मात्रा के गुणा के उलटे अनुपात में मार्क की खरीदने की ताकत कम हो गई है।

महंगाई का असली कारण है – राज्य की ब्याज की ज़िम्मेदारी। यह ब्याज की ज़िम्मेदारी टैक्स को ज़रूरी बनाती है, क्योंकि राज्य सिर्फ़ वही दे सकता है जो उसे अपने नागरिकों से किसी न किसी रूप में लेना ही पड़े।

जैसा कि हमने देखा है, राज्य द्वारा अपने नागरिकों की इस तरह की लूट तीन तरह की होती है –
या तो डायरेक्ट टैक्स के ज़रिए या ज़्यादा असरदार तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए या महंगाई के खास इनडायरेक्ट तरीके से। आखिरी तरीका सबसे ज़्यादा गलत है, और इसी से दिवालिया देश अपना सिर ऊपर रखना चाहते हैं – यह सबसे बढ़िया जालसाज़ी है। लेकिन यह आखिरी तरीका खास तौर पर इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि इससे आबादी के सबसे काबिल और मेहनती हिस्से की बचत की दौलत बस खत्म हो जाती है।

यह जर्मन लोगों की दुखद घटना का सबसे चौंकाने वाला चैप्टर है। लाखों मेहनती, मेहनती मज़दूर, कर्मचारी, अधिकारी, अलग-अलग पेशे के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वगैरह ने अपनी पूरी ज़िंदगी, कड़ी मेहनत करके, अपने और अपने परिवार के लिए पैसे बचाए ताकि वे बिना किसी चिंता के और आज़ादी से बुढ़ापा जी सकें। उन्होंने अपनी बचत एक-एक पैसा और एक-एक निशान जमा किया है, और हर निशान का मतलब है बुढ़ापे में हर दिन गुज़ारे के लिए कम से कम गुज़ारे की गारंटी। लेकिन जिस सरकार को इन बदकिस्मत लोगों ने अपनी बचत सौंपी थी, उसने 1923 की महंगाई में, उस निशान का कोई पेमेंट नहीं किया जो उसे किसी तरह से बचत के तौर पर सौंपा गया था – तब भी नहीं जब ये बचाए गए पैसे उस समय चमकदार सोने के सिक्कों में जमा किए गए थे – लगभग 30 मिलियन पेपरमार्क[75], बल्कि उसने अपनी वजह से करेंसी में आई गिरावट का फ़ायदा उठाया और कहा: एक निशान = एक निशान। इस तरह उसने इन सभी लोगों से उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत का फल छीन लिया और उन्हें बहुत बुरी मुश्किल में धकेल दिया। फिर सरकार ने उन्हें बेकार और बेकार मदद देकर टाल दिया, प्राइवेट चैरिटी को मदद के लिए आगे आना पड़ा – लेकिन यह तरीका उन लोगों के लिए खास तौर पर शर्मनाक था, क्योंकि प्राइवेट हाथों से मिले ये तोहफ़े असली मदद ही रहे, चैरिटी के तोहफ़े जिनके लिए इन बदकिस्मत लोगों को शुक्रगुज़ार होना पड़ा, भले ही यह उनके कमाए हुए अधिकारों की एक ऑर्गनाइज़्ड लूट थी। ऐसे अधिकार जो अगर वापस मिल भी जाएं, तो लूटे गए लोगों से "शुक्रिया" मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

75 अगस्त 1914 में मार्क के गिरने की वजह से पेपरमार्क बनाया गया, और गोल्डमार्क और सोने के बीच का कनेक्शन खत्म कर दिया गया। नवंबर 1923 तक महंगाई की दर बढ़ती रही, जब 1 ट्रिलियन पेपरमार्क की कीमत वाले नए रेंटेनमार्क को बनाने की घोषणा से करेंसी को स्थिर किया गया। रेंटेनमार्क, जो 1924 में लागू हुआ, उसी साल बाद में रीच्समार्क से बदल दिया गया।

हम पहले ही दूसरे हिस्सों में इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि एक झूठे सिद्धांत ने इन गरीब लोगों से अपना भयानक बदला लिया - असल में कैपिटल पेंशन का आदर्श। ऐसा नहीं है कि ये लोग इस किस्मत के लायक थे, बल्कि इसके उलट – इन लुटे हुए लोगों को जितना हो सके मुआवज़ा देना नेशनल स्टेट का एक सम्मानजनक फ़र्ज़ होगा। फिर भी, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह डरावना सबक लोगों के अचेतन में घूमता रहेगा और कैपिटल पेंशन का आदर्श डूब जाएगा और सही बचत के आदर्श – बुढ़ापे की देखभाल, महिलाओं और बच्चों की देखभाल का पूरी तरह से जर्मन विचार, अपना घर, खेत और बगीचा वगैरह बनाकर – को एक सफलता और जीत दिलाने में मदद करेगा।

सरकार द्वारा नागरिकों की लूट का दूसरा तरीका, जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है, वह है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अपने नतीजों के हिसाब से, सच में एक सामाजिक अपराध है। यह बेरहमी से और लगातार, एक ऐसे रूप में जिससे कोई बच नहीं सकता, बड़ी आबादी पर पूरी तरह से भारी पड़ता है, जबकि अमीरों पर आम तौर पर इनडायरेक्ट टैक्स का कोई असर नहीं पड़ता।

डायरेक्ट टैक्स, अगर टैक्स देने वाले की आर्थिक क्षमता के हिसाब से बांटा जाए, तो अपने आप में एक सही और सही टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स, आम कामों के लिए सरकार को दिया जाने वाला एक कंट्रीब्यूटरी पेमेंट भी है, लेकिन यह किसी भी तरह से ऐसा टैक्स नहीं है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा महंगा हो जाए, क्योंकि इसे तभी लिया जाना चाहिए जब असल में ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा सरप्लस हो। लेकिन आज जैसा डायरेक्ट टैक्स को माना जाता है, यह महंगाई की तरह, सरासर लूट है और वाइमर संविधान के आर्टिकल 153 में बताई गई प्रॉपर्टी की गारंटी के सीधे उलट है।

कुल मिलाकर, एक बार फिर यह बता दें कि हमें यहाँ महंगाई से निपटना है जो आम तौर पर इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए सरकार की ब्याज की ज़िम्मेदारी का नतीजा है। यह हमारे देश के आर्थिक शरीर से लंबे समय तक खून चूसने का मामला है, जो सुपरनेशनल फाइनेंशियल पावर के पक्ष में है, जिसके लिए हमारा अपना देश टैक्स-कलेक्टर का काम करता है।

यहां बात महंगाई के एक खास रूप की है – ब्याज पूंजीवादी महंगाई की।
नेचुरल महंगाई तब होती है जब फसल कम होती है या देश में कोई महामारी आती है, जब नेचुरल डिमांड मौजूदा सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। हालांकि, ऐसी महंगाई हमेशा कुछ समय के लिए ही होती है। अगला अच्छा साल परेशानी दूर कर देता है और कीमतें अपने नेचुरल लेवल पर वापस आ जाती हैं।

लेकिन, ब्याज वाली कैपिटलिस्टिक महंगाई एक ऐसी आग की तरह है जो तब तक नहीं बुझती जब तक वह दुनिया के सारे खज़ाने खा न ले और पूरी इंसानियत को इंटरनेशनल फाइनेंस का ब्याज-गुलाम न बना दे – या जब तक ब्याज की गुलामी खत्म न हो जाए।

राष्ट्रीय वित्तीय सुधार

हमारे राज्य के फाइनेंस की बीमारी का इतनी अच्छी तरह पता चलने के बाद, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल आम तौर पर सिस्टम को देखते हुए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इलाज के लिए सही नुस्खे दे पाएंगे।

वे नियम और उपाय जो अभी की स्थिति से भविष्य के रूप में बदलाव को रेगुलेट करते हैं, इस काम के दायरे में नहीं आते। इन उपायों के लिए यह आम गाइडलाइन सही है कि इनके ज़रिए जहाँ तक हो सके, आर्थिक जीवन में हर तरह की गड़बड़ी से बचा जाना चाहिए। ज़ाहिर है, यह यहाँ-वहाँ थोड़ी गंभीरता के बिना और कुछ समय के दखल के बिना नहीं होगा, लेकिन, बहुत ध्यान से तैयार किए गए ऑपरेशन के मामले में भी, यह थोड़े खून के नुकसान के बिना नहीं होता है।

हमारा सबसे बड़ा और शानदार आखिरी लक्ष्य ब्याज की गुलामी को तोड़ना है।

पहला और बुनियादी कदम, जो नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को एक प्राइवेट संस्था, राइशबैंक, plc. को सौंपने से होता है, वह है राइशबैंक का नेशनलाइज़ेशन।

इस बैंक के स्कोप से यह पहले से ही साफ़ है कि "रिक्सबैंक" असल में राइख का ही एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक वैसे ही जैसे राइखपोस्ट या राइखकोर्ट। यह पूरी तरह से पब्लिक ओपिनियन को गुमराह करने वाला बताया जाना चाहिए कि राइखबैंक, pic, को यह नाम रखने की इजाज़त है।

एक असली राइक्सबैंक का काम भी दोहरा होना चाहिए। पहला, राइक्स के फाइनेंशियल बिज़नेस का इंतज़ाम उसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये इंतज़ाम अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पदों से और सीधे तौर पर नहीं किए जा सकते, जैसा कि पोस्ट और रेलवे के मामले में होता है, और दूसरा, पेमेंट ट्रांज़ैक्शन में फिड्यूशरी मीडिएशन में इसे पूरी नेशनल इकॉनमी के लिए मज़बूत सपोर्ट बनाना चाहिए। इसका काम यह भी देखना होगा कि मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन के लिए लगातार काफ़ी कैश एसेट मौजूद रहें।

इन कामों के लिए, इसे नेशनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूटिव अंग होना चाहिए, जिसे पूरी तरह से इसके अंडर रखा जाना चाहिए। राइक्सबैंक के अधिकारी भी दूसरे अधिकारियों की तरह सरकारी अधिकारी होने चाहिए। एक एडवाइजरी काउंसिल, जो आज की तरह बड़े ज्यूरी के प्रतिनिधियों से बनी है, ज़ाहिर है पूरी तरह से फालतू है। यह वाकई काफी है अगर बैंक के फाइनेंशियल काम की देखरेख के लिए एक स्पेशल स्टेट कमिश्नर, जो बैंक के फाइनेंशियल काम के लिए ज़िम्मेदार हो, को राज्य द्वारा नियुक्त किया जाए। बैंक के काम उसके अपने राइक्सबैंक कानून के तहत ठीक से तय किए जाएंगे ताकि बैंक का फाइनेंशियल काम पहले से ही यह गारंटी दे सके कि राइक्सबैंक की संस्था सिर्फ़ देश के हितों की सेवा करती है।

लेकिन अब हमारे पास पहले से ही एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो इन मांगों को पूरी तरह से पूरा करता है जो हमें राइक्सबैंक पर रखनी चाहिए। यह बवेरियन स्टेट बैंक है। बवेरियन स्टेट बैंक असल में एक पूरी तरह से नेशनल बैंक है, और कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि इसने एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपने कामों को बिना किसी आपत्ति के पूरा नहीं किया है। यह स्वाभाविक रूप से इस चेतावनी के साथ है कि इसने ब्याज वाली कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के आम रिवाजों के अनुसार भी काम किया है। लेकिन किसी भी मामले में, इस बैंक ने बैंक कैपिटल के लिए प्रॉफिट पर विचार किए बिना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो पहला काम है। इसने इस तरह यह बहुत ही खास बात दिखाई है कि बैंक, अपनी बहुत ही छोटी कैपिटल, सिर्फ 8,000,000 मार्क्स के साथ, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की सभी मांगों को पूरा करने और अरबों का रेवेन्यू मैनेज करने की स्थिति में था।

यह बताना दिलचस्प होगा कि स्टॉक-एक्सचेंज ईयरबुक (सैलिंग की स्टॉक-एक्सचेंज ईयरबुक, कैपिटलिस्ट और स्टॉकहोल्डर्स के लिए एक हैंडबुक, 1914/15 के लिए,

जर्मन बैंक), इस बवेरियन स्टेट बैंक (उस समय भी "रॉयल बवेरियन बैंक") के होने को बस नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, भले ही इस हैंडबुक के पेज 644 पर इस ज़रूरी सरकारी संस्था का ज़िक्र करने का मौका और जगह थी। लेकिन जो बैंक सिर्फ़ प्राइवेट कैपिटलिस्टिक मकसदों को पूरा नहीं करता, वह साफ़ तौर पर, हाई फाइनेंस के लिए, बैंक नहीं है।

यह और भी खास बात है कि युद्ध और म्यूनिख बोल्शेविक दौर के तुरंत बाद, बवेरियन स्टेट बैंक को "एक बड़े बेसिस पर" रखने की कोशिशें चल रही थीं, जैसा कि इसके लिए एक मज़ेदार स्टॉक-एक्सचेंज टेक्निकल शब्द था, ताकि इस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को भी प्राइवेट कैपिटल के "प्रॉफिटेबल बनाने" के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह हमारी मांग का बवेरियन स्टेट बैंक में एक प्रैक्टिकली बचा हुआ मॉडल है। इस तरह यह एतराज़ कि बैंक को एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर चलाना मुमकिन नहीं है, गलत साबित होता है।

राइक्सबैंक के लिए, राइक्सबैंक कानून ने असल में एक नेशनलाइज़ेशन का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार राइक्स को एक साल के नोटिस के बाद, पहली बार 1.1.1891 को, फिर दस साल के समय में, या तो राइक्सबैंक को खत्म करने और उसके एसेट्स (जिसमें बहुत कीमती बिल्डिंग्स भी शामिल हैं) को नेट एसेट वैल्यू (!) के पेमेंट पर खरीदने या सभी शेयर फेस वैल्यू (!!) पर खरीदने का अधिकार होगा। इस तरह, 1 जनवरी 1921 को, राइक्स जर्मन लोगों के खिलाफ़ राइक्सलेजिस्लेशन की एक बड़ी गलती को ठीक कर सकता था अगर उसने राइक्सबैंक की पूरी प्रॉपर्टी को 1.80 मिलियन की मामूली रकम में खरीद लिया होता – जो कि राइक्सबैंक के शेयरों की फेस वैल्यू है।

वोल्किशे बेओबैक्टर उस समय राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मज़दूर पार्टी के कब्ज़े में नहीं था, जिसका नेतृत्व उस समय पहले से ही राष्ट्रीय समाजवाद के बौद्धिक अग्रदूतों से जुड़े लोग कर रहे थे, और डॉ. एस.च. का साप्ताहिक।

पुडोर, डेर ड्यूश फिनान्ज़मैन ने समय पर इस ओर ध्यान दिलाया – बेशक एकमात्र सार्वजनिक जर्मन समाचार पत्र की आवाज़ के रूप में – स्वाभाविक रूप से बिना किसी सफलता के।

यह और भी खास बात है कि, हालांकि राइक्सबैंक के शेयर नामों पर बनाए गए हैं, लेकिन राइक्सबैंक के शेयर कम से कम 2153 विदेशियों के पास थे! इन 2153 विदेशियों (1913 तक) ने राइक्सबैंक की पूरी कैपिटल का कितना हिस्सा बेचा, यह बदकिस्मती से राइक्सबैंक के खुलासे से साफ नहीं है। वैसे भी, यह बहुत बड़े परसेंटेज की बात है, क्योंकि लोकल शेयर-होल्डर्स की संख्या सिर्फ 16,646 बताई गई है। अब यह साफ है कि, लोकल शेयर-होल्डर्स के मामले में, बहुत कम रकम हासिल की गई होगी, जबकि यह मानना सही होगा कि जब कोई विदेशी जर्मन राइक्सबैंक के शेयर खरीदता है, तो उसे सिर्फ एक या दो शेयर नहीं मिलते, बल्कि सीधे एक अच्छा पैकेज मिलता है। यह बात उस अजीब स्थिति को छिपाती है कि युद्ध के दौरान भी, "जर्मन राइक्सबैंक" से विदेशों में डिविडेंड के रूप में काफी बड़ी रकम निकाली गई थी।

अब, राइक्सबैंक का प्रॉफ़िट शेयरिंग, जो अपना मुख्य प्रॉफ़िट बिल डिस्काउंटिंग से कमाता है – जैसा कि हमने ऊपर जाना – बहुत ही ओरिजिनल है। सबसे पहले, शेयर-होल्डर्स को 31/2 % का प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, और बचे हुए प्रॉफ़िट में से एक चौथाई शेयर-होल्डर्स में बांटा जाता है। इस बचे हुए प्रॉफ़िट का तीन-चौथाई हिस्सा राइक्स को ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद 10% रिज़र्व फंड में ट्रांसफर किया जाता है। 1913 में, इस तरह से 31,025,555 मार्क राइक्स को ट्रांसफर किए गए थे। इसी वजह से, राइक्स ने इस खास संस्था को तथाकथित बैंक-नोट प्रिंटिंग प्रिविलेज दिया है, यानी अपने ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरत के हिसाब से बैंक-नोट जारी करने का अधिकार। युद्ध शुरू होने तक, राइक्सबैंक को इन बैंक-नोट्स के कवर के तौर पर कम से कम एक तिहाई सोना या चांदी जर्मन या विदेशी सिक्कों या बार में तैयार रखना था। इस रोक के हटने के बाद भी, अनलिमिटेड पेपर मनी प्रिंटिंग के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। राइक्सबैंक के पास अपने पेपर मनी के लिए जो एकमात्र कवरेज (!) था, वह शानदार राइक्सट्रेज़री बिल थे – इस तरह एक बार फिर सिर्फ़ एक और

कागज़, जिसके पीछे एक दिवालिया देश खड़ा था। कोई हैरानी नहीं कि ऐसे हालात में, जर्मन करेंसी का ऐसा पतन हुआ जिसे रोका नहीं जा सका।

बेशक, एक नेशनलाइज़्ड बैंक के लिए यह एक बहुत ज़रूरी सरकारी काम है कि वह हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि पेमेंट के तरीकों के लिए इकॉनमी के दावे पूरी तरह से पूरे हों; क्योंकि अगर यहां कोई रुकावट नहीं आती है, भले ही दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी दावों को पूरी तरह से पूरा कर सकें, तभी पैसे की कमी के आधार पर ब्याज वसूली होती है – जिससे दुनिया में सबसे बड़े संकट पैदा हो सकते हैं –
बाहर रखा गया। इसके उलट, जारी किए गए पैसे, इकॉनमी में कम तेज़ी के समय में भी, पब्लिक मनी ट्रांज़ैक्शन के अनगिनत चैनलों के ज़रिए राइक्सबैंक में वापस आते हैं ताकि वह नोटों को फिर से सर्कुलेशन से निकाल सके। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के मामले में, जैसा कि सब जानते हैं, यह रिवाज़ है कि जो नोट बैंक में वापस आता है, उसे दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि पुराने नोट को नष्ट करते समय उसे नए नोट से बदल दिया जाता है। यह मुख्य रूप से साफ़-सफ़ाई के कारणों से होता है।

अब करेंसी का सवाल भविष्य में सच में और भी ज़रूरी हो जाएगा, जब तथाकथित मनी सरोगेट, जैसे बिल ऑफ़ एक्सचेंज और चेक, और खासकर कैशलेस मनी ट्रांज़ैक्शन, ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे।

ऐसी क्लियरिंग इकॉनमी में, पोस्टल चेक ऑफिस, जो आज भी कैशलेस और बिना ब्याज के शुद्ध पैसे के लेन-देन के लिए मिसाल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करेंगे। आज के पोस्टल चेक ऑफिस में वे कोर सेल्स देखे जा सकते हैं जिन्हें सरकारी निगरानी में एक आदर्श पैसे के लेन-देन सिस्टम के लिए आसानी से डेवलप किया जा सकता है – जो पूरी तरह से नेशनल पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हो।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पोस्टल चेक ऑफिस से पेमेंट का लेन-देन ज़्यादा तेज़ी से और भरोसे के साथ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट और डेबिट नोट ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों में नहीं निपटते, जबकि दूसरी तरफ़, आज बैंकों में यह देखा जा सकता है कि लंबे समय से मिले अमाउंट के क्रेडिट नोट सिर्फ़ 8 से 14 दिन बाद बनते हैं। अगर बैंक कस्टमर को अपने काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो भी उसे बैंक क्रेडिट क्लेम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पोस्टल चेक ऑफिस से पैसे के लेन-देन के मामले में पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि पेमेंट के लेन-देन में काफ़ी बड़ी राहत और आसानी होती है, खासकर साल के आखिर की डेडलाइन पर। पोस्टल चेक कस्टमर को हर साल 2 जनवरी को – और हर दिन मांगने पर – पोस्टल चेक अकाउंट में अपने अकाउंट की हालत के बारे में सही जानकारी मिलती है।

इस तरह, बैंकों के ज़रिए पैसे के लेन-देन में मध्यस्थता इकॉनमी के लिए किसी भी तरह से खास फ़ायदेमंद नहीं है। बैंकों के ज़रिए सिर्फ़ पैसे का लेन-देन प्रोडक्शन पर हर तरह के प्रोविज़न का बोझ डालता है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकों को ही इंटरेस्ट से फ़ायदा होता है, लेकिन बैंक का इस्तेमाल करने वाले को कभी नहीं। एक सही फ़ैक्टरी मालिक और एंटरप्रेन्योर के लिए, कुछ समय के क्रेडिट के लिए कुछ मार्क्स इंटरेस्ट मिलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक सही एंटरप्रेन्योर खुद को इस तरह से चलाता है कि उसके पास बैंक में सिर्फ़ उतना ही पैसा हो जिससे वह अपनी सैलरी और दूसरे मौजूदा पेमेंट कर सके।

पोस्टल चेक अकाउंट इन मांगों से पूरी तरह मेल खाते हैं और यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है कि युद्ध के दौरान भी, लंदन में "फेबियन" की इंग्लिश सोसाइटी, "फेबियन सोसाइटी"76 ने एक्सचेकर के लॉर्ड चांसलर को एक मेमोरेंडम भेजा था, जिसका टाइटल था: "हम युद्ध के लिए पैसे कैसे दें?", जिसमें उन्होंने मदद के तौर पर जर्मन और ऑस्ट्रियन पोस्टल चेक अकाउंट के ऑर्गनाइज़ेशन की ओर इशारा किया था। दुश्मन हमेशा तेज़ नज़र वाले होते हैं और जब वे इशारा करते हैं

76 फैबियन सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट संगठन है जो क्रांति के बजाय सुधार का पक्षधर है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसके शुरुआती सदस्यों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एचजी वेल्स, एनी बेसेंट, लियोनार्ड और वर्जीनिया वुल्फ शामिल थे, हालांकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिडनी और बीट्राइस वेब थे। असल में सिडनी वेब ने ही 1900 में नई लेबर पार्टी का संविधान बनाया था।

अगर कोई संस्था अपने देश के लिए मिसाल बन जाए, तो कोई भी पक्का हो सकता है कि उसमें कुछ तो बात है।

जो बात राइशबैंक के नेशनलाइज़ेशन के बारे में कही गई थी, वही बात दूसरे सेंट्रल बैंकों के नेशनलाइज़ेशन के बारे में भी सच है, जैसे बवेरिया के लिए, "बवेरियन सेंट्रल बैंक"। बवेरियन सेंट्रल बैंक भी एक प्योर स्टॉक कंपनी है, जिसमें ज़्यादातर शेयर-होल्डर्स, उदाहरण के लिए, बैंक के गोल्ड रिज़र्व को शेयर-होल्डर्स में बांटने का फ़ैसला कर सकते हैं, जिस पर बैंक को नोट जारी करने का खास अधिकार है। असल में, हमें आज भी याद है कि म्यूनिख में यहूदी बैंकर श्लेइसहाइमर ने इस दिशा में कोशिशें की थीं। इस बार बवेरियन सरकार के एतराज़ के कारण प्लान फेल हो गया। उस समय बवेरियन सरकार ने छठा हिस्सा शेयर ले लिया था, जबकि छठा हिस्सा बवेरियन मॉर्गेज एंड डिस्काउंट बैंक ने ले लिया था और बाकी दो-तिहाई शेयर-होल्डर्स को दे दिए गए थे।

यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी देश को डर हो कि सेंट्रल बैंक के "शेयर-होल्डर्स" के दखल से उसका गोल्ड स्टॉक खतरे में पड़ सकता है। जो लोग यहूदियों की मज़बूती को जानते हैं, वे जानते हैं कि बवेरिया के गोल्ड स्टॉक का खतरा इस बात से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ कि सरकार एक बार के लिए मज़बूत रही। इसके खिलाफ़ असल में सेंट्रल बैंकों का नेशनलाइज़ेशन ही एक बड़ा तरीका है। बवेरियन सेंट्रल बैंक के अलावा, जर्मनी में हमारे पास बाडेन बैंक, ड्रेसडेन में सैक्सन बैंक और वुर्टेमबर्ग सेंट्रल बैंक भी हैं।

राइशबैंक और सेंट्रल बैंकों के नेशनलाइज़ेशन के मामले में, बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को ज़ाहिर है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अपने कब्ज़े में ले लेगी। इस तरह नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ़ सरकार के पास होगा। नोटों का ऐसा इश्यू सिर्फ़ फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डिनेंस के बाद ही हो सकता है और सिर्फ़ पूरे कवरेज के खिलाफ़। इसी सिलसिले में हमारी करेंसी को स्टेबल करने का बड़ा काम हल करना है। हालाँकि, यह काम सेंट्रल बैंकों के छोटे दायरे का नहीं है; उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि बिना कवरेज के नोटों का कोई इश्यू न हो।

नोट्स बनाने के लिए अब तक के तय नियम मान्य हैं। हर नकल के लिए पीनल कोड, सेक्शन VIII, आर्टिकल्स 146-152 के नियमों के अनुसार बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी।

शेयरहोल्डर्स को मुआवज़ा दिया जाएगा। शेयरहोल्डर्स की तरफ़ से बैंक के गोल्ड स्टॉक्स पर किसी भी तरह का दावा कानूनी तौर पर बाहर रखा जाएगा।

हमारी करेंसी का असली स्टेबलाइज़ेशन तब तक पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, जब तक हम उम्मीद करते हैं कि जर्मन लोगों से ब्याज और ड्यूटी चार्ज, जैसा कि बताया गया है, लंबे समय में पूरे नहीं हो सकते। करेंसी को स्टेबलाइज़ करने के लिए कोई बड़ा तरीका अपनाना भी गलत है।

यहाँ कोई खास समस्या नहीं है जिसे इंटरेस्ट इकॉनमी की इंटरनेशनल समस्या से अलग किया जा सके। जब तक यह इंटरनेशनल लुटेरी इकॉनमी, जो पूरी तरह से यहूदी हाई फाइनेंस की है, बनी रहेगी, तब तक अलग-अलग देशों की करेंसी हमेशा हाई फाइनेंस के सट्टेबाज़ी का पसंदीदा विषय बनी रहेंगी। इसके अलावा, एक करेंसी की स्थिरता – जिसे "करेंसी" शब्द का अंदरूनी मतलब बताता है – दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, खासकर ट्रेड बैलेंस की एक्टिविटी या पैसिविटी पर। यहाँ हमारी नज़र अपने देश की सीमाओं से आगे जाती है, और घरेलू इकॉनमी दूसरे देशों की नेशनल इकॉनमी के साथ आपसी रिश्ते बनाती है।

इंटरनेशनल फाइनेंस के इस बड़े फील्ड में जल्दी से अपनी जगह बनाने के लिए, हमें एक बार फिर यह ध्यान रखना होगा कि इस इंटरनेशनल इकॉनमी का मतलब और मकसद प्राइवेट कैपिटल के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ज़रूरत को पूरा करना है। बाकी सब कुछ तो बस एक एक्सेसरी, एक मदद है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकॉनमी – इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन

– लेकिन आज वही चीज़ सबसे ज़रूरी लगती है और जो आज असल में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ये इंटरनेशनल बैंकिंग हाउस हैं जो आज असल में दुनिया पर राज करते हैं, जो देशों की पैसे की ज़रूरत को "पूरा" करते हैं, और इसलिए उन्होंने राज अपने हाथ में ले लिया है; ये इंटरनेशनल बैंकिंग हाउस हैं जो आज बड़े-बड़े ट्रस्टों में प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे लोहा, स्टील, पेट्रोलियम, डिब्बाबंद खाना, अनाज, चर्बी, तेल, कपास, वगैरह। इंटरनेशनल बैंकिंग हाउस ने लड़ाइयों को फाइनेंस किया, बड़े बैंकिंग हाउस ने लड़ाई के सभी इंतज़ामों को फाइनेंस किया और कंट्रोल किया। उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, न ही उन्होंने प्रोडक्शन में हिस्सा लिया, और न ही लड़ाई की एक्टिविटीज़ में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया; उन्होंने हर एक चीज़ से, खून-खराबे से, लड़ाई के खौफ से, आम लोगों की भूख से, नए अमीरों की बर्बादी से, स्टॉक-एक्सचेंज पब्लिक के सट्टेबाज़ी के गुस्से से सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाया है।

यह सब इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए सोना और सोने की कीमत बन जाता है। उत्पादक देशों का हर काम इंटरनेशनल फाइनेंस में दिलचस्पी लाता है। यहां तक कि इंटरनेशनल इकॉनमी में भी, हमें कैपिटल और काम के बीच सही और सही रिश्ते को पूरी तरह से बदलना होगा।

मज़दूर सही तरीके से काम करते हैं और अपने काम के प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाज़ार में बेचते हैं – ताकि उन्हें विदेशी काम के प्रोडक्ट्स (कच्चे प्रोडक्ट्स, आधे या पूरी तरह से बने हुए) से बदला जा सके। एक ठीक-ठाक इकॉनमी को विदेशी करेंसी (डॉलर या इंग्लिश पाउंड नोट) को सप्लाई किए गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से बदलने और फिर उन्हें कैंसल करके विदेशी करेंसी में और सट्टा लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। एक अच्छी इकॉनमी के समय में कोई भी फैक्ट्री मालिक ऐसा नहीं सोचेगा। बेशक, उसे अपने आगे के प्रोडक्ट्स के लिए कमाई की ज़रूरत होती है, ताकि वह और प्रोडक्शन कर सके, अपने मज़दूरों को पेमेंट कर सके और नया कच्चा माल खरीद सके। यह पूरी तरह से नामुमकिन है कि पूरी जर्मन इकॉनमी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से विदेशी करेंसी या विदेशी एक्सचेंज के रूप में अपनी कमाई इकट्ठा करे, क्योंकि उसी जर्मन पूरी नेशनल इकॉनमी को अपनी कच्चे माल की ज़रूरतें जैसे कपास, विशाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, हमारी उतनी ही विशाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए तांबा, रेशम, जूट, ट्रॉपिकल फल, घरेलू प्रोडक्शन से ज़्यादा बढ़ी हुई डिमांड, खाना और चारा, वगैरह, ये तो बस कुछ नाम हैं, खरीदनी होंगी। इसलिए, मिले हुए विदेशी पैसे को तुरंत फिर से बांटना होगा। यह अपने आप में काफी नेचुरल भी है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में कोई भी अपने देश में फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज भी ऐसा ही है। अमेरिकन वर्कर को फ्रेंच फ्रैंक से पेमेंट नहीं किया जा सकता, और इंग्लिश बिजनेसमैन को उसकी दुकानों में इटैलियन लीरा से पेमेंट नहीं किया जाता। करेंसी को दूसरे देशों में ले जाने का भी कोई मतलब नहीं है, जहाँ उन्हें पेमेंट के लीगल तरीके के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोकल करेंसी सिर्फ़ उस देश की अंदरूनी ज़रूरतों को पूरा करती है और उसे पूरा करना चाहिए जो करेंसी जारी करता है। जैसे, एक नेशनल इकॉनमी में, गुड्स प्रोडक्शन का मतलब पैसे का ट्रेडिंग करना और फिर उस पैसे पर बैठे रहना और उसे इकॉनमी से रोक लेना नहीं है, वैसे ही गुड्स का इंटरनेशनल इकॉनमिक एक्सचेंज तभी पूरा होता है जब इम्पोर्ट का पेमेंट एक्सपोर्ट से किया जाता है।

थ्योरी के हिसाब से आइडियल सिचुएशन अब यह होगी कि हर देश अपनी इम्पोर्ट की ज़रूरत को ठीक अपने एक्सपोर्ट से पूरा कर सके और उसका पेमेंट कर सके। तब, और सिर्फ़ तभी, कोई फॉरेन करेंसी की पूरी स्टेबिलिटी की बात कर सकता है। अब हर ऊपर की ओर बढ़ती नेशनल इकॉनमी की कोशिश ज़ाहिर तौर पर इम्पोर्ट की ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस पाने की होती है। सिर्फ़ यही वेल्थ में बढ़ोतरी का इशारा करता है। तब कोई एक्टिव बैलेंस ऑफ़ ट्रेड की बात करता है। अगर इम्पोर्ट की ज़रूरत एक्सपोर्ट से ज़्यादा बनी रहती है, तो इस कमी को बैलेंस करने के लिए अंदरूनी वेल्थ के कुछ हिस्से विदेशी देशों को देने होंगे। लेकिन ये डिलीवरी, क्योंकि इन्हें असल में वर्क इनकम से नहीं निकाला जा सकता, एक बार फिर सिर्फ़ वेल्थ से ही ली जानी चाहिए। यह या तो गोल्ड या सिक्योरिटीज़ के एक्सपोर्ट से होता है। खासकर आखिरी "एक्सपोर्ट" तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट स्लेवरी की शुरुआत के अलावा और कुछ नहीं है। क्या यह "सिक्योरिटीज़ का एक्सपोर्ट" आगे बढ़ता है?

मौजूदा इंटरनल सिक्योरिटीज़ या विदेशी "बॉन्ड्स" के रूप में छिपा हुआ है, इससे प्रभावित देशों को असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोच में भी, सिर्फ़ बड़े लोन कैपिटल के मुनाफ़े का पागलपन ही राज करता है, इसलिए एक अच्छी नेशनल इकोनॉमी के सभी सही शक प्रेस और पार्लियामेंट के ज़रिए कुचल दिए जाते हैं, और इस बॉन्ड को बनाने वाले इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए सभी देशों की इंटरनेशनल गुलामी एक डरावने दायरे तक फैल जाती है।

यहां तक कि इंटरनेशनल इकॉनमी में भी वही चीज़ें दिख रही हैं जो देश की अंदरूनी इकॉनमी में हैं और आज अलग-अलग देशों की इकॉनमी को हिला देने वाले भयानक संकट, जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी कल्चरल सर्कल के सभी देशों की गुलामी का नतीजा हैं। कमज़ोर करेंसी वाले देश, जिनकी अंदरूनी इकॉनमी बहुत कमज़ोर हो गई है (रूस) या जिनकी अंदरूनी हालत क्रांति की वजह से अनिश्चित हो गई है (जर्मनी) और जिनका अभी भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन सरप्लस दुश्मन से हर्जाने के तौर पर मुफ़्त में ज़ब्त कर लिया गया है, उनके पास अब सरप्लस खरीदने की ताकत नहीं बची है, इसलिए वे अब अपनी इम्पोर्ट की ज़रूरतों को सामान से नहीं, बल्कि कागज़ के पैसे से पूरा कर सकते हैं, जिसे वे बड़ी मात्रा में दूसरे देशों में फेंकते हैं ताकि उससे विदेशी करेंसी खरीद सकें।

इस तरह वे अंदरूनी इकॉनमी और विदेशी इकॉनमी, दोनों को एक जैसा नुकसान पहुंचाते हैं।
दूसरी तरफ, जिन देशों की करेंसी मज़बूत होती है, वे अपनी करेंसी के बढ़ने पर ही दम तोड़ देते हैं (जैसे, स्विट्ज़रलैंड)। वे अब अपने प्रोडक्ट्स को पहले के बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पैसे की ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू की वजह से उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं। ये देश अपनी मज़बूत करेंसी से अपनी इम्पोर्ट की ज़रूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं।

लेकिन जब खराब करेंसी वाले देशों में तैयार सामान बहुत सस्ता मिलता है, तो व्यापारी और मुनाफाखोर कमज़ोर करेंसी वाले देशों में जाकर इन देशों को खरीद लेते हैं और लूट लेते हैं, जिससे दोनों देशों को नुकसान होता है – लोकल प्रोडक्शन को नुकसान होता है और जिन देशों को खरीदा जाता है, वहां खपत को नुकसान होता है, जिसमें पहले से ही कम स्टॉक में सामान होने की वजह से इन बेतहाशा खरीदारी से और भी कम हो जाता है। इस तरह कमज़ोर करेंसी वाले देशों में नेशनल करेंसी की खरीदने की ताकत एक बार फिर डूब जाती है।

इन पूरी तरह से उलट-पुलट रिश्तों को देखते हुए, सब कुछ बहुत पहले ही खत्म नहीं हुआ है, इसका कारण यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंस की सभी चालों के ऊपर भी, आपसी इंटरनेशनल ज़रूरतें बस हावी रहती हैं। बस, सब कुछ आखिरी पल में, कराहते हुए होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल की ब्याज की मांग – इंटरनेशनल इकॉनमी के कामों में अड़चन डाल दी गई है। या, मेडिकल इमेजरी में कहें तो: इंटरनेशनल इकॉनमी के हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन में, पहले छोटा, लेकिन आज पहले से ही बहुत बड़ा, कार्सिनोमा हो गया है, जिसका सिर्फ एकतरफा फायदा है कि वह शरीर के बाकी हिस्सों की कीमत पर सारा खून अपने अंदर खींच ले और हर चीज़ से एक ट्रांज़िट टोल, एक फायदा ले। सारा खून बेशक दिल में बहता है, लेकिन दिल हर धड़कन के साथ खराब खून भी बाहर निकालता है। सरकारी बैंक जो सिर्फ़ पैसे का लेन-देन करता है, ठीक इसी इमेज से मेल खाता है – और कैंसर से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फाइनेंस की एक्टिविटी मेल खाती है, जो अपने क्रेडिट बैंकों के ज़रिए दुनिया के सारे पैसे को भी कंट्रोल करता है और पूरी इंटरनेशनल इकॉनमी को अपनी पकड़ में रखता है और हर जगह इंटरेस्ट लेता है। यह सब ज़रूरी नहीं है! दुनिया के देशों को किसी भी तरह से सुपरनेशनल फाइनेंशियल पावर की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है, ऐसे इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं जो क्लियरिंग हाउस या पोस्टल चेक अकाउंट के तौर पर इंटरनेशनल पैसे के लेन-देन को इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करें। इसका ध्यान सरकारी फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस रख सकते हैं और रखेंगे।

किसी भी मामले में, इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन को ऑर्गनाइज़ करने के लिए काफ़ी तरीके और साधन हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन बनाना मुमकिन था।

ज़्यादातर क्लियरिंग के ज़रिए, बिना इंटरनेशनल फाइनेंस को इन सभी आसान मर्केंटाइल कामों में दो या तीन गुना फ़ायदा पहुँचाए और प्रोडक्टिव देशों की कीमत पर बड़े और मोटे बनते हुए। यहाँ डिटेल्स फालतू हैं।

इसलिए, जैसा कि ज़ोर दिया गया है, करेंसी के स्टेबलाइज़ेशन को इंटरनेशनल रिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों या नोट प्रिंटिंग प्रेस के बिना रोक-टोक वाले मैनिपुलेशन में मौजूद गलतियों और गैर-ज़िम्मेदारियों के सोर्स को हटाने की कई संभावनाएं हैं।

प्रस्तावित उपाय पहले से टेस्ट किए गए सिस्टम के दायरे में आते हैं; जैसे राइशबैंक और सेंट्रल बैंकों का नेशनलाइज़ेशन, ये सिर्फ़ पैसे के लेन-देन के रक्षक के तौर पर सरकार के अपने कामों के प्रति नए नज़रिए के लॉजिकल नतीजे के तौर पर सामने आते हैं। ये सिर्फ़ उन हालातों पर एक नैचुरल रिएक्शन दिखाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की सबसे बड़ी कीमत पर हाई फाइनेंस के फ़ायदे के लिए थे। राइशबैंक के नेशनलाइज़ेशन का समझदारी भरा तरीका पोस्टल चेक सिस्टम के मॉडल के हिसाब से सरकार द्वारा पैसे के लेन-देन का रेगुलेशन और बीच-बचाव करना है , जिसे इस मकसद के लिए और बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा सही तरीके से डेवलप किया जाएगा।

ये सभी उपाय असल में पहले से ही काफी मज़बूत कदम हैं, लेकिन इन्हें नेशनल सोशलिस्ट सिद्धांत के हिसाब से आर्थिक नज़रिए को पहले से ही पूरी तरह बदले बिना भी किया जा सकता है, जिसे पूरे ज़ोर के साथ पेश किया गया है: "इकॉनमी का काम ज़रूरत को पूरा करना है, न कि प्राइवेट कैपिटल का मुनाफ़ा कमाना"।

फाइनेंशियल और टैक्स सिस्टम के क्षेत्र में यह बुनियादी बदलाव और नई व्यवस्था, और खासकर लोन के रास्ते से बचते हुए बड़े सरकारी कामों की फाइनेंसिंग, साथ ही फाइनेंशियल पॉलिटिकल उपाय जो असल में सोशल पॉलिसी के क्षेत्र के कामों के दायरे के करीब आते हैं, इन पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे।

नए तरीके

बड़े पब्लिक कामों की फाइनेंसिंग।

राज्य के सबसे ज़रूरी कामों में से एक है, काफी बड़े आर्थिक कामों को पूरा करना, जिनका काम प्राइवेट बिज़नेस ग्रुप के कैपिटल रिसोर्स से ज़्यादा होता है, और जिनके काम में काफी पब्लिक-लीगल हित भी शामिल होते हैं और जिनका काम प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल पर आधारित होता है। इसलिए, ऐसे काम जिनमें समुदाय की प्राकृतिक ताकतों के इस्तेमाल का मुद्दा हो, या जिनका काम उन कामों के दायरे में होना हो जो मुख्य रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का पूरा क्षेत्र।

हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से मुमकिन है कि जिस फील्ड में सरकारी पहल को डेवलप किया जा सकता है, उसे ठीक-ठीक लिमिट किया जाए, बिना प्राइवेट एंटरप्रेन्योरियल पहल के लिए लिमिट तय किए या राज्य को उससे मुकाबला करने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा, इसके अलावा, यह भी सच है कि इन बड़े पब्लिक कामों को करने का काम नैचुरली लगभग पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को ही दिया जाता है।

हमने पहले ही बेसिक बातों में डिटेल में बताया है कि सरकार ने हमारे जर्मन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कितने अच्छे तरीके से बनाया है। ज़रूर, कुछ जगहों पर इसे प्राइवेट कंपनियों ने ज़्यादा समझदारी और सस्ते में डेवलप किया होता, लेकिन जिन कामों में लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी हो, उनमें सवाल उससे ज़्यादा मज़बूती का है। अब, ट्रांसपोर्ट का काम पक्का पूरी तरह से सरकार का काम है।

भरोसा, समय की पाबंदी, सुरक्षा, रेलवे और डाक के लिए एक जैसा टैरिफ़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तय करने वाले नज़रिए होने चाहिए – न कि प्राइवेट कैपिटल का मुनाफ़ा।

लेकिन यह सवाल इतने बड़े पब्लिक फंड की फाइनेंसिंग के तरीके से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है।
कार्य.

हम पहले ही अंदर की बकवास देख चुके हैं जो इस बात से पता चलती है कि पार्लियामेंट से मंज़ूर "क्रेडिट" को बाद में प्राइवेट कैपिटल से फिर से "मंज़ूर" करवाना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को ब्याज के वादे के ज़रिए खुद पर एक बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ता है।

अब यहाँ इस बात की ज़रूरत नहीं होगी कि ब्याज के इस वादे के खतरनाक नतीजों के बारे में आम तौर पर बताया जाए। यह काम असल में इस बात को साबित करने के लिए है। फिर भी, यहाँ इस बात का भी खास ज़िक्र करना ज़रूरी है कि सरकारी लोन पर ब्याज के इस वादे ने रेलवे टैरिफ को कितना ज़्यादा महंगा बना दिया है, और हर उस इंसान के लिए जो इन आंकड़ों को पहली बार सुनता है, कितने अविश्वसनीय तरीके से।

जर्मन राइश रेलवे के पूरे नेटवर्क की कैपिटल कॉस्ट, जिसे लोन लेकर बनाया गया था या शुरू किया गया था, 1914 तक लगभग 25 बिलियन गोल्ड मार्क्स थी। इस रकम पर इंटरेस्ट पेमेंट, औसतन 31/2 – 4% इंटरेस्ट के साथ, लगभग 800-900 मिलियन गोल्ड मार्क्स था। पर्सनल (ऑफिसर और एम्प्लॉई) और मटीरियल (कोयला और लुब्रिकेंट) खर्चों को हटाने के बाद, नेट रेवेन्यू लगभग 800-1100 मिलियन मार्क्स था।

इस तरह इंटरेस्ट पेमेंट ने जर्मन रेलवे की लगभग पूरी नेट रेवेन्यू खत्म कर दी। यह हमेशा पब्लिक ओपिनियन को गुमराह करने वाला था जब यह बात बड़े गर्व के साथ बताई जाती थी कि पोस्ट और रेलवे से होने वाली कमाई स्टेट बजट की रीढ़ है। बेशक, ऐसा हो सकता था, अगर इंटरेस्ट पेमेंट ने पूरी नेट रेवेन्यू खत्म न की होती। तुलना में एक और दिलचस्प बात यह है कि सभी जर्मन रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों और प्लांट और लाइन पर काम करने वाले रेलवे वर्कर्स की सैलरी और वेतन पर कुल खर्च, कुल मिलाकर ठीक उतना ही था जितना

जितना लोन कैपिटल पर इस इंटरेस्ट चार्ज ने किया! दूसरे शब्दों में: 782,731 लोगों की हेडकाउंट वाली सबसे ऊंचे पदों तक के जर्मन रेलवे कर्मचारियों की बड़ी सेना को अपने काम के लिए उतनी ही इनकम मिली है जितनी लोन कैपिटल के पूरी तरह से इनैक्टिव हाथ ने अपनी जेब में डाली है।

सिर्फ़ रेलवे से लोन कैपिटल पर यह इंटरेस्ट पेमेंट उस समय की हमारी पूरी बड़ी राइख सेना के कुल खर्च से भी ज़्यादा था! – और असल में इससे जुड़ी हर चीज़ के लिए, जिसमें मिलिट्री सुपरविज़न, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ जस्टिस, जिसमें गैरीसन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन के सिस्टम, मिलिट्री एजुकेशन और डेवलपमेंट सिस्टम, टेक्निकल इंस्टिट्यूट, रिलीफ और मिलिट्री विडो फंड शामिल हैं – और, इसके अलावा, सैनिकों के कपड़े और हथियार भी शामिल हैं! हमारी पूरी सेना के लिए कुल रकम 1913 में – यानी शांति के आखिरी पूरे साल में, 775,385,300 मार्क थी। ऐसे कम्पेरेटिव आंकड़े गहरी समझ देते हैं। जबकि सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक पक्ष पार्लियामेंट्री सेशन और प्रेस में "मिलिट्री हथियारों के बोझ" के खिलाफ़ लगातार आवाज़ उठाते रहे, वहीं पब्लिक लोन से ऐसे इंटरेस्ट के बोझ के खिलाफ़ – जो बाकी सभी खर्चों से कहीं ज़्यादा है – एक भी शब्द नहीं मिलता। असल में, आम ज़रूरत के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट से पूरी नेवी को भी पेमेंट किया जा सकता था। 1913 में हमारे गर्वित राइख्सनेवी का पूरा खर्च 197 मिलियन था। और यह सोचना चाहिए कि ये सारे खर्च बिना एक पैसे के पूरे हो सकते थे अगर हमारे राज्य के बजट पर इतने बड़े ब्याज का बोझ न होता।

कुछ मुट्ठी भर बड़े लोन कैपिटलिस्ट – कुछ हज़ार 'हैंगर-ऑन', यानी कुछ हज़ार मार्क की संपत्ति वाले छोटे बचत करने वाले, ऐसे पब्लिक लोन में कोई भूमिका नहीं निभाते –
इस प्रकार, हर साल, बिना किसी काम या प्रयास के, हम इतनी रकम अपनी जेब में जमा कर लेते थे जिससे हम अपने पूरे राइख प्रशासन, अपनी पूरी सेना और अपनी नौसेना को चला सकते थे और उनका भुगतान कर सकते थे।

जो लोग ऐसे आंकड़ों को देखते हुए, आम तौर पर ब्याज की समस्या की बहुत ज़्यादा अहमियत और खास तौर पर लोन इकॉनमी के साथ पूरी तरह से फेल हो चुकी नेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी को नहीं समझते, उनकी मदद नहीं की जा सकती। और तो और, जो आंकड़े और नंबर ऐसी जानकारी देते हैं, वे सभी के लिए आसानी से मिल जाते हैं। वे जर्मन राइख के लिए स्टैटिस्टिकल ईयरबुक में मिलते हैं , जिसे पहले के रॉयल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बहुत ध्यान से छापा था। और वे इसी तरह रिपब्लिकन स्टैटिस्टिकल राइख्सऑफिस द्वारा पब्लिश जर्मन राइख, पुट्टकैमर और मुहलब्रेक्ट पब्लिशर्स के लिए स्टैटिस्टिकल ईयरबुक में भी मिलते हैं।

राइख्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और नेवी के लिए ज़रूरी खर्चों और लोन कैपिटल के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए राज्य के खर्चों के बीच इस तरह का असंतुलन एक अन्याय बन जाता है, जो आसमान छू रहा है। यह बात पूरी तरह तभी साफ़ होगी जब हम देखेंगे कि राइख अब इन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अपनी पैसे की ज़रूरत को कैसे पूरा करता है। यहाँ हम कस्टम और टैक्स के फील्ड पर आते हैं। मुझे यहाँ एक बार फिर अपनी किताब 'द कमिंग टैक्स स्ट्राइक' में इस स्थिति के पूरे चित्रण की ओर इशारा करना होगा, जहाँ मैंने यह पक्का सबूत दिया है कि सभी टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा काम करने वाली आबादी के बड़े हिस्से द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार हमारे सामने यह तथ्य है कि राज्य पहले, अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी में मौजूद संभावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, बड़े सार्वजनिक कामों को पूरा करने के लिए लोन का रास्ता अपनाता है, यानी कर्ज़ लेता है; फिर वह अपने बजट पर इस तरह से और बोझ डालता है कि उसे अपनी सारी नेट कमाई इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसे अपनी इंटरेस्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लोगों पर ड्यूटी और टैक्स लगाकर और ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है। राज्य के सभी ज़रूरी काम अब उसे प्रांतीय और राइख्सपार्लियामेंट में सबसे बड़े विरोध के खिलाफ लड़ने होंगे, और आखिर में राज्य खुद को लोन कैपिटल के लिए ब्याज वसूलने वाले की भूमिका में देखेगा, जैसा कि हम आज देखते हैं।

इसका रास्ता बहुत पहले ही बताया जा चुका है – आज के अजीब हालात की इतनी डिटेल में जांच के बाद यह साफ़ है; वह यह है कि:

सरकार अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के आधार पर और पार्लियामेंट के ज़रिए लोगों की मंज़ूरी के बाद, राइख के सभी बड़े पब्लिक कामों को फाइनेंस करेगी, और कैशलेस ट्रांसफर ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए सीधे पैसे बांटने या बिना ब्याज वाले सरकारी ट्रेजरी नोट जारी करके लोन देने से पूरी तरह बचेगी।

मैं इस बात को एक उदाहरण से सबसे अच्छे से समझा सकता हूँ: बवेरियन हाइड्रो-एनर्जी का विकास।

पहाड़ी नदियों में मौजूद बहुत ज़्यादा हाइड्रो-एनर्जी को, बड़ी पहाड़ी झीलों के साथ मिलाकर, काम का बनाने की योजनाएँ और कोशिशें दो दशक से भी ज़्यादा पुरानी हैं। बेशक, इस हाइड्रो-एनर्जी के मामले में, यह देश के एनर्जी सोर्स का मामला था जो कम्युनिटी के थे और उनसे लेकर पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इस तरह, यह साफ़ है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, कई पब्लिक और प्राइवेट कानूनी हित प्रभावित हुए। यह यहाँ एक ऐसे फ़ील्ड का मामला है जो सिर्फ़ स्टेट के असर वाले इलाके में आता है। लोगों ने भी दिसंबर 1920 में अपने नुमाइंदों के ज़रिए क्रेडिट को ज़बानी मंज़ूरी दे दी थी। इस पर काफ़ी सलाह दी गई थी, बार-बार टेस्ट किया गया था और फिर से प्लान किया गया था और बड़े आर्थिक फ़ायदों के बारे में पूरी तरह साफ़ था। स्टेट और लोगों ने एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था, अब उन्हें इस क्रेडिट मंज़ूरी के साथ, बस यह फ़ैसला लेना था कि एंटरप्रेन्योर्स द्वारा कमाई गई रकम को मंज़ूर क्रेडिट के आधार पर सीधे स्टेट बैंक द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। यह कैश के बिना होगा, गिरो ट्रांज़ैक्शन में ट्रांसफर के ज़रिए होगा, या पोस्टल चेक अकाउंट में क्रेडिट एडवाइस के ज़रिए होगा या कैश में होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

यह सच में साफ़ है, अगर हम सोचें कि ऐसे मकसदों के लिए स्टेट बैंक ज़रूरी और मंज़ूर क्रेडिट की रकम के लिए अपना पैसा जारी करेगा। इस तरह ये हाइड्रो-एनर्जी कंस्ट्रक्शन नोट्स कुछ हद तक स्टेट ट्रेजरी नोट्स थे जो स्टेट गारंटी के तहत एंटीसिपेटरी क्रेडिट के तौर पर बढ़ते पानी के कामों को जारी किए जाते थे। इस तरह यह कई तरह से कवर किए गए पैसे का मामला था। कवरेज में सबसे पहले तैयार या बढ़ते वाल्चेन्सी काम वगैरह शामिल थे और दूसरा स्टेट गारंटी में कि पेमेंट के बजाय पब्लिक ट्रेजरी से पैसा पूरी वैल्यू पर लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन नोट्स उसी समय वाटरवर्क्स पर पार्शियल डिबेंचर भी होंगे, हालांकि उनसे कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं जुड़ा होगा। हालांकि, जैसा कि सब जानते हैं, सर्कुलेशन में मौजूद किसी भी दूसरे नोट के साथ ऐसा नहीं है।

हाइड्रो-एनर्जी कंस्ट्रक्शन नोट्स में इन स्पेसिफिकेशन्स को उनकी कीमत के पूरे कवरेज पर उनके इंप्रिंट के टेक्स्ट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: "यह हज़ार मार्क का नोट बवेरियन हाइड्रो-एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे इंस्टॉलेशन की कीमत में थोड़ा-बहुत कवरेज पाता है। इसे सभी सरकारी ट्रेजरी में पेमेंट के तौर पर लिया जाता है"।

अगर कोई और आगे जाना चाहे, तो काम पूरा होने के बाद, नोट जमा करने के बदले में, राज्य के इतने किलोवाट घंटे बिजली या इतने सौ वज़न नाइट्रोजन देने का वादा करने में कोई रुकावट नहीं है।

कोई भी सरकार से मिले ऐसे पैसे को लेने से मना नहीं करेगा जो पूरी तरह से सामान से भरा हो, और जिसे कुछ हद तक बिजली के लिए राशन कूपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके उलट, हम पक्का मान सकते हैं कि ऐसे पैसे को खास पॉपुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि यह पैसा – स्टेबल है, बिल्कुल डॉलर जितना स्टेबल, या उससे भी बेहतर क्योंकि इसके बदले में कोई भी काफी तय मात्रा में बिजली या नाइट्रोजन ले सकता है – जो आर्थिक उतार-चढ़ाव से अलग हो। यह लोगों की पूरी छोटी सोच की निशानी है कि अलग-अलग बहस करने वालों के पब्लिक प्रोपेगैंडा में यह एतराज़ उठा कि – "कोई भी इस पैसे को नहीं लेगा"।

किसी भी आदमी ने, यहाँ तक कि इन बहस करने वाले सज्जनों ने भी – सरकार द्वारा जारी किया गया पैसा लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सबने राइशबैंक के सबसे खराब पेपर मनी को भी स्वीकार कर लिया है, भले ही वह पैसा पूरी तरह से महंगाई वाला पैसा था। और फिर भी सबने इसे स्वीकार कर लिया, तब भी जब चालाक सट्टेबाजों ने इसे विदेशी करेंसी या सामान के बदले जितनी जल्दी हो सके बेचने की कोशिश की।

असल में, शहरों और समुदायों की इमरजेंसी करेंसी को भी किसी ने मना नहीं किया, जो इसी तरह बिना कवर वाला पेपर मनी था। और अब क्या हमारे बड़े कामों के लिए मटेरियल एसेट्स से पूरी तरह कवर किया गया कंस्ट्रक्शन मनी जैसा बेहतर कवर्ड पेपर मनी तुरंत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? ज़रूर, जो लोग अपने मालिकों की तरफ से या उनकी भावना से बिना ब्याज वाले सरकारी पैसे पर ऐसी आपत्तियां उठाते हैं, वे भी असल में ऐसा नहीं मानते।

यह बात सच साबित हो चुकी है कि "मेटलिस्ट" जो सिर्फ़ कीमती धातुओं से बने पैसे को ही पैसा मानते हैं, उनकी सभी शिकायतों के बावजूद, "पैसा" वह है जिसे सरकार पैसा घोषित करती है – चाहे यह पैसा कागज़ या चीनी मिट्टी, लोहे या चमड़े या किसी और चीज़ का बना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इस पैसे की खरीदने की ताकत की बात आती है तो यह बिल्कुल अलग होता है। वहाँ मेटलिस्ट सही हैं कि सोने से बनी करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादातर तब भी बनी रहती है जब सरकार में राजनीतिक उथल-पुथल मच जाती है। हालाँकि, कीमती धातुओं से बने मेटैलिक पैसे की यह स्थिरता उसके मॉनेटरी कैरेक्टर की वजह से नहीं, बल्कि एक कमोडिटी, यानी सोने के कैरेक्टर की वजह से है।

इस बात पर कोई शक नहीं हो सकता कि राज्य किसी बड़े काम के लिए अपनी पैसे की ज़रूरत को जिस तरह से बताया गया है, उसे पूरा करने का सही तरीका है। पहली बात, राज्य सॉवरेन है, यानी उसे किसी के असर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर है, और दूसरी बात, ऐसा तरीका सबसे सख्त कमर्शियल जांच में खरा उतर सकता है। राज्य यह कैश एक तरह से अपने क्रेडिट के आधार पर वाउचर के तौर पर देता है। किसी को भी राज्य के क्रेडिट की तुलना में बैंकों के क्रेडिट से कम परवाह क्यों होनी चाहिए, खासकर तब जब राज्य समुदाय की भलाई के लिए काम कर रहा हो। भले ही कोई यह कहे कि राज्य किए गए काम (वाल्चेंसी के काम में लगे एंटरप्रेन्योर और वर्कर) का पेमेंट कागज़ से करता है, तो यह सच में सही है क्योंकि बाद में, काम पूरा होने के बाद, राज्य इस कागज़ को अपने किए गए काम (बिजली या नाइट्रोजन की सप्लाई, वगैरह) के पेमेंट के तौर पर एक बार फिर लेता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक साइकिल पूरा हो जाता है। इस तरह, कंस्ट्रक्शन के नोट एक बार फिर पहले सालों की बिजली सप्लाई वगैरह से भुनाए जाते हैं, नोट नष्ट कर दिए जाते हैं, और एक इंटरेस्ट फ्रीवे पर सभी के लिए बिना इंटरेस्ट वाली सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशनल आर्ट का एक बहुत बड़ा काम बनाया गया है। एक ऐसा काम जिसने, बिजली कंज्यूमर्स पर ज़्यादा बोझ डाले बिना, राज्य के लिए पैसे का एक और बड़ा सोर्स इस्तेमाल किया है, जो बदले में राज्य को एक हेल्दी नेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी के आदर्श लक्ष्य – बिना टैक्स वाला राज्य – के करीब लाता है।

अब, इसके अलावा, यह भी बात है कि किसी खास काम के लिए अपने कंस्ट्रक्शन के पैसे जारी करने के बताए गए प्रोसेस में, ऐसे कंस्ट्रक्शन नोट्स में पूरी मंज़ूर रकम जारी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि असल में एंटरप्रेन्योर्स को पेमेंट का ज़्यादातर हिस्सा कैश में नहीं, बल्कि कैश फ्री, ट्रांसफर के ज़रिए होता है। लेकिन, अगर यह मान भी लें कि किसी ने नए कंस्ट्रक्शन की पूरी रकम नए स्टेट बैंक नोट्स में जारी की है, तो भी यह रकम उन दूसरी रकमों की तुलना में ज़्यादा नहीं होगी जिनकी आज राज्य को ज़रूरत है।

ठीक उसी समय जब बवेरियन हाइड्रो-एनर्जी के लिए 800 मिलियन के क्रेडिट को लेकर बवेरियन पार्लियामेंट में किसी का सिर फूटा था – या बेहतर कहें तो: टूटा नहीं बल्कि बस एक बार फिर "लोन" का सहारा लिया गया था, 8000 मिलियन को पार्लियामेंट में "जनरल इमरजेंसी के मकसद से तीसरी रीडिंग में बिना बहस के" मंज़ूरी दे दी गई थी।

यहां मैं एक बार फिर उन बातों को याद दिलाता हूं कि, नए पैसे जारी करके ऐसी फाइनेंसिंग के मामले में, किसी भी तरह की महंगाई नहीं आएगी, दूसरी ओर, कंस्ट्रक्शन के समय ब्याज वाले बॉन्ड जारी करना किसी भी मामले में एक खास बात दिखाता है।

महंगाई, क्योंकि ब्याज तो पहले ही चुकाना होगा, भले ही काम से अभी तक कोई प्रोडक्टिव काम न हुआ हो।

लेकिन, क्वांटिटी थ्योरी के हिसाब से, पैसे और चीज़ों के बीच नेशनल इकोनॉमिक बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे की तरफ़ पेमेंट के तरीकों में बढ़ोतरी के मुकाबले, चीज़ों में ठीक ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अगर बाद में, ऐसे कामों से होने वाली कमाई के ज़रिए, जारी किया गया पैसा एक बार फिर निकालकर खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसे नए कामों की कुल कीमत के हिसाब से नेशनल इकोनॉमिक बैलेंस अपने आप नेशनल दौलत के फ़ायदे के लिए बेहतर हो जाता है।

यहां भी यह बताना ज़रूरी है कि ऐसे कामों के प्रोडक्ट की लागत पर ब्याज कितना ज़्यादा असर डालता है। इस सवाल की डिटेल में जांच करने पर ओस्कर पोबिंग77 ने पाया है कि एक किलोवाट घंटे के लिए प्रोडक्शन की लागत, लोन पर 500% (!) की भारी रकम के ब्याज के बोझ से और महंगी हो जाती है। अब हमारे बवेरियन हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कामों से बिजली हमें पांच गुना ज़्यादा महंगी मिलती है क्योंकि हमने एक बार फिर उस लोन के रास्ते का सहारा लिया है जो "सबसे पास" है। यहां भी यह सोचना सही है कि बड़े बवेरियन इलेक्ट्रिक कामों और इंटरअर्बन ऑफिसों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पूरा सामान और पर्सनल खर्च – यानी इन कामों में लगे सभी लोगों की सारी सैलरी और वेतन – जैसे स्लूस अटेंडेंट, मशीनिस्ट, वर्कर, मज़दूर, सुपरवाइज़री कर्मचारी, और आगे डायरेक्टर तक पूरा टेक्निकल और कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिलकर हर साल अपने काम के लिए उस रकम का सिर्फ़ पांचवां हिस्सा लेते हैं जो – इतने अच्छे – लोन कैपिटलिस्ट हर साल बिना मेहनत या काम के – ब्याज के तौर पर लेते हैं।

ब्याज सब कुछ खा जाता है, ब्याज हर चीज़ को और महंगा बना देता है। सिर्फ़ लोन कैपिटल को फ़ायदा होता है, नुकसान आबादी को होता है। जो आबादी अपनी ताकत से काम बनाती है, उसे नुकसान होता है; क्योंकि फिर बवेरियन काम कौन बनाता है? - असल में बवेरियन इंजीनियर, बवेरियन वर्कर, बवेरियन फोरमैन और एंटरप्रेन्योर; बवेरियन फैक्ट्रियां ज़्यादातर मशीनें और इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं – और जो बवेरियन में खुद नहीं बनता, उसके लिए बवेरियन अनाज या मवेशी देने पड़ते हैं, इस तरह बदले में बवेरियन काम एक बार फिर देना पड़ता है – सिर्फ़ बवेरियन लोग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं लगाते (ज़ाहिर है!), और इसलिए इसके लिए उसे न्यूयॉर्क और लंदन, पेरिस और बर्लिन के बड़े कैपिटलिस्ट की ज़रूरत होती है। बवेरियन लोगों को दुनिया के सभी देशों से उधार लेना पड़ता है और अपनी हाइड्रो-एनर्जी पर ब्याज का बोझ डालना पड़ता है जिससे बिजली 500% ज़्यादा महंगी हो जाती है!

क्या यह पागलपन नहीं है? क्या यह एक आर्थिक अपराध नहीं है? जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस एक बार अपनी कलम चलाई और चेक लिखा या अपने बैंकर को बवेरियन हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लोन पर साइन करने के लिए कहा, उन्हें इसके लिए, साल दर साल, बवेरियन लोगों से ब्याज मिलता है।

इतना ही नहीं, पानी के प्लांट अब बवेरियन लोगों के पास नहीं रहे, बल्कि वे कैपिटलिस्ट के पास गिरवी रखे गए हैं। और भी मज़ेदार बात यह है कि बड़े कैपिटलिस्ट स्वाभाविक रूप से "अपना अच्छा पैसा" ऐसे राज्य को उधार नहीं देंगे जो खुद कैपिटल और हितों के लिए "अच्छा" न हो, इसलिए उसे अभी भी इतना क्रेडिट मिलता है कि कोई भी

इसमें 800 मिलियन डॉलर डाले गए। और असल में, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक बॉन्ड के टेंडर में वह गारंटी थी जो कैपिटलिस्ट को इतनी लुभावनी और भरोसा दिलाने वाली थी कि "बवेरियन सरकार अपनी पूरी दौलत के साथ कैपिटल और इंटरेस्ट की गारंटी देती है – (!)"

---

77 ओस्कर पोबिंग (1882-1956) एक बवेरियन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने म्यूनिख में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काम किया था।
वह डाई वासेरक्राफ्ट बायर्न्स (1919) और ज़ूर बेस्टिमुंग स्ट्रोमेन्डर फ्लुसीगकेइट्समेन्गेन इन ऑफ़ेनेन गेरिनेन (1922) जैसे अध्ययनों के लेखक थे ।

मनीबैग, तुम्हें और क्या चाहिए! तो यहाँ बवेरियन सरकार साफ़-साफ़ मानती है कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, कि उसे वाल्चेन्सी हाइड्रो-एनर्जी और मिडिल इसार के लिए 800 मिलियन का लोन दिया जा सकता है, लेकिन – वह अपनी फ़ाइनेंशियल सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करके इन कामों को अपनी अथॉरिटी से फ़ाइनेंस नहीं कर सकती। क्यों?? क्योंकि वह लोन और इंटरेस्ट के पागलपन में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, क्योंकि उसके ज़िम्मेदार नेताओं में इतनी सोचने की क्षमता और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है कि वे इन आसान और साफ़ प्लान को इंटरेस्ट के लिए जज करने की हिम्मत करें।

खुद से फ्री फाइनेंसिंग; इसलिए वे प्रोफेशनल बैंकिंग एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंजम्पशन वाला अपने ट्यूबरकुलोसिस बैसिली से पूछे कि क्या उन्हें लगता है कि उसकी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उसका दावोस जाना सही है या एंगाडिन78, और उन्होंने उसे भरोसा दिलाया: "नहीं, बस ऐसा मत करो, सफर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, शायद कोई रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, बल्कि अपने घर में, अपने नॉर्मल माहौल में रहो। तुम्हारी हालत में तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए! वगैरह।" ट्यूबरकुलोसिस बैसिली के नज़रिए से इस सलाह को मानने से, कंजम्पशन अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बैसिली बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। फाइनेंशियल और इंटरेस्ट इकॉनमी के हमारे मामले में बिल्कुल ऐसा ही है।

अपने ही दुश्मनों से सलाह लेना, सीधे-सादे जर्मन लोगों की खासियत है। अगर कोई ऐसा आदमी सामने आता है जो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और उन्हें यह-वह सलाह देता है और ज़िम्मेदार लोगों को इस या उस बदमाशी के बारे में बताता है, तो शर्त लगा सकते हैं कि परेशान लोग उस बदमाश के पास दौड़कर जाएंगे और उससे बहुत भोलेपन से पूछेंगे: "मुझे बताओ, फलां ने मुझसे कहा है कि तुम बदमाश हो, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या यह सही है!" और अगर दूसरा उसे दुनिया के सबसे ईमानदार चेहरे से समझाता है: "लेकिन तुम क्या सोचते हो – मैं एक बदमाश हूँ! – इसके उलट, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैंने हमेशा हमारी पैसे की मुश्किलों से तुम्हारी मदद की है", तो सीधा-सादा सवाल पूछने वाला काफी खुश होता है – उसने काफी कुछ कर लिया है और वह खास तौर पर खुश होता है कि उसे अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ता। लेकिन, लोगों के परेशान करने वाले दोस्त को वह आम तौर पर अपने जवाब के लायक नहीं समझते – और चीज़ें ब्याज वाली कैपिटलिस्टिक लोन पॉलिसी की खाई में और फंस जाती हैं, जब तक कि मुफ़्त राष्ट्रीय दौलत का आखिरी आइटम फ़ाइनेंशियल ताकतों के पास गिरवी न रख दिया जाए और पूरा देश सिर्फ़ इंटरनेशनल फ़ाइनेंस को ब्याज देता रहे।

आखिर में, हमें इसी संदर्भ में इस बात पर और ज़ोर देना चाहिए कि बवेरियन सरकार – जब यह किसी भी तरह से बवेरियन हाइड्रो-एनर्जी के विकास जैसा कोई ज़रूरी सरकारी काम नहीं था, यानी, जब यह नवंबर सरकार के पैसे के संकट को ठीक करने का मामला था – बवेरियन स्टेट बैंक से बवेरियन स्टेट बैंक के लगभग 130 मिलियन सरकारी ट्रेजरी नोट जारी करने में बहुत तेज़ी दिखाई। यह पूरी तरह से बिना किसी पहचान के हुआ – और हर किसी ने इन बवेरियन नोटों को उतनी ही खुशी से लिया जितना राइक्सबैंक के नोटों को, और हर कोई बवेरियन वाउचर से अपने लिए उतनी ही रोटी खरीद सकता था जितनी राइक्सबैंक के नोटों से। असल में, यह पूरे बवेरियन राज्य के लिए ज़रूरी भी नहीं था, अगर राज्य की राजधानी म्यूनिख के मेयर और शहर के कुछ बड़े-बुज़ुर्गों के नाम ऐसे रंगीन कागज़ों पर छप जाते, तो यह काफ़ी होता, और यह इमरजेंसी पैसा भी चलता, हर कोई इसे लेता और हर कोई इसे बिल्कुल राइख्सबैंक के टुकड़ों की तरह बाँटता, और यह इमरजेंसी पैसा खुद ही किसी भी पैसे का काम करता था – सामान के लेन-देन में मदद का काम – बिना किसी रोक-टोक के।

प्रांतों और समुदायों के इन बनावटी कामों से सिर्फ़ एक दफ़्तर पर बहुत बुरा असर पड़ा – ज़्यादा फ़ाइनेंस – और उन्होंने अक्टूबर 1921 में एक राइख क़ानून लागू किया जिसके मुताबिक प्रांतों और समुदायों को ऋण जारी करने की सख़्त मनाही थी।

---

[78] स्विट्जरलैंड में डेवोस 18वीं सदी के बीच से ही फेफड़ों की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए एक मेडिकल रिसॉर्ट के तौर पर मशहूर रहा है। एंगाडिन स्विस आल्प्स में एक घाटी है।

इमरजेंसी मनी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सका। यह कानून असल में यहूदियों की सुरक्षा के लिए एक साफ़ कानून था, जिसे 1922 में "रिपब्लिक की सुरक्षा के लिए कानून" के तौर पर लागू किया गया।

मैं इंटरनेशनल फाइनेंस के अचानक डर का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकता हूँ जब उन्हें पता चला कि बिना ब्याज वाले पैसे में, यहाँ तक कि इमरजेंसी पैसे के नुकसान न पहुँचाने वाले रूप में भी, लोगों के हाथ में एक हथियार था – ज़ाहिर है लोगों को यह पता भी नहीं था – जो एक ही झटके में सदियों से चले आ रहे अंडरग्राउंड और नकली कामों से झूठ और धोखे से बनाए गए सुनहरे नेटवर्क को तोड़ सकता था और लोगों को ब्याज की गुलामी से आज़ाद करा सकता था।

उस समय भी, बवेरियन सरकारी पैसे के मामले में, राइक्सबैंक ने बहुत जल्द मांग की कि इस पैसे को एक बार फिर वापस लिया जाए, जो 1921 में मान लिया गया। कारण: इस पैसे से ज़्यादा फाइनेंस मिलता था, कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसा कि राइक्सबैंक के पैसे से राइक्स के ट्रेजरी बिल के इनडायरेक्ट रास्ते से मिलता है।

नेशनल सोशलिस्ट राज्य में, भविष्य में सभी बड़े सरकारी कामों को बताए गए तरीके से फाइनेंस और ऑर्गनाइज़ किया जाएगा, जिसमें लोन का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाया जाएगा। हम आम तौर पर इंटरेस्ट फ्री कंस्ट्रक्शन मनी का इनडायरेक्ट रास्ता तभी अपनाएंगे जब ज़रूरी पैसे दूसरे सरकारी कंपनियों के सरप्लस से या ऐसे खास कामों के लिए स्पेशल लेवी से नहीं जुटाए जा सकते। वैसे भी, हम जानते हैं कि फाइनेंसिंग का यह तरीका देश के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करने, ट्रांसपोर्ट रूट को बेहतर बनाने वगैरह की बहुत बड़ी और अनदेखी संभावनाएं खोलता है।

हर देश उतना ही अमीर है जितना वह काम को ऑर्गनाइज़ करने में सक्षम है।79

---

79 यह बात 30 जनवरी, 1939 को राइखस्टाग में हिटलर के भाषण में दिखती है, जिसमें उसने कहा था: "ज़रूरत की मजबूरी में... हमने सबसे पहले एक देश की सबसे ज़रूरी पूंजी, यानी उसकी काम करने की क्षमता का पूरा ध्यान रखना सीखा है।" (आर डी रूसी डी सेल्स (एड.) एडॉल्फ हिटलर: माई न्यू ऑर्डर, लंदन: एंगस एंड रॉबर्टसन, 1942, पेज 457f में कोट किया गया)।

सामाजिक निर्माण और आर्थिक बैंक

पिछले चैप्टर के साथ लॉजिकल कनेक्शन में एक सोशल कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक बनाना है, जिसका काम खास तौर पर घर बनाने के लिए बिना ब्याज के कंस्ट्रक्शन का पैसा देना है। बेशक, इस सोशल कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक को एक सरकारी संस्था के तौर पर नहीं, बल्कि पब्लिक लॉ के कॉर्पोरेशन के तौर पर चलाया जाना चाहिए। इसलिए लॉजिकली इसकी चर्चा नेशनल सोशलिस्ट टैक्स सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन के बाद होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह सोशल कंस्ट्रक्शन- और इकोनॉमिक बैंक प्राइवेट इकॉनमी की स्थितियों और असल में खासकर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम को ट्रांसफर की गई बिना ब्याज की फाइनेंसिंग के अलावा और कुछ नहीं है – इस तरह यह इकॉनमी की सबसे यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस वाली ब्रांच है – इसलिए इसे पहले रखना शायद सही है।

ऐसे कंस्ट्रक्शन बैंक को पूरी तरह से सरकारी कंपनी की तरह क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि ऐसे पब्लिक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सरकारी कंपनी की तुलना में ज़्यादा आसानी से मैन्यूवर किया जा सकता है। अगर यह सिर्फ़ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का मामला होता, तो यह इतना बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जहाँ यह सबसे ज़रूरी कामों का मामला होगा जो इनडायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, और तब बैंक, जो असल में अपने मैनेजमेंट के लिए सरकार के प्रति ज़िम्मेदार है, उसे सभी शर्तों की पूरी तरह से जाँच करने के बाद इंटरेस्ट-फ्री क्रेडिट जारी करने की भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए।

लेकिन, फ़ैसले की ऐसी आज़ादी सिर्फ़ सरकारी कंपनियों में मुमकिन नहीं है। इसलिए इसे प्राइवेट पहल पर छोड़ देना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर यहां ऐसे कानून का खाका पेश किया जा सकता है जो पास हुआ था
1922 में बवेरिया के लिए:

बवेरियन सोशल कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक के डेवलपमेंट पर कानून।

कला. I

एक नेशनल बवेरियन सोशल कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक (BWB) बनाया जाएगा।

BWB का काम राज्य के एंटरप्राइज या प्राइवेट लोगों (चाहे वे व्यक्ति हों या सोसाइटी) के देश के आर्थिक रूप से कीमती एंटरप्राइज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, जो देश के विकास में मदद करते हैं या आम भलाई के लिए फायदेमंद हैं।

अनुच्छेद 2

BWB एक पब्लिक लॉ कॉर्पोरेशन है। इसके ऑर्गनाइज़ेशन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटी और इसके डायरेक्टरशिप के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन पूरी मिनिस्ट्री तय करेगी।

अनुच्छेद 3

BWB को पहले ब्याज-मुक्त ट्रेजरी नोट जारी करने की अनुमति दी गई है।
भौतिक संपत्तियों द्वारा 50 मिलियन गोल्ड मार्क तक की राशि।

यह इश्यू सिर्फ़ इस कानूनी तरीके से हो सकता है कि किसी भी समय जारी और सर्कुलेशन में मौजूद पैसे की रकम कम से कम उसी कीमत की ज़रूरी सिक्योरिटीज़ (इंटरेस्ट-फ्री सिक्योरिटी मॉर्गेज, सिक्योरिटी बिल ऑफ़ सेल, हाइपोथेकेशन, वगैरह) से कवर हो और ट्रेजरी नोट्स का रीपेमेंट या रिटर्न, सही समय सीमा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के अंदर डेवलप होने वाले एंटरप्राइज़ या इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यू से सुरक्षित हो।

अनुच्छेद 4

BWB के जारी ट्रेजरी नोट्स के कारण गिरवी रखे गए और सिक्योरिटीज़ की कुल रकम
BWB का कवरेज एसोसिएशन बनाता है।

किसी भी तरह के कानूनी लेन-देन जो सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी कवरेज को परेशान करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं कवरेज एसोसिएशन से जुड़े सभी नियम और शर्तें अमान्य हैं।

कवरेज ऑर्गनाइज़ेशन के तहत आने वाले ऑब्जेक्ट या अधिकारों में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी या कब्ज़े का बदलाव सिक्योरिटीज़ के होने पर असर नहीं डालता है और नए खरीदार के लिए भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहता है; टाइटल में पहले वाला पर्सनल लायबिलिटी से तभी आज़ाद होता है जब BWB देनदार के व्यक्ति में बदलाव के लिए सहमत हो। इसके उलटे अरेंजमेंट अमान्य हैं...

अनुच्छेद 5

BWB के कवरेज ऑर्गनाइज़ेशन के सभी हिस्से और अधिकार इस पब्लिक रजिस्टर में रिकॉर्ड किए गए हैं; इस बुक के लिए सिद्धांत और कानूनी नतीजे रजिस्टर की तरह ही मान्य हैं; रजिस्टर पर जनता का भरोसा है और यह अपने आप में अधिकार का अनुमान रखता है।

रजिस्टर या उसके ज़रूरी सेक्शन तक एक्सेस हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो एक्सेस में कानूनी दिलचस्पी दिखाता है।

जारी किए गए ट्रेजरी नोट्स की कुल रकम, साथ ही इनके लिए BWB को देय सिक्योरिटीज़ की कुल रकम, साथ ही जोड़ और कटौती, और ट्रेजरी नोट्स के सफल रीपेमेंट और रिडेम्पशन पर बैलेंस जैसी समरी हर साल पब्लिश की जानी है।

अनुच्छेद 6

BWB के ट्रेजरी नोट लीगल करेंसी हैं। सभी को उन्हें राज्य की दूसरी लीगल करेंसी के एक्सचेंज रेट के मुकाबले उनकी फेस वैल्यू के पूरे रेट पर स्वीकार करना होगा।

अगर कोई क्रेडिटर ऊपर बताए गए मिनिमम एक्सचेंज रेट पर पेमेंट के बजाय BWB के ट्रेजरी नोट्स लेने से मना कर देता है, तो कर्जदार, अगर उसने असल में ट्रेजरी नोट्स में पेमेंट ऑफर किया है, तो इस रकम के कर्ज से मुक्त हो जाता है।

BWB बिना ब्याज के ट्रेजरी नोट्स जारी करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट में, इश्यू के समय और रेट, देनदार द्वारा चुकाए जाने वाले सिक्योरिटीज़ और मॉर्गेज, साथ ही रीपेमेंट और दूसरी ज़रूरी कानूनी शर्तों के बारे में आपसी कानूनी शर्तों की आम और खास शर्तों पर सहमत होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी कवरेज एसोसिएशन के रजिस्टर में एंट्रीज़ के अपेंडिक्स के तौर पर सभी को उपलब्ध कराई जानी है।

BWB को लोन देने में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च और सालाना कलेक्शन के लिए सरचार्ज या फीस तय करने या उससे जुड़े प्रीमियम या डिस्काउंट किसी भी समय एक जैसे पब्लिक तरीके से तय करने का हक है।

आर्टिकल 1 में तय मिनिमम रेट से ज़्यादा रेट का इश्यू या स्टॉक-एक्सचेंज कोटेशन मंज़ूर है।

रीपेमेंट सिर्फ़ उसी तरह के ट्रेजरी नोट्स में किया जा सकता है जैसे जारी किए गए थे।

अनुच्छेद 7

BWB की एक्टिविटी, जहाँ तक इस कानून में दिए गए निर्देशों का पालन करने तक फैली हुई है, एक पब्लिक सुपरवाइज़री काउंसिल के कंट्रोल और सुपरविज़न के तहत आती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर या उनके द्वारा चुना गया कोई रिप्रेजेंटेटिव, इंटीरियर मिनिस्टर या उनके द्वारा चुना गया कोई रिप्रेजेंटेटिव, जस्टिस मिनिस्टर या उनके द्वारा चुना गया कोई रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट से दो साल के लिए चुने गए तीन लोग शामिल होते हैं।

अनुच्छेद 8

पेनल्टी क्लॉज़: कवरेज एसोसिएशन की सिक्योरिटीज़ को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने और इसी तरह कमर्शियल या कस्टम, खासकर स्टॉक-एक्सचेंज, कंस्ट्रक्शन बैंक नोट्स या उनके एक्सचेंज रेट वैल्यू में तोड़फोड़ करने या ऐसा करने की कोशिश करने पर जेल की सज़ा। इसके अलावा, इसके लिए कानूनी लोगों पर भी ज़्यादा पैसे का जुर्माना लगाया जा सकता है।

"एग्जीक्यूटिव कंडीशंस" में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और एडवाइजरी बोर्ड के गठन पर सटीक निर्देश जारी किए गए, जिसमें मिनिस्ट्रीज़, पार्लियामेंट और बिल्डर्स के प्रतिनिधि शामिल हैं। ऐसे एडवाइजरी बोर्ड का काम कंस्ट्रक्शन नोट्स के कानूनी इस्तेमाल को कंट्रोल करना, रीपेमेंट की जांच करना, हाइपोथेकरी इंडेम्निटीज़ का वेरिफिकेशन करना, इंटरेस्ट-फ्री कंस्ट्रक्शन नोट्स के साथ मॉर्गेजिंग के बेसिस को अप्रूव करना वगैरह है।

आगे की शर्तों ने रीपेमेंट और क्लीयरेंस, कंस्ट्रक्शन नोट्स की जारी सीरीज़ और उसके लिए रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ पर स्टॉक-पोस्टिंग, और इसके अलावा, अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन वगैरह पर और ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन को रेगुलेट किया। उस समय ऐसे सोशल बैंक को बनाने की प्रेरणा घरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और इस हालात से मिली थी कि राइख और प्रांत किसी भी तरह से इस मुश्किल को असरदार तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हाउसिंग ऑफिस के संबंधित संस्थान बेशक यहाँ-वहाँ रहने की जगह खाली कर सकते थे – लेकिन वे कोई नया घर नहीं बना सकते थे। नए कंस्ट्रक्शन के काम में सामान की कमी थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि किराए पर मौजूदा इमरजेंसी कंट्रोल के साथ, नए घरों का निर्माण प्राइवेट कैपिटल के लिए बिल्कुल "फायदेमंद नहीं" था।

तथाकथित खोए हुए कंस्ट्रक्शन-खर्च की भरपाई के लिए राइख और प्रांतों द्वारा दिए गए ग्रांट, बढ़ते करेंसी डीवैल्यूएशन में काफ़ी नहीं थे।
यहां तक कि यहां-वहां शुरू हुए अलग-अलग घरों के कंस्ट्रक्शन से भी घरों की आम दिक्कत दूर नहीं हो पाई। सस्ते मॉर्गेज के पैसे बनाना भी नामुमकिन था, क्योंकि उस समय किराया तय था, इसलिए सबसे सस्ते कंस्ट्रक्शन के पैसे पर भी 4% का इंटरेस्ट नहीं लगता था।

इसलिए ऐसा होता है कि, जैसा कि पहले ही मौलिक टिप्पणियों में सुझाया गया है, सबसे बड़ी आवश्यकता के बावजूद - अपर्याप्त लाभप्रदता के कारण - आवश्यकता को आसानी से पूरा नहीं किया जाता है।

अब, अगर कोई हर साल आने वाले ब्याज के बोझ को हटाने में कामयाब हो जाता है, अगर कोई घर की ज़रूरत वाले लोगों के लिए बिना ब्याज के साधन देने का इंतज़ाम करता है, तो हाउसिंग मार्केट में बड़े पैमाने पर तेज़ी आ सकती है। लेकिन इससे न सिर्फ़ घर की भयानक ज़रूरत और उसके सभी सामाजिक और सेहत से जुड़े नुकसान दूर होंगे, बल्कि अंदरूनी मार्केट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि अनगिनत दूसरे काम करने वाले लोग, जैसे ताला बनाने वाले, बढ़ई, छत बनाने वाले, प्लंबर, शीशा लगाने वाले, लगाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, फ़र्श बिछाने वाले और टाइल लगाने वाले, पेंट करने वाले और प्लास्टर करने वाले, वे सब इस पर निर्भर हैं, फिर उन्हें अपने हिस्से का काम और रोज़ी-रोटी मिलती है और उनकी खरीदने की क्षमता मज़बूत होती है।

हालांकि, इसका मतलब है कि यह ब्याज-मुक्त कंस्ट्रक्शन के पैसे में दिया जाता है।

ये कंस्ट्रक्शन नोट्स "सोशल कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक बैंक" द्वारा जारी किए जाते हैं।
इस पैसे से सप्लायर और एंटरप्रेन्योर को कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट किया जाता है। बिल्डिंग का मालिक मिले हुए इंटरेस्ट-फ्री पैसे को कंस्ट्रक्शन के कैरेक्टर और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से 30-50 साल के टाइम में सही इंस्टॉलमेंट में वापस कर देता है। कंस्ट्रक्शन नोट्स राइख या प्रोविंशियल मनी से वैसे ही अलग होते हैं जैसे राइख्सबैंक नोट्स लोन ट्रेजरी नोट्स से अलग थे। जैसा कि पहले ही बताया गया है, इन कंस्ट्रक्शन नोट्स का पूरा मटेरियल कवरेज इस बात में होता है कि, उसी समय, कंस्ट्रक्शन बैंक के क्रेडिट में, जारी किए गए नोट्स के बराबर अमाउंट में, नए मटेरियल एसेट्स (घर) भी बनते हैं।

जो उसी रकम के इंटरेस्ट-फ्री मॉर्गेज के रजिस्ट्रेशन के ज़रिए कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं।

असल में, यहां भी नई बिल्डिंग्स की पूरी कीमत कंस्ट्रक्शन नोट्स में नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ़ असल बिल्डिंग खर्च ही बताया जाएगा। इसलिए, ज़मीन कम से कम बिल्डर्स या बिल्डिंग सोसाइटियों या कम्युनिटीज़ को देनी होगी और इसके अलावा, बिल्डिंग की कीमत का कम से कम 10-30% उन लोगों को देना होगा जिन्हें घर की ज़रूरत है, जिसमें से 5% कंस्ट्रक्शन बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को कवर करने के लिए वहीं रखा जाएगा।

इसके बाद बिना किसी ब्याज के कैलकुलेशन के पेमेंट किया जाता है। इस तरह घर के मालिकों की फ्री प्रॉपर्टी उनके घरों में साल दर साल बढ़ती है और इसी तरह जारी किए गए कंस्ट्रक्शन नोट्स के कवरेज के तौर पर टोटल एसोसिएशन में वैल्यू बनी रहती है।

इस तरह, रीपेमेंट के हिसाब से सर्कुलेशन में कंस्ट्रक्शन नोट्स की मात्रा कम हो जाती है।

इस कंस्ट्रक्शन मनी का लीगल कैरेक्टर बॉन्ड जारी करने के अलावा और कुछ नहीं है।
इस बॉन्ड का देनदार कंस्ट्रक्शन बैंक है। बॉन्ड का क्रेडिटर मौजूदा मालिक होता है।
यह बॉन्ड.

किसी को भी बॉन्ड जारी करने से मना नहीं किया जा सकता, यह हमेशा सिर्फ़ बाहरी हालात का सवाल होता है, कि किसी के जारी किए गए बॉन्ड आम तौर पर पेमेंट के तौर पर लिए जाते हैं या नहीं। जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है, कंस्ट्रक्शन नोट्स हमेशा और किसी भी सोची जा सकने वाली आर्थिक और राजनीतिक हालत में इनके बदले में मौजूद मटेरियल एसेट्स से पूरी तरह कवर होते हैं। इसलिए बैंक के किसी भी समय मुश्किल में पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

लेकिन, सबकी मंज़ूरी की गारंटी तब मिलती है जब राज्य कंस्ट्रक्शन नोट्स के टाइम-लिमिटेड रिडेम्पशन की गारंटी लेने का वादा करता है और नोट्स के समय के दौरान, अपने रजिस्टर में नोट्स को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करता है या जब उन्हें पेमेंट का कानूनी तरीका घोषित किया जाता है।

गारंटी को ऐसे स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि राज्य पर असल में सबसे कम बोझ पड़ेगा; बल्कि इसके उलट। आज राज्य को असल में खर्च करना होगा और उस पर ब्याज देना होगा, और फिर आम टैक्स के ज़रिए खोए हुए कंस्ट्रक्शन खर्च के लिए मंज़ूर ग्रांट के लिए हर साल अनगिनत मिलियन खर्च करने होंगे। यह तब पूरी तरह से कैंसल हो जाता है।

इसलिए, अब राज्य जो ग्रांट देता है, वह असल में खोया हुआ पैसा है जिसे कम्युनिटी को वापस पाना होगा, और जो कुछ खुशकिस्मत लोगों को मिलता है जो सच में ऐसी ग्रांट ले पाए।

इस तरह, जब बिना ब्याज वाले कंस्ट्रक्शन नोट पाने वालों में से कोई बकाया पेमेंट करने वाला असल में कभी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता, तो भी राज्य के बजट से होने वाली भारी बचत के मामले में इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इस तरह उसे कोई ऐसा त्याग भी नहीं करना पड़ता जो पूरी तरह से बेकार हो जाए।

क्योंकि यह बहुत बड़े सामाजिक महत्व के काम का सवाल है, इसलिए एक कानून बनाना सही है।
एक इंडिपेंडेंट पब्लिक लीगल कॉर्पोरेशन को इसके एग्ज़िक्यूशन के इंस्ट्रूमेंट और बेयरर के तौर पर।

इस तरह यह संस्था प्राइवेट आर्थिक सामाजिक तरीकों के दायरे से हट जाएगी, जिनसे लोगों की नज़र में स्वाभाविक रूप से निजी मुनाफ़ा और अमीरी के इरादे जुड़े होते हैं। दूसरी ओर, यह संस्था पूरी तरह से सरकारी काम के दायरे से हट जाएगी, जिसके खिलाफ भी, पूरी तरह से अन्याय के बिना नहीं, जनता के बीच सभी आर्थिक मामलों में एक तरह की नफ़रत मौजूद है।

इम्प्लीमेंटेशनल रेगुलेशंस में सब कुछ रिकॉर्ड किया जाना है जो बेसिकली है
जनता के लिए और बैंक के बिज़नेस मैनेजमेंट की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।

प्रस्तावित एडवाइजरी काउंसिल इससे आगे भी अपना असर दिखा सकती है। एडवाइजरी काउंसिल खुद भी सभी संबंधित इंटरेस्ट ग्रुप्स की झलक है।

एक पब्लिक लीगल कॉर्पोरेशन के तौर पर कंस्ट्रक्शन बैंक बनाने का एक अच्छा साइड-इफेक्ट यह भी है कि इस तरह से बनाई गई वेल्थ वैल्यू का पूरा कॉम्प्लेक्स राज्य की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी की प्रॉपर्टी के तौर पर दिखता है, जो कि कंस्ट्रक्शन बैंक है।

इस कंस्ट्रक्शन बैंक का कानूनी मतलब या कानूनी पहचान इस तरह है: कंस्ट्रक्शन बैंक एक कानूनी संस्था है क्योंकि इसे एक पब्लिक लीगल कॉर्पोरेशन के तौर पर मान्यता मिली है या बनाया गया है; इस कंस्ट्रक्शन बैंक में कोई भी अलग-अलग सदस्य नहीं होते; यह खुद ही उन अधिकारों और जिम्मेदारियों का मालिक होता है जो इसकी गतिविधियों से बनते हैं। हालांकि, यह कोई ऑफिशियल संस्था भी नहीं है और न ही कोई सरकारी संस्था है, न ही किसी सरकारी संस्था का सदस्य है।

ऐसा कानूनी रूप बनाना कोई आम और पारंपरिक बात नहीं है; लेकिन फिर भी, यह कानून में पहले से ही तय है; लेकिन आज के हालात में मॉडर्न तरह के ऐसे ही संस्थानों की ज़रूरत है। जब इस तरह की कोई चीज़ बनती है, तो असल में यही काम आता है: कि, एक तरह से, कोई इंसान पारंपरिक चीज़ों की सीमाओं से आगे बढ़कर समय की ज़रूरतों के हिसाब से ढल जाता है।

बिज़नेस कैसे चलता है, इसे एक उदाहरण से सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है: कंस्ट्रक्शन बैंक पहले से ही उन बुनियादी बातों और शर्तों के बारे में बता देता है, जिन्हें कंस्ट्रक्शन-बैंक के पैसे की मंज़ूरी के लिए रिक्वेस्ट पर विचार करने के लिए पूरा करना होगा।

आवेदक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्शन-बैंक को भेजता है और, पॉज़िटिव मामलों में, घर की ज़रूरत वाले लोगों (घर के मालिकों) के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है।

इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले वो सब कुछ बताया जाना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन-बैंक ऑर्डिनेंस और इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन में बताया गया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ़ बिल्डिंग बनाने के लिए करना, मॉर्गेज स्टेटस की ज़िम्मेदारी और रीपेमेंट की ज़िम्मेदारी। लेकिन, इसके अलावा, इस कॉन्ट्रैक्ट में बाकी सभी कानूनी शर्तें भी तय की जानी चाहिए। यह खास तौर पर तय किया जाना चाहिए कि जिसे घर की ज़रूरत है, उसे प्रॉपर्टी दोबारा बेचने का कोई हक नहीं है, जो कि मॉर्गेज ऑर्डर में पहले ही बताया जा चुका है। विरासत के बंटवारे और पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के मामले में शर्तों को एक या ज़्यादा रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट के साथ रेगुलेट किया जाना चाहिए।

(डिटेल्स इस मामले के नेचर से सामने आई हैं)।

क्योंकि सभी डिलीवरी फर्म और सभी वर्कर को सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स में पेमेंट किया जाता है, जिसे कंस्ट्रक्शन बैंक खुद बनाता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन बैंक नोट्स सभी हालात में पहली बार सर्कुलेशन में तभी आते हैं, जब पेमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी को बराबर रकम मिलती है। वर्कर और सप्लायर से, कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स जनता तक पहुँचते हैं; मौजूदा सिक्योरिटीज़ के हिसाब से और खासकर इसलिए क्योंकि सरकार कंस्ट्रक्शन बैंक नोट्स की गारंटी लेती है और सरकारी खजाने कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स को पेमेंट के तौर पर लेते हैं, जनता कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स को किसी भी दूसरे पैसे की तरह ही मानेगी। इसलिए, यह घर के मालिक पर छोड़ दिया जाता है कि वह कंस्ट्रक्शन-बैंक को लोन की रकम का 2% सालाना कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स में चुकाने की अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करता है। दूसरे शब्दों में, बिल्डिंग के मालिक और कंस्ट्रक्शन-बैंक के मॉर्गेज डेटर को हर साल सर्कुलेशन में मौजूद रकम में से 2% कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स में देना होगा। असल में ऐसा होगा कि मॉर्गेज डेटर कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स इकट्ठा करेंगे जो असल में लोकल पैसे के साथ उनके रीपेमेंट ड्यूज़ की एक्सपायरी डेट से पहले सर्कुलेट होते हैं और उससे अपना पेमेंट पूरा करेंगे।

ज़िम्मेदारी। कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट पाने के लिए सबसे सही जगह वे कंस्ट्रक्शन साइटें होंगी जो किसी भी समय चल रही होती हैं।

अगर कोई अंदाज़ा लगाने के लिए यह मान ले कि एक साल में म्यूनिख में 10 मिलियन के कंस्ट्रक्शन बैंक नोट जारी किए जाते हैं, तो इसमें से हर साल 200,000 गोल्ड मार्क कंस्ट्रक्शन-बैंक में वापस आ जाएँगे; इस तरह, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल बाद, पूरे 10 मिलियन कंस्ट्रक्शन बैंक में वापस आ जाएँगे और जमा हो जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल बाद इससे बने घर चुका दिए जाएँगे और अपने मालिकों की कर्ज़-मुक्त प्रॉपर्टी बन जाएँगे। पूरा पेमेंट बिना किसी फ़ालतू ब्याज के हुआ है; पेमेंट और कुछ नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन-बैंक बनाने के आसान तरीकों से किया जाता है, जो सरकारी गारंटी से बंधा होता है।

सोशल एक्ट में यह बात शामिल है कि सरकार ने घरों की कीमत बिल्कुल शून्य से बनाई है, कि इस पूरी बिल्डिंग को बनाने से हज़ारों मज़दूरों और बिज़नेसमैन के लिए इनकम पैदा हुई है। अगर कोई यह मान ले कि यह हज़ारों अलग-अलग घरों का मामला है, तो हज़ारों ज़मीनहीन लोग ज़मीन वाले बन जाते हैं।

अलग-अलग आपत्तियां और रिज़र्वेशन किए जाएंगे, जिनमें से सबसे ज़रूरी ये हो सकते हैं:

1. महंगाई का एतराज़। यह एतराज़ जितना दूर की नहीं है, उतना ही बेमतलब भी है; जैसा कि पहले बताया गया है, महंगाई तभी हो सकती है जब बिना कवर वाला पैसा जारी किया जाए। यहाँ मटेरियल कवरेज कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स के खिलाफ है; इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट्स की काफी मात्रा भी सर्कुलेशन में आ जाए तो भी यह कोई मायने नहीं रखता।

2. यह आपत्ति कि यह मामला नया है और अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। यह आपत्ति लागू नहीं होती, और यह मामला शायद जर्मनी के लिए नया है। दूसरी जगहों पर, ऐसे इंटरेस्ट-फ्री डेट सर्टिफिकेट की आदत होती है जो मटेरियल एसेट्स से कवर होते हैं। इसका एक आम उदाहरण इंग्लिश वारंट है जो सौ साल पहले आया था और आज भी संभाल कर रखा गया है। वारंट एक ऑर्डर है जो मालिक को एक खास सेंट्रल स्टोरहाउस में रखे कच्चे लोहे की एक तय मात्रा पर अधिकार देता है। इन वारंट नोट्स का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर किया जाता है; वारंट की परचेजिंग पावर में सिर्फ़ वही उतार-चढ़ाव होते हैं जिनसे दुनिया के बाज़ार में कच्चे लोहे की कीमत जुड़ी होती है।

उदाहरण के लिए, अगर जर्मनी में हमारे पास ऐसे वारंट होते, तो ये जर्मन करेंसी और उनके उतार-चढ़ाव से पूरी तरह अलग होते। इन वारंट की वैल्यू कच्चे लोहे की कीमत से जुड़ी होती थी, और इन कीमतों की वैल्यू बदले में करेंसी के हिसाब से अपने आप रेगुलेट हो जाती थी।

वारंट में हमें इस इंटरेस्ट-फ्री डेट सर्टिफिकेट और डेट-ऑर्डर के पॉपुलर नेचर का एक अहम उदाहरण मिलता है, जो एक मटेरियल एसेट से कवर होता है।

जहां तक नई इमारतों का बड़ा और देश के लिए आर्थिक रूप से ज़रूरी निर्माण करने की बात है, तो पूरी कॉलोनियों को एक के बाद एक बनाना ज़रूरी है।

यह गलत नज़रिया होगा अगर कोई अकेले घर या टेरेस हाउस तभी बनाना चाहे जब घर ढूंढने वाला खुद उसका मालिक बनना चाहता हो।

जिस नुकसान को ठीक करना है, वह है घर की तंगी, इसलिए यह मुख्य रूप से घर का मामला नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से घर के मौके बनाने का मामला है। इस ज़रूरत को इस बात से भी ठीक किया जाएगा कि किराए के फ्लैटों के कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए, पुराने स्टाइल के किराए के घर के मालिक को नया किराए का घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन-बैंक नोट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों के मामले में, पूरी बिल्डिंग के सिर्फ़ 10% से ज़्यादा एडवांस में कैश में पेमेंट की मांग करना मुमकिन होगा।

वैल्यू; इनमें से कई लोग घर बनाने के लिए अपने पास से काफी पैसा खर्च करने को तैयार हैं और इस स्थिति में हैं, अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन-बैंक से ग्रांट के तौर पर उतनी ही बची हुई या थोड़ी रकम बिना ब्याज के मिल जाए। कंस्ट्रक्शन-बैंक के पैसे का ब्याज-मुक्त होना ही बिल्डिंग मार्केट के फिर से शुरू होने के इस पहलू पर ध्यान देना मुमकिन बनाता है, जो बड़े शहरों के लिए बहुत ज़रूरी है।

हालांकि, यह सोशल कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक बैंक बाद में हाउसिंग बिल्डिंग्स की फाइनेंसिंग की लिमिट से आगे बढ़कर देश के आर्थिक रूप से ज़रूरी कामों, इंडस्ट्रीज़, कम्युनिटी के कामों, खेती में सुधार वगैरह के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट भी देगा, भले ही पेमेंट की टाइम-लिमिट कम हो।

कर रहित राज्य

नेशनल सोशलिस्ट राज्य का मुख्य लक्ष्य है: बिना टैक्स वाला राज्य। अगर आज के हालात में यह एक पागल यूटोपिया जैसा लग सकता है, अगर कई लोगों को यह एक ऐसा वादा लग सकता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी हम जानते हैं कि यह लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है, कम से कम इस हद तक कि लोगों पर से भारी टैक्स का दबाव हटाया जाना चाहिए।

हमने पिछले चैप्टर्स में साफ़-साफ़ यह सबूत दिया है कि आज लगभग सारे टैक्स सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट में ही खत्म हो जाते हैं। हम जो भी रोटी खाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, हर वार्म पार्लर पर ज़्यादा टैक्स लगता है, हर खरीद पर सेल्स टैक्स का बोझ पड़ता है।

लेकिन इस तरह से टैक्स में जाने वाली सारी रकम, अकेले मुआवज़े के कर्ज़ पर टैक्स देने के लिए काफ़ी नहीं है।

अगर कोई ऐसे मुख्य लक्ष्य को नज़रअंदाज़ करता है, जो बिना टैक्स के राज्य को बेशक एक यूटोपिया जैसा बनाता है, तो यह हमेशा पसंद और समझ की कमी दिखाता है। जो आज की फाइनेंशियल पॉलिटिक्स के चौड़े और उलझे हुए रास्तों पर हमारे साथ चला है और जिसने एरिडने धागा – राज्य की ब्याज की ज़िम्मेदारी – नहीं खोया है, उसके लिए मिनोटौर की इस भूलभुलैया से बाहर निकलना भी आसान होगा।

जो खुद को गिरावट से ऊपर उठाता है और एक उच्च दृष्टिकोण से वर्णित संबंधों का सर्वेक्षण करता है: राज्य का ब्याज दायित्व - कर - मुद्रास्फीति, जिसने पश्चिमी सांस्कृतिक मंडल के सभी देशों के ब्याज दायित्व को हर चीज पर हावी होने वाले तथ्य के रूप में पहचान लिया है, जिसने पहचान लिया है कि हम काम और धन के बीच स्वस्थ और उचित स्थितियों के पूरी तरह उलट होने के युग में रहते हैं, जो अब इस दबाव वाले तर्क से बच नहीं सकता है कि विशेष रूप से राज्य, अपनी वित्तीय संप्रभुता के आधार पर, ऋण मार्ग से पूरी तरह से बंधा नहीं है बल्कि यह अपने अधिकार के माध्यम से रचनात्मक रूप से सभी बड़े सार्वजनिक राज्य कार्यों को वित्तपोषित कर सकता है, उसके लिए यह एक वित्तीय राजनीतिक नई दुनिया में केवल अंतिम कदम है कि एक ऐसे राज्य की मांग की जाए जिसमें राज्य वित्तीय प्रशासन इसे अपना पहला कार्य नहीं मानता

हम इस बात के सबूत पेश करने की स्थिति में हैं कि बिना टैक्स वाला राज्य कोई यूटोपिया नहीं है, बल्कि हर सही राज्य बजट में इसकी संभावना दी गई है, अगर राज्य खुद को उस पर पड़े ब्याज के बोझ से मुक्त कर ले। यह बिना किसी जवाबदेही के भी ऐसा कर सकता है, यह राज्यों के दिवालिया होने के इतिहास से साबित होता है, जिसमें दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य दिवालिया होकर अपने ऊपर पड़े ब्याज और कर्ज के बोझ से बच निकले हैं।

यहां एक बार फिर उस सटीक प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बात करना हमें बहुत दूर ले जाएगा जो मैंने अपनी छोटी सी बहस वाली किताब, 'द स्टेट बैंकरप्सी: द सॉल्यूशन' में दिया है, यानी, पब्लिक लोन से ब्याज पेमेंट का एडजस्टमेंट और बॉन्ड को एक साथ ब्याज-मुक्त बैंक एसेट्स में बदलना, किसी भी तरह से बैंकरप्सी के बदनाम नाम के लायक नहीं है, बल्कि राज्य और लोगों को उसके ब्याज-बंधे कर्ज से आज़ादी देने का यह तरीका असल में राज्य और अर्थव्यवस्था को असहनीय जंजीरों से आज़ादी दिखाता है।

लेकिन, इन इंटरेस्ट पेमेंट का एडजस्टमेंट, युद्ध से पहले ही, पूरे राज्य प्रशासन के लिए राज्य के खर्चों को कवर करना मुमकिन बना देता। मैंने उदाहरण के तौर पर 1911 का बवेरियन राज्य बजट पेश किया है। उस समय, बवेरियन राज्य को तथाकथित कमर्शियल सरकारी कंपनियों (रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ) से 120 मिलियन गोल्ड मार्क्स की कमाई होती थी, और राज्य के जंगल से 40 मिलियन मार्क्स की कमाई होती थी। कुल

न्याय के प्रशासन के लिए पूरे राज्य प्रशासन का खर्च (सभी जिला अदालतें, उनके सभी कर्मचारियों और सामान का खर्च, सभी प्रांतीय अदालतें, क्षेत्रीय अदालतें और म्यूनिख, नूर्नबर्ग, वगैरह में सबसे बड़ी कानूनी अदालतें) 27 मिलियन था। पूरे बवेरियन राज्य के पूरे बड़े और इतने ध्यान से बनाए गए अंदरूनी प्रशासन के लिए – यानी कई जिला अदालतों के लिए, काउंटी सरकारों के लिए, म्यूनिख के पुलिस विभाग के लिए, जेंडरमेरी के लिए, और कई दूसरी संस्थाओं और अधिकारियों जैसे मेडिकल अधिकारियों, प्रांतीय वैक्सीनेशन अस्पताल, खाने और सेमी-लग्ज़री खाने के लिए रिसर्च संस्थानों, सेनेटोरियम और मेंटल असाइलम, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, प्रांतीय स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मेट्रोलॉजिकल अधिकारियों, इंश्योरेंस चैंबर वगैरह के लिए राज्य के बजट में खर्च किया गया था। एजुकेशन, स्कूल और चर्च के लिए, खासकर सभी मिडिल स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों, प्रिपरेटरी स्कूलों, लैटिन स्कूलों, सेकेंडरी एजुकेशन स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों, हायर वोकेशनल स्कूलों, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स, सभी स्टेट कंस्ट्रक्शन स्कूलों और स्पेशलिस्ट स्कूलों, ट्रेड और म्यूजिक स्कूलों, एग्रीकल्चरल और डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग स्कूलों, वेहेनस्टेफन[80] और बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए, सभी महिलाओं के एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के लिए, और फिर, सबसे बढ़कर, यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनके अनगिनत कलेक्शन और –, 1911 में, 40 मिलियन इंस्टिट्यूट के लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरी आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ट्रेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक के लिए, फिर मैक्सिमिलियनियम[81] के लिए, और आगे साइंस और आर्ट के सेंट्रल इंस्टिट्यूट, एकेडमी ऑफ़ साइंसेज, स्टेट के साइंटिफिक कलेक्शन, बवेरियन म्यूजियम, स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट थिएटर, वगैरह के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर के इन बड़े कामों के लिए, जिसमें हज़ारों अधिकारी हैं, कलेक्शन और म्यूजियम में कला के बड़े खजाने के लिए, इन सभी को सच में बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और देखभाल की ज़रूरत है, 1911 में, कुल 51 मिलियन बांटे गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के फील्ड में , जो असल में सिर्फ़ लोगों से पैसे निकालने वाले काम ही नहीं करता, सैकड़ों फॉरेस्टर वाले फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी आते हैं, इसके अलावा माइंस, स्मेल्टिंग वर्क्स, सॉल्ट वर्क्स, पूरे सेंट्रल और सब्सिडियरी कस्टम ऑफिस, सेंट्रल मिंटिंग ऑफिस, स्टेट डेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट बैंक, इसके अलावा सर्वेयर ऑफिस और प्रोविंशियल सर्वेइंग ऑफिस, फिर स्टेट स्पा एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ब्रूअरी ऑफिस, म्यूनिख, वगैरह भी आते हैं। इसी तरह इस बहुत बड़े काम पर 15 मिलियन का खर्च आया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के खर्च उसके अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू से पूरे हुए, दूसरी तरफ, पुराने सिविल सर्वेंट की पेंशन के लिए लगभग 36 मिलियन की बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ी।

इस प्रकार, कुल मिलाकर न्याय प्रशासन, इमारतों सहित आंतरिक प्रशासन - जिसका मैंने ऊपर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है - और वित्त प्रशासन, साथ ही शिक्षा और विकास, और पेंशन की मांग 27+40+51+13+36 = 167 मिलियन है।

सरकारी कंपनियों, पोस्ट और रेलवे, खदानों और जंगलों से मिलने वाला सरप्लस, जो लगभग 160 मिलियन था, वह असल में पूरे बड़े सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कवर करने के लिए काफी होता – बिना एक पैसा टैक्स दिए!

इस तरह बिना टैक्स वाला राज्य एक सच्चाई होता, अगर बवेरियन लोगों से लिए गए कुल टैक्स, यानी 60 मिलियन डायरेक्ट टैक्स और 53 मिलियन इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके अलावा 31 मिलियन फीस, यानी कुल मिलाकर 134 मिलियन, का इस्तेमाल पूरी तरह से लोन कैपिटल के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए न करना पड़ता। अकेले बवेरियन राज्य के कर्ज़ों का इंटरेस्ट पेमेंट

[80] वेहेनस्टेफ़न अपर बवेरिया में 11वीं सदी का एक मठ है जिसे 1803 में एक फ़ॉरेस्ट्री स्कूल और सरकारी शराब की भट्टी में बदल दिया गया था।

[81] म्यूनिख में मैक्सिमिलियनियम को बवेरिया के राजा मैक्सिमिलियन II ने स्टूडेंट्स फाउंडेशन की सीट के तौर पर डिज़ाइन किया था।
1949 से यहां बवेरियन राज्य की संसद है।

84.6 मिलियन (!) की मांग की और बवेरिया को भी रीच के कर्ज के ब्याज के पेमेंट के लिए रीच को 50 मिलियन देने पड़े।

मैंने हमारे राज्य के जीवन के बड़े और छोटे क्षेत्रों का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। यह इसलिए भी खास तौर पर ज़रूरी लगता है क्योंकि नेशनल सोशलिज़्म यह भी ध्यान में रखता है कि पुराने राज्य ने कितना असाधारण और कितना शानदार काम किया, जिसमें से बहुत कुछ में किसी सुधार और सुधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका उन मामलों से कोई लेना-देना नहीं है जिनका कभी नतीजा नहीं निकल सकता।
यह बात हर सरकारी संस्था के लिए भी सच है कि अगर वह जड़ नहीं बनना चाहती तो वह स्थिर नहीं रह सकती। कई क्षेत्रों में एक नई और आज़ाद भावना से कोई नुकसान नहीं होगा, और यहाँ-वहाँ बड़े सुधार सही हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कई ब्रांच में कम से कम एक नई भावना आनी चाहिए, खासकर सिविल सर्वेंट की अपने कामों और जिन लोगों की वह सेवा करता है, उनके प्रति पक्की ज़िम्मेदारी की भावना।

केवल एक क्षेत्र को पूरी तरह से गलत तरीकों पर मजबूर किया गया - राज्य वित्तीय प्रशासन।
अगर अभी बताए गए हालात मुमकिन हैं, तो यह सच में इस बात का संकेत है कि यहां एक बड़ा बदलाव लाना होगा। हालांकि, यह बात युद्ध से पहले ही राज्य के लिए सच थी – उस समय भी राज्य प्राइवेट लोन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट सर्विस में शामिल था।

उस समय पहले से मौजूद लोन कैपिटल पर सरकार की निर्भरता को इनकम के अलग-अलग तरीकों पर टैक्स के बंटवारे के सर्वे से ज़्यादा चौंकाने वाला कोई तरीका नहीं दिखाता। 1911 के बजट के अनुसार, जिस पर हमने अब तक अपने ऑब्ज़र्वेशन आधारित किए हैं, ज़मीन की प्रॉपर्टी 12.6 मिलियन, घर की प्रॉपर्टी 12.1 मिलियन, कमर्शियल बिज़नेस 17 मिलियन आंके गए थे, लेकिन दूसरी ओर, 253 (!) मिलियन गोल्ड मार्क्स की कुल पेंशन इनकम वाली कैपिटल पेंशन सिर्फ़ 10 मिलियन थी। इस तरह यह उन लोगों के साथ वाकई बहुत ज़्यादा नरमी वाला बर्ताव है जो बिना मेहनत और काम के जी सकते हैं, और यह काम करने वाले लोगों की कीमत पर किया जा रहा है।

बहुत सारी छोटी पेंशन इनकम – हम 70-700 मिलियन मार्क्स के पेंशन ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं – असल में संख्या में कैपिटल पेंशन टैक्स देनदारियों का बड़ा हिस्सा हैं, यानी लगभग 150,000, लेकिन न तो कैपिटल इंटरेस्ट से उनकी इनकम और न ही उनका टैक्स पेमेंट, जो लगभग 0.7 मिलियन है, राज्य के बजट में कोई भूमिका निभाएगा – लेकिन जो बात इन आंकड़ों को हमारे लिए इतना खास बनाती है, वह यह है कि बड़े लोन कैपिटल ने इन लाखों छोटे इंटरेस्ट पाने वालों में इंटरेस्ट से होने वाली मेहनत और बिना काम की इनकम पर होने वाले सभी हमलों के खिलाफ एक मज़बूत सुरक्षा कवच बना दिया है।

इन छोटे ब्याज पाने वालों को यह समझाना आसान है कि उनकी बचत से कुछ हद तक ब्याज पर पक्का दावा मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और असल में अपनी बचत के लिए काम किया है, सरकार में पेंशन पाने वालों और कर्मचारियों की हालत से मिलती-जुलती है। लेकिन जो बात इस नज़रिए को पेंशन के विचार से अलग करती है, वह यह है कि पेंशन का दावा व्यक्ति पर निर्भर करता है और मौत पर खत्म हो जाता है, जबकि ब्याज का दावा एक ज़रूरी दावा होता है और यह व्यक्ति से अलग, सिर्फ़ पैसे के मालिकाना हक के तौर पर एक "हमेशा चलने वाला कानूनी दावा" होता है।

हम आम बुढ़ापे की पेंशन की चर्चा में इन कनेक्शन पर आगे बात करेंगे, क्योंकि इन बातों से हमें गलत हमेशा के फायदे से लेकर हर देश के साथी के बेफिक्र बुढ़ापे के सही दावे तक का बदलाव देखने को मिलेगा।

हम जिस सवाल पर बात कर रहे हैं, उसमें पुराने राज्य की तरफ से लोन कैपिटल के साथ किए गए बहुत ज़्यादा नरमी वाले बर्ताव के बारे में इन छोटे ब्याज पाने वालों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ़ उन लोगों पर ध्यान दिया जाता है जो कैपिटल पेंशन का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं और फिर राज्य के बड़े फाइनेंशियल डोनर बनकर सामने आते हैं।

तो इस नेशनल इकोनॉमिक बकवास को, जिसमें कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट वाला सरकारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दूर करें और सभी टैक्स से मुक्त काम और परफॉर्मेंस वाले फ्री नेशनल सोशलिस्ट स्टेट में जाएं।

एक बार जब राज्य अपने ब्याज की ज़िम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद हो जाएगा, तो देखा जाएगा कि राज्य क्या हासिल कर सकता है। अगर इसके अलावा बड़े पैमाने पर कमाई के नए सोर्स आते हैं, जैसे हाइड्रो-एनर्जी और देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, तो बिना टैक्स वाला राज्य असल में कोई यूटोपिया नहीं बल्कि एक खुशी की सच्चाई होगी।

अगर हम फिर भी नेशनल सोशलिस्ट राज्य की टैक्स पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे टैक्स सोर्स से कई ऐसे कामों के लिए पैसे मिल सकते हैं जिनका असल में राज्य के समाधान का इंतज़ार है, जिनके लिए राज्य के बजट में कभी कोई और पैसा नहीं था। हम यहाँ नेशनल हेल्थ, यौन रोगों से लड़ने, शराब की लत, फिजिकल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, कला और विज्ञान को और ज़्यादा बढ़ावा देने, मैटरनिटी लीव, बच्चों की देखभाल, गार्डन-सिटी बनाने और सबसे बढ़कर जर्मन लोगों के युद्ध में घायल हुए लोगों और युद्ध में विधवा हुई महिलाओं और अनाथों के सम्मान के कर्ज से मुक्ति जैसे बड़े क्षेत्रों के बारे में सोच रहे हैं।

टैक्स पॉलिसी के क्षेत्र में नेशनल सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम के लिए नीचे दिए गए सिद्धांतों को गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर लिया जाना चाहिए:

1. इंटरनल लोन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के मकसद से टैक्सेशन को बाहर रखा गया है।
2. टैक्स सिर्फ़ गैर-उत्पादक कामों, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय व्यवस्था, मिलिट्री, पुलिस और हेल्थ सिस्टम और शिक्षा के लिए सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए ही लगाए जा सकते हैं, जब तक कि कमर्शियल सरकारी कंपनियों, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, सरकारी जंगलों और सरकारी खदानों का सरप्लस, साथ ही बड़े सरकारी इंटर-अर्बन बेस से बिजली सप्लाई, उनके कवरेज के लिए काफ़ी न हो।
3. खास ज़रूरतों या खास इमरजेंसी के लिए, खासकर युद्ध के मामले में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स न सिर्फ मंज़ूर हैं बल्कि ज़रूरी भी हैं।
4. प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट टैक्स किसी भी तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन यहां एक बड़े लेवल पर लेवलिंग प्लान करना होगा। इनकम को एक हद तक टैक्स-फ्री रखना होगा। इस मामले में, अब तक के मुकाबले इस बात पर ज़्यादा ध्यान से सोचना चाहिए कि टैक्स देने वाले का परिवार है या नहीं, बच्चे हैं या देखभाल के दूसरे काम हैं।
5. राज्य के अधिकारियों को मूल रूप से टैक्स से मुक्त रखा जाना चाहिए। शादीशुदा लोगों के बच्चों के लिए अलाउंस की गारंटी दी जानी है।
6. आम समय में इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ़ लग्ज़री चीज़ों पर ही लागू होते हैं। सरकार के पास इस तरह से काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे उन चीज़ों के प्रोडक्शन की कीमतें कंट्रोल की जा सकें और बढ़ाई जा सकें जो सिर्फ़ आकर्षक लग्ज़री, खाने-पीने में शान-शौकत और लालच, और फैशन की ज़्यादा चीज़ों के लिए होती हैं। यहाँ तक कि तंबाकू, शराब, वाइन जैसी सिर्फ़ सेमी-लग्ज़री चीज़ों पर भी, अगर वे सेहत के लिए काम नहीं करतीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे। दूसरी ओर, सभी इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आज लोगों का पूरी तरह से शोषण करते हैं, उनसे पूरी तरह बचना चाहिए। हमारा मतलब उन सभी फालतू इनडायरेक्ट टैक्स से है जो सिर्फ़ कीमतें बढ़ाने वाले तरीके से काम करते हैं, जैसे चीनी, नमक, माचिस, लैंप, नींबू पानी, कोयले पर लगने वाले टैक्स जो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा महंगा बनाते हैं, पर्सनल और सामान के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले टैक्स, और सबसे बढ़कर कमोडिटी सेल्स टैक्स।
7. युद्ध और क्रांति से होने वाले मुनाफ़े को इकट्ठा करना न्याय का काम है। ऐसे काम के लिए, ज़ाहिर है, पहले हिसाब-किताब का एक सही आधार बनाना होगा, जिस पर आज की दौलत की तुलना पहले की दौलत से की जा सके। ज़ाहिर है, यहाँ भी प्रोडक्टिव काम से मिलने वाली दौलत में फिर से फ़र्क करना होगा, जिसके लिए युद्ध ने एक खास तेज़ी दिखाई। यह सही और

यह सही है कि इतने बड़े युद्ध मुनाफ़े का एक हिस्सा समुदाय को दिया जाए।
दूसरी ओर, उस दौलत के मामले में ज़्यादा गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो बिचौलिए के व्यापार और सट्टेबाजी से पैदा होती है।

8. स्टाम्प ड्यूटी और फीस, यहाँ तक कि ऐसे टैक्स भी जो पैसे के कुछ हिस्सों को बेचने के आज़ाद अधिकार पर रोक लगाते हैं, जब तक कि यह बेचना आम भलाई के खिलाफ न हो, जहाँ तक हो सके, सीमित किए जाने चाहिए। इसमें विरासत और गिफ्ट टैक्स भी शामिल हैं।

असल में टैक्स फाइनेंशियल पॉलिसी को "बिना टैक्स वाला राज्य" के आखिरी लक्ष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राज्य का काम अपने नागरिकों से पैसे ऐंठना नहीं है ताकि असल में झूठी स्टेट लोन इकॉनमी चलती रहे, बल्कि लोगों की आम भलाई को बढ़ाना है।

राज्य बड़े लोन कैपिटल पर ब्याज वसूलने के लिए नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा करने और देश के प्राकृतिक संसाधनों को समुदाय के काम का बनाने के लिए है। जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य के बेकार कामों के लिए साधन मुख्य रूप से कमर्शियल सरकारी कंपनियों के सरप्लस से, और दूसरे लग्ज़री टैक्स से, तीसरे उस दौलत और इनकम से लिए जाने चाहिए जो सिर्फ़ काम करके मिल सकती है, और उसके बाद ही अमीर मिडिल-क्लास से, साथ ही उन सेमी-लग्ज़री चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स से जिनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ़ युद्ध के समय में, जब पूरे देश की जान को खतरा हो, राज्य यह मांग कर सकता है कि समुदाय भी – जैसा कि वह अपनी सर्विस सॉवरेनिटी के ज़रिए हर किसी से मिलिट्री सर्विस की मांग कर सकता है –, और एक बार फिर खास तौर पर अमीर वर्गों के संदर्भ में, युद्ध के संचालन में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के रूप में अपना फाइनेंशियल योगदान दे।

आखिर में हम "कमर्शियल सरकारी कंपनियों" के सवाल पर कुछ और कह सकते हैं। अब यह कहना ज़्यादा सही होगा कि सरकारी कंपनियाँ "मुनाफ़े वाली" नहीं हैं। हम मुनाफ़े के बुनियादी सवाल पर पहले ही विस्तार से बात कर चुके हैं।

रेलवे वगैरह को "बिज़नेस की तरह" चलाने, "उन्हें अनइकोनॉमिक सरकारी काम से आज़ाद करने" या "उन्हें मिक्स्ड इकॉनमिक रूप में लाने" की कोशिश में, बड़ी लोन कैपिटल की यह बुरी तरह छिपी हुई इच्छा छिपी है कि देश के इस बड़े वेल्थ कंपोनेंट को भी अपने काम का बनाया जाए। अगर सरकार वेल्थ के इन कंपोनेंट्स को भी सौंप देती है, तो यह पूरी तरह से लोन कैपिटल को सौंप दिया जाता है और लोन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट कलेक्टर के तौर पर काम करने की इजाज़त के अलावा, उसके पास कोई और फ़ील्ड नहीं बचता जिसमें वह सॉवरेन हो, या जिसमें वह रेगुलेटरी तरीके से काम कर सके और जिससे वह अपने कामों को पूरा करने के लिए काफ़ी रेवेन्यू पा सके।

राज्य की वित्तीय और राजनीतिक मुक्ति

हमने पहले बताया कि भविष्य में ऐसे हालात को नामुमकिन बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। इन कामों के लिए सच में क्रिएटिव सर्विस की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी इन्हें मौजूदा कानूनी शर्तों को नुकसान पहुँचाए या बदले बिना किया जा सकता है। हमारे देश के अंदरूनी और बाहरी क्रेडिटर पर ब्याज वाले कर्ज़ की मौजूदा चेन को तोड़ने के मामले में यह अलग है।

यहां उठाए जाने वाले कदम अपने आप में बहुत आसान हैं, बस उन्हें लागू करने में कई मुश्किलें आएंगी। अंदरूनी लोन से हमेशा ब्याज देने की ज़िम्मेदारी का हल है: इस ब्याज पेमेंट को कानूनी तौर पर खत्म करना। दूसरी तरफ, बड़ी लोन कैपिटल, छोटे पेंशन पाने वालों के फायदे की दुहाई देते हुए, बहुत शोर मचाएगी और उस देश के खिलाफ सबसे डरावनी धमकियां देगी जो "अपने पैरों तले उन अधिकारों को रौंदता है जो छीने नहीं जा सकते", जो "कानून तोड़ता है जिससे उसका भरोसा भी खत्म हो जाएगा"। बड़ी कैपिटल अपने आप "बुनियादी आर्थिक कानूनों के खिलाफ बड़े जुर्म" को रोकने के लिए सभी कदम उठाएगी। ज़ाहिर है! - कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई इंटरनेशनल ताकत अचानक राज करने का अपना दावा छोड़ देगी।

इस लड़ाई में बस हिम्मत बनाए रखने और खुद को हिम्मत न हारने देने की बात है।
प्रेस कुलियों की चीख-पुकार से डरो मत, जिन्हें हाई फाइनेंस से रखा जाता है।

यहूदी इस लड़ाई को बहुत मज़बूती से लड़ेगा, क्योंकि यह "उसकी इज़्ज़त" का मामला है, जैसा कि पुराने रॉथ्सचाइल्ड ने कहा था: "मेरा पैसा मेरी इज़्ज़त है, और जो मेरा पैसा लेता है, वह मेरी इज़्ज़त मुझसे छीन लेता है"।

अब बेशक, सरकारी बॉन्ड के मालिकों से उनका पैसा किसी भी तरह नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन कानूनी मांगों को हटा देना चाहिए जो असल में राष्ट्रीय समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय बन गई हैं।

लेकिन सरकार के नज़रिए से, और साथ ही उन लोगों के नज़रिए से जिन्हें इन "सरकारी कर्ज देने वालों की कानूनी मांगों" को पूरा करने के लिए अपने काम से बहुत ज़्यादा रकम जमा करनी पड़ती है, यह "कानूनी मांगों" का मामला नहीं है, बल्कि अब तक के सबसे बड़े अन्याय का मामला है – सरकार के सपोर्ट से बड़े पूंजीपतियों के एक छोटे से हिस्से के फ़ायदे के लिए मेहनतकश लोगों की हमेशा चलने वाली लूट का मामला है। जो सरकार "ब्याज की गुलामी को तोड़ने" को सच बनाती है, वह किसी भी तरह से अन्याय नहीं करती, बल्कि वह एक बहुत बड़े अन्याय का प्रायश्चित करती है, जिसे करने के लिए उसने खुद गुलामी की है।

बेशक, इसका मतलब है मौजूदा सरकार का पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज़ेशन; उसे यह तय करना होगा कि वह पूरी सरकार की सेवा करना चाहता है या, जैसा कि अभी है, इंटरनेशनल फाइनेंस का बेलिफ बनना चाहता है।
इस सवाल पर कोई समझौता नहीं है। यहां सिर्फ़ एक पक्का कदम ही लक्ष्य और समाधान तक पहुंचा सकता है।

नेशनल सोशलिस्ट सरकार को सच में इस मज़बूत फ़ैसले का पता है – अगर हमें ठीक से पता न हो कि हमें इंटरेस्ट कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की जगह क्या बनाना है, तो ऐसा अहम कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि हम यह जानते हैं, इसलिए हम दुनिया के इतिहास की इस सबसे बड़ी लड़ाई में जीत के पूरे भरोसे के साथ उतरते हैं। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट का राज सिर्फ़ झूठ और धोखे पर बना होता है और, क्योंकि हम यह जानते हैं और साफ़ तौर पर पहचान चुके हैं, इसलिए हम यह भी जानते हैं कि झूठ और धोखे का ऐसा मकड़ी का जाल , चाहे उसे कितनी भी मुश्किल से बुना गया हो, एक झटके में फाड़ा जा सकता है।

बस एक और सवाल, आखिरी सवाल, हमें सोचना चाहिए, वह यह कि विदेशी देश ऐसे बड़े सुधार और खासकर विदेशी ब्याज देने वालों को और ब्याज देने से मना करने पर क्या कहेंगे?

हाँ, विदेशी देश इस पर क्या कहेंगे? यह सवाल अपने आप में हमारे जर्मन संकट और सबसे बड़े ग्रुप के कॉस्मोपॉलिटन रवैये के लिए बहुत ज़रूरी है।
आम तौर पर "विदेशी देश" क्या हैं? क्या वे फ्रेंच, अंग्रेज, अमेरिकी हैं? क्या वे स्वीडिश, डच और नॉर्वेजियन हैं? क्या वे रूसी या चीनी हैं? या वे भारतीय या फ्यूजियन82 या कांगो के नीग्रो हैं? असल में, ये सभी लोग हमारे हिसाब से "विदेशी देशों" के हैं। अब, इन सभी "विदेशियों" में से ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, सबसे कम चीनी, और सबसे कम रूसी और फ्रेंच लोग ही आम तौर पर जानते होंगे कि यह किस बारे में है। आखिर में, हमारे युद्ध के दुश्मनों की सरकारें बची हैं और फिर ज़ाहिर है – जो सच में इसमें दिलचस्पी रखते हैं – यहूदी इंटरनेशनल बैंकर, जो "इसके बारे में कुछ कहेंगे"। हालांकि, इंटरनेशनल फाइनेंस इस पर क्या कहेगा, इसका जवाब देना बहुत आसान है। वह अपने पास मौजूद सभी तरीकों से, इस तरह के काम को सभ्य इंसानों के खिलाफ एक ऐसा जुर्म बताएगा जो पहले कभी नहीं हुआ, वह अपने समर्पित प्रेस के ज़रिए हर तरह के झूठ और तोड़-मरोड़ के साथ, तथाकथित सभ्य दुनिया को किए गए वादों के ऐसे पहले कभी नहीं हुए उल्लंघन के खिलाफ खड़ा करेगा, वह यूरोप के पूरी तरह खत्म होने की बात करेगा, और वह फ्रांस को, जो यूरोपीय सभ्यता का खास तौर पर सही वाहक है, जर्मनी के खिलाफ खुली जंग के लिए उकसाने की कोशिश करेगा। विदेशी देश, यानी यहूदी हाई फाइनेंस, बड़े यहूदी समुदाय की पूरी ताकत के खिलाफ इस तरह की हत्या की कोशिश के खिलाफ जो कुछ भी कहेंगे, वह सब यही होगा।

इसलिए कोई भी खुद को सवाल और जवाब दोनों से बचा सकता है। क्योंकि, यह साफ़ है कि जिस ताकत के खिलाफ़ आज़ादी की लड़ाई है, वह बिना लड़े हार नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ बात जर्मनों की नहीं है, जिनके लिए विदेशी हित और अधिकार ज़्यादातर जर्मनों के अधिकारों से ज़्यादा पवित्र हैं, बल्कि उन लोगों की है जिनकी सबसे खास बात ताकत पाने की क्रूर इच्छा है।

ऐसे सभी आखिरी ऐतिहासिक सवालों में, यह अंदाज़ा लगाना बिल्कुल बेकार है कि दुश्मन अब क्या करेगा, क्योंकि यह साफ़ है कि दुश्मन तुरंत आज़ादी या बगावत नहीं होने देगा। यह सोचना बिल्कुल अलग है कि दुश्मन के पास ताकत के कौन से तरीके हैं और यह जानना कि उसके पास क्या ताकत है। अगर, इसके अलावा, कोई ठीक-ठीक जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या करेगा, तो उसे देखना चाहिए कि दुश्मन हमले को कैसे रोकेगा और उसके बाद ही वह जवाबी कदम उठा सकता है। कोई भी मिलिट्री प्लान पहले हमले के बाद के अभियान को तय नहीं कर सकता, लेकिन यह वाकई एक ज़ोरदार कार्रवाई के लिए आम गाइडलाइन दे सकता है। यहाँ भी ऐसा ही है।

हमारे मामले में विरोधियों को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि यह एक इंपर्सनल और सुपरनेशनल पावर का मामला है। इसलिए कैंपेन प्लान में पहले यह सोचना होगा कि कौन सी पावर और हित विरोधियों के तौर पर ध्यान में नहीं आते हैं। यह ज़रूरी है ताकि पावर का बेवजह इस्तेमाल ऐसी दिशा में न किया जाए जहाँ से कोई खतरा न हो।

इस सवाल के पीछे, "विदेशी देश इस पर क्या कहेंगे?" ज़्यादातर यह चिंता छिपी है कि ऐसे में हमें विदेश से कोई क्रेडिट, खाना या दूसरा कच्चा माल नहीं मिलेगा।
अब यहां क्या स्थिति है?

एक नेशनल इकॉनमी के तौर पर, हम लंबे समय में अपने इंपोर्ट का पेमेंट हमेशा अपने एक्सपोर्ट से ही कर सकते हैं, यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन पेपर मनी या "क्रेडिट" से नहीं।
यह सब कुछ समय तक काम करता है, जब तक विदेशी देश असली क्रेडिट देते हैं, यानी, जब तक अलग-अलग विदेशी सप्लायर को भरोसा है कि जर्मन इंपोर्टर संबंधित सामान का पूरा पैसा देंगे। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब इंपोर्टर ने जर्मन सामान के एक्सपोर्टर के तौर पर विदेशी पैसा इकट्ठा किया हो। यह डर कि हमें कोई कॉटन या फैट नहीं मिलेगा,

82 दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित द्वीपसमूह टिएरा डेल फ्यूगो के निवासी।

कॉपर या चारा, इंटरनेशनल इंटरेस्ट पेमेंट से मना करने की वजह से ऐसे सवाल जुड़ जाते हैं जिनका असल में एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ तक कि पूरी तरह से यहूदी बड़ी बैंक पावर भी लंबे समय में कच्चा माल बनाने वाले देशों में सरप्लस को जर्मन फैक्ट्रियों और काम की जगहों तक पहुँचने से किसी भी तरह नहीं रोक सकती, और इसी तरह जर्मन तैयार माल को दुनिया के सेल्स मार्केट में पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। अलग-अलग देशों की इकॉनमी के बीच सामानों का यह आपसी लेन-देन असल में सप्लाई और डिमांड के ज़रूरी नियमों के हिसाब से होता है। बेशक, मजबूरी में, और कुछ समय के लिए, यहाँ भी पाबंदियाँ और रुकावटें आ सकती हैं जैसा कि हमने युद्ध में और फिर रुहर इलाके में देखा[83]। लेकिन ये सभी ज़बरदस्ती के कदम हैं जो दूसरे देशों को भी इसी तरह नुकसान पहुँचाते हैं।

इसलिए हम पक्के तौर पर मान सकते हैं कि होलसेल ट्रेड पूरी तरह से ज़रूरी इम्पोर्ट की ज़रूरत को पूरा करने में कामयाब होगा। हमेशा ऐसे न्यूट्रल देश होंगे जिनके ज़रिए ये इम्पोर्ट हम तक पहुँच सकते हैं।

इसके अलावा, एक नेशनल इकॉनमी जो एक बार फिर अपने नेशनल कर्तव्यों के प्रति जागरूक है और जिससे एक्सपोर्ट की चीज़ों के मामले में फिर से ज़्यादा कुशल बन जाएगी, वह इस बात पर ज़्यादा भरोसा कर सकती है कि वह पुराना भरोसा फिर से हासिल कर लेगी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में टेम्पररी इंटरमीडियरी क्रेडिट ट्रेड हाउस के मामले हैं और उनके पर्सनल क्रेडिट पर आधारित होते हैं।

अब इस सवाल का एक और पहलू है, वह है राइख या फेडरल राज्यों के वॉर बॉन्ड और दूसरे ब्याज वाले बॉन्ड के नेशनल इंटरेस्ट पेमेंट को सस्पेंड करने की वजह से पॉलिटिकल मजबूरी वाले कदमों का डर। यह भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ सवाल जर्मन सरकारी बॉन्ड के अलग-अलग प्राइवेट क्रेडिटर की ब्याज मांगों का है, जिनके लिए शायद ही कोई पॉलिटिकल एक्शन लिया जा सकता है। असल में, राज्यों के दिवालिया होने के इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जब किसी राज्य ने अपना ब्याज पेमेंट सस्पेंड किया हो तो मिलिट्री दखल दिया गया हो। इसके उलट यह राय कि, इस मामले में, फ्रांसीसी तुरंत बदला लेंगे, किसी भी तरह से लॉजिकल आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि नहीं तो, दुश्मनों को उस समय जर्मन मार्क की गिरावट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के ज़रिए दखल देना पड़ता। करेंसी की गिरावट ने आखिरकार जर्मन बॉन्ड के विदेशी क्रेडिटर को सब कुछ छीन लिया। अब हमारे कदमों से इन अंदरूनी जर्मन सरकारी कर्जों को खत्म करने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि सिर्फ ब्याज को कैंसल करने और बॉन्ड को बैंक एसेट में बदलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, विदेशी क्रेडिटर को तुरंत कैश पेमेंट दिया जा सकता है।

यह कैसे हो सकता है कि ऐसे मामले में, यानी जब मिस्टर X. इलिनोइस या शिकागो को अपने बैंकर से यह जानकारी मिले कि जर्मन सरकार वॉर बॉन्ड कैश में वापस कर रही है और यह रकम उनके अकाउंट में जमा हो गई है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाएं और अपनी सरकार को जर्मनी के खिलाफ खड़ा कर दें?

अगर एक राष्ट्रवादी जर्मन सरकार सभी ब्याज वाले बॉन्ड से ब्याज खत्म करने और साथ ही इन बॉन्ड को सरकारी बैंकों या पोस्टल चेक अकाउंट में ब्याज-मुक्त एसेट में बदलने का ऐलान करती है, तो किसी भी तरफ से गंभीर विरोध की उम्मीद नहीं की जा सकती।

हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हमारे उपायों से समुदाय को नुकसान न हो, – यह बात कि कैपिटलिस्ट तरफ से विरोध किया जाएगा, आज़ादी देने वाले काम को रोक नहीं सकती। इस उपाय के मामले में हम ठीक यही देखेंगे कि यहाँ आत्माओं का अलगाव होगा और जो लोग इस सरकारी उपाय में आज़ादी महसूस करेंगे, उनका बंद ग्रुप आज़ादी महसूस करेगा।

---

[83] जब 1922 के आखिर में, यह पाया गया कि जर्मन, मित्र देशों को युद्ध के हर्जाने के तौर पर लकड़ी और कोयले के पेमेंट में गंभीर रूप से डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री रेमंड पॉइनकेयर के डायरेक्शन में फ्रांस और बेल्जियम ने जनवरी 1923 में रुहर इंडस्ट्रियल इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इस कब्ज़े पर जर्मनी का रिएक्शन ज़्यादातर पैसिव रेजिस्टेंस था, जिसने दुनिया की हमदर्दी जीती और डावेस पैक्ट में हर्जाने की शर्तों को "नरम" कर दिया।

अप्रैल 1924 (ऊपर पेज 94 देखें), जिसमें रूहर से एलाइड कब्ज़ा करने वाली सेनाओं को वापस बुलाने की भी बात कही गई थी।

बहुत ज़्यादा दबाव से काम की आज़ादी में बहुत जल्द सभी मज़दूर शामिल हो जाएँगे। सिर्फ़ बैंक और स्टॉक-एक्सचेंज सर्कल और अपने फ़ायदों में फँसे छोटे पेंशन पाने वालों के सर्कल में ही उनके विरोधी बने रहेंगे।

जो काम करता है, उसे इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती कि उसे अपने टेम्परारी एसेट्स पर बैंकों से ब्याज मिलता है, और क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा ब्याज देने में तो उसकी दिलचस्पी और भी कम होती है; अपने पैसे को वर्किंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल करके वह काम करना और कमाना चाहता है। इसी वजह से, सभी बिज़नेसमैन, फैक्ट्री मालिक और कारीगर ब्याज वाले कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बनाए रखने में बहुत कम दिलचस्पी लेंगे। – यह बात उन सभी के लिए बिल्कुल साफ़ हो जाती है जो यह ध्यान में रखते हैं कि सरकारी ब्याज – जैसा कि हमने सबसे साफ़ तौर पर दिखाया है – सिर्फ़ प्रोडक्टिव वर्कर्स की काम की इनकम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए निकाला जाता है।

जिसके मन में यह बात साफ़-साफ़ बैठ जाती है, उसे किसी भी पल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सच में एक बुनियादी उसूल है: कि सरकार सिर्फ़ वही दे सकती है जो उसे किसी न किसी रूप में अपने नागरिकों से फिर से लेना ही पड़े।

राज्य के इंटरेस्ट पेमेंट का इंटरेस्ट हर हाल में प्रोडक्टिव वर्कर्स से ही लिया जाना चाहिए। कोई भी वर्कर इस नियम से बाहर नहीं है, खासकर वह मेहनती मज़दूर जिसके पास कोई इंटरेस्ट वाले बॉन्ड नहीं हैं। यह स्थिति उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि डायरेक्ट और खासकर इनडायरेक्ट टैक्स भी उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब, जब ठीक इसी वर्कर को इनकम डिडक्शन के रूप में डायरेक्ट इनकम टैक्स के ज़रिए टैक्स के लिए बुलाया जाता है, तो बाकी सभी सर्कल से पहले ही वर्कर को इन मामलों में भविष्य बताने वाला बना दिया है; यही बात सभी वेतन और सैलरी कमाने वालों के लिए भी सच है। सच तो यह है कि ये सर्कल ज़्यादा रेडिकल इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बहुत कम जागरूक हैं – हालांकि वे उन्हें ज़्यादातर इन्फ्लेशन में महसूस करते हैं, जैसा कि "इन्फ्लेशन" चैप्टर में बताया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स सबसे अनसोशल टैक्स है। यह प्योर लोन कैपिटल के पक्ष में काम पर बोझ डालता है। कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता, और इसलिए यह सबसे कम इनकम वाले पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर - कोयला, नमक, माचिस, चीनी, बीयर और पेय कर, व्यक्तिगत परिवहन कर, आदि - बड़ी पूंजीगत संपत्ति के मालिक को कम से कम परेशान नहीं करते हैं।

इसलिए मज़दूरों के ग्रुप में से एक जो ऐसे आज़ादी देने वाले काम का विरोधी है
ऐसा सिर्फ़ इन कनेक्शन के बारे में जानकारी और समझ की कमी से ही हो सकता है।

आखिरी और सबसे मुश्किल बात जिससे हमें इस चैप्टर में निपटना है, वह है इंटरनेशनल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन्स को हटाने का सवाल – दूसरे शब्दों में, युद्ध के कर्ज़ों के लिए आगे इंटरेस्ट पेमेंट से इनकार करना।

यह सवाल जर्मन ऐतिहासिक सवाल से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, असल में यह आम तौर पर जर्मन सवाल है, क्योंकि यह कहता है: क्या जर्मन राष्ट्र आज़ादी चाहता है या गुलामी?

हम जानते हैं कि ऐसे आखिरी सवालों में, सिर्फ़ पक्की इच्छा ही जीत तय कर सकती है और उसे हासिल कर सकती है – इसलिए इस सवाल का जवाब फाइनेंशियल पॉलिटिकल नज़रिए की रेंज से बहुत आगे जाता है। लेकिन यह ज़रूरी है कि एक देश जिसे अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करनी है, वह यह जाने कि उसकी गुलामी सबसे पहले फाइनेंशियल पॉलिटिकल है, कि यहाँ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी के हालात में यही नई बात है कि इस पर फाइनेंशियल पावर के पॉलिटिकल नज़रिए का राज है और मिलिट्री पावर के पॉलिटिकल नज़रिए दूसरे नंबर पर आते हैं।

हम सच में मैमोनिस्टिक युग को एक नए युग के तौर पर कह सकते हैं। भगवान मैमोन इस दुनिया की गद्दी पर बैठे हैं। राजा-महाराजा उनके सामने सिर झुकाते हैं। पार्लियामेंट और सरकारें उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। वह बड़े आंदोलनों को जोड़ने में कामयाब रहे हैं – जैसे मज़दूरों की अपनी तरक्की के लिए कोशिशें। इंटरनेशनल कैपिटल ने भी इसी तरह

दुनिया के प्रेस को अपने लक्ष्यों के लिए उपयोगी बनाना – क्योंकि इसने खुद को सांस्कृतिक संपदा का प्रशासक और हर राष्ट्रीय स्वदेशी कला और साहित्य का मिलावटखोर भी बना लिया है।

इस मैमोनिस्टिक इंफेस्टेशन और दुनिया पर राज के सबसे खास वाहक के तौर पर हमने यहूदियों को पहचान लिया है और इसलिए हमारे ज्ञान का सर्कल एक बार फिर सभी सवालों के सवाल – यहूदी सवाल के साथ बंद हो गया है।

इंटरेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहूदी सवाल का सॉल्यूशन है। हमारे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इंटरेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहूदी दुनिया के राज को तोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया के यहूदियों की ताकत – उनकी फाइनेंशियल ताकत – को खत्म कर देता है।

लेकिन ब्याज की समस्या का समाधान, इसके अलावा, एक कंस्ट्रक्टिव अर्थ में भी है,
समय सामाजिक प्रश्न का समाधान भी है।

युद्ध के कर्ज़ों पर हर ब्याज और ड्यूटी पेमेंट से इनकार करने पर इंटरनेशनल फाइनेंस, या फ्रांस, के सामने पूरे जर्मनी के पूरे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्ज़ा करने का सवाल आ जाएगा। अगर राइख के सभी टैक्स हटा दिए जाएं जो अब दुश्मन को ब्याज पेमेंट के तौर पर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि सबसे पहले अंदरूनी तौर पर पागलपन भरे टैक्स जुल्म से छुटकारा मिलेगा, जो सबसे बड़े पैमाने का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक काम होगा, और दुश्मन को जर्मनी में अपना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करनी होगी।

लेकिन अगर जर्मन लोगों ने हर टैक्स और पेंशन ऑफिस में फ्रेंच या यहूदी टैक्स कलेक्टर को बैठे देखा, और अगर ये विदेशी ज़ालिम किसानों के बाड़ों से सबसे अच्छी गायें ले गए – तो शायद गुस्सा और गुस्सा जल्द ही इतना बढ़ जाएगा कि एक रात खूनी झाड़ू से विदेशी साया मिटा दिया जाएगा और जर्मनी को आज़ाद कर दिया जाएगा।

क्या, आम तौर पर, कोई मिलिट्री ताकत किसी की सेवा में ऐसा काम करेगी?
इसलिए फाइनेंशियल पावर अभी भी बहुत संदिग्ध है।

आज़ादी की हमारी इच्छा की उम्मीदें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी पहली नज़र में लग रही थीं – इसके उलट। पहली बार जब जर्मनी ने एकमत होकर अपने "वॉर हीरोज़" को सौंपने से मना कर दिया, तो इस "नहीं" के साथ ही डर खत्म हो गया।

अब इंटरनेशनल फाइनेंस ज़रूर दूसरे तरीके अपनाएगा, खासकर बॉयकॉट का तरीका और इंटरनेशनल मार्केट को पूरी तरह से दबाना। यह भी पक्का है कि वह बाद वाले तरीके में कामयाब नहीं होगा, और जर्मन सामान का बॉयकॉट जर्मनी को, शुरू में सिर्फ़ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और कुछ समय के लिए सिर्फ़ अपने अंदरूनी मार्केट की तरफ़ ले जाएगा। इसलिए यहाँ भी यह सिर्फ़ एक अच्छी घरेलू पॉलिसी का काम होगा – खासकर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रमोशन के ज़रिए – कि मुश्किल समय से निकला जाए और लोगों की भलाई के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए, जब तक कि दुनिया के लिए नए रास्ते तय न हो जाएं।

दुनिया के लिए नए रास्ते खुलने का यह रास्ता दूसरे देशों के बीच भी यहूदियों के दबदबे को खत्म करके ही खुलेगा, क्योंकि अलग-अलग देशों के लिए भी एक हेल्दी नेशनल इकॉनमी का रास्ता तभी हो सकता है जब वे यहूदी-मैमोनिस्टिक ज़हर से अपने घरेलू ज़हर से ठीक हो जाएं। तब देशों के बीच एक हेल्दी इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक कॉमर्स के नैचुरल रास्ते अपने आप खुल जाएंगे – और इंसानियत, यहूदी ज़ुल्म से आज़ाद होकर, पहले कभी न देखी गई खुशहाली के दौर का अनुभव करेगी – और सबसे बढ़कर, जर्मनी - जो दुनिया का दिल है!

संस्करण 1.0

सुडेटेनलैंड वर्लाग द्वारा ईसाई कैलेंडर के कलियुग अक्टूबर 2018 में AH के वर्ष 130 में प्रकाशित।

SUDETENLAND
VERLAG

एइनार बिर्केमैन द्वारा एडिट किया गया।

किताब का फ्रंट कवर इटालो ने बनाया है।